राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या: 11

गुरुवार,

18 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

बी.पी.एल. परिवारों को एक रुपये प्रति किलो गेहूं उपलब्ध करवाने की योजना

203. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश के सभी बी.पी.एल. परिवारों को एक रुपया प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): जी हां। राज्य में 01 मार्च, 2019 से बी.पी.एल. परिवारों के लाभार्थियों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। आदेश दिनांक 07.02.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 08.02.2019 की प्रति परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक रुपये किलो गेहूं उपलब्ध करवाने की बात कही तो एक रुपये किलो में कुल कितना गेहूं दिसम्बर से लेकर जून तक राजस्थान में बांटा गया और इसमें कुल कितना खर्चा आया?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में हमारे जो बी.पी.एल. के लोग हैं उनकी संख्या 1 करोड़ 16 लाख 46 हजार 913 है, इन लोगों को एक रुपये किलो गेहूं बांटा गया।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान सरकार द्वारा एक रुपये किलो वितरण करने वाले राशन डीलर्स का विगत माह फरवरी से कमीशन नहीं दिया जा रहा है? इससे राशन वितरण व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है एवं सरकार बकाया भुगतान कब तक करने की मंशा रखती है?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, कमीशन दिया जा रहा है और हमने कमीशन को बढ़ाया भी है। जो पहले हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था थी वह 50-50 परसेंट थी, अब हमने 38 रुपये, 17 रुपये बढ़ाया और कमीशन बढ़ाने की वजह से राज्य सरकार का जो व्यय है वह 60 परसेंट हो गया और भारत सरकार का 40 परसेंट हो गया है। आप कह रहे हैं, यदि कहीं पर प्रोब्लम है, किसी डीलर से संबंधित तो आप मुझे बताएं, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिर्राज सिंह।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): सर, एक और है। एक रुपये किलो जो गेहूं दिया जा रहा है, उसमें से भारत सरकार द्वारा कितना गेहूं आबंटित किया गया है एवं किस भाव से राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाया जा रहा है?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): भारत सरकार से तो हमें दो रुपये किलो मिल रहा है। राज्य सरकार उसको अपने राज्य कोष से वहन कर रही है, एक रुपये किलो। आबंटित जो मात्रा है, अगर आप पूरे राजस्थान की चाहें या जिले की चाहें तो उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या-204

श्री गिर्राज सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

विराटनगर उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

205. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने उपखण्ड मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विराटनगर उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार विराटनगर उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) वर्तमान में प्रदेश के 289 उपखण्ड मुख्यालय में से 114 उपखण्ड मुख्यालय ऐसे हैं जहां राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं हैं। सूची परिशिष्ट- '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विराटनगर उपखण्ड मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय महाविद्यालय, थानागाजी, 50 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय महाविद्यालय व राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटपूतली, 35 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय कला व राजकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, चिमनपुरा तथा 27 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय कन्या महाविद्यालय, शाहपुरा संचालित है।

विराटनगर उपखण्ड जिला जयपुर में वर्तमान में निजी क्षेत्र में 5 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट- '2' पर संलग्न है।

अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट बहस पर जवाब में राजस्थान में जो 25 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है। उसके तहत माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि विराटनगर में अभी परसों ही नया राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सौभाग्यशाली इंसान हूं कि जिसका प्रश्न आने से पहले ही उसकी घोषणा हो चुकी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी एवं उच्च शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह महाविद्यालय कब तक संचालित हो जाएगा?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान में 25 नए राजकीय महाविद्यालय, 5 नए राजकीय कन्या महाविद्यालय और 3 मूल बजट में नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा इस सदन में की है। हमारा बजट सत्र अभी वर्तमान में चल रहा है। बजट पारित होने के बाद में अतिशीघ्र इन तमाम राजकीय महाविद्यालयों को खोलने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

पोंग बांध के विस्थापितों को जमीन का आबंटन

206. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध के निर्माण के समय विस्थापितों को सिंचित इलाके में जमीन आबंटन किये जाने पर हिमाचल सरकार व राजस्थान सरकार के बीच एम.ओ.यू. हुआ था? यदि हां, तो एम.ओ.यू. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पोंग बांध का पानी इंदिरा गांधी नहर को मिल रहा है? यदि हां, तो कितना पानी प्राप्त हो रहा है? समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पोंग बांध के समय हुए विस्थापितों को जमीनों का आबंटन सिंचित इलाके में होना था? यदि हां, तो कितने परिवारों को कितनी-कितनी जमीन कितनी-कितनी किश्त राशि पर आबंटित की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कितने विस्थापितों को जमीन आबंटन करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जमीन आबंटन के उपरांत कितने आबंटन निरस्त किये गये, कितनी आबंटित जमीनों पर कब्जे हैं? इन कब्जों को मुक्त कराने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गए हैं? क्या सरकार सभी विस्थापित परिवारों को

(श्री सुभाष पूनिया)

पुनर्वास किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विपक्ष के एमएल.ए. साहब को कि मेहरबानी करके कम से कम प्रश्न करने के लिए तो आप यहां पर आए, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज प्रश्न का उत्तर दें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जी हां। एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। पोंग बांध का इंदिरा गांधी नहर में 6.99 एम.ए.एफ. पानी उपलब्ध हो रहा है। समझौते की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) पोंग बांध विस्थापितों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि का आबंटन किया जाना था। विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(4) राजस्थान सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से अब तक 13483 पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें से 12016 प्रकरणों में आबंटन किया जा चुका है। शेष 1467 प्रकरण विचाराधीन हैं।

(5) विवरण परिशिष्ट-"द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): एम.ओ.यू. किस तिथि को हुआ और विस्थापितों को आबंटन करने के बाद कितने विस्थापितों को कब्जा दिया गया? एक।

दूसरा, मेरा यह प्रश्न है कि आप यह कह रहे हो कि 6.99 एम.ए.एफ. पानी उपलब्ध हो रहा है। अभी तक हमें जो बताया गया है कि इतना पानी अपने समझौते के अनुसार नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज एक-एक प्रश्न पूछें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): एम.ओ.यू. 10.07.1967 के अंदर हुआ था। 6.99 एम.ए.एफ पानी समझौते के तहत हमको मिलना चाहिए था, उसमें से 6.00 एम.ए.एफ. मिल रहा है और पाइंट 99 एम.ए.एफ. अभी तक हम लोगों को पंजाब से नहीं मिल रहा है।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): यह कब तक मिलेगा?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): आपने पूछा कि कब तक मिलेगा तो जहां कहीं पर भी हम लोगों को, जहां पर यह फैसला होता है, वहां राजस्थान का पक्ष, राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान के विभागों द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, पत्र भी लिखे जा रहे हैं और उस बोर्ड के अंदर भी उसका पक्ष रखा जा रहा है। आपने पूछा कि कब तक मिलेगा? प्रयास जारी है, जब कभी प्रयासों में सफलता मिल जाएगी तो उस दिन से मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, please correct it. आप कह रहे हैं कि- "6.99 एम.ए.एफ. पानी उपलब्ध हो रहा है।" अब यह कह रहे हैं कि 6.00 एम.ए.एफ. ही आ रहा है। 6.99 is our समझौते का पार्ट है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): हां, वह समझौते का है, सर।

श्री अध्यक्ष: हमको 6.00 एम.ए.एफ. ही मिल रहा है।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): आपने तो यह कहा कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। इसमें हम लिख रहे हैं कि- "पोंग बांध पर इंदिरा गांधी नहर में 6.99 एम.ए.एफ. पानी उपलब्ध हो रहा है।" we're committing it and we're getting it. This is not correct. Please correct it 6.00.

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): हां, मैं यही कह रहा हूं कि साहब 6.99 एम.ए.एफ. तो समझौता का है और 6.00 एम.ए.एफ. मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप अपने उत्तर में पढ़िये। मान्यवर, आपका जो उत्तर सरकार में आ रहा है वह "6.99 एम.ए.एफ." का आ रहा है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): सर, 6.99 एम.ए.एफ. तो समझौता है और 6.00 एम.ए.एफ. मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर पढ़ें। उपलब्ध हो रहा है, उपलब्ध means we're getting and which is not correct. यह आपका आफिशियल रिकार्ड होगा तो कल की डेट में सरकार के सामने यह होगा कि सरकार ने यह कहा है। जो 6.99 एम.ए.एफ. हमारा समझौता है, हमें 6.00 एम.ए.एफ. ही मिल रहा है। इसमें लिख रखा है कि 6.99 एम.ए.एफ. पानी उपलब्ध हो रहा है, as if we're getting which is not correct.

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, समझौता भी

(श्री बलवान पूनियां)

8.60 एम.ए.एफ. का है। सर, मैं करैक्ट कर रहा हूं। 8.60 एम.ए.एफ. का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठें। माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठें। अगला प्रश्न।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): दूसरा प्रश्न है कि जिन भूमि का आबंटन हुआ था क्या उनको भौतिक कब्जा दे दिया गया था और जिनको नहीं दिया उनको कब तक कब्जा देने का प्रयास किया जाएगा?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भौतिक कब्जा देने के लिए नियमों के अंदर परिवर्तन किया गया। 6(अ) के तहत उनको भौतिक कब्जा कराने की व्यवस्था की गयी पर सुप्रीम कोर्ट तक यह प्रकरण गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह 6(अ) धारा को रद्द कर दिया गया इसलिए कोर्ट से जो आदेश आया हुआ है, उस कारण से यह भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, बलवान पूनियां। माननीय सदस्य, दो प्रश्न हो गये, प्लीज, बैठें।

गोगामेड़ी मेले से प्राप्त आय

207. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गोगामेड़ी मेले (नोहर) हनुमानगढ़ में विगत 10 वर्ष में चढ़ावे से कितनी आय हई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मेला व्यवस्था में उक्त अवधि में कुल कितनी राशि व्यय की गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 1 जनवरी, 2018 से 31 मई, 2018 तक कुल कितनी राशि गोगामेड़ी मंदिर निर्माण पर व्यय की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी, गोगामेड़ी (नोहर) हनुमानगढ़ मेले में पिछले 10 वर्षों में भेंट, गल्लों व रसीदों से चढ़ावे के रूप में प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा मेला व्यवस्था पर गत दस वर्षों में वित्तीय वर्ष अनुसार किये गये व्यय की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(देवस्थान मंत्री)

(3) मंदिर श्री गोगाजी गोगामेड़ी (नोहर) हनुमानगढ़ के निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु क्रमांक पं. 4(2)देवस्थान/2015/पार्ट-II दिनांक 18.09.2015, 14.07.2017 एवं संशोधित स्वीकृति दिनांक 28.02.2018 के अनुसार 25 करोड़ 27 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 2 करोड़, वर्ष 2016-17 में 2 करोड़, वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ एवं वर्ष 2018-19 में 9 करोड़, कुल 23 करोड़ रुपये कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. को आबंटित किये गये, जिसमें से अब तक 22 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्षजी, गोगामेड़ी मेले का रेवेन्यू गोगामेड़ी में ही क्यों नहीं लगता? प्रश्न नंबर-एक। मेरा दूसरा प्रश्न है, गत दिनों 2018 में, पिछली सरकार के समय में गबन के मामले में क्या कार्यवाही की गयी है अब तक और आगे विभाग क्या करेगा? गोगामेड़ी मंदिर की रेवेन्यू..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, काफी है, पहले इसका जवाब आने दें। बैठें, प्लीज।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेड़ी से प्राप्त आय में से श्रद्धालुओं के सुविधार्थ बैरिकेडिंग, विद्युत व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, टैंट व्यवस्था, पानी व्यवस्था आदि पर व्यय किया जाता है। शेष राशि का ड्राफ्ट बनाकर प्रधान कार्यालय भिजवाया जाता है, जिसका राजस्थान निधि एवं बजट लेखा नियम, 2015 के तहत नियमानुसार व्यय किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप बैठें प्लीज। इनका प्रश्न यह है कि यह आय वहीं पर क्यों खर्च नहीं की जाती है और दूसरा, गबन के बारे में है। इन दोनों का जवाब बताएं।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): इसकी पूरी जांच करायी जाएगी। अभी इंस्पैक्शन हुआ है, अध्यक्ष महोदय, और उसमें अभी आप चाहें तो मैं पूरा पढ़कर सुना दूं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मोटा-मोटा सुना दो। दो-तीन बात, जिससे अगला ठीक हो जाए।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): अभी कमेटी बनायी है, जो गबन आपने पूछा, 1.24 करोड़ का गबन हुआ है, उसमें एफ.आई.आर. रजिस्टर हो गयी है। यह गबन हुआ था 26.11.2018 को, उसमें कमेटी बना दी है, उसमें एफ.आई.आर. रजिस्टर हो गयी है, चार्जशीट दे दी है असिस्टेंट कमिशनर को, एस.डी.ओ. को, ए.डी.ओ. भादरा को, ए.ओ. गोगामेड़ी को, कैशियर को, ए.ओ. सस्पेंड कर दिये गये हैं। सैक्रेटरी और कमिशनर साहब अभी होकर आये हैं 5.7.2019 को और इंस्ट्रक्शन प्रिवेंट कर रहे हैं कि ऐसे दुबारा गबन न हों।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एक छोटा-सा प्रश्न और है। गोगामेड़ी मंदिर की रेवेन्यू ड्राप कैसे हुई? गत वर्षों में जो रेवेन्यू थी, वह ड्राप कैसे हुई?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): अभी इसका जवाब मैं वैसे दे चुका हूं। नहीं, राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगामेड़ी का मास्टर प्लान लागू होने पर मंदिर का नव-निर्माण, यह तो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आप पूछना चाह रहे हैं कि रेवेन्यू क्यों ड्राप हुई?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): है मेरे पास उत्तर, एक सैकण्ड। आप कहें तो मैं थोड़ी देर में आपको बता दूं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोतमलाल।

धरियावद में नगरपालिका बनाने की योजना

208. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नई नगरपालिका बनाने के क्या मानदण्ड हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार धरियावद जिला प्रतापगढ़ को नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत संक्रमणशील क्षेत्र को नगरपालिका बनाने का प्रावधान है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ से ग्राम पंचायत धरियावद को नगरपालिका बनाये जाने के संदर्भ में नियमानुसार जन आपत्तियां प्राप्त कर निस्तारण करते हुए स्पष्ट तथ्यात्मक टिप्पणी/अभिशंसा चाही गयी है। जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ से अभिशंसायुक्त प्रस्ताव/टिप्पणी प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ के बाद में धरियावद बहुत बड़ा कस्बा है और ग्राम पंचायत के पास में साधन-सुविधा नहीं होने से न तो वहां पर साफ-सफाई होती है और न उनके पास में कोई साधन है। मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय द्वारा जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ से जो टिप्पणी चाही गयी है, मान लो उसमें जनसंख्या की कोई कमी हो तो धरियावद पंचायत समिति के पास में जो पंचायतें हैं, उसके गांव भी एक-दो किलोमीटर में लगे हुए हैं, तो आपने प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर से जो टिप्पणी मांगी है, उसकी प्रति भी हमको दें और मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि धरियावद को नगरपालिका बनाने का मन साफ है कि आप नगरपालिका बनाएंगे? यही आपसे कहना है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक जनसंख्या का सवाल है, धरियावद की जनसंख्या सिर्फ 11 हजार 368 है। दूसरा, आपने जो कहा कि साहब, आपकी मंशा साफ है, हमारी तो मंशा बहुत साफ है, लेकिन पुरानी बात बता देता हूं पूर्ववर्ती सरकार की, कि उसने जिला कलेक्टर को वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी लेकर स्पष्ट राय भिजवाने के लिये तथ्यात्मक टिप्पणी करने के लिये चार-चार, पांच-पांच बार पत्र लिखे। वह पत्र लिखे- मार्च, 2016 में, अप्रैल, 2017 में, फरवरी, 2018 में, मार्च, 2018 में, फिर मई, 2018 में और उसके बाद में फिर जुलाई, 2018 में भी लिखे, लेकिन पांच पत्रों के बाद भी उस सरकार को तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मोटी बात यह होती नगरपालिका बनाने के लिये कि सबसे पहले कलेक्टर को कहा जाता है कि अपनी अनुशंसा भेजें और अनुशंसा भी भेजें तो उसके 8-10 पाइंट होते हैं कि किन-किन पाइंट पर वह अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट भेज

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सकता है। यह पाइंट है - जनसंख्या देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, कृषि और अकृषि की सीमा देखी जाती है, इसके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो विकास के काम किये जाते हैं, उससे नगरपालिका बनाने से नगरपालिका को फायदा होगा या नुकसान होगा ग्राम पंचायत हटने के बाद, यह भी देखा जाता है। इसी के साथ-साथ उसका स्टाफ देखा जाता है कि ग्राम पंचायत का कितना स्टाफ है। यह सब चीजें देखने के बाद वह अपनी अनुशंसा भेजता है। भेजने के बाद सरकार फैसला करती है तो आप वाकई इसके लिये गम्भीर हो तो मेहरबानी करके कलेक्टर के दफ्तर में जाइए और इन सब चीजों को भिजवाने की कोशिश करिए ताकि राज्य सरकार उस पर विचार कर सके।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए आपके माध्यम से यह निवेदन किया था कि धरियावद की जनसंख्या कम हो तो उसके पास में लगी हुई ग्राम पंचायतों के गांव हैं दो-तीन किलोमीटर पर। बात यह है कि धरियावद जो कस्बा है, वहां का सरपंच भी नहीं बन सकता, क्योंकि वहां एस.टी. की सीट सुरक्षित है तो दूसरे गांव से तो हम सरपंच बनाते हैं। मेरा निवेदन है कि नगरपालिका बनानी बहुत आवश्यक है और दूसरे गांव की जो सहमति है, आपने जो मांगा है, उसकी एक प्रति हमको दें ताकि हम वहां जाकर सबकी सहमति बनाकर जिला कलेक्टर को भी दें। साथ ही आपने जो भी टिप्पणी मांगी है और इसके मानदण्ड की एक प्रति आप हमको उपलब्ध कराएं और मेरा आपसे निवेदन है आप नगरपालिका धरियावद को बनाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, ट्राइबल सब-प्लान का पैसा राजस्थान सरकार को आता है। यह प्रतापगढ़ जिले में सबसे बड़ा टाउन है प्रतापगढ़ के बाद। क्या राजस्थान सरकार ट्राइबल इलाके में नगरपालिका कैसे बने, जिससे ट्राइबल के लोगों को उसका लाभ मिल सके, इस बारे में कोई विचार करके यदि वहां पर सरकार नगरपालिका बनाएगी तो उस ट्राइबल इलाके में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि आजादी के बाद एक नगर कैसे बनता है आदिवासी इलाके में, उस दृष्टि से राजस्थान सरकार यदि सोचेगी तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार का एक अच्छा मैसेज ट्राइबल इलाके में जाएगा। माननीय मंत्री जी, इस पर विचार करें।

अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

टाटगढ़ उपखण्ड को जवाजा जी.एस.एस. से जोड़ने की योजना

209. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टाटगढ़ उपखण्ड की ग्राम पंचायतों में विद्युत सप्लाई भीम जी.एस.एस. से होती है?

(2) क्या यह भी सही है कि टाटगढ़ उपखण्ड अजमेर जिले में स्थित होने के कारण भीम में जब भी विद्युत आपूर्ति बंद की जाती है तो सबसे पहले टाटगढ़ उपखण्ड की विद्युत सप्लाई बंद की जाती है?

(3) क्या सरकार टाटगढ़ उपखण्ड को जवाजा जी.एस.एस. से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। टाटागढ़ उपखण्ड की ग्राम पंचायतों में विद्युत आपूर्ति 33/11 केवी सब-स्टेशन टाटगढ़ से की जाती है एवं 33/11 केवी सब-स्टेशन टाटगढ़ की विद्युत आपूर्ति 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन भीम से जुड़ी है।

(2) जी नहीं। 33/11 केवी सब-स्टेशन टाटगढ़ की विद्युत आपूर्ति 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन भीम से 33 केवी फीडर के द्वारा की जाती है। उक्त फीडर पर कुल तीन 33/11 केवी के सब-स्टेशन टाटगढ़, बरार एवं अजीतगढ़ स्थापित हैं। 33 केवी फीडर के फाल्ट होने की स्थिति में ही 33/11 केवी सब-स्टेशन टाटगढ़ की विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है जिसे यथाशीघ्र ठीक कर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जाती है। उक्त फीडर पर सामान्य परिस्थितियों में विद्युत आपूर्ति निगम नियमानुसार सुचारु रूप से की जाती है।

(3) जी नहीं। टाटगढ़ 33/11 केवी सब-स्टेशन को जवाजा 33/11 केवी सब-स्टेशन से जोड़ा जाना वित्तीय रूप से साध्य नहीं है क्योंकि टाटगढ़ से जवाजा सब-स्टेशन की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि टाटगढ़ से यह जो 50 किलोमीटर की दूरी बतायी गयी है यह भी गलत आंकड़े हैं और वहां टाटगढ़ से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा खेड़ा जी.एस.एस. बना हुआ है, टाटगढ़ का जी.एस.एस. बना हुआ है, टाटगढ़ 40 किलोमीटर आगे है और बड़ा खेड़ा उसके

(श्री शंकर सिंह रावत)

पहले है तो अगर बड़ा खेड़ा से जवाजा के तारागढ़ को अगर जोड़ दिया जाता है तो मात्र 10 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है। अगर वो लाइन जुड़ जाती है तो उधर सीधे ही, दूसरे विधान सभा क्षेत्र से या दूसरे जिले से लेने की आवश्यकता नहीं होगी, यह मेरा निवेदन था।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी एक नया स्टेशन बता दिया, जवाजा वास्तव में इससे 50 किलोमीटर की दूरी पर है और भीम मात्र केवल 33 किलोमीटर की दूरी पर है और चूंकि नई लाइन डालेंगे तो वह असाध्य और अनइकोनोमिक है इसके कारण से सम्भव नहीं है। बाकी आपके यहां किसानों को छह घंटे बिजली और आम उपभोक्ताओं को 22 से 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। इस पूरे ग्रिड में भीम, अजीतगढ़, बरार इन पर मात्र 2.35 मेगावाट का लोड है और यहां पर इस एक फीडर पर 1x3.15 एमवीए के आधार पर बिजली दी जा रही है इसलिए वहां कोई प्रोब्लम नहीं है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, प्रोब्लम है जब ही तो हम निवेदन कर रहे हैं कि टाटगढ़ एरिया, टाटगढ़ उपखण्ड, वो सात ग्राम पंचायतों का एरिया है और सबके अन्दर शाम के टाइम में जिस प्रकार दीपक जलता है उस रूप में वहां पर लाइट आती है, पूरा पावर नहीं पहुंच पाता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने प्रश्न टाटगढ़ से जवाजा पूछा है, आपको यह पूछना चाहिए था कि बड़ाखेड़ा से जोड़ा जाए कि नहीं, तो मंत्री जवाब देते। आपने जो सजेशन दिया ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): इसमें जोड़ने के लिए लिखा हुआ है, हुकुम।

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न संख्या तीन में यह नहीं लिखा है। आप माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए इसको एक्सप्लोर करें।

अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ की ग्राम पंचायतों में पट्टों का वितरण

210. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविरों द्वारा ग्रामीणों को उनके आवास के पट्टे उपलब्ध करवाने के लिए पट्टा वितरण

(श्रीमती संतोष)

अभियान का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2017 से मई, 2019 तक कब-कब ग्रामीण शिविर लगाए गये, इनमें कितने आवेदकों को पट्टे वितरित किये गये? वितरित पट्टों का पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पट्टा वितरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाएं व सामान्य वर्ग के कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितनों को आवासों के पट्टे उपलब्ध करवाये गये? ग्राम पंचायतवार आवंटित पट्टों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) जी हां। दिनांक 14 अप्रैल, 2017 से 31 जुलाई, 2017 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविरों तथा दिनांक 01 मई, 2018 से 30 जून, 2018 तक न्याय आपके द्वारा शिविरों में ग्रामीणों को उनके आवास के पट्टे उपलब्ध कराये गये थे। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा लगाये गये शिविरों का तिथिवार व वितरित किये गये पट्टों का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) पट्टा वितरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाएं एवं सामान्य वर्ग के प्राप्त आवेदन एवं आवेदकों को उपलब्ध कराये गये पट्टों की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें इन शिविरों में कई आवेदकों ने पट्टों के लिए आवेदन किये थे लेकिन आवेदन के बावजूद सूची में उनका कहीं नाम भी नहीं है और उनको पट्टे भी नहीं दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि जिन अधिकारियों ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी और उन आवेदकों को पट्टे क्यों नहीं दिये गये?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या बोल रही हैं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह दो शिविर जो लगाये गये थे, हालांकि यह निरन्तर प्रक्रिया है लेकिन विशेष अभियान चलाया जाता है कि जो भूमिहीन हैं या जिनके पट्टे नियमित नहीं हैं उनको नियमन करा सकें।

(श्री सचिन पायलट)

अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो पहला शिविर लगा था उसमें लगभग 97 प्रतिशत, 9566 आवेदन आये थे उसमें से 9265 को पट्टे मिल गये हैं और इसी प्रकार जो दूसरा शिविर लगा था उसमें भी लगभग 95 परसेंट, जो आवेदन आये थे उनको पट्टा आबंटित किया गया है। फिर भी अगर माननीय सदस्या चाहेंगी, कोई विशेष ऐसा व्यक्ति या परिवार हो जिनको आबंटन नहीं किया गया, नियमानुसार हम आबंटन करने के लिए तैयार हैं।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन आवेदकों को इन शिविरों के माध्यम से पट्टे नहीं मिले, उनको पट्टे नहीं मिलने का क्या कारण रहा है और उनको कब तक पट्टे उपलब्ध करवाये जाएंगे?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको विदित है ये जो आबादी के लिए जमीन है उसमें से हम लोग पट्टे आबंटित कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान बनाया हुआ है रेवेन्यू की भूमि पर तो उसको हम सैट-अपार्ट करके फिर उसका नियमन कर सकते हैं। अगर कोई पारिवारिक झगड़ा है या जंगल की जमीन है या सिवायचक की जमीन जिसको हम आबंटित नहीं कर सकते हैं, वो कानून के दायरे के बाहर आती है लेकिन फिर भी जैसा आपने देखा होगा, जो आवेदन आये थे उसमें लगभग 97 प्रतिशत, क्योंकि जब सरकार अभियान चलाती है तो हमारी मंशा पट्टे आबंटन करने की है, न कि उसको ना करने की। इसलिए सरकार संवेदनशील है और खासकर जो एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., महिलाएं या गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए हम अधिक प्रयास करके और पट्टा आबंटित करेंगे।

प्रश्न संख्या 211

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

भरतपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत देय अनाज

212. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्तर्गत किस गांव में कितने खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़े हुए हैं? ग्रामवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत चार वर्ष में खाद्य सुरक्षा योजना से काटे गये एवं जोड़े गये व्यक्तियों के ग्रामवार व नाम-पिता के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला भरतपुर के लिए विगत चार वर्ष में विधान सभा क्षेत्रवार कब-कब कितना-कितना अनाज आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गरीबों को मिलने वाले खाद्य सुरक्षा में गेहूं को पांच किलोग्राम की जगह दस किलोग्राम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. के लिए चीनी देने का क्या प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए परिवारों की संख्या सूची ग्रामवार परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्तर्गत विगत चार वर्षों में 485 परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से काटे गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर तथा परिवारों को जोड़े गये नामों का विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है। सम्पूर्ण विवरण विभाग के पोर्टल (food.raj.nic.in) पर Annexure VSO 1899 लिंक पर उपलब्ध है।

(3) जिला भरतपुर के लिए विगत चार वर्ष में विधान सभावार आबंटित किये गये खाद्यान का विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ए.पी.एल. में बी.पी.एल. को चीनी देने का वर्तमान में प्रावधान नहीं है। केवल अन्त्योदय परिवारों को एक किलोग्राम चीनी प्रति माह प्रति राशनकार्ड उपलब्ध करायी जा रही है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-'य' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है खाद्य सुरक्षा, इस पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

जो प्रश्न मैंने लगाया था उस पर माननीय मंत्री जी से जवाब आया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जो एस.डी.ओ. हैं, बी.डी.ओ. हैं ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): प्रश्न से सम्बन्धित ही है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): मेरा प्रश्न यह है कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए कोई समय सीमा लागू है जिससे लोग ज्यादा चक्कर नहीं लगाएं? मैं माननीय मंत्री से एक तो यह पूछना चाहता हूं कि उसके लिए कोई समय निर्धारित है या नहीं? दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा, मैं पहले मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि पिछले दिनों मैंने हमारे विधान सभा क्षेत्र की एक गैस एजेंसी की शिकायत की। मंत्री जी ने उस पर तत्काल एक्शन लिया और उसके खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज करायी, उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं। क्योंकि..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य। पहले प्रश्न का जवाब दें, फिर दूसरा प्रश्न। (व्यवधान) प्रश्न पूछें, ऐसे नहीं।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): इसका जवाब दे दें फिर उसके बाद।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 30 दिन ... (व्यवधान) निस्तारण करने की।

श्री अध्यक्ष: 30 दिन बता दिया। अगला प्रश्न।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): मैं यह भी कहना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, कहना नहीं चाहता, प्रश्न पूछो।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं कि जो अपात्र लोग हैं, जिस तरह से अभी मुझे एक सूची दी गई उसमें वहां से काफी नाम हटाये गये हैं और मैं समझता हूं कि जब सरकार वास्तव में गरीब की मदद करना चाहती है तो अपात्र लोगों के जो नाम हैं ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): अपात्र लोगों के नाम हटाने का शिकायत के बाद में कितने दिन में, क्या प्रावधान है?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसमें सबसे

(श्री रमेश चन्द मीना)

पहले तो यह है कि एक सादा कागज पर समावेशन के जो आधारभूत दस्तावेज हैं, आप आनलाइन, आफलाइन, एसडीएम, डीएसओ के यहां उपस्थित होकर के, एसडीएम और डीएसओ के माध्यम से और अगर रूरल का है तो विकास अधिकारी, ग्राम सभा के माध्यम से जाएगा परीक्षण के लिए। अरबन एरिये में नगर निकाय, नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी, आयुक्त हैं, उनके माध्यम से जाएगा। उसके बाद वहां से आता है कि डीएसओ का कन्फर्म हो जाए कि समावेशी दस्तावेज बिलकुल सही हैं, तो तुरन्त एसडीएम और डीएसओ कर सकता है। उसका नाम जोड़ सकता है। जो समावेशन की सूची में नहीं आता है, पात्रता नहीं रखता है तो उसका निस्तारण हो जाता है।

इसी प्रकार राजस्थान में लगभग 29 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होंने एक बार भी गेहूं नहीं लिया। हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि जो पात्र व्यक्ति नहीं हैं, उनकी समीक्षा करके उसके अनुसार कार्य करें। अपात्र को हटाएंगे और पात्र को जोड़ेंगे। जब तक हम कन्फर्म नहीं कर लें कि वास्तव में कोई पात्र व्यक्ति रह नहीं जाए, इसकी हम समीक्षा करेंगे। आपकी कोई अन्य समस्या है तो आप मुझसे सम्पर्क कर लें। आपको सूची उपलब्ध करवा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): पोस मशीनों का जो पाइंट है, लास्ट। माननीय अध्यक्ष, केवल आखिरी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। नो, प्लीज आप बैठें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): केवल आखिरी है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठें। नो, माननीय सदस्य, बैठें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): अध्यक्ष जी, केवल एक।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठें। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। श्री हरीश चन्द्र मीना।

देवली-उनियारा से शिक्षकों का स्थानान्तरण

213. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा जिला टोंक में गत पांच वर्षों में

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

कितने शिक्षकों का विधान सभा क्षेत्र से बाहर स्थानांतरण किया गया है? अध्यापकों के नाम, विद्यालय एवं विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र से बाहर शिक्षकों के स्थानांतरण किये जाने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उनियारा, जिला टोंक में गत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र से बाहर किये गये अध्यापकों के स्थानान्तरणों का नामवार, विद्यालयवार एवं विषयवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) शिक्षा विभाग अन्तर्गत शिक्षकों के स्थानांतरण प्रशासनिक, स्वैच्छिक/पारस्परिक एवं राज्य हित के आधार पर विधान सभा क्षेत्र उनियारा, जिला टोंक से बाहर स्थानान्तरण किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उसको मैंने ध्यान से पढ़ा। मेरा मूल प्रश्न है कि विधान सभा क्षेत्र उनियारा, जिला टोंक में गत पांच वर्षों में कितने शिक्षकों का विधान सभा क्षेत्र से बाहर ट्रांसफर किया गया? मैं यह मानता हूं कि शिक्षकों में अध्यापकों के साथ प्रधानाध्यापक भी आता है। जवाब में उसको छिपा लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण रहे आधा जवाब देने के?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो परिशिष्ट 'क' और 'ख' आपको दिया गया था। वह आपने अध्यापकों का पूछा था। प्रिंसिपल की सूची, 29 ऐसे प्रिंसिपल थे...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका कहने का मतलब है कि प्रधानाध्यापक को अध्यापक मानते हैं कि नहीं मानते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): इन्होंने अध्यापक पूछा तो मेरे विभाग ने केवल व्याख्याता तक का दिया। मैं मानता हूं इस बात को, कि देना चाहिए था। प्रिंसिपल का भी इनको देना चाहिए था लेकिन मैं इनके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रश्न की मंशा समझता था इसलिए मैं पूरक में यह सामग्री लेकर आया हूं। 29 प्रिंसिपल हैं, जिनमें से 7 का प्रशासनिक और राज्यादेश के द्वारा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब मैंने सूची को देखा, जो राज्यादेश या प्रशासनिक आधार पर किए गए, उसमें रामनिवास मीना, रामविलास मीना, हीरालाल मीना, रामभजन मीना, शराफत अली खान, हरिसिंह मीना, तो इस तरह लगा कि यह राजनीतिक दुर्भावना से तो कहीं स्थानांतरण नहीं किए गए हैं? मैं आपके माध्यम से सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो भी अध्यापक है, उसको अगर राजनीतिक आधार पर प्रताड़ित किया गया है तो उसके साथ न्याय करने की पूरी मंशा रखती है। जब विधान सभा सत्र का समापन हो जाएगा, उसके बाद स्थानांतरण करेंगे तो इस बात को भी पूरा ध्यान में रखा जाएगा कि इनके साथ में न्याय हो।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, एक मेरा पूरक प्रश्न है। मैं एक घटना बताना चाहता हूं। हमारे वहां उनियारा के पास में अलीगढ़ एक कस्बा है। वहां एक स्कूल में अध्यापक नहीं थे। वह छात्राओं की स्कूल थी। छात्राओं ने विरोध किया। पुलिस ने आकर लाठी चार्ज किया। उस हैड मास्टर ने आकर विरोध किया, लड़कियों पर जब लाठी चार्ज हो रहा था, तो उन लड़कियों को गिरफ्तार किया, हैडमास्टर को गिरफ्तार किया और लड़कियों का चालान किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के संस्थान में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिले।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, उसको प्राइमाफेसी मैंने दिखवाया है। उसमें सत्यता है। इसलिए यह दोनों जो प्रिंसिपल हैं, इनका स्थानान्तरण राजनीतिक दुर्भावना से किया गया है। मैं तत्काल, आज ही निर्देश दूंगा अधिकारियों को, कि वह उनको न्याय दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल नागर।

अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने के मानदंड

214. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बाबूलाल नागर)

सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? क्या सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल क्षेत्रों में उपखण्ड स्तर पर सरकारी महाविद्यालय खोलने के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): राजकीय महाविद्यालय खोलने के मापदण्ड परिशिष्ट 01 पर संलग्न है।

जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 की अनुपालना में वर्तमान में महाविद्यालय से वंचित रहे उपखण्ड मुख्यालयों पर संभावनाओं के परीक्षण हेतु नई नीति लाकर चरणबद्ध तरीके से राज्य में नए महाविदयालय खोले जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि मैंने जो प्रश्न किया था कि अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल क्षेत्रों में उपखण्ड स्तर पर सरकारी महाविद्यालय खोलने की कोई नीति बनाने का विचार रखते हैं? आपने जवाब दिया, उपखण्ड स्तर पर, आपने अपने बजट भाषण में भी शामिल किया है कि परीक्षण कराएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल क्षेत्र में..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछ रहा हूं। जो आप उपखण्ड स्तर की नीति बना रहे हैं महाविद्यालय खोलने के संबंध में, मेरा यह आग्रह है कि उस नीति में क्या उन क्षेत्रों को प्राथमिकता से रखेंगे, जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति का बहुल है? आपको मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न। हो गया प्रश्न? माननीय मंत्री जी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, 10 जुलाई को जो बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा रखा गया, उसमें महाविद्यालय से वंचित उपखण्डों पर नई नीति लाकर चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालय खोलने की बात कही गई है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने की बात कही गई है, उसमें मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि

(श्री भंवर सिंह भाटी)

टीएसपी एरिया में या एस.सी./एस.टी. के क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालय अभी जो घोषणा की गई है, उसमें खोले गए हैं। आगामी वर्षों में भी नवीन महाविद्यालय खोले जाएंगे। उसमें एस.सी./एस.टी. के क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालय खोलने की बात का ध्यान रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा को नवीन जिला बनाने की कार्ययोजना

215. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नवीन जिलों के गठन एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण कर नए जिले स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा वर्ष 2018 में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो सरकार के परीक्षणाधीन है?

(3) क्या यह भी सही है कि बालोतरा को जिला बनाने की मांग विभिन्न संस्थाओं/संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही है? यदि हां, तो तत्संबंधित दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार के परीक्षणाधीन रिपोर्ट में बालोतरा का प्रस्ताव है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार बालोतरा को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जी हां। समिति का गठन आदेश दिनांक 20.01.2014 के द्वारा किया गया था। समिति के सदस्यों के विवरण से संबंधित आदेश के प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) केवल समिति के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2018 में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(3) जी हां। संबंधित दस्तावेजो की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में नवीन जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के active consideration में नहीं है।

(5) नवीन जिला बनाने का प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के

(राजस्व मंत्री)

active consideration में नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सक्षम स्तर पर विचार कर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, मैंने 2011 में पूरी किताब, जी.एस. संधु की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उस समय भी दी। बाद में परमेशचंद्र जी की अध्यक्षता में बनी। इस प्रश्न में जो मेरा दायित्व है, इससे ज्यादा दायित्व मंत्री जी जो स्थानीय हैं, इनका भी है। अंदर से भावना भी है कि बालोतरा जिला बने।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि बाड़मेर में से बालोतरा जिला बनना चाहिए। बूंदी, धौलपुर वगैरह जैसे 5 जिले बनाए जा सकते हैं, बाड़मेर क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा है। मेरा निवेदन है कि वह जवाब तो सभी देते हैं और कई साल हो गए। अब गोलमोल जवाब नहीं। बालोतरा की जनता मांग करती है, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे?

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, समिति की रिपोर्ट आज दिनांक तक पूरी आई भी नहीं है। जब समिति की रिपोर्ट पूरी आएगी, उसके बाद ही जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत ही मेरा विभाग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं कुछ भी चाहूं, कुछ भी ना चाहूं, वह अलग है। नियमों, कायदे-कानून और प्रक्रिया से मैं एक मंत्री के तौर पर बंधा हुआ हूं। मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि समिति की रिपोर्ट जब आएगी तो गुणावगुण के आधार पर इसका निर्णय कर लिया जाएगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, 27 लाख की आबादी है और 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप धन्यवाद दो उन्होंने इतना कह दिया कि गुणावगुण के आधार पर करेंगे। धन्यवाद दो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बिलकुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा है बालोतरा इस सत्र में जिला बने।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

कोटा संभाग के पर्यटक स्थलों के विकास की कार्ययोजना

216. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत चार वर्षों में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय कर कौन-कौन से कार्य करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है? यदि हां, तो क्या?

(4) विगत पांच वर्षों में कोटा संभाग में कितने विदेशी पर्यटक पर्यटन हेतु आये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) कोटा संभाग के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार की क्या योजना है? विगत चार वर्षों में इन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) विगत चार वर्षों में प्रदेश में पर्यटन को बढावा देने के लिए कराए गए विकास कार्यों तथा उन पर किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में केन्द्र सरकार से पर्यटन स्थलों के विकास कार्य हेतु राशि रुपये 213.05 करोड़ (दो सौ तेरह करोड़ पांच लाख) प्राप्त हुए हैं। विवरण परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को निम्न प्रोजेक्टों की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेषित की गई है:-

1. वाइल्ड लाइफ टूरिज्म सर्किट
2. डैजर्ट सर्किट
3. ट्राइबल टूरिज्म सर्किट
4. ईको एडवेन्चर सर्किट

(4) जिलेवार प्राप्त सूचना के आधार पर गत पांच वर्षों में कोटा

(पर्यटन मंत्री)

संभाग में भ्रमण पर आए विदेशी पर्यटकों की वर्षवार संख्या विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**जिलेवार प्राप्त सूचना के आधार पर कोटा संभाग में आये विदेशी पर्यटकों की संख्या**
2014	18710 (अट्ठारह हजार सात सौ दस)
2015	17993 (सत्रह हजार नौ सौ तिरानवे)
2016	17359 (सत्रह हजार तीन सौ उनसठ)
2017	18514 (अट्ठारह हजार पांच सौ चौदह)
2018	18502 (अट्ठारह हजार पांच सौ दो)

(5) कोटा संभाग में विगत चार वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

विभाग में बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों हेतु युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन के माध्यम से प्रदेश आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित हों, इसके लिए वर्तमान बजट बहुत अपर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए, प्लीज।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही है। भविष्य में पर्यटन विकास के लिए सरकार ने क्या-क्या बहुआयामी योजनाएं बनाई हैं? इनके समुचित बजट प्रावधान के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार से 213.05 करोड़ रुपये की राशि पर्यटन विभाग को प्राप्त हुई है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से प्रसार एवं स्वदेश दर्शन योजना में अब तक कुल राशि रुपये 213.05 करोड़ प्राप्त हुई है जिसमें से अभी तक राशि रुपये 178.24 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, भविष्य की योजनाएं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, भविष्य में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नई पर्यटन नीति हम जल्दी से जल्दी तैयार कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जो नए सर्किट बनाए जा रहे हैं, उसमें रिलीजियस टूरिज्म भी होगा, एडवेंचर टूरिज्म भी होगा, पुरातत्व विभाग को भी हमने चिट्ठी लिखी है और हम मिक्स सर्किट बनाना चाहते हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ को भी इनक्लूड करेंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक राजस्थान में आकर्षित हो सके।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि हाड़ौती में प्रति वर्ष 18-19 हजार विदेशी पर्यटक और शैक्षणिक नगरी में पूरे देश से लोगों का आवागमन होता है। मैं जानना चाहता हूं कि कोटा में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए जैसे चम्बल नदी के किनारे गरडिया महादेव, चम्बल सफारी व चम्बल एडवेंचर, एजुकेशन टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म, बूंदी, बारां, झालावाड़ के पर्यटक स्थल और कोटा के प्राचीन धार्मिक स्थल कंसुआ धाम, भीतरिया कुण्ड, मथुराजी के कुण्ड का परिक्रमा मार्ग, गैपर नाथ मंदिर, उतपुरिया गांव में ईको टूरिज्म प्लेस...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): यही साहब, जामुनिया द्वीप, किशोर सागर तालाब...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इन सारे स्थानों को जोड़कर हाड़ौती में पर्यटन सर्किट बनाकर पर्यटन बजट स्वीकृत करने की सरकार कोई मंशा रखती है, विचार रखती है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा हाड़ौती में निजी निवेशकों द्वारा पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु राजस्थान टूरिज्म प्रोजेक्ट अनुमोदन गाइड लाइन, 2009 के प्रावधानों के तहत पर्यटन विभाग को प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु वर्ष 2018-19 में कुल 9 प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए जिसमें कुल राशि रुपये 49.85 करोड़ रुपये का निवेश तथा कुल 205 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार अवसर उपलब्ध होने की संभावना है।

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 15 जुलाई, 2019 तक कुल 3 प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें कुल राशि रुपये 10.6 करोड़ का निवेश तथा कुल 44 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में अनुमोदित प्रोजेक्ट का जिलावार विवरण चाहेंगे आप?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि हाड़ौती में पर्यटन सर्किट बनाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठ जाएं, रिकार्ड नहीं होगा। मंत्रीजी खड़े हैं और आप बोल रहे हैं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नीचे बैठें, प्लीज। बैठिए माननीय मंत्रीजी।

प्रश्न संख्या 217

अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर में चम्बल योजनान्तर्गत लाभान्वित ग्राम

218. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में चम्बल परियोजना से किन-किन ग्रामों को लाभान्वित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 चम्बल पेयजल परियोजना से किन-किन ग्रामों को जोड़ा जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति, कोटड़ी के अन्तर्गत चम्बल परियोजना से लाभान्वित किए जाने से शेष रहे गये ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चम्बल परियोजना से लाभान्वित किए जाने से शेष रह गए ग्रामों को उक्त परियोजना से जोड़े जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) चम्बल -भीलवाड़ा वृहद् पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण की दिनांक 30.05.2013 को राशि रुपये 1495.68 करोड़ की स्वीकृति के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के 8 कस्बे एवं वर्ष 2001 की जनगणनानुसार भीलवाड़ा जिले के 1688 ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य 8 पैकेजों के अन्तर्गत किया जाना प्रावधित है। इनमें से 4 पैकेज (1, 2, 5 एवं 6) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष 4 पैकेज का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में तहसील जहाजपुर के 217 एवं तहसील कोटड़ी के 102, इस प्रकार कुल 319 ग्रामों में से तहसील कोटड़ी के पैकेज संख्या-6 में सम्मिलित 99 ग्रामों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में लाभान्वित किया जा चुका है। पैकेज संख्या 7 एवं 8 में जहाजपुर क्षेत्र के सम्मिलित 220 ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।

उक्त लाभान्वित किये गये 99 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्तानुसार विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के शेष रहे 220 ग्रामों में से पैकेज संख्या-7 के अन्तर्गत 191 ग्रामों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में चरणबद्ध रूप से लाभान्वित करना प्रस्तावित है। इन 191 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील जहाजपुर के 29 ग्रामों को पैकेज संख्या 8 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2020 तक चरणबद्ध रूप से लाभान्वित करना निर्धारित है। इन 29 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) चम्बल-भीलवाड़ा वृहत् पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण में पंचायत समिति, कोटड़ी के वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 174 ग्राम (विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर एवं माण्डलगढ़ के क्रमश: 102 एवं 72 ग्राम) सम्मिलित किए जाकर 152 ग्राम (विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर एवं माण्डलगढ़ के क्रमश: 99 एवं 53 ग्राम) अब तक लाभान्वित किए गए हैं तथा शेष 22 ग्रामों (विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर एवं माण्डलगढ़ के क्रमश: 3 एवं 19 ग्राम) को पैकेज संख्या 7 के अंतर्गत लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार पंचायत समिति, कोटड़ी के ग्रामों की

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

संख्या बढ़कर 180 हो गई है। इस प्रकार 6 ग्राम (विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर एवं माण्डलगढ़ के क्रमश: 04 एवं 02 ग्राम) नवसृजित होने के कारण उक्त पेयजल परियोजना में स्वीकृत नहीं हैं। ग्रामों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) जी हां। वर्ष 2001 की जनगणना के उपरांत विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के नवसृजित 17 राजस्व ग्रामों सहित भीलवाड़ा जिले के कुल 199 नये राजस्व ग्राम तथा 1337 ढाणियों की जल मांग परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्व से ही सम्मिलित है, परन्तु इन्हें क्लस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करने का कार्य स्वीकृत नहीं है।

उक्त ग्राम एवं ढाणियों को तृतीय चरण के अन्तर्गत क्लस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करने के लिये सर्वे एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने के कार्य की विभागीय वित्त समिति की 745वीं बैठक दिनांक 16 से 18.06.2018 द्वारा राशि रुपये 140.72 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

सर्वे एवं डीपीआर तैयार करने के कार्य की वित्त विभाग से वित्तीय सहमति लेने हेतु प्रकरण पर कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। वित्तीय सहमति उपरांत तृतीय चरण की प्रस्तावित परियोजना की डीपीआर तैयार कराने की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि नासरजीत गांव को जोड़ने, योजना से कब तक लाभान्वित करने की मंशा सरकार रखती है? जैसे गांव- शिवनगर, भगवानपुरा, बागड़ा, माताजी खेड़ा, रामनगर।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि तृतीय चरण के कार्य की डीपीआर रुपये 140.72 लाख की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं सर्वे एवं डीपीआर तैयार करने के लिये कार्य की वित्त विभाग से वित्तीय सहमति आने पर इस पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मेरे दो प्रश्न हैं। जनसंख्या को जब आधार मानकर पानी की व्यवस्था करते हैं तब नये विलेज के आधार पर

(श्री अध्यक्ष)

कनेक्शन जोड़ने के लिये क्यों स्वीकृति मांगी जाती है? विभाग में जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उस इलाके की जितनी पापुलेशन है, उस पापुलेशन को आधार मानकर स्कीम बनती है। पूरे रेवेन्यू विलेज में जितनी पापुलेशन है, उसे पानी से नहीं जोड़ा जाता है। नम्बर एक। उस पापुलेशन से नया गांव बन गया तो नये गांव की पापुलेशन तो इसमें इन्क्लूड थी, फिर नये रेवेन्यू विलेज के नाम पर जोड़ने के लिये हम अलग प्रस्ताव क्यों लाते हैं? यह विभाग की क्या नीति है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह योजना बनी थी, उस समय 2001 की जनगणना को आधार माना था, फिर उसके बाद में 2011 की जनगणना आ गयी तो उसे आधार मानकर थर्ड फेज हमने बनाया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न यह नहीं है। मैं दोबारा अपना प्रश्न कहता हूं। मैं दो प्रोजेक्ट से संबंधित कह रहा हूं- एक बाघेरी का नाका और एक भीलवाड़ा का। प्रोजेक्ट जब बनता है तो उस इलाके की पंचायत समिति की पूरी पापुलेशन को जोड़ा जाता है तो उसे आधार बनाकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। उस रेवेन्यू विलेज जिसकी पापुलेशन है, उसकी वन थर्ड पापुलेशन को पानी मिलता है, टू थर्ड पापुलेशन जो हैमलेट में रहती है, उसे पानी से नहीं जोड़ा जाता है और हम कह देते हैं प्रोजेक्ट कमप्लीट हो गया। उसी जगह पर जब नया रेवेन्यू विलेज बन जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि रेवेन्यू विलेज नया बन गया, इसलिये नयी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। विभाग की जो नीति है, उसमें यह बड़ी खामी है। जब आप योजना बना रहे हैं तो पूरी पापुलेशन को लेते हैं और रेवेन्यू विलेज को जब आप लेते हैं तो रेवेन्यू विलेज की जो पंचायत मुख्यालय के जो हैमलेट हैं, उन्हें पानी से नहीं जोड़ा जाता है, जबकि आप स्कीम लेने में पापुलेशन को जोड़ते हैं। विभाग को कम से कम यह डाइरेक्शन दें कि यदि पापुलेशन को आधार माना है तो उस पंचायत की बसावट है, उन सारे हैमलेट को पानी से जोड़ा जाना चाहिए। प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो पापुलेशन लेते हैं और बैनिफिट देने में हम हैमलेट्स को डिप्राइव करते हैं। नया विलेज बनता है, उसके नाम से नये कनेक्शन लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि विभाग को इस संबंध में नीति में दोबारा सोचना चाहिए। वित्तीय प्रावधानों का दुरुपयोग होता है, लोगों को बैनिफिट नहीं मिलता है।

(श्री अध्यक्ष)

जो बाघेरी प्रोजेक्ट बनाया गया, मैं भी दस साल बाद गया। बाघेरी प्रोजेक्ट में रेवेन्यू विलेज की टू थर्ड हैमलेट को पानी का बैनिफिट नहीं है और आपकी पापुलेशन में है बाघेरी प्रोजेक्ट में कि हमने इतने आदमियों को पानी का बैनिफिट दे दिया। यही की यही स्थिति भीलवाड़ा में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर यदि प्रोजेक्ट में पूरी पापुलेशन को आधार माना है तो पूरी पापुलेशन की जो बसावट है, जो हैमलेट्स हैं, जिनमें खासतौर से एससी/एसटी के लोग जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं, पंचायत मुख्यालयों से उन्हें पानी से जोड़ना उस प्रोजेक्ट का पार्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जो सुझाव दिये हैं, उन्हें हम क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा से बगदून्दा सड़क को टू-लेन करने की योजना

219. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में गोगुन्दा उप खण्ड में गोगुन्दा से बगदून्दा तक सड़क की क्या स्थिति है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क को टू-लेन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) गोगुन्दा से बगदून्दा सड़क की लम्बाई 8 किमी है एवं वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। इस सड़क को एसआरएफ (एमडीआर) योजना में दिनांक 11.09.2018 को नवीनीकरण हेतु स्वीकृत कर कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। स्वीकृति/कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़क पर यातायात के भार को दृष्टिगत रखते हुए इस सड़क को टू-लेन करने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी से मेरा यही निवेदन है कि कार्य 11.09.2018 को स्वीकृत

(श्री प्रताप लाल भील (गमेती))

हुआ। उसका टैंडर वापस 05.10.2018 को खुल गया और वर्क आर्डर भी 15.10.2018 को जारी कर दिया गया और उस सड़क को पूर्ण करने की तारीख भी 14.04.2019 तय की गयी। वर्तमान में एक भी तगारी उस रोड पर नहीं पड़ी और दो-दो फीट के वहां खड्डे पड़ गये, आये दिन वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस स्वीकृत कार्य को आप कब चालू करेंगे?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि इसका वर्क आर्डर पहले जारी किया गया था पिछले वर्ष कुछ महीने पहले और अब उसकी समय-सीमा भी निकल गयी है, लेकिन हकीकत यह है और अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि कड़वी बात भी आपको सुननी चाहिए कि चुनाव से पूर्व इस प्रकार के वर्क आर्डर दिये गये थे जो हजारों करोड़ ज्यादा थे अपने बजट प्रावधान से।

मैं आरोप-प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष आज मौजूद नहीं है। लेकिन यह बात सच है कि चुनाव की पूर्व संध्या पर बहुत से ऐसे काम स्वीकृत किये गये थे, विभाग और मैं पूरी तरह चिंतित हैं और माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके विधान सभा क्षेत्र में 1312 किलोमीटर की टोटल सड़क है, उसमें से 380 किलोमीटर हम चिह्नित कर चुके हैं जिसे हमें रिपेयर और री-कारपेट करनी है। 128 करोड़ का बजट है, जिसमें से 62 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं और 157 कामों में से 109 काम पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन यह जो 8 किलोमीटर की सड़क है, सदन की सहमति से जैसे ही बजट पास होगा, हम इसे प्राथमिकता के आधार पर लेकर काम जल्दी शुरू करवाकर खतम करवाएंगे।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): मेरा निवेदन यह था कि गोगुन्दा से जो झाड़ोल उपखण्ड है, उसे जोड़ने का जो मेन रोड है, उस पर मार्बल के भी बड़े-बड़े वाहन चलते हैं, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसे आप अतिशीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करें।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि हम जो काम स्वीकृत हो चुके हैं, पहले उन्हें प्राथमिकता पर लेंगे, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जनता वही है। जो काम स्वीकृत हो चुके हैं, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पहले उन्हें पूर्ण कराएं, उसके बाद जो भी माननीय सदस्य के सुझाव होंगे, अकोर्डिंगली काम कराएंगे।

प्रश्न संख्या 220

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री रामलाल जाट।

भीलवाड़ा जिले के भामाशाह खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थी

221. श्री रामलाल जाट (माण्डल): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में गरीबों की कल्याणकारी योजना भामाशाह खाद्य सुरक्षा योजना में नये सिरे से गरीब जनता को जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को उक्त योजना से जोड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भामाशाह खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को मिलने वाला एक रु. प्रति किलो गेहूं प्राप्त आवेदनों में से कितने स्वीकृत हो चुके हैं एवं कितने किन कारणों से शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 की पालना में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की मांग करने वाले नागरिकों को अपीलीय प्रक्रिया द्वारा उक्त योजना में पात्र लोगों का नाम जोड़ा जाता है। भीलवाड़ा जिले में अब तक कुल 1634430 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 1 मार्च, 2019 से बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को 1 रु. प्रति किलो के हिसाब से गेहूं वितरण की व्यवस्था की गई है। उक्त योजना में भीलवाड़ा जिले में बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय अन्न योजना के प्राप्त, स्वीकृत एवं शेष रहे आवेदन पत्रों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया, बनेड़ा उपखण्ड में 69 परसेंट लक्ष्य प्राप्त हो जाने के कारण उसमें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बाकी उपखण्ड में कितने-कितने परसेंट लोग खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिये गये हैं नम्बर एक? दूसरा, जो नहीं जोड़ पाये हैं, उन लोगों को जोड़ने की मंशा मंत्री महोदय रखते हैं या नहीं?

(श्री रामलाल जाट)

मेरा दूसरा प्रश्न है कि पंचायत समिति में पिछली बार सरकार ने कैंप लगाए, उनमें हजारों की संख्या में, मैं पर्टीकूलर मांडल विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूं तो कम से कम 9 हजार फार्म अभी भी पंचायत समितियों में पड़े हैं। इन्होंने जो सूची मुझे दी, उसमें स्वीकृत आवेदन, अस्वीकृत आवेदन की संख्या निल दी है केवल बनेड़ा तहसील के उपखण्ड के अलावा। बाकी पंचायत समितियों में फार्म पहले के भरे हुए पड़े हैं। सारी प्रक्रियाएं जब मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि हाकम चला जाता है, हुक्म नहीं जाता है। पिछली सरकार चली गयी, लेकिन सर्वे होकर पात्र व्यक्तियों के फार्म पड़े हैं, उनका कब तक निपटारा कर देंगे?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो लम्बित प्रकरण हैं, उनके बारे में बताया है तो इसमें जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, निस्तारण हुआ है और जो अपात्र घोषित हुए हैं, उनकी संख्या आपको बता दी गयी है। इसमें जानकारी आपको भी है, आप माननीय सदस्य पुराने हैं, क्योंकि रूरल एरिया में 69.09 प्रतिशत और अरबन एरिया में 53 प्रतिशत एक सीमा निर्धारित की गयी है। उसके बावजूद भी हमने रूरल एरिया में करीब 79 प्रतिशत तक लोगों को पहुंचा दिया है और जो पात्र व्यक्ति हैं और समावेशन के जो आधारभूत दस्तावेज हैं, जो पात्रता रखते हैं, उनका शीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा और पर्सनली आप बनेड़ा, मांडल, जो भी आप बताएंगे कि यहां पर ये लोग रूके हुए हैं क्योंकि उपखण्ड अधिकारी है, हमारा जो डी.एस.ओ. है, यह उनको जोड़ता है तो यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है या अवहेलना कर रहा है, लापरवाही है तो उन्हें दिखवा लेते हैं और उसके बाद शीघ्र ही आने वाले दिनों में राजस्थान में शिविर लगाकर जो लोग जुड़ने से वंचित रह रहे हैं उनको जोड़ा जाएगा।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से सोजत शहर में सीवरेज लाइन के अभाव में सड़कों पर गंदे पानी के आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में बढ़ रही हत्या एवं आत्महत्या की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के किसानों की 2017 में शीतलहर से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में व्याप्त पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के संबंध में।

(5) श्री बाबुलाल (झाड़ोल), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की चारागाह भूमि पर वर्षों पूर्व बने मकानों की भूमि का किस्म परिवर्तन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज का दूषित जल सप्लाई होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से लूणकरणसर व नापासर ग्राम पंचायतों को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में।

(8) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की ग्राम पंचायत बजरांगसर की सरपंच श्रीमती प्रियंका सिहाग द्वारा पिछले 06 दिनों से उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की मांग को लेकर भूख हड़ताल करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से प्रदेश में अनधिकृत रूप से संचालित हुक्का बारों से युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में मन्दिर के पास तथा एस.सी. एवं एस.टी. मौहल्ले में अवैध शराब की बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में टिड्डियों द्वारा फसलें चौपट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में मध्यप्रदेश की तरह 09 अगस्त को राजकीय अवकाश घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से जावर माइन्स उदयपुर से निकलने वाले अपशिष्ट केमिकल के कारण जन हानि होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सन् 1984 से प्रस्तावित योजना में हाउसिंग बोर्ड का स्वामित्व होने के बावजूद कब्जा नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री रामप्रसाद, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले की तहसील बिछीवाड़ा के ग्राम मौजा मालमथा और अन्य गांवों के 86 काश्तकारों की भूमि वन विभाग से वापस राजस्व विभाग में हस्तान्तरित करने के संबंध में।

(16) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में चरागाह एवं आबादी भूमि विनियमन न होने से आमजन को होने वाली कठिनाइयों के संबंध में।

(17) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से नगरपालिका क्षेत्र भादरा में बरसात के पानी की निकासी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में बांग्लादेशी परिवारों का अवैध रूप से कालोनियां बसाकर अपराधों में लिप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(19) श्री छगनसिंह एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में आर.ए.एस. की मुख्य परीक्षा प्रणाली में रही खामियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(20) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से रायसिंहनगर एवं गंगानगर जिले में पंजाब के हरिके बैराज के पीछे से आ रहे अनेक नालों से फैक्ट्रियों के कैमिकल युक्त पानी की रोकथाम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(21) श्री वाजिब अली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के ग्राम गुलपाड़ा में 10 जुलाई, 2019 को 11 हजार केवी के तार टूटकर बस पर गिरने से हुई तीन लोगों की मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(22) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा खाद्य परिवहन कार्य बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री छगनसिंह, श्री बलवीर सिंह लूथरा, श्री वाजिब अली एवं श्री खुशवीरसिंह को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में व्याप्त हड्डा रोडी की समस्या का स्थाई निराकरण किये जाने के संबंध में।

(2) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर को स्थाई मान्यता नहीं होने से विद्यार्थियों के प्रवेश में हो रही कठिनाइयों के संबंध में।

(3) श्री विजयपाल मिर्धा, सदस्य की ओर से प्रदेश में अवैध बजरी खनन की रोकथाम हेतु पुख्ता व स्थायी समाधान किये जाने के संबंध में।

(4) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के द्वारा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के मामले में छात्रों के साथ हुई धोखाधड़ी के संबंध में।

(5) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(6) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर में खेल विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(7) श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बौंली में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(9) श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में गैर मुमकिन भूमि पर बसी कालोनियों को आबादी भूमि में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

(10) श्री अमीनुद्दीन कागजी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनपोल स्थित दरबार स्कूल की जमीन पर हाई स्कूल व बालिका महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(11) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से भादरा व नोहर में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था व खाला का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूदड़ी के खेल मैदान व श्मशान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाये जाने के संबंध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उपरोक्त सारे प्रस्ताव सदन में पढ़े हुए माने जाएंगे।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 18 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 31 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	**नाम सदस्य**	**विषय**
1.	श्री पब्बाराम	फलौदी क्षेत्र में वर्षा नहीं होने से अकाल की स्थिति के कारण पशु चारा डिपो व पशु शिविर खोलने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

क्र. सं.	**नाम सदस्य**	**विषय**
2.	श्री अभिनेश महर्षि	नोहर तहसील के जसारा गांव के निवासी पवन व्यास की हत्या करने वाले अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3.	श्री अमृतलाल मीणा	जयसमन्द झील की परिधि में बसे 93 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री बलजीत यादव	किसानों को दिये गये ऋण में हुई अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव पर, श्री छगनसिंह। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि चिकित्सा जैसी प्रमुख मांग पर चर्चा करनी है इसलिए कृपया अपनी बात को 2-2 मिनट में ही समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): बुलाओ तो सही।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें आप। आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, बैठो आप। आ गये न वे, आपके कहते ही आ गये। माननीय छगनसिंह। माननीय सदस्य, आप हल्ला करने के लिए आए तो नहीं। माननीय सदस्य को पुकार लिया गया है। माननीय सदस्य श्री छगनसिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम भी इस सदन के सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं, नहीं बोलना है तो आप बाहर ही रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से न तो अन्दर आए हैं और न बाहर जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: आप मेरे कहने से बैठ जाइए। यह हाउस मेरे कहने से चलेगा, आपके कहने से नहीं चलेगा। हाउस मेरे कहने से चलेगा। हाउस मेरे कहने से चलेगा, आपके कहने से नहीं चलेगा। आपके कहने से नहीं चलेगा हाउस।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, नहीं, एतराज तो यही है न, राजस्थान के अवाम ने चुनकर भेजा है।

श्री अध्यक्ष: आपके कहने से नहीं चलेगा हाउस। आप आएं या नहीं आएं, हाउस चलेगा। आपके कहने से नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आउट करो न आप। आप मार्शल को कहकर करो न बाहर। (व्यवधान) बाहर निकालो न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये प्लीज। प्लीज बैठें। छगनसिंह जी, बोलो आप। बैठें प्लीज। आपके कहने से नहीं चलेगा। अध्यक्ष को दबाव में नहीं ले सकते हैं। माननीय सदस्य छगनसिंह जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आर.ए.एस. की मुख्य परीक्षा प्रणाली में खामियां

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.पी.एस.सी. द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा होती है उसमें तीन स्टेप में परीक्षा होती है, आरएएस प्री, आरएएस मेन्स और इंटरव्यू। आरएएस प्री में आब्जैक्टिव होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं। फिर मेन्स में लिखित में परीक्षा होती है जिसमें खामियां हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, अपने स्थान पर। ऐसे नहीं।

श्री छगनसिंह (आहोर): अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में एक ही प्रकार से उत्तर देने के बाद भी नम्बर अलग-अलग मिलते हैं क्योंकि परीक्षार्थी लिखता तो सही है लेकिन जो वीक्षक, जांचकर्ता है, वे अलग-अलग होते हैं जिससे नम्बर देने में कमी होती है। जो नम्बर दिए जाते हैं, जिसने सही लिखा है, दोनों सही लिखते हैं लेकिन जांच अधिकारी अलग-अलग होते हैं तो दोनों के नम्बर अलग-अलग आ जाते हैं जिससे हमेशा संदेह रहता है। मैंने इतना अच्छा उत्तर लिखा था, फिर उसमें कम नम्बर आ जाते हैं। फिर, लिखित परीक्षा में समय भी बहुत ज्यादा है, 4 से 5 वर्ष तक समय लगता है। 4 से 5 वर्ष तक समय लगने से जो परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वे इतने सक्षम नहीं होते हैं कि 4-5 साल तक एक ही परीक्षा का इंतजार करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया जिनको बात करनी है, सदन से बाहर, प्लीज।

श्री छगनसिंह (आहोर): इसमें खर्चा भी बहुत आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को अवगत कराऊंगा कि लिखित परीक्षा में भी आब्जैक्टिव परीक्षा ली जाए तो इसमें विश्वसनीयता भी आएगी, जिससे परीक्षार्थी को भी विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो लिखा और विश्वसनीयता भी बनी रहेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवीर सिंह लूथरा, श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): हां जी, साहब।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव, माननीय सदस्य, रायसिंहनगर गंगानगर जिले में हरिके बैराज से आने वाले...

इन्दिरा गांधी नहर में पंजाब से केमिकलयुक्त पानी का प्रवाह

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): हां जी, हां जी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पंजाब क्षेत्र में लगातार कारखानों, फैक्ट्रियों का केमिकलयुक्त पानी डाला जा रहा है। इसके कारण राजस्थान में फसलों के साथ-साथ मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बीकानेर संभाग में प्रतिदिन कैंसर रोग के मरीज बढ़ रहे हैं। क्या सरकार स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप स्थगन प्रस्ताव पर तैयार ही नहीं हैं, क्या बोले प्लीज।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): इस प्रकार फैक्ट्रियों, कारखानों का केमिकलयुक्त गंदा पानी नाला में डाला जाता है, क्या सरकार द्वारा इस गंदे पानी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? यदि नहीं, तो सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे अन्यथा भविष्य में गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलें-बोलें, आप ठीक बोले।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): उक्त परियोजना में केमिकलयुक्त पानी डालने से रोकने के लिए पंजाब सरकार के साथ क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां तो, क्या व नहीं तो क्यों? मंत्री जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: श्री वाजिब अली, श्री वाजिब अली। श्री खुशवीरसिंह।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा खाद्य परिवहन कार्य बन्द करना

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत सोच समझकर जब देश आजाद हुआ, उस वक्त हमारे प्रधान मंत्रीजी ने एक सपना संजोया था और उन्होंने एक नारा दिया था, 'सबका साथ, सबका विकास' और उसी के तहत जय सहकार का नारा गुंजायमान हुआ और हमारी सहकारी व्यवस्था इतनी मजबूत हुई है।

(श्री खुशवीरसिंह)

आज भी ये सहकारिता मूवमेंट जो है, वह इतना सफल हुआ आज भी अमूल, सरस, इफ्को, कृभको, ये सभी इसके माध्यम से चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिलो में राशन वितरण की जो व्यवस्था थी, वह ग्राम सेवा सहकारी समिति और केवीएसएस द्वारा व्यवस्था की जा रही थी लेकिन, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले वर्ष इन्होंने यह व्यवस्था, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा यह व्यवस्था निगम द्वारा करवा ली गई और निगम ने जो व्यवस्था की है, उन्होंने एक प्राइवेट ठेकेदार को कांट्रेक्ट दे दिया और हमारी क्रय-विक्रय सहकारी समिति जो कर रही थी, वह काम उसकी जगह निगम ने किया और निगम ने वितरण व्यवस्था ज्यों ही शुरू की, यह अख़बार की खबर भी है, मैं बताना चाहूंगा, "निर्धनों के गेहूं पर डाका, वज़न करवाया तो कम निकली मात्रा" ये सभी चोरी की गई और वहां जो सप्लाई हुई है, उसमें से माल गायब था। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध इतना ही है कि आपने निगम के माध्यम से करवाया, निगम का गठन कब हुआ और क्या जरूरत थी उस निगम की...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, निगम का जो गठन हुआ और निगम ने जो कृत्य किया है, वह आपको मैं बताना चाहूंगा। निगम ने हाल ही 2016-17 में 50 हजार मैट्रिक टन चीनी खरीद ली और उस वक्त बाजार कीमत थी 34-35 रुपये किलो और निगम ने खरीद लिया...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज डिबेट करनी है, प्लीज वाइंड-अप। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): हां, मैं वाइंड-अप कर रहा हूं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आज ही आदेश करें, मंत्री महोदय केवीएसएस द्वारा ही यह व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात... **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

श्री अध्यक्ष: बस धन्यवाद, समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। प्लीज समाप्त हो गया।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): 10 सैकण्ड, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज बैठें आप। प्लीज अंकित नहीं होगा।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम। प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा। पब्बाराम जी।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप विराजें। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम जी। समाप्त करें, माननीय सदस्य। नहीं सुना क्या आपने, मैं आपको अलाउ ही नहीं करूंगा अब, यदि नियम का पालन नहीं करेंगे तो। मुझे क्षमा करें। श्री पब्बाराम जी, पर्ची पर।

पर्ची के माध्यम से उठाए गये मुद्दे

फलौदी क्षेत्र में चारा डिपो व पशु शिविरों की व्यवस्था

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी क्षेत्र हमेशा से ही मौसम की मार से पीड़ित रहा है। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर माइनस जीरो डिग्री तापमान वहां पर रहता है और गर्मियों में 52 डिग्री तक तापमान जाता है। यही कारण है कि हमारे यहां पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र भी भरला में लगा हुआ है जो एशिया का सबसे बड़ा है। परन्तु इन सबका हमें लाभ न मिलकर, हमारे वहां वर्षा के मौसम में भी माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में जो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, वह बीकानेर है और बीकानेर से हमारी सीमा बाप की लगती है। पिछले वर्षों का हमारी वर्षा का औसत निकालें तो बीकानेर और हम बराबर हैं।

माननीय महोदय, अकाल की स्थिति है, आज 18 तारीख हो गई है, कोई एक छांट बरसात की वहां नहीं गिरी और स्थिति यह है कि पिछले 10-15 दिनों से लगातार आंधीबाजी है और आंधी चलने के कारण वहां पर सड़कों पर आ गया गर्द। वहां पर लोगों ने पशुओं को छोड़ दिया है। विशेषकर गायें जो दुधारू हैं, उनको तो आम लोग अपने घर पर जैसे-तैसे ही गुजारा करते हैं, परन्तु जो बाखड़ जिसको बोलते हैं, जो दुधारू नहीं है, उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा बाप क्षेत्र, नोखा से लगता हुआ है। नोखा जो है जैसलमेर में है और सावरा गांव हमारे फलौदी में है। 4 किलोमीटर की दूरी में है। नोखा में तो पशु शिविर चल रहे हैं और सावरा गांव के पशु भटक रहे हैं। इसी प्रकार से नेवा में पशु भटक रहे हैं और चिन्नू जो

(श्री पब्बाराम)

सात किलोमीटर दूर है, जैसलमेर में वहां पशु शिविर और चारा डिपो चल रहा है। मैं माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री से निवेदन करूंगा, हमारे वहां पर एक बट्टा चार क्षेत्र सिंचित है। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)** तीन बट्टा चार वर्षा के ऊपर निर्भर करता है और आज 18 तारीख हो गई है, पशु दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहां पर अगर चारा डिपो खोल दिए जाएं और पशु शिविर लगा दिये जाएं..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मैं सिर्फ एक तहसील की बात करूं, सिर्फ एक तहसील बाप में ये कर दिए जाएं तो बड़ी कृपा होगी। पिछले दिनों में गोमाता....तो कृपया आपदा प्रबंधन मंत्री मेरा आग्रह है कि मेरे यहां पर कैटल कैम्प और पशु शिविर लगाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य समाप्त करें। श्री अभिनेश महर्षि। आज डिबेट करानी है।

नोहर तहसील के जसारा गांव में हत्या के अपराधियों पर कार्यवाही

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पर्ची के माध्यम से एक ऐसे जघन्य हत्याकाण्ड के बारे में बातचीत करने का मौका मिला है। 17 अक्टूबर, 2017 नोहर तहसील का जसारा गांव, बूढ़े और बेसहारा बाप का बेटा पवन व्यास, जिसकी पंचायत समिति के अंदर जो ई-मित्र है उसमें धारदार हथियार से गला रेंतकर उसकी हत्या कर दी गई। पौने दो साल तक बूढ़ा बाप न्याय की गुहार करते-करते ऐसा कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, जहां पर वह न्याय की उम्मीद करता था और वहां पर नहीं गया हो, 131 दिन तक वह धरना लगाकर के न्याय की गुहार करता रहा लेकिन उसके बाद भी उसको पौने दो साल तक भी न्याय नहीं मिला। इस हत्याकांड के विरोध में नोहर कस्बा भी बंद रहा माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद चुनावों में मतदान का बहिष्कार करके भी उन्होंने अपने विरोध को जताया, लेकिन किसी तरह का कोई न्याय आज दिन तक नहीं मिला है। परिवार के अन्दर इकलौता कमाने वाला पवन व्यास था। दो छोटे-छोटे बच्चे, विधवा बहन।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप करें। काम की बात बोलें। घटना हो गयी, क्या चाहते हो वह बोलें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि सरदारशहर के अन्दर जो कस्टोडियल डैथ हुई है उसके अन्दर जो सीआई अभी-अभी जिसको सस्पैंड किया गया है तत्कालीन वो वहां पर...

श्री अध्यक्ष: प्लीज किसी का नाम नहीं लें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): नाम लेकर नहीं, वहां पर सीआई था। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ही और वो ही एसपी जो रतनगढ़ में कस्टोडियल डैथ हुई उस समय एसपी था। ऐसी स्थिति में न्याय की गुहार लगाने के लिए अस्सी साल का बूढ़ा बाप वहां से पैदल चलकर जयपुर में आ रहा है। मेरी मांग है कि उस परिवार को न्याय मिले और माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब नोहर गये थे...

श्री अध्यक्ष: विराजिए। प्लीज।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं तो उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि सीबीआई से जांच कराएंगे यदि हमारी सरकार आएगी तो। माननीय मुख्य मंत्री महोदय बहुत संवेदनशील हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं कि उनको न्याय दिलाने की कृपा करें और सीबीआई से जांच करवाएं। एसपी का नार्को टैस्ट करवाएं। सबूतों को मिटाने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह वाजिब मांग उठायी है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। हो गया।

श्री अमित चाचाण (नोहर): लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। तत्कालीन सरकार की उदासीनता की वजह से तेरह महीने तक उन्होंने ...(व्यवधान) इंक्वायरी सही नहीं की।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): अब तो सरकार आ गई। मुख्य मंत्री जी ने कहा था। सरकार आ गई अब तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। यों आपस में क्या कर रहे हैं यहां? श्री अमृतलाल जी मीणा।

जयसमन्द झील की परिधि में बसे 3 गांवों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माही के व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोक कर जाखम के माध्यम से जयसमन्द में डाल करके सराड़ा, सलूम्बर, लसाड़िया, वल्लभनगर, कुराबड़ और भीण्डर होते हुए इनके पीने के पानी की व्यवस्था की जाए।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जयसमन्द की परिधि में 72 गांव सलूम्बर के और 21 गांव लसाड़िया के हैं। ये बिलकुल झील किनारे हैं उनको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए।

तीसरी बात, सलूम्बर में नगरपालिका क्षेत्र में पांच करोड़ पचास लाख की राज्य सरकार के पास योजना विचाराधीन है। चार उसमें जलाशय हैं और पानी की पाइपलाइन है और देवेन्द्र एनीकट के पानी से सराड़ा के 27 गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। सोमकमला में ऐसे 14 गांव जो उस एरिया में बिलकुल झील के किनारे हैं उनके भी पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

एक निवदेन और है कि पानी से संबंधित समयावधि प्रकरण 10-15 साल से जो सरकार के पास विचाराधीन हैं वो सर्किल लेवल पर दिये जाएं ताकि इनका निस्तारण जल्दी हो सके।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बलजीत यादव।

किसानों को दिये गये ऋणों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में पिछले काल में सबसे पहले यह मांग उठायी थी कि कोआपरेटिव बैंकों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा पूरे राजस्थान में करोड़ों रुपयों की लूट हो गयी है। ऋण माफी में घोटाला हुआ है। सरकार ने जांच के आदेश दिये। मेरे बहरोड़ में जांच हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में बताना चाह रहा हूं कि आप हैरान रह जाएंगे कि इन भ्रष्टाचारियों के कितने मजबूत गठजोड़ हैं और सरकार इनके सामने घुटने टेक चुकी है। पहले वाली भी और आज मुझे कहने में गुरेज नहीं है, दुःखी मन से कह रहा हूं। वर्तमान सरकार से भी आज मैं निराश होकर कह रहा हूं कि दो हजार लोगों के फर्जी खाते खुलते हैं और उनके नाम से पोर्टल पर लिस्ट डल जाती है और यह कह

(श्री बलजीत यादव)

दिया जाता है कि आपके नाम से इतना ऋण माफ हो चुका है और फिर जांच होती है कोई +++ मैनेजर बहरोड़ में कोआपरेटिव बैंक में जांच करते हैं और वे क्या कहते हैं, लिखित में लेते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति के सचिव दे देते हैं और मात्र पांच सोसायटियां हैं कि साहब ये नाम हमने नहीं दिये, अपने आप बैंकों ने चढ़ा दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले लिस्ट देती है सोसायटी कि इन-इन नाम के लोगों के खाते खोलो, फिर उनके नाम से ऋण माफ होता है। वो लिस्ट गायब हो गयी माननीय अध्यक्ष महोदय, और गायब होने के बाद में क्लीन चिट दे दी, उन बैंक वालों को भी क्लीन चिट दे दी और सहकारी समिति के सचिव को भी। फिर उनको सस्पैंड किया। सस्पैंड करके वापस उनको बहाल कर दिया और जो +++ हैं उनको वापस बहरोड़ में ही उसी बैंक में मैनेजर लगा दिया और जो एमडी थे जो मिले हुए थे इस घोटाले में जो कम से कम दस करोड़ का घोटाला है। यह तो आन रिकार्ड है। सरकार को बताना चाहता हूं। धारीवाल जी, आप बैठे हैं आप बताना मुख्य मंत्री जी को। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सर, थोड़ा सा। सर, यह बहुत सीरियस सिचुएशन है। आगे मेरा समय कभी भी काट लेना। आप मुख्य मंत्री जी से कहना, सरकार इसीलिए बदल जाती है कि जनता के साथ न्याय नहीं होता है। सिर्फ थोथी बातें होती हैं कोई न्याय नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं। आप चैक करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सर, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गुस्सा नहीं करें। शांत रहें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): एक मिनट मुद्दे की बात। आप सर, चैक करवाइये। मैं बहरोड़ की बता रहा हूं। आप तो बहुत इंटेलीजेंट हैं। कोआपरेटिव बैंक में दो हजार, एक-दो नहीं दो हजार लोगों की पोर्टल पर लिस्ट ग्राम सेवा सहकारी समिति पहाड़ी, कांकरा मोहम्मदपुर, गूंती, हमीदपुर, जैनपुरवास, केवल इनके सचिव ने दो हजार लोगों के नाम की आपके वहां लिस्ट दे दी, उनका लोन भी आपने माफ कर दिया जो पिछला वाला था और यह हो गया कि ये लोन उठा लेंगे वह तो पैसा आया नहीं था, नहीं तो वह उठ जाता एक जगह से दस करोड़ और उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई थाने में उसमें एफआर लगवा दी क्योंकि रिपोर्ट आपके मैनेजर ने दे दी +++ कि यह कोई घपला नहीं

(श्री बलजीत यादव)

हुआ था चूंकि पैसा गया नहीं है। गया तो नहीं लेकिन चला जाता न। गया तो नहीं लेकिन यह चला नहीं जाता क्या? तो पूरे राजस्थान में कितनी बड़ी लूट हो रही है, लोन मिल नहीं रहा है, पैसा नहीं है सरकार के पास, क्योंकि पैसा लुटेरे लूट ले जाते हैं। सरकार में लूट ले जाते हैं और आप रोक नहीं पाते हो और उसको ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। हो गया।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। हो गया। 131, श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, खाली 131 पर बोलिये।

श्री अमीन खां (शिव): मैं इंदिरा गांधी नहर का...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। माननीय सदस्य, 131 में जो लिखा है टॉपिक, वह बोल दें बस। देट्स आल।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

इन्दिरा गांधी नहर योजना के काम का गडरा रोड तक विस्तार

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी नहर का दूसरा चरण रामदेव बाबा की ब्रांच आरडी नंबर 302 पर नहर का काम बंद क्यों किया गया इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सिंचित क्षेत्र शुरूआती दौर में जल उपलब्धता के आधार पर 19 लाख 63 हजार हैक्टेयर सोचा गया था परन्तु पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य के हिस्से का पानी न देने के कारण 2005 में राज्य सरकार ने सिंचित क्षेत्र 16 लाख 17 हजार हैक्टेयर सीमित कर दिया। पंजाब से 0.6 एमएएफ शेष पानी का हिस्सा लेने के लिए निरन्तर पंजाब सरकार से और भारत सरकार से प्रयास किये जा रहे हैं। जब तक पंजाब से 0.6 एमएएफ हिस्सा नहीं मिलता तब तक नहरों का विस्तार किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नहर का महत्व केवल हमारे बाड़मेर जिले तक ही नहीं है। क्या यह नहर पूरे देश की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है? क्या यह पश्चिमी राजस्थान में हमेशा अकाल पड़ते हैं उस धरती को हरा-भरा करने का एक स्रोत है? क्या इस नहर से 3 लाख किसान जिनका लक्ष्य था कि उनकी जमीन को सिंचित करेंगे तो इतनी बड़ी नहर का महत्व और भूतपूर्व मुख्य मंत्री राजस्थान श्री मोहन लाल सुखाड़िया और देश के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने इसका महत्व समझा देश की सुरक्षा के मामले में? अभी आप पंजाब का कह रहे हो कोर्ट में आपकी सरकार की पैरवी नहीं। पंजाब से पानी लेना राजस्थान के हक का स्टेट की जिम्मेदारी है और आप हमको कह देते हो कि पंजाब अगर खुश नहीं हुआ तो आप जाकर रोओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे बाड़मेर सीमावर्ती जिले के साथ अन्याय है। सरकार को इसको गंभीरता से विचार करके इस नहर का काम चालू करना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय से आप भी वाकिफ हैं। हमने 1981 में जो समझौता किया था 0.6 एमएएफ पानी हमने सरेण्डर किया इस आधार पर कि अभी हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं। जब हम इन्फ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे तब राजस्थान को यह पानी मिल जाएगा। आप और हम सब मिलकर इस बात का प्रयास करें, अपन ने उस समय समझौते के कारण से छोड़ दिया लेकिन 0.6 एमएएफ पानी लेने के लिये हमको सर्वसम्मति से अपना मन बनाकर केन्द्र सरकार के पास भी, यहां कोर्ट तक भी इस बारे में अपन गये हुए हैं लेकिन यह पानी हमको हर हालत में पंजाब से लेने के लिये जो भी एफर्ट्स हम कर सकते हैं, हमने गलती से छोड़ दिया या हमने देखा कि कोई बात नहीं हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, पर इसके लिये हम सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिये और 0.6 एमएएफ जो हमारा पानी वह हमें राजस्थान को मिलना चाहिये।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पीड़ा प्रतिपक्ष के माननीय नेता और माननीय सदस्य ने बताई है, वह वाजिब है और इसके लिये सरकार बराबर प्रयत्नशील है। बार-बार भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ मीटिंगें हो रही हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। पहले पंजाब सरकार ने विधान सभा में प्रस्ताव पारित करके उस समझौते

(श्री अंजना उदयलाल)

को ही तोड़ दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में गये, वहां से जीते हैं और उसके बाद वापस बराबर मीटिंगें हो रही हैं और जल्दी ही इस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

पिण्डवाड़ा तहसील की पंचायतों का जनजाति उप योजना क्षेत्र में सम्मिलन

श्री अध्यक्ष: अगला 131. श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत मेरे विधान सभा पिण्डवाड़ा तहसील की शेष रही पंचायतों को भी जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित करने के संबंध में मैं आपके माध्यम से जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 19 मई, 2018 को अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार संबंधी अधिसूचना जारी की गई जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले पिण्डवाड़ा तहसील के 51 ग्राम अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिण्डवाड़ा तहसील के शेष रहे गांवों की सूची मय जनसंख्या के परिशिष्ट 'प' पर संलग्न है। इन ग्रामों के निर्धारित मापदंडों की पूर्ति नहीं करने के कारण अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं, जिस प्रकार से हमारी पिण्डवाड़ा तहसील रेवदर आबू रोड से भी, जिस प्रकार एसटी की रिजर्व सीट है, उसमें भी अगर जनसंख्या के आधार पर संख्या ज्यादा होती है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पूरी तहसील को टीएसपी क्षेत्र में जोड़ा जाए ताकि जो जनजाति के लोग रहते हैं उनको हर प्रकार की सुविधा मिल सके और बेरोजगारों को रोजगार भी मिले। पिण्डवाड़ा तहसील आदिवासी क्षेत्र है, 76 परसेंट एसटी बेल्ट है। इसलिए किसी कारणवश शेष रही पंचायतों को भी पूर्ण सर्वे करवाकर केन्द्र सरकार को भेजने का प्रयास करे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, भारत सरकार का जो क्राइटेरिया है ट्राइबल सब प्लान का, माडा का, माडा के consecutive विलेज होने के कारण माडा में डिक्लेयर होता है। तो चाहे पिण्डवाड़ा हो, गोगुन्दा हो, कुम्भलगढ़ हो, नाथद्वारा हो, उन सब के आदिवासियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। राजस्थान सरकार भारत सरकार से यह कहे कि यह जो आधार बना रखा है, उस आधार के बनिस्बत् जहां-जहां भी आदिवासी पापुलेशन है, उन सबको इसका लाभ मिले, इसके बारे में प्रयत्न करे जिससे वंचित लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): अध्यक्ष महोदय, आगे इस बात का ध्यान रखकर नियमों की छूट मांगते हुए पत्र व्यवहार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के प्रतिवेदन (क्र सं. 1 से 28)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2019-20 के निम्न प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं:-

1. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 256वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का प्रथम प्रतिवेदन।
2. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 251वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का द्वितीय प्रतिवेदन।
3. जन लेखा समिति, 2016-17 (चौदहवीं विधान सभा) के 152वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का तृतीय प्रतिवेदन।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य-वित्त) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 2.4 पर्यटन एवं पशुपालन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का चतुर्थ प्रतिवेदन।

5. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 240वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का पांचवां प्रतिवेदन।

6. जन लेखा समिति, 2016-17 (चौदहवीं विधान सभा) के 176वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का छठा प्रतिवेदन।

7. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 243वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का सातवां प्रतिवेदन।

8. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 253वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का आठवां प्रतिवेदन।

9. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 237वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का नवां प्रतिवेदन।

10. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 221वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का दसवां प्रतिवेदन।

11. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 258वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 2.2 तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का बारहवां प्रतिवेदन।

13. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 3.4 से 3.9 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का तेरहवां प्रतिवेदन।

14. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 3.3 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का चौदहवां प्रतिवेदन।

15. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.8 एवं वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 3.11 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

16. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 2.1 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का सोलहवां प्रतिवेदन।

17. जन लेखा समिति, 2016-17 (चौदहवीं विधान सभा) के 136वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का सत्रहवां प्रतिवेदन।

18. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 231वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का अठारहवां प्रतिवेदन।

19. जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 277वें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का उन्नीसवां प्रतिवेदन।

20. जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 284वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का बीसवां प्रतिवेदन।

21. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 197वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का इक्कीसवां प्रतिवेदन।

22. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 259वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का बाईसवां प्रतिवेदन।

23. जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 272वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का तेईसवां प्रतिवेदन।

24. जन लेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 85वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का चौबीसवां प्रतिवेदन।

25. जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 294वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का पच्चीसवां प्रतिवेदन।

26. जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 264वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का छब्बीसवां प्रतिवेदन।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

27. जन लेखा समिति, 2018-19 (चौदहवीं विधान सभा) के 265वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

28. जन लेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 235वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान, श्री रघु शर्मा, चिकित्सा मंत्री जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 104,41,27,20,000 (अक्षरे एक सौ चार अरब इक्तालीस करोड़ सत्ताईस लाख बीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 26 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मांग संख्या 26 पर आज विचार-विमर्श हो रहा है, मैं भी इसमें अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पेज नंबर 23 पर कहा कि गरीब, निर्धन को नि:शुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिये हमने मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना और जांच योजना प्रारम्भ की थी। पर मुझे इस बात की पीड़ा है कि पिछली सरकार की योजनाएं

(श्री कालीचरण सराफ)

प्राथमिकता में नहीं रहीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय नि:शुल्क दवा योजना और जांच योजना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल थीं। हमने दोनों योजनाओं के बजट में कमी नहीं की बल्कि बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की। हमारे समय में इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। आपके समय में यह योजना 2011-12 में प्रारम्भ हुई थी और तीन साल यह योजना चली थी। उस समय कुल 694 करोड़ की दवाइयां खरीदी गई थीं। माननीय मंत्री महोदय, जबकि हमारे शासन काल में प्रथम तीन वर्षों में 2014-15 से 2017 तक कुल 1129 करोड़ की दवाइयां खरीदी गई। यानी इनके शासन काल में 694 करोड़ और हमारे शासन काल के प्रथम तीन साल में 1129 करोड़। 2011-12 से 2013-14 तक, तीन साल में 16 करोड़ 19 लाख व्यक्तियों को नि:शुल्क दवा उपलब्ध कराई गई और हमारे शासन में प्रथम तीन वर्षों में 27 करोड़ 89 लाख व्यक्तियों को नि:शुल्क दवा उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार हमारे शासन काल में मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना को भी अधिक मजबूती से लागू किया गया। 2015-16 से 2017-18 के दिसम्बर माह तक 11 लाख 84 हजार से अधिक जांचें की गईं। 5 करोड़ 92 लाख से अधिक व्यक्तियों को इसका लाभ मिला। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने कैंसर की 48 दवाइयों को जरूरी मानकर नि:शुल्क दवा योजना में शामिल करने की अनुशंसा की थी और आपकी सरकार आते ही आपने उसमें कटौती कर दी और केवल 11 दवाइयों को ही जरूरी माना। इतना ही नहीं वर्तमान में हीमोफीलिया की दवाइयां भी अस्पतालों से गायब हैं। और तो और सामान्य दर्द की Paracetamol, बेहोशी की Midazolam, फंगल इंफेक्शन की Amphtericin-B जैसी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हैं।

इसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के ग्रामीण एवं दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिये हमने मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय लिया था और मेरे द्वारा उसका शिलान्यास भी कर दिया गया था परन्तु पिछली सरकार द्वारा इसका कार्य रोक दिया गया। अब मैं श्रीगंगानगर में पुन: मेडिकल कालेज का कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं। अच्छा तो होता इसके साथ माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी कहते कि देश की आजादी के बाद प्रदेश में 65 सालों में जहां 7 मेडिकल कालेज ही खुले,

(श्री कालीचरण सराफ)

एक जयपुर में, एक अजमेर में, एक बीकानेर में, एक कोटा में, एक उदयपुर में, एक झालावाड़ में और एक जोधपुर में। वहीं भाजपा सरकार के पांच सालों में 8 मेडिकल कालेज स्वीकृत कराये गये और उनमें से 5 मेडिकल कालेज चूरू, भीलवाड़ा, पाली, डूंगरपुर और भरतपुर में 1 जुलाई, 2018 से यह शुरू भी हो गये। बाकी तीन मेडिकल कालेज सीकर, बाड़मेर और धौलपुर में जो 1 जनवरी, 2019 से शुरू होने थे लेकिन दुर्भाग्य से आपकी सरकार बन गई और अनदेखी के कारण ...(व्यवधान)

(12.40 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

पैसा पूरा दिया, आप लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया। मंत्री जी, अपने जवाब में बताएं कि आप कब तक इन तीन मेडिकल कालेज को शुरू करवाएंगे। इसी प्रकार से न तो अब तक सीकर का मेडिकल कालेज चालू हुआ, न बाड़मेर का हुआ और न धौलपुर का हुआ। मैं चाहूंगा कि जब आप अपना जवाब दें, तो उस समय बताएं कि श्रीमान् इनको आप कब चालू करेंगे। (व्यवधान) बीच में मत बोलिये। ये टोकाटोकी नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यदि ये टोका-टोकी करेंगे तो हम भी करेंगे। हमारे फर्स्ट स्पीकर बोल रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य, आप विराजें। माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार के सहयोग से सुपर स्पेशिलिटी ब्लाक के मेडिकल कालेज को 200 करोड़ रुपये। बीकानेर, कोटा और उदयपुर को डेढ़-डेढ़ सौ करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। राज्य कैंसर संस्थान के लिये 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है? उनका क्या भविष्य है, कृपया आप अपने जवाब में बताएं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने प्रदेश में 13 दिसम्बर, 2015 से भामाशाह स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 1 करोड़ परिवारों को साधारण बीमारी में 30 हजार रुपये और गम्भीर बीमारी में 3 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा प्रदान की गयी थी और तीन साल में करीब 1300 करोड़ रुपये की राशि सरकार द्वारा खर्च की गयी और इसके चलते प्रदेश में 21 लाख मरीजों को इस

(श्री कालीचरण सराफ)

योजना का लाभ मिला, लेकिन आपकी सरकार ने आते ही आपने इस योजना को अघोषित रूप से बंद कर दिया और जो मरीज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में नामित थे, उन्होंने इलाज करवाया तो आपने उनका भुगतान रोक दिया जिससे निजी अस्पतालों का भुगतान रुक गया और सीधे-सीधे इससे गरीब जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। 774 निजी अस्पतालों को इस योजना में शामिल किया गया था और 1401 बीमारियां पंजीकृत थीं। इनमें 663 अति गम्भीर बीमारियां भी इसमें सम्मिलित थीं। अब यह कहा जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार की आयुष्मान भारत योजना प्रदेश में लागू करेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। कब लागू करेंगे? मंत्री जी अपने जवाब में बताएं। जब तक यह योजना चालू नहीं होगी, तब तक भामाशाह योजना को चालू रखा जाए, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ बात करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अच्छा। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के 15 अगस्त, 2016 से एक-एक पीएचसी की स्थापना करने का निर्णय किया। चाहे वहां पर कांग्रेस का विधायक हो, चाहे निर्दलीय विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो। हमने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के इस योजना को चालू किया और 295 ब्लाक में आदर्श स्वास्थ्य केन्द्रों का शुभारंभ किया। ऐसी पीएचसी में हमने व्यवस्था की कि पर्याप्त स्टाफ हो, उपकरण और दवाइयां भी यहां मिलें। आयुष चिकित्सक लगाकर आयुर्वेद और योग की सेवाएं वहां पर दी जाएं। इसके कारण आउटडोर में 26 परसेंट की वृद्धि हुई और डिलीवरी में 4 परसेंट की वृद्धि हुई। इसकी सफलता को देखकर हमने दूसरे चरण में 11 जुलाई, 2017 से 286 पीएचसी में इस कार्य को प्रारम्भ किया, परन्तु खेद है कि अब इस योजना को भी अघोषित रूप से आपने बंद कर दिया। बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं की।

माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों में बीपीएल नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों को सीटी स्कैन की सुविधा नि:शुल्क दी जाएगी। आपने घोषणा की थी, परन्तु प्रदेश की जनता को निराशा हुई, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल प्रदेश के मेडिकल कालेजों में ही इस सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा की घोषणा की। जबकि आपने कई जगह इस प्रकार की घोषणाएं की थीं कि सीएचसी और पीएचसी में

(श्री कालीचरण सराफ)

भी आप इस प्रकार की जांचें करवाएंगे। आपने Indian Section of International Society for Heart Research के वार्षिक सम्मेलन में यह घोषणा की कि बढ़ रहे हार्ट मरीजों के समुचित इलाज के लिए अब राज्य सरकार पीएचसी और सीएचसी पर भी हार्ट के इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी, क्या हुआ? बजट में तो इसका जिक्र नहीं है। माननीय सभापति महोदय, नवजात के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है। अनेक इंटरनेशनल स्टडीज में यह स्पष्ट हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने 12.35 पर आपने शुरू किया। 1.05 तक मैं आपको बोलने दूंगा। आप इधर देखकर बात करें। माननीय मंत्री महोदय, बीच में इंटरवीन न करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप निश्चिंत रहें, मैं टाइम लिमिट में ही बोलूंगा। नवजात को यदि मां का दूध पिलाया जाए तो नवजातों की मौतों में 15 से 20 प्रतिशत की कमी आ सकती है। हमने 17 जिलों में मदर मिल्क बैंक की स्थापना की और इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। इसमें 20 हजार से अधिक माताओं ने 40 हजार बार में लगभग 43 लाख एमएल दूध दान किया। इसमें लगभग 13 हजार नवजात बच्चों को लाभान्वित किया गया। बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी कोई चर्चा नहीं की कि बाकी शेष जिलों का क्या करेंगे।

PCPNDT Act, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा तो हम सब लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा PCPNDT Act जो 1994 में लागू हुआ और 2013 तक केवल 21 डीकाय आपरेशन हुए। हमने पांच साल के शासन में 90 से ज्यादा डीकाय आपरेशन किये, जिसके परिणामस्वरूप 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात 888 था, वह बढ़कर 939 हो गया। अब आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, वह भी बताइये।

इसी प्रकार से इंट्रीग्रेटेड एंबुलेंस सेवा हमने चालू की। सड़क दुर्घटनाओं के गोल्डन आवर में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके हजारों लोगों की जानें बचायीं और प्रसूताओं, नवजात और गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को भी समय पर सुविधा उपलब्ध करवायी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां तक नियुक्तियों का सवाल है, हमने हमारे कार्यकाल में 19973 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति दी और 5334 डाक्टर्स की नियुक्ति हमने की, परन्तु दुर्भाग्य से...

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, इनके कार्यकाल में पैट्रोल पंप के ऊपर...

श्री सभापति: सहयोग करें, माननीय सदस्य। प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आप विराजें। मैंने आपको अलाउ नहीं किया।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, हम आपके संरक्षण में हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, हमने 5334 डाक्टर्स की नियुक्ति की, परन्तु दुर्भाग्य है कि इनका सलेक्शन भी, हो गया, अपाइंटमेंट भी दे दिया, पर उनमें से केवल 3118 डाक्टर्स ने जाइन किया। आज भी स्थिति यह है कि डाक्टर्स के 11 हजार स्वीकृत पदों में से 3 हजार से ज्यादा पद खाली हैं। मैं चाहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर कोई इस प्रकार की नीति बनायी जाए, जिससे कम से कम पांच साल तक नया डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी दे सके।

इतना ही नहीं, सरकारी मेडिकल कालेजों में सरकार के बड़े खर्चे पर पीजी करने के बाद गांवों के अस्पतालों में पांच साल तक अनिवार्य सेवा देने का प्रावधान है, परन्तु स्थिति यह है कि 50 परसेंट डाक्टर्स गांव में नहीं जाते हैं, शहर में निजी प्रैक्टिस करते हैं। प्रदेश में डाक्टर्स से 25 लाख और 50 लाख के बांड भी भरवाये जाते हैं। पंजीकरण रद्द करने का भी प्रावधान है परन्तु केवल नोटिस और चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। सख्ती की जाए, बांड जब्त किये जाएं और पंजीकरण रद्द किये जाएं, जिससे कि वे ड्यूटी जाइन कर सकें।

इसी प्रकार से, एसएमएस हास्पिटल हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। लगभग 30 लाख मरीज यहां पर इलाज कराने के लिये आते हैं। मरीजों का दबाव कम करने के लिए हमने जयपुर के दक्षिण में जयपुरिया, पश्चिम में कांवटिया, उत्तर में गणगौरी और पूर्व में सेठी कालोनी हास्पिटल में आवश्यक सुविधाएं मुहैया करायी हैं। जयपुरिया में सीटी स्कैन, एमआरआई, 2डी इको, टीएमटी व अन्य सुविधाओं के साथ-साथ सुपर स्पेशियलिटी उपचार प्रारम्भ किया। अस्पताल की क्षमता 500 बैड की गई। परिणामस्वरूप यहां

(श्री कालीचरण सराफ)

पहले 250-300 का आउटडोर होता था। उसकी जगह 2500-3000 का आउटडोर हुआ। परन्तु सरकार बदलते ही यहां सुपर स्पेशियलिटी की सुविधा समाप्त कर दी। एक्स-रे की फिल्म नहीं हैं। मोबाइल से एक्स-रे देख रहे हैं और उनके पास स्मार्ट फोन नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर बात करिए। उनको इनवाइट क्यों कर रहे हैं? आप इधर बताइये, मुझे बताइये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमने पूछा तो कहा कि बजट की कमी है। बाद में एमआरआई और सीटी स्कैन का ईएचसीसी हास्पिटल से जो एमओयू हुआ, उसमें यह प्रावधान था कि बीपीएल परिवार और वरिष्ठ नागरिकों की जांच नि:शुल्क की जाएगी परन्तु आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि तीन-तीन, चार-चार महीने की वेटिंग है और उनकी जांच नहीं की जा रही है। इसी प्रकार से आरयूएचएस के द्वारा नवीन चिकित्सालय 500 बैड का स्वीकृत करा लिया, निर्माण कार्य पूरा हो गया। मुख्य मंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया परन्तु अभी तक उसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कांवटिया हास्पिटल, ब्लड बैंक, इकोकार्डियोग्राफी सेन्टर, आईवीएफ सेन्टर सहित कई अनेक सुविधाएं हमने दीं। ओपीडी 2 हजार से बढ़कर 4 हजार हो गया। गणगौरी हास्पिटल में भी ये सुविधाएं बढ़ाई गई। सेठी कालोनी में मेडिसिन सर्जरी, शिशु रोग कार्डियोलोजी की ओपीडी सुविधा, सोनोग्राफी, ये सब की गई।

इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि एसएमएस हास्पिटल हो या अन्य हास्पिटल हो, इनमें जो हम करोड़ों रुपये की मशीनें खरीदते हैं, वह खराब पड़ी रहती हैं। वह खराब इसलिए रहती हैं कि डाक्टर्स के कमीशन का चक्कर होता है। निजी सेन्टर में जांच के लिए भेजते हैं तो उसमें उनकी कमीशन होती है। मैं यह चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर राजस्थान के जितने भी चिकित्सालय हैं, उनमें जो मशीनें खराब पड़ी हैं, उनको ठीक कराने का उपाय करें। इसी प्रकार से हमने वहां रिसेप्शन सेन्टर भी बनवा दिया, अंडरग्राउण्ड, ट्रोमा सेन्टर के लिए रास्ता भी बनवाया। ट्रोमा सेन्टर की भी स्थापना हो गई परन्तु यह बिल्डिंग पुरानी है। कभी तो छत से प्लास्टर गिरता है, कभी वहां पर शार्ट सर्किट के कारण आग लगती है। मैं यह चाहूंगा कि इसकी परमानेंट मॉनिटरींग हो। इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था निश्चित रूप से हमें करनी चाहिए।

(श्री कालीचरण सराफ)

इसी प्रकार से जेके लोन में सीटी स्कैन शुरू करने की फाइल कई सालों से अटकी हुई है। जयपुरिया में सीटी स्कैन का कांट्रेक्ट भी खतम हो गया है। बाहर से खरीदा जा रहा है। इसकी भी आप लोग व्यवस्था करें। इसी प्रकार मेडिकल कालेजों में मेडिकल टीचर्स की कमी है। एक हजार डाक्टर्स हर वर्ष बनते हैं। एमसीआई का निरीक्षण होता है तो कमी का हवाला देकर मेडिकल टीचर्स को इधर से उधर किया जाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए मेरा सुझाव है कि भर्तियां एक साथ निकाली जाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यदि आप माननीय दो जो यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, यदि उनको बताना है तब तो आप लिखकर के उनको दे दो। आप आसन की तरफ बात करिए। डायरेक्शन आप इधर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं आपको ही देखकर बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराजिए आप। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर बात करिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपसे ही कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चिकित्सा मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि भर्तियां एक साथ निकाली जाएं और उसकी बिना किन्तु-परन्तु के वित्त विभाग से मंजूरी ली जाए। आरपीएससी के माध्यम से जो भर्तियां होती हैं, उसमें समय ज्यादा लगता है। अभी जो नये मेडिकल कालेज हमने खोले थे, पांच स्थानों पर, उसमें हमने डायरेक्ट इंटरव्यू करके डाक्टर्स की नियुक्ति की थी। मैं चाहूंगा कि पुराने मेडिकल कालेजों में भी इसी प्रकार से यदि डाक्टर्स की, टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी तो जल्दी हो जाएगी। सेवानिवृत्ति की आयु तो हमने 65 साल कर दी और अब यह कहा जा रहा है कि हम 70 वर्ष करेंगे। इसका चारों ओर विरोध हो रहा है। मैं यह चाहूंगा कि नई भर्ती की योजना बनाकर भर्तियां की जाएं जिससे कमी पूरी हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि डाक्टर्स के साथ चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे निजी अस्पताल हो, मरीजों के परिजनों के द्वारा आए दिन मारपीट की जाती है, बदसलूकी की

(श्री कालीचरण सराफ)

जाती है। इन घटनाओं को सख्ती से रोका जाना आवश्यक है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जितने भी बड़े हास्पिटल हैं, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाएं और वहां पुलिस चौकी की स्थापना की जाए। जैसे अभी परसों जयपुरिया हास्पिटल में झगड़ा हुआ। कावंटिया हास्पिटल है, जयपुरिया हास्पिटल है, गणगौरी हास्पिटल है, यहां पुलिस चौकी की स्थापना होगी तो इस प्रकार की घटनाएं रुकेगी।

आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी यह कहा है कि हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करेंगे। आप अपने जवाब में बताए कि इसको आप कब लागू करेंगे? आपने निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाने के लिए यह घोषणा की कि हम रैग्यूलेटरी बोर्ड बनाएंगे। उसका क्या हुआ? इसके बारे में भी बजट में कोई जानकारी नहीं दी। राइट टू हैल्थ की बात तो आपने की परन्तु इसका भी कोई जिक्र बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? यह भी आप बताएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में लापरवाही बरतना राज्य के लिए बहुत महंगा पड़ा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्र से मिला सम्पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य 85 परसेंट पूरा नहीं करने के कारण केन्द्र सरकार ने राजस्थान को देय 500 करोड़ रुपये का इन्सेन्टिव रोक लिया।

इसी प्रकार पिछले दिनों एनएचएम के तहत कम्यूनिटी हैल्थ आफिसर्स के 2500 पदों की भर्ती भी राज्य सरकार 30 जून तक नहीं कर पाई। 600 करोड़ रुपया पेनल्टी लगाने का प्रावधान यानी 600 करोड़ तो वह और 500 करोड़ रुपये यह, 1100 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान हुआ। मैं पूछना चाहूंगा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने एनएचएम के एमडी का ट्रांसफर कर दिया। कुछ अधिकारियों को वहां से हटा दिया। इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाए और इसमें कौन दोषी हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसी प्रकार से राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, वहां जो रजिस्ट्रार लगे हुए हैं, +++ उनके विरुद्ध एसीबी में जांच हुई और दोष सिद्ध हो गया। हमने उसको हटा दिया। उन्होंने स्वयं ने भी इस्तीफा दे दिया। परन्तु क्या कारण रहे कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने उस आदेश को बदलकर पुन: उस भ्रष्ट व्यक्ति को दोबारा लगा दिया? मैंने आपको एक पत्र भी लिखा। मेरे समझ में नहीं आया कि उसको वापस आपने क्यों लगाया है? इसके बारे में भी कृपया अपने

(श्री कालीचरण सराफ)

जवाब के समय बताएं। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, टीकाकरण के नाम पर बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। जयपुर, गंगानगर, सीकर में बच्चों को दिमागी बुखार से बचाने वाली नकली वैक्सीन मिली है। सरकारी मेडिकल स्टोर में नकली स्प्रिट पाई गई है। यह एक शर्मनाक घटना है। जोधपुर, जयपुर, अजमेर के ब्यावर में अमानक दवाइयां मिली हैं। इन पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? इसके बारे में भी बताएं।

स्वाइन फ्लू, मुझे तकलीफ है यह बताते हुए कि हिन्दुस्तान में जितनी मौतें हुई उसमें से 26 परसेंट मौतें केवल राजस्थान में हुई। यह मौतें क्यों हुई क्योंकि उस समय मंत्री जी को रामगढ़ के उपचुनाव से फुर्सत नहीं थी। इनको पूछा पत्रकारों ने कि श्रीमानजी स्वाइन फ्लू से लोगों की मौतें हो रही हैं तो इन्होंने कहा कि मैं पहले 26 जनवरी को झण्डारोहण करूंगा और उसके बाद प्रभावित जिलों का दौरा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपके इतना सरकारी अमला है, उनको तो कम से कम मानिटरींग के लिए भेजते। मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे स्वाइन फ्लू हो चाहे डेंगू हो, चाहे अन्य बीमारियां हो, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, अभी से आप इसकी कार्य योजना बनाएं क्योंकि ये तो हर साल आएगी। मौसम का जैसे ही परिवर्तन होता है, ये बीमारियां होती हैं। इस बार यह शर्मनाक स्थिति नहीं आए तो निश्चित रूप से आप इस पर कोई न कोई कार्यवाही करेंगे।

एक बड़ी शर्मनाक बात, पूरे देश में 8 फरवरी को नेशनल डी-वार्मिंग डे मनाया जाता है। परन्तु हमारे यहां इस बार नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? हमने पता किया तो यह पता लगा कि चिकित्सा विभाग के पास यह दवाई नहीं थी जो बच्चों को पेट के कीड़े मारने के लिए उस दिन पिलाई जानी थी। एलवेड़ा जोल दवा देने वाली कम्पनी ने

(13.00 बजे)

विभाग को इसकी सप्लाई ही नहीं की। इसका परिणाम क्या हुआ कि 01 साल से 19 साल तक के करीब 80 लाख बच्चे इस दवाई से वंचित रह गए। इस गम्भीर लापरवाही के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? आपने इसकी क्या जांच कराई, क्या कार्यवाही की? इसके बारे में भी आप बताएं।

मुख्य मंत्री जी ने बजट में हैल्थ से संबंधित कई घोषणाएं की हैं परन्तु राजस्थान की जो पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, यूनानी व हौम्योपेथी, इनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। आयुर्वेद विभाग के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसा लगता है कि एक हजार करोड़ बजट सालाना वाले

(श्री कालीचरण सराफ)

आयुर्वेद, हौम्योपेथी व यूनानी चिकित्सा की जान बूझकर उपेक्षा की गई है। राजस्थान में देश का सबसे बड़ा आयुर्वेद का ढांचा है। एस.एम.एस. हास्पिटल जैसे हास्पिटल में भी एक छत के नीचे आयुर्वेद, हौम्योपेथी व यूनानी चिकित्सा उपलब्ध है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने इसके लिए 2018-19 में मदन मोहन मालवीया आयुर्वेद कालेज, उदयपुर में 20 सीटों वाला बीएचसी नर्सिंग कोर्स, 30 सीटों वाला एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठयक्रम, रोग निदान व प्रसूती रोग विभाग की यूजी से पीजी में क्रमोन्नत, पंचकर्म चिकित्सा विद्या को प्रोत्साहन देने के लिए एक वर्षीय पंचकर्म तकनीकी सहायक डिप्लोमा कोर्स कराने की घोषणा की थी। उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, यह बताएं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में पिछले 6 महीने में, जब से यह सरकार बनी है चिकित्सा व्यवस्था बिलकुल चौपट हो गई है, मैं उसकी कुछ बानगी आपको बताना चाहूंगा। अभी भास्कर अख़बार ने स्टिंग आपरेशन किया। उसमें 13 ज़िलों में भास्कर टीम ने लेबर रूम की हकीकत के बारे में जानकारी ली। प्रसूता बिलखती रहती है, परिजन हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और सफाईकर्मी डाक्टर बनकर डिलीवरी करवा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती।

इसी प्रकार से प्रसव केन्द्र है, ऐसा लगता है कि प्रसव यातना केन्द्र में परिवर्तित हो गए हैं। 24 साल की दीक्षा कंवर, 07 जनवरी का दिन कभी नहीं भूल सकती। जैसलमेर के रामगढ़ में डिलीवरी के दौरान मेल नर्स ने उसके शिशु को इस तरह से खींचा कि उसके दो टुकड़े हो गए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती।

इसी तरह से एक समाचार आया कि प्रसूता को प्रसव पर पांव में कैंची चुभाई गई, थप्पड़ मारे, वीडियो वायरल हुआ। इसकी जांच के लिए जब मंत्री जी ने आदेश दिया तो जांच कमेटी ने उसको दोषी माना पर उसके साथ-साथ लीपापोती कर दी कि यह गैर इरादतन मामला था, इसलिए इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से प्रसूता के शरीर में रूई छोड़ दी गई, टांके खोलकर फिर निकाली गई। केबिन के बाहर मृत महिला का आपरेशन कर बेटी को बचाया। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अख़बार से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और किससे बोलूं, आपसे थोड़े बोलूं, आपसे थोड़े ही बोलूंगा (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसी प्रकार से नागौर के सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद डाक्टर ने पांच हजार रुपये मांगे, उसका भी वीडियो वायरल हुआ। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, जननी की जान पर पग-पग पर सौदा, गर्भस्थ शिशु की जान गई और चाय-पानी के पैसे मांगते रहे। बेटी पैदा होने पर 700 रुपये लेते हैं, तीन पुलिसकर्मी निलम्बित हुए। अस्पताल में प्रसव के लेते थे रुपये, 7 कर्मचारी निलम्बित। और तो और अपने यहां जेके लोन हास्पिटल में, एस एम एस अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में सैम्पल लेने पर कहा सुनी हुई तो हमारे डाक्टर ने गुस्सा खाकर 14 सैकिण्ड में मरीज को चार थप्पड़ मारे। मालपुरा सीएचसी नर्सिंग पर प्रशिक्षु छात्र ने मरीज को थमाई एक्सपायरी डेट की दवा। एस एम एस हास्पिटल में रेजीडेंट ने मारे लात-घूंसे, वीडियो वायरल। दाएं पैर का इलाज करना था, डाक्टर ने बाएं पैर का इलाज कर दिया। यानी इस प्रकार की घटनाएं इनकी मोनीटरिंग करिए, किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है, इसके लिए कौन दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकते हैं? इसके बारे में निश्चित रूप से आप कोई न कोई व्यवस्था करेंगे यह मेरा कहना है। आपने मुझे एक बजकर पांच मिनट का समय दिया था, मैंने वह पूरा कर दिया है, एक मिनट भी ज्यादा नहीं बोला हूं। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, proverb, 'A Healthy body keeps a Healthy Mind' चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का राजस्थान में जो सैटअप है, सभापति महोदय, मैं शुरूआत करना चाहूंगा क्योंकि एस.एम.एस. मेडिकल कालेज हास्पिटल, एशिया का सबसे बड़ा आउटडोर एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में है। माननीय Deputy Leader of Opposition, 1993 में हैल्थ मिनिस्टर थे, उस समय आपका बहुत अच्छा वर्किंग रहा।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, एस एम एस मेडिकल कालेज का मिर्जा इस्माइल में निर्माण शुरू हुआ तो 1940 में बनकर कमप्लीट हुआ, आज 80 साल हो गए। मेरा सौभाग्य है कि मेरे स्वर्गीय पिता डाक्टर छोगालाल जी जिन्होंने इंडिया के प्रिमियर मेडिकल कालेज आर. जे. मेडिकल कालेज कलकत्ता से 1937 में एमबीबीएस किया। आप तो कलकत्ता में रहे हैं। पहला भवन आज से 80 साल पहले बना, he was in the team of Doctors. डा. एस सी मेहता उस वक्त, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी संस्थान को 80 साल हो जाते हैं तो फिर आवश्यकता होती है कि उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए। आपको एक लोंग टर्म प्लान करना पड़ेगा। एस एम एस मेडिकल कालेज हास्पिटल सिर्फ राजस्थान का 50 percent part of the health with the SMS Medical College.

सभापति महोदय, यहां पांच स्टेट के पेशेंट आते हैं। हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, यूपी, बहुत से आते हैं। बहुतसी एमीनेंट पर्सनल्टी एस एम एस मेडिकल कालेज से निकली हैं जिन्होंने दुनिया में और पोलिटिक्स में नाम रोशन किया।

मैं बताना चाहूंगा, डाक्टर फारूख अब्दुल्ला, मैं फर्स्ट ईयर में था वह फाइनल ईयर में थे। वह कश्मीर के सी. एम. रहे और अल्टीमेटली सैन्ट्रल में भी मिनिस्टर रहे। डाक्टर बी. के. गोयल सांभर के थे और बोम्बे में शेरिफ रहे and he was one of the top Cardiologist of India after Dr. Rustom Jalwaki.

माननीय सभापति महोदय, जयपुर फुट की बहुत सारी बातें होती हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे मेडिकल कालेज के गुरु डाक्टर पी.के. सेठी, जब विदेशों में मैटेलिक फुट आता था, वियतनाम के बम एक्सप्लोजन में, ईराक में, लाखों लोगों के पांव एम्प्युटेशन हो गए। डाक्टर पी.के. सेठी ने जयपुर फुट बनाया। मैं भी उस टीम में था। वह रबर फुट था। डाक्टर पी.के. सेठी ने लाखों -लाखों लोगों के जीवन की तकदीर बदल दी। उन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया and he was from the SMS Medical College.

हमारे सम्माननीय अशोक पानगड़िया, डाक्टर एस.आर. मेहता, डाक्टर करणसिंह यादव, डाक्टर शिव सरीन, डाक्टर सत्यवान, ये एमिनेंट डाक्टर्स हैं जिन्होंने एस एम एस मेडिकल कालेज का और जयपुर का नाम रोशन किया।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, अमेरिका और इंग्लैण्ड में, अगर हिन्दुस्तानी डाक्टर एक दिन के लिए कालऑफ पर बैठ जाए तो उनकी सारी व्यवस्था चरमरा जाए। Dr. Denton Cooley, स्वर्गीय ओनरेबल भैरोंसिंह शेखावत साहब सीकर से थे, पिताजी से घनिष्ठ संबंध थे उनके, जब वह बाईपास के लिए गए, डाक्टर Dr. Denton Cooley उस समय वहीं थे तो thoracic surgeon, Dr Denton Cooley is the number one. 50 परसेंट डाक्टर्स राजस्थान के थे डाक्टर डेंटेन कूली की यूनिट में। उनको बहुत खुशी हुई जब मैं उनकी तबीयत पूछने गया। उनको पता नहीं कि राजस्थान के डाक्टर वहां भी हैं। अमेरिका में डाक्टर्स एसोसिएशन ने राना अलग से बना रखा है। खैर, वह एक अलग बात है लेकिन इन लोगों को याद करना मेरे लिए आज के दिन जरूरी है। सभापति महोदय, एशिया का सबसे बड़ा आउटडोर एस एम एस मेडिकल कालेज में है। पर डे 8-10 हजार पेशेंट आते हैं और वार्षिक, जैसा कि माननीय फोर्मर हैल्थ मिनिस्टर ने कहा 30 लाख एन्युअल पेशेंट्स का आउडडोर है और बहुत बड़ी संख्या में, ढाई लाख इन्डोर पेशेंट्स हैं। उस सबकी व्यवस्था में एस.एम.एस. मेडिकल कालेज का स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। आप रोज देखें, प्लास्टर गिर रहा है, वह गिर रहा है। अस्सी साल की इमारत यह सब नहीं सह सकती है।

अब आवश्यकता इस बात की है कि एक मास्टर प्लान बनाया जाए और एस.एम.एस. मेडिकल कालेज होरिजेंटल नहीं, बल्कि सात मंजिला वर्टिकल एक्सपेंशन किया जाए और टुकड़ों में इसको डिवाइड किया जाए। जहां ट्रोमा सेन्टर है, उसके पीछे चार-पांच बंगले हैं। उनको सिस्टम से आधा-आधा करके, जहां आपके काटेज वार्ड्स बने हैं, सभापति महोदय, वह बहुत आवश्यक हो गया है। पी.जी.आई., चंडीगढ़; आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तर्ज के ऊपर आपको फर्दर जो भी इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, उनका फर्दर प्लान आपके आर्किटेक्ट के माध्यम से बनाना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, वर्ना जितना दबाव, 70 हजार लोग पर-डे पेशेंट्स के साथ एस.एम.एस. हास्पिटल को विजिट करते हैं।

सभापति महोदय, मार्डन, जैसा कि माननीय फोर्मर हैल्थ मिनिस्टर बता रहे थे, जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत, मैं बताना चाहूंगा, यह जो मुफ्त दवा योजना है, सभापति महोदय, मैं खुद एम.बी.बी.एस. करके, पिताजी ने शर्त लगाई थी कि आप आधे दिन क्लिनिक पर बैठोगे। मेरे पिता

(श्री जितेन्द्र सिंह)

शेखावाटी के आइडेंटिकल थे। उन्होंने एस.एम.एस. हास्पिटल छोड़ा। उनके जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा, छोगालाल, ये क्या कर रहे हो, जयपुर छोड़कर खेतड़ी जा रहे हो? मेरे भाई साहब हैं, वे मैसूर हाई-कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा, आपां तो गांव का डाक्टर हां, वठे जार सेवा करां। मेरे पिताजी ने एस.एम.एस. छोड़ा, सारा जीवन त्याग की मूर्ति बनकर शेखावाटी में धोरों के अन्दर उन्होंने जिन्दगी बिता दी। मैं समझता हूं, एक डाक्टर को, आज जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। Jesus Christ has told regarding the physician-doctors “A good doctor is a half God half pagan'' मैं डाक्टर्स से भी कहना चाहूंगा कि जो जीसस क्राइस्ट ने और जो हर व्यक्ति कहता है कि डाक्टरजी भगवान हो, उनकी भावना को मत तोड़ना।

माननीय सभापति महोदय, मैंने डाक्टर होने के नाते बहुत से नजारे देखे हैं। भगवान गरीबी किसी को नहीं दे। मैंने बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की लाश को जाते देखा है। मैंने मांओं की गोद में तड़प-तड़पकर बच्चों को दम तोड़ते देखा है। सभापतिजी, एक जगह मैं तो दंग रह गया। नीमकाथाना में एक नव-वधू अपने पेशेंट पति को लेकर आई and he was dead in her arms. मैं पूछता, चौधरी इलाज क्यों नहीं कराते, उसकी आंख में आंसू होते और कहता कि डाक्टरजी, पैसे नहीं हैं। उसका जवान बेटा इसलिये मर गया कि उसके पास इलाज का पैसा नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुफ्त दवा योजना चालू की और मुफ्त दवा योजना का बहुत बड़ा लाभ मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपके एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में इंवेस्टीगेशंस सीनियर सिटीजंस और बी.पी.एल. के लिये फ्री हैं। आज उनकी जो एडवांस्ड मशीनें हैं एम.आर.आई., सी.टी. स्कैन, ये सब बहुत पुरानी हो गई हैं, सात साल पुरानी हो चुकीं। जैसे मंत्री महोदय भी कह रहे थे कि री-टेंडर होकर जो टैक्नोलाजी की अच्छी लेटेस्ट मशीन्स हों, सी.टी. स्कैन, वह खरीदना अत्यन्त आवश्यक है। महोदय, क्योंकि एस.एम.एस. हास्पिटल पूरे देश के अन्दर एक शान है। It is recognized. It is in the World List. SMS Medical College and RNT Medical College, they are recognized hospitals in WHO (World Health Organization) इनका अपना स्थान है।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, एस.एम.एस. हास्पिटल से जुड़ा हुआ है हमारा जे.के. लान हास्पिटल। बच्चे, आज बच्चे के लिये लोग कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जे.के. लोन हास्पिटल, जो एक अटैच्ड हास्पिटल है, उनका पर-डे आउटडोर 1000 का, इन्डोर पेशेंट्स स्ट्रेंथ है। लेकिन उनको अभी भी बहुत आवश्यकता है। उनको डवलप करने की जरूरत है। कार्डियोलाजी, पीडीएट्रिक कार्डियोलाजी नहीं है, not even a single Pediatric Cardiology Surgeon is in the J.K. Lon Hospital और जो सबसे दु:खद अध्याय होता है, सभापति महोदय, किसी महिला के अगर विकलांग बच्चा, मंदबुद्धि पैदा हो गया, सारी जिन्दगी उसको भुगतना पड़ता है। अभी यह लेटेस्ट डवलपमेंट है, this is a genetic defect. माननीय अशोक गहलोतजी के टाइम में, उन्होंने पैसा दिया, उसमें जेनेटिक डिफैक्ट के लिये अलग से लैब बनी। जो महिलाएं, अगर उनके आलरेडी एक बच्चा मंदबुद्धि है तो वह अगली स्टेज में, before six weeks, उसके एम्नीआटिक स्लज की जांच करके पता लगाया जा सकता है कि अगला बच्चा मंदबुद्धि होगा क्या। बाकी सरकार को निर्णय करना है कि वह क्या करती है। अगर मंदबुद्धि बच्चा यूटरस में है तो उसका निर्णय सरकार को लेना है। सभापति महोदय, तो यह इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कार्डियोलाजी, बच्चों के हार्ट में छेद होते हैं। This is the congenital defect और कार्डियोलाजिस्ट अगर नहीं होगा, वे मारे-मारे बच्चों को लेकर फिरते रहेंगे, और बच्चे में सारा घर बर्बाद हो जाएगा। यह शुरुआत है। इस हास्पिटल में, माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, Pediatric Cardiology department is a mass, न्यूरोलाजी, अर्ली स्टेज में अगर बच्चे का पता लग गया कि यह मंदबुद्धि है तो उसके डाइटरी हैबिट्स से, उन सबसे करके उसकी वह स्थिति नहीं आ सकती, जिसके घर में हो गया, सभापति महोदय, घर की हालत नर्क जैसी होती है, अगर मंदबुद्धि बच्चा हो गया तो उनको शर्म आती है। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है। यह सब खुदा के यहां से फरमान होकर आया हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, डैथ रेट, अमेरिका में हजार पर दो या तीन, जबकि हमारे बच्चों की डैथ रेट एक हजार पर 24 है, हमारे बच्चों की डैथ रेट। उसको किस तरह से इम्प्रूव करें, यह बहुत अत्यन्त आवश्यक है।

सभापति महोदय, हमारे एस.एम.एस. मेडिकल कालेज हास्पिटल का ब्लड बैंक इंडिया में सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। हमारे पूर्व माननीय स्टेट हैल्थ

(श्री जितेन्द्र सिंह)

मिनिस्टर राजकुमारजी अभी नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा जन्म दिन पर जाकर मैं ब्लड इकट्ठा करता हूं। माननीय लीडर आफ अपोजिशन, आप तो मंत्री रहे हैं, आज एस.एम.एस. हास्पिटल में 83 हजार यूनिट पर-ईयर कलैक्ट होता है, करीबन एक लाख 33 हजार लोगों को दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से 436 कैंम्प्स लगते हैं। एस.एम.एस. मेडिकल कालेज हास्पिटल अगर इम्प्रूव होगा तो मैं समझता हूं, सारी आस-पास की जनता को सबसे बड़ा लाभ क्योंकि it is a referral hospital और मंत्री महोदय, इस एस.एम.एस. हास्पिटल का भार कम करें। इसकी हालत उस एक बैल की तरह हो गई है, जिस पर वज़न डालते जाते हैं। जो आपने पैरीफेरी हास्पिटल्स बनाये हैं, इनको डवलप करना पड़ेगा। जाना ही नहीं चाहते, राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, पेलेशल हाउस है उसका, पेलेशल हास्पिटल है and nobody is going there. यह डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आप उसको पी.जी.आई. और एम्स की तरह बनाने की बात करते हैं तो आपको सैपरेशन करना पड़ेगा।

दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेज है, वह है डिपार्टमेंट आफ कार्डियालाजी। सभापति महोदय, मैं स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब को नमन करता हूं। 1993 में डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन हैल्थ मिनिस्टर थे। भैरोंसिंहजी शेखावत के भाई बिशनसिंहजी काटेज में एडमिट थे। मेरे पास बहुत सारे मेडिकल कालेज के साथी आते थे। मेडिसन में, सभापति महोदय, Cardiology was in the medicine, मर्ज था, न्यूरोलोजी मर्ज था तो डाक्टर मधोक और अन्य आते थे कि डाक्टर साहब, आप हाउस में सिर्फ अकेले ही डाक्टर हो, सौभाग्य से मैं ही बचकर आया हूं डाक्टरों के अन्दर, जो सारे के सारे, आप तो बहुत बड़े डाक्टर हैं। आप तो डाक्टर बनाने वाले हैं। सभापति महोदय, कार्डियोलाजी डिपार्टमेंट उस समय मेडिसन से अलग किया गया। 1993 में माननीय परसरामजी मदेरणा लीडर आफ अपोजिशन थे। उन्होंने मुझे कहा, डाक्टर साहब बोलिये। मैंने बोलना शुरू किया। माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन ने, उस वक्त इमर्जेंसी बहुत शानदार बना रखी थी। मैंने कहा इमर्जेंसी बहुत शानदार है। मदेरणाजी खड़े होकर मुझे देखने लगे। क्योंकि यह तो बड़ाई होती डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन की। मैंने कहा, Sir, I'm adding a few lacuna's also. कार्डियोलाजी डिपार्टमेंट उस वक्त बना और सभापति महोदय, डाक्टर कर्णसिंह यादव मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट थे। बाई-पास सर्जरी के लिये डाक्टर त्रेहान की यूनिट को ले-लेकर आते थे और यहां हमारी टीम

(श्री जितेन्द्र सिंह)

कार्डियो थोरेसिक सर्जिकल, वर्ना हार्ट का मतलब लोग मौत समझते थे। किसी की बाम्बे जाने की हिम्मत थी नहीं। डाक्टर गिरधारी शर्मा, डाक्टर बी.के. गोयल, ये झुंझुनूं एमिनेंट पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने कार्डियो थोरेसिक सर्जरी में बाम्बे हास्पिटल में बहुत नाम किया। यह शुरुआत हुई। उस समय हम मांग किया करते थे, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, हार्ट के वाल्व के लिये दस हजार रुपये दे दीजिये। 1993 में, दूसरा वाल्व है, उसके लिये दस-दस हजार रुपये मिलते थे। जिस तरह से माननीय अशोक गहलोत साहब ने एक बड़ा दिल रखते हुए हार्ट, कैंसर और किडनी की दवाएं फ्री कीं। माननीय सभापति महोदय, घर बर्बाद हो जाते हैं, इनके इलाज में घर बर्बाद हो जाते हैं। हार्ट में, किडनी फेल्योर में, किडनी ट्रांसप्लांट में, कार्डियोलाजी में। शुरूआत हुई और मैं सभी साथियों को एक डाक्टर होने के नाते यह बताना चाहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने एंजियोग्राफी फ्री कर दी, फ्री कर दी, फ्री कर दी। जितने भी हाउस में माननीय सदस्य बैठे हैं, मेरा एक सजेशन है, as a doctor, जो 60 साल से ऊपर है, उन सबको हमारे सीटी-एंजियो करवाना चाहिए और मैं यह बताना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, भगवान न करे, बहुतों के ब्लाक निकलेंगे।

श्री सभापति: डराकर मारोगे क्या, डाक्टर साहब?

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फ्री किया है। मेरी, as a doctor not as a politician advise to all of you. क्योंकि आप ढाई-ढाई लाख, तीन-तीन लाख लोगों को रिप्रजेंट करते हैं यानी पूरा राजस्थान यहां पर बैठा है जो सारा कर रहा है लेकिन मास्टर को स्वस्थ रहना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, एंजियोग्राफी कोई छोटी चीज नहीं है और आपको मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की पहली एंजियोग्राफी हमारे जयपुर के डाक्टर जगत नरूला ने की थी, वर्ल्ड की सीटी एंजियोग्राफी यू.एस.ए. में, he was the first doctor. जिसने यह किया।

माननीय सभापति महोदय, यह अत्यन्त आवश्यक है कि करीब 12 हजार एंजियोग्राफी हर साल होती है। 6 हजार की एंजियोप्लास्टी होती है, स्टेंट लगते हैं, इसके अंदर एक स्टेंट हमारा करीब 54 हजार का पड़ता है और दो स्टेंट 75 हजार के पड़ते हैं। अदर स्टेट्स के आ रहे हैं। माननीय सभापति

(श्री जितेन्द्र सिंह)

महोदय, कार्डियोलाजी डिपार्टमेंट में क्रांति हो गयी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अलग से हमारा जो कार्डियोलाजी डिपार्टमेंट है इनकी आई.सी.यू. बैड बढ़ाई जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि 10 करोड़ रुपये से 50 आई.सी.यू. के बैड बढ़ाये जाएंगे in general wards, दस आई.सी.यू. ढाई करोड़ की लागत से न्यूरोलाजी डिपार्टमेंट में बढ़ाए जाएं लेकिन कार्डियोलाजी डिपार्टमेंट, माननीय सभापति महोदय, भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु दर और the main cause of the death is heart and cancer. तो इसलिए हार्ट पर विशेष नजर रखना जरूरी है और जो डायबिटिक्स होते हैं, they're prone to heart disease, they're prone to hemiplegia and they're prone to cancer. यह बहुत सारी आवश्यकता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कार्डियोलाजी को और विशेष तौर से पीडियाट्रिक कार्डियोलाजी को, पीडियाट्रिक सर्जन नहीं है तो अलग से हमारा जो हास्पिटल है जे.के. लोन में व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, the third most important, very dangerous and very costly, एक मैं यह बताना चाहूंगा कि one heart by-pass surgery is cost 50 लाख रुपये और एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में बाईपास सर्जरी हो जाती है 65 हजार रुपये में। कितना अंतर है? बहुत सारे विदेशी, मैं तो यह कह रहा हूं कि हमारा यह जयपुर मेडिकल टूरिज्म का हब बन सकता है।

माननीय सभापति महोदय, the second biggest trauma to the general public is kidney failure. जवान-जवान, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में गया तो मंत्री महोदय, 25 साल का बच्चा खतम हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा कि डाक्टरजी, इसने कोई पाउडर घोल-घोल कर पिया था, उसके कारण दोनों किडनी डैमेज हो गयीं। जो यह दर्द की गोलियां, बार-बार हरी गोली लेते रहते हैं तो कृपया सावधान हो जाइए। यह किडनी फेल्योर का कारण बनता है। Once kidney is failed, फिर खुदा बचा सकता है। एक किडनी है तो भी जिंदा रह जाएगा। Adolf Hitler was having one kidney. एक बहुत बड़े नेता हमारे झुंझुनूं के थे, He was also having one kidney.

किडनी डोनर, माननीय सभापति महोदय, पूरे भारत में आज 2 लाख 20 हजार लोगों को किडनी की जरूरत है। हर साल 7500 ट्रांसप्लांट होते हैं

(श्री जितेन्द्र सिंह)

और एस.एम.एस. हास्पिटल में हमारे 1997 से 482 किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं जिनमें केडेवरिक, अब एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, माननीय सभापति महोदय, जागरूकता नहीं है। घर में अगर किसी के बूढ़े मां-बाप हों, इसमें tissue matching होता है। वह tissue matching होगा माता-पिता से या भाई से या बहन से। बहन, भाई को दे नहीं सकते किडनी तो इसलिए केडेवरिक ट्रांसप्लाट, माननीय सभापति महोदय, मैंने 131 लगाया था किडनी ट्रांसप्लांट के विषय में 1993 में, अगर आपको याद हो और आपकी बड़ी मेहरबानी हुई, उस चक्कर में आपने मुझे तातीजा हास्पिटल दे दिया। बैठो डाक्टर साहब, देता हूं। मैं उस हास्पिटल के लिए धन्यवाद दूंगा। किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी में यह दर्द की गोलियां सोच-समझ कर लें। ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन जांच करवाते रहें। एक बार किडनी फेल हो गयी तो by chronic renal failure और दुबारा नहीं।

आज केडेवरिक ट्रांसप्लाट जो ब्रेन डैड लोग हैं, केडेवरिक ट्रांसप्लांट उनका होना जरूरी है लेकिन उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। जैसे ब्लड के लिए आज सब जागरूक हैं, अब शरीर का दान, यह बहुत आवश्यक है कि आपके शरीर का, आपने अख़बार में पढ़ा होगा कि कोरिडोर बना और एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, यहां से वह गया तो इसके लिए लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी कि किडनी, अपने अंग दान के लिए उनको लिखना चाहिए। जैसे माताएं, दुग्ध बैंक बनी हुई है मदर्स की तो किडनी, भगवान जब भी अंतिम समय दे तो हमें सोचना है। जिस तरह से ब्लड डोनेशन करते हैं उसी तरह से हमें हमारे अंग दान के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, नहीं तो यह लोग तड़प-तड़पकर किडनी ट्रांसप्लांट होने के इंतजार में रह जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, the fourth important thing is diabetes. हमारे वर्ल्ड की 25 परसेंट डायबिटिक्स इंडिया में है। 60 लाख लोग अकेले राजस्थान में डायबिटीज के हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद, माननीय सभापति महोदय, राजा अजीत सिंहजी जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजा थे, वह स्वामी विवेकानंदजी को लेकर आए थे। उस समय स्वामी विवेकानंदजी को कोई नहीं जानता था। उनका नाम था विविदिशानंद, स्वामीजी उनके पास 6 माह रहे, उनका बहुत शानदार म्यूजियम बना हुआ है और फिर यहां से शिकागो गये, महाराजा अजीत सिंहजी ने उनको शिकागो भेजा। Swami Vivekananda Ji was diabetic. एक पाउडर रखा हुआ था

(श्री जितेन्द्र सिंह)

उनके म्यूजियम में तो मैंने पूछा कि यह क्या है? अमरीका में जब गये थे तो डायबिटीज थी तो वहां से यह पाउडर लेकर आए हैं शुगर फ्री, in the age of 39, स्वामीजी चले गये। आज इम्पोर्टेंट है कि डायबिटीज से किस तरह से बचाया जाए। खान-पान, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर चैक-अप, आप physically docile habits न रखें, मार्निंग वॉक करें, खाने में वसा का कम प्रयोग करें तो यह आज सबसे ज्यादा डायबिटीज क्यों है? यू.एस.ए., चाइना के बाद इंडिया का नम्बर है और इंडिया में राजस्थान का भी बहुत बड़ा नंबर है तो आज यह आवश्यक हो गया कि हमारे, and it is a genetic disease, ट्रांसफर होती है, पिताजी डायबिटिक है, मदर डायबिटिक है, 50 percent of the family are supposed to be diabetic. तो हमें उसी समय बहुत सावधान हो जाना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने खुद विजिट किया है एस.एम.एस. हास्पिटल को, यहां का जो एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट है, लैब है, वह भारत के अच्छे लैब्स में से एक है, मैं आपको यह बताना चाहूंगा। यह बड़े गर्व की बात है। बहुत रिसर्च हो रही है डायबिटीज के ऊपर और वह वहां पर वर्ल्ड में भी उनका रिकागनिशन है, यह बहुत अच्छा है।

नम्बर-5, माननीय सभापति महोदय, the cause of highest death in our Country is cancer. मुझे एक दिन याद है। मैं मेरी क्लिनिक पर बैठा था तो एक सज्जन नीचे बैठे थे, पीले हो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि who're you? उन्होंने कहा कि डाक्टर साहब, मैं आई.ए.एस. हूं। मैं दिल्ली में पोस्टेड हूं। इकलौता लड़का हूं यह मेरे बूढ़े मां-बाप बैठे हैं and I'm at the last stage of cancer, भगवान के लिए इनको मत बता देना, मेरी जिंदगी डाक्टर साहब, बहुत छोटी है। वह सीनियर आईए.एस. आफिसर, just in the age of 30, he passed away. What're the causes of cancer? यह अचानक बढ़ गया। यह गंगानगर में एक मेडिकल कालेज है। रेल आती है पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस, हमारे पेस्टीसाइड फ्रूट्स में डल रहे हैं, this is the cause of cancer. हमारे पीने का जो प्लास्टिक का कप है, इसको सावधान होकर पीएं, फेंक दो इसको। कांच को रख लो, कुल्हड़ को रख लो। That causes cancer and diabetes. इसलिए सरकार ने जो यह बंद किया है प्लास्टिक, उसको बहुत सीरियसली लेना है। सभी साथी इससे सावधान रहें,

(श्री जितेन्द्र सिंह)

this plastic cup is a horror. इसको बंद करें। इसमें कैंसर के लिए माननीय सभापति महोदय, हमारे टोबैको में सबसे पहले हमारे यूनिसेफ ने राजस्थान को फर्स्ट स्थान दिया है, हमको एप्रीशिएट किया है। टोबैको पर, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो तंबाकू बंद की योजना चलाई, वह हाइएस्ट कैंसर, वह लंग कैंसर है, माननीय सभापति महोदय, स्मोकर्स के होता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बंद किया, इसकी मुहिम चलाई तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि यह हमको बंद करना है क्योंकि इतनी बड़ी हर साल साढ़े तीन लाख लोग, माननीय सभापति महोदय, कैंसर से चले जाते हैं।

एस.एम.एस. हास्पिटल के अंदर बहुत शानदार बिरला कैंसर सेंटर है, जिसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। इसमें, सभापति महोदय, बहुत जरूरी है। महिलाएं शर्म के मारे नहीं बता सकतीं, the highest cause of death in women is cancer of uterus तो उनको सावधान होना चाहिए। breast cancer and uterus cancer are very common, कोई भी ग्लेंड हो तो उनको सावधानी रखनी चाहिए। मैं तो मेरे सजेशन दे रहा हूं और यह पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा। सभापति महोदय, एक बार कैंसर हो गया तो कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत सारे केसेज देखे हैं। एक केस मेरे अपने मित्र की पत्नी थी, ब्रेस्ट कैंसर था, आज उन बातों को 25-30 साल हो गये। मेरे परिवार से एक मेरी भांजी थी and she had cancer और उसको 30 साल हो गये, and she is surviving अगर समय पर कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है तो यह लाइफ सेविंग है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम जो कैंसर के मेन रीजन हैं, उनको करें।

And the second biggest cause of the death is dust. हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो कोल है, सांस की बीमारियां, सभापति महोदय, सबसे ज्यादा राजस्थान में है। राजस्थान में भी विशेष तौर से शेखावाटी और मेरे बाड़मेर, जैसलमेर में जहां पर धोरों में रेत उड़ती है। आज टोबेको में 80 प्रतिशत लंग्स कैंसर होता है। सभापति महोदय, बहुत आवश्यक है कि अलग से माननीय मंत्री महोदय, गौर करें जरा। मंत्री महोदय, एस.एम.एस. हास्पिटल में एक्सपर्ट नहीं हैं आपके respiratory medicine, pulmonary medicine, आप अलग से रोटेशन पर भेजें। वही हाल हो रहा है जो कार्डियोलाजी मेडिसन में घुसी हुई थी, बाहर ही नहीं निकली तो आप एक टीम रोटेशन पर भेज दें और सफिशिएंट है और उसके अंदर अति आवश्यक है कि जो हमारे टी.बी. की

(श्री जितेन्द्र सिंह)

डाट्स दवा है, अब माननीय सभापति महोदय, इसका समय रिड्यूज करके इसको इन्होंने आठ सप्ताह का कर दिया।

सभापति महोदय, टी.बी. किसी वक्त में राजयक्ष्मा कहलाती थी। बड़े-बड़े लोग चले गये। रामानुजम् द ग्रेट मैथेमेटिशियन, कमला नेहरू, हमारे खेतड़ी की सारी रायल फैमिली except Ajit Singh Ji, they died of tuberculosis. इलाज नहीं था। स्ट्रेप्टोमाइसिन सैकिण्ड वर्ल्ड वार में आया। पेनिसिलिन सैकिण्ड वर्ल्ड वार में आया और आज सारा क्योर है, यह जो डस्ट और उसमें घूमते हैं, उनको सावधान करें। एक बार चूने की फैक्टरी में या पत्थर की फैक्टरी में अंदर आपके जम गया सिलिकोसिस, माननीय चले गये, सिलिकोसिस, आपके लंग्स जो रबर की तरह होते हैं, वह पत्थर की तरह हो जाएंगे।

श्री सभापति: संक्षिप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): इसलिए हमें उस बात की बहुत जरूरत है कि इसके अंदर हमें ध्यान करना चाहिए। सभापति महोदय, नये-नये मेडिकल कालेज खुल रहे हैं। बहुत बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के समय में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी। मैं उसका मिनिस्टर भी था, तो हमारे यहां स्टाफ नहीं है। इधर के डाक्टर उधर, उधर के डाक्टर इधर। नई भर्ती कीजिये, माननीय मंत्री महोदय, आर.पी.एस.सी. से और यह जो नये-नये सात मेडिकल कालेज बने हैं, सीकर में, चूरू में, सब जगह, उन सबको अगर यह टीम नहीं मिलेगी, आर पी एस सी से आप भर्ती कीजिये इमिजिएटली, नहीं तो अगर मेडिकल कालेज का एक बार स्टैण्डर्ड गिर गया तो दुबारा कोई संभालने के लिये नहीं आएगा।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना है। यह अपने आप में बहुत आवश्यक है और 608 तरह की दवाइयां माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने स्तर पर चालू कीं और बहुत बड़ा बजट करीब एक करोड़ लोग मुफ्त दवा से लाभान्वित हो रहे हैं और 1200 करोड़ हमारी मुफ्त दवा योजना में एनुअल खर्चा हो रहा है, जो अत्यन्त आवश्यक है। सभापति महोदय, हमारा डाक्टर और पेशेंट का रेशो है 10 हजार पर एक।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): लास्ट है। 10 हजार पर एक है। इसको

(श्री जितेन्द्र सिंह)

बढ़ाना पड़ेगा और सभापति महोदय, आपने समय दिया और जो मैं कह सकता था, बेस्ट पासिबिल मैंने कहने की कोशिश की। बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा स्वास्थ्य और सफाई पर चर्चा के लिये मुझे भाग लेने का आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया था तो मैंने निवेदन किया था, सभापति महोदय, कि दूदू ऐसी जगह बना है, जहां राजस्थान के तीन संभाग के लोग आते हैं और आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है। वहां पर ब्लड बैंक नहीं है और बड़ा हास्पिटल नहीं है, डाक्टर नहीं है। इस पीड़ा को मुख्य मंत्रीजी ने समझा। वह केवल दूदू की जनता के लिये ही नहीं, राजस्थान के तीन संभाग के लोगों के लिये उन्होंने मुझे तीन उप जिला अस्पताल अपने जवाब में उन्होंने खोलने की घोषणा की और ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने आज राजस्थान का जो बजट प्रस्तुत किया, वैसे भी मुख्य मंत्रीजी, तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं। अशोक जी गहलोत का इतिहास रहा है कि गरीब को गणेश मानकर, चाहे कोई विभाग हो, हर विभाग में कार्य योजना आम आदमी और गरीब को केन्द्र बिन्दु मानकर उन्होंने योजना बनाकर राजस्थान की जनता को दी है। इस राजस्थान में जब कभी भी गरीब आदमी हास्पिटल में जाया करता था, बहुत महंगे इलाज होते थे। पहली बार बी.पी.एल. परिवारों के लिये नि:शुल्क योजना अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में लागू की और असाध्य बीमारियां - कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी पूरे राजस्थान के गरीबों को इलाज के लिये, उनके प्राण निकल जाते थे, लेकिन अशोक जी गहलोत ने रास्ता दिखाया और राजस्थान में बी.पी.एल. के लिये नि:शुल्क दवा योजना लेकर आये।

आदरणीय सभापति महोदय, जो लोग बी.पी.एल. में नहीं हैं, प्रदेश में बी.पी.एल. सर्वे होता है, कई बार ऐसे गरीब लोग छूट जाते थे, जो गरीब तो हैं, लेकिन उनका किसी कारण से बी.पी.एल. में चयन नहीं हुआ, उनके लिये भी अशोक जी गहलोत ने सोचा और मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष योजना

(श्री बाबूलाल नागर)

राजस्थान में शुरू की। इसके साथ ही जिनकी एक लाख रुपये तक की आमदनी थी, दो लाख रुपये तक असाध्य बीमारियों का इलाज भी उन्होंने अपनी कांग्रेस सरकार के समय में शुरू किया।

सभापति महोदय, आज मुझे इस बात की खुशी है कि प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। आज यह जनता क्लिनिक की घोषणा, मेरे बहुत-से साथियों को लगता है कि कैसे यह सफल होगी। जब निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में शुरू की थी तो इसी सदन में पक्ष-विपक्ष के लोगों ने बहुत शंकाएं व्यक्त की थीं और वह सोच रहे थे कि पूरे राजस्थान की जनता को किस तरह से निःशुल्क दवा उपलब्ध होगी, इतनी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, लेकिन जिस मंशा के साथ अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में यह जनता क्लिनिक खोलने की जो घोषणा की है, इससे निश्चित रूप से आम आदमी और आम गरीब को अपने मौहल्लों में, गलियों में इलाज का मौका मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा यह जनता क्लिनिक उन छोटे-छोटे मौहल्लों में, गलियों में खोलने की सरकार की मंशा है। इस जनता क्लिनिक में आम लोगों को जागरूक करने का भी काम होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जिनकी अगर थोड़ी बहुत सावधानी बरती जाए और उन बीमारियों के लिये क्या-क्या ऐसे रास्ते अपनाये जाएं, क्या-क्या ऐसी व्यवस्था की जाए कि बीमारियां ही पैदा नहीं हों, तो मैं समझता हूं लोगों में इसकी जागृति आएगी।

मुख्य मंत्रीजी ने निःशुल्क योजना में दवाइयां बढ़ायीं। मेडिकल कालेजों में जांच बढ़ायी, इसके लिये तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

पिछली सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आये, इसकी भी मैं तारीफ करता, लेकिन यह भामाशाह स्वास्थ्य योजना आम आदमी के लिए है, राजस्थान के लोग इसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, इसको खाद्य सुरक्षा से जोड़ा। अब खाद्य सुरक्षा से जोड़ा, यह तो एक सरकारी कानून-कायदा हो सकता है, लेकिन जिन लोगों का गेहूं बंद हो गया और वह इस भामाशाह योजना से वंचित हो गये। गेहूं किन लोगों का बंद होता है, गेहूं, जो गरीब आदमी हो, जिसको राशन का डीलर गेहूं नहीं दे, कहीं उसके पोस मशीन नहीं चले, कहीं

(श्री बाबूलाल नागर)

किसी का अंगूठा नहीं मिले, कहीं दुकान खुली नहीं हो तो उस आदमी का कोई दोष नहीं है। उसको भामाशाह का आपने कार्ड बना दिया, लेकिन जिसको गेहूं मिल रहा है, उसी का इलाज होगा। इससे राजस्थान के गरीबों को इतना बड़ा नुकसान हुआ, सभापति महोदय, राजस्थान के लाखों लोग, जो गरीब लोग थे, जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए था, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। मैं इस अवसर पर आपको यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह नि:शुल्क दवा योजना या भामाशाह योजना, एक अच्छी योजना है, लेकिन इसकी कार्य योजना बनाते समय आम गरीब पर इसके जो प्रभाव हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।

इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि आज कैंसर, हार्ट अटैक और किडनी की बीमारी है, कैंसर के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान में लीनियर एक्सीलरेटर मशीन जोधपुर में स्थापित करने की बात की है। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राजस्थान के हर संभाग मुख्यालय पर यह मशीन होनी चाहिए। आज कैंसर एक ऐसी बीमारी है, हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज कराने का मौका ही नहीं मिलता। सभापति महोदय, आज जवान-जवान लड़के जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनको इलाज कराने का अवसर ही नहीं मिलता है। राजस्थान में लोक कल्याणकारी सरकार है और जब इतनी बड़ी योजना, आम गरीब को केन्द्र बिंदु बनाकर यह सरकार योजना लेकर आ रही है, पूरे राजस्थान की जनता की, पूरे राजस्थान के गरीबों, आम आदमी की दवा नि:शुल्क कर रही है, तरह-तरह की अन्य योजनाएं लेकर आ रहे हैं। यह जो जांच है, सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कैंसर, हार्ट अटैक और किडनी की जांच चाहे आप संभाग मुख्यालय पर कराओ लेकिन साल में एक बार पूरे राजस्थान की जनता को आप यह अधिकार दो कि जब चाहे तब अपने शरीर की जांच कराएं। अगर उसको यह पता पड़ जाएगा कि मेरे कैंसर की संभावना है, मेरे हार्ट अटैक होने की संभावना है या मेरे कुछ प्राब्लम आ रही है तो कम से कम वह इलाज करा लेगा और उस बीमारी से आगे पीड़ित नहीं होगा। इतना बड़ा जो आप खर्चा कर रहे हैं, उससे भी निजात मिल जायेगी।

मुख्य मंत्री जी ने मिलावटखोरी पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना बनायी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें उन्होंने खाद्य विभाग, चिकित्सा विभाग दोनों का कार्य दल बनाने की बात की है। पिछली बार कांग्रेस सरकार

(श्री बाबूलाल नागर)

थी उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चालू किया था, उसमें सात विभाग को जोड़कर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की कार्य योजना में सात विभाग जोड़े थे। सभापति महोदय, जब सात विभाग के लोग एक साथ किसी भी निरीक्षण पर जाते हैं, चाहे हैल्थ डिपार्टमेंट के लोग, हैल्थ आफिसर उसमें निरीक्षण करता है तो सातों ही विभाग के लोग एक साथ मिलकर गड़बड़ नहीं कर सकते, इसमें पुलिस की भी जरूरत पड़ती है। इसमें हमारे बीजों की भी जांच होती है, इसमें खाद्य सामग्री की भी जांच होती है इसलिए मैं चाहूंगा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जैसा किया इसी तरह, चाहे आप खाद्य विभाग को जोड़ो या नहीं जोड़ो या चिकित्सा विभाग को ही चलाओ लेकिन सात विभाग की एक कमेटी होनी चाहिए और सातों को मिलकर प्रदेश में मिलावट को रोकने का काम हाथ में लेना चाहिए।

सभापति महोदय, मिलावट के सम्बन्ध में मेरा अनुभव रहा है। सैम्पल लेने के लिए आज राज्य सरकार के पास सैम्पल लेने वाले कर्मचारी नहीं हैं, आज खाद्य निरीक्षक ही नहीं हैं। पूरे प्रदेश में आज खाद्य निरीक्षकों के ही पद खाली पड़े हैं और जिन लोगों को सैम्पल लेना चाहिए वह कर्मचारी आज नहीं हैं। इस अवसर पर मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि चिकित्सा, शुद्ध सामग्री, मिलावट पर अंकुश, ये स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज पूरे राजस्थान में जितने संभाग हैं, आपकी प्रयोगशालाएं हैं आपकी पीएफए में जांच करने वाली लेकिन आज वह कार्यरत नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, उनका पूरा तंत्र ही नहीं है, पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर यह लैबोरेटरीज होनी चाहिए जिससे कि खाद्य सामग्री पर, इन पर नियंत्रण हो सके।

सभापति महोदय, जब पिछली कांग्रेस सरकार थी तब राजस्थान में चल प्रयोगशाला शुरू की गई थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन प्रयोगशालाओं को चाहे कानूनी मान्यता नहीं थी लेकिन ये जागरूकता का बहुत बड़ा काम करते थे। हर जिले में एक चल प्रयोगशाला थी, दो मिनट में सामग्री में मिलावट है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है, नि:शुल्क पूरे राजस्थान में चल प्रयोगशाला शुरू हुई थी, मुझे नहीं पता कि किस कारण से ये बंद कर दी गयीं लेकिन मैं चाहूंगा कि चिकित्सा मंत्री जी, राजस्थान में चल प्रयोगशाला शुरू करें जिससे आम आदमी जो भी कहीं सामान खरीदे, उसको यह नि:शुल्क व्यवस्था हो। इससे जागृति आती है और जो दुकानदार हैं उन लोगों पर भी

(श्री बाबूलाल नागर)

अंकुश बढ़ता है, उन लोगों में भी जागृति आती है। मैं तो यह चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में जगह-जगह व्यापार मण्डल बने हुए हैं, सरकार के पास अगर तंत्र कम है तो समन्वय बनाकर राजस्थान के जो व्यापार मण्डल हैं, अपने स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र में छोटे स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित करें, उसको प्रमाणित कराएं और उसके बाद उन दुकानों पर खाद्य सामग्री बिके तो मैं समझता हूं कि कम से कम आम आदमी को शुद्ध सामान मिल सकता है।

सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सरकार को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम हाथ में लेने चाहिए। टीकाकरण, संक्रमण रोग, ये जितनी भी मौसमी बीमारियां हैं अगर सरकार समय पर अभियान चलाये तो बहुत सी बीमारियों पर नियंत्रण हो सकता है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बीमारी के सम्बन्ध में जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, चाहे हमारे सैकण्डरी तक एजुकेशन हो, प्राइमरी तक एजुकेशन हो, ऐसी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, किन सावधानियों की जरूरत है, यह पाठ्यक्रमों में भी शामिल करना चाहिए जिससे बच्चों में जागरूकता हो और बहुत सी बीमारियों से निजात मिल सकती है।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि पहले राज्य में बहूद्देशीय कार्यकर्ता एमपी.डब्ल्यू., इनका प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। चेचक, हैजा, प्लेग, मलेरिया, मलेरिया का कंट्रोल, पोलियो के नियंत्रण के लिए बहुत बड़ी सफलता जो हमारे एम.पी.डब्ल्यू. के कार्यकर्ता हैं इन्होंने राजस्थान में साबित की थी। पिछले तीन साल से एम.पी.डब्ल्यू. के कार्यकर्ताओं की भर्ती बंद हो गयी जिसके कारण आज गांवों में संक्रमण बीमारियां, मलेरिया, पोलियो यह जो जगह-जगह बीमारियां फैलती हैं, लोगों में जागृति नहीं आती जिसके कारण लोगों को बीमार होना पड़ता है।

सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जिस तरह से सी.एल.जी. बैठक होती है, क्योंकि आज हमारे चिकित्सकों में और हमारे आम व्यक्तियों में, जो मरीज हैं इनमें भी समन्वय और समझ की आवश्यकता है, सी.एल.जी. बैठकों में चिकित्सा विभाग को भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे उनका समन्वय बने। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में डाक्टर लगा देते हैं लेकिन वे अधिकतर वहां ठहराव नहीं कर पाते हैं। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई एम.बी.बी.एस. की डिग्री ले लेता है उसके बाद एक निश्चित समय तक उसको गांवों में रहना पड़ेगा और गांव में रहने के बाद ही चाहे पी.जी. करता है या उसको अन्य कोई आर्थिक लाभ मिलता है, तो चार साल का, पांच साल का उसका निश्चित कार्य तय करना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मेरे क्षेत्र में फागी में सी.एच.सी. है, वहां की स्थिति बहुत खराब है। प्रदेश में जितनी भी सी.एच.सीज. हैं वहां न कोई बेहोशी का डाक्टर है, न वहां कोई सर्जन है, न वहां पर फिजिशियन है, वहां पर गाइनी की कोई डाक्टर नहीं है, ऐसी बुरी हालत है तो सी.एच.सीज. का क्या मतलब है? यह सी.एच.सीज. लगातार खुल रही हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, अब जिस सी.एच.सी. में गाइनी नहीं हो, बेहोशी का डाक्टर नहीं हो और सर्जन नहीं हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही बढ़िया है तो इसलिए मैं चाहूंगा सरकार की कार्य योजना में कम से कम यह तीन तरह के डाक्टर हर सी.एच.सी. में आवश्यक रूप से हों। और जो लोग लग भी जाते हैं प्रतिनियुक्ति के अपने अड़ंगे में वहां से तत्काल आपके शहर में आ जाते हैं, तनख्वाह वहां से उठाते हैं और वहां अपनी उपस्थिति दे देते हैं। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं बात शुरू करूं उसके पहले एक निवेदन कर दूं। आज चिकित्सा पर डिमाण्ड है और हम सब मिलकर चिकित्सा क्षेत्र में कोई दलगत राजनीति की बात नहीं करके सीधी-सीधी मरीज के हित की बात करें।

माननीय सभापति महोदय, हमको अगर बीमारी को रोकना है तो दो तरफा प्रयास करने होंगे। पहला, बीमारी फैले ही नहीं या उस पर अंकुश लग

(श्री ज्ञानचंद पारख)

जाए, कम फैले। मैं एक निवेदन करूंगा कि गंदगी के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जब से स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की है। जिस तरह से सफाई व्यवस्था दिनों दिन सुधर रही है, तो उसका परिणाम भी आया है। पहले की तुलना में चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, स्वाइन फ्लू हो, पीलिया हो, अनेक बीमारियां जो गंदगी से होती हैं, उसमें काफी कमी आई है। हम भी नरेन्द्र मोदी के उस अभियान के साथ अपने आपको जोड़कर हमारे प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे तो बीमारियों से मुक्ति मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं उज्ज्वला योजना की बात करूंगा। फ्री गैस कनेक्शन दिए, वह बड़ी बात नहीं है। हमारी माताएं, बहनें ग्रामीण क्षेत्र की, जो वर्षों से लकड़ी से चूल्हा जलाती थीं, उनकी आंखों में धुआं जाता था। उससे आंखें खराब होती थी। धुआं जाने से फेफड़े भी खराब होते थे। सांस की प्रोब्लम होती थी। टी.बी. भी उससे होती थी। आज गैस का चूल्हा आ गया, तो कई माताओं, बहनों की आंखें खराब होनी बंद हो गई। सांस की बीमारी से वह मुक्त हो गईं। इस दिशा में भी हमको प्रयास करना होगा।

माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे नहीं हैं। हमें 'शुद्ध के लिए युद्ध' की शुरूआत भी वापस करनी पड़ेगी। जैसी एक बार बाबूलाल जी ने पहले की थी। बीमारियों की अधिकांश वजह यह मिलावटी चीजें हैं। अगर मिलावटी चीजों पर प्रभावी अंकुश लग जाए और हर व्यक्ति को शुद्ध खाना मिले तो शायद कई बीमारियों से हम बच जाएंगे। चाहे हार्ट का, चाहे कैंसर का, चाहे शुगर का रोगी है, अधिकांश कोई न कोई दूषित चीज खाते हैं, उसके कारण ही अपने शरीर में बीमारियों को पालकर बैठ जाते हैं। सरकार से आग्रह रहेगा कि एक अभियान चलाकर हम मिलावटखोरों के खिलाफ जितनी कठोर कार्यवाही कर सकें, उतनी करनी चाहिए। इससे बीमारियों से हमें निजात मिल जाएगी।

सभापति महोदय, हमारे पास फूड इंस्पैक्टर भी हैं। करते क्या हैं, मुझे नहीं पता। मुझे भी आज 21 साल हो गए, शायद 21 लोगों को भी कभी उन्होंने सज़ा नहीं दिलवाई होगी जबकि मिलावट के हजारों केस आज हमारी आंखों के सामने हैं। मेरा जिला बहुत बड़ा गवाह है। सुमेरपुर में नकली घी का व्यवसाय कितनी तेजी से हो रहा है। हमारे दुधारू पशु कम हो रहे हैं और घी जितना चाहें उतना बाजार में उपलब्ध है। इस नकली घी की वजह से जो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

बीमारियां फैल रही हैं, उसमें हार्ट की बीमारी विशेष तौर से हैं। इस दिशा में भी हमको कोई न कोई प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि यह मिलावट का गंदा खेल खतम हो जाए।

सभापति महोदय, हमें पर्यावरण पर भी जोर देना होगा, यदि बीमारियों में कमी लानी है तो। मैं वापस धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी को कि हमारा अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। मात्र यह आदेश नहीं दिया कि एक बूथ पर आपको 100 सदस्य बनाने हैं, इसके साथ में हमको पाबंद भी किया कि जिसको भी आप सदस्य बनाओगे, साथ में एक पौधा उसको भेंट करके पाबंद करोगे कि उस पौधे को वह जीवित रखे। इतना पाबंद किया है। एक बूथ पर सौ-सौ पौधे लगाने की बात भी कही है। अगर हरा-भरा राजस्थान हो जाएगा तो आज आपके जितने अस्पताल छोटे पड़ रहे हैं, यह सारे खाली नजर आने चालू हो जाएंगे। इसलिए पर्यावरण पर भी हमें बहुत जोर देना होगा।

सभापति महोदय, बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण भी हमारे अस्पतालों में भारी भीड़ रहती है। बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। प्रभावी कार्यवाही भी जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की। आपको पता होगा जब यह किशनगढ़ से लेकर जयपुर तक 6 लेन नहीं बना था, उसके पहले इस रोड पर 1 साल में 1 हजार से ज्यादा व्यक्ति दुर्घटनाओं में मौत के शिकार हो जाते थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। बाद में जब 6 लेन बन गया, तो मरने वालों की संख्या 100 से भी कम आ गई, 10 से भी कम पर आकर अटक गई। दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण हमारा बेतरतीब इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसको भी दुरुस्त करें। इससे जब यह ट्रोमा सेंटर की मांग बार-बार उठती है तो उसमें कमी आ सकती है।

सभापति महोदय, यह बढ़ती आबादी, जनसंख्या जो है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय संजय गांधी जी को, आज से 44 साल पहले उन्होंने इस समस्या की गंभीरता को भांप लिया था। उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की और दनादन नसबंदियां चालू कर दी थीं। अगर वह हमारे बीच में होते तो शायद हमारी जनसंख्या 100 करोड़ के अंदर रह जाती। आपके नेता थे। वह आपके और

(श्री ज्ञानचंद पारख)

हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन जो उन्होंने देश के बारे में सोचा, उसको करने का दायित्व हमारा बनता है। फर्ज हमारा बनता है। हम बिना किसी से डरे जनसंख्या के नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाएं। यहां चिकित्सा मंत्री जी हैं नहीं, मैं तो उनको आग्रह करूंगा, उनके विभाग से जुड़ा हुआ यह विषय है। आप तो राजस्थान से शुरूआत कर दो। चिंता ही मत करो। पूरे देश में आपका नाम हो जाएगा। शुरूआत भी आपके विभाग से करो कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, जो भी सरकारी सुविधाएं चिकित्सा की मिलती हैं, वह सारी की सारी उसकी बंद कर दो। वह या तो नसबंदी करा ले या सुविधाएं बंद करा ले। आप तो दोनों में से एक काम करवा दो। इससे हमें बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी।

सभापति महोदय, इतना भी कहूंगा, मान लो आपने जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभावी अंकुश लगाया, कोई कठोर कार्यवाही की और उस कठोर कार्यवाही के चलते माननीय मंत्री महोदय पर कोई कार्यवाही हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहां अभी भर्ती चालू है। सतीश जी बैठे हैं, भर्ती कर लेंगे। अभी जगह-जगह भर्ती चल रही है। लेकिन प्रभावी कार्यवाही निश्चित रूप से हो जाए, यह मेरा आग्रह रहेगा।

सभापति महोदय, अब जहां तक सरकारी योजनाओं की बात है। इसमें हर सरकार प्रयास करती है। इसमें यह नहीं कि मैंने कम किया, उसने ज्यादा किया, ऐसा कुछ नहीं है। हर सरकार प्रयास करती है कि बीमार व्यक्ति की, मरीज की ज्यादा से ज्यादा मदद सरकारी स्तर पर कैसे हो सके। शुरूआत में हमने बीपीएल के जरिए इसको चालू किया। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनको नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिल जाए।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अशोक जी गहलोत को जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में नि:शुल्क दवा योजना और नि:शुल्क जांच योजना की शुरूआत की। मुझे धन्यवाद देने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई हर्ज भी नहीं है। मैं उनकी कोई कमी भी नहीं निकालता हूं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर था कि जितना फायदा आप देना चाहते थे, दे नहीं पाए। आपने शुरूआत की। आपकी मंशा अच्छी थी लेकिन हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने जो भामाशाह बीमा योजना के नाम से काम किया, हिन्दुस्तान में राजस्थान पहला राज्य बना जहां इस तरह की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध थी। पहले तो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मात्र नि:शुल्क दवा मिलती थी। आपरेशन का पैसा लगता था। मैं भी हार्ट के आपरेशंस करवाता हूं। मुझे पता है। हार्ट के एक भी मरीज का, एक भी पैसा नि:शुल्क दवा के बावजूद भी उसकी आपरेशन की लागत में से कम नहीं हुआ था। जबसे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, हजारों लोगों ने मात्र सरकारी अस्पतालों में नहीं, जहां कभी कोई गरीब जाने की सपने में भी नहीं सोच सकता था, ऐसे 5 स्टार श्रेणी के निजी अस्पतालों में, अपना कार्ड लेकर के बेखौफ चला जाए, इलाज भी पूरा का पूरा फ्री और खाना भी फ्री। मैंने खुद ने इस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से लगभग 700 से ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी करवा दी। यह कोई मामूली बात नहीं है। अन्यथा तो यह बहुत मुश्किल काम था। यह सौगात हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री जी की थी।

सभापति महोदय, समय के साथ-साथ कुछ कमियां महसूस होती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि कुछ कमियों को भी आप दुरुस्त कर देंगे तो जो कार्डधारी मरीज हैं, जिनके पास भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का कार्ड है, उसको थोड़ी और राहत मिल जाएगी।

(14.00 बजे)

माननीय मंत्रीजी, कोई मरीज यदि भामाशाह बीमा योजना के माध्यम से किसी निजी अस्पताल में अपना आपरेशन करवाना चाहता है, आपरेशन फ्री में होता है पर जांच उसको बाहर पैसे देकर करवानी पड़ती है। उसको यदि वहां पर ब्लड की जरूरत है, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी में कम से कम चार यूनिट ब्लड लगता है। सरकारी ब्लड बैंक में भी यदि वह ब्लड लेने जाता है, खुद का ब्लड देता है तो ब्लड का चार्ज जो 1250 रुपए है एक यूनिट के, चार यूनिट चाहिए तो उसको लगभग 6000 रुपये जेब से देने पड़ते हैं। अगर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से वह किसी भी अस्पताल में अपना आपरेशन करवा रहा है तो हर सरकारी अस्पताल जो उस जिले में है वहां उसकी जांच की नि:शुल्क व्यवस्था का आप प्रावधान कर दें, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुभव बताता हूं आपको। आपका जो हिप रिप्लेसमेंट है, कूल्हा प्रत्यारोपण का काम, यह पहले भामाशाह योजना में था और बाद में एक परिवर्तन कर दिया उसमें यदि दुर्घटना में हिप टूटेगा तो ही भामाशाह बीमा योजना में कवर होगा। जिसका हिप खराब हो गया,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

चलने-फिरने में असहाय हो गया, ऐसे एक नहीं 30 से 40 साल की उम्र के बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे। तो ट्रोमा से ही हिप टूटे उसका ही नहीं, हिप यदि और कारणों जैसे घिस गए हों, खराब हो गए हों, तो उसका भी हिप बदलना जरूरी है, कूल्हा बदलना जरूरी है। उसमें यह प्रावधान वापस जोड़ दें मेहरबानी करके, बीमा कम्पनी उसका पैसा भी अस्पतालों को दे दे और अस्पताल वह आपरेशन कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, पहले इसमें क्यू-लेसिक भी था। हमारी जो छोटी बच्चियां हैं, 18-20 साल से कम उम्र की, नजरें कमजोर है उसकी, आंखों से कम दिखता है, लम्बा चौड़ा चश्मा लगता है नजर का, पहले प्रावधान था इसमें, नि:शुल्क करने का, बाद में पता नहीं बीमा कम्पनियों के दबाव में आकर हमारे अधिकारियों ने उसको निकाल दिया तो ऐसी सैकड़ों बच्चियां होंगी एक-एक जिले में, एक-एक शहर में जिनको नजर का मोटा चश्मा लगता होगा, शादी में दिक्कत आती होगी। उसको वापस जुड़वा दें जो पहले प्रावधान था। मैं नई किसी चीज को जोड़ने की बात नहीं कर रहा इसमें। पहले था उसको ही आप वापस जुड़वा दें तो भी बहुत बड़ा काम होगा।

हम नई-नई चीज कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि हमने एंजियोग्राफी कर दी इसमें, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको। आपने सीटी स्कैन, एमआरआई की घोषणा कर दी, उसका भी धन्यवाद आपको। पर और जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी आप पूर्ति करें। जो बात अभी दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है कि इसका लाभ उसी को मिलता है जिसका खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ा हुआ है। यही दिक्कत मेरे क्षेत्र में भी आ रही है मुझे। पात्र व्यक्ति तो बहुत ज्यादा हैं, जो नियम बने हुए हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में ये-ये व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे उसको पेंशन मिलती हो, चाहे नरेगा में सौ दिन काम किया उसने, चाहे उसके पास लैबर कार्ड है, या इतनी कम भूमि है, बहुत सारे प्रावधान हैं, वह प्रावधान में पात्र है लेकिन एक सीमा तय कर रखी है, वह सीमा समाप्त होने के बाद भी इस कारण से उसका नाम उसमें जुड़ नहीं पा रहा है। मान लो दो रुपये किलो गेहूं उसको नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं, यह तो आपके हाथ में है कि जो पात्रता रखता है वह भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड लेकर गेहूं भले ही प्राप्त न करे, पर अपना इलाज सरकारी खर्च पर करवा दे, इतना काम तो हम सरकार के माध्यम से करवा सकते हैं।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, ये दवाएं, ये जांचें, सरकारी अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई वहां सारा फोकट में है, पर सरकारी अस्पतालों में जाने वाले मरीजों की संख्या निजी अस्पतालों में जाने वाले मरीजों की संख्या से बहुत कम है। जांचों के नाम पर लूट सबको पता है सब जानते हैं कि जांचों के नाम पर लूट है, कमीशनखोरी है, सबको पता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। दवाओं के कमीशन की जानकारी भी सभी को है, हमको कोई न कोई कठोर कानून बनाकर जांचों की दरें भी निर्धारित करनी चाहिए और दवाइयों की दरें भी निर्धारित होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी को पुन: धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हार्ट स्टैंट की दरों में कितनी कमी करवा दी है। कितनी कमी, कोई मामूली कमी नहीं। कैंसर की दवाइयां जो हजारों रुपयों में आती थीं, सैकड़ों से नीचे ला दिया, अंकुश लगा दिया। वह काम किये क्योंकि यह क्षेत्र ऐसा है कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। हमारे स्टेट में ऐसा कदम उठाएं कि कोई दवा कम्पनी या कोई डाइग्नोस्टिक सेंटर हमारे मरीज को लूट नहीं सके। यह काम भी हमको करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज भी बहुत बड़ी संख्या में मरीज दिल्ली या गुजरात जाकर आपरेशन करवाते हैं। हमारे पास अच्छे डाक्टरों की कमी नहीं, हमको कारण ढूंढना होगा कि क्या मजबूरी है उनकी कि यहां वे आपरेशन नहीं करवाते। आर्थोपेडिक्स में तो मैं कह दूं आपको कि साइंस कहीं चली गई, निजी और बाहर के अस्पताल कहीं के कहीं पहुंच गए और राजस्थान का एसएमएस अस्पताल जो कभी डाक्टर पीके सेठी के नाम से आर्थोपेडिक्स का सिरमौर हुआ करता था, आज आर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है हमारा यह अस्पताल। कारण एक ही है कि जितने संसाधन, उपकरण उनको चाहिए, डाक्टरों की कमी नहीं है, उनके कौशल में भी कमी नहीं है, कहीं न कहीं सरकारी स्तर पर हमको जो सुविधाएं उनको देनी हैं, साधन उनको देने हैं, उसकी कमी के चलते हुए हम निजी अस्पतालों से पिछड़ते जा रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि आर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में जो मरीज राजस्थान से बाहर जाकर अपना इलाज करवाते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी नए साधन आ गए हैं, वह उनको उपलब्ध कराएं।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, कभी आप अहमदाबाद गए होंगे तो आपने खुद ने देखा होगा कि वहां एक गली या एक मौहल्ले में पांच आर्थोपेडिक्स के हास्पिटल मिल जाएंगे, पांच।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी से मुझे समय दिया गया है उसमें मैं समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: मैं पार्टी की सीमा के हिसाब से ही कह रहा हूं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, बिलकुल, जो मुझे बताया गया है उसी में कहूंगा मैं।

श्री सभापति: अब आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आपने कह दिया। मैं अंत में खुद के क्षेत्र के अस्पतालों पर आ जाता हूं। माननीय मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, आप मेरी बात मंत्री महोदय तक पहुंचा दें। माननीय मंत्रीजी खुद पाली आए थे और पाली आकर डाक्टरों की मीटिंग ली। मीटिंग में जो समस्याएं बताईं, तो माननीय मंत्रीजी वहां पर वादा करके गए थे, आश्वासन देकर गए थे कि मैं जयपुर पहुंचने पर आपकी जो कमियां हैं, उन सारी कमियों को बहुत जल्दी ही दुरुस्त कर दूंगा। पता नहीं उनके हाथ में जादू का डण्डा है कि जयपुर आकर घुमाएंगे और सारे काम हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वे वादे या आश्वासन माननीय मंत्री महोदय ने पाली में दिए, उनमें से एक भी काम अभी तक नहीं हुआ है, एक भी काम। वह काम मेहरबानी करके करवा दो।

माननीय सभापति महोदय, दो महीने पुरानी बात है, हमारे यहां निश्चेतना विभाग में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री अमीन खां।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, उनका नाम भी 'रघु' है। हमारे यहां कहते भी हैं, 'रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई।' पर उनको परवाह ही नहीं है। उन वादों को पूरा करने का मेरा उनसे आग्रह रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26, चिकित्सा, स्वास्थ्य ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सरकार की उदासीनता देखो कि सरकार का एक भी मंत्री आसन की अगली पंक्ति में विराजमान नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए, यह आपकी चिंता की बात नहीं है। प्लीज सहयोग करें, विराजें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप सरकार को कहो तो सही कि गम्भीर रहे।

श्री सभापति: आपका बोलने का है, मैं आपको बता दूं कि जितनी देर आप बार-बार खड़े होंगे, मैं टाइम गिन रहा हूं और उतना ही टाइम आपको कम मिलेगा। (व्यवधान) धन्यवाद, प्लीज विराजिए आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिए। सहयोग करें। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की मांग पर मैं अपने अनुभव के आधार इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार चाहे हमारी रही, चाहे बीजेपी की रही, क्या कारण है कि हम लोग समझ नहीं पाए। जितने भी पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर खोले जाते हैं उनमें 60 परसेंट जगह खाली रहती है। हमारी तो समझ के अनुसार हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा इकाई आप खोलो। आप अपने बजट के अनुसार जितनी इकाइयां खोलते हैं, उस इकाई की पूर्ति करना अति-आवश्यक है और उस पूर्ति से ही सरकार पर जनता का भरोसा होता है कि यहां सब-सेंटर है तो इसमें एक एएनएम आज जरूर मिलेगी या कम्पाउन्डर मिलेगा। अधिकांश जगहों पर जाते हैं तो सारी जगह खाली मिलती हैं। इन खाली जगहों के बारे में मैं मंत्री महोदय से बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि एक भी खाली जगह नहीं रहनी चाहिए।

दूसरी बात, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम सीमावर्ती लोग बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर जैसे जिलों में रहते हैं। हमसे नजदीक जो बड़ी जगह है, वह जोधपुर है और वहां बहुत बड़े-बड़े और अच्छे डाक्टर हैं और बड़े अस्पताल हैं, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर का आदमी, चाहे किसी का एक्सीडेंट

(श्री अमीन खां)

होता है या किसी के कोई बीमारी अचानक होती है तो लोग टैक्सी लेकर गुजरात, पालनपुर, खराद, मेहसाणा, अहमदाबाद पहुंचते हैं, लेकिन जोधपुर नहीं जाते हैं और न ही बाड़मेर जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्या हमारे डाक्टरों पर, हमारी अस्पताल व्यवस्था पर लोगों का इतना अविश्वास क्यों है, इसकी सरकार को गहन जांच करनी चाहिए और गुजरात में जितने भी मरीज जाते हैं, उनके रिश्तेदार जाते हैं, वे वापस संतुष्ट होकर आते हैं।

सभापति महोदय, एक चीज मैंने खुद ने भी देखी। पिछले साल गुजरात के विधान सभा चुनावों में मुझे अशोक जी ने एक क्षेत्र में लगाया था। मैं वहां चालीस दिन तक था। मैंने हर ग्राम में सब-सेंटर जहां था, पूछा कि यहां कोई नर्स या कम्पाउन्डर है? कहीं पर भी मुझे खाली जगह की कोई इत्तिला नहीं हुई चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। मास्टर का पूछा तो भी देर-सबेर की तो गलती जरूर करते हैं, लेकिन वहां मास्टर है ही नहीं या एएनएम है ही नहीं या कम्पाउन्डर है ही नहीं, ऐसी शिकायत मैंने वहां नहीं देखी। कहने का मतलब यह है कि हमारा राजस्थान उनसे पीछे है। पीछे रहने का कारण दोनों तरफ गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें भी यही की यही हालत और यहां विधान सभा में वे कहते हैं कि हमने सब कुछ किया, आपने कुछ नहीं किया। हम कहते हैं कि हमने सब कुछ किया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन गलती रही है। फिर यह बजट जो हमसे पास कराते हैं, इसका मतलब पैसा तो आपके पास है और उन पैसों के अनुसार आपकी एएनएम क्यों नहीं है, आपका कम्पाउन्डर क्यों नहीं है, आपका डाक्टर क्यों नहीं है? आपका सब-सेंटर या पीएचसी-सीएचसी का भवन क्यों नहीं है? मेरा इतना ही कहना है कि ये जो खाली जगह हैं, ये लोगों में असंतोष फैलाती हैं और इन खाली जगहों की वजह से कई लोगों की तो बिना इलाज मौत भी हो जाती है। कई लोग इधर-उधर घूमकर के बर्बाद होते हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है कि इन खाली जगहों की पूर्ति करने का पूरा बंदोबस्त करें और सरकार के पास खाली जगह भरने की धन-दौलत की बजट में व्यवस्था नहीं है तो जगह उतनी ही खोलें जितना आपके पास धन है। चाहे कम जगह खुलती हैं तो उससे भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र शिव में 60 परसेंट डाक्टर, कम्पाउन्डर, नर्स की जगह खाली है और यह हमेशा रही है।

(श्री अमीन खां)

कोई आज की बात नहीं है। आज भी वही हालत है, पांच साल पहले भी वही हालत थी और पंद्रह साल पहले भी वही हालत थी।

हमारा यही निवेदन है कि सरकार इस चीज की ओर सख्त रहे और सक्रिय रहे। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने दवाइयां जो फ्री की हैं, उससे काफी लोगों को राहत मिली है और ये कैंसर के मरीज जो हैं, इनका वहां कोई किस्म का इलाज आज तक नहीं है, इसके इलाज के लिये भी एक्सपर्टों को कम से कम जिला हैडक्वार्टर के अस्पतालों में रखना चाहिए। बाड़मेर मेडिकल कालेज जो खुला है, उसके लिये राजस्थान के मुख्य मंत्री को बहुतबहुत धन्यवाद और इस मेडिकल कालेज में भी खाली जगह अभी नहीं भरी गयी हैं। ये सारी जगह भर दीं तो वहां की सीमावर्ती गरीब जनता को अच्छी सुविधा मिलेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आज चिकित्सा की मांग की इस चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो राजस्थान के माननीय चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वे राजस्थान के 70 साल के इतिहास में पहले ऐसे चिकित्सा मंत्री हैं, जिन्होंने अपना कार्यभार संभालने के एक वर्ष से भी कम समय में राज्य के हर जिले का दौरा किया। हर जिले की जानकारी लेने की उन्होंने चेष्टा की, प्रयास किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की गुजरात सीमा के जिले सिरोही से आता हूं। हमारे यहां रोजाना सुबह गाड़ियां लग जाती हैं मरीजों को ले जाने के लिये। लगभग हर पंचायत में एक-दो गाड़ियां लग जाती हैं और भोर होते ही वे सारे मरीज सवार होकर गुजरात चले जाते हैं अपना इलाज कराने के लिये। सिरोही जिला एक अत्यन्त महत्वपूर्ण जिला है। हमारे पास फोरेस्ट हैं, खनिज हैं, टूरिज्म है और हम बहुत अच्छा रेवेन्यू राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार को देते हैं, लेकिन इस सबके बावजूद, जितनी कमाई स्टेट और सेंटर को सिरोही जिला देता है, हमारे जिले को उसकी तुलना में विकास पर, शिक्षा पर और स्वास्थ्य सुविधाओं पर वह धन क्यों प्राप्त नहीं हो पाता है?

माननीय सभापति महोदय, 2014 का वह चुनाव मुझे याद है।

(श्री संयम लोढ़ा)

सुमेरपुर में भाजपा के प्रधान मंत्री पद के प्रत्याशी श्री नरेन्द्र मोदी जी की सभा थी और उसमें उन्होंने डेढ़ लाख लोगों को यह भरोसा दिलाया था कि आप लोग जो सुबह उठते ही तड़के गुजरात चले जाते हैं अपना इलाज कराने के लिये, मैं आपके जिले में ऐसी चिकित्सा सुविधाएं लाकर दूंगा कि आपका गुजरात जाना बंद हो जाएगा और आपको अपने ही जिले में वे सुविधाएं मिलने लगेंगी।

माननीय सभापति महोदय, जब हम हालात देखते हैं, ऊपर पहाड़ से लेकर के, खाट पर लेकर के नीचे मरीज को लेकर आ रहे हैं और राजस्थान के चारों तरफ का हम परिदृश्य देखें, किसी सरकार के कार्यकाल की बात मैं नहीं करना चाहता। बच्चे का जन्म क्या होता है, एक उत्सव होता है हमारे लिये कि परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है और जो लोग पैसे से सक्षम हैं, अपनी बेटी को पता चलते ही कि वह गर्भवती है, दूसरा महीना लगते ही हम कहते हैं- ध्यान से चलना। उसकी इतनी देखभाल में लग जाते हैं, लेकिन हम लोगों को राज में बैठाने वाली उस माता का क्या करते हैं?

इस सदन में नारे लगते हैं- 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम'। भारत माता की जय कब होगी, भारत माता क्या भूमि का एक टुकड़ा है? भारत माता क्या कोई पॉलिटिकल वाल है? जब तक हमारे घरों में रहने वाली वह माता, खेत में काम करने वाली वह माता, मजदूरी करने वाली वह माता, उसका जब तक हम ख्याल नहीं रखेंगे, भारत माता की जय नहीं हो सकती।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्या हालात हैं राजस्थान के? नीति आयोग ने इस साल की शुरुआत में देश के प्रमुख 21 राज्यों की जो अपने पैरामीटर्स पर सूची जारी की है, उसमें राजस्थान बीसवें नम्बर पर खड़ा हुआ है। पड़ौस का एम.पी. 17वें नम्बर पर खड़ा हुआ है। दो मंत्री, पिछली बार भी, इस बार भी। 6 आईएएस, 9 आरएएस और हम 20वें नम्बर पर खड़े हैं। यह आत्मलोचन का विषय है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारियों को ज्यादा वीडियो कान्फ्रेंस में बिजी मत करो, इन्हें अपने कमरे से बाहर निकालो, आप इनको टास्क दो कि उनको क्या-क्या काम करना है और महीने में रिपोर्ट लाये तथा एक-एक जगह जाकर देखें। लेबर रूम के क्या हालात बने हुए हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं 6 महीने बाद सिरोही के अस्पताल का मौका देखने गया। वहां पर एक परिचित

(श्री संयम लोढ़ा)

टांग टूटा हुआ पेशेंट मिल गया, मैंने पूछा कैसे हो। पता नहीं, क्या दिमाग में आया और मैंने उसको पूछ लिया कि यह सर्जरी कहां पर करवाई तो उसने मुझे पीएमओ की मौजूदगी में कहा कि उस प्राइवेट हास्पिटल में करवाकर आया हूं। सरकारी अस्पताल में पेशेंट भर्ती हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट वहां से ले जाकर बाहर दूसरे अस्पताल में हो रहा है, वहां सर्जरी हो रही है। क्यों हो रही है? ट्रोमा सेंटर बना हुआ है, सीआर मशीन नहीं है। यह कौन देखेगा? यह व्यवस्था कैसे हो कि हमारे अपने डाक्टर उन प्राइवेट हास्पिटलों में इलाज करना कैसे छोड़े। मैंने उस प्राइवेट हास्पिटल के मालिक को बुलाकर उसी वक्त कहा कि किसी सरकारी डाक्टर को अपने हास्पिटल में नहीं बुलाएगा। इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं।

क्या है जन्म के साथ लिंगानुपात में हमारी हालत? हम देश के 21 राज्यों में 18वें नम्बर पर खड़े हैं। क्या है हमारी स्थिति पूर्ण टीकाकरण में? हम 21 राज्यों में देश में 20वें नम्बर पर खड़े हैं। यह नीति आयोग के आंकड़े हैं, उसकी रेटिंग है, माननीय सभापति महोदय, जो देश के प्रधान मंत्री के प्रिय अध्यक्ष श्री अमिताभ कांत ने जारी किया है। नवजात मृत्यु दर में हम 18वें नम्बर पर खड़े हैं, 5 साल तक की मृत्यु दर में हम 17वें नम्बर पर खड़े हैं। जन्म के समय कम वज़न में हम 21वें नम्बर पर खड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, जो नीति आयोग ने अपेक्षा की है कि हम एनुअल इम्प्रूवमेंट लायें, उसमें भी हम 8वें नम्बर पर हैं। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य हमसे आगे है, वो 5वें नम्बर पर है। क्या परिस्थितियां बनी हुई थीं? कभी डेंगू मारक बन जाता है, कभी चिकनगुनिया मारक बन जाता है, कभी स्वाइन फ्लू मारक बन जाता है और इस देश का दुर्भाग्य है और सभापति महोदय, हमारा दुर्भाग्य है कि जब कोई गौ रक्षा का मुद्दा हो, हजारों लोग सड़क पर आ जाते हैं, कोई खराब फिल्म लगे तो हजारों लोग सड़क पर आ जाते हैं और हमारी चिकित्सा व्यवस्था ऐसी बदहाल स्थिति में खड़ी हुई है पर इस पर लोग सड़क पर आना ठीक नहीं समझते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे जो लास्ट हुआ है 5 साल से कम आयु के राजस्थान के 39 परसेंट बच्चे अविकसित हैं। शहरी इलाके में 33 परसेंट और ग्रामीण में 40.8 परसेंट और कुपोषित, अति कुपोषित बालकों की संख्या हमारे स्टेट में 4.86 लाख है और लड़कियों की संख्या 4.2 लाख है।

(श्री संयम लोढ़ा)

चाइल्ड मैरिज, अभिशाप बन चुका है हमारे स्टेट के लिए। हमारे प्रदेश की 6.3 फीसदी लड़कियां 15 से 19 वर्ष की आयु में मां बन जाती हैं या गर्भवती हो जाती हैं। इतना बड़ा प्रशासन का लवाजमा हम लेकर खड़े हैं कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हैं, हम 116 परसेंट तनख्वाह, पेंशन और ब्याज के भुगतान में खर्चा कर रहे हैं पर नतीजा क्या आया? क्या हम उनसे काम ले पा रहे हैं माननीय सभापति महोदय? 35 फीसदी पुरुष हमारे स्टेट के अन्दर 21 साल से कम उम्र में शादी कर लेते हैं। कानून बने हुए हैं, गांव में पटवारी, ग्राम सेवक, फलां, ढीकड़ा, सब लगे हुए हैं पर नतीजा क्या है?

माननीय सभापति महोदय, हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री जी, हमारी सरकार, हमारी सरकार बार-बार कर रहे थे। एक वीडियो का भी जिक्र कर रहे थे कि वो वीडियो वायरल हुआ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी स्वच्छ अभियान का जिक्र किया। उसमें महात्मा गांधी जी का चश्मा दिया हुआ है जिसमें एक पर लिखा हुआ है स्वच्छ और दूसरे पर कुछ भी नहीं है। आपने तो वह स्वच्छ पढ़ लिया पर हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री उस स्वच्छ को नहीं पढ़ पाये। वीडियो वायरल होने की बात तो कही पर उस फोटो के वायरल होने की बात भी बताते जब राजस्थान का +++ यह उसका फोटो है माननीय सभापति महोदय। मेन सड़क पर, सरकारी गाड़ी खड़ी हुई है, पी.ए. पास में खड़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो-जो माननीय सदस्य बीच में इंटरवीन करेंगे, समय नहीं दूंगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 00

श्री सभापति: विराजिए आप। संयम लोढ़ा जी, विराजिए आप। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: आसन पैरों पर। निर्देश नहीं मानेंगे आप?

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। आप इतने सीनियर हैं, उम्र से भी हैं। आसन का निर्देश नहीं मानेंगे आप? विराजिए आप। जो भी माननीय सदस्य बीच में इंटरवीन कर रहा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि समय बिलकुल नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं बैठिये आप, बिलकुल बैठिये। मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। आपको शायद संसदीय परम्पराओं का ज्ञान नहीं है। आसन यदि आपका नाम लेता है तो यह गम्भीर बात है। मैं आपको सिर्फ माननीय सदस्य कह रहा हूं, मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। आसन बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अनुशासन में रहें। जब सुबह व्यवस्था हो गई, नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठकर चर्चा हो गई, सारी बात हो गई उसके बाद में बार-बार क्यों इंटरवीन कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलने देते उनको? मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मेरे जो 5 मिनट इन्होंने खराब किये हैं उनका आप ध्यान रखना।

श्री सभापति: फिर आप बीच में इंटरवीन कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं क्या बात करूं, उस सरकार के कशीदे पढ़ने वाले मेरे पूर्व वक्ता की, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि कोटा में मौसमी बीमारियों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में सरकारी बैठक थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां भी बैठे हैं और नहीं भी हैं पर उनका वक्तव्य मैं आपको सुनाता हूं। हमने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया- गुंजल। पूरा कोटा त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहा है, हमने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। एक बेहूदा सिस्टम है जो आटो मोड पर काम कर रहा है, आप 5 बनावटी मरीज भेज दो, बिना सिफारिश अस्पताल में बैड नहीं मिलेगा। यह कोटा के माननीय सदस्य का सरकारी बैठक में वक्तव्य है। जनता गालियां दे रही है हमें - चन्द्रकांता। घर-घर में डेंगू के मरीज हैं, हर मौहल्ले में मौत हो चुकी लेकिन अफसर तीन ही बता रहे हैं, जनता नेताओं को गालियां दे रही है, हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएं- चन्द्रकांता मेघवाल, विधायक, रामगंजमण्डी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप विराजिए। जब आपका समय आये तब आप अपनी बात बता देना। बोलने दीजिये माननीय सदस्य को।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लाडपुरा के विधायक भवानी सिंह राजावत

(श्री संयम लोढ़ा)

क्या कहते हैं - लग रहा है हमारी सरकार संवेदनशील नहीं- राजावत। यह मौतें हमारे माथे पर कलंक हैं। महामारी की तरह कोटा में डेंगू फैला हुआ है, लोगों को लग रहा है कि हमारी सरकार संवेदनशील नहीं है। विद्याशंकर नंदवाना, विधायक पीपल्दा क्या कहते हैं - सरकारी अस्पताल से प्राइवेट में रैफर करने का काम कर रहे हैं और भामाशाह कार्ड प्राइवेट अस्पतालों में चल ही नहीं रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये वक्तव्य मेरे नहीं हैं, ये उन जन-प्रतिनिधियों की पीड़ा है जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता ने भुगती है और जनता की वजह से हमारे जन-प्रतिनिधि ऐसा वक्तव्य देने के लिए विवश हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हालात थे। बांसवाड़ा का अस्पताल, चार दिन के मासूम को चूहे ने कुतरा। यह हमारी सरकार थी? जयपुर में आप क्या करना चाह रहे थे। आज जयपुर में असाधारण मरीज की क्या हालत है? पूरे राजस्थान का मरीज सब जगह से धक्के खाकर बेहतर इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस हास्पिटल में आता है। भर्ती करा देता है अपने परिवार के सदस्य को और रात के 10 बजे के बाद सिर्फ एक जने को छोड़कर बाकी को सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकाल देते हैं और वो सारे लोग सड़क पर पड़े रहते हैं, वहीं सोते हैं। कभी उनका मोबाइल चोरी हो जाता है, कभी उनकी जेब कट जाती है। आप क्या बनाने चले थे? एसएमएम अस्पताल में वीआईपी के लिए अलग विंग, 28 लोगों का स्टाफ, 10 करोड़ का खर्च, अमीरों के लिए कालीन और गरीबों के लिए बढ़ती कतार।

माननीय सभापति महोदय, इतना प्रचण्ड विरोध हुआ कि बैक-आउट होना पड़ा। लेकिन यह आपकी सोच प्रदर्शित करता है। एसएमएस जैसे हास्पिटल को आपने बना दिया था कि जिसके पास आपकी सिफारिश हो, उसको तो डाक्टर देख रहे हैं और जिसके पास आपकी सिफारिश नहीं हो, उसको रवाना कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पैट्रोल पम्प बहुत चर्चा में रहा। सरकारी मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर रखा है कि किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, लेकिन ये आंकड़े गवाह हैं। माननीय सभापति महोदय, एक-एक साल में सात-सात सौ डाक्टर के डेपुटेशन किए गए। यह तो सर्वविदित है, सर्वविख्यात है कि कैसे हुए और माननीय सभापति महोदय, नर्सिंग कालेज की मान्यता क्या रहा, +++

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, आप जो बोल रहे हैं, कुछ भी अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: जवाब दे देना, बैठिए आप। आप विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य। मैं माननीय संयम लोढ़ा जी आपसे आग्रह करूंगा...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने किसी का नाम नहीं लिया, माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बात सुनिए, ऐसा आप कोई आरोप नहीं लगाएंगे और मैं निर्देश देता हूं कि ऐसी कोई भी बात असंसदीय हुई हो, तो उसके एक्सपंज किया जाए। आप ऐसा कोई आरोप नहीं लगाएं, जिससे बेवजह उत्तेजना पैदा हो और देना है तो नियमों में उनके खिलाफ लिखकर दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जिस पर लगाना होगा, 173 का नोटिस देकर लगाऊंगा, माननीय सभापति महोदय, मैं डरता नहीं हूं किसी से।

श्री सभापति: आप दीजिए, नोटिस के माध्यम से आइए, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लेकिन मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: मैं अलाउ नहीं करूंगा माननीय सदस्य, मुझे नाम पुकारना पड़ेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपका नाम मुझे पता है, कालीचरण जी सराफ साहब आपका नाम है।

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा, समाप्त करें। विराजिए, विराजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): समाप्त क्या करें, जब शुरू ही नहीं हुआ हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही आपको निवेदन कर दिया है बार-बार इंटरवीन करके मेरा समय खराब कर रहे हैं, आप इसका ध्यान रखें।

श्री सभापति: अब आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा स्वाइन फ्लू बड़ा प्रकोप बता रहे थे, लेकिन क्या इस सदन को बताएंगे कि डब्ल्यूएचओ ने जिस जीएमपी प्रमाण पत्र की आवश्यकता रखी थी। उसको हटाने का काम किसने किया, पांच करोड़ की दवा खरीदने के लिए दो करोड़ की टर्न ओवर वाली कंपनी को काम किसने दिया, 20 करोड़ टर्न ओवर की पात्रता को किसने हटाया, तीन साल के अनुभव को हटाकर के एक वर्ष किसने किया, 16 लाख 31 हजार 832 आसेन्टिवेट कैप्सूल, आइटी 75 एमजी, स्वाइन फ्लू से मौतों का रिकार्ड तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? लज्जा आनी चाहिए एक विधायक को स्वाइन फ्लू से मरना पड़ा, 26 विधायकों की इसी जयपुर के अन्दर स्क्रीनिंग हुई।

माननीय सभापति महोदय, इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊंगा, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम रखा, डाक्टरों की ट्रेनिंग रखी, बुलाए और 200 डाक्टरों ने फर्जी बिल पकड़ा दिये। रुके किसके यहां, बिल किसका बताया, नम्बर किसी के दिये। माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब डब्ल्यूएचओ ने 1 हजार पर एक डाक्टर की सिफारिश की है। हमारे देश में दस हजार से भी ज्यादा संख्या पर एक डाक्टर है। आप नीति लेकर के आइए, राजस्थान के हर जिले के अंदर मेडिकल कालेज खुलना चाहिए, देश के प्रधान मंत्री ने 75 मेडिकल कालेज खोलने का एलान किया, हमारी तैयारी होनी चाहिए कि राजस्थान के हर जिले के अंदर हम उस एलान का लाभ उठा सकें, 60 फीसदी पैसा भारत सरकार देगी, 40 फीसदी आप देंगे।

मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा आपने बजट में घोषणा की है 500 बैड बनाने की, क्या आपको लगता है कि इस 500 बैड के जरिए, आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आप कुछ मेडिकल कालेज प्राप्त कर सकेंगे, कम से कम आप इतनी व्यवस्था तो करिए कि राजस्थान का हर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल 300 बैड का हो, जिससे आपकी तैयारी हो। उसकी पात्रता में 15 हैक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। क्या राजस्थान के हर जिले के अंदर आपने चिकित्सा विभाग के लिए 15 हैक्टेयर जमीन अलाट करा रखी है? और नहीं है तो आप उसकी तैयारी करिए, जिससे राजस्थान को वास्तविक रूप से आने वाले वक्त में हम लाभान्वित कर सकें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, दो एक्ट चर्चा में हैं। एक तो Clinical Establishment Act और दूसरा Right to Health है। मैं चाहूंगा कि सरकार ढुलमुल रवैया नहीं अपनाए। आप अभी मैंडेट लेकर के आए हैं। पहला साल है आपको दृढ़ता के साथ आगे आना चाहिए और इस व्यवस्था को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा टीबी...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दो मिनट में खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, इन्होंने टाइम बहुत खराब कर दिया। टीबी एक गम्भीर संक्रामक रोग है और 2025 तक हमने लक्ष्य तय किया है कि पूरे देश को टीबी से मुक्त करेंगे, जिलों के अन्दर बीआरटीपी बहुत चिह्नित किए हैं, लेकिन एमजेआर, एक्सपीआर मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण सिलिकोसिस की बीमारी की भी संख्या बढ़ रही है। अतः आपको न्यूमोकोन्योसिस वार्ड स्थापित करने चाहिए।

हमारे सिरोही के कलेक्टर ने तो आपको प्रस्ताव भी भेजा है और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आपका उसमें कुछ खर्चा भी नहीं आ रहा था, इसके बावजूद उसकी घोषणा नहीं की।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि सबसे ज्यादा फोकस आपको हास्पिटल्स के लैबर रूम को सुधारने में करना चाहिए। इसके साथ-साथ 2022 तक आपको मलेरिया को भी राजस्थान में खतम करना है और इसके लिए भी आप रेपिड डायग्नोस्टिक टैस्ट निचले स्तर तक उपलब्ध करवाएं।

एक बात मैं आपको निवेदन करूं अभी कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर की भर्ती बहुत चर्चा में है। जिसको लेकर राजस्थान का चिकित्सा विभाग बहुत चर्चा में आया और पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों ने इस हाउस में भी अनर्गल आरोप लगाए, जिसका सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ सका।

मैं जानता हूं उसमें सत्यता क्या है। हमारे मंत्रीजी की इसमें सिर्फ प्रशासनिक भूमिका है और उन्होंने उस बीमारी का इलाज किया है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी मंत्री महोदय जवाब दें उस कम्युनिटी हैल्थ आफिसर की भर्ती के बारे में एक पूरा क्लियर स्टेटमेंट दें जिससे राजस्थान की जनता को मालूम पड़ सके कि यह वर्तमान सरकार

(श्री संयम लोढ़ा)

एक पारदर्शी तरीके से एक लोकहित का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए काम करना चाहती है, पैट्रोल पम्प पर बैठकर के विभाग नहीं चलाना चाहती। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य भारत माता का जिक्र कर रहे थें और उस मां का जिक्र कर रहे थे, जिसके कारण से यह पूरा संसार चलता है। सृजन की शक्ति वो मां, वो बेटी जो बहुत कम उम्र में ब्याह दी जाती है। वहां से शुरू होता है स्वास्थ्य का पूरा चक्र, एक कमजोर मां, एक कमजोर बेटी जब मां बनती है तो निश्चित रूप से उसका पूरा जीवन बर्बाद होता है और उसकी आने वाली सात पीढ़ियां भी बर्बाद होती हैं। इतने सारे इंडेक्स हैं, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया उन सब इंडेक्स में हम बहुत निचले पायदान पर हैं और इस निचले पायदान पर होने की जो जड़ है, जो समस्या की जड़ है, उसका भी उल्लेख थोड़ा बहुत उन्होंने किया। मैं उसी पर आना चाहूंगी क्योंकि जब कमजोर बालक और कुपोषित बालक पैदा होता है तो निश्चित रूप से न तो वह अच्छी शिक्षा ले पाता है और न अच्छा जीवन जी पाता है और उस कुपोषित मां से पैदा होने वाला कुपोषित बालक आने वाली सात पीढ़ियों को भी कुपोषित करता है। इसलिए समस्या की जड़ जहां है यदि उस जड़ को समाप्त किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम बहुत-कुछ अच्छे सुधार की स्थिति में होंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने एक योजना चलायी थी और वह भी मां के नाम से ही चलायी थी। प्रधान मंत्री मातृत्व वन्दना योजना। क्या है यह योजना? यह योजना वह योजना है जिसमें वे गरीब मांएं जो गर्भकाल के दौरान पौष्टिक भोजन नहीं कर सकती हैं, जिनकी ढंग से चिन्ता नहीं की जाती है, उन मांओं को इस योजना के माध्यम से कुछ सहारा मिले, ताकि आने वाले भविष्य का भारत जो उसके गर्भ से पैदा होने वाला है वह स्वस्थ हो। लेकिन धीरे-धीरे इस

(श्रीमती अनिता भदेल)

योजना पर जिस तरह से पर्दा डाला जा रहा है, जिस तरह से इस योजना की मैं यह कहूंगी कि चिन्ता नहीं की जा रही है और उसी का परिणाम है कि इस योजना में आने वाली उन मांओं को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस योजना में उन पात्र गर्भवती महिलाओं को जो गर्भवती हो जाती हैं उनको टैस्ट होने के बाद में पता चलता है, वे ममता कार्ड बना लेती हैं तो उनको फर्स्ट किश्त के रूप में एक हजार रुपया दिया जाता है और जब 150 दिनों का गर्भकाल हो जाता है तो दूसरी किश्त के रूप में उनको दो हजार रुपये का भुगतान मिलता है और उसके बाद में जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद में बच्चे का सम्पूर्ण टीकाकरण का यदि वह ममता कार्ड लाकर के देती है आंगनबाड़ी पर तो उसको दो हजार रुपये की किश्त पुन: मिलती है। इसको एक के साथ दूसरा इन्सेटिव और टीकाकरण दोनों को आपस में जोड़ा गया है, ताकि आपका टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो जाए। कोई भी बच्चा टीकाकरण से महरूम न रहे और उस मां को वह पांच हजार रुपये अलग-अलग किश्तों में मिल जाए, ताकि परिवार भी चिन्ता करे और खुद वह मां भी चिन्ता करे कि जो उसके गर्भ में बालक पल रहा है वह स्वस्थ पैदा हो।

दूसरी तरफ बाल विवाह की बात करें तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बोलना चाहूंगी क्योंकि सरकार में अलग-अलग विभाग होते हैं बाल विवाह को महिला और बाल विकास विभाग देखेगा। स्वास्थ्य को मेडिकल देखेगा। सफाई को नगर निगम देखेगा। ये तीनों डिपार्टमेंट आपस में संयुक्त होकर के यदि अच्छे से काम करें तो निश्चित रूप से हम ज्यादा और अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। पर यदि मेडिकल डिपार्टमेंट की योजना है तो फिर दूसरा डिपार्टमेंट उसको इतनी तरजीह नहीं देता है और उस कारण से अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाते जो आने चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, कि इस बाल विवाह की जो जड़ है उस जड़ को खतम करिये और राजस्थान प्रदेश में 30 परसेंट बाल विवाह होते हैं। 30 प्रतिशत विवाह जिस प्रदेश में बाल विवाह हो रहे हों वहां कैसे हम स्वास्थ्य की चिन्ता कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो जिले इसमें सर्वाधिक हैं जैसे भीलवाड़ा है, दौसा है, टोंक है, यह तो राजस्थान का मैं आपको एवरेज बता रही हूं। इन जिलों में 45 से 60 परसेंट तक बाल विवाह होते हैं और सबके सामने हम ये बाल विवाह देखते हैं। हम खुद भी

(श्रीमती अनिता भदेल)

देखते हैं बाल विवाह, पर रोकने का प्रयास नहीं करते हैं तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी सरपंचों को जो हमारे स्थानीय जन प्रतिनिधि हैं, उनको आप कहिये क्योंकि नीचे का स्थानीय प्रतिनिधि जब कोई बाल विवाह रुकवाने जाता है, पुलिस प्रशासन या कोई जिला प्रशासन तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं और यह कहते हैं कि नहीं-नहीं यह तो बापड़ा है बेचारा दो बेटियों की शादी एक साथ ही कर रहा है क्या टैन्शन है, हो जाने दो न उसकी बेटी की शादी। पर बेटी को पराया करके वह सुख-चैन की नींद नहीं ले सकता? वह बचपन में पराया जरूर कर देता है लेकिन जिन्दगी भर की टैन्शन अपने ऊपर रखता है क्योंकि उसकी बेटी कभी-भी ऐसी स्थिति में स्वस्थ बालक को जन्म नहीं दे सकती इसलिए प्रधान मंत्री जी की जो मातृत्व वन्दना योजना है उसकी ओर आपको अपना ध्यान देना चाहिए, ताकि अच्छे से उन गर्भवती प्रसूताओं की हम चिन्ता कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 15-20 सालों में मैंने देखा, संस्थागत प्रसव होने चाहिए। पहले डिलीवरी घर पर होती थी और दाइयां कराती थी, लेकिन यह संस्थागत प्रसव होने चाहिये इसके ऊपर सरकार ने हजारों-लाखों रुपये खर्च किये। जननी सुरक्षा योजना चलायी। उनको इन्सेंटिव दिया कि यदि संस्थागत प्रसव होगा तो महिलाओं को हम इतना रुपया देंगे। धीरे-धीरे सब लोगों में यह अवेयरनैस आयी और अब अधिकतर जो माताएं हैं वे संस्थागत डिलीवरी के लिए हास्पिटल जाती हैं, लेकिन हास्पिटल में हो क्या रहा है? बहुत चिन्ता का विषय है कि एक तो उसकी जो घर पर डिलीवरी होती थी वह मानसिकता अब बड़ी मुश्किल से खतम हुई है। यदि हास्पिटल में उन प्रसूताओं के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो कौन परिवार ऐसे हास्पिटल्स में उन प्रसूताओं को डिलीवरी के लिए लेकर आएगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करूंगी एक अजीबोग़रीब बात इस बजट में लिखी है। बजट के पैरा नं. 103 में 'बीकानेर कालेज से सम्बद्ध अस्पताल में प्रसूताओं को दर्द रहित प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नवीन यूनिट प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं।' माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही है। अब आप बताएं ऐसा कौनसा प्रसव है जो दर्दरहित होता है? कौनसा प्रसव है जो दर्द के बगैर हो जाता है? सिर्फ एक ही प्रसव है और वह है सिजेरियन। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बीकानेर हास्पिटल में जितनी भी गर्भवती महिलाएं आएंगी

(श्रीमती अनिता भदेल)

डिलीवरी के लिए उनमें नोर्मल डिलीवरी होने वाली महिलाओं की भी आप सिजेरियन डिलीवरी करेंगे? इसको किसी ने पढ़ा नहीं क्या? प्रिंसिपल सैक्रेटरी, फाइनेंस सैक्रेटरी किसने लिखकर दिया माननीय मुख्य मंत्री जी को यह बजट? पढ़ना तो चाहिए कम से कम कि हम लिख क्या रहे हैं और पढ़ने के बाद में इसमें संशोधन करना चाहिए या ध्यान दिलाना चाहिए मंत्री जी को मुख्य मंत्री जी को यह बात गलत लिख रहे हैं आप इसको ठीक करिएगा। यह तो प्रभु जी का काम था।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जिक्र किया आपको। देखिये हमारी संस्कृति में मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना था। मंत्री जी को भी बताना चाहूंगी। हम बहुत छोटे थे तो वह कुछ महिलाओं का विशेष ध्यान रखती थीं और जब हम पूछते थे उत्सुकतावश तो वह अनेकों बार अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलती थी 'आ तो दो जीवड़ी है।' तो चूंकि छोटी थी इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता था दो जीवड़ी क्या होता है, बड़ी हुई तो बाद में समझ में आया कि वह गर्भवती है इसलिए उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है तो इसलिए माननीय मंत्री महोदय को मैं कहना चाहूंगी सभापति महोदय, कि जनाना हास्पिटल्स में एक संवेदनशील स्टाफ होना चाहिए। उनकी संवेदनाएं कहां मर जाती हैं? महिला डिलीवरी के लिए जाती है उसको इतना अंट-शंट कम्पाउण्डर बोलते हैं, 'लेकर आ गई।' यह प्रकृति है। उनके बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे क्या? इतना बुरा बर्ताव जिसकी कल्पना नहीं कर सकता कोई और यदि बेटा हो गया तो उससे नाजायज डिमाण्ड की जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि संवेदनाएं हों हास्पिटल्स में डाक्टर्स में और स्टाफ में। जनाना हास्पिटल्स के स्टाफ में संवेदनाएं कैसे पैदा की जा सकती हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ और नवाचार करके उसकी कोशिश करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक योजना का और जिक्र किया है कि हम निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मेरे अजमेर के विषय पर तो मैं आयी नहीं हूं। दो-तीन मिनट में बस मैं अपने पाइंट की बात कहूंगी। मैंने कोई भी नाजायज बात नहीं कही, न किसी को

(श्रीमती अनिता भदेल)

मैंने आरोपित किया है कि आपने यह किया या हमने यह किया। मैं चिकित्सा के मामले में यह स्पष्ट जानती हूं कि सब सरकारें बहुत अच्छा करती हैं। हमारी जीवनशैली के कारण से इतनी सारी बीमारियां हुई हैं। पहले तो संक्रमण के कारण से होती थी कि गन्दगी है उसके कारण से हो रही है, इसके कारण से हो रही है, लेकिन अब जीवन शैली ऐसी हो गयी है कि डायबिटिज के बहुत सारे मरीज हैं, हार्ट के बहुत सारे मरीज हैं और हम जितना पेस्टीसाइड यूज करते हैं उसके कारण से कैंसर के इतने मरीज हैं कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं तो इसलिए मैं यह निवेदन करना चाह रही हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने योग शुरू किया। योग दिवस शुरू किया। रामदेव जी ने इसको जन क्रांति बनाया और उसके कारण से आज लोग सुबह सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं तो यह सब नवाचार, ये उपाय हमको करने चाहिये क्योंकि बीमारी के बाद में इलाज होना मुश्किल होता है परन्तु यदि हम पहले से उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप में हम इस प्रदेश के बजट के पैसे को भी बचा पाएंगे और लोगों को बीमार होने से जो दु:ख होता है उस दु:ख से भी हम निजात दिला पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से मेडिकल कालेज खुले हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं समाप्त कर रही हूं। मैं दो-तीन पाइंट ही बोलूंगी। एक तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आयुष मंत्रालय के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जबकि यह हमारी परम्परागत पद्धति है तो माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आयुष नर्सेज में जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी पे ग्रेड में और मेडिकल के नर्सेज के पे ग्रेड में बहुत अन्तर है। 3600 और 4200 का अन्तर है जबकि भारत सरकार में यह रूल है कि दोनों नर्सेज का एक पे ग्रेड होना चाहिए तो यह एक ग्रेड पे हो इसकी चिन्ता करें और इसकी कोशिश करें। एक बात और महत्वपूर्ण है यह मंत्रालय इतने दिनों से चल रहा है बहुत पुराना मंत्रालय है लेकिन इस तरह की कैडर रिव्यू की कोई बात इसमें नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय,

(श्रीमती अनिता भदेल)

बस दो मिनट, मैं अपने अजमेर की बात ही कर रही हूं। इसको कैडर रिव्यू कराएं और जो नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में तैनात होता है, वह नर्सिंग के रूप में ही रिटायर हो जाता है। इसलिए इसका कैडर रिव्यू कराना बहुत जरूरी है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसी प्रकार से होम्योपैथी के लिये भी इतना ही निवेदन है कि होम्योपैथी में जो आपने प्रमोशन किये हैं, कैडर रिव्यू का बोर्ड बना दिया लेकिन कैडर रिव्यू के बोर्ड बनाने के बाद भी उसको वह फाइनल नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी जल्दी से उसको फाइनल करें।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। आप सहयोग करें, सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक जो नर्सिंग काउंसिल आयुर्वेद का है वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह प्रदेश की चिंता की बात है। हमारे प्रदेश के आयुर्वेद में नर्सिंग किये हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको बाहर के प्रदेशों में नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसलिए उनको नौकरी मिलनी चाहिये।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: नहीं, विराजिए आप। प्लीज सहयोग करें। विराजिए, विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय श्री संयम लोढ़ा जी ने पूर्व चिकित्सा मंत्री के संदर्भ में यदि कोई भी बात कही तो उसे विलोपित करें। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मौका दिया। महोदय, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बोला राजस्थान में बीमारियां, मौसमी बीमारियां, गम्भीर बीमारियां एक बड़ा अभिशाप बनकर रह गया है। इन बीमारियों के इलाज के पहले इनके कारणों को भी जानना जरूरी है। जब तक हम उन

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

कारणों को दूर नहीं करेंगे, जिसके कारण बीमारी फैलती है, बीमारियों की रोकथाम सम्भव नहीं होगी। महोदय, यह गरीब प्रदेश है, यहां कुपोषण की स्थिति है, भुखमरी है एवं लोग गरीबी का जीवन जीते हैं। अब एक आदमी जो गरीबी में पैदा हुआ हो, कुपोषित परिवार में पैदा हुआ हो, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, यह एक चिंता का विषय है। उसके ऊपर यहां हर चीज में मिलावट है, खाद्यान्नों में मिलावट, पानी में मिलावट, हवा शुद्ध नहीं, यहां तक कि दवाइयों में भी मिलावट है। ऐसे वातावरण में आप स्वस्थ जीवन की कैसे कल्पना कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा यह आग्रह है कि कृपया कम से कम पीने का पानी तो राजस्थान में पीने योग्य हो। सर, जब मैं दौसा से एमपी था तो मैंने इसको लैब में टैस्ट करवाया तो रिपोर्ट आई कि यह पानी पीने योग्य नहीं है और जो पानी पीने योग्य नहीं है उसको हमारी सरकारें सप्लाई करती हैं तो उसका स्वास्थ्य पर कितना विपरीत असर पड़ता होगा, यह आप कल्पना कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में मवेशी गाय, भैंस, सब कम हो गये, धीरे-धीरे समाप्त हो गये पर दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। यह दूध असली है, नकली है, पानी का मिलावटी है या सिंथेटिक है। घी, तेल, हर चीज में मिलावट है। इसका कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि न सिर्फ इलाज की ओर ध्यान दे बल्कि कैसे उसका प्रबंधन किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए, उसकी ओर भी ध्यान दें ताकि बीमारियां फैले नहीं।

महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र टोंक जिले में है। अभी राज्य सरकार ने अनेक मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की है। मैं तो सिर्फ मेरे क्षेत्र की ही बता सकता हूं जो हमारे आसपास लगते हुए क्षेत्र हैं, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा और करौली, एक भी मेडिकल कालेज की घोषणा नहीं हुई। अगर हमारे यहां के आदमी को कोई गम्भीर बीमारी होती है तो या तो वह कोटा जाए या जयपुर आये या दिल्ली जाए। गरीब आदमी के पास इतने साधन नहीं, इतना पैसा नहीं। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि जो सुविधाएं जयपुर में उपलब्ध हैं, जो कोटा में या दिल्ली में हैं, वह हमारे लोगों को वहीं उपलब्ध हों, ऐसी सरकार से मेरी गुजारिश है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र, देवली उनियारा में 5-7 कस्बे ऐसे हैं जिनकी करीब 15 हजार की आबादी है, जैसे कि घाड़, नासरदा, राजमल, बनेठा और नगर फोर्ट। यह इतने बड़े कस्बे हैं और किसी में भी सीएचसी नहीं है, एक भी

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सीएचसी नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा इनकी मांग को देखते हुए क्योंकि यह लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हर छोटी चीज के लिये टोंक चले जाएं या कोटा चले जाएं। इनको जो बेसिक फैसेलिटीज हैं वह उनको वहीं उपलब्ध रहे।

महोदय, एक और विचित्र बात है कि पूरे टोंक जिले में जितने भी सीएचसी हैं, सब 50 बैड के हो चुके हैं, एक मात्र अस्पताल जिसको छोड़ा गया है, जो भेदभाव किया गया है, वह उनियारा का है। जो पूरे जिले में लागू है, जो पूरे प्रदेश में लागू है, वह नियम उनियारा में क्यों नहीं लागू होता? क्या वहां के लोग गरीब हैं, या वहां के लोग असहाय हैं जिसकी सरकार उनको सज़ा दे रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनियारा के अस्पताल को भी सीएचसी की भांति 50 बैड का करने की कृपा करें।

(14.55 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

नये सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आजकल संस्थागत प्रसव की बड़ी बात चल रही है। अगर कोई महिला अस्पताल में अपने प्रसव के लिये आती है तो सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं इसका स्वागत करता हूं, महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य के लिये बहुत अच्छी योजना है। पर अस्पतालों की हालत तो देखें, 5 परसेंट अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं है। अगर पद स्वीकृत है तो महिला नहीं है, अगर चिकित्सक है तो नर्सिंग स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ है तो मशीन नहीं है और मशीन है तो बिल्डिंग नहीं है। कृपया हमारे हास्पिटल को ऐसे बनाने का प्रयास करना चाहिये डाक्टर भी हो, मशीन भी हो, दवा भी हो, भवन भी हो ताकि जो मरीज आये उसका अच्छा इलाज हो सके।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा देवली है, जहां चार, पांच जिलों की सीमाएं मिलती हैं। एक किलोमीटर दूर भीलवाड़ा जिला शुरू हो जाता है, दो किलोमीटर पर बूंदी शुरू हो जाता है, अजमेर की सीमा लगती है, सवाईमाधोपुर लगता है और टोंक में है ही। वहां से अनेक नेशनल हाईवे गुजरते हैं और वहां एक्सीडेंट की वारदातें होती रहती हैं, गाड़ियां तेज चलती हैं, वाहन भी बहुत ज्यादा है। एक छोटी सी मशीन होती है सीआर, जो हडि्डयों के टूटने पर काम आती है, हर एक्सीडेंट में हड्डी टूटती है। उस

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

मशीन के लिये भी आदमी को या तो कोटा जाना पड़ता है या टोंक जाना पड़ता है। यह सामान्य चीज है और मैंने कीमत पता लगाई, कहते हैं 12 लाख की है। यह तो मैं आग्रह करता हूं कि कम से कम इस मशीन के अभाव में हमारे गरीब लोगों को शिकायत न हो और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर अतिशीघ्र कार्यवाही करेगी।

मैं बड़े-बड़े अस्पतालों की बात कर रहा हूं, छोटों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। दो मेरे बड़े कस्बे हैं घाड़ और राजमल, वहां वर्तमान में एक भी डाक्टर नहीं है, एक भी नर्स नहीं, एक भी एएनएम नहीं और अस्पताल चल रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि डाक्टर के, नर्स के अभाव में वहां इलाज कौन कर रहा है। उन मशीनों को कौन चला रहा है, उनकी जांच कौन कर रहा है।

इसी तरह से जो मेरे दो उपखण्ड मुख्यालय हैं उनियारा एवं देवली, दोनों में से एक भी जगह ब्लड बैंक नहीं है। आज आप जानते हैं छोटी से छोटी दुर्घटना में, इलाज में खून की आवश्यकता होती है। जब ब्लड बैंक है ही नहीं तो कहां से होगा। मेरा आदरणीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि देवली और उनियारा में आप ब्लड बैंक स्थापित करने की मेहरबानी करें।

सर, अस्पताल में कोई भी मरीज जाता है उसको जांच करवानी पड़ती है, बीपी, एक्स-रे, क्या-क्या होती है मुझे पता नहीं क्योंकि न तो मैं मरीज हूं, न डाक्टर हूं। मैं कभी बीमार भी नहीं हुआ तो मुझे ज्यादा पता नहीं पर मुझे यह जरूर पता है कि चिकित्सा विभाग में सबसे बड़ा माफिया अगर है तो यह जांचों का माफिया है। कोई चीज हो वहां जांच करा लो, खून की करवा लो, एमआरआई करवा लो और यह सब प्राइवेट लोगों की हैं। जितने हमारे अस्पताल हैं इनमें कम से कम जो मूलभूत यंत्र हैं, वह उपलब्ध होने चाहिये ताकि हमारे गरीब लोगों को इधर उधर धक्का नहीं खाना पड़े और इन माफियाओं के शिकंजे से उनको बाहर निकालें ताकि इनका जीवनयापन अच्छी तरह हो सके।

(15.00 बजे)

सर, अंत में मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा। हम दोनों कांस्टीट्यूएंसी साथ-साथ हैं। ये मेरे मित्र हैं, मेरे ऊपर बड़े मेहरबान हैं। महोदय, जितने भी पद स्वीकृत हैं। आप नये पद दें या नहीं दें, जितने पद स्वीकृत हैं, उनको उसी स्थान पर लगाएं।

एक तहसील मुख्यालय नासरदा है, रूह क्षेत्र में। सदा की भांति, वहां

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

पर डाक्टर नहीं हैं। स्वीकृत हैं, पर डाक्टर नहीं है। वहां एक नर्स पदस्थापित थी, वह हास्पिटल को चला रही थी। उसको भी पिछले दो साल दूसरी जगह लगा दिया। ऐसे हास्पिटल में लगा दिया, जहां पर आलरेडी एक नर्स है। उस एकमात्र नर्स को यहां से हटाकर रघुनाथपुरा गांव है, वहां लगा दिया। सर, इन लोगों ने ऐसी क्या गलती की? डाक्टर मिलना चाहिए था, पर आपने तो नर्स भी हटा दी। मेरा आग्रह यह है कि ऐसा लगे कि, जैसे कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय संवेदनशील हैं, तो संवेदना दिखनी भी चाहिए। क्योंकि यदि गरीब का समय पर इलाज हो जाए तो वह बहुत दुआ देता है और तो उसके पास क्या है? वोट तो पांच साल में एक बार देता है, दुआ वह रोज दे सकता है। कम-से-कम हम उसकी दुआ तो लें।

सर, एक यह डेपुटेशन का सिस्टम मेरी समझ में नहीं आया। पूरे राजस्थान के लोग पोस्टिंग तो वहां करवा लेते हैं तो सब डेपुटेशन में, कोई जयपुर लगा हुआ है, कोई टोंक लगा हुआ है। अस्पतालों में जिनकी ड्यूटी है, जिन अस्पतालों से उनकी तनख्वाह उठती है। वे जहां भी नियुक्त हैं, जहां उनकी नियुक्ति है, जहां उनका पद है। काम वे वहीं करें तो हमारी जनता को न्याय मिलेगा। महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी जी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या - 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की मांगें रखने से पहले वहां की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में अवगत कराना चाहती हूं। 30 मई की रात को एक गरीब परिवार की 10 वर्षीय बालिका जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे सांप ने काट लिया। उसे कैथून सीएचसी अस्पताल लेकर गये और वहां डाक्टर होते हुए भी मात्र ड्रिप चढ़ाकर, खानापूर्ति करके उसे वहां से कोटा रैफर किया गया और कहा गया कि उसकी स्थिति गम्भीर है। वहां पर एंबुलेंस का ड्राइवर मौजूद नहीं था। बालिका के पिता अपने साधन से ड्राइवर को ढूंढकर लेकर आये और उसे कोटा अस्पताल ले गये। परन्तु, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस बालिका की मृत्यु हो गयी। इस घटना की जानकारी लेने पर पता चला कि अस्पताल में 17 वॉयल एंटीमैनम, जो कि एंटीडोज होते हुए भी केवल ड्रिप चढ़ाकर उसे कोटा रैफर किया गया। अगर इस मासूम बालिका को समय पर डाक्टर देख लेता तो इलाज के अभाव में उसकी

(श्रीमती कल्पना देवी)

मौत नहीं होती। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करवाने का निवेदन करती हूं। इसमें जिसकी भी लापरवाही हो, उस पर सख्त कार्यवाही की जाए और मैं गरीब परिवार को राहत देने की मांग करती हूं।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में मण्डाना कस्बा है, जिसमें 4 करोड़ रुपये की लागत से नये सीएचसी भवन का निर्माण हुआ था। यह भवन बनकर पूर्ण हो चुका है। मुझे इस भवन के बारे में अवगत कराया गया। मैंने चिकित्सा अधिकारी एवं जो स्थानीय जन प्रतिनिधि हैं, उनके साथ मौका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नये भवन में दरारें, दरवाजे में गैप और वहां जो ड्रेनेज के लिए ड्रेन बनाये गये हैं, उनमें कोई आउटलैट नहीं है। ऐसी कई कमियां पायी गयीं। मौके पर ही अधिकारियों को उन कमियों को जल्द ठीक करने को कहा गया। इस विषय पर 18 मार्च को मैंने मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, परन्तु इतने माह पश्चात् भी इन कमियों का सुधार नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, कोटा शहर में स्थित डीसीएम क्षेत्र में शहरी पीएचसी केन्द्र का निर्माण 75 लाख रुपये की लागत से लगभग पूरा हो चुका है। शेष बचे कार्य, जो कि छोटे-मोटे कार्य हैं, उनको भी जल्द पूरा करवाकर इसका शीघ्र उद्घाटन करने का आदेश प्रदान करें।

मेरे क्षेत्र में ग्राम पंचायत रंगपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 21 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी लेकिन भवन के लिए आबंटित भूमि पर अतिक्रमण होने की वजह से आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। यही स्थिति मेरे क्षेत्र में केवल नगर व धाकड़खेड़ी ग्राम पंचायत की भी है। जहां पर आज तक जमीन उपलब्ध नहीं करवायी गयी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि मेरा क्षेत्र काफी बड़ा है और फैला हुआ है। दूरदूर से लोगों को उपचार के लिये कोटा शहर आना पड़ता है। आपसे निवेदन है कि कैथून कस्बे में सैटेलाइट अस्पताल बनाया जाए, इसकी मैं मांग करती हूं। इससे आसपास के लगभग 30-40 गांवों को लाभ मिलेगा और कोटा नहीं जाना पड़ेगा। इससे एक और फायदा है कि हमारा जो माहाराव भीम सिंह अस्पताल है और जेके लोन हास्पिटल है, उस पर भी कम दबाव पड़ेगा।

इसके अलावा किशनपुरा तकिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग करती हूं। क्योंकि इसके आसपास कोई भी उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को इलाज के लिये बहुत दूर जाना पड़ता है।

(श्रीमती कल्पना देवी)

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कई पद रिक्त हैं, जिन्हें शीघ्र भरा जाए, ताकि जनता को इसकी सुविधा जल्दी मिल सके। सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहती हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं गरीब व्यक्ति खास तौर पर बीपीएल लोगों को सम्पूर्ण तरीके से मिलनी चाहिए। सबसे अधिकतम जरूरत इन लोगों को है। जैसे कहते हैं कि health is wealth. परन्तु मैं कहना चाहती हूं good health is wealth. यहां पर जो भी बैठे हैं, हम सब का एक ही लक्ष्य है कि जो भी सेवाएं हैं, वे हर नागरिक तक पहुंचें और इसी उम्मीद के साथ आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वे इन सब समस्याओं को ध्यान में रखें और इनका समाधान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला जी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप यह मान लें कि आप इधर से हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह तो मैंने आपको पहले ही, पांच साल पहले जब भी बोलती थी तो यही कहती थी कि तुम इधर आओगे हम उधर बैठेंगे। हर बार यही कहती थी, इतना कांफिडेंस था।

"आसमां में तारा कहीं भी उगे,

रोशनी एक-जैसी देता है।"

तो हम वो स्टार हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हम सब की मंशा है कि हम प्रश्न पूछें और आप उनका रिप्लाई दें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपका कोई काम हो तो आप मुझे आदेश दें।

श्री सभापति: शकुंतला जी अपनी बात शुरू करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आज का विषय अति महत्वपूर्ण विषय है, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सफाई। यह जीवन का एक हिस्सा है। आज के युग का यह महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज का इंसान अधिकतर दवाओं पर जीवन यापन कर रहा है और दवाई जिंदगी का एक हिस्सा बन गयी है। सरकार के सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जिससे कि एक आम नागरिक को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उसे वहीं पर बीमारी का ट्रीटमेंट मिल जाए। आज कई तरह की बातों का सदन में जिक्र हो रहा था। सभापति महोदय, मैं आज उनका नाम लेना चाहूंगी। हमारे भारत देश की पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की सोच को, उनकी इतनी दूरदर्शिता की सोच को, अपने देश हित की सोच को कि उन्होंने नसबंदी को चालू किया। बहुत अधिक विरोध हुआ लेकिन विरोध होने के बाद भी उन्होंने यह कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि एक-एक परिवार की यह आवश्यकता होगी और एक-एक परिवार इसे अपनाएगा, अपने आप लाइन पर आएगा। आज वह दिन है। ऐसी दूरदर्शी सोच थी अपने देश के लिए इंदिरा गांधी जी की। अभी मंत्री महोदय, आपकी तो छुट्टी करूंगी। आप क्या-क्या घोषणा करके आए थे मेरे बानसूर में। मेडिकल में भामाशाह योजना, चौंक गए? भामाशाह योजना चलाई जिससे आम नागरिक के लिए, अखबारों में बहुत बड़ा-बड़ा दिया गया, चर्चाएं हुईं लेकिन आज इस भामाशाह योजना के कारण, अगर चुनाव है तो आचार संहिता लग रही है खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ेगा, अगर उसका लंबा खर्चा चल गया तो उसको पूरा खर्चा नहीं देंगे। इन्होंने यह किया कि पूरा ट्रीटमेंट मिला किसी ट्रस्टी को दे दिया, पता नहीं कहां चला गया सारा पैसा। इसका सही लाभ नहीं मिल पाया।

सम्माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार की एक-एक योजना जनहित तक गांव, झोपड़ी और ढाणी तक पहुंचने वाली योजना थी। जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे जच्चा-बच्चा का ख्याल रखने के लिए हो, उसके पास अगर खर्चा नहीं है तो ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार की थीं। जितने भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं, हास्पिटल हैं, जो संविदा पर कर्मचारी पिछली सरकार ने इधर से उधर कर रखे थे, उन्हें अपने सही स्थान पर पहुंचाएं जिससे जो जगह रिक्त पड़ी हैं, वह भर सकें। बानसूर में एक प्रोग्राम था मूर्ति अनावरण का। पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जो सदन में मौजूद हैं, राठौड़ साहब, यह वहां पर उद्घाटन करने गए। सभापति जी, उद्घाटन किस मूर्ति का था, फीता कौन-सी मूर्ति का काटकर आए। सुभाष चन्द्र बोस की टीम में स्वतंत्रता सेनानी, जो कई सालों तक विदेश में, जो वहां के अंग्रेजों की कीलों के जूतों के नीचे रहे, सुभाष चन्द्र बोस के साथ रहे स्वतंत्रता सेनानी सम्माननीय उदमी राम जी, उनकी मूर्ति का उद्घाटन करने गये और वहां पर घोषणा करके आए कि एक पीएचसी खोल दी जाएगी। बड़े-बड़े भाषण देकर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

आए लेकिन कहां खुली? वैसे ही घोषणा कर देते, कोई बात नहीं। कहीं असत्य बोल देते, कोई बात नहीं लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी के वहां पर असत्य बोल कर आ गए और भाषण दे दिया। अभी तो जब पीएचसी का उद्घाटन होगा, बिल्डिंग बन जाएगी तब और आएंगे। कहां आओगे, पहले ही चले गए। लेकिन कम से कम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से एक पीएचसी तो खोलकर आते। क्यों नहीं खोला? दुर्भावना थी इनकी क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी की विधायक थी इसलिए नहीं खोला उन्होंने। इस बात से इनकी दुर्भावना झलकती है। उससे भी बड़ा फिर गए बानसूर हास्पिटल में और वहां घोषणा करके आ गए। घोषणा के साथ-साथ आर्डर भी निकाल दिए। आर्डर निकालने के बाद में जितनी पीएचसी व सीएचसी को यह क्रमोन्नत करने की घोषणा करके आए, ये मंत्री महोदय थे उस टाइम पर। उस लिस्ट में मेरे बानसूर का भी नाम था। यह है 12वें नंबर पर घोषणा 13 में। वहां जाकर घोषणा कर आए। सभापति महोदय, हास्पिटल में जाकर सबके सामने और लिखित में आर्डर निकाल दिए। फिर बानसूर का नाम कहां खो गया, कहां है वह आर्डर? हमारे वर्तमान मंत्री महोदय, इस आर्डर को ढूंढे और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। मेरे हिसाब से सारे के सारे आर्डर इस तरह ही कर गए ये लोग। असत्य बोल गए। असत्य को सत्य में साबित कर दें।

सभापति महोदय, इनका हर भाषण असत्य था। आंकड़ों में एक नंबर पर है। आंकडों की सरकार है ये। आंकडे दिखा रही हूं, अगर शक है तो एक कापी ले जाओ। सदन के अंदर कोई और बोलता है तो कहते हैं कि वह पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से यह पढ़े-लिखे थे और पूर्व चिकित्सा मंत्री ने यह कहा कि अलवर का ईएसआई हास्पिटल और आपके यहां महिला चिकित्सक हम डेढ़ महीने के अंदर लगा देंगे। मैंने दोबारा रिपीट किया जिससे कि अंकित हो जाए। मैंने कहा कि मंत्री महोदय क्या बोला? आप मुझे बोलकर बताएं। कह रहे हैं कि डेढ़ महीने के अंदर आपके यहां महिला चिकित्सक लग जाएगी। अलवर का मेडिकल कालेज चालू हो जाएगा। ईएसआई अस्पताल चालू हो जाएगा। इतना असत्य का पुलिन्दा जो सदन में पेश करती थी सरकार, यह बड़े शर्म की बात है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगी कि मंत्री महोदय, अब उस बानसूर अस्पताल को 30 बैड से 100 बैड का क्रमोन्नत करें क्योंकि वहां का आउटडोर 500-600 तक पर-डे है। इन व्यस्तताओं को देखते

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हुए उसकी शय्याएं बढ़ाने का कष्ट करें। दुर्घटनाएं अधिक होती हैं क्योकि दिल्ली और जयपुर रोड वहां से नजदीक पड़ता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगी की एक ट्रोमा वार्ड वहां बने। दुर्घटनाएं तो आज वर्तमान का एक भयानक विषय है। सुबह अख़बार खोलो तो यही चीजें देखने को मिलती हैं। स्पीड में इंसान दौड़ रहा है। किसी ने खूब कहा है कि अगर सुबह मुस्कुराने का मन करे तो उठते ही अख़बार मत पढ़ो। अख़बार के प्रत्येक पन्ने पर कहीं न कहीं कोई एक पेज ऐसा मिलता है जहां किसी मां के लाल की फोटो मिलती है मृत अवस्था में। दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हम कोई प्रयास करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बानूसर में गायनी महिला चिकित्सक लगाएं जिससे कि पिछली सरकार के असत्य के पुलिन्दे से निजात मिल सके। जो छींड एरिया है जैसा धामला का बास है या नाथूसर लोज, इस तरह के जो छींड एरियाज हैं, वहां पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें जिससे उनको प्राथमिक उपचार मिल सके। नारायणपुर में चाहे देवनारायण योजना से बनाएं या अन्य योजना से बनाएं, एक महिला चिकित्सालय बनाएं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं मिल सकें।

एसएमएस अस्पताल जो एक बड़ा राजधानी का अस्पताल है, उसमें जाकर देखें तो रूह कांप उठती है। वहां के जो डाक्टर्स है, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इनसे बैठकर बात की जाए जिससे ये बार-बार जो स्ट्राइक की कंडीशन आती है, वह नहीं आए। आयुष के बारे में बोल चुके हैं कि आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स इनकी 15 वर्षों से डीपीसी नहीं हुई है। इनके वेतनमान और प्रमोशन भी एलोपैथी के बराबर किए जाएं। सभापति महोदय, पूर्व सरकार की जो घोषणाएं थीं, उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक और छोटा-सा है मेरा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि जो हरसोरा पीएचसी है उसे सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए। उसमें 50 गांव आस पास लगते हैं और बिल्डिंग अगर दें, पूरा खर्चा भी उठाने को वहां एक भामाशाह तैयार है तो चतरपुरा में एक पीएचसी खुलवाने का कष्ट करें। हमारी पिछली सरकार ने, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मुंडावरा गढ़ी में नई पीएचसी खुली थी, उस पीएचसी का नाम श्रीमती पार्वती देवी के नाम से करने का कष्ट

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

करें। वह पूरी बिल्डिंग, जमीन एक भामाशाह ने दी है। केवल जी सेठ, उनके भाई और सभी ने और वह सभी तरह से मदद करते रहते हैं।

सभापति महोदय, मूक-बधिर बच्चों के लिए कोकलियर इम्पलीमेंट सर्जरी होती है। उसके लिए आयु निश्चित होती है, आठ साल की उम्र तक ही वह लग सकती है। उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। उस प्रक्रिया का सरलीकरण करें जिससे कि उसका फायदा मिल सके। पहले हमारी सरकार की तरफ से यह बहुत बच्चों को लगी थी, फायदा मिला था।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बस समाप्त ही है। डाक्टर्स के रिक्त पद हैं, जीएनएम के हैं, उनको भरने की कृपा करे। जो संविदा पर लगे हुए हैं इन सबको भी। सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं जीवन के लिए दो लाइन मेरी तरफ से कहूंगी।

"फूल-फल हमेशा पेड़ पौधे पर लगते हैं, पत्थर पर नहीं
इंसान का जीवन एक बार मिलता है बार-बार नहीं।"

धन्यवाद।

श्री सभापति: सुमित जी गोदारा। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम पहले अपने क्षेत्र की और डिमांड पर बात करें, फिर इधर-उधर जाएं तो अच्छा रहेगा। मूल बात रह जाती है, फिर आप बाद में समय मांगते हो कि मेरे क्षेत्र की, मेरे गांव की बात रह गई। इससे अच्छा है कि अपने क्षेत्र की और डिमांड पर बात करके फिर इधर उधर घूमेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): सभापति महोदय का आभार। मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य। सर्वप्रथम तो आजादी के 70 वर्ष से, डाक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस कर्मचारी, समस्त जो इस वर्ग से जुड़े हुए थे उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा। राजस्थान में आज चिकित्सा सुविधाओं में ऐतिहासिक सुधार हुआ है, मानव जीवन की उम्र बढ़ी है, जो सुविधाएं मिलीं, उसके लिए समस्त का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

मेरे पिताजी कैंसर के डाक्टर रहे हैं। मैंने आज सुबह उनसे पूछा कि मुझे इस बारे में बोलना है, तो क्या बात कहूं कि जो वास्तव में आपने इन पिछले 60 सालों में देखा है कि राजस्थान में चिकित्सा सेवा में क्या सुधार हुआ। तो अनेक बातें कहीं लेकिन उन्होंने कहा जिन्होंने मानव जीवन को बहुत

(श्री सुमित गोदारा)

बड़ी सुविधा और जीवन दान दिया है इन दो बातों का जरूर जिक्र करना। पहली मुख्य मंत्री नि:शुल्क योजना जो राजस्थान सरकार लेकर आई, दूसरी भामाशाह योजना। यह दो योजना ऐसी हैं जिससे गांव व शहर के वासी हैं उनको उच्च क्वालिटी की चिकित्सा सुविधाएं सुलभ होने लगी हैं। यह दो बहुत ही महत्वूर्ण योजनाएं हैं।

पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमारा यह उद्देश्य है कि राजस्थान की सात करोड़ की जनता है उसको अच्छी सुविधाएं मिलें, उस भावना के साथ आज यह चर्चा हो रही है, उसमें मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि हमारी प्राथमिक इकाई उप स्वास्थ्य केन्द्र है। ज्यादा से ज्यादा उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। जहां खोले जाएं वहां पर यह भी प्रयास किया जाए कि जो रिक्त पद हैं, उन को भरा जाए।

मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि उप स्वास्थ्य केन्द्र पर लाइट की बहुत दिक्कत रहती है, वहां पर सोलर प्लांट लगाए जाएं ताकि 24 घंटे लाइट मिले जिससे वहां जो इंजेक्शन और मेडिसिन रखी जाती है उनका स्टोरेज व रेफ्रीजरेशन हो सके और उपयोग हो सके।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के रानीसर जो कि रामबाग ग्राम पंचायत का है, रावासर, किस्तूरिया, खारी, खोडाला एवं डांडूसर में निवेदन करूंगा कि उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं और खुले हुए हैं वहां भवन निर्माण कराया जाए।

उसके बाद, उप स्वास्थ्य केन्द्र का, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकार डेजर्ट एरिया के लिए बहुत बढ़िया योजना लेकर आई कि जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका 10 परसेंट, 20 परसेंट, 30 परसेंट, उसमें कोटा हो, उस हिसाब से रखा, प्रथम साल, दूसरे साल, तीसरे साल के हिसाब से। उसकी वजह से ग्रामीण अंचल, रेगिस्तान अंचल में डाक्टर आने लगे पर विडम्बना यह है कि डाक्टर्स की पोस्टिंग तो कर दी लेकिन वह वहां पर बैठते नहीं हैं। यह प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा डाक्टर वहां बैठे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा। मूलसर, रामसर, कुजटी, राजासर, करणीसर, सेजरासर, धिलेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हमारे विधान सभा क्षेत्र में लूणकरणसर, नापासर, महाजन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं,

(श्री सुमित गोदारा)

उनमें अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं। लूणकरणसर इतना बड़ा कस्बा है, उसमें डाक्टर के 12 पद स्वीकृत हैं। मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कि उसमें 9 पद रिक्त पड़े हैं। बीकानेर जिले में एक सीएमएचओ है, दस साल से एक सीएमएचओ एक ही स्थान पर पोस्टेड है। ऐसा भ्रष्ट सीएमएचओ, मंत्री जी और सब यहां बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा, दस-दस साल तक एक ही अधिकारी रहे, चिकित्सा जैसे विभाग में, जहां नर्सिंग और डाक्टर्स का स्टाफ रहता है, गठजोड़ करके सिस्टम चला रखा है। डाक्टर, नर्स वहां जाते नहीं हैं और सीएमएचओ अपना प्रयास करता रहता है। कोई भी सरकार हो, यहां सरकार का महत्व नहीं है। महत्व यह है कि गांव के लोगों को सुविधा मिले। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, वह सीएमएचओ जान बूझकर डाक्टर को हटा रहा है। लूणकरणसर में बीजेपी को वोट दे दिए तो जान बूझकर सीएमएचओ, लूणकरणसर ने उसने हटाए, नापासर से डाक्टर हटाए। कल उसने दो डाक्टर लगाए क्योंकि उसको पता था कि आज मांग संख्या पर बात उठेगी। ऐसे अधिकारियों, ऐसे डाक्टर्स के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यह संदेश जाना चाहिए कि सरकार सजग है। ऐसे अधिकारियों को सरकार लगा देती है, वह लोगों को तंग करते हैं, लूटते हैं और हम बात करते हैं कि राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं सुधारी जाएं। जिसके हाथ में पूरी जिम्मेदारी है, जब वो ही चोर बैठा है तो आगे की हम क्या बात करें।

माननीय मंत्री जी आप बात अच्छी करते हैं, आपकी कार्यप्रणाली से लगेगा कि इस पर एक्शन हुआ है। नहीं होगा तो हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ समय-समय पर आंदोलन करेंगे। बीकानेर ज़िले में जिसने भ्रष्टाचार, लूट का अड्डा मचाया हुआ है, ऐसी सेवा जो मानव सेवा का काम है, उसको अपने घर भरने का, राजनीतिक सेवा करने का उसने उद्देश्य बनाया हुआ है उसको हम बंद कराएंगे, यह आपसे निवेदन है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक निवदन और करूंगा। पीजी एडमिशन में सरकार अभी 30 लाख का बान्ड भराती है, 5 साल के लिए बाध्य होता है कि पीजी करने के बाद वह डाक्टर सेवा करे। पर आज तक राजस्थान सरकार ने इसको कभी गंभीरता से लागू नहीं किया। राजस्थान से पीजी करते हैं और नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। राजस्थान से 80 परसेंट डाक्टर्स पीजी करके, नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। महाराष्ट्र और दूसरी जगह पर बाध्यता हो। क्यों नहीं बाध्यता हो कि आपको राजस्थान में ही काम करना पड़ेगा। नहीं करे तो

(श्री सुमित गोदारा)

उनके 30 लाख रुपये काटो। नहीं तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल, आरएमसी है वहां उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो। एमसीआई को लिखकर दे दो कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करे, ऐसे डाक्टर कहीं भी प्रेक्टिस नहीं कर पाए। ऐसे पीजी किए हुए डाक्टर अगर हमें मिलेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह अपने आप ही सुधर जाएंगी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और हास्पिटल में बढ़ी है।

मेडिकल कालेज की बात, जहां से डाक्टर निकलते हैं, सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि आज के टाइम मेडिकल कालेज में चिकित्सक बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे हैं। अटेंडेंस नहीं रहती है, 75 परसेंट अटेंडेंस जरूरी है पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रिंसिपल हो, कोई हो, छात्र-छात्राएं कालेज में आते नहीं हैं। जब आते ही नहीं हैं तो कहां से पढ़ाई करेंगे। जब उनका बेस ही कमजोर होगा तो हम कहां से उम्मीद करेंगे कि वह अच्छे डाक्टर बनेगे। सीनियर डाक्टर है, मेडिकल कालेज एसोसिएट ग्रुप आफ हास्पिटल है, वह टाइम पर राउण्ड नहीं लेते हैं। आज तो यह हालत हो गई कि रेजीडेंट राउण्ड लेने लग गए हैं, डाक्टर राउण्ड नहीं लेते हैं। सीनियर डाक्टर्स ज्यादातर घर पर बैठ जाते हैं। हाज़िरी का सिस्टम आपने बायोमेट्रिक कराया है, वह एक बार सुबह आकर हाजिरी लगाकर चला जाता है, पूरे दिन वह कुछ भी करता रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है।

मेडिकल कालेज की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खेतड़ी के विधायक महोदय ने कहा कि 50 परसेंट पेशेंट का लोड है और मेडिकल कालेज स्टाफ है। चाहे एस.एम.एस. हो, चाहे बीकानेर का सरदार पटेल मेडिकल कालेज हो, वहां पर सुधार करने के लिए अटेंडेंस दोनों टाइम रखो। मूवमेंट रजिस्टर सख्ती से फोलो होना चाहिए।

एक समय था जब रेजीडेंट डाक्टर को, चीफ का बड़ा खौफ होता था पर आज के टाइम रेजीडेंट डाक्टर भी लापरवाही बरतने लगे हैं। एक लोग बुक होती है उसे हर साल पीजी स्टूडेंट भरे, जिससे वह एक कम्पीटेंट डाक्टर बन सके।

एक निवेदन और है। मेडिसिन सर्जरी गाइनिकी डिपार्टमेंट है जहां बड़े मेडिकल कालेज में 6-6, 7-7 यूनिट हैं। अब एक यूनिट का एक सप्ताह में आउटडोर आता है तो यूनिट वाले डाक्टर सप्ताह में एक दिन आते हैं और

(श्री सुमित गोदारा)

बाकी दिन आते ही नहीं हैं। सिर्फ आधे घंटे का राउण्ड लिया, कोई उनको पूछने वाला ही नहीं है कि कौन कहां है। आप कह रहे हो कि इतने पेशेंट आ रहे हैं, इतना लोड बढ़ रहा है, अपन डेढ़-दो लाख रुपये तनख्वाह उनको दे रहे हैं तो क्यों नहीं उस यूनिट का सप्ताह में दो बार आउटडोर हो जाए। एक ही दिन हो तो दो-दो यूनिट बैठे मेडिसिन की, ताकि बीमार को अच्छी चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सके तथा हास्पिटल पर लोड भी कम हो सके। सरकार चाहे तो आराम से करा सकती है।

बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल है, वह 150 करोड़ से बनकर तैयार है पर अभी तक शुरू नहीं किया गया। मैं खेतड़ी के माननीय विधायक साहब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही कि मेडिकल कालेज जहां भी बन रहे हैं उसको अपन हर जगह होरीजेंटल बना रहे हैं। बीकानेर का हमारा हास्पिटल, महाराजा गंगासिंहजी, हिज हाइनैस, उन्होंने उस समय, आज से लगभग 90 साल पहले जगह आबंटित की। कितनी बढ़िया भूमि उन्होंने दी और वहां पर इतना बढ़िया हास्पिटल बना। पर अब हो क्या रहा है कि हर डिपार्टमेंट अपने लिये अलग-अलग जगह बना रहा है। उससे न तो जगह का उपयोग हो रहा है, न सुविधाएं मिल रही हैं और पेशेंट फुटबाल बना हुआ घूम रहा है। उसको आप एक जगह वर्टिकल लेंगे तो एक जगह सारी की सारी चिकित्सा, एक तो इंटरडिपार्टमेंटल सुविधाएं मिलेंगी, सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी होगी और सेफ्टी की भी सुविधा मिलेगी।

मैं माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि मेडिकल कालेज की फीस हर साल बढ़ाई जा रही है। बीकानेर में भी मेडिकल कालेज के छात्र-छात्राओं में रोष है। उस फीस को आप वापस लें ताकि छात्र-छात्राओं को सुविधा हो सके।

मेडिकल कालेज के साथ, जो सबसे बड़ी मांग, यहां मैंने देखा, विधान सभा में सब विधायक महोदयों ने ट्रोमा सेन्टर को लेकर उठाई। वास्तव में यह हकीकत है। मैं खुद ट्रोमा सेन्टर में, बहुत बार, महीने में ऐसा पांच-सात बार होता है, घटनाएं होती हैं तो रात को मैं खुद जाता हूं। ट्रोमा सेन्टर ऐसी जगह है, जहां एक-दो मिनट की देरी से ही बीमार के जीवन-मरण का प्रश्न उठता है। हमारे बीकानेर का ट्रोमा सेन्टर हो, या मेडिकल कालेज में जहां भी होगा,

(श्री सुमित गोदारा)

तो वहां पर स्पेशलाइज्ड डाक्टर रात को नहीं बैठते हैं। वहां सिर्फ जो रेजीडेंट्स हैं, जो कर रहे हैं वे बैठते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि स्पेशलाइज्ड डाक्टर, जो सीनियर डाक्टर्स हैं, उनकी रात को ड्यूटी अवश्य लगाई जाए, वे वहां पर बैठे हैं। उनको अवश्य लगाया जाए, ऑन-काल की जगह सीनियर डाक्टर रेगुलरली बैठें। ओर्थोपेडिक्स के पद हैं, वे भरे हैं क्योंकि ओर्थोपेडिशियंस के ज्यादातर पद खाली हैं। ओर्थोपेडिक्स के पद भरे जाएंगे तो ट्रोमा में 70-80 केसेज ओर्थोपेडिक्स और 10-20 प्रतिशत न्यूरो सर्जरी के जो केसेज आते हैं, उनको सुविधा मिले।

एक बहुत बड़ी विडम्बना बीकानेर में हमारे ट्रोमा सेन्टर में है कि दिन में ही दो बजे के बाद किसी की कोई घटना हो जाए तो वहां सोनोग्राफी नहीं होती। अब एक्सीडेंट होता है तो पेट में भी लगती है। बहुत कैजुअल्टीज होती हैं सोनोग्राफी नहीं होती तो। सोनोग्राफी के लिये उसको दो किलोमीटर तक दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। एम.आर.आई. भी वहां नहीं होती, उसके लिये भी एक किलोमीटर, कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप उसको लेकर जाओ। तो मैं सदन के माध्यम से कहूंगा कि ये सब बातें गौण हैं जब हम ट्रोमा सेन्टर जैसी जगह, जो मरीज है जिसको तुरन्त, इमरजेंसी आवश्यकता है, उसके लिये हम वहां सोनोग्राफी नहीं करा सकते, हम वहां पर एम.आर.आई. नहीं करा सकते। बीकानेर का इतना बड़ा हास्पिटल है, वहां सिर्फ एक एम.आर.आई. सेन्टर है, वह भी दूर है। पेशेंट्स का इतना लोड है कि रात को तीन-तीन बजे वह टाइम देता है। बताओ, गांव का गरीब आदमी कहां तीन-तीन बजे एम.आर.आई. कराएगा। सरकार यह नियम लेकर आये कि जो पी.पी.पी. मोड पर दिये हैं, एक व्यक्ति कर रहा है, यह सबसे बड़ा मजाक हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को ठेका दे दिया और वही चला रहा है। लोग पीड़ित हैं। आम आदमी परेशान हो रहा है, पर उसको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा कि एम.आर.आई. सेन्टर दो-दो, तीन-तीन खोले जाएं। चाहे पी.पी.पी. मोड पर खोलें, पर एक नहीं, दो-तीन जगहों पर खोले जाएं जिससे कि बीमार को सुविधा सुलभ हो सके।

अंत में मैं बात करते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सुपर स्पेशलिटी सेन्टर के जो डाक्टर्स हैं, डी.एम., एम.सीएच. करे हुए, चाहे वे

(श्री सुमित गोदारा)

असिस्टेंट प्रोफेसर हों, एसोसियेट हों या प्रोफेसर हों, सरकार ने जो फीस निर्धारित की हुई है, सभी जगह डाक्टर्स निर्धारित फीस से ज्यादा फीस वसूल कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे डी.एम. हो चाहे एम.सीएच. हो, उसकी सौ रुपये फीस है। पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान के किसी भी कोने में सरकारी डाक्टर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, डी.एम. का होगा, वह दो सौ-ढाई सौ रुपये से कम कहीं फीस नहीं लेगा। सरकार यह तय करे कि, सरकार ने नियम बना रखा है कि वह अपनी फीस चार्ट लगाए कि कितनी फीस लेनी है। वह हर जगह प्रदर्शित होनी चाहिए कि इतनी फीस लेगा। वह डाक्टर उससे ज्यादा फीस नहीं ले। उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि वह सरकार के माध्यम से ही सुपर स्पेशलाइज्ड डाक्टर बना है तो उसका धर्म सेवा करना है, न कि लोगों को लूटना है। सरकार यह कार्यवाही करे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): बस, माननीय सभापति महोदय, एक ही बात।

सरकार ने सी.एच.सी. पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 50-50 लाख की धर्मशालाएं बनाई थीं। वे बनी हुई पड़ी हैं। पर उसका कहीं भी उपयोग नहीं हो रहा है। 50-50 लाख की बिल्डिंग्स यूं ही व्यर्थ जा रही हैं, आज 5-5, 7-7 साल हो गये। तो सदन के माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि उन धर्मशालाओं को शुरू किया जाए ताकि बीमारों को सुविधा मिले। चाहे उसे किसी भी मोड पर दिया जाए पर लोगों को सुविधा मिले और जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार ने चिकित्सा के लिये किया है, वह व्यर्थ नहीं जाए।

अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए, बीकानेर का आचार्य तुलसी कैंसर सेन्टर, जहां मेरे पिताजी डाइरेक्टर रहे, उसके बारे में, जो पूरे नार्थ इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर सेन्टर है, जो हिज हाइनैस महाराजा गंगासिंहजी के समय बीकानेर में शुरू हुआ था। वहां पर एक डीएम., ओंकोलाजी व एम.सीएच., ओंको सर्जरी के नये पद सृजित किये जाएं जिससे बदलती मेडिकल साइन्स में कैंसर रोगी को लाभ मिल सके।

ओंको सर्जरी के लिये वहां पर एक दानदाता है, वह दो करोड़ रुपये देने को तैयार है। जगह वहां तैयार है। सरकार ओंको सर्जरी के लिये, दो करोड़ जो दानदाता दे रहा है, उसको स्वीकृति प्रदान करे ताकि लोगों को कैंसर की सुविधा मिल सके।

(श्री सुमित गोदारा)

टर्सरी कैंसर सेन्टर पर राज्य सरकार के द्वारा दो मशीनें देने की घोषणा की गई थी, वे अभी तक नहीं लगीं। माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि दोनों मशीनें लगाएं, जिससे कैंसर जैसी बीमारी है, जो इस समय ज्वलंत बीमारी है, उसका इलाज मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियॉजी।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय, मेरे को मांग संख्या-26 पर बोलने का मौका दिया।

मैं सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र से आती हूं। उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह क्षेत्र हरियाणा के बार्डर से सटा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दो नेशनल हाईवे राजगढ़-चूरू के 709 और 52 निकलते हैं। तेज गति के कारण या मैं कहना चाहूंगी कि आवारा पशुओं के कारण या किसी भी कारण से होने वाले एक्सीडेंट की तादाद काफी ज्यादा होती जा रही है जिसकी वजह से प्रियजनों को और उन क्षेत्रवासियों को काफी जन की हानि हो रही है। ट्रोमा सेन्टर नहीं होने के कारण, मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी, जैसा कि बताया हरियाणा से लगता होने के कारण ज्यादातर पेशेंट हिसार जिले में जाकर अपना इलाज करवाते हैं, जिससे राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का वे फायदा भी नहीं ले पाते हैं और हरियाणा में जाकर उन्हें महंगा इलाज करवाना पड़ता है जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान तो है ही। मैं कहना चाहूंगी कि जो सुविधाएं हम स्थानीय हास्पिटल में दे सकते हैं, उनके अभाव में उन्हें उनसे दूर जाना पड़ रहा है। मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से ट्रोमा सेन्टर खोलने की भी मांग करती हूं।

मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से सादुलपुर हास्पिटल को 50 बैड से क्रमोन्नत करके 100 बैड का करने की भी मांग करती हूं। साथ में, सादुलपुर हास्पिटल के अन्दर जितने भी रिक्त पद हैं, उनको भी जल्द से जल्द भरा जाए। मैं उनसे यह भी मांग करती हूं। खास करके सबसे ज्यादा समस्या रेडियोलोजिस्ट के बारे में हमें ज्यादा मिल रही है। मेरे काफी बार आग्रह करने के बाद भी, लेकिन राजस्थान सरकार में कमी होने के कारण मुझे लग रहा है कि यह व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही है। इसके लिये भी हमें कोई न कोई

(श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ)

ऐसा नियम बनाना चाहिए, जिससे ग्रामीण पृष्ठभूमि के अन्दर, हास्पिटल के अन्दर अगर रेडियोलोजिस्ट वहां पर मिलता है तो जो भी हमारी फेसिलिटीज, जिसके कारण रोगियों को सामना करना पड़ रहा है, उससे हमें निजात मिल सकती है।

वर्तमान में राजस्थान में तीन हजार व्यक्तियों पर एक बैड की व्यवस्था है जबकि अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार 25 से 30 व्यक्तियों के ऊपर एक बैड होना चाहिए। इसके साथ-साथ राजस्थान में मल्टी-स्पेशलिटी हास्पिटल की मान्यता के लिये राजस्थान सरकार ने कम से कम 150 बैड की अनिवार्यता रखी गई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि अगर 150 बैड की बजाय इसे 70 या 80 कर दिया जाता है तो कम दूरी में हमारे पास मल्टी-स्पेशलिस्ट डाक्टर मिल जाएंगे, हास्पिटल मिल जाएंगे जिससे, चाहे एक्सीडेंटल केस हो, चाहे सीरियस केस हो, अगर कम दूरी के ऊपर हमें अच्छे हास्पिटल मिल जाते हैं तो हमें इलाज पाने के लिये, ऐसी गम्भीर स्थिति में जब पेशेंट होता है तो उसे ज्यादा लम्बी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इसलिये सम्माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। राजस्थान की जन-स्वास्थ्य योजना, जिला स्तर पर 50 बैड की मल्टी-स्पेशलिस्ट सुविधा मिल जाती है लेकिन उसे 50 से 25-30 बैड करने से और भी हास्पिटल खुलने की सम्भावना बढ़ जाती है।

भारत में दुर्घटना से मौत के आंकड़े काफी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। प्रति वर्ष डेढ़ से दो लाख दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं, जिनमें से 25 से 30 प्रतिशत लोग या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या फिर ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं कि वे चलने-फिरने की, या किसी भी कार्य को करने की क्षमता में नहीं रह पाते। एक तरह से मैं कहना चाहूंगी कि न वे जीवित रहते हैं और न वे मरते हैं। ऐसे में हमारी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं और जो फेसेलिटीज हैं, उनको दूर-दराज ढाणियों में, गांवों में, रुरल एरिया में पहुंचाने के लिये हमें हमारे नियम भी थोड़े बदलने की आवश्यकता मुझे लगती है।

मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे इतना ही कहना चाहती हूं कि कुछ नियम ऐसे बनें, जिससे हम कम दूरी के ऊपर अच्छे हास्पिटल और अच्छे डाक्टर उपलब्ध करा सकें।

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगी कि डाक्टर्स ज्यादातर सिटी में रहना चाहते हैं और सिटी में काम करना चाहते हैं। उनके लिए भी कोई अनिवार्यता होनी चाहिए कि कम से कम इतना समय उन्हें रूरल एरिया में दिया जाए, यह कम्पल्सरी उनके लिए पीरियड होना चाहिए ताकि हमारे गांव-वासियों को, रूरल से आने वाले लोगों को चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं मिल सकें, अच्छा लाभ मिल सके।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि काफी बहस इसके ऊपर चलेगी लेकिन सम्माननीय मंत्री महोदय से यह जरूर कहना चाहूंगी कि ट्रोमा सेंटर और हास्पिटल को 100 बैड में क्रमोन्नत करने के लिए मैं मांग करती हूं और खासकर रेडियोलोजिस्ट के लिए मेरी काफी दिनों से मांग चल रही है। मैं यह भी उम्मीद करती हूं कि जो खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरा जाए और रेडियोलोजिस्ट को भी लगाया जाए। आप सबका बहुत-बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषय को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। मैं अपने इस वक्तव्य में कहीं भी किसी सरकार या मंत्री को कठघरे में खड़ा नहीं करना चाहता लेकिन जनता की जो मूल समस्याएं हैं, उनको रखने का प्रयास करूंगा।

सरकार आज इनकी है, पहले हमारी थी और आगे जिसकी भी होगी हम सब मिलकर एक ही विचार करें कि आमजन स्वस्थ रहें, क्योंकि आम जन जब स्वस्थ रहेगा तो उसका मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और निश्चित रूप से उसके कारण से पूरी तरह जनता के, देश के, समाज के विकास में भी उसकी भूमिका होगी इसलिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है लेकिन मुझे एक पीड़ा रहती है कि राजस्थान इस समय स्वास्थ्य सूचकांक में देश में 16वें नम्बर पर है। चिकित्सा के विस्तार की बहुत आवश्यकता है लेकिन इस बजट को देखते हुए यह लगता है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है। 2009-10 से लेकर 2013-14 तक चिकित्सा में, 2009-10 में इनका बजट था 1905 करोड़, 2013 में बढ़कर हुआ 2912 करोड़, 53 परसेंट की वृद्धि हुई

(श्री वासुदेव देवनानी)

लेकिन जब हम आए, हमने प्रारम्भ किया वर्ष 2014-15 में 3953.99 करोड़ से और जब 2018 में सरकार छोड़ी, उस समय बजट था 8729.8 करोड़ लेकिन वर्तमान बजट में आपने जो प्रावधान रखा है वह केवल 6717 करोड़ का रखा है यानी पहले से कम रखा है। राजस्थान को जब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, बीमारियां बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, चारों ओर अपने विधायक और सब लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे यहां पर व्यवस्थाएं सुधरें, नए हास्पिटल खुलें, डाक्टर्स आएं लेकिन यह वर्तमान बजट का जो अमाउंट है, उसको देखकर लगता है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है।

अब आपने घोषणा की कि नि:शुल्क दवाइयां देंगे, अच्छी बात है। नि:शुल्क जांच करेंगे, अच्छी बात है लेकिन इनको लागू करने के लिए किसकी आवश्यकता है? आज फार्मासिस्टों की 17 हजार पदों की जरूरत है और आपके स्वीकृत पद कितने हैं? स्वीकृत पद हैं 6646, उसमें से भी खाली कितने हैं? 1736 पद खाली पड़े हैं तो इतने सारे लोगों को आखिर दवाइयां कौन देगा? नि:शुल्क दवाइयों में जब पेशेंट जाता है तो उसको एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर घुमाया जाता है और कभी वह डाक्टर लिखता है पांच दिन की दवाई और वह उसको एक दिन की या दो दिन की देकर टालता है। दुबारा आकर फिर लंबी लाइन में खड़े हो, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं और वही परिस्थितियां जांचों के साथ है। जांचों की मशीनें खराब पड़ी हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं। आज जयपुर में ही केवल 105 मशीनें खराब पड़ी हैं जिसमें एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और जांचों की हालत तो यह है कि यदि किसी के पेट में दर्द है तो उसको सोनोग्राफी की तारीख दस दिन के बाद दी जाती है। ऐसे में नि:शुल्क जांच का लाभ कैसे मिलेगा?

हमारे अजमेर के जे.एल.एन. हास्पिटल में भी यही हालत है। उसको सात से दस दिन के बाद की डेट देते हैं। उसको आज जरूरत है सोनोग्राफी की लेकिन उसकी मशीनों के अभाव में वह दर-दर भटकता है, प्राइवेट हास्पिटल में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। और तो और जो बुजुर्ग हैं, पेंशनर्स हैं, वह श्वांस रोग, डायबिटीज, किडनी, हृदय, कैंसर जैसे गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त है। नि:शुल्क दवाइयां लेने के लिए सहकारी बाजार में जाते हैं लेकिन

(श्री वासुदेव देवनानी)

उनको दवाइयां उपलब्ध नहीं होतीं। वहां से एन.ए.सी. मिल भी गई, पैसा खर्च भी कर लिया लेकिन जब बिल देते हैं तो बिल का पेमेंट नहीं होता है। आज केवल जयपुर में ही 80 करोड़ का भुगतान बाकी है। पूरे राजस्थान-भर का निकालेंगे तो यह शायद बहुत ज्यादा अमाउंट आएगा।

फिर इन्होंने अभी जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की। दिखने में यह बड़ी अच्छी है कि हमारे मौहल्ले में क्लिनिक खुलेगा लेकिन खोलोगे कैसे? आपके पास स्टाफ कहां है? आज 45 परसेंट पद आपके खाली पड़े हैं। तीन हजार से अधिक तो केवल मेडिकल कालेज और इनमें ही डाक्टर्स के खाली हैं। अच्छी घोषणा करना अच्छा है, ताली बजवाना अच्छा लगता है और जनता में वाहवाही और धन्यवाद मिलना भी स्वाभाविक है। हममें से भी आपके दल के कुछ लोग कहेंगे लेकिन प्रेक्टिकली इन जनता क्लिनिक को चलाएगा कौन? क्या आपके पास डाक्टर्स हैं? क्या आपके पास ट्रेंड स्टाफ है? क्या वह अन-ट्रेंड स्टाफ से चलाओगे या झोलाछाप डाक्टर्स से चलाओगे तो उसके आधार पर स्थितियां और बिगड़ेंगी, सारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी।

आपने बजट में पांच नए ट्रोमा सेंटर खोलने की बात की, खोलने चाहिए लेकिन जो पुराने खुले हुए हैं, जरा आपने उनकी स्थिति देखी है क्या? मैं अजमेर के ट्रोमा सेंटर के बारे में कह सकता हूं कि वहां पर आपका स्टाफ नहीं है और वहां पर केवल एक आर्थोपेडिक वार्ड के रूप में चल रहा है। आप अजमेर के हैं, जिस प्रकार हनुमानजी को अपनी शक्ति की याद दिलानी पड़ती है, आपको भी याद दिला रहा हूं कि आप अपने आपको केवल केकड़ी का विधायक या केकड़ी का मंत्री न मानें, आप जरा इसकी चिंता करें कि ट्रोमा सेंटर जो खुले हुए हैं उनके लिए भी स्टाफ की व्यवस्था हो, संसाधनों की व्यवस्था हो, उसके बिना निश्चित रूप से चाहे आप ट्रोमा सेंटर कितने ही नए खोलते जाओ लेकिन जनता को किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है।

चिकित्सा विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। एस.एम.एस. हास्पिटल में आपके लाइफ लाइन स्टोर में आग लगी। जांच के लिए बैठे, जांच कौन कर रहा है, जो कोई कहीं न कहीं उसमें भागीदार है और फिर आज ही अख़बार में पढ़ा कि केवल एक जूनियर व्यक्ति को आपने सस्पैंड करके और दूसरे दो-तीन को नोटिस देकर इतिश्री मान ली। माननीय सभापति महोदय, इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसके लिए मेरा तो आरोप है कि सत्ता

(श्री वासुदेव देवनानी)

के नजदीक के लोगों तक यह शक की सुई जा रही है इसलिए इस मामले में अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। इसकी निष्पक्ष जांच करवाकर जो एक्चुअल दोषी लोग हैं, उनको सज़ा मिले तो ही आपकी वाहवाही होगी, बाकी वहां पर जो मिलीभगत चल रही है, उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा।

इसके साथ ही, एन.आर.एच.एम. के जो ढाई हजार पद थे, उसकी तो आपको जानकारी है ही कि क्या हुआ? अब कहा जाता है कि साहब, इनका दोष नहीं है। एक माननीय सदस्य ऐसा कह रहे थे। आपने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी। ए.सी.एस. कह रहा है कि आपको जानकारी नहीं थी लेकिन ए.सी.एस. ने उस एग्जिक्यूटिव मीटिंग की अध्यक्षता की है। उसके मिनट्स में उसने साइन किए हैं। वह फाइल यदि आप तक नहीं आई तो ए.सी.एस. की गलती है और आपने दूसरे नीचे के सैक्रेटरी को अपने विभाग से हटा दिया। यह आपका अधिकार है, आप हटा सकते हो लेकिन इसके पीछे कहा गया, लाख-डेढ़ लाख की रिश्वत की बात आई। कौन है? जो कम्प्लेंट है उसकी जांच तो करें। दोषी व्यक्ति तक तो पहुंचो। अब ढाई हजार आपने यह पद नहीं भरे उसके कारण से राजस्थान को 600 करोड़ का नुकसान हुआ। आपने तीन-चार करोड़ की बात कही। आप देखना अब जो बजट केन्द्र से आएगा तब भी आप हमको ही कहेंगे तो हम तो आपकी मदद राजस्थान के लिए करेंगे कि छह सौ करोड़ मिलें लेकिन उसमें यह तय है कि 30 दिसम्बर तक हमने यह नहीं करवाए तो अगले आप एक जनवरी को करेंगे, एक जनवरी वाले छह महीने के लिए होंगे, छह महीने तीस जून तक होंगे तो 31 मार्च तक आपके टार्गेट पूरे नहीं होंगे, आप इसको जरा देख लीजिए।

उसके साथ आज नकली दवाइयां खूब बिक रही हैं जिसके अंदर अल्सर, बुखार, सिर दर्द तक की दवाइयां और फिर आपके सैम्पल लेने की भी अव्यवस्था है। आज भी छह हजार सैम्पल बिना जांच के पड़े हुए हैं, चाहे वह अजमेर हो, चाहे जोधपुर हो या अन्य स्थानों पर हो। अचानक दवाइयों के सैम्पल फेल हो रहे हैं उसके मामले में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल एस.एम.एस. है। 80 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है। आपने एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई

(श्री वासुदेव देवनानी)

थी। एम.एन.आई.टी. के इंजीनियर्स की कमेटी बनी, उन्होंने जांच करके उसकी रिपोर्ट दी, आप उस रिपोर्ट को तो पढ़ें। रिपोर्ट में कहा है कि यह जर्जर हो गयी है। आज इतना बड़ा हास्पिटल है, पता नहीं कब क्या दुर्घटना हो जाए, उस बिल्डिंग की जांच की रिपोर्ट पढ़कर आज असुरक्षित है और रोजाना वहां पर प्लास्टर गिरने की खबरें अख़बारों में आए दिन आती रहती हैं और वहां का ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है।

आज अजमेर के जे.एल.एन. हास्पिटल की बिल्डिंग के कई वार्डों की हालत खराब है। जरा चिंता तो करो, तब जाकर ठीक होगा और डिपार्टमेंट के पास यदि हमारी सरकार कुछ बनाकर जाए, इनको शुरू कराने की भी फुर्सत नहीं है।

आज आपका स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट 500 करोड़ की लागत से बना हुआ पड़ा है और केवल आप तय करो, आज तक शुरू नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि जो एस.एम.एस. में डाक्टर्स और स्टाफ बैठे हैं, वह दूर जाना नहीं चाहते। यह लोग वहीं जमा रहना चाहते हैं। इसके कारण से उस अस्पताल का उद्घाटन नहीं हो रहा है।

फिर आपने एलोपैथी की तो चिंता थोड़ी बहुत की। आज राजस्थान के लगभग 25 परसेंट पेशेंट आयुर्वेद को अपनाते हैं। उसके लिये बजट के अंदर कहीं एक शब्द भी नहीं है। करें क्यों, क्योंकि भारतीयता के साथ और भारत के साथ कहीं आपका मोह नहीं है। आप सोचते हो जो भी भारत के गौरव की बात है, चूंकि आयुर्वेद इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसके लिये क्यों चिंता की जाए। इसलिये मैं आपसे आग्रह करता हूं आयुर्वेद पद्धति आज भी एलोपैथी से कई गुना बैटर है। जड़ से बीमारी को नष्ट करती है। उसकी ओर विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और तो और, अभी मेरे से पूर्व हमारी पार्टी के वक्ता, ज्ञानजी ने कहा कि हम पुरानी परम्पराओं और योग को अपनाएंगे तो रोग ही शुरू नहीं हो, इसके लिये योग दिवस 21 जून को मनाया गया। पिछली बार 2018 के अंदर कोटा के अंदर अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो राज्यस्तरीय कार्यक्रम था, उसमें एक लाख पांच हजार लोगों ने भाग लिया और उसने वर्ल्ड रिकार्ड स्थापित किया। इस बार आपकी सरकार आने के बाद क्या किया? आपने अजमेर में स्टेट लेवल का तो रखा, आप स्वयं उसमें थे, मैं भी था। कितनी संख्या थी और कौन मंत्री और बाकी के

(श्री वासुदेव देवनानी)

लोग, राजस्थान के कहां थे? यानी आपका योग के प्रति किसी प्रकार का जुड़ाव ही नहीं है। यानी योग से ही बीमारियां नष्ट होती हैं।

आज भी कह रहा हूं, इतने लोगों की चर्चा हुई, यदि आप लोग लौकी का जूस पीना शुरू करें तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, राजस्थान भी स्वस्थ रहेगा, हार्ट भी अच्छा होगा, एसिडिटी भी नहीं होगी। कई प्रकार की बीमारियां दूर होंगी। इसलिए आप प्राचीन पद्धति और प्राचीन चिकित्सा पद्धति की ओर थोड़ा ध्यान तो देने का विचार करें।

अब एक अत्यन्त ही गम्भीर व्यवस्था की चर्चा कर रहा हूं, जो पूरे राजस्थान की है। सभी प्रमुख अस्पतालों में कैजुअलिटी वार्ड तो हैं, लेकिन उस कैजुअलिटी वार्ड में एक भी सीनियर डाक्टर रात को नहीं मिलता। कोई गम्भीर से गम्भीर भी पेशेंट आ जाए तो वह रेजिडेंट के भरोसे रहता है। इसलिए आवश्यक है कि रोटेशन में हर जगह कम से कम कैजुअलिटी वार्ड में एक सीनियर आदमी को आप बैठाएंगे तो निश्चित रूप से उस पेशेंट को इलाज मिलेगा। और तो और, मुझे लगा कि आपके अधीन जितने भी अस्पताल हैं कालेज के, उसमें कार्यवाहक लोग लगे हुए हैं। और तो और मुख्य मंत्री के गृह जिले के अंदर, जो तीन हास्पिटल हैं - महात्मा गांधी हास्पिटल, उम्मेद हास्पिटल और मथुरादास हास्पिटल, उनमें आज भी सुपरिंटेंडेंट कार्यवाहक हैं। आपने तो कार्यवाहक रख दिये, लेकिन उसका खामियाजा अजमेर को भुगतना पड़ा।

मुख्य मंत्रीजी ने मेडिसिटी की घोषणा नहीं की, क्योंकि आप उनके जिले की घोषणा नहीं करोगे, वह आपके जिले की नहीं कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति बने, मेरा आपसे आग्रह है कि कार्यवाहक एस.एम.एस. में भी है, अजमेर में भी है, तो इस प्रकार की कार्यवाहक पद्धति आप यदि समाप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा।

मैं चूंकि, समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, आप देख रहे हो, मैं केवल अब अपने अजमेर की ओर आ रहा हूं। आज अजमेर का जो जे.एन.एल. हास्पिटल है, जब आप चिकित्सा मंत्री बने तो हमें बड़ी आकांक्षाएं जगीं और अब तो अजमेर की सारी चिकित्सा की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन पिछले सात महीनों से हम बहुत निराश हुए और आज जब जवाहर लाल नेहरू हास्पिटल खुद वेंटिलेटर पर है, अजमेर को आपने मेडिसिटी का

(श्री वासुदेव देवनानी)

सपना दिखाया, परन्तु बजट मौन है। क्षेत्रवासी बरसों से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी है और हम सोच रहे थे बजट में अनाउंसमेंट होगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बिना निश्चित रूप से अजमेर का भला होने वाला नहीं है।

माननीय मंत्रीजी, आपसे एक निवेदन करूंगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हास्पिटल केवल केकड़ी का नहीं है, केकड़ी की जनता है, अजमेर संभाग का हास्पिटल है। पूरे भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, अजमेर के लाखों लोग वहां से जुड़े हुए हैं और उसके अंदर सीटी स्कैन मशीन केवल एक ही है। वह भी क्षमता से अधिक काम कर चुकी है, खराब पड़ी है। इसलिए मैं आपकी ओर से मांग कर रहा हूं कि कम से कम दो सीटी स्कैन मशीन वहां पर रहे। कम से कम एक कैजुअलिटी में और दूसरी ओ.पी.डी. में तो निश्चित रूप से इलाज होगा। दूसरा, चिकित्सालय में दो सोनोग्राफी मशीनें तो हैं, लेकिन एक-एक पेशेंट को सात से दस दिन का समय मिल रहा है। जांच के अभाव में मरीज को कोई इलाज नहीं मिल रहा है। चिकित्सालय में कम से कम दो और सोनोग्राफी मशीनें लगनी चाहिए। चिकित्सा में हमने नया कैजुअलिटी वार्ड बनाया तो शायद बाकी राजस्थान के कई हास्पिटल्स से अच्छा है। आपने उसका उद्घाटन भी किया, लेकिन उसके अंदर सेंट्रल आक्सीजन सिस्टम और सेंट्रल सकिंग सिस्टम नहीं है, जिससे आने वाले गम्भीर मरीजों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। चिकित्सालय में इस समय अधिकतर वेंटिलेटर खराब पड़े हैं, उनको जरा आप ठीक कराएं।

सभापति महोदय, हमारे मेडिकल आई.सी.यू. की हालत खराब है। ए.सी. खराब पड़े हैं, कूलर आदि की व्यवस्था नहीं है। गम्भीर से गम्भीर मरीज परेशान होता है। और तो और, मेल मेडिकल वार्ड नंबर एक दो वर्ष से बंद पड़ा है। प्रशासन ने कहा इसका रिनोवेशन कराना चाहते हैं, होना चाहिए। आखिर कितना समय बंद रखेंगे, दो वर्ष से बंद पड़ा है। यह कार्य नहीं करने से 60 पलंग की क्षमता वाला वार्ड बेकार पड़ा है। डिजीटल एक्स-रे और दंत एक्स-रे की फिल्में नहीं हैं। इस कारण से मरीजों को मजबूरन निजी केन्द्रों पर जाना पड़ता है। जनाना हास्पिटल में लैब नहीं होने से आवश्यक जांच के लिये सैम्पल लेकर आने पड़ते हैं। मेरी आपसे अपेक्षा है जे.एन.एल. मेडिकल कालेज में न्यूरोलोजी, यूरोलोजी और गेस्ट्रोलोजी में एम.सी.एच. कोर्स आप प्रारम्भ कराएंगे और आपके जो अजमेर में खाली पद हैं, जो 322 में से 149 पद

(श्री वासुदेव देवनानी)

खाली पड़े हैं, जरा उनको आप भरें और यूरोलोजी विभाग के तो हाल इससे और बुरे हैं। एक मिनट और लूंगा। वहां पर सुविधाओं का अभाव है। ए.सी. तो छोड़ो, पंखे और कूलर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जरा एक बार आप हमारे साथ विजिट करो, खुद विजिट करोगे तो आपको ध्यान आएगा कि उस जगह, उस वार्ड में आपका कोई परिचित रह सकता है क्या? यह सारी स्थिति है।

अजमेर में एक आयुर्वेद महाविद्यालय खोला जाए। साथ में, हास्पिटल में हमारे बड़े प्रयासों से कार्डियोथोरोसिक सेंटर तो उपलब्ध हैं, परन्तु विशेषज्ञ सर्जन नहीं हैं। सर्जन नहीं होने से सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। न्यूरोलोजी, नेफ्रोलोजी विभाग में विशेषज्ञ नहीं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय हाथीखेड़ा पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करोगे तो ग्रामीण जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा।

इसी तरह पंचशील क्षेत्र के अंदर कुंदानगर क्षेत्र में एक पी एच सी की आवश्यकता है और हमारे शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो हमारे पिछले स्वास्थ्य मंत्रीजी ने हमें दिया था, उसका निर्माण पूरा हो चुका, जरा उसको शीघ्र प्रारम्भ कराएं। मैं सोचता हूं यह अजमेर की कुछ आवश्यकताएं हैं जो लाखों लोगों की हैं। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि अपने आपको हनुमान की तरह शक्ति को पहचानो और चिकित्सा की समस्याएं राजस्थान की तो दूर करो, लेकिन अपने गृह जिले की भी दूर करके लोगों की दुआएं लो, ताकि आप और आगे बढ़ो। जनता की समस्याओं का समाधान हो। हालांकि बजट को देखते हुए हमें कोई विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, यह बजट आप किसी तरह से बढ़वाएं और हमारी अजमेर की समस्याओं का समाधान करें, राजस्थान की समस्याओं का समाधान करें। व्यक्ति को स्वस्थ रखने में आगे आएं, भारतीय पद्धतियों को सम्मान दें ताकि हम सब लोग आगे बढ़ सकें, राजस्थान स्वस्थ रहे।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण जी मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। माननीय सभापति महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह हमारे प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से

(श्री लक्ष्मण मीणा)

संबंधित मामला है। इस पर सभी हमारे माननीय विधायकों ने अपने-अपने विचार रखे हैं।

माननीय सभापति जी, लोक स्वास्थ्य के लिये जो घातक है और जो इसकी जड़ है, वह है मिलावटी खाद्य पदार्थ, मिलावटी दूध, मिलावटी दवाइयां और प्रत्येक चीज, जो हम खाते हैं, हम पीते हैं, उनमें सबमें मिलावट है। दूसरा है पेस्टीसाइड्स का अन-कंट्रोल्ड-वे में प्रयोग। तीसरा है गंदे पानी से सब्जियां उगाना, गेहूं पैदा करना और उसको मार्केट में लाकर बेचना, जिसमें सीधे-सीधे कैमिकल्स और ऐसी चीजें होती हैं, जो सीधे हार्ट-अटैक और कैंसर के लिये जिम्मेदार होती हैं।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, अपन देखते हैं कि जब शादी का सीजन होता है तो उस समय जयपुर जैसे शहर में 1500 से 2000-2500 शादियां होती हैं, लोग वहां भारी संख्या में आते हैं और वहां दूध, मावा और मिठाई परोसी जाती है लेकिन यह समझ में नहीं आता कि उस टाइम में कौनसी, कितनी गायें, भैंसें और वह दूध कहां से आता है जो सारे लोगों को सप्लाई किया जाता है? माननीय सभापति महोदय, यह बनावटी दूध होता है, फर्जी होता है और केमिकलयुक्त होता है, इसमें यूरिया मिलाया जाता है और उस दूध से मिठाइयां बनती हैं, मावा बनता है, कई चीजें बनती हैं और हम उसका उपभोग करते हैं और वो सीधे-सीधे आपके हार्ट अटैक, कैंसर और डायबिटीज के लिए कॉज होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस्सी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वहां किसी के गमी होती है जब हम जाते हैं, क्योंकि हम राजनीति में हैं, सब जगह जाना पड़ता है, तो इस इलाके में जो सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, हमारे माननीय विधायक जी ने बताया था कि सबसे ज्यादा कैंसर के केसेज गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब साइड में हैं लेकिन यह बीमारी सभी जगह है, राजस्थान के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में ईवन रूरल एरियाज में जहां स्वच्छ हवा मिलती है, स्वच्छ पानी भी मिलता है वहां भी यह बीमारी फैल गयी है। तो सबसे ज्यादा जो डैथ हो रही हैं वे कैंसर से हो रही हैं, वे हार्ट अटैक से हो रही हैं, ईवन यंग-यंग बच्चे जिनकी उम्र 15-20 साल है उनकी भी हार्ट अटैक से डैथ हो रही है। कैंसर और हार्ट अटैक है, गांव में कोई भी

(श्री लक्ष्मण मीणा)

अपने स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से नहीं कराता है और जब इन बीमारियों का पता चलता है, हार्ट अटैक में तो जब डैथ हो जाती है कि इसकी अचानक मौत हुई है, हार्ट अटैक हुआ है और कैंसर से जब वो लास्ट स्टेज पर होता है तब पता चलता है। माननीय सभापति महोदय, जब तक इन चीजों पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा चाहे कितनी भी चिकित्सा सुविधाएं दे दें, कितने ही हास्पिटल खोल दें, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जिस स्पीड से अपन हास्पिटल्स, डाक्टर्स लगा रहे हैं, इलाज की सुविधा दे रहे हैं, फ्री दवाइयां दे रहे हैं लेकिन फिर भी कम पड़ रही है तो मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि जो मिलावटी चीजें हैं उन पर और पेस्टिसाइड पर प्रतिबंध लगाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस्सी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे वहां तीन सी.एच.सी. हैं और तीनों को पांच साल पहले खोला था। अभी तो उनको जमीन भी आबंटित नहीं हुई है। दो सी.एच.सी. जो चल रही हैं उनमें 50 परसेंट भी स्टाफ नहीं है तो वे नाम मात्र की सी.एच.सी. हैं। ये सी.एच.सी. खोलने से क्या फायदा जब तक वहां कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ, मेडिकल आफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं लगा दें तब तक कोई फायदा नहीं होगा।

नि:शुल्क दवाइयां माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, अभी भी 104 और एड की हैं, 608 पहले थीं लेकिन उनको भी कोई बांटने वाला, उनको लिखने वाला, इलाज करने वाला तो होना चाहिए। इस पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो स्टाफ की कमी है, उसकी पूर्ति की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बस्सी विधान सभा क्षेत्र में पिछले 60-70 साल में जितनी चिकित्सा सुविधा थी उसके बराबर, जितनी पहले थी उसके बराबर माननीय अशोक गहलोत साहब की पिछली सरकार ने 2008 से लेकर 2013 में हास्पिटल्स खोले, डाक्टर्स लगाए लेकिन अभी तक उनकी जमीनें नहीं हैं, डाक्टर की बैठने की जगह नहीं है। महिला डाक्टर लगा दी जाती हैं, लेकिन गांवों में जहां हास्पिटल है वहां उनको मकान नहीं मिलता, क्वार्टर्स नहीं हैं, वे ठहरते नहीं हैं तो माननीय चिकित्सा मंत्री जी इस बात पर भी ध्यान देंगे कि जहां-जहां हास्पिटल हैं उनके डाक्टर्स के लिए रहने की जगह होनी

(श्री लक्ष्मण मीणा)

चाहिए ताकि नाइट के समय अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा मरीज आता है तो उसको तुरन्त डाक्टर वहां उपलब्ध हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, अभी कहने को तो यह है कि वहां चौबीसों घंटे डाक्टर रहता है लेकिन उनका जो समय निर्धारित है उसके अलावा डाक्टर मिलते ही नहीं हैं। बस्सी की सबसे बड़ी समस्या है कि वहां बस्सी में वही डाक्टर लगते हैं जो जयपुर में रोज अप-डाउन करते हैं। मान लो अगर उनके समय के अलावा कोई एक्सीडेंट होता है या लोग गम्भीर बीमारी से आते हैं तो उनको वहां चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। माननीय सभापति महोदय, इस वजह से भी यह सम्भव नहीं हो पा रहा कि उनकी रहने की जगह ही नहीं है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारी दो और जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक खतेपुरा और लालगढ़, वहां भी पी.एच.सी. खोली जाएं ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक सफाई की बात है, पहले भारत सरकार ने जब कांग्रेस की सरकार थी निर्मल भारत के नाम से एक अभियान चलाया था, उसमें बहुत सारे टॉयलेट्स बने थे। इसके बाद उसका नाम बदल कर स्वच्छ भारत मिशन चलाया, इसमें भी काफी अच्छा काम हुआ है और जो टायलेट्स बने हैं उसकी वजह से जो लोग शौच के लिए बाहर जाते थे वे करीब-करीब 80-85 परसेंट बंद हो गये हैं। इसकी वजह से जो स्वच्छता अभियान था उससे फायदा हुआ है, उससे लोक स्वास्थ्य को भी फायदा हुआ है। लेकिन जहां बड़े कस्बे हैं वहां जगह-जगह गंदगी रहती है। अभी बरसात का मौसम है, जैसा कि कोटा से आने वाली माननीय विधायक स्नेक बाइट का बता रही थीं, स्नेक बाइट के कई इलाकों में हास्पिटल्स में वे इंजेक्शन होते ही नहीं हैं और माननीय सभापति महोदय, अब बरसात का मौसम है, इसमें स्नेक बाइट की बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रत्येक हास्पिटल में स्नेक बाइट के इंजेक्शन होने चाहिए और हास्पिटल के डाक्टर्स को पता होना चाहिए कि कौनसा कीड़ा, कौनसा जहरीला कीड़ा खाने पर कौनसा इंजेक्शन लगाया जाएगा।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

माननीय सभापति महोदय, अभी मच्छर पैदा होने लग गये और इनकी वजह से भी कई बीमारियां, चिकनगुनिया और कई तरह के अलग-अलग नाम आजकल बीमारियों के हैं, बुखार हैं, कई तरह के वायरल हैं तो यह मच्छरों की वजह से होता है तो अभी से छिड़काव होना चाहिए, सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए तो लोगों का जो लोक स्वास्थ्य है वह अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा तो उसकी वजह से लोगों को गरीबी में डाक्टर के जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं वे नहीं करने पड़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज और कहूंगा कि यह जो झोलाछाप डाक्टर होते हैं फर्जी, कई इलाके में बंगाली डाक्टर भी बोलते हैं, कोटा साइड में बंगाली डाक्टर्स के मार्केट के मार्केट हैं, यह भी लोक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए। ये ऐसी मेडिसिंस देते हैं जो लेने वाले को एक बार तो लगता है कि बिलकुल इलाज हो गया लेकिन बाद में उसको साइड इफैक्ट्स होते हैं, किडनी खराब होती है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इस पर भी सरकार पाबंदी लगाए और उन पर प्रतिबंध लगा कर यह सुनिश्चित करे कि वे लोग बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सरकार की अनुमति के कोई इलाज नहीं करे। आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 'आज उसने हंस कर पूछा मिज़ाज, उम्र भर के रंजो गम याद आते हैं।' स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। जनहित में गरीब, जरूरतमंद, कमजोर वर्ग को हम स्वास्थ्य सुधार के लिए संसाधन उपलब्ध कराएं, यह हमारी जिम्मेदारी है। सर्वप्रथम तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहूंगी कि अभी-अभी आपके सामने आफर आई थी कि लौकी का जूस पीएं और स्वस्थ रहें। मैं नहीं चाहती हूं कि आप लौकी का जूस पीकर के अस्वस्थ हो जाएं, क्योंकि अभी पूर्व में सदस्य बोलते हुए कह रहे थे कि इतनी पेस्टिसाइड और मिलावट है कि रात को वह होती नहीं है और सुबह 2 फुट की लंबी हो जाती है। ऐसी लौकी का जूस पीकर के अस्वस्थ मत हो जाइए।

सभापति महोदय, बजट प्रोविजन से स्टार्ट करूंगी। अभी पूर्व में बहुत से वक्ताओं ने कहा कि जो बजट एलोकेशंस सोशल सेक्टर में, वैसे तो हमारे

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

43 approx सबसे ज्यादा इन्क्रीज हुए हैं, मगर स्वास्थ्य के अंदर बजट को बढ़ाने की जरूरत है। मैं इस बात का बिलकुल समर्थन करती हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सरकार की इस अदला-बदली के अंदर बहुत कम बजट, आपने भी हमारी सरकार के अंदर वापस आते हुए स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया नहीं। आज भी, कभी 1 टू 2 परसेंट और GSDP हमारे स्वास्थ्य का बजट होता है। Developed economies के अंदर कम से कम 8 टू 9 परसेंट आफ GSDP होता है और उनकी जीडीपी भी बहुत huge होती है। हमारा per capita expenditure on health in Rajasthan is about Rs. 789 and on average it is Rs. 785, बिलकुल मार्जिनल टच कर रहे हैं। सिक्किम और दूसरे जो छोटे स्टेट्स हैं, उनका per capita expenditure is Rs. 4480 but उनका क्षेत्रफल छोटा है। लेकिन बहुत से प्रांत ऐसे हैं जो हमसे बेहतर कर रहे हैं और बड़े क्षेत्रफल के हैं। निश्चित रूप से we have to invest a lot more, the investment in health is obvious to manipulate.

सभापति महोदय, जो हमारे हैल्थ इंडिकेटर्स हैं, निश्चित रूप से they're in very poor conditions. हमारी infant mortality rate is about 38, हमारी मैटरिनिटी मोर्टेलिटी की रेट 199 है। सैक्स रेशो इज 928, जो कि इक्वल होना चाहिए। जो भी टार्गेट सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स के तहत 2015 के लक्ष्य थे, उन्हें भी हम नहीं छू पाए। 2030 के जो लक्ष्य हैं, उनको छूना है तो उसके लिए हमें बहुत रिफार्म इस सैक्टर में लेकर के आने पड़ेंगे। हैल्थ इंडिकेटर्स कैसे इम्प्रूव होंगे? स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से तो किसी भी तरीके से यह हैल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव नहीं हो सकते। इनको इम्प्रूव करने के लिए हमें बजटीय प्रोविजन इन्क्रीज करने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, दूसरा लक्ष्य जो हमारा है, Out of Pocket Expenditure (OOP) इसको कम करने की आवश्यकता है। यह भी हमारा एक प्राथमिक गोल है। या तो इलाज के लिए लोग पहुंचते नहीं हैं, पहुंचते हैं तो अधूरा इलाज कराते हैं या फिर इलाज के चलते Out of Pocket Expenditure (OOP) से गरीब हो जाते हैं। NSO और NHA की 71 राउंड में यह कहा गया है कि अबाउट 5.5 करोड़ OOP के कारण गरीबी की रेखा से नीचे आ गए हैं। अगर उसको कैलकुलेट करें कि हमारी जनसंख्या 7 करोड़ है तो approximately 29 लाख लोग catastrophic out of pocket expenditure

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

के कारण गरीबी रेखा में आ गए हैं। इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। IPHS (Indian Public Health Standards) जो ड्राफ्ट था 2005 में जिसको 2012 के अंदर रिवाइज किया, वह तो अभी बहुत दूर का सपना है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। कोसों दूर है। 50 प्रतिशत भी हम उन स्टैंडर्ड के पास नहीं पहुंच पाए हैं।

सभापति महोदय, दूसरी बात, what Rajasthan is facing at the moment is the ‘double burden disease’ पहले हमारी 10 में से 6 मौतें communicable diseases से होती थीं और आजकल हमारी 10 में से 7 मौतें non-communicable diseases से होती हैं। 40 प्रतिशत डैथ्स CMNND से होती हैं, communicable diseases, maternal diseases, neonatal nutritional diseases. 11 प्रतिशत डैथ्स एक्सीडेंट और इंजरीज से होती हैं and the rest of them by non-communicable diseases से होती हैं। यह आंकड़ा बढ़ गया है। यह सब लाइफ स्टाइल चेंजेज के कारण है।

सभापति महोदय, इनको कैसे कम कर सकते हैं? We'll have to focus. हमें हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा जो कि बहुत कमजोर है, बिलकुल चरमरा गया है। हमारा हैल्थ सेक्टर तीन लेयर्स में बंटा हुआ है primary, secondary और tertiary. हमें जरूरत है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स कॉज करें, प्राइमरी हैल्थ केयर भी दो भागों में बंटा हुआ है। हैल्थ एजुकेशन एवं प्रिवेंटिव मेजर्स बीमारी की रोकथाम और अगर कोई बीमारी हो जाती है तो कफ आदि जिनका कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार मिल जाना चाहिए, वह उपचार हम दिला पाएं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नल खुला है और हम पोचा लगाते जा रहे हैं। बीमारियों की रोकथाम पर हम काम करें नहीं। हमारी जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, वह सैकण्डरी और टर्शरी लेयर्स के ऊपर स्पैंडिंग कर रही हैं। जरूरत है कि हम इसकी नीचे से एक डी-सेन्ट्रलाज्ड योजना बनाकर लेकर आएं।

सभापति महोदय, आपके SMS की ओपीडी which is about approximately 60 lakhs per annum. एम्स से भी ज्यादा हो गई है। सिक्स टाइम हमारी ओपीडी बढ़ गई है। एक तो यह जुकाम जैसी चीजें जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या अरबन पीएचसी में जाकर दिखा सकते हैं। उसके लिए भी एसएमएस की ओपीडी पर भार आ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

अभाव के कारण या तो 2 एएनएम बैठी हैं, या पीएचसी के ताला लगा है। वहां पर जांच जो करनी चाहिए, वह उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमें जरूरत है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत क्लीयर होना चाहिए। स्ट्रीम लाइन करना पड़ेगा। यह अब नीड आफ दी आवर हो गई है। रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन युक्तिसंगत हमें रिसोर्सेज को बांटना पड़ेगा। जब तक जमीनी स्तर से स्वास्थ्य की योजना नहीं आएगी, डीसेन्ट्रलाइज्ड हैल्थ प्लानिंग नहीं होगी, हम हैल्थ इंडिकेटर्स को और हैल्थ के गोल्स को मीटअप नहीं कर पाएंगे।

जैसे कि Village Health Sanitation and Nutrition Committees (VHSNCs) अब इतने सारे विधायक हैं, मुझे बताइए कि क्या वह चलती है? बिलकुल पंगु अवस्था में है। आन पेपर है। हमें इस डिसेन्ट्रलाइजेशन को नीचे से ऊपर उठाना पड़ेगा। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। पीएचसीज की एक ओर चीज है कि हमने अभी पोपुलेशन के नार्म्स पर कर रखा है। मुझे लगता है कि we need to change these population norms क्योंकि अलग-अलग एरिया में जैसे उनकी पोपुलेशन कम कर रखी है जैसे हिली, डेजर्ट और छितराई हुई ढाणियां हैं। जैसे सीएचसी में मुझे लगता है कि one hour motorized distance होना चाहिए। अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो पहला एक घंटा, जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उसमें नहीं पहुंचता है, अगर सीएचसी एक घंटे से दूर है तो सैकिण्ड आवर के अंदर 50 प्रतिशत से भी कम उसके बचने के चांसेज होते हैं। पीएचसी हमारे को कभी 3 किलोमीटर या फिर हाफ एन आवर, वाकिंग डिस्टेंस जहां पर कोई मां अपने बच्चे को गोद में लेकर चलकर जा सके, क्योंकि गांवों के अंदर संसाधन नहीं हैं। कई बार आपको वहां पैदल जाना पड़ता है। वहां पर इतनी व्यवस्था नहीं होती है। दूसरी चीज, इन पीएचसीज के अंदर अभी भी हमारे वह माइक्रोस्कोप से जांच होती है जिससे 10 या 12 जांच होती होंगी। ब्लड सैल काउंट्स, सेमी आटो एनेलाइजर, आटोमैटिक इंस्ट्रूमेंट्स जांच के लगाने चाहिए जिससे कम से कम 35 जांच जिनमें यूरिया, हीमोग्लोबिन, सीडब्ल्यूसी इस तरह की जो प्राथमिक जांचें हैं, उसको वह सुविधा वहीं पर मिल जाए।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं अब आना चाहूंगी हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के ऊपर चाहे वह भामाशाह हो, चाहे सेंटर से आई हों। पूर्व में माननीय सदस्य इसके बारे में बता रहे थे।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

मौत का भी इलाज हो शायद,

जिंदगी का कोई इलाज नहीं

जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो प्राइवेट चाहे कोई भी संस्था हो, उसका अल्टीमेट मोटिव बिजनस रहेगा, प्रोफिट रहेगा। प्रोफिट मोटिव, मनी, और इसको कैसे साधेगा? एक्सप्लायटेशन से। जो आज आप कहते हैं कि हमारी मिक्स इकोनामी है, एक हमारा पब्लिक हैल्थ केयर है और एक प्राइवेट हैल्थ केयर है। जो प्राइवेट हैल्थ केयर है, वह भी पब्लिक हैल्थ केयर के ऊपर ही थ्राइव कर रहा है।

मैं अभी देख रही थी, मालपुरा के अंदर एक एपीओ भी किया। मंत्री महोदय के संज्ञान में होगा कि एक प्राइवेट के लिए पर्ची देते हुए पकड़ा गया। यह एक आम प्रेक्टिस है जो सब कोई जानता है। पब्लिक हैल्थ केयर में बैठे हुए डाक्टर्स भी प्राइवेट में प्रिसक्राइब करते हैं। इन योजनाओं के अंदर पहले से पैकेजेज इनके तय होते हैं। इम्पैनल्ड हास्पिटल्स के अंदर ही आप सुविधा ले सकते हैं। मान लीजिए आपको हार्ट अटैक या ऐसी कोई चीज हो गई दुर्लभ, जो इस पैनल में है ही नहीं, तो वह अधमरी सिचुएशन में कौनसा दूसरा हास्पिटल ढूंढेगा? उसको कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी जाएगी। वह कोई मदद नहीं करेंगे। वह रात को मरता, पड़ता जा रहा है, उसको क्या पता कि इसमें कौनसा पैकेज है, कौनसा नहीं है?

सभापति महोदय, यह जो बीमा योजनाएं हैं, मेनली इनमें सर्जीकल पैकेजेज हैं और यह सैकण्डरी और टर्सरी लेयर को ही कवर करते हैं। यह पीएचसी की लेयर को कवर नहीं करती। बिना इंडिकेशन के यहां पर ट्रीटमेंट कर देते हैं। आम जन यह सुनता है कि पेट दर्द हुआ और अपेंडिक्स निकाल दिया। आप गए नहीं और बिल फाड़ा नहीं। यह एक बहुत बड़ा दरवाजा एक्सप्लोयटेशन का हम प्राइवेटाइजेशन से खोलते हैं।

दूसरी चीज, आज तक इनके पास कोई स्टडी है तो बता दें, एनएसओ के अंदर स्टडी है and I have this report with me कि बीमा योजनाओं से catastrophic OOP कम नहीं हुई है। आपका 3 लाख का पैकेज है, वह तो वह लेते ही लेते हैं। लेकिन अंडर दी टेबल आपकी ओओपी भी ले लेते हैं। इतना भार उसके ऊपर पड़ता है। जो इम्पेक्ट पेशेंट की बाडी पर होता है, वह सोचिए कि जब मानवीय संसाधन, जब स्वस्थ मानव, हयूमन रिसोर्स हमारा

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

एक एसेट्स है, उसको हम किस तरीके से प्राइवेट हाथों में देकर किस तरीके से डेस्ट्राय कर रहे हैं। भामाशाह के अंदर खाद्य सुरक्षा से जोड़ो। फिर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो। चुनाव से पहले बहुत सारे कैम्प लगे थे और मैं उनमें गई थी। आज आपरेशन करना है, आज मर रहा है, वह देख रहा है कि कितना प्रतिशत उस गांव का है, खाद्य सुरक्षा उसको मिल ही नहीं पा रही है, the need of the urgency in medical is at that moment. इतने सारे बेरियर्स हैं और मेरा यह मानना है कि हैल्थ केयर के अंदर यूनिवर्सल पालिसी होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। इसको और सरल बनाने की आवश्यकता है, जो भी पालिसी हम लेकर आएं, उसके अंदर बेरियर कम से कम हो। दूसरी चीज यह लेकर आए पीपीपी माडल, तो फिर मुझे प्राइवेटाइजेशन पर जॉन ऑलिया का शेर याद आ जाता है,

इलाज यह है कि मजबूर कर दिया जाऊं,
वरना यूं तो किसी की भी सुनी नहीं मैंने

जब आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपको मजबूर कर देंगे कि आपको यह-यह कराना है, यह-यह पर्ची लिख देंगे, किस तरीके से आपको एक्सप्लोयट करेंगे, पीपीपी माडल में जितनी भी 82 पीएचसी और उसका विवरण प्रतिवेदन में पढ़ा है जो हैंड ओवर की है। एन्टायर हैल्थ पूरा का पूरा हम उनको हैण्ड ओवर कर देते हैं, we have no monitoring system on it, no regulatory system on it. प्राइवेट एजेंसी का गवर्नमेंट सिर्फ एक फाइनेंसर बन जाती है। यह धारणा कि कभी भी गवर्नमेंट एजेंसीज स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हो सकतीं, यह हमें तोड़नी होगी। अगर हम सब प्राइवेट करके बैठ जाते हैं, then what’s the meaning of governance here, फिर गवर्नमेंट का क्या अभिप्राय है? स्टेट जो पब्लिक वैलफेयर के लिए सोच सकता है, यह प्राइवेटाइजेशन की धारणा कभी भी पब्लिक वैलफेयर के बारे में नहीं हो सकती क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ प्रोफिट मेकिंग के बारे में होती है। इनके कोई रैगुलेटरी सिस्टम्स नहीं होते। सबसे बड़ी बात पीपीपी मोड में यह होती है कि अपोलो तो कभी गांव में जाकर हास्पिटल खोलता नहीं है क्योंकि वहां पर पर्चेजिंग पावर नहीं है। आप जब इनको पीपीपी मोड में दे देते हैं, तो ये इनके कैचमेंट एरिया की तरह काम करता है, ये वहां से अपने पेशेंट्स को हास्पिटल की तरफ ट्रांसफर करते हैं और फिर एक्सप्लोयट करते हैं। दूसरी बात इन

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

सरकारी जिसके अंदर हमने प्राइवेटाइजेशन इन्वाल्व किया पर मैं सिम्पली प्राइवेट सैक्टर पर भी बात करना चाहती हूं। फिर मुझे प्राइवेटाइजेशन के एक्सप्लाइटेशन के ऊपर एक और शेर याद आता है,

वो भी आता है, बताता है क्या,

कोई इलाज बंट न जाए तेरे बीमार महालों को

क्या होता है जब हम प्राइवेट हास्पिटल्स में जाते हैं, मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया की तरफ से यह दे रखा है कि prescription capital letters में होना चाहिए and the medicines should get prescribed in generic names. मेडिसन एक बड़ा काम्प्लेक्स सब्जैक्ट है। इसके दो चीजें हैं एक तो unnecessary, unethical practices और एक pricing. अभी मेरे से पूर्व में बता रहे थे, झोला झाप के बारे में बात कर रहे थे। कैसे लगाम लगाएंगे आप? क्या मोनिटरिंग हो सकती है, क्या रेगुलेटरी हो सकती है? डिग्रीज नहीं है इनके पास में, दूसरा यह पर्ची लिखते हैं, पांच मेडीसिन रखते हैं, 3 इर्रेलेवेंट और unnecessary और इर्रेशनल होती है और वह 3 सबसे महंगी होती है। काम्बिनेशन ड्रग बनाकर लेकर आ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि The Clinical Establishments Act Government जो कि enforce नहीं हुआ है and it is only on the papers इसको enforce कराने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): बहुत जरूरी है- ethical forms and irrational. दूसरी चीज pricing की है। National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)- drug price control, जो essential drug list को price करती है। जो मैं कहती हूं कि दो सबसे महंगे होते हैं। मान लीजिए i.e. पेरासिटामोल 500 मिलीग्राम essential drug list में आती है तो 600 बना देंगे। एक नई काम्बिनेशन ड्रग बनाकर कर देंगे। यह प्राइवेट सैक्टर और बीमा कम्पनियां तो चाहते हैं कि आप बीमार हों, ज्यादा से ज्यादा बीमार हों ताकि हम प्रोफिट बना सकें। ये पब्लिक वेलफेयर के बारे में नहीं सोच सकते जो कि एक स्टेट एजेंसी ही सोच सकती है। पालिसी का फर्क है। बजट तो आपने भी इंक्रीज नहीं किया, बजट तो दोनों सरकारें हैल्थ पर उतना ही दे रही हैं। मैं मान रही हूं और स्वास्थ्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जरूरत आ गई है कि हम अपने स्टेट के मानवीय संसाधनों के लिए उसको

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

इंक्रीज करें। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में पालिसी और अप्रोच का फर्क है। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारी पोस्ट्स वेकेंट हैं। 33097 पैरामेडिकल, 3305 चिकित्सकों की मेडिकल कालेजेज के अंदर बहुत सारी पोस्ट्स वेकेंट हैं। What quality of education will be like to give them when we're making doctors. इनको भरने की आवश्यकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण मैं ट्रांसफर पालिसी पर बोलना चाहती हूं। हमारी ट्रांसफर पालिसी वर्क लोड बेस्ड नहीं है, नीडफुल बेस्ड नहीं है। पीएचसीज में एमबीबीएस चाहिए लेकिन हमने स्पेशलिस्ट लगा रखा है, क्योंकि उसके घर में पीएचसी है। वहां वह अपनी सिफारिश करके पोस्टिंग करवा लेता है। कम पेशेंट पर ज्यादा डाक्टर हैं और ज्यादा स्टाफ है, ज्यादा पेशेंट पर कम डाक्टर हैं। फर्स्ट रैफरल यूनिट्स आधी से ज्यादा हमारी फंक्शनरी नहीं हैं। Gynecologist, Child specialist, Anesthetist इसका हम सैट ही नहीं बना पा रहे, सिजेरियन करना है, अगर हम आईएमआर और एमएमआर को कम करना चाहते हैं तो हमको यह करना पड़ेगा।

मैं प्रतिवेदन पढ़ रही थी और बहुत से लोगों ने यहां कोट भी किया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से इतने लाभांवित हुए, नि:शुल्क दवा योजना से इतने लाभांवित हुए। हम तो न्यूमरेटर्स दे रहे हैं, डिनोमिनेटर्स तो हम दे ही नहीं रहे हैं। फोर एक्जाम्पल सौ लोग आए, अस्सी को दवा दी तो आप तो लिख देते हो कि अस्सी को दवा दी, अस्सी लाभांवित हुए, तो सौ का आंकड़ा कहां गया, हजार का आंकड़ा कहां गया बीच का? हाउ मैनी पीपल जो रीच ही नहीं हुए, मानिए हजार लोग थे छह सौ आए, चार सौ को आपने दवाई दी, दो सौ को किसी कारण नहीं दे पाए, पर वे चार सौ कहां हैं जो अब तक पहुंच ही नहीं पाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे उसके बारे में सुधार करेंगे?

जनता क्लिनिक की हमने बात की, पर हमने कोई बजटरी प्रोविजन ही नहीं किया एक रुपये का, हमने यह सोच लिया कि दानदाता देंगे और हम कर देंगे। कैसे वह करेंगे? देहली के अंदर हण्ड्रेड परसेंट बजट है मोहल्ला क्लिनिक का, इसके अंदर हमने गाइड लाइन की बात की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): तो सोच समझकर हमें कहना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अंत में बोलना चाहूंगी दो पोइंट्स पर। नि:शुल्क दवा योजना। यह एक बहुत बढ़िया योजना है क्योंकि यह तीनों स्टेज

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

को कवर करती है, प्राइमरी, सैकंडरी और अपर, लेकिन यह कहेंगे कि इतनी लोकप्रिय थी कि ये बंद नहीं कर पाए, यह कहेंगे कि हमने बजट भी कम नहीं किया। जी बिलकुल नहीं किया आपने, लेकिन आपने इसके आपरेटिव पार्ट को हिट कर दिया बड़ी चतुराई से। इसका एक कांसेप्ट था, online entry, real time monitoring, entry of prescription and stock in-and-out पता लग सके, उसके लिए 5500 में से 4000 कम्प्यूटर आपरेटर सिर्फ स्पेशली इसके लिए डिजाइन किए थे। इन्होंने वह कम्प्यूटर आपरेटर हटाकर दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए और पूरी की पूरी स्कीम को पैरालाइज कर दिया। प्रेस्क्रिप्शन आडिट नहीं हो सकती, स्टाक आउट हो गए, फिर वही डाक्टर्स प्राइवेट में भेज रहे हैं। इन्होंने जो साफ्टवेयर चेंज और डिमांड और सप्लाई थी वह पूरी जाम कर दी।

माननीय सभापति महोदय, आखिर में मैं सबसे इम्पोर्टेंट दो बोलना चाहूंगी। राइट टू हैल्थ पर जो हमारे जन घोषणा पत्र में था and we need ‘Walk the Talk.’ एक रिफोर्म होगा हैल्थ सैक्टर के अंदर and if somebody can imply this and implement this. I believe, the Hon’ble Minister of Health can do it. यह जो सामने बैठे हैं माननीय सदस्य, चूरू से आए हैं, छात्र संघ का इनके काम्पीटिशन भी होता है, यह स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। मुझे लगता है कि राइट टू हैल्थ एक्ट अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप आगे याद किए जाएंगे।

मैन पावर हमारे पास आशा और इन सबको मिलाकर डेढ़ लाख है, अड्डाह हजार के करीब हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तेरह, साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपये के बीच में हमारा पैसा लगता है। इतना सारा हमारा पैसा लगता है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, रिसोर्स हम दे रहे हैं, आउटपुट का मिल रहा है यह हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। हैल्थ सर्विस प्रोवाइडर है उसकी मर्जी पर है, ताला लग जाता है, डाक्टर आए तो आए नहीं आए तो नहीं आए, बहुत जरूरी है कि राइट टू हैल्थ के अंदर हम सर्विस गारंटी दें कि with basic minimum needs, decide accountability, doctors को देना पड़ेगा, एक entitlement of health मिलेगा और एक mechanism of "Grievance Redressal" मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं ओसियां विधान सभा क्षेत्र की तीन चीजें कहना चाहूंगी। तिंवरी पीएचसी को क्रमोन्नत करके सीएचसी में करें। इसके चार पीएचसी से कवर करते हुए 80-1.20 लाख की जनसंख्या चाहिए तो यह कवर करें। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मथानिया, जहां से विश्व प्रसिद्ध मिर्ची आती है, वहां पर पिछली सरकार में भी वहां की जनता और मुख्य मंत्रीजी से मिली थी और एक सैटेलाइट हास्पिटल की मांग थी। मैं आपके न्यू पीएचसीज और सब सेंटर्स, जो भी हैं उनके बारे में मैं लिखित रूप से बता दूंगी। एमडीएम और न्यूरो फिजिशियन नहीं हैं, कहीं सफाई नहीं होती, कहीं और कुछ नहीं होता।

माननीय सभापति महोदय, आखिर में मैं बस यही कहना चाहती हूं,

देखी जो नब्ज मेरी तो हंस कर बोला हकीम,

तेरे मर्ज का इलाज तेरे संघर्षों में है।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रसादजी।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 26 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में हम बताना चाहते हैं कि हमारे खासतौर से गांवों की हालत है वह इस तरह की बनी हुई है कि वहां पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाईं, मुफ्त दवा योजना हो चाहे स्वास्थ्य मिशन के तहत हो, कोई भी हो वहां पर गांवों में कोई भी मरीज जाता है तो उसको मुफ्त में दवाई, गोली तक नहीं मिलती है, इंजेक्शन तक नहीं मिलता है, बोतल भी चढ़ाते हैं तो वह भी मुफ्त में नहीं मिलती है। उसका सारा ही वह दवाई का पैसा वसूल करते हैं। हमने यह देखा है कि वह लोग हास्पिटल्स के अंदर नहीं करते अपने क्वार्टर होता है, वहां पर वह पैसे वसूल करते हैं और दवाई करते हैं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि खास तौर से गांवों में जो चल रहा है उसको किस तरह से रोका जाए। और वहां से जब मरीज बढ़िया अस्पताल में पहुंचता है, सागवाड़ा पहुंचता है तो वहां की हालत और ज्यादा खराब है। वहां पर हमने देखा कि जब डिलीवरी जाती है तो वहां पर हमने अंदर जाकर देखा तो सारी की सारी डिलीवरियां जो होती हैं, उन सबको ओपन किया जाता है तो हमने

(श्री रामप्रसाद)

सोचा कि यह क्या बात है कि ऐसी कोई भी सिम्पल डिलीवरी नहीं होती है, सारी डिलीवरियां ओपन करनी पड़ती हैं। जब हमने जानकारी ली तो यह पता चला कि हर डिलीवरी पर 6, 7, 8 हजार रुपये वसूल करते थे और जब ये वसूल करते थे तो जब जानकारी ली गयी और हमने पूछा कि क्या बात है, आप हर डिलीवरी से 6, 7, 8 हजार रुपये वसूल करते हैं तो जो इंचार्ज था, उसने कहा कि बात तो सही है, 11-12 परसेंट तो हो सकती है, ओपन किया जा सकता है, लेनी पड़ सकती है इतनी, लेकिन यह जो 90 परसेंट डिलीवरियों को ओपन करते हैं, उसके पीछे पैसा ही था और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। इस बात को लेकर डाक्टर से बात की, लेकिन सवाल यह है कि वहां डाक्टरों की भी कमी है। इसकी वजह से वहां जो मुख्य अधिकारी हैं, वे भी नहीं हैं वहां पर। वहां पर क्या होता है, आजकल शुरुआती हो गया है कि चाहे डिलीवरी हो, चाहे कोई केस हो या कोई भी हो, उसे रैफर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन लोगों ने अस्पतालों में बैठना बंद कर दिया है। वे घर पर पर्चियां बनाते हैं, घर पर ही उनका पैसा वसूल करते हैं। इस वजह से उन्होंने सीधा रैफर करना शुरू कर दिया। यदि पूछते हैं तो वे क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं कि यहां ब्लड बैंक नहीं है। ब्लड की वजह से या डाक्टर नहीं है या इस वजह से उसे रैफर कर दिया है। जिस तरह से उनकी मोनोपोली चल रही है गरीब लोगों को परेशान करने की, उसके लिये खासतौर से कुछ न कुछ ऐसा इलाज किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से और उन्हें पाबंद किया जाना चाहिए। हम सदन को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि खासतौर से हमारे अस्पतालों में जो यह अव्यवस्था फैली हुई है, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। इतना करप्शन बढ़ गया है। खासतौर से मैं सागवाड़ा में हमारे जो डाक्टर हैं, उनके चौदह पद स्वीकृत हैं, उसमें से केवल पांच डाक्टर हैं और नौ डाक्टरों के पद रिक्त हैं। इस तरह की जो हालत गांवों में बनी हुई है, इसलिये सभापति महोदय के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो अस्पताल हैं, उनमें डाक्टर और स्टाफ की जो कमी है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि जो ब्लड बैंक हैं, वे स्टाफ की कमी की वजह से बंद हैं। एक्स-रे मशीन्स हैं, वे काम नहीं कर रही हैं। एमआरआई व सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। शिशु वार्ड में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(श्री रामप्रसाद)

इस तरह से अस्पतालों में जो अव्यवस्था है और जो डाक्टर्स, नर्सेज की कमी है, उसे पूरा किया जाए। 2013 में कांग्रेस सरकार ने भर्ती निकाली थी, जो संविदा पर लगी हुई थी, जैसे ही बीजेपी सरकार आयी, उसने द्वेषतापूर्वक 4514 पदों को घटा दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पद घटा दिये गये हैं, उन्हें वापस वर्तमान सरकार मुक्ति प्रदान करे और इनकी परेशानी को समझते हुए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अविलम्ब उस पर कार्यवाही करके भर्तियों को पूरा किया जाए। मैं अपनी बात खतम करता हूं।

श्री सभापति: श्री गुरदीप सिंह।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो अस्पताल हैं। एक पचास बैड का है और एक तीस बैड का है, जिसके अंदर स्टाफ की भारी कमी है। वहां स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, जनरल सर्जन नहीं है, नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है, मेडिकल आफिसर नहीं है, वार्ड बाय नहीं है, चपरासी नहीं है, ईसीजी तकनीक नहीं है, डिजिटल एक्स-रे मशीन नहीं है और जो उप-स्वास्थ्य केन्द्र पड़ते हैं फतेहपुर, कीकरवाड़ी, रासुवाला, नाथवाणा, हरिपुरा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उसमें लीलावाली पीएचसी, किशनपुरा उतरादा पीएचसी, भीमगढ़ पीएचसी, लोकियारा पीएचसी, ढामा पीएचसी में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है।

लीलावाली पीएचसी के अंदर जो एक एएनओ पोस्ट है, उसे भी डेपुटेशन पर हनुमानगढ़ लगा रखा है। संगरिया सीएचसी में भी एक रिक्त पद है और ऐसे ही मेरे टिब्बी के अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन), कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जन), कनिष्ठ विशेषज्ञ (अधिकारी), चिकित्सा अधिकारी और संगवाड़ाखुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर और स्टाफ नहीं है और न ही वहां पर क्वार्टर हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में संगरिया और टिब्बी में जो भवन बने हुए हैं, उनकी हालत बड़ी गम्भीर है और उसके लिये उसकी मेंटीनेंस की जरूरत है।

टिब्बी में जो अस्पताल है, उसकी चारदीवारी भी नहीं है और वह एक

(श्री गुरदीप सिंह)

ग्राम पंचायत के ऊपर है। सफाई में संगरिया में तो हमें कर्मचारी मिल जाते हैं, पर टिब्बी में हमें कर्मचारी भी नहीं मिलते हैं, इसलिये मेरी आपसे मांग है कि एक तो जो हमारी टिब्बी की बिल्डिंग है, उसकी मेंटीनेंस करायी जाए और चारदीवारी बनवायी जाए। साथ ही हमारे टिब्बी क्षेत्र में जो उप-स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए आपने मंजूर किये हुए हैं उसके अंदर सारेकांच, आरआरपी, बुढिया, धोकेशनी, भराणपुरा, मसानी, 2 डीडीएलडब्ल्यू नाईवाला, यहां पर हमारे भवन नहीं हैं। यहां भवन बनाने की आप कृपा करें और यहां हमारे साथी इंदिरा गांधी कैनाल की बात कर रहे थे और थर्ड फेज के अंदर पानी की बात कर रहे थे। मैं मेरे सभी साथियों को, आठ जिले के जो मेरे साथी यहां बैठे हैं, उनसे विनती करूंगा कि आप एक कमेटी बनाकर सभी विधायक पंजाब में चलकर आएं और वहां से जो हमारा पानी आ रहा है, वह कैसा आ रहा है, वह नहाने के लायक भी नहीं है। हमें इस समय बरसात के समय 11 हजार क्यूसेक्स पानी मिल रहा है राजस्थान कैनाल में और छह या सात हजार क्यूसेक्स गंग कैनाल का मिल रहा है। उसमें बुढागढ़ नाला और जितनी भी पंजाब की फैक्ट्रियां हैं, उन सबका पानी सतलुज में मिलाकर हमारे पानी के अंदर दिया जा रहा है, जो कि 11 हजार क्यूसेक्स के अंदर 3 हजार क्यूसेक्स पानी गंदे नाले और फैक्ट्रियों के कैमिकल का आ रहा है। हमारे जो आठ जिले हैं, वे उस पानी को पीते हैं और खासकर जिस कैंसर की ट्रेन का नाम लिया जाता है, वह मेरे क्षेत्र से होकर गुजरती है और मैं खुद कैंसर का मरीज हूं और मैं 2011 में टाटा के अंदर आपरेशन करवाकर आया हूं।

मैं सभी से विनती करता हूं कि आप जो नहरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इंदिरा गांधी कैनाल से, आप सभी जाकर वहां बीकानेर व पंजाब के अंदर हाल देखकर आएं और मैं सरकार से विनती करूंगा कि मंत्री महोदय, आप की ही कांग्रेस सरकार वहां पर है और कांग्रेस की ही सरकार यहां पर है, दोनों मुख्य मंत्रियों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए और जो गंदे नाले का पानी है और फैक्ट्रियों के कैमिकल का पानी है, वह बंद कराया जाए, क्योंकि मेरे साथी राजकुमार गौड़ जी ने भी तीन दिन पहले यह मुद्दा उठाया था। यह बड़ा गम्भीर मुद्दा है। हमारे दोनों जिले एक भयानक रूप ले रहे हैं, इसके लिये अभी तो छोटे-छोटे ज्ञापन दे रहे हैं, पर थोड़े दिनों बाद इसका एक बहुत बड़ा

(श्री गुरदीप सिंह)

मुद्दा उठेगा और सरकार को घेरेंगे इसलिए आप पहले ही सचेत हो जाएं तो वो कैमिकलयुक्त पानी आ रहा है वह बन्द हो जाए।

दूसरा, अभी मेरे साथी दूध की बात कर रहे थे कि दूध आप अभी आर्डर कर दो, हजारों लीटर अभी मिल जाएगा तो इतना आता कहां से है। एक जो खाने-पीने की चीजें हैं, हमारे जिला जो सिंचाई से जुड़ा हुआ है तो हमारे गंगानगर जिले के अन्दर, बीकानेर जिले के अन्दर इतनी जहरीली पेस्टिसाइड यूज होती है जिसके कारण भी कैंसर की बीमारियां फैल रही हैं इसलिए आप पेस्टिसाइड पर ध्यान दीजिये।

विधायक कोष के लिए सभी ने समर्थन दिया है तो मैं भी आपके मार्फत सरकार को रिक्वैस्ट करूंगा कि जो हमारा विधायक कोष है उसको पांच करोड़ किया जाए। लोगों को विधायक के ऊपर बड़ी उम्मीद होती है कि हमें विधायक कोष से पैसा दें। माननीय, मैं आपके थ्रू सरकार से निवेदन करता हूं कि इस कोष को पांच करोड़ किया जाए।

दूसरा, हमारे जिले में जितनी भी एम्बुलेंस दे रखी हैं उनमें 108 जो दे रखी हैं वह सारी नाकारा हो चुकी हैं और 104 है ही नहीं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके थ्रू मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि हमारे जिले में जर्जर हालत में 108 हो रही है वह नई दी जाए और जो 104 नहीं है वह भी हमारे को उपलब्ध कराई जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे टाइम दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा चल रही है। कहा भी गया है कि सबसे पहले नीरोगी काया। अगर मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है और अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मनुष्य के लिए सारा ही बेकार है। इस स्वस्थ शरीर के लिए आज मेरे से पूर्व वक्ता भी बोले कि जिस तरह से चाहे पानी की बात करें, दूध, घी, मसाला, सब्जी, दवाई, जितनी भी चीजें हैं उन सबमें मिक्स है। इसको अगर ठीक नहीं कर पाये तो हम शरीर को भी स्वस्थ नहीं रख पाएंगे इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको हम किस तरह से रोकें, यह हमारे लिए पहला उद्देश्य होना चाहिए।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो निःशुल्क दवा की सबसे पहले शुरूआत राजस्थान में की है उसका फायदा आम गरीब, जिसके पास दो वक्त की खाने की रोटी नहीं, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, उनके लिए मुफ्त इलाज होना यह होने से उसको अपने आप में अपने जीवन में आनन्द मिलता है कि देखो मेरा इलाज निःशुल्क हो रहा है तो मुख्य मंत्री जी को वह अपने दिल से दुआ दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे चिकित्सा मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाड़मेर में मेडिकल कालेज जो पूर्व में हमारी सरकार ने खोला था और 5 साल तक शुरू नहीं कर पाए। अभी एमसीआई की टीम आई और उन्होंने भी निरीक्षण कर कालेज शुरू करने की परमिशन दे दी, मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज प्रथम वर्ष से शुरू हो जाएगा। इससे जो इस बोर्डर एरिया में डाक्टरों की कमी है उसकी आने वाले समय में पूर्ति होगी।

सभापति महोदय, कई बातें यहां हुईं, डाक्टरों की कमी की बात हुई, स्टाफ की कमी की बात हुई और कैसे हम ठीक करें उसकी चर्चा हुई। हास्पिटल में सबसे पहले तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि इसको हम साफ-सुथरा कैसे रखें। अगर हास्पिटल साफ है, उसके टायलेट्स साफ हैं, उसके अन्दर पानी की व्यवस्था है तो मरीज जो जाएगा उसको इससे ही सबसे पहले फर्क पड़ जाएगा कि वहां मैं आराम से उस हास्पिटल में जाऊं, दिखाऊं, चैक कराऊं, मुझे बैड मिले, बिस्तर मिले और अन्दर सफाई हो। इसलिए यह बहुत जरूरी है। दूसरा, वह वहां जाए, डाक्टर अच्छी तरह से देखे।

आज मैं बाड़मेर की बात करना चाह रहा हूं। बाड़मेर में मेडिकल कालेज है, स्टाफ भी खूब है, गायनी का स्टाफ है, सर्जन है, आर्थोपेडिक है, अन्य स्टाफ भी काफी है परन्तु उसके बाद भी दुःख की बात यह है कि उसके बाद जो एक्सीडेंटल केस आये उसको भी रैफर करना पड़ रहा है जबकि वहां सर्जन बैठे हुए हैं। गायनी केस भी ट्रांसफर हो रहे हैं। उसको आपरेशन करना आता है लेकिन रैफर करके बाहर भेजते हैं जबकि वहां 7-7, 8-8 गायनी डाक्टर है तो हास्पिटल के अन्दर जिस तरह से यह हो रहा है इसको हम कैसे रोकें सभापति महोदय। डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं। उनके प्राइवेट हास्पिटल खोले हुए हैं और उन हास्पिटल में अगर एक्सीडेंट होकर कोई आया,

(श्री मेवाराम जैन)

भर्ती किया, उसको कहा कि आपका नम्बर तो 5-6 दिन बाद आना है और अगर आज ही कराना है तो उस हास्पिटल में चला जा। अगर उस हास्पिटल में जाता है तो उसका उसी दिन आपरेशन हो जाता है, नहीं तो वह उस हास्पिटल के अन्दर ही सड़ता है। इसी तरह से गायनी की बात है, गायनी के अन्दर भी फिक्स है प्राइवेट हास्पिटलों में। वहां सीजेरियन कम करते हैं और बाहर भेज देते हैं तो इस प्रथा को हमें रोकना पड़ेगा और इस पर कैसे अंकुश लगाएं। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही जरूरी है कि मेडिकल कालेज जैसी जहां सारी सुविधाएं हैं और उसमें भी अगर इस तरह से नहीं रोक पाएं तो इसको रोकना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में रेन्डोक्स मशीन जो करीब 35 लाख की टैस्टिंग की मशीन है वह 2013 में आई और उसको आज 6 साल हो गये पर वह मशीन आज भी ताले के अन्दर बन्द पड़ी है। अगर वह मशीन प्रारम्भ हो जाती तो उसके अन्दर कितने टैस्ट उस मशीन से हो जाता। स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी थी परन्तु वह शुरू नहीं हो पाई। मंत्री जी को मैं धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि मंत्री जी ने हमारे यहां जो डाक्टर्स की कमी थी, चाहे रेडियोलोजी, कार्डियोलोजी, चाहे अन्य डाक्टर इन्होंने भेजे इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जिला मुख्यालय है वहां पर बैड बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे मरीज भी ज्यादा आ रहे हैं। इस बजट में आपने सिर्फ 500 का ही लिया है इसलिए इसकी जगह ज्यादा बढ़ायें। जिला मुख्यालय में भी कम से कम 300 बैड का हास्पिटल जरूर करें।

दूसरा, हमारे बाड़मेर में मेडिकल कालेज और जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन, अन्य सुविधाएं हैं पर एमआरआई मशीन नहीं है। जहां इतनी कम्पनियां हैं, तेल-गैस के अथाह भण्डार हैं, इतनी रायल्टी दे रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि एक एमआरआई मशीन बाड़मेर के हास्पिटल में लगाई जाए ताकि वहां की जनता को काफी फायदा होगा। इसके लिए फण्ड का भी केयर्न एनर्जी और राजवेस्ट सहयोग कर सकती है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि स्टाफ की कमी है, जहां पीएचसी है, सीएचसी है वहां स्टाफ लगाएं। दूसरा, जहां सब-सेंटर है, कई सब-सेंटर तो ऐसे हैं जहां 2-2, 3-3 एएनएम हैं और

(श्री मेवाराम जैन)

कई सब-सेंटर ताले लगे हुए बन्द पड़े हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस तरह के सबसेंटर हैं जहां एक से ज्यादा एएनएम हैं उनको बन्द सब-सेंटर हैं उनमें लगाए जाएं ताकि सबको इसकी सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भी अच्छा दिया है और इसमें पीएचसी, सीएचसी, सब-सेंटर का भी प्रावधान रखा है। पिछले हमारे पांच साल में खूब पीएचसी, सीएचसी दीं, सब सेन्टर दिए, उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। उसके अन्दर भवन जो कई सब सेन्टर सैंक्शन है, एक हमारी पीएचसी सांसठा भी है, बाकि बिल्डिंग बन गई, इन पांच सालों में भवन नहीं बन पाए तो मैं निवेदन करना चाहूंगा जहां सब सेन्टर सैंक्शन है वहां भवन बन जाए, ताकि वहां एएनएम के रहने के लिए आराम हो जाए और पीएचसी सांसठा है, उसके भवन की राशि स्वीकृत करें, ताकि वहां भवन बन सके।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चवाह पीएचसी है, आस-पास में कई पंचायतें लगती हैं, उसको क्रमोन्नत कर सीएचसी की जाए और पीएचसी के लिए मेरी विधान सभा में मारोडिया और दुधावेरी दो ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनके आसपास आबादी के हिसाब से भी देखें, नार्म्स के हिसाब से भी देखें तो फिट बैठती है और आवश्यकता भी है तो एक खोलने की मैं मांग रखता हूं।

मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पूरे राजस्थान में पद खाली है, ज्यादा से ज्यादा भरें और डाक्टर्स जो प्राइवेट में जा रहे हैं इनको रोकने के लिए इनकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, तब ये रूकेंगे, नहीं तो प्राइवेट फील्ड में जाएंगी।

मैं एक उदाहरण दूंगा बाड़मेर के अन्दर केयर्न एनर्जी ने तीन डाक्टर दिये सीएसआर फण्ड से, अब उन डाक्टरों को वे ढाई-ढाई लाख रुपये प्रति महीने दे रहे हैं तो वे यहां कैसे आएंगे। प्राइवेट में तो आप देख लो किस तरह से लूटमार है। उनको तो कितने ही पैसे दो, वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए अगर उनको रोकना है तो इनके पैसे बढ़ाएंगे, तब ही वे ज्यादा रूकेंगे, वर्ना वे फिर बाहर जाएंगे।

(श्री मेवाराम जैन)

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस और भी ध्यान दें और किस तरह से हम स्वास्थ्य को ठीक कर सकें, इसके लिए हमें राजनीति से ऊपर उठकर, मैं यही निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग और मन स्वस्थ रहेगा, मन हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम सब स्वस्थ हैं। इसलिए मैं यही निवेदन करता हूं कि जो भी मैंने ये सुझाव दिये हैं एक मेरे बाडमेर जिला अस्पताल में एम्बुलेंस, इतना बड़ा अस्पताल है तीन एम्बुलेंस थीं, जिसमें दो खराब पड़ी हैं, बिलकुल आक्शन लायक, सिर्फ एक ही बची है, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सके तो आप कराएं, 108 भी खराब पड़ी है, इसकी भी मांग करना चाहूंगा कि वहां व्यवस्था करें।

अब मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह जो स्वास्थ्य का जिस तरह से मिशन चल रहा है, जिस तरह से नि:शुल्क दवाइयों की व्यवस्था इस बजट में की है, जिस तरह से पीएचसी और सीएचसी की व्यवस्था की गई है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 26 पर बोलने का जो अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय जी, मैं आपके सामने धौलपुर जिले की एक गम्भीर समस्या

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

रखना चाहती हूं, जो जनता जनार्दन के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। समस्या यह है कि धौलपुर जिले में जितने भी छोटे व बड़े सरकारी हास्पिटल खुले हुए हैं उन सभी में ज्यादातर हास्पिटलों में कर्मचारी और डाक्टरों के जितने पद स्वीकृत हैं, उतने पदों पर कर्मचारी और डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं और कई हास्पिटलों में कुछ आवश्यक नये उपकरणों की कमी है और इन हास्पिटलों में जांच के लिए जो उपकरण लगे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर उपकरण खराब पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जनता जनार्दन को परेशानी उठानी पड़ रही है और मजबूरन प्राइवेट हास्पिटलों में जनता को जाना पड़ता है। वहां प्राइवेट हास्पिटलों में मनमानी फीस वसूली जाती है। हमारे धौलपुर में सामान्य चिकित्सालय में सोनोग्राफी की गंभीर समस्या है, जब गर्भवती महिलाएं टैस्ट के लिए आती हैं तो दो-तीन दिन में नम्बर आता है। एक ही सोनोग्राफी से इतने बड़े हास्पिटल में काम चल रहा है, वह भी राम भरोसे, वह मशीन भी आए दिन खराब होती रहती है। मजबूरन लोग प्राइवेट हास्पिटलों में जाकर सोनोग्राफी करवाते हैं और मनमानी फीस लेते हैं, पांच सौ से सात सौ रुपये तक। हमारी गरीब जनता जनार्दन को बहुत कष्ट होता है। मैं चाहती हूं कि धौलपुर सामान्य चिकित्सालय में कलर सोनोग्राफी मशीन दिलाने का श्रम करें।

हमारे धौलपुर सामान्य चिकित्सालय में पुराने पीएमओ लगे हुए थे। वे कर्मठ, सेवक रात दिन काम करते थे, हास्पिटल और फील्ड में काम करते थे, मात्र राजनीतिक द्वेष से उनको हटा दिया गया है। हमें जनता जनार्दन की सेवा करनी है, दादागीरी नहीं, इसलिए माननीय हमारा आपसे निवेदन है कि चिकित्सा मंत्री जी को निर्देश दिए जाएं, जिससे मंत्रीजी इस गम्भीर समस्या का निराकरण कर सकें। आदरणीय आपने मेरी बात को गम्भीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री सुरेश जी टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई मांग संख्या 26 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं सबसे पहले मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की समस्या से शुरू करूंगा, ज्यादा जरूरी यही है, मैं उसी पर बात करूंगा। हालात करीब-करीब वही है जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वही

(श्री सुरेश टाक)

है। मैं सबसे पहले रिक्त पदों की बात करूंगा, चाहे ग्रामीण सीएचसी हो, पीएचसी हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, कहीं भी हो, स्थितियां बहुत गम्भीर हैं।

मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति बताना चाहूंगा, सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय को, मेरा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है सुरसा, कुल पांच पद स्वीकृत हैं और पांचों ही रिक्त हैं, आज की तारीख में। केवल कागज में अस्पताल चल रहे हैं, यह स्थिति बिलकुल भी ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कुचील में दो पद स्वीकृत हैं, दोनों ही खाली पड़े हैं। सिलौरा में एक पद स्वीकृत है और एक ही रिक्त पड़ा है। त्योद में एक पद स्वीकृत है एक पद रिक्त पड़ा है। बांदरसिंदरी में एक एएनएम लगी हुई है। दो सीएचसी हैं, आप सीएचसी की स्थिति देखें। बोराडा में 37 पद स्वीकृत हैं, 37 के अगेंस्ट में 13 पद काम कर रहे हैं, 24 पद खाली पड़े हैं। अरांई में 39 पद स्वीकृत हैं, 19 कार्यरत है, 20 पद खाली हैं, ऐसी स्थितियां पीएचसी की हैं। कमोबेश सभी जगह कुल 158 पदों में से 67 कार्यरत हैं, बाकी सब खाली पड़े हैं। ऐसी स्थिति में कैसे हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि हम स्टाफ के अभाव में कहीं न कहीं सरकार को भी यह सुनना पड़ेगा कि हम स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे हैं।

मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि जितना जल्दी हो सके ये भर्तियां शुरू की जाएं। कम से कम एक-एक सीएचसी, पीएचसी में एक-एक डाक्टर तो उपलब्ध हो जाए ताकि कोई ग्रामीण जन वहां जाए तो उनको चिकित्सा सेवा तो मिले, अगर नहीं मिला और वो खाली हाथ वहां से लौटेगा तो मुझे नहीं लगता, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात है, हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं ठीक नहीं होगा।

मैं दो-तीन जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के सुरसा और कुचील प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आपसे मांग करूंगा। जितनी जनसंख्या है वहां पर, जिस तरह से लोग वहां रह रहे हैं, उस हिसाब से वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। कुछ ऐसी जगह हैं, जहां पर अभी तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ही नहीं है और बहुत बड़ेबड़े गांव हैं। वहां के आम जन को बहुत दूर तक इलाज के लिए जाना पड़ता है और नेसेसरी है कि वहां पर किसी भी तरह का छोटा सा स्वास्थ्य केन्द्र भी हो।

(श्री सुरेश टाक)

(17.00 बजे)

मैं देवपुरी, खंडाच, खातोली, नलू, मूंडोलाव, वरना में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र की मांग रखूंगा कि वहां खोलें। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर भामाशाह भवन बनाकर देने को तैयार हैं तो मैं यह चाहूंगा कि उन जगहों को प्रायोरिटी मिले, ताकि ऐसे भामाशाहों को भी हम प्रमोट कर सकें और बहुत सारी जगह ऐसी हो सकती हैं जहां पर आज मुख्य मंत्री जी की योजना है जनता क्लिनिक खोलने की। अगर हम ऐसी योजनाओं पर जल्दी से काम करेंगे जहां भवन बनाने को भामाशाह तैयार हैं तो जनता क्लिनिक के लिए भी लोग आगे आएंगे और हो सकता है बहुत सारे गली मौहल्लों में ऐसे जनता क्लिनिक खुलें जिससे हमारा यह स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का सपना है वह पूरा हो सके।

सभापति महोदय, मेरे यहां राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय जो किशनगढ़ का बड़ा अस्पताल है, उप जिला अस्पताल है वहां रेडियोलोजी है। मेरे वहां पर मार्बल की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। टैक्सटाइल पार्क है। 40 हजार अपंजीकृत मजदूर हैं जो शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़ी संख्या है मेरे जिले की या बल्कि राजस्थान की जहां पर इतने ज्यादा मजदूर कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना और जांच योजना के अन्तर्गत एक जो रेडियोलोजी का विभाग है वहां इतना अधिक भार है कि शायद हम सब चीज जमीन पर उतार ही नहीं पा रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं, जो सरकार सोच रही है तो इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। मेरे वहां पर वाई.एन. अस्पताल में रेडियोलोजी विभाग को अपग्रेड करें और उसके लिए भवन और उसका शायद तकमीना सारा डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है उस पर गौर करें। माननीय मंत्री महोदय अजमेर जिले से हैं, प्रभारी हैं हमारे, केकड़ी से चुनाव जीत कर आये हैं। उनको सारी स्थिति पता है कि हमारे वाई.एन. अस्पताल की स्थिति क्या है। किशनगढ़ बहुत-बड़ा शहर है। देश और विदेश से बहुत सारे लोग वहां आते हैं। नेशनल हाईवे हैं दो। एक मेगा हाईवे है। एयरपोर्ट है। रेलवे स्टेशन है। बहुत सारी केजुअल्टीज होती हैं हाईवेज पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रोमा यूनिट थी, पहले ट्रोमा सेन्टर की बात हुई फिर ट्रोमा सेन्टर के नाम पर, कोई भी सुविधा वहां पर नहीं है तो मैं चाहूंगा जिस तरह से मैंने अभी तारांकित प्रश्न लगाया था। माननीय मंत्री महोदय ने मुझे यह कहा था कि ट्रोमा सेन्टर वहां है तो वास्तव में ट्रोमा सेन्टर की सारी

(श्री सुरेश टाक)

सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हों। 2004 में एम्बुलेंस आयी थी वहां। आज 2018 हो गया वह एम्बुलेंस कंडम होने की कगार पर है। शायद राजस्थान सरकार के नियम भी होंगे कि दस साल बाद और फिर चिकित्सा सेवा की एम्बुलेंस जो 14 साल से चल रही है वो किस तरह की सेवाएं दे सकती हैं तो अति आवश्यक है कि वहां पर एक नयी एम्बुलेंस हमें मिले। बोराड़ा और अरांई दो बड़े-बड़े क्षेत्र हैं जहां पर 104 और 108 की सुविधा है, पर दो एम्बुलेंस भी होना वहां अति आवश्यक है क्योंकि बड़ा एरिया है। कम से कम सौ से डेढ़ सौ किलोमीटर के दायरे में मेरा एरिया है जो शहरी क्षेत्र से दूर है तो मैं चाहूंगा कि मनोहरपुरा और जीरोता दो ऐसी जगह हैं जहां पर 104 और 108 की व्यवस्था अगर हो जाए तो वहां के लोगों को जल्दी से स्वास्थ्य लाभ मिले, वे जल्दी से जल्दी नजदीकी सेन्टर पर पहुंच सके, चाहे उनको अजमेर जाना हो, चाहे कहीं पर जाना हो। मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के दो गांव हैं। डसूक एक बहुत-बड़ा कस्बा है जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र में क्रमोन्नत होना बहुत जरूरी है। मनोहरपुरा, बांदरसिंदरी और डसूक ये तीन गांव हैं जिनमें प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। अति आवश्यक है ये तीनों जगह इतनी आवश्यक हैं कि यहां पर रहने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और दूर भी बहुत है। नजदीकी डिस्पेन्सरी यहां से बहुत दूर है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं।

सभापति महोदय, मैं छोटे-छोटे सुझाव आपको देना चाहूंगा। मैं यह चाहता हूं चूंकि मैं किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन का दस साल चैयरमेन रहा हूं और एक मार्बल सिटी अस्पताल सौ बैड का हम वहां पर चला रहे थे। मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है। मैं चाहता हूं कि अस्पतालों में जितना भी स्टाफ जो डाक्टर्स हैं उनको अतिरिक्त जगह लगाया जा रहा है यह मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरे कामों के लिए डाक्टर्स को नहीं लगाया जाकर उन डाक्टर्स की सेवाएं ली जानी चाहिए। इसके लिए एमबीए सैक्टर से हास्पिटल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज के लोगों को लेना चाहिए हमें, ताकि वे अस्पताल की दूसरी व्यवस्थाओं को देख सकें या हम कहीं भी जहां उनको शिफ्ट कर रहे हैं जो इस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं डाक्टर जैसे चाहे सैक्रेटेरिएट में भी डाक्टर्स लगे हुए हैं अगर वह डाक्टर्स वहां चले जाएं तो शायद जनता की सेवा ज्यादा कर पाएंगे और हमारा जो सपना है लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का जल्दी से जल्दी और शीघ्र से शीघ्र वह पूरा हो पाएगा।

(श्री सुरेश टाक)

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए रिसेप्शन पर, हर हाल में अगर डाक्टर्स पर निगरानी रखनी है तो। डाक्टर्स आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और चले जाते हैं। मरीज उनको ढूंढता रहता है, यह स्थिति नहीं आनी चाहिए। सरकार अगर सुविधाएं दे रही हैं और आप निश्चित हैं वहां स्टाफ देने के बाद तो अगर वहां के डाक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं तो सारी परेशानी सरकार को झेलनी पड़ेगी, वहां के एमएलए को झेलनी पड़ेगी कि डाक्टर ने रजिस्टर में हाजिरी लगा रखी है और डाक्टर अपने रूम में मौजूद नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरे लगा दिये जाएंगे तो डाक्टर्स पर निगरानी रहेगी वे लोग अपने रूम में रहेंगे। लोग जहां उनको जाना है उनकी निगरानी पूरी रहेगी और दूसरा साथ में यह भी रहेगा कि जो नीचे का जितना स्टाफ है चाहे वह मेल नर्स है, चाहे वार्ड ब्वाय है, चाहे कोई भी है, उनका मरीजों के प्रति व्यवहार किस तरह का है। आम शिकायत है यह कि मरीजों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। न डाक्टर्स का व्यवहार ठीक है और न ही मेल नर्स का या वार्ड ब्वाय का व्यवहार ठीक है। कम से कम इन चीजों की निगरानी के लिए जरूरी है कि उनके मन में एक डर हो कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है तो कल देख लेगा, ताकि वह अपने काम में अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं करे। छोटा सा सुझाव है लेकिन बहुत-बड़ा काम कर सकता है यह। मैं यह चाहूंगा कि सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करना चाहिए हर हाल में और डाक्टर्स जहां तनख्वाह ले रहे हैं उनकी नियुक्ति वहीं हो। इधर-उधर डाक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो। मेरी बात को आपने सुना, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। बहुत सारे लोगों को बोलना है। मैं चाहूंगा कि इन सुझावों पर अमल हो, स्टाफ की भर्ती हो, अस्पताल में जितने डाक्टर्स उपलब्ध हैं उनको अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करें, ताकि हम वहां अधिक से अधिक सेवाएं दे सकें। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री किसनाराम जी।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, आपने मुझे चिकित्सा, स्वास्थ्य और सफाई की मांग संख्या-26 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह अति संवेदनशील विषय है। मनुष्य जीवन में कहा गया है कि मनुष्य जीवन में सात सुख होते हैं सबसे पहला सुख होता है नीरोगी काया। उस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मेरे को आपने बोलने का मौका दिया। आज जिस तरीके से एक वातावरण बना हुआ है

(श्री किसनाराम विश्नोई)

स्वास्थ्य के प्रति खान-पान की वजह से। सबसे ज्यादा आबादी बढ़ने के साथ-साथ बीमारियों का भी बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है खान-पान। खान-पान में गिरावट आई है। खान-पान की क्वालिटी में गिरावट आई है। उसका सबसे बड़ा कारण है पेस्टीसाइड से पैदा हुई रासायनिक सब्जियां, अनाज। आबादी के साथ -साथ यह बीमारी बढ़ने का बहुत-बड़ा कारण रहा है।

सभापति महोदय, पुराने जमाने में बीमारियां कम होती थीं और दूसरे संसाधन भी कम होते थे। इलाज का कोई साधन नहीं होता था इसके बावजूद भी बीमारियां कम होती थीं। उसका सबसे बड़ा कारण था मनुष्य वनस्पति की सब्जियां खाता था। वनस्पति से बिना पेस्टीसाइड का अनाज खाते थे और मनुष्य की सबसे ज्यादा रोग प्रतिस्पर्धा की क्षमता होती थी। आज जिस तरीके से कहा गया है कि तीन-चार तरीके के इलाज हैं। इलाज की पद्धति है एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, इस तरीके से सभी इलाज होते हैं लेकिन फिर भी बीमारियां आये दिन बढ़ती जाती हैं। आखिर सर्जरी से ही वह इलाज होता है। दूसरी दवाइयों से इलाज कम हो रहा है।

सभापति महोदय, जिस तरीके से मुख्य मंत्री जी ने दस तारीख को अपने बजट में क्योंकि अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्य मंत्री बने, जो गरीब को गणेश मानकर अपने जीवन में हमेशा कार्य करते थे। इन्होंने 6 सौ, सवा 6 सौ दवाइयों की पिछले कार्यकाल में नि:शुल्क दवा योजना की घोषणा की। पूरे देश में कई प्रदेशों ने तमिलनाडु ने, आन्ध्र प्रदेश ने उसको अपनाया। कई प्रदेशों ने मुख्य मंत्री जी की इस योजना को लागू किया। पिछले कार्यकाल में सौ-सवा सौ दवाइयां कम कर दी गईं। उस योजना को कमजोर किया गया। यह बहुत खेदजनक विषय रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरीके से इलाज के लिए बहुत बड़े-बड़े हास्पिटल बन रहे हैं लेकिन आज हास्पिटल्स में डाक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज तीन-चार घंटे से चर्चा चल रही है उसका सबसे बड़ा निचोड़ है कि आज डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ की बहुत-बड़ी कमी है। कमी से आमजन परेशान है। मेरे विधान सभा क्षेत्र लोहावट में जहां 2008-13 तक 5 पीएचसी से सीएचसी बनाई गई लेकिन आज वहां डाक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। सीएचसी में एक भी नर्स नहीं है। डिलीवरी के लिये लोग

(श्री किसनाराम विश्नोई)

ढाणियों से आते हैं लेकिन नर्स नहीं मिलने के कारण जोधपुर जाना पड़ता है, भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सभापति महोदय, जिस तरीके से गांव में, ढाणियों में देशी इलाज करते थे, हम सुनते थे कि गंगानगर में गेहूं और कनक पेस्टीसाइड से पैदा होती है इसलिए वहां कैंसर की बीमारी ज्यादा होती है। गंगानगर से बीकानेर तक ट्रेन आती थी, उसको लोग पेशेंट ट्रेन ही कहने लग गये थे। धीरे-धीरे हमारे मारवाड़ में भी मूंगफली की खेती शुरू हो गई। सभापति महोदय, जिस लोहावट विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं वहां सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मूंगफली की बम्पर पैदावार होती है लेकिन उस पैदावर में मूंगफली की एवरेज ज्यादा लेने के लिये रासायनिक दवाई डाली जाती है। उसका चारा पशुओं को खिलाते हैं, गाय और भैंस को खिलाते हैं फिर उस दूध की वजह से बीमारियां भी ज्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से आज पूरे मारवाड़ में, पूरे प्रदेश में कैंसर का बोलबाला ज्यादा हो गया है। पुराने जमाने में हमारे मारवाड़ में खेजड़ी की सांगरी की सब्जी खाते थे, कुमटिया की सब्जी खाते थे, कैर की सब्जी खाते थे। आज वह कैर और सांगरी कटाई की वजह से लुप्त होने के कगार पर है।

माननीय सभापति महोदय, खेजड़ी आक्सीजन भी देती है और खाने के लिये सांगरी भी देती है, उस सब्जी में कभी भी बीमारी नहीं होती है। आक्सीजन देने वाली खेजड़ी जिसको आज से दो सौ साल पहले मैं जिस समाज से आता हूं, मेरे समाज ने उस खेजड़ी को बचाने के लिये, उस वृक्ष को बचाने के लिये मेरे विश्नोई समाज के 363 लोग शहीद हो गये थे। सभापति महोदय, ऐसा पूरे देश में कोई उदाहरण नहीं है। लोग जोरू और जमीन के लिये शहीद हुए हैं, देश की सीमा के लिये शहीद हुए हैं लेकिन खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिये कोई शहीद हुआ है तो वह विश्नोई समाज हुआ है और मैं उस समाज से आता हूं। आज जगह-जगह खेजड़ी की कटाई हो रही है। यह विश्नोई समाज खेजड़ी की कटाई को रोकने में भी हमेशा अग्रसर रहता है। फिर भी जिस तरह से कटाई हो रही है, यह बहुत खेदजनक है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि वृक्षों की कटाई न हो। पेस्टीसाइड सब्जियों की तरफ न जाकर हम वापस वनस्पति सब्जियों की तरफ जाएं तब हमारी बीमारियों में कमी आएगी। आबादी भी बढ़ रही है और बीमारी भी बढ़ रही है, यह प्रदेश के लिये बहुत ही चिंताजनक विषय है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की

(श्री किसनाराम विश्नोई)

चर्चा करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र लोहावट में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, लोहावट, क्षेत्राबाद, देचूं, आऊ, उनमें आज केवल एक-एक डाक्टर है। नर्सिंग स्टाफ नहीं है। एक भी नर्स का नहीं होना बहुत चिंताजनक विषय है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं मांग करना चाहूंगा कि अतिशीघ्र चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों के पद भरे जाएं। मेरा इलाका छितराई ढाणियों में बसा हुआ है, 10-10 किलोमीटर तक नजदीक कोई गांव नहीं है। वहां जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो मां बच्चे को लेकर एक गांव में नर्स के पास जाती है, डाक्टर के पास जाती है, 10-10 किलोमीटर तक उसको गोद में लेकर जाना पड़ता है। एएनएम की एक टेंडेंसी बनी हुई है, उनके ठहराव में बहुत कमी है। उसकी हमेशा एक मानसिकता बनी रहती है कि गांव में जाकर वापस शहर में आना है। यह अप डाउन व्यवस्था बंद होनी चाहिये, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा।

आज हमारे मारवाड़ में जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर जो रेगिस्तानी इलाका है, इनमें कई झोला छाप हैं, जैसा कि मेरे से पूर्व के माननीय सदस्य भी कह रहे थे, झोला छाप डाक्टर जगह-जगह पहुंच गये हैं। कहीं बंगाली, कहीं यूनानी, न तो उनके पास कोई डिग्री है, न उनके पास कोई प्रशिक्षण है। वह हैवी डोज देते हैं जिससे एक बार तो आराम आ जाता है लेकिन हैवी डोज देने से लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं। इसलिए इन झोला छाप डाक्टरों पर प्रतिबंध लगाया जाए।

आज पूरे प्रदेश में जो मावा होता है यह सबसे ज्यादा नकली मावा आता है, असली मावा कहीं है ही नहीं। इस नकली मावे पर भी रोक लगाई जाए। इसके सैम्पल टैस्ट लिये जाएं। मसाले के सैम्पल टैस्ट किये जाएं। हजारों की संख्या में मसालों के सैम्पल टैस्ट लेते है लेकिन उसका कभी परिणाम नहीं आता है। यह भी एक चिंताजनक विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 तारीख के बजट में 104 दवाई बढ़ाई हैं, कुल 608 दवाई की हैं। इन दवाइयों के लिये, आज एक गरीब आदमी जिसके पास एक भी पैसा नहीं है वह आज सीना तान कर हास्पिटल में जाता है, बगैर पैसे जाता है और उसको इलाज मिलता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि हास्पिटल में एक अटेंडेट होना चाहिये। हास्पिटल में नि:शुल्क इलाज कराने के लिये एक गरीब आदमी आता है और चूंकि गांवों में,

(श्री किसनाराम विश्नोई)

ढाणियों में लोग अनपढ़ होते हैं, उसको यह मालूम नहीं होता है कि इसकी प्रक्रिया क्या है, नि:शुल्क दवा कहां मिलती है, कौनसे काउंटर पर मिलती है, उसके लिये गेट पर दो चार अटेंडेंट खड़े रहने चाहिये ताकि गरीब आदमी को आसानी से वह इलाज सुलभ हो सके। मुख्य मंत्री जी की यह योजना पूरे प्रदेश में राम बाण साबित हुई है। साथ ही साथ 10 तारीख के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता क्लिनिक, और आगे बढ़ते हुए, जनता क्लिनिक की घोषणा की है। वह भी गरीब के लिये, गली, मौहल्ले में बैठे आदमी के लिये घर बैठे इलाज के लिये आशा करते हैं कि राम बाण साबित होगी।

सभापति महोदय, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की कमी है। मेरे क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन भी नहीं है। अनेक गांवों में नर्स के बैठने के लिये कोई भवन नहीं है, भवन का भी निर्माण कराया जाए और खाली पड़े पदों को भरा जाए। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की करीब 5 लाख की आबादी है। 5 लाख की आबादी में एक भी ट्रोमा सेंटर नहीं है। वहां से दो स्टेट हाई वे गुजरते हैं। एक मेरे लोहावट मुख्यालय पर ट्रोमा सेंटर भी खोला जाए, यह मैं आपके माध्यम माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। जो मेरी 5 सीएचसी हैं वहां एक भी महिला चिकित्सक नहीं है, महिला चिकित्सक के पद भी भरे जाएं ताकि लोगों को सुविधा मिले। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर एक ब्लाक सीएमएचओ का पद भी सृजित किया जाए ताकि वहां आसपास अच्छी तरह से मानिटरिंग हो सके। यह जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांगें हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि अतिशीघ्र जो डाक्टरों के पद हैं, जो नर्सिंगकर्मियों के पद हैं, अतिशीघ्र भरे जाएंगे और जो पीएचसी और सीएचसी में क्रमोन्नत करने की मेरी मांग है, वह भी पूरी की जाए ताकि छितराई हुई ढाणियों में लोगों को समय पर इलाज सुलभ हो सके। यही कहते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे सभापति ने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गम्भीर समस्या है। हालांकि हमारा कुशलगढ़ जिला उप जिला है और हास्पिटल में 16 डाक्टर के पद हैं। 16 में से 10 पद रिक्त पड़े हैं। इसी वजह से हमारे कुशलगढ़ की जनता बहुत दुःखी है। वहां सोनोग्राफी नहीं है, एक्स-रे नहीं है, इसकी वजह से आये दिन हमारे कुशलगढ़ एरिये में रोड खराब होने की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उपचार के लिये उनको

(श्रीमती रमीला खड़िया)

बांसवाड़ा भेजा जाता है, दाहोद भेजा जाता है। वहां सुविधाएं नहीं होने के कारण रास्ते में ही मौत हो जाती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं कि कुशलगढ़ क्षेत्र में डाक्टरों की भर्ती की जाए। जो स्टाफ नर्स हैं, जो डेपुटेशन पर इधर-उधर हैं और तनख्वाह कुशलगढ़ से ली जा रही है, इसके बारे में भी गंभीरता से देखने व सोचने की जरूरत है।

मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूं कि मेरे कुशलगढ़ क्षेत्र में 100 बैड का हास्पिटल है, उसे 200 बैड का किया जाए और हमारा यह हास्पिटल राजा-महाराजाओं के टाइम का बना हुआ है। वहां पर गम्भीर समस्या है और वहां पर पानी भी गिर रहा है। इसी तरह से हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र के डूंगरा में 30 बैड का हास्पिटल है, उसे 100 बैड का किया जाए। वहां पर भी राजा-महाराजाओं के टाइम की बिल्डिंग बनी हुई है। वहां पर भी पानी के कारण खड़े रहने की जगह नहीं है। इसी कारण से मरीज इधर-उधर भटकते रहते हैं। कहीं दुर्घटना होती है, तो सोनोग्राफी के लिये, एक्स-रे के लिये, सीटी स्कैन के लिये बांसवाड़ा भेजा जाता है। वह डेढ़ घंटे का रास्ता है। दाहोद भेजा जाता है, वह भी डेढ़ घंटे का रास्ता है। ऐसी समस्याओं के कारण हमारे यहां आये दिन मौतें होती रहती हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि हमारे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र को विशेषकर नया भवन दिलवाने का कष्ट करें। मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री संजय जी शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई के लिये आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं जिस जिले से आता हूं, अलवर क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है। उसके साथ-साथ उसमें 11 विधान सभा क्षेत्र हैं और हमारे क्षेत्र की जनता की मेडिकल कालेज की बहुत पुरानी मांग रही है, जिसे लेकर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने अपने बजट अभिभाषण में मेडिकल कालेज की घोषणा भी की थी और दिनांक 27.06.2016 के आदेश के तहत मेडिकल कालेज हेतु अलवर शहर में जेल परिसर के पास भूमि का आबंटन भी कर दिया गया लेकिन किन्हीं कारणों से वह मेडिकल कालेज अपना अमलीजामा नहीं पहन पाया और वह कहीं और चला गया। आपके

(श्री संजय शर्मा)

माध्यम से मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अलवर जिले की और अलवर शहर की बहुत पुरानी मांग है कि वहां पर मेडिकल कालेज खुले। इस दृष्टिकोण से हमें मेडिकल कालेज दिया जाए क्योंकि वहां पर मेडिकल कालेज के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित की जा चुकी है। इसके साथ-साथ 800 करोड़ रुपये का पीपीपी माडल पर ईएसआई अस्पताल हेतु काफी लंबे समय से भवन बना हुआ तैयार खड़ा है। उस भवन में ईएसआई का अस्पताल चल रहा है जबकि वह भवन मेडिकल कालेज के लिए बना था। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे केन्द्र सरकार में माननीय मंत्री महोदय से बातचीत करके शीघ्र अतिशीघ्र इस ईएसआई मेडिकल कालेज को भी यदि शुरू करेंगे तो इससे अलवर जिला ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों को भी लाभ मिलेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा एक महती आवश्यकता है। उसको देखते हुए, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग है कि जो मेडिकल कालेज राज्य सरकार की ओर से अलवर जिले को मिलना चाहिए और जो ईएसआई का मेडिकल कालेज केन्द्र सरकार की तरफ से खुलना चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार पहल करके मेडिकल कालेज खुलवाने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से अलवर जिले की जनता को और साथ ही साथ अलवर जिले के आसपास के जो हमारे आम जन हैं, उनको भी फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री को एक आग्रह करना चाहूंगा कि अलवर शहर में सामान्य चिकित्सालय का जो मुख्य भवन है, वह बहुत पुराना है। वह भवन अंग्रेजों के जमाने का है और आज उसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, नवीनीकरण की आवश्यकता है। जहां हमारे चिकित्सकगण बैठते हैं, जहां हमारे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं, उस जगह भी पानी टपकता है और छत का प्लास्टर गिरता रहता है। इसके लिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि उस ऐतिहासिक भवन के जीर्णोद्धार के लिए भी कोई बजट का आबंटन करें। आप अपनी कोई घोषणा करके उस भवन के जीर्णोद्धार के लिये कोई नयी योजना या बजट का आबंटन करें।

(श्री संजय शर्मा)

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में सामान्य चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय और काला कुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में कुल 501 बैड स्वीकृत हैं और अलवर शहर में सामान्य चिकित्सालय अस्पताल है। चूंकि हमारा जिला हरियाणा से लगता हुआ है और 11 विधान सभा क्षेत्र हैं। 11 विधान सभा क्षेत्र के मरीजों के अतिरिक्त हरियाणा सीमा से लगते हुए जो गांव हैं, भरतपुर सीमा से लगते हुए जो गांव हैं, उनके मरीज भी बहुतायत संख्या में हमारे अलवर सामान्य चिकित्सालय में आते हैं, जिसके कारण बेडों की संख्या काफी कम पड़ती है। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे जो चार प्रमुख अस्पताल हैं, उन चारों अस्पतालों में कम-से-कम 100-100 बैडों की वृद्धि करके कुल 900 बैड हमारे अलवर में करने का आश्वासन दें, कृपा करें। उसके साथ-साथ मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि राजकीय सामान्य चिकित्सालय में सुपरस्पेशलिटी चिकित्सकों के पद सृजित करके उनकी नियुक्ति करने का काम करें।

मैं एक जानकारी आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी को देना चाहूंगा कि अलवर शहर के अंदर वर्तमान में कुल 20 पद रिक्त हैं। उसके साथ हमारे जिले में कनिष्ठ विशेषज्ञों के 67 पद रिक्त हैं, चिकित्सा अधिकारियों के 43 पद रिक्त हैं। यदि मैं जिले की बात करूं तो जिले के अंदर 130 पद रिक्त हैं। सरकार एक और जनता क्लिनिक खोलने की बात कर रही है। यह अच्छी सोच है। वार्डवार खुलें, मौहल्लेवार खुलें, जनता क्लिनिक खुलें, लेकिन जब हमारे पास इतने पद रिक्त हैं, संसाधनों की कमी है तो उन जनता क्लिनिकों में हम डाक्टर्स कहां से लाएंगे, नर्सिंग स्टाफ कहां से लाएंगे, इसका जवाब हमारे चिकित्सा मंत्री जी को देना चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, डाक्टर को भगवान के रूप में पूजा जाता है और डाक्टर का निवास या नर्सिंगकर्मियों का घर है। यदि वह ही जर्जर अवस्था में हो तो डाक्टर कितना ही अच्छा रहने का प्रयास किया, कितना ही अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करे, कहीं न कहीं उसके मन में यह भाव आता है कि 24 घंटे सेवा करने के बाद भी मुझे जो सेवाएं मिलनी चाहिए, वे राज्य सरकार के द्वारा नहीं मिल रही हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मांग करूंगा कि मेरे अलवर शहर विधान

(श्री संजय शर्मा)

सभा क्षेत्रों में जो चिकित्सकों के लिये जो क्वार्टर बने हुए हैं, नर्सिंग कर्मचारियों के लिये जो क्वार्टर बने हुए हैं, उनके लिये भी कुछ बजट आबंटित करें और नये क्वार्टर बनाकर हमारे चिकित्सकों को और नर्सिंग कर्मियों को सुविधा उपलब्ध कराएं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी से मांग करूंगा कि अलवर शहर स्थित चिकित्सालय नंबर-2 जो एनईपीपी में स्थित है। शहर के उस तरफ स्थित है, उस इलाके को हम पटरी पार इलाका बोलते हैं। उस चिकित्सालय को सैटेलाइट हास्पिटल के रूप में क्रमोन्नत करें। निश्चित रूप से जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग उस क्षेत्र में रहता है, उससे उनको सुविधा मिलेगी।

उसके साथ-साथ वैशाली नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वैशाली नगर में खोलकर आम जन को राहत प्रदान करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री मुरारीलाल जी मीना।

श्री मुरारी लाल (दौसा): सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई के संबंध में सभी साथियों ने अपने-अपने विचार रखे। मैं सीधा मेरे विधान सभा क्षेत्र दौसा पर आऊंगा। मेरे जिला मुख्यालय विधान सभा क्षेत्र से कई हाईवे गुजरते हैं। अभी वर्तमान में वहां 250 बैड का हास्पिटल है। पर-डे करीब तीन हजार से साढ़े तीन हजार के आसपास वहां पर आउटडोर होता है और हजार से पन्द्रह सौ पर-डे डिलीवरी होती है। मान्यवर, दौसा जिले से लगते हुए हमारे और भी जिले हैं जैसे करौली, सवाई माधोपुर और पास में ही टोंक है। अधिकतर जो जयपुर एसएमएस के अंदर जो मरीज आते हैं, मैं समझता हूं कि इन चारों जिलों से ही आते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी हास्पिटल वर्तमान में 250 बैड का है, उसको 300 बैड का किया जाए। एसएमएस में जितना भी प्रेशर है, अभी मरीज इन जिलों से आते हैं। बहुत-से साथियों की मांग है कि हमारे भी मेडिकल कालेज होना चाहिए लेकिन वहां की लोकल सुविधा के साथ-साथ एसएमएस का लोड भी कम होगा यदि दौसा में मेडिकल कालेज खुल जाता है। मैं मंत्री महोदय से इस मामले में अपनी मांग रखूंगा।

(श्री मुरारी लाल)

मान्यवर, इसके साथ-साथ दौसा के अंदर नांगल राजावतान है जो उपखण्ड कार्यालय है, वहां एसडीओ बैठता है, तहसीलदार बैठता है, सीईओ बैठता है। वहां मात्र पीएचसी हैं। वैसे तो पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो हमारे यहां पर तीन सीएचसी, पांच-सात पीएचसी, तीस-पैतीस करीब उप-स्वास्थ्य केन्द्र भी हमारे मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने खोले थे। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग है कि उसको सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो हमारे जो स्वास्थ्य केन्द्र खोले थे, उन सबमें भवन स्वीकृत हो गए थे और टेंडर भी हो गए थे। जैसे ही सरकार चली गई पता नहीं क्या हुआ? 23 उप-स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे रह गए जिनके भवन बने ही नहीं। पता नहीं ठेकेदार भाग गये या पैसे भाग गये। पता नहीं इन लोगों ने क्या किया? जब हमारे मंत्री हुआ करते थे राजकुमार जी। मेरा निवेदन है कि उन सब पर भवनों का निर्माण होना चाहिए।

इसके साथ-साथ मेरे एक-दो सुझाव और हैं। मान्यवर, ज्यादातर देखने में आया है, वैसे हम मेडिकल साइड के आदमी तो नहीं है, मंत्री महोदय, ज्यादातर यह सुनने में आया है कि दवाई की जो प्रिंट रेट होती है और जिस रेट में बिकती है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। कई दवाइयों के बारे में सुनने में आया है, देखने में आया है कि प्रिंट रेट है 100 रुपये और वह दवाई मिल जाती है मात्र 20 रुपये में। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या कारण है? मंत्री महोदय, आप दोनों बैठे हैं राज्य मंत्री जी और मंत्री जी, इस बात पर जरूर ध्यान दें कि यह प्रिंट रेट और सेल रेट का क्या चक्कर है? प्रिंट रेट है 100 रुपये और दवाई मिल जाती है मार्केट में 20 रुपये में। मैं समझता हूं कि यदि इस बात पर कंट्रोल हो जाए तो गरीब आदमियों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हास्पिटल में जो फ्री दवाई हमारी पिछली सरकार ने की थी, जो आम गरीब के लिए एक वरदान सिद्ध हुई थी। उसमें भी अभी हाल ही में 608 दवाइयां थीं उनको 712 तक किया। जो जांचें थीं, उनको 90 तक पहुंचाया। मैं समझता हूं यह एक ऐसा काम था कि गांव के गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर जो पैसे की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते थे, उनको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, वरदान सिद्ध हुई। इसमें कई बार एक बात देखने को मिलती है कि दवाइयों का भूमाफिया टाइप पनप गया। दवाइयां स्टोर में है और जो हमारे काउंटर सेन्टर होते हैं, उन पर दवाइयां नहीं मिलतीं। इसमें कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो दवाइयां स्टोर

(श्री मुरारी लाल)

में हैं, अब तो वैसे कई जगह आपने आनलाइन कर दी, उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, छोटे हास्पिटल में भी ऐसी कोई व्यवस्था की जाए ताकि मरीजों को यह पता रहे कि यह दवाई है या नहीं। लोगबाग जैसे ही काउंटर पर आते हैं, उनकी सीधी सैटिंग मेडिकल स्टोर वालों से होती है और कहते हैं कि दवाई नहीं मिली तो बाहर जाकर मार्केट में खरीद कर लाते हैं। उनका फालतू में पैसा जाता है। जिस तरह से खान माफिया और जो माफिया होते हैं, इसी तरह से दवाई माफिया भी इनकी सरकार में पिछली बार इतना जबरदस्त पनपा जिसको कोई सोच नहीं सकता। मंत्री महोदय तो हैं नहीं, पता नहीं वे संयम लोढ़ा जी का भाषण सुनकर ही चले गए। हो सकता है कि उनसे सुना नहीं जा रहा हो।

मेरा निवेदन है, सभी सदस्यों ने कहा कि मेरे डाक्टर कम हैं, मेरे डाक्टर कम हैं। मेरे दौसा जिले में तो डाक्टर पूरे हैं। हो सकता है कि कोई एक-दो डाक्टर कम हों। इसमें तो आप एक मेहरबानी करना कि पिछली बार इन्होंने डाक्टर्स को लगाया था, वह पता नहीं किस तरीके से लगाया? क्यों लगाया था? किस तरह से उन्होंने जनता में लूट की थी? हो सकता है ऊपर से इस हिसाब से गए होंगे। इनको चेंज कर देना। नये नाम हम दे देंगे। उनको हटा दो। उनकी खानापूर्ति हो गई होगी अब तो। उन्होंने तीन-चार साल तक खूब कमा लिया। जनता का खून पी लिया और जिस हिसाब से वह लगे थे, मेरे हिसाब से उनकी पूर्ति हो गई होगी।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे छोटे कस्बे टाइप गांव हैं, एक तो है काली पहाड़ी, एक है बनियाना और एक है लालडी का बास। इन तीन-चार जगह पर आप आने वाले समय में निश्चित पीएचसी खोलेंगे। हमारे मंत्री जी साइड में बोल रहे थे, हाल ही में इन्होंने एक फैसला किया है, यह वैसे तो बात करते हैं, ब्लड पर जीएसटी, ब्लड पर 12 परसेंट जीएसटी। इस पर तो आप लोगों को भी ऊपर तक लिखना चाहिए और सबको विरोध करना चाहिए। फिर तो आप जन्म पर, मरण पर भी जीएसटी लगा देंगे। मशीन से थोड़ी बनता है ब्लड जो उस पर जीएसटी लगा दी। इस पर हम सबको ऊपर भी लिखना चाहिए। यह एक ऐसी चीज है, यह काम हमको नहीं करना चाहिए।

बीमारी फैलने का सबसे मुख्य कारण है, जिस पर माननीय बस्सी के सदस्य ने बोला है-दूध। हमारी जो जयपुर सरस डेयरी है, इसमें हमारे दौसा से भी दूध आता है, बस्सी से भी आता है। यह बिलकुल फैक्ट है कि जितना दूध

(श्री मुरारी लाल)

पैदा नहीं होता, जितने जानवर दूध नहीं देते, उससे 20 गुना ज्यादा दूध जयपुर डेयरी रोज बेच देती है। दूध आखिर आता कहां से हैं? इस बात पर हमको गौर करना पड़ेगा। यह सही है कि कई जगह पकड़ में भी आया है। इसमें ज्यादातर यूरिया मिलाते हैं। यूरिया मिलाने से पता नहीं क्या केमिकल है कि दूध भी बन जाता है, उससे मावा भी बन जाता है, मिठाई बन जाती है। लोग दूध भी पी लेते हैं। इससे इतनी जबरदस्त बीमारियां फैलती हैं। मैं समझता हूं कि उन बीमारियों पर कितना खर्च होता है। लोगों को कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। मैं समझता हं कि इस मामले पर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। हम इसे एनालिसिस भी करेंगे कि जब दूध इतना पैदा ही नहीं हो रहा है तो बिक कहां से रहा है? इतना दूध पैदा ही नहीं हो रहा है तो इतना मावा बन कहां से रहा है? इस बात पर गौर करें तो स्वास्थ्य के संबंध में हमारा मामला और ठीक-ठाक हो सकता है।

अभी हाल ही में गरीबों के लिए जनता क्लिनिक का मामला चालू किया है। पिछली बार स्वास्थ्य के मामले में जितना हमारी सरकार ने ध्यान दिया था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने क्योंकि इतने हास्पिटल, मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में पहले एक भी सीएचसी नहीं था, पिछली बार तीन सीएचसी क्रमोन्नत हुए थे। पीएचसी दो-तीन थे तो पांच-छह पीएचसी बनाए थे। 28-30 उस समय उप-स्वास्थ्य केन्द्र भी बने थे। मैं समझता हूं कि पिछली बार जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कुछ किया नहीं। मेरा यही निवेदन है कि दौसा जिला मुख्यालय आपके यहां से बहुत नजदीक है और एसएमएस में आपका बहुत ज्यादा लोड है। वैसे तो जो भी सदस्य सुबह से बोल रहा है, वह कह रहा है कि हमारे यहां मेडिकल कालेज होनी चाहिए। यह सही बात भी है कि इतनी मेडिकल कालेज तो कोई खोल नहीं सकता। लेकिन यहां की परिस्थितियों को देखते हुए, एसएमएस की परिस्थितियों को देखते हुए, पूर्वी राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए और चार जिलों की परिस्थितियों को देखते हुए दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक और सरकार में उनकी हिस्सेदारी को देखते हुए। भाई, ज्यादातर एमएलए हमारे तो वन साइड ही हैं। इसे देखते हुए, यहां के लोड को कम करते हुए, आप तो रघु जी हमारे प्रभारी भी रहे हैं, संगठन के प्रभारी इंचार्ज भी हो तो हम तो यह कहेंगे कि रघु जी के नेतृत्व में हमारा जो हास्पिटल था वह 250 बैड से 300 बैड का हो गया और नांगल जो हमारा पीएचसी था, वह सीएचसी हो गया और

(श्री मुरारी लाल)

राजकुमार जी के टाइम पर हमारे जो उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के पैसे सैंक्शन हो गए थे, वह पता नहीं कहां चले गए? इसलिए उन पैसों को वापस दिखवा लो। वह टेंडर हो भी गए थे। पता नहीं कहा गायब हो गए। हम भी हार गए और पैसे भी गायब हो गए। इन दो-तीन चीजों पर और विशेषकर यह जो प्रिंट रेट है, इस पर आप जरूर ध्यान दें। हमने देखा कि 100 रुपये की दवाई मिलती है 20 रुपये में। इसका कारण क्या है? दो चीज ऐसी होती हैं कि कोई भी मरीज जब दुकान पर जाता है, उसका कोई भी अटेंडेंट जाता है तो दवाई की कभी रेट नहीं पूछता। प्रिंट रेट सीधी देखी और भाग कर लेकर आता है।

श्री सभापति: माननीय समाप्त करें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): यह एक ऐसी चीज है जिस पर लोगों की लुटाई होती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शोभा।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): मैं सबसे पहले माननीय सभापति महोदय जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं सफाई पर सदन में बोलने का मौका प्रदान किया। कटौती प्रस्ताव की मांग संख्या 26 के द्वारा सरकार से मांग रखती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों व्यवस्था अत्यन्त ही दयनीय अवस्था में है। चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अन्य शासकीय पद रिक्त होने के साथ ही सोजत अस्पताल में आईसीयू वार्ड नहीं होने, कुछ चिकित्सकों के निजी चिकित्सालय में सेवा देने के कारण रोगियों व घायलों को समय-समय पर उपचार की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिससे इनको मजबूरीवश महंगे निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। इसी क्रम में मेरा आपसे आग्रह है कि रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरवाएं। आईसीयू वार्ड को तत्काल चालू करवाएं। निजी चिकित्सालयों में सेवा देने वाले चिकित्सकों पर कठोर कार्यवाही की जाए ताकि आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, रायपुर चिकित्सालय शहरी श्रेणी में आता है जबकि रायपुर में शहरी जैसी कोई सुविधा नहीं है। इस चिकित्सालय में एक भी चिकित्सक नहीं आना चाहता क्योंकि इनको दो साल का सेवाकाल ग्रामीण क्षेत्र

(श्रीमती शोभा चौहान)

में देना अनिवार्य होता है। रायपुर चिकित्सालय में सेवा देने के बाद भी शहरी श्रेणी में गिना जाता है तो रायपुर चिकित्सालय शहरी श्रेणी से ग्रामीण श्रेणी में तब्दील कराया जाए। वहां पर इतनी बड़ी पंचायत होने के बावजूद भी सिर्फ एक डाक्टर के भरोसे पूरा अस्पताल है, इससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में घायलों के उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए राजकीय चिकित्सालय सोजत शहर में ट्रोमा सेंटर स्थापित किया जाए। साथ ही सीआरएम डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराई जाए। खराब पड़े उपकरणों को तत्काल बदला जाए।

दूसरी ओर बगड़ी नगर में सीएचसी को भी क्रमोन्नत किया जाए, ताकि वहां के लोगों को फायदा मिल सके। राजकीय चिकित्सालय में मैं जब दौरे पर गई थी तो बहुत गंदगी फैली हुई थी। गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा रहता है इसलिए वहां के कर्मचारियों को थोड़ा कसा जाए। राजकीय चिकित्सालय रायपुर की जनसंख्या करीबन 25 हजार के करीब हैं और वह एक डाक्टर के भरोसे है। काफी पद खाली पड़े हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने की वजह से महिलाओं को डिलीवरी के समय ब्यावर और पाली जाना पड़ता है। कई बार तो पेशेंट की मृत्यु तक हो जाती है। चिकित्सकों के पद भरे जाएं, इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं, ताकि वहां की जनता को फायदा हो सके।

कई ग्राम पंचायतें ऐसी भी हैं जहां आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं हैं। कई बार डिलीवरी के समय महिलाओं को पाली से ब्यावर ले जाया जाता है इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वहां पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं शिशु रोग विशेषज्ञ का पद भरा जाए ताकि वहां की जनता को फायदा मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह जी।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मंत्री जी की काम करने की शैली है वह वास्तव में काबिलेतारीफ है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा, समय कम है और आपसे संरक्षण भी चाहूंगा।

(श्री खुशवीरसिंह)

सभापति महोदय, अभी हाल ही 6 मई को विधान सभा क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में 22 वर्ष का युवा घायल हो गया, वह जैतपुरा गांव का था, प्रकाश प्रजापत उसका नाम था। उसको सीएचसी मारवाड़ जंक्शन पर पहुंचाया गया। मारवाड़ जंक्शन पहुंचने के बाद डाक्टर ने रैफर किया, इसको पाली जिला हैडक्वार्टर भेज दिया जाए। 108 एम्बुलेंस मंगवाई, फोन किया तो एम्बुलेंस एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, आ रही है साहब, आ रही है और फिर उसका फोन स्विच आफ हो गया। चार घंटे इंतजार करने के बाद परिवार वाले जीप में डालकर लेकर गए और हास्पिटल के बाहर जैसे ही पहुंचे, उसकी मृत्यु हो गई। सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं बाद में पता चला कि जो एम्बुलेंस आ रही थी वह मारवाड़ जंक्शन और जाडन के बीच जहां नेटवर्क नहीं है, वहां खराब हो गई। सभापति महोदय, 1500 एम्बुलेंस खरीदी गई थीं जीवीके कम्पनी को 2017 में कांट्रेक्ट हुआ है। एक एम्बुलेंस, एक महीने का 1 लाख 57 हजार रुपये, चले या नहीं चले, तीन ड्राइवर, तीन इमरजेंसी मेडिकल टीम, ईएमटी, यह उन्होंने शर्त रखी थी। 200 एम्बुलेंस बंद हैं, लेकिन अभी तक किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको कंडम डिक्लेयर कर दे। 1 लाख 57 हजार रुपये उनका उठ रहा है। अगर आप उनकी लॉग बुक मंगवा दें तो आप देखेंगे कि एक महीने में 150-200 किलोमीटर से ज्यादा कोई एम्बुलेंस नहीं चली है। 200 तो बिलकुल ही नहीं चली है। उसका पैसा उठ रहा है, इतना घपला हुआ है। वह घपला हुआ है। पिछली बार एम डी, एनआरएचएम, अब बीच में से आर हट गया एनएचएम रह गया, एनएचएम का एम डी, एम डी साहब तो बहुत बड़े होते हैं, अपना तो वहां नम्बर ही नहीं आता, उन्होंने अपनी मनमर्जी से कांट्रेक्ट दे दिया। 104 का 94 हजार दिया, 108 का 1 लाख 57 हजार रुपये में दिया, चले या नहीं चले। 1500 एम्बुलेंस हैं, 1 लाख 57 हजार रुपये x 1500 आप कर लीजिए, महीने का कितना बजट होता है, साल का कितना होता है। इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मैं यह आरोप लगाता हूं। आप इसकी जांच करवाइये। आज 7-8 महीने हो गए कांग्रेस का शासन आए, अब तो उम्मीद रखते हैं। मैं आज आपके ध्यान में यह बात लेकर आए हैं, आप जांच करवाइये। 200 एम्बुलेंस खराब पड़ी हैं और अभी तक उनको कंडम डिक्लेयर नहीं किया गया। किसकी जरूरत है कि इसको डिक्लेयर कर दे। आप इसकी जांच करवाइये।

मंत्री महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा। दूध मिलावट वाली बात

(श्री खुशवीरसिंह)

है, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे। यू ट्यूब पर मैंने देखा कि उसके अंदर यूरिया डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, अभी तक हमारे पास लैक्टोमीटर या ऐसी कोई मशीन नहीं है कि यह पता चल सके वह कैमिकल वाला दूध है, फैट भी बराबर बताता है। अब कोई मशीन आई हो तो पता नहीं लेकिन अभी तक ऐसा कोई उपकरण नहीं है कि पता चल सके कि कैमिकल वाला दूध है या ओरिजिनल दूध है।

मंत्री महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि बाजार में मिठाई मिलती है, आप देखिए कि हर मिठाई पर सफेद रंग का फोइल लगा हुआ होता है। वह सिल्वर फोइल के नाम से है, चांदी का वर्क है, आप उसकी जांच करवाइये कि वह किस मैटल का बना हुआ है। स्वास्थ्य के लिए वह बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए जो कैमिकल वाला दूध, मिलावट वाला दूध बनाते हैं। आजीवन कारावास की सज़ा का कानून बनाया जाए, तभी इस तरह के लोग बाज आएंगे।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए मंत्री महोदय से चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 76 ग्राम पंचायतें हैं, एक नगरपालिका है, दो पंचायत समिति मुख्यालय भी हैं, मगरा क्षेत्र भी आता है। मगरा क्षेत्र में घाट सैंक्शन होने की वजह से दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं।

मंत्री महोदय, मुझे ज्यादा नहीं, दो सीएचसी, आप लिख लें, दो सीएचसी अगर आप स्वीकृत कर दें, बहुत पिछड़ा हुआ मगरा क्षेत्र है तो वहां की जनता आपको धन्यवाद देगी। दुर्घटनाग्रस्त होकर जो लोग आते हैं उनको भी राहत मिलेगी।

मंत्री महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इतना ही कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में 62 एएनएम के पद रिक्त पड़े हैं। आपने डाक्टर के काफी तो भर दिए उनके लिए तो धन्यवाद लेकिन अभी भी वहां पर 9 पद रिक्त हैं। भवनरहित सब सेंटर को आप तुरन्त स्वीकृति प्रदान करें। जो हास्पिटल जर्जर है जिनको मेंटिनेंस की जरूरत है। हमारी दो-चार पीएचसी हैं, उनके रिपेयर की भी व्यवस्था कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती मीना कंवर।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती हूं।

(श्रीमती मीना कंवर)

मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति बालेसर के सबसे पुराने हास्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेसर का निर्माण वर्ष 1980 में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय दादोसा हुकुम खेतसिंह जी राठौड़ ने करवाया, जिसके बाद आज तक स्वास्थ्य केन्द्र की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में इसका भवन जर्जर अवस्था में हो रहा है। वहां पर ट्रोमा सेन्टर की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि यह स्वास्थ्य केन्द्र नेशनल हाई-वे 125, जोधपुर से पोकरण के मध्य स्थित एकमात्र स्वास्थ्य केन्द्र है। यहां पर लाखों की संख्या में हर वर्ष भक्तगण रामदेवरा यात्रा पर जाते हैं। दुर्घटना की स्थिति में सुविधाओं के अभाव में, ट्रोमा सेन्टर नहीं होने के कारण उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। अत: मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेसर का नवीन भवन बनवाने हेतु इसे क्रमोन्नत करके सैटेलाइट हास्पिटल का दर्जा दिया जाए।

दूसरा निवेदन यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेसर में प्रति माह दो सौ से अधिक प्रसव किये जाते हैं लेकिन उपकरणों एवं चिकित्सकों की कमी के कारण सामान्य प्रसव के अलावा सभी मरीजों को जोधपुर रैफर किया जाता है। इससे आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में बहुत बार प्रसव रास्ते में ही हो जाता है। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिये भी इस अस्पताल में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर परिजनों के ठहरने के लिये धर्मशाला की व्यवस्था होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेसर की मोर्चरी नहीं होने के कारण खुले में ही पोस्टमार्टम किया जाता है, जो जनहित में सही नहीं है। अत: मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर समुचित चिकित्सकों की व्यवस्था कर परिजनों के ठहरने हेतु धर्मशाला की व्यवस्था की जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेसर में केवल विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जबकि एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों का एक भी पद स्वीकृत नहीं है। अत: एम.बी.बी.एस. डाक्टर के पद स्वीकृत करवाकर चिकित्सकों की पदस्थापना करवाई जाए।

चिकित्सा मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान के बेरोजगार भाइयों और बहनों की तरफ दिलाना चाहती हूं। नेशनल हैल्थ मिशन के अंतर्गत विगत भा.ज.पा. सरकार ने 2016 में 3167 पदों के लिये जी.एन.एम.

(श्रीमती मीना कंवर)

भर्ती परीक्षा करवाई थी जिसका परिणाम युवाओं की हितैषी कांग्रेस सरकार ने 06 फरवरी, 2019 को जारी किया था। इसके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है लेकिन मेरे बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अत: सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इनको शीघ्र नियुक्ति देने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री संदीपजी शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 26 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य किसी भी प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय का कार्य है। जो सरकार इन विषयों के प्रति गम्भीर होती है, निश्चित रूप से वह राज्य खुशहाल होते हैं। उन राज्यों में स्वस्थ लोग बसते हैं और वे निश्चित रूप से उस प्रदेश के विकास के लिये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस परिकल्पना के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने समझा और उन्होंने सम्पूर्ण देशवासियों में पहली बार स्वच्छता और सफाई के अभियान को लेकर सम्पूर्ण देश में अलख जगाई। साथ ही चिकित्सा के रूप में भी उन्होंने आधुनिक चिकित्सा को और गुणवत्तायुक्त चिकित्सा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। देश के कई राज्यों में मेडिकल कालेजेज और एम्स की स्थापना कर आधुनिक चिकित्सा को लोगों की पहुंच तक पहुंचाया और योग के द्वारा इस देश को जागृत करके योग की महत्ता को पूरे विश्व को समझाया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का 2019-20 का बजट राजस्थानवासियों के लिये एकदम निराशाजनक बजट रहा है। न तो कोई महत्वपूर्ण चिकित्सा योजना है और न ही कोई इस प्रकार का कार्य, जिससे राजस्थानवासियों को लगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नया होने जा रहा है अथवा उन्हें चिकित्सा के लिये कोई आधुनिक चिकित्सा अथवा कुछ अच्छी चीज मिलने वाली है। और तो और, हमारी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को तो उन्होंने बजट में कोई स्थान ही नहीं दिया। यही हाल, ऐसी ही

(श्री संदीप शर्मा)

चिकित्सा पद्धति, जो निरापद और बिना किसी साइड-इफैक्ट के है, होम्योपैथी, उसको भी चिकित्सा के बजट में कोई स्थान नहीं दिया।

सभापति महोदय, मेरा मानना है कि सिर्फ दवाइयां फ्री कर देने से या जांच फ्री कर देने से मरीज का सम्पूर्ण इलाज नहीं हो सकता। सम्पूर्ण इलाज के लिये आवश्यक है, उस मरीज का सम्पूर्ण इलाज हो सके। उसके लिये हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने भामाशाह बीमा योजना लागू की थी, जिसके माध्यम से 30 हजार से 03 लाख रुपये तक का पूरा इलाज उस मरीज का होता था, वह प्राइवेट अस्पतालों में भी जा सकता था। जिंदगी में उसने कभी प्राइवेट बड़े अस्पताल नहीं देखे होंगे। पहली बार उसने जीवन में 30 हजार से लेकर 03 लाख रुपये तक का इलाज प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में करवाया।

मैं कोटा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। कोटा विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना 1993 में हुई। इस मेडिकल कालेज में कोटा, बारां, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के भी मरीज आकर अपना इलाज कराते हैं। पिछले पांच वर्षों में 2013 से 2018 के पीरियड में, इस मेडिकल कालेज का स्वर्णिम काल रहा है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी को अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारा सुपर स्पेशलिटी ब्लाक, 150 करोड़ रुपये की लागत से, कैथ लैब, किडनी ट्रांसप्लांट, इसके अलावा महिलाओं की प्रारम्भिक जांच के लिये, उनके ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिये मेमोग्राफी मशीन, जिससे महिला को पहले ही मालूम पड़ जाता है, अगर उसमें जांच हो जाए, उसके ब्रेस्ट अथवा सर्वाइकल कैंसर की प्रारम्भिक स्टेज उसे मालूम पड़ जाती है। बुजुर्गों के लिये जीरियाट्रिक वार्ड, बच्चों के लिये नीकू-पीकू वार्ड, द्वितीय तल का 40 करोड़ का कार्य, लाइब्रेरी, बैड्स में बढ़ोतरी, मेडिकल छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी और कई मशीनें, जिनके द्वारा महत्वपूर्ण जांचें सम्भव हो पाईं और लगभग 300 करोड़ से अधिक के कार्य, इस 2013 से 2018 के भा.ज.पा. शासनकाल में हुए।

साथ ही एक करोड़ की डिस्पेंसरी केशवपुरा में, एक करोड़ की डिस्पेंसरी सुभाषनगर में स्थापित हुई। दस करोड़ की लागत से ई.एस.आई. हास्पिटल के रिनोवेशन का कार्य हुआ लेकिन 2008 से 2013 का कालांश कोटा में चिकित्सा के लिये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जिसमें बहुत ही कम कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में हो पाये और मुख्यत: मेडिकल कालेज में कोई विशेष प्रभावशाली योजनाएं चिकित्सा सम्बन्धी योजनाएं उस समय प्रारम्भ नहीं हुईं।

(श्री संदीप शर्मा)

मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि 2008 से 2013 के काल में मात्र दो से पांच करोड़ के कार्य हुए होंगे। मैं कोटा शहरवासियों की ओर से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि आज मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लाक तैयार होकर खड़ा है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, यदि वहां पर स्टाफ और परम विशेषज्ञ चिकित्सक बैठ जाएं तो पूरे क्षेत्र में हम चिकित्सा के रूप में आत्म निर्भर हो सकते हैं। हमें न जयपुर जाने की आवश्यकता है, न दिल्ली जाने की आवश्यकता है। हम कोटा में बड़े से बड़ा इलाज कर सकते हैं लेकिन आपको सिर्फ वहां स्टाफ का बंदोबस्त करना है और वहां पर परम विशेषज्ञ चिकित्सक बैठाने हैं।

(18.00 बजे)

आज जिस प्रकार से मेडिकल कालेज का आउटडोर बढ़ा है, गायनी में महिलाओं का तेजी के साथ आउटडोर बढ़ा है इसलिए वहां पर मातृ एवं शिशु कल्याण चिकित्सालय की आवश्यकता है। उसकी जननी सुरक्षा को देखते हुए यह आवश्यक है कि आप वहां पर अपने बजट में इस मातृ एवं शिशु कल्याण चिकित्सालय को प्रारम्भ करें। प्राइवेट वार्ड वहां की चिर-प्रतीक्षित मांग है। यदि वहां पर प्राइवेट वार्ड खुल जाते हैं तो एम.बी.एस. की तरह हमारा मेडिकल कालेज भी वहां पर लोगों के भर्ती होने के लिए चालू हो सकता है।

यहां पर जोड़ प्रत्यारोपण के आपरेशन नित-प्रतिदिन होते हैं। यहां पर जोड़ प्रत्यारोपण के मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत बोन-बैंक स्थापना करने व माड्यूल ओ.टी. की आवश्यकता है। न्यू मेडिकल कालेज में ई.एन.टी. वार्ड, नेत्र रोग विभाग की सेवाएं नियमित नहीं मिल रही हैं, इनको नियमित किया जाए।

मेडिकल कालेज चिकित्सालय परिसर में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सालय भी एक ही परिसर के नीचे खोलने का अगर चिकित्सा मंत्रीजी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इससे वहां पर बहुत सारी पद्धति से लोगों को चिकित्सा का लाभ मिलेगा।

प्रदेश में कार्यरत संविदाकर्मियों के मानदेय बढ़ाये जाएं। द्वितीय तल का कार्य भी बड़ी धीमी गति के साथ चल रहा है, इसको भी तेजी से करवाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों व राजकीय कर्मचारियों को एम.आर.आई. व सीटी स्कैन फ्री की है परन्तु चिकित्सा विभाग में रेडियोलाजिस्ट चिकित्सकों की संख्या कम है, इनकी नई

(श्री संदीप शर्मा)

भर्ती करने की आवश्यकता है। वर्तमान में कोटा मेडिकल कालेज में इन जांचों को करवाने के लिए रेडियोलाजिस्ट चिकित्सक के अभाव में मरीजों को 15 से 20 दिन तक की वेटिंग करनी पड़ रही है। इस मेडिकल कालेज में पोस्टमार्टम रूम भी तैयार है, उपकरण लग चुके हैं, इसे शुभारंभ करने की आवश्यकता है, जिससे यहां पर सुचारु रूप से कार्य हो सके।

मेडिकल कालेज चिकित्सालय और सुपर स्पेशलिटी ब्लाक को पुल के माध्यम से जोड़ने का कार्य, पार्किंग स्थल, वर्तमान गेट को चौड़ा करने का कार्य भी अधूरा पड़ा है।

दादाबाड़ी में हमारा चिकित्सालय है जिसमें नए कोटा क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र इलाज करवाने आता है, इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसका बहुत बड़ा आउटडोर है। इसको सैटेलाइट के रूप में परिवर्तित किया जाए और साथ ही स्वास्थ्य केन्द्र सूरजपोल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है।

पांच करोड़ की लागत से विज्ञान नगर में भाजपा के शासन काल के समय से प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार खड़ा है, आवश्यकता है कि इसका उद्घाटन मंत्रीजी आकर करें और इसका शुभारंभ करें जिससे विज्ञान नगर के क्षेत्रवासी इसमें इलाज पा सकें और चिकित्सा करवा सकें।

माननीय सभापति महोदय, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा में भामाशाह व निर्धन लोगों को स्पाइन के आपरेशन के लिए इम्प्लांट नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण निर्धन व्यक्ति परेशान हो रहा है।

मैं सरकार का ध्यान होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह चिकित्सा पद्धति असाध्य रोगों के निरापद रूप से इलाज करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसमें लोगों का रुझान बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है क्योंकि इस पद्धति से साइड इफैक्ट्स नहीं होते हैं। हमारे यहां पर स्थिति यह है कि होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए डिस्पेंसरीज में स्टाफ नहीं है, डाक्टर नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के दादाबाड़ी शापिंग सेंटर, अनन्तपुरा में स्थित डिस्पेंसरी में भी यही स्थिति है। इन डिस्पेंसरीज की स्थिति बजट के अभाव में बिलकुल बीमारू अवस्था में है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता है। होम्योपैथिक चिकित्सकों की डी.पी.सी. एक बार भी नहीं हुई तथा चिकित्सकों का एक समान वेतनमान करने की आवश्यकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन औषधि

(श्री संदीप शर्मा)

निरीक्षक के कार्य क्षेत्र से स्थानांतरित की जाए। प्रदेश स्तर पर एक भी महाविद्यालय होम्योपैथिक का नहीं है, उसको खोलने की आवश्यकता है जिससे होम्योपैथिक को बढ़ावा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारी प्राचीन पद्धति आयुर्वेद के विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि चरक व पतंजलि जैसे महान ऋषियों ने इसकी खोज की और सम्पूर्ण विश्व में हमारी आयुर्वेदिक पद्धति का लोहा माना जाता है परन्तु इस बजट में इस आयुर्वेद को कोई स्थान हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नहीं दिया, यह बड़े दु:ख का विषय है। भारतीयों का इस आयुर्वेद की पद्धति में बहुत गहरा विश्वास है और निश्चित रूप से लोगों का आयुर्वेद से अपना इलाज करवाने के लिए पूरी तरीके से उनका प्रयास रहता है। आज आवश्यकता है कि प्रदेश में कई डिस्पेंसरीज व चिकित्सालय, जिनमें दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, उनमें दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएं। औषधालयों को स्वयं का बजट प्राप्त होना चाहिए जिससे तात्कालिक रूप से मौसमी बीमारियों के प्रकोप के समय, काढ़ा वितरण के समय उन्हें काम में लिया जा सके। पिछले आठ वर्ष से आयुर्वेद विभाग में विभागीय डाइरेक्टर पद सहित आयुर्वेद चिकित्सक, चिकित्सा-कर्मियों के पद रिक्त हैं, इन्हें भरा जाए।

माननीय सभापति महोदय, कोटा में दाऊदयाल जोशी ग्रेड-ए जो हमारा आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, वह 22 बीघा में स्थित है और यहां पर वैलनेस सेंटर की बहुत पुरानी मांग है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय में वैलनेस सेंटर की स्थापना की जाए।

मेरा अंत में माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप चालू होने वाला है और किस कदर हमने इस दंश को राजस्थान में झेला है, कोटा में झेला है। महामारी के रूप में डेंगू ने पैर पसार कर हजारों लोगों को बीमार कर दिया, आर्थिक रूप से उनकी जेबों पर भार आया और पैसे उधार करके उनको इलाज करवाना पड़ा और कई लोगों ने इसमें अपनी जान खो दी इसलिए यह आवश्यक है कि हम अभी से अपने इस चिकित्सा तंत्र को सचेत करें जिससे यह बीमारियां फैलने से पहले एंटी लार्वा एक्टिविटीज और अन्य एक्टिविटीज के माध्यम से हम इस बीमारी पर रोक लगा सकें। होने से पहले ही यह महामारी का रूप नहीं ले लें इसलिए मेरा निवेदन है क्योंकि स्वाइन फ्लू और डेंगू ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रमित बीमारियां हैं। यह

(श्री संदीप शर्मा)

संक्रमण के द्वारा फैलती हैं और यदि एक बार किसी शहर में इन बीमारियों का प्रकोप चालू हो जाए तो वह रोकने से भी नहीं रुकता इसलिए इन महामारियों को रोकने के लिए हम अभी से चाक-चौबंद हो जाएं और अपने चिकित्सा तंत्र को पूरी तरीके से दुरुस्त कर लें।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा पर काफी समय से सारगर्भित चर्चा हो रही है। चर्चा में कई बिंदु सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने जो जनता क्लिनिक खोलने की बात कही है, उस पर प्रतिपक्ष के कुछ साथी कह रहे हैं, झोला-छाप डाक्टर, वह डाक्टर, यह डाक्टर, कैसी व्यवस्था होगी? अभी तो इस योजना की घोषणा हुई है। घोषणा होने के बाद अब इसकी नीति बनेगी और नीति बनकर इसकी क्रियान्विति नहीं हुई, उससे पहले ही आपने आलोचना करना शुरू कर दी। विरोध करना आपका धर्म है लेकिन जो चीज आई नहीं उसका विरोध एकदम से करना, मैं मानता हूं कि उचित नहीं है।

मुख्य मंत्रीजी की इस योजना को लागू करने के पीछे जो मंशा है, जैसा कि नि:शुल्क दवाओं को बढ़ाने की जो उनकी मंशा थी और बढ़ाने की घोषणा की है। 104 तरह की दवाइयों की, किडनी की, कैंसर की, हार्ट की जो गम्भीर बीमारियां हैं जिनका इलाज आम आदमी नहीं करवा सकता है, बहुत महंगी दवा है, उनको फ्री करना बहुत अच्छी बात है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए और बी.पी.एल. परिवारों के लिए मुख्य मंत्रीजी ने एस.एम.एस. मेडिकल हास्पिटल में सीटी स्कैन, एम.आर.आई., एंजियोग्राफी जो फ्री की है, उसी तर्ज पर सारे मेडिकल कालेज पर राजस्थान में फ्री करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं और इन योजनाओं से मुझे यह विश्वास हो रहा है कि मुख्य मंत्रीजी की भावना राजस्थान को राइट टू हैल्थ की तरफ ले जाने की है और आम आदमी को यह अधिकार देने की उनकी भावना है कि हर आदमी को चिकित्सा प्राप्त करने का इस राजस्थान प्रदेश में अधिकार है। उनकी ऐसी सोच बहुत ही ऊंची सोच है और अभी वर्तमान में सरकार में आते ही सरकार

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

ने जो फैसले किये हैं। स्वाइन फ्लू के बारे में अभी सदन में चिंता हो रही थी, कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे भीलवाड़ा की पूर्व माननीय सदस्या, कीर्ति बाईसा की स्वाइन फ्लू से डैथ हुई थी, और भी कई लोगों के डैथ हुई। राजस्थान में काफी जिलों में हुई। बड़ी चिंता का विषय था, लेकिन राजस्थान में यह सरकार आते ही दवा टेमी फ्लू, जो स्वाइन फ्लू के काम में ली जाती थी, वह हैडक्वार्टरों पर मिलती थी, उस दवा को माननीय मंत्री महोदय ने उप-स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचाने का जो काम किया, वह ऐतिहासिक निर्णय है, ताकि स्वाइन फ्लू होते ही वह टेबलेट ले तो उससे मरीज को राहत मिलती है। ऐसे बड़े कदम उठाये हैं। एनीमिया, जो किशोरियों और किशोर बच्चों को आयरन की कमी की वजह से हो रही है और जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर असर पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। ऐसी बीमारी को एक सघन अभियान चलाकर स्वास्थ्य केन्द्र तक इस एनीमिया की बीमारी के इलाज की व्यवस्था आते ही वर्तमान सरकार ने, मंत्रीजी ने की है। मंत्रीजी इसके लिये बधाई के पात्र हैं।

इसके साथ ही, कई सदस्य चिंता कर रहे थे और खाद्य की बात कर रहे थे, खान-पान की बात कर रहे थे जिससे गम्भीर बीमारियां होती हैं, यह होता है, वह होता है। वास्तव में आपकी चिंता जायज है, वाजिब है। सरकार के आते ही मिलावटखोरों के खिलाफ, राजस्थान में मंत्रीजी ने आदेश दिया और जो धरपकड़ शुरू हुई है वह तारीफे-काबिल है और यह अभियान आप निरन्तर चलाये रखें। ड्रग इंस्पेक्टर अगर आपके विभाग में कम हैं, तुरन्त आप इसकी भर्ती करवाकर इस अभियान को राजस्थान में जारी रखेंगे तो उतना ही हम चिकित्सा के मामले में सफल हो पाएंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरा, मेरा आपसे यह निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, सभी मेडिकल कालेजों पर हम यह सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिये, बी.पी.एल. के लिये करेंगे तो मेरे भीलवाड़ा में गहलोत साहब द्वारा जो मेडिकल कालेज खोला गया था, वह मेडिकल कालेज आज प्रारम्भ हो चुका है। वहां कैथ-लैब की आवश्यकता है। कैथ-लैब आप वहां लगाएं मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुसार और एंजियोग्राफी की सुविधा उसमें उपलब्ध हो और कार्डियोलोजिस्ट का पद माननीय मंत्री महोदय, भीलवाड़ा में आप स्वीकृत करें

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

(18.12 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

ताकि वह व्यवस्था सुचारु रूप से चले और सारे जो मशीन-उपकरण हैं, वह सब आप सरकार से आबंटित कराएं।

दूसरा, इमरजेंसी ओ.टी. की व्यवस्था करें जिसमें 25 शय्याओं वाली एक इमरजेंसी ओ.टी. भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हास्पिटल में बने। वेंटीलेटर्स, मोनीटर्स, यह सारी सुविधाएं महात्मा गांधी हास्पिटल में करने की नितांत आवश्यकता है। कालेज बिल्डिंग में 201 कमरे हैं और 201 कमरे और 750 बच्चे वहां आएंगे, 150 प्रतिवर्ष आएंगे। आपके एम.सी.आई. के नोर्म्स के अनुसार भी 60 प्रतिशत रहने की व्यवस्था बच्चों की होनी चाहिए तो वहां कमरों की व्यवस्था भी और कराएं, क्योंकि वह कालेज शहर से आठ किलोमीटर दूर है।

कालीचरण जी, माननीय पूर्व मंत्री महोदय, आप जो नमस्कार कर रहे हैं, मैं आपको यहां तक नमस्कार करता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र के गहलोत साहब के स्वीकृत सी.एच.सी. हास्पिटल भवन, जिसमें 3 करोड़ 25 लाख सैंक्शन था, आज तक नहीं बना पाये, आपने पांच साल निकाल दिये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरिया स्वीकृत था गहलोत साहब के जमाने का, सवा करोड़ रुपये उस पर स्वीकृत था, आज तक आप नहीं बना पाये। हाथ तो मैं आपके जोड़ता हूं। आपने दियास, मेहंदी, राणात, मोखमपुरा, बाडिया खुर्द, भटेवर, यह सारे उप स्वास्थ्य केन्द्र, जिस पर 25-25 लाख रुपये स्वीकृत हैं, वह आप पांच साल में नहीं बना पाये, इसलिए हाथ मैं जोड़ता हूं। आप बहुत महान व्यक्ति हैं।

मंत्री महोदय, मोकुन्दा की पी.एच.सी. की चारदीवारी नहीं होने से गांव में वहां लोग गंदगी करते हैं और चिकित्सालय का सही उपयोग नहीं होता है तो वहां पर चारदीवारी के लिये, जो भी बजट दें, उससे चारदीवारी वहां पर बनवाएं। गंगापुर को, जो नेशनल हाईवे पर है, वहां से भीलवाड़ा 50 किलोमीटर पड़ता है, उदयपुर 80 किलोमीटर पड़ता है, बीच में है और गंगापुर से करेड़ा-आसीन्द का राजमार्ग भी उस रोड पर है, तो गंगापुर हास्पिटल को आप सैटेलाइट हास्पिटल घोषित करें और सैटेलाइट हास्पिटल बनने से वहां दुर्घटना में घायल हुए लोगों का भी इलाज होगा, साथ ही उस एरिये की बहुत

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

बड़ी पापूलेशन है, उधर तो 80 किलोमीटर जाना और इधर 50 किलोमीटर जाना, तो यह दूरी तय करने में मरीज की जान निकल जाती है। कम से कम लोगों को वहां तुरन्त अच्छा उपचार मिल जाए। गंगापुर हास्पिटल में सी.एच.सी. में डाक्टरों ने मांग की थी कि हमें सोनोग्राफी मशीन चाहिए, हमें ब्लड बैंक के लिये जनरेटर चाहिए, हमें पोछा मशीन चाहिए, हमें इंटरनल रोड्स चाहिए। इन सारी व्यवस्थाओं के लिये मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि गंगापुर नगरपालिका बोर्ड की तरफ से यह प्रस्ताव पास किया कि 50 लाख के जो भी काम है, नगरपालिका चिकित्सालय को उपलब्ध कराएगी सारी मशीनें, सोनोग्राफी और यह सारी मशीनें नगरपालिका आपकी सी.एच.सी. को उपलब्ध करा रही है, तो आपसे मेरा यह निवेदन है कि सोनोग्राफी का डाक्टर वहां पर आप तुरन्त भिजवा दें ताकि वह मशीन देखकर, जिस कम्पनी की मशीन खरीदनी है, आपके जो अधिकारी हैं, वह हमें इस मामले में अवगत करा दें। रायपुर के अंदर बैड बढ़ाने की बात है। रायपुर में आप कुछ बैड बढ़ाएं।

दूसरा, मेरा निवेदन था आपसे कि रायपुर उपखण्ड स्तर का हास्पिटल है। राजस्थान में आयुर्वेद की 62 ब्लाकों और तहसीलों पर औषधालय हैं। मेरे ब्लाक पर आयुर्वेद का कोई भी हास्पिटल नहीं है। वहां पर आप 'ए' क्लास हास्पिटल खोलने की कृपा करें ताकि उस क्षेत्र के लोगों का आयुर्वेदिक इलाज लोगों की भावना के अनुरूप, वहां पर ग्रामीण लोग हैं, वह आयुर्वेदिक दवाओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो यह उन लोगों के लिये लाभप्रद होगा।

आयुर्वेद के जो आपके निदेशक हैं, वह निदेशक आयुर्वेद का जिसको 10 साल का अनुभव हो, वह डायरेक्टर हो तो कम से कम वह इस मामले में यह महसूस कर सके कि कौनसी दवाएं, कौनसे क्षेत्र में, कौनसे औषधालय में भेजना है, वहां कौनसी बीमारियां हो रही हैं। अलग-अलग रेगिस्तान में अलग तरह की बीमारियां आ रही हैं, हमारे यहां अलग तरह की बीमारी आ रही है, कोटा की तरफ अलग तरह की बीमारी आ रही है तो उस औषधि का उन्हीं को अनुभव होता है, जो इस विभाग में काम कर चुके होते हैं। आयुर्वेदिक हास्पिटलों में परिचारक की बहुत कमी है और साफ-सफाई वाले को आप सवा सौ रुपये महीने के दे रहे हो। सवा सौ रुपये महीने में कोई महीने भर आपका हास्पिटल साफ करने वाला नहीं है। इस बारे में भी आपको गम्भीर चिंतन करना चाहिए कि क्या हम यह वाजिब कर रहे हैं या उनका शोषण कर रहे हैं।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

काफी चीजें ऐसी हैं, एक आनलाइन दवा, अखबारों में बड़े-बड़े एड आ रहे हैं कि 30 प्रतिशत छूट, 40 प्रतिशत छूट, 50 प्रतिशत छूट, आनलाइन दवा, जीवन रक्षक दवा, आप हमारे यहां से मंगवाइए। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आनलाइन दवा किस लेबोरेट्री से टैस्ट होकर आ रही है? आनलाइन दवा देने वाले की कोई रेस्पांसिबिलिटी भी है कि नहीं? आनलाइन खरीदी दवा खाने वाले की क्या हालत होगी? इसके ऊपर एक चिंतन करने की जरूरत है कि आनलाइन दवा बेचने वाले लोग कौन हैं?

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि जेनेरिक दवाओं की कोई लेबोरेट्री हो, कोई ऐसी व्यवस्था हो, अच्छी दवाएं हैं जेनेरिक, लेकिन जेनेरिक दवाओं के लिये, उनमें कौनसा साल्ट कितना होना चाहिए, कौनसा कितना होना चाहिए तो उसके लिये जब तक लेबोरेट्री नहीं होगी, तब तक वह दवाएं देना भी सार्थक नहीं है तो लेबोरेट्री की व्यवस्था जेनेरिक दवाइयों के लिये भी हो।

इसी तरह अभी मुरारी जी कह रहे थे और राजकुमार जी कह रहे थे कि ब्लड बैंक में ब्लड के ऊपर, जो हम अपना ब्लड देते हैं उस पर 12 परसेंट जी.एस.टी. लगा रखी है। मंत्री जी, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आदमी के खून पर तो लगा रखी है, इन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, मंदिर की पूजा के सामानों पर भी जी.एस.टी. लगा रखी है। यह हालत है सरकार की।

आप जो चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल कर रहे हैं, जो भी करने का है, जिसका पुरानी सरकार का प्रस्ताव हो सकता है, मेरे तो ऐसा सुनने में आया है तो एज का अगर कोई है, यह ऐसा प्रस्ताव है या कोई ऐसी खबर है तो कृपा करके आप उम्र नहीं बढ़ाएं और हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चों के लिए जाब सिक्योरिटी रखें और आने वाली पीढ़ी के बच्चे इससे महरूम नहीं रहें। (व्यवधान) एम.एल.ए. की उम्र तो अस्सी। (व्यवधान) वो कटारिया साहब कह दें उतनी रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं और वैसे तो मोदी जी तय करेंगे, साहब।

श्री मुरारी लाल (दौसा): पूजा के सामान से हटाओ ...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): नहीं हटाएंगे। साहब, ब्राह्मण दु:ख पा रहे हैं, राजस्थान के सभी ब्राह्मण दु:ख पा रहे हैं।

अभी पारख साहब बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि मोदी जी ने देश

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

में बहुत बढ़िया फैसला किया कि हार्ट अटैक के स्टेंट की कीमत कम की है। मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आपने भामाशाह कार्ड चलाया, 54 हजार रुपये में हार्ट का स्टेंट डालना है। एस.एम.एस. में भी 54 हजार और प्राइवेट हास्पिटल में भी 54 हजार। एस.एम.एस. में डाक्टर हमारा सरकार की तनख्वाह का, कैथ लैब हमारी, सारी व्यवस्था हमारी, नर्सिंग स्टाफ हमारा, वहां 54 हजार में ओरिजिनल स्टेंट डल सकता है लेकिन मैं यह मानता हूं कि जो प्राइवेट में आपने इसको अलाउ कर रखा है, या तो वो पेशेंट से अधिक पैसा वसूल करते हैं कि आपको अच्छा स्टेंट लगवाना है तो 20 हजार एक्स्ट्रा दीजिए या 30 हजार एक्स्ट्रा दीजिए, या फिर ऐसा स्टेंट लगाते हैं। मैंने खुद भीलवाड़ा में एक प्राइवेट हास्पिटल में देखा है, उसने कहा, साहब, जो स्टेंट भारत सरकार ने बताया है इसकी रेट 17 हजार और हम आपको 30 हजार का लगाएंगे, तो हमारे को इतने रुपये और चाहिए। तो इसके ऊपर भी आपको एनेलिसिस करना चाहिए कि इसमें वास्तविकता क्या है?

सबसे बड़ी बात, मंत्री महोदय का धन्यवाद कि आपने बहुत बड़े फैसले लिये। मैं नेता प्रतिपक्ष से एक निवेदन करना चाहता हूं। वास्तव में आप सभी माननीय सदस्य इतनी चिंता कर रहे थे तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जर्मन, अमेरिका और बाहर से कैथ लैब की मशीनें, एम.आर.आई. की मशीनें, सीटी-स्कैन की मशीनें आ रही हैं उस पर भारत सरकार की जितनी भी ड्यूटी और जितने भी टैक्स हैं वो खतम करके राजस्थान सरकार में वो मशीनें उपलब्ध करायी जाएं ताकि राजस्थान और हिन्दुस्तान में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जांच मशीनों का फायदा हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा मशीनें राजस्थान में, हिन्दुस्तान में हर गरीब प्रांत में भी लग सकती हैं। इस मामले में आप लोग भारत सरकार से चर्चा करें तो ज्यादा उचित होगा। मंत्री महोदय, अगर आपकी भी जरूरत पड़े तो इनके साथ पधारिये, सप्रेम पधारिये और इस पुण्य काम में आप भी पुण्य कमाइये।

होम्योपैथिक की अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, वास्तव में होम्योपैथिक भी चिंता का विषय है। होम्योपैथी के 295 ब्लाक में से सिर्फ 85 ब्लाक में ही यह चल रहा है और हमारे स्टेट लेवल पर कोई होम्योपैथिक का महाविद्यालय नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। होम्योपैथिक का एक महाविद्यालय होना चाहिए। मुख्य मंत्री जी से भी मेरी यह मांग है कि इतने महाविद्यालय खोले जा रहे हैं तो एक स्टेट लेवल का होम्योपैथिक

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

महाविद्यालय खुले जिससे होम्योपैथिक के हमारे डाक्टर तैयार हों, राजस्थान में तैयार हों।

सभापति महोदय, आयुर्वेद के 700-750 चिकित्सक 05.05.1990 के बाद एडहोक पर लगे हैं जिनकी स्क्रीनिंग कई वर्षों बाद हुई, अब उन्हें कई वर्षों बाद नियमित किया गया जिससे पेन्शन के अपात्र हो जाएंगे, इस पर भी विचार करने की जरूरत हे। 27 आयुर्वेद के चिकित्सक 20 वर्ष की सेवा के बाद अभी भी उनके नियमितीकरण के आदेश नहीं हुए हैं तो हमें चिकित्सकों की सर्विस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा और आम जन की चिकित्सा से सम्बन्धित समस्याओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं समझता हूं इन सारी चीजों पर विचार करके और जब मंत्री महोदय जवाब दें तो उसमें इन पर जरूर ध्यान दें।

जो मेरे क्षेत्र की डिमांड्स हैं, जो जिला हैडक्वार्टर की डिमांड्स हैं उन पर भी मंत्री जी से चाहूंगा कि उन पर भी आप गौर फर्माएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री लाखन सिंह (अनुपस्थित)। माननीय श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में से दो हाईवे निकले हैं और उन पर काफी एक्सीडेंट होते हैं और हास्पिटल में इतनी परेशानी आती है कि ब्लड का कहा जाए, कोई देने के लिए तो तैयार नहीं होता है, कोई बाहर के लोग होते हैं तो उनकी लोग इतनी तो मदद कर देते हैं कि उठाकर उनको हास्पिटल में पहुंचा देते हैं बकाया कोई व्यवस्था नहीं कर पाता है। जब तक उनके घर वाले आते हैं उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तब तक उनकी जान चली जाती है तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़ी में ब्लड बैंक खोली जाए।

सभापति महोदय, मेरे बाड़ी में 100 बैड का हास्पिटल है और उसको 200 बैड का किया जाए। मरीजों की संख्या इतनी हो जाती है कि जमीन पर भी जगह नहीं मिलती है। आप वहां का रिकार्ड मंगवाकर देख लें कि क्या स्थिति है, कि जरूरत है कि नहीं है। कोई चीज की जरूरत है जब ही मांग की जाती है।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, बाड़ी में 100 बैड का हास्पिटल है और बजट सिर्फ 50 बैड का ही जा रहा है। तो जब 100 बैड का हास्पिटल है और अभी तक अपन उसमें बजट 50 बैड का ही दे रहे हैं तो हास्पिटल कैसे चलेगा?

सभापति महोदय, एक सैपउं हास्पिटल है उसको 50 बैड का किया जाए। बसई नवाब है, उसको भी 50 बैड का किया जाए। सभापति महोदय, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है केतरी में, नेशनल हाईवे पर पड़ता है बार्डर है यू.पी. का और राजस्थान का, तो वहां पर पी.एच.सी. खोली जाए। दानदाता ने भवन बनाकर दे दिया, वहां पर यह भी नहीं कि सरकार का कोई एक्स्ट्रा पैसा भी लग रहा हो, तो खोलने में मैं समझता हूं कि सरकार की कोई ज्यादा लागत नहीं आ रही और न कोई परेशानी आ रही हो।

सभापति महोदय, एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। बाड़ी में पुराना हास्पिटल है और काफी कम जगह है, उस हिसाब से मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक 200 बैड का हास्पिटल बनाया जाए वो आगे की सोच रख कर, यह जो हास्पिटल हमारे यहां बना हुआ है वो करीबन 50 साल पहले बना हुआ है। वह जब जमीन दी गई, तब लोगों के पास कार, जीप, ट्रैक्टर और मोटर साइकिलें नहीं थीं। आज लोगों को पार्किंग की भी जरूरत है। उस हिसाब से ही जमीन अलाट की जाए। आगे जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। वह तो कोई कम होने वाली नहीं है तो बिल्डिंग भी उसी हिसाब से बनाई जाए। उसी हिसाब से जमीन अलाट की जाए कि आगे चलकर दुबारा से अगर उसमें बैड बढ़ेगे तो भी दिक्कत नहीं हो। हर 5 साल में बैड बढ़ाने पड़ते हैं। सरकार बार-बार तो बिल्डिंग बना नहीं सकती है। उस हिसाब से इतनी जगह हम लेकर चलें कि वह आगे भी हमारे काम में आए।

सभापति महोदय, कालीचरण जी गए, भाषण तो वह बहुत अच्छे देते हैं। उनको बार-बार टोकने की आदत है। मेरे क्षेत्र में जो पहले स्वीकृत हास्पिटल थे, उनमें से एक की भी बिल्डिंग पर उन्होंने काम नहीं होने दिया है। यह तो महान व्यक्ति हैं। इनके बारे में क्या कहा जाए?

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक हमारे यहां मेडिकल कालेज स्वीकृत है। उस पर जल्दी काम चालू कराया जाए और वह बिल्डिंग बनाई जाए।

सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा में जो नाम हैं, उन लोगों के लिए ही

(श्री गिर्राज सिंह)

भामाशाह कार्ड चालू कर रखा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस भामाशाह कार्ड को आप कहीं उठाकर फेंक दें। यह इन्होंने एक ड्रामा किया था। इन्होंने इसमें कौनसा दान दिया है? इन्होंने क्या घर से दान दिया है? किस बात का भामाशाह कार्ड? किस बात का फोटो लगा रखा है इन्होंने पूर्व मुख्य मंत्री जी का? पैसा सरकार का, जनता का और फोटो मुख्य मंत्री जी का? किस बात के लिए फोटो? खाद्य सुरक्षा में जिन लोगों के नाम हैं, उनको ही इलाज के लिए अधिकृत कर रखा है। यह जो रोक लगा रखी है, इसको हटाया जाए। जब तब हम खाद्य सुरक्षा में उनके नाम जोड़ते हैं, वह गरीब लोग हैं, गरीब आदमी जाते हैं। इसमें अड़चन आती है और जो लोग बीमार हो गए, वह लोग एक-एक महीने, दो-दो महीने चक्कर लगाते हैं। पैसे वाले लोग जा रहे हैं क्या उन हास्पिटलों में? वह क्या आपने लाइन में लगे देखे हैं? वे नहीं जाते हैं। एसडीएम कार्यालय और पटवारियों के वह गरीब लोग चक्कर लगाते हैं। तब जाकर उनका खाद्य सुरक्षा का बनाते हैं। जब बना दिया तो उसको जोड़ने के लिए आनलाइन कराकर आओ। इसको हटाया जाए। मैं तो मंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि जैसे पहले व्यवस्था चल रही थी, वैसे ही चलने दो। अगर आपको रखना है कि नहीं, इलाज के लिए बाहर के लोग आ जाते हैं तो आप इसमें कोई परिचय पत्र, आधार कार्ड या कोई अन्य कार्ड लगा दो।

खाद्य सुरक्षा वाली बहुत बड़ी समस्या है। इससे बहुत परेशानी आती है। हम लोगों को परेशान होना पड़ता है। उसका नाम जुड़वाने के लिए कभी एसडीएम को फोन करो। कभी तहसीलदार के पास फोन करना पड़ता है। कभी पटवारी को देखना पड़ता है। इस समस्या का आप समाधान करें।

सभापति महोदय, एक यह जो जांचें हैं, आप सैम्पल भराते हैं तो अख़बार में आता है और यह लगता है कि बड़ी अच्छी कार्यवाही हुई है। लेकिन जब वह जांच के लिए जाते हैं तो सभी पास हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वह दो-दो, तीन-तीन साल तक सैम्पल पैंडिंग पड़े रहते हैं। उसके बाद इनकी जांच होती है। ऐसी क्या जांच होती है? अगर जांच करानी है तो उसकी तत्काल जांच कराओ। इसमें हमें कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो मिलावटखोर हैं, वह दुबारा से मिलावट नहीं करें। जिनके सैम्पल भरकर जाते हैं, उनमें से 90-95 परसेंट के सैम्पल पास हो जाते हैं। जब वह सैम्पल भरते

(श्री गिर्राज सिंह)

हैं और उस समय बात करते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ मिली है क्या, तो वह कहते हैं कि इसमें गड़बड़ मिली है। इसमें यह मिला है, इसमें वह मिला है, इस तरह की बातें वह बना देते हैं। लेकिन जब तीन-चार साल हो जाते हैं और उसके बाद सैम्पल जाते हैं तो किसी का ध्यान नहीं रहता है। उसके बाद वह सब पास हो जाते हैं। इससे दूसरे दिन से ही उसकी मिलावटखोरी वापस चालू हो जाती है। वह बंद तो तब करेगा, जब वह जेल के अंदर जाए, उसको सज़ा मिले। तब जाकर उनमें सुधार होगा। इससे पहले वह क्यों सुधार करेगा?

सभापति महोदय, मैं तो मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो मैंने मेरे क्षेत्र की समस्याएं रखी हैं, इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। भामाशाह कार्ड को दूर करें। इन लोगों ने तो नाम के लिए किया। इनका इस योजना को बंद करने का इरादा था। कोई भी अच्छी योजना इनको अच्छी नहीं लगती है। इन लोगों ने सोचा कि यह दवा योजना बहुत अच्छी है, तो इसको फेल करने के लिए ऐसे ही इन्होंने भामाशाह कार्ड चालू कर दिया। इनको क्या जरूरत पड़ी थी भामाशाह कार्ड चालू करने की? सिर्फ इसी वजह से कि यह योजना कैसे फेल हो और हम यह साबित करें कि यह योजना कांग्रेस की योजना थी और यह सब खराब थी। जबकि हकीकत बात यह है कि आप कहीं भी जनता में सर्वे करा लो, सभी लोग यह कहते हैं कि गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। गरीब आदमियों के पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। काफी अच्छी यह योजना चली।

सभापति महोदय, इन लोगों ने हमारे क्षेत्रों को पहले चिह्नित कर लिया कि इनके क्षेत्रों में काम नहीं कराने हैं। जो स्वीकृत बिल्डिंग, हास्पिटल हैं, उनको चालू कराया जाए। मैं तो मंत्री जी से यही निवेदन कर रहा हूं कि हम इनके साथ ऐसी राजनीति नहीं करें। वहां पर वोट बीजेपी का भी रहता है। कांग्रेस के भी रहते हैं। इस योजना का सभी को लाभ मिले। मैं तो यही निवेदन करता हूं। आपने बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आज हम एक बीमार महकमे की सेहत की चर्चा कर रहे हैं। आजादी के 72 वर्ष

(श्री सतीश पूनियां)

और लोकतंत्र के 67 वर्ष हुए। यहां पर मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने काफी बातें कही हैं। "हैल्थ इज वैल्थ", यह सामान्य सी उक्ति है। नीरोगी काया, इसके बारे में अक्सर सनातन परम्परा में बातें कही जाती हैं। 'पहला सुख नीरोगी काया', 'शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्' जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति शरीर से ही सम्भव है।

सभापति महोदय, WHO तो कहता है कि 1 हजार पर 1 डाक्टर की जरूरत आज है लेकिन राजस्थान का जिक्र करूं तो 10190 लोगों पर एक चिकित्सक की व्यवस्था है। मैं बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर है कि झोला छाप से लेकर फोर्टिस अस्पताल तक निजी पेशे के लोग भी इस व्यवस्था में हैं। एक दूसरी सरकारी व्यवस्था जो नर्स, कंपाउंडर से शुरू होकर एसएमएस मेडिकल कालेज के किसी प्रोफेसर तक जाती है। एसएमएस मेडिकल कालेज की बढ़ती हुई भीड़ और पीएचसी के सब सेंटर्स के खाली दरवाजे यह सरकार की और सरकारी प्रयासों की हकीकत बयान कर देते हैं।

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि पानी, अपराध और उसके बाद स्वास्थ्य, यह सबसे बड़ी चेतावनी समाज के साथ है। यह मुद्दा किसी भी सियासत से ऊपर है। मैंने जब सुबह प्रवेश किया तो तीन तरह के लोग मुझे विधान सभा के दरवाजे पर मिले। होम्योपैथिक के चिकित्सक मिले। आयुर्वेद के बेरोजगार चिकित्सक मिले। एमबीबीएस करने वाले वो विद्यार्थी मिले जिनको प्रवेश में कठिनाई आ रही है। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रबंधन इस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकता है। एक मजबूत सिंहावलोकन की जरूर आवश्यकता है क्योंकि अभी तक की जो व्यवस्था है उसमें स्वास्थ्य की चेतना हमारी प्राथकिता में नहीं रही। यहां नि:शुल्क दवा योजना के बारे में चर्चा हुई, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में चर्चा हुई। आयुष्मान योजना की चर्चा हुई लेकिन निःशुल्क दवा योजना के नाम पर आज जब मैंने चर्चा से पहले सामान्य तौर पर कुछ जगह पता किया तो एक सामान्य सी दवाई है, 'डाइक्लोपार' जो दर्द निवारक है और पैरासिटामोल का भी कंटेंट है लेकिन वह अभी मरीजों को उपलब्ध नहीं है, यह अपने आपमें एक बानगी है। जो सरकार आयुर्वेद से, योग से दूर भाग रही है क्योंकि जब हम यह कहते हैं कि बीमारी होनी ही नहीं चाहिए तो एक तरफ तो दुनिया अंतरिक्ष में चली गई, चांद पर

(श्री सतीश पूनियां)

चली गई, दूसरी तरफ बीमारी के कारकों ने अपने आपको इतना इम्यून कर लिया, पुराने समय से आप भी वाकिफ हैं कि जब डीडीटी छिड़की जाती थी तो मच्छर भाग जाते थे, आज आप कुछ भी छिड़क लो लेकिन बिजली के लट्टू पर मच्छर बड़े आराम से नृत्य करता हुआ दिख जाता है। मच्छर ने डेंगू जैसी बीमारियों को पैदा कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि एक अच्छे प्रबंधन की, एक अच्छी रणनीति की इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी जरूरत है। जो नीचे का सब सेंटर है, मेरे खुद के इलाके में 55 सब सेंटर आते हैं, या तो उनके भवन नहीं है या वहां पर नर्स की या कम्पाउण्डर की उतनी उपस्थिति नहीं है। लोग इन्तजार करते हैं कि हमें 24 घंटे चिकित्सा सुविधा मिले और सरकार भी दावा करती है कि हम 24 x 7 ये सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। सामान्य तौर पर पीएचसी पर वहां की जनता उम्मीद करती है कि हमें 24 घंटे, रात में यदि इमर्जेंसी डिलीवरी की जरूरत पड़ गई तो हमें वहां एक डाक्टर उपलब्ध हो जाए। मुझे लगता है कि पीएचसी पर दो डाक्टर्स की नियुक्ति जरूरी है। जितने सब सेंटर्स हैं उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह राजधानी के बिलकुल निकट का क्षेत्र है, जयपुर से भी पुराना कस्बा है। वहां केवल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, एक हजार के लगभग आउटडोर है, बहुत सारे संस्थान और बड़ी आबादी, खास तौर से पेशे से किसान और मजदूर हैं लेकिन बला टालने के लिए चिकित्सक सीधे-सीधे उनको एसएमएस में रैफर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं कि एसएमएस का प्रेशर कम करें, मेरा सुझाव है कि आमेर की उस सीएचसी को या तो जिला या रैफरल अस्पताल में तब्दील करेंगे, वहां की कुछ सुविधाओं को दुरुस्त करेंगे और ऐसी बानगी सब जगह मिलेगी इस तरीके का अस्पताल जिनको क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है तो मुझे लगता है कि किया जाना चाहिए।

सोनोग्राफी मशीन की मांग आमेर की सीएचसी में हम बहुत समय से करते रहे हैं लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन मंत्री, माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर के जालसू में साढ़े पांच करोड़ की सीएचसी, जिसका नया भवन बनकर तैयार हुए छह महीने हो गए, मैंने

(श्री सतीश पूनियां)

मंत्रीजी से गुजारिश की है कि जल्दी से जल्दी उसका फीता काटे जिससे कम से कम वहां के सौ गांवों को लाभ मिले। वहां एक ब्लड बैंक की भी आवश्यकता है। गुढ़ा सूरजा और जाहोता, बड़े गांव हैं जिनमें मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में डिलीवरी की एक बड़ी फ्रिक्वेंसी है।

माननीय सभापति महोदय, दिल्ली और सीकर रोड, दो बड़े नेशनल हाईवे से गुजरता हुआ यह क्षेत्र और ट्रोमा सेंटर की लगभग सभी सदस्यों ने मांग की है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से दुर्घटनाओं का अम्बार है और उस अम्बार के नाते जिस तरीके की तात्कालिक चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है वह निश्चित रूप से पूरी की जानी चाहिए। रामपुरा डाबड़ी और चन्दवाजी, दो बड़े केन्द्र हैं जहां ट्रोमा सेंटर की जरूरत है। अचरोल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है। मुझे लगता है कि वहां की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करेंगे तो एक बड़े तबके को वहां राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के जो सुधार हुए, उसमें 108 की व्यवस्था ने काफी कुछ लोगों को राहत जरूर पहुंचाई है। मेरे यहां मानपुरा में 108 की व्यवस्था ठीक कराई जाए। 14 पीएचसी हैं मेरे यहां। इनमें 2 पीएचसी, रायथल और कुनाना, उनके नए भवन के निर्माण के लिए मैं आग्रह करूंगा। यहां पर सदस्य वाकिफ होंगे कि दिल्ली रोड से गुजरते हैं तो कूकस एक बड़ा कस्बा आता है, जिसमें पांच विश्वविद्यालय हैं, पन्द्रह फाइव स्टार होटल हैं, बहुत सारे अन्य संस्थान हैं, वहां पर केवल सब सेंटर है, मैं मंत्रीजी से गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि कूकस और पीली की तलाई, यहां पर दो शहरी पीएचसी का हमें लाभ दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, तीन ज्ञापन जो मुझे मिले हैं, होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में आप सब लोगों ने भी कहा कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति यह भी रोगियों के दबाव को कम कर सकती है जिस पर लोग भरोसा करते हैं तो होम्योपैथी को निश्चित रूप से मान मिलना चाहिए।

यह पहली सरकार है और पहला बजट है जिसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को जगह नहीं मिली है। दुनिया तो योग को पूजती है और आयुर्वेद के लिए मुझे लगता है कि दुनिया के बहुत से देश भरोसा करते हैं। आयुर्वेद का भी विकास किया जाना चाहिए।

एक बहुत बड़ा तबका ग्रामीण विद्यार्थियों का, जिनका एमबीबीएस में

(श्री सतीश पूनियां)

नीट के द्वारा सलैक्शन होता है, जो शहर के विद्यार्थी हैं और बैंक गारंटी देते हैं वह प्लाट के आधार पर बैंक गारंटी मिल जाती है लेकिन ग्रामीण विद्यार्थियों को, जो प्राइवेट कालेज हैं, वह परमिट नहीं करते हैं और एक बड़ी आबादी है तो मैं माननीय मंत्रीजी से निश्चित रूप से गुजारिश करूंगा कि उनको निश्चित रूप से छूट मिले ताकि इनको दो साल के लिए अग्रिम जमा करवाते हैं बहुत बड़ी पूंजी प्राइवेट मेडिकल कालेज, उससे इन विद्यार्थियों को निश्चित रूप से निजात दिलाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको फिर से धन्यवाद देते हुए गुजारिश करूंगा कि निश्चित रूप से इस मांग में सफाई का जिक्र है और महात्मा गांधीजी कहते थे कि स्वच्छता ही देश भक्ति है। आप और हम सब गांधीजी के अनुयायी हैं, गांधीजी ने जो बात कही उस बात को देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदीजी ने यह कल्पना से परे बात थी कि देश का प्रधान मंत्री सफाई की बात करे और इतना बड़ा व्यापक अभियान बना, मुझे लगता है कि बीमारियों से बचने के लिए सफाई एक बड़ा अस्त्र है उसको इस्तेमाल किया जाए। योग को एक तरीके का प्रोत्साहन दिया जाए, आयुर्वेद को अपनाया जाए तो मुझे लगता है कि सर्वे संतु निरामया की कल्पना करते हैं, वह साकार हो सकती है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मेरा माननीय सभी सदस्यों से आग्रह है कि करीब 28 स्पीकर्स हैं हाउस में तो मिनिमम फाइव मिनट्स, बिटविन फाइव टू सैवन मिनट्स लेने का कष्ट करें ताकि तीन घंटे में समाप्त कर सकें। माननीय लाखन सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, एक इधर से एक उधर से माननीय सदस्य हो जाए। यह तो न्याय करो आप। दो-दो, तीन-तीन उधर से बुलाते हो फिर आपको हमारी याद आती है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, बीच वालों का भी ध्यान रखें।

श्री सभापति: माननीय लाखन सिंह। (व्यवधान) मैं सुनूंगा आपको धैर्यपूर्वक।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा भाषण टेबल करना चाहता हूं, आप मेरा नाम पुकारो। (व्यवधान) नाम तो पुकारो। टेबल कर देता हूं।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, मुझे राजस्थान की इस विधान सभा में मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का अवसर आपने दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि करौली जिला हैडक्वाटर पर एकमात्र सरकारी अस्पताल है, जिसमें डाक्टरों की बहुत कमी है। करौली जिला हैडक्वार्टर पर कोई भी प्राइवेट हास्पिटल नहीं है इसलिए सभी शहर एवं ग्रामीण लोग इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। करौली अस्पताल में केवल करौली जिला ही नहीं इसमें दूरदराज एवं दूसरे जिले जैसे धौलपुर जिले से सरमथुरा एवं बाड़ी एवं बसेड़ी क्षेत्र से इसी अस्पताल में दिखाने के लिए आते हैं। इस अस्पताल में करणपुर, मंडरायल, मासलपुर, सपोटरा एवं चम्बल पार से मध्य प्रदेश से मरीज भी करौली अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, सामान्य चिकित्सालय, करौली में चिकित्सकों के वर्तमान में 64 पद स्वीकृत हैं जिनमें 44 पद भरे हुए हैं, 20 पद रिक्त हैं। एनेस्थीसिया चिकित्सक के दो पद स्वीकृत हैं जिनमें 1 पद रिक्त है। वर्तमान में दोनों चिकित्सालयों में होने वाले आपरेशनों में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होता है। अत: एनेस्थीसिया चिकित्सक लगवाने का श्रम करें। एमसीएच चिकित्सालय मंडरायल रोड, करौली में पाँच चिकित्सक स्त्री रोग विशेषज्ञ लगवाने का श्रम करें। वर्तमान में चार स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं। जिले में कुल 34 पीएचसी एवं सीएचसी संचालित हैं, जिनमें भी स्टाफ की कमी है। इस पर पर्याप्त स्टाफ लगाया जाए।

इस अस्पताल परिसर एमसीएच में पानी की सप्लाई के लिये एक वर्ष पूर्व टैंडर हो चुका है, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीएचईडी की ओर से भी समुचित पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। पानी के अभाव में चिकित्सालय चलाना दुर्लभ है। नवीन भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए, जिससे दोनों ही अस्पताल एक ही परिसर में संचालित किये जा सकें। नवीन चिकित्सालय, मंडरायल रोड, करौली की सड़क शिकारगंज से लेकर अस्पताल तक पूर्णत: जर्जर अवस्था में है। प्रसव हेतु आने वाली महिलाओं को अनावश्यक परेशानी होती है। इस सड़क को भी तुरन्त बनवाया जाए। चिकित्सालय को 300 बैड में क्रमोन्नत किया जाए। वर्तमान में 225 बैड

(श्री लाखन सिंह)

चिकित्सालय में स्वीकृत हैं। चिकित्सालय में पानी, बिजली, वाहन मरम्मत आदि मदों में बजट उपलब्ध नहीं है। अत: उक्त मदों में बजट आबंटन कराने का श्रम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस अस्पताल में डाक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ के सभी पद भरे जाएं एवं कुछ दिन पूर्व हमारे यहां से कुछ अच्छे डाक्टरों का स्थानांतरण कर दिया गया। उन डाक्टरों को भी पुन: जिला अस्पताल में पदस्थापित करें, जिससे हमारे डांग क्षेत्र के गरीब पिछड़े किसान, मजदूर एवं शहरी लोगों को इलाज की सुविधा मिल सके। नवीन चिकित्सालय में पिछले कुछ दिनों से किसी भी प्रकार के आपातकालीन आपरेशन नहीं हो रहे हैं, जिन्हें तुरन्त चालू करवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, करौली जिले में पत्थर खनन मजदूरों की प्रमुख रोजी-रोटी का जरिया है, जिससे इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में सिलिकोसिस, टयूबरकुलोसिस रोग से लोग पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में निकट भविष्य में राज्य सरकार की ओर से यहां पर मेडिकल कालेज की स्वीकृति मिल जाए, यह मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं। पूर्वी राजस्थान के पिछड़े हुए क्षेत्र के लिये गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं आसानी से मिल सकें, इसके लिये जिलावासियों को समुचित सेवा मिल सके, अत: यहां पर मेडिकल कालेज खुलना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मासलपुर में डाक्टरों के सात पद स्वीकृत हैं, लेकिन कई सालों से चार डाक्टरों के भरोसे चल रहा है। ऐसे ही नर्सिंग स्टाफ के चार पद स्वीकृत हैं, लेकिन उनमें एक भी रेगुलर नर्सिंग नहीं है। एक नर्सिंग स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है, इसलिये मान्यवर से निवेदन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मासलपुर में अतिशीघ्र डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ के पदों को भरा जाए। इसके अलावा इस अस्पताल में एक्स-रे मशीन, आपातकालीन ट्राली, आक्सीजन सिलेंडर आदि की व्यवस्था की जाए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो अंतिम छोर पर बैठे गरीब किसान, मजदूर, जिनके पास अस्पताल जाने के किराये के लिये भी पैसा नहीं है, मैं बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि

(श्री लाखन सिंह)

इन्होंने जो जनता क्लिनिक योजना गांव और गली-मोहल्लों में चलायी है, यह बिलकुल अंतिम छोर के गरीब के लिये फायदे की चीज है कि उन्हें वहां दवा मिल सकती है और वे दवा लेकर चलने लायक हो जाएगा तो अस्पताल भी पहुंच जाएगा। हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो कई गांवों में ऐसी स्थिति है कि उनके पास सौ रुपये भी नहीं है कि एक गोली लेकर वे अस्पताल जा सकते हों, इसलिये मैं इस जनता क्लिनिक योजना के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बारम्बार धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय भीम।

श्री सभापति: माननीय श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। पहला सुख नीरोगी काया, Health is wealth. माननीय सदस्या कल्पना जी ने इसे और करेक्ट कर दिया, Good health is wealth.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दूसरे सुख के बारे में भी बता दें, पहला सुख नीरोगी काया, दूजा सुख घर में माया।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, डाक्टर्स हमारे प्रदेश में हैं नहीं और डाक्टर्स को कैसे और बढ़ाया जाए। मेडिकल कालेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर जो कक्षाएं हैं, उनके अंदर सीटें बढ़ाये बिना डाक्टर्स नहीं बढ़ सकते हैं। डाक्टर्स नहीं बढ़ेंगे तो इस प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, यह मेरा पक्का मानना है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दवा बढ़ाने की बात तो कर दी, लेकिन डाक्टर्स नहीं है, इस दवा को लिखेगा कौन? बजट में अभी जनता क्लिनिक की बात आयी थी, जनता क्लिनिक के साथ एक राइडर लगा दिया और उसमें लिख दिया कि दानदाताओं और समाजसेवियों के द्वारा यदि भवन उपलब्ध करवाया जाएगा तो जनता क्लिनिक उन भवनों में चलेंगे। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, यदि भवन नहीं होंगे तो जनता क्लिनिक चलेंगे नहीं, यही तो मंशा है।

ट्रोमा सेंटर्स की बात भी की कि और नये ट्रोमा सेंटर्स खोले जाएंगे। मैं भी मांग कर रहा हूं और आपका पुराना साथी रहा हूं। आपने अपने हस्ताक्षर से इस राजनीति में भर्ती किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। आपने यह भी सिखाया था कि किसी बात को मजबूती से कहना और उसी के ऊपर काम

(श्री अभिनेश महर्षि)

करना। कल-परसों ही कह रहे थे कि पढ़कर भी हमें बात करनी होती है। मैंने पूरा बजट पढ़ा। आपके द्वारा कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा-पत्र है, उसे भी पूरा का पूरा मैंने पढ़ लिया और उसके बाद मैंने जब उसे पूरे से थोड़ा कम पढ़ा तो मैंने उसे बंद कर दिया, इसलिये कि उसके अंदर रघु जी के खिलाफ बोलने की बहुत सारी बातें मुझे मिल गयीं। मैं आपके खिलाफ कोई भी बात बोलना नहीं चाहता था। रघु जी के खिलाफ नहीं, बल्कि चिकित्सा मंत्री और राजस्थान की सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें बोलने को मिल गयीं।

ट्रोमा सेंटर की बात हुई। मेरे यहां रतनगढ़ में ट्रोमा सेंटर खोला था, वह बंद हो गया। वहां डाक्टर्स नहीं हैं। वहां का पीएमओ उस ट्रोमा सेंटर को बंद करके और किसी काम में ले रहा है। ये हालात रतनगढ़ के अंदर हैं। आपने देखा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ बैठे हैं, मेरे यहां के सांसद भाई राहुल कस्वां जी, मैं और खेमाराम जी, पिछले दिनों हम सब बीदासर गये थे। वहां इतनी गम्भीर समस्या हो गयी, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन खराब हो गयी और खराब क्यों हो गयी, क्योंकि वहां पर चिकित्सक नहीं हैं। एक लड़का महीनों से वहां पर धरना देकर बैठा हुआ है। क्या हठधर्मिता थी ऐसी कि बीदासर में चिकित्सक नहीं लगेंगे? उसके बाद छापर में धरना लग गया, उसके बाद में राजलदेसर में धरना लग गया। डाक्टर्स का अभाव है। मैं समझता हूं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है डाक्टर्स का, वह इस तरह का किया जाना जरूरी है, जिससे सब जगहों पर डाक्टर्स मिल सकें। रतनगढ़ अस्पताल, जहां कभी हरियाणा से पेशेंट आते थे, जहां पंजाब से पेशेंट आते थे, सुदूर इलाकों से पेशेंट आते थे, उस जालान अस्पताल में डाक्टर्स के अभाव में जो बहुत शानदार आपरेशन थिएटर था, वह बंद हो गया।

वहां पर लगी हुई मशींस जंग खा गयीं, क्योंकि वहां एनेस्थेसिस्ट नहीं हैं, वहां डिलीवरी कराने के लिये गायनीकोलोजिस्ट नहीं है। उस स्थिति में जो मेरा रतनगढ़ नेशनल हाई-वे और मेगा हाई-वे का जंक्शन पाइंट है, उसके ऊपर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि उस ट्रोमा सेंटर में डाक्टर्स की नियुक्ति करवाकर इस आपरेशन थिएटर को शीघ्रता से चालू करवा दें।

(श्री अभिनेश महर्षि)

मुझे पता है आपकी काबिलियत का, आप निश्चित रूप से यह करा देंगे। माननीय, जो बीदासर की घटना की मैं बात कर रहा था, वह घटना बहुत महत्त्वपूर्ण इसलिये हो गयी, क्योंकि जब हम गये तो लोग इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने पथराव किया, मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी, मेरा पीए घायल हो गया, उसके सात टांके आये और उसके बाद में लोगों ने यह कहा कि ऐसी सरकार जो लोगों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित नहीं है, आप उसके लिये बीच में मत आइए।

(19.00 बजे)

पीएचसी खाली पड़ी है, सीएचसी खाली पड़ी है, सिटी अस्पताल, उप केन्द्र सहित चिकित्साकर्मियों के अनेक पद खाली पड़े हुए हैं। अब बजट के अन्दर सरकार ने घोषणा की 15 हजार चिकित्साकर्मियों को भर्ती किया जाएगा लेकिन, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, उसके अन्दर यह बताना भूल गये कि उसके अन्दर कितने डाक्टर होंगे, कितने दूसरे चिकित्साकर्मी होंगे, नर्सिंग कितने होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ कितना होगा। यह भी यदि आप लोग बता देते तो निश्चित रूप से ठीक हो जाता।

माननीय सभापति महोदय, आपके जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 5 में- राजकीय अस्पतालों को 24X7 अर्थात् 24 घंटे सातों दिन प्रसूती की सेवाएं प्रदान करने के लिए डिलीवरी पाइंट विकसित कर आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की भी बात की थी। लेकिन घोषणा जो बजट के अन्दर की है उसके अन्दर जो उपलब्ध उपकरण पहले से हैं वो जंग खा रहे हैं और नये उपकरणों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा लगेगा यदि वो पुराने उपकरण भी ठीक हो जाएं तो निश्चित रूप से सरकार का खर्चा भी बच जाएगा।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आयुर्वेद के बारे में, होम्योपैथी, योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सबके बारे में बात की। मुझे ऐसा लगता है और लगता ही नहीं है यह बजट देखने के बाद में पक्का भरोसा हो गया है कि जिस तरह से इनके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया उससे ऐसा लगता है कि आपने यह सोच लिया कि ये सारी की सारी पद्धतियां तो भारतीय जनता पार्टी की पद्धतियां हैं। ये इसी देश की पद्धतियां हैं जिनके ऊपर विश्व में भरोसा किया गया है इसलिए इनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

आपने सीटी स्कैन, एमआरआई की नि:शुल्क जांच की घोषणा की उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं माननीय मंत्री महोदय। लेकिन इनको कराएगा कौन? रेडियोलोजिस्ट तो हैं ही नहीं, डाक्टर्स हैं नहीं, रेडियोलोजी वाले डाक्टर्स नहीं है। आपके घोषणा पत्र के बिन्दु 18 में मल्टीपल आर्गन ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट की स्थापना के बारे में कहा था लेकिन बजट में वह गायब हो गया।

माननीय सभापति महोदय, एसएमएस अस्पताल की बात आपने भी की जहां से आपने एमबीबीएस भी किया है। एसएमएस अस्पताल जब तक रैफरल अस्पताल नहीं बनेगा, नीचे से कोई भी जो रैफर होकर केसेज आएंगे, जो गम्भीर बीमारियां हैं उनका इलाज होने के लिए जब तक एसएमएस आइडेंटिफाइड नहीं होगा तब तक इसका भार कम नहीं होगा। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, इसका भार कम करने के लिए मैं एक सुझाव और देता हूं कि जयपुर की इतनी बड़ी आबादी हो गई इसलिए आप चारों कोनों में 3 से 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना दीजिये और वहां पर जाएं। अभी कई माननीय सदस्यों ने भी इस बात की डिमाण्ड की है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि एसएमएस हास्पिटल का भार कम करना है तो निश्चित रूप से कम से कम चार डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल और बनने चाहिए और वो कम से कम 100 से 150 बैड के हास्पिटल होने चाहिए जिससे मरीजों की संख्या वहां पर जाए तो यहां कुछ भार कम हो जाए।

अब मेडिकल टीचर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस की बात। मेडिकल टीचर्स, जिनकी टीचिंग का काम करने के लिए नियुक्ति होती है। मेरी मान्यता यह है कि यदि उन टीचर्स को सिर्फ शिक्षा के काम में लगा दिया जाए, उनको एनपीए दो और बड़ा अच्छा एनपीए दो, नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता उनको दे दो। अब वो पूरे दिन तो घर पर रहते हैं, आते नहीं हैं और नहीं आने का कारण यह देखिये- 'स्ट्रैस के कारण डाक्टर की मौत', एक मां ने अपनी लाडली बेटी को खो दिया। एक ने नहीं खो दिया, अनेकों ने खोया है और आगे भी यदि यही हालात रहे तो खोएंगी और यह सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैस का कारण है। इस अख़बार के अन्दर भी लिख रखा है कि रेजिडेंट डाक्टर्स के ऊपर 24 घंटे काम करने का दबाव रहता है, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसियेट प्रोफेसर्स आते नहीं हैं और उनको लगातार राउण्ड द क्लाक काम करना पड़ता है लिहाजा वो अवसाद के अन्दर आते हैं और जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो देश के

(श्री अभिनेश महर्षि)

होनहार डाक्टर्स हैं वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह इतनी बड़ी गम्भीर समस्या है जिसका ध्यान सरकार की तरफ आकर्षित करने की आज आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, कई डाक्टर्स ने इस घटना के ऊपर लिखा है कि प्रशासनिक नकारापन। शब्द हल्का हो सकता है लेकिन सत्यता जरूर है महोदय।

समाज के लिए नासूर बनता जा रहा पान मसाला, गुटका, इसके ऊपर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगना चाहिए यदि हमें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है तो और इसके ऊपर सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट के अन्दर घोषणा की थी कि छाबड़ा जी के नाम पर उन्होंने एक कालेज कर दिया। मुझे खुशी होती यदि राजस्थान की वर्तमान सरकार छाबड़ा जी के बारे में इतनी चिंतित थी तो पूर्ण शराबबन्दी कर देती, उस आत्मा को शांति मिल जाती। आदरणीय रघु शर्मा साहब, लिवर वाला जो डिपार्टमेंट है उसका तो भार कम हो जाता यदि आपने पूर्ण शराबबन्दी की घोषणा करते। यह समाज के लिए नासूर है जिसको ठीक होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या और है। एक सफेद पुडिया के नाम से बाजार के अन्दर एक ऐसा मादक पदार्थ बेचा जाता है जिसका कई लोगों को ध्यान है, मैं जानता हूं कि पुलिस को भी इस बारे में ध्यान है लेकिन सबकी बंधियां फिक्स है। कोई काम नहीं कर रहा है और वह हमारे नौजवानों को मौत के मुंह के अन्दर वह सफेद पुड़ियाएं ले जा रही हैं इसलिए इसके ऊपर भी प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है।

दोनों चिकित्सा मंत्री महोदय बातों में मशगूल हैं। एक सदस्य अपनी बात को कह रहा है लेकिन, माननीय कालीचरण जी भाईसाहब,.....

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपका छोटा भाई हूं बहुत गम्भीरता से, मेरे दिल से बातें कह रहा हूं, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बातें कर रहा हूं। लोगों के बारे में इस सदन में हम बैठकर चिन्ता कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि गम्भीरता से मेरी बात को सुना जाए।

मिलावटी मावा, अन्य मिलावटी पदार्थ, घी, मसाले, ये भी सारे के सारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनके ऊपर भी रोक लगाने की आवश्यकता है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

सभापति महोदय, सीटी स्कैन, एमआरआई के अन्दर 4-4, 5-5 दिन से लोगों का नम्बर आता है। क्या इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी व्यवस्था, उसके अन्दर और सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें नहीं लगें, प्राइवेट हाथों में जो दे रखा है उनके ऊपर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। वे जिसकी मर्जी होती है उसकी पहले करते हैं नहीं तो लोगों को 4-4, 5-5 दिन तक वहां पर धक्के खाने पड़ते हैं।

एक और गम्भीर समस्या है। जितनी भी प्राइवेट कालेजेज हैं, मेडिकल कालेजेज हैं उनके अन्दर जो फीस है वह बड़ी गम्भीर अनियमितता है। एक कालेज के अन्दर तो 12 लाख रुपये की फीस है और एक के अन्दर 15 लाख की है, एक के अन्दर 17 लाख की है, एक के अन्दर 19 की है, 20 लाख, 22 लाख रुपये तक की फीस है। यह जो गम्भीर विषय है इसके ऊपर माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश के अन्दर फीस का समान ढांचा है वैसे फीस का समान ढांचा कर देना चाहिए जिससे किसी विद्यार्थी के ऊपर इस तरह का भार नहीं आये और मन में यह नहीं हो कि इसमें तो फीस कम थी, इसमें ज्यादा थी।

मैं बहुत अधिक लम्बा समय नहीं लूंगा लेकिन मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में न्यामा, मालासी, बिरमसर, जेगणिया बिदावतान में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मैं मांग करता हूं। चक राजियासर में पीएचसी बनकर तैयार है, उस पीएचसी के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी उद्घाटन करने के लिए पधारो म्हारे देश चिकित्सा मंत्री महोदय जिससे वहां पर लोगों को सुविधा मिल सके और आने वाले समय के अन्दर रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बराबर, कुसुमदेसर, जोगलिया, डडेरू, लाछासर, चाड़वास सहित अन्य अस्पतालों में और बाकी विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण अस्पतालों के अन्दर जो खाली पद पड़े हैं उनको भरने के लिए भी मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से इनको भरने से तुरन्त राहत मिलेगी।

'अ' श्रेणी का आयुर्वेद चिकित्सालय मेरे रतनगढ़ में भी एक है। उसके अन्दर भी सब पद खाली पड़े हैं और वह भी बन्द होने के कगार पर है। उसके अन्दर भी यदि वैद्य लगा दिये जाएं तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। छापर के अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की भी मैं आपसे मांग करता हूं।

(श्री अभिनेश महर्षि)

एक और मांग है कि फतेहपुर से सालासर के बीच वाला नेशनल हाईवे जो मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजरता है वहां पर एक स्यानण डूंगरी माता जी का मन्दिर है, माताजी आपको आशीर्वाद देगी वहां पर एक ट्रोमा सेंटर खोल दो। वहां पर एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट प्रोन एरिया होने के कारण वहां पर एक ट्रोमा सेंटर की भी मैं मांग करता हूं।

आदरणीय रघु शर्मा साहब, आपसे तो अभी बानसूर से आने वाली हमारी माननीय सदस्य कह रही थीं कि यह भेदभाव होता है बीजेपी कांग्रेस, मुझे पक्का विश्वास है रघु शर्मा साहब कि आप यह भेदभाव कम से कम मेरे साथ तो नहीं करेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री महेन्द्र विश्नोई।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): सभापति महोदय, आज आपने मुझे चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की मांग पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं लूणी विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे से पहले मेरे दादा और मेरे पिता दोनों ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और उनके साथ रहे काफी माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद हैं, मैं इन सभी को प्रणाम करता हूं।

मुख्य मंत्री जी ने चिकित्सा बजट के अंदर, जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है। इसके लिए दवाई फ्री की है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। कैंसर का रोगी दु:ख झेलता है पर उसके साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। उसको देखते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने जो दवाई फ्री की है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्य मंत्री दवा और जांच, जो इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में फ्री की थी, उससे काफी लोगों को फायदा हुआ था। इसको दूसरे राज्यों ने काफी सराहा और अपने यहां काम किया, जिसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं।

जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। उसके अन्दर चारों तरफ जो लूणी का क्षेत्र लगता है। मैं मांग करूंगा कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर भी छोटे-छोटे जनता क्लिनिक खोले जाएं। जहां से मैं आता हूं, वहां पर जोजरी नदी बहती है। जब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं सभी, तो जोजरी नदी में सीवरेज का पानी, औद्योगिक इकाइयों का पानी उसी के अंदर छोड़ा जाता है

(श्री महेन्द्र बिश्नोई)

और वह नदी पूरे लूणी में बहती है। उसके अंदर मच्छर, कीट-पतंगे और काफी जीव-जन्तु पनपते हैं और इससे आस-पास के गांवों के अंदर मच्छर चले जाते हैं और जब मैंने बात की, सीएमएचओ ने कहा, हमारे पास फोगिंग का बजट नहीं है इसलिए मैं मांग करूंगा कि हमारे लूणी क्षेत्र के अंदर जो आसपास के गांव हैं, उनके अंदर फोगिंग और दवाई का एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए।

मेरे विधान सभा के अंदर भैरू हास्पिटल है, जो पीपीपी मोड पर पिछली सरकार ने दिया था। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। उसके अंदर न डाक्टर, न एएनएम, जीएनएम किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। उनको सरकार की तरफ से सालाना 35 लाख रुपये दिया जाता है। मेरी जानकारी में है 35 लाख रुपये सालाना दिया जाता है और वहां पर एक पैसे की सुविधा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसका टेण्डर निरस्त कर, वापस सरकार अपने पास लें, जिससे सरकारी योजनाओं का मेरे क्षेत्रवासियों को लाभ मिल पाए।

मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अंदर दो ब्लाक हैं, मण्डोर ब्लाक और लूणी ब्लाक। लूणी ब्लाक के अंदर ही करीब 11 डाक्टरों के पद रिक्त हैं। हमेशा मेरी मांग पहले से ही रही है, जब मैं विधान सभा का सदस्य नहीं था, तब भी मेरी मांग रही थी। मेरे एरिये में रेडियोग्राफर की, धुंधाला के अंदर, सालावास के अंदर, लूणी के अंदर, यहां रेडियोग्राफर की बहुत कमी है। रेडियोग्राफर की आज मैं फिर मांग करता हूं क्योंकि पिछली बार हमने राज्य सभा मैम्बर से पैसे लेकर वहां पर मशीनें तो सारी लगा दीं, पर पिछले पांच साल से रेडियोग्राफर वहां नहीं मिल पा रहा है तो मेरी मांग रहेगी माननीय चिकित्सा मंत्री जी से क्योंकि मैंने पिछली बार भी मांग थी, वहां से विधायक महोदय करा नहीं पाए थे। मैं इस बार मांग करता हूं कि आप मेरी ये मांग पूरी करेंगे।

हमारे यहां जो 108 एम्बुलेंस है, उसका कोई रख-रखाव नहीं है, उसके अंदर न तो आक्सीजन की व्यवस्था है, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है, गाड़ियां खराब हैं। या तो नये एक्यूपमेंट वाली गाड़ियां लेकर आएं और उनको दे, काफी जगह से हटा भी दी गई हैं। जैसे खेजड़ली जिसकी सभी बात कर रहे थे आप लोग कल जब पर्यावरण की बात चल रही थी, खेजड़ली के अंदर 108 हुआ करती थी वो पिछली सरकार की वजह से हटा दी गई। मेरा निवेदन

(श्री महेन्द्र बिश्नोई)

रहेगा मेरे क्षेत्र के अंदर से जो एम्बुलेंस हटाई गई वह वापस दी जाए। आपने मुझे चिकित्सा पर बोलने का मौका दिया, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती इन्दिरा देवी।

श्री इन्दिरा देवी (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मेड़ता क्षेत्र में सरकारी हास्पिटल है। उसके अंदर सुविधा नहीं है और गांव के लोग आते हैं मरीज को लेकर, उनको बोल दिया जाता है, यहां डाक्टर नहीं, डाक्टरनी नहीं है इसलिए उनको रैफर कर देते हैं तो फिर अजमेर ले जाते हैं, सौ-सौ किलोमीटर की दूरी पर डाक्टर नहीं है, हास्पिटल नहीं है इसलिए अजमेर ले जाते हैं और बीच में वो खतम हो जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि हमारे मेड़ता क्षेत्र में 100 बैड का हास्पिटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आपके आसन पर विराजने के बाद पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला है, आपको बहुत-बहुत बधाई। वैसे सभी जानते हैं कि आप एक दयालु प्रवृत्ति के महान पुरुष हैं और काफी साथियों की शिकायत है कि मेहरबानी करके आप धीरे बोलें, इसलिए मैं बहुत धीरे ही बोलूंगा और बातें काफी हुई। करीब-करीब बात सब हो गई और सभी ने कहा पहला सुख नीरोगी काया और आज यह कलियुग है और उलटा लग रहा है कि लोगों ने जो दो नम्बर पर था कि दूसरा सुख घर में माया, उस दूसरे नम्बर को लोगों ने पहले अपना लिया और पहले वाले को भले ही सातवें नम्बर पर डाल दिया है।

मांग संख्या 26 पर बहुत बड़ा गम्भीर मुद्दा और सभी बातें कह रहे थे और हम सब साथ हैं। हमारी सबकी भावना है, बीमारी मुक्त राजस्थान हो। किसी परिवार में भगवान करें बीमारी नहीं आए, सभी सुखी रहें और एक बात आ रही थी। माननीय सभापति महोदय, आज इस गम्भीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए परन्तु लगभग हमारे कहावत है, राजनीति की सभी ने करीब-करीब, लेकिन कहते हैं कि इस गम्भीर मुद्दे पर राजनीति, इस बारे में हमारे मारवाड़ में कहावत है कि 'काका तू है काली रोड रो, पण कहूं कोनी' मतलब आप हो ऐसे, लेकिन मैं कहूं नहीं।

(श्री मदन प्रजापत)

अब माननीय सभापति महोदय, हम साथ हैं, एक बीमारी आए और इनका इलाज हो और मेरा मानना है कि बीमारी आए ही नहीं, हम सभी का मिलकर दायित्व करोड़ों जनता अपने ऊपर उम्मीद लगाई बैठी है और माननीय मंत्रीजी जो चिकित्सा मंत्री हैं, बहुत मजबूत मंत्री हैं और सेवाभावी हैं और हम सभी मिलकर ऐसा प्रयास करें जो बीमारी आए और उनका इलाज हो और हम चाहते हैं कि बीमारी आए नहीं, लेकिन आज पैसों की लालसा ने और आधुनिक दौड़ में शारीरिक, दिमागी टेंशन है और ये मेरा मानना है कि पैसों की जगह अगर पुराना सिस्टम वस्तु आदान-प्रदान अधिनियम हो जाए, तो ये बीमारियां आधी कम हो जाएं। जहां सफाई होगी वहां बीमारी कम आएगी।

एक बात गांधी जी की याद आती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्होंने भी सफाई पर जोर दिया था कि अगर गंदगी करने वाला गंदा नहीं होता तो गंदगी को साफ करने वाला कभी गंदा नहीं हो सकता। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा और सफाई के अलावा मिलावट, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं, हाथ खड़ा करवा दें, ऐसा कौन बाप है जो अपने बेटे को मिलावटी आइटम खिलाना चाहता है। पूरी दुनिया में एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा, ऐसा कोई बाप हमको नहीं मिलेगा, जो अपने बेटे को मिलावटी खाना। अगर एक बात ये पूछी जाए कि एक का दस हो जाएगा, डबल-तिबल, सौ गुना, पांच गुना मुनाफा होगा और एक मिलावटी फैक्ट्री लगाने के लिए कौन-कौन तैयार है, तो इस कलियुग में मामूली परसेंट हाथ है, जो खड़े नहीं होंगे, बाकि डबल-तिबल में सब खड़े कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज मिलावट के ऊपर बहुत बड़ी गम्भीर बात है और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं जिलेवाइज अभियान चलाएं, भले ही मंत्री जी का रिश्तेदार हो, चाहे मेरा भाई हो, इससे समझौता नहीं हो, ये इलाज कर रहे, दवाइयां कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आज बीमारी का कारण सफाई के बाद में प्रदूषण के बाद में कोई मुद्दा है तो यह मिलावटी जहर खिला रहे हैं और आज हमारे एक साथी कह रहे थे कि सरस दूध के ऊपर भी डाउट होता, तो माफ करना माननीय किसके ऊपर भरोसा करेंगे, किसके ऊपर विश्वास करेंगे। हम पेट में जहर डाल रहे हैं और लालसा के कारण और बाद में उम्मीद भी करते हैं कि अपनी 100 साल से ऊपर उम्र हो तो यह उम्मीद करना भी बेकार है। माननीय सभापति महोदय, कई बातें हैं मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहना चाहता हूं कि एक समय था और

(श्री मदन प्रजापत)

मारवाड़ी में कहावत थी कि ‘दूध बेचना तो पूत बेचना’। दूध के पैसे नहीं लेते थे और आज यह जमाना आ गया कि पानी बेचना अलग बात है पानी में मिलावट। रेत में मिलावट तो सोने-चांदी में तो होगी ही वह तो परम्परा है लेकिन पानी में मिलावट एक खारा और एक मीठा और रेत में मिलावट। आज माननीय सभापति महोदय, जो गोबर खाद है उसमें भी लोग रेत डालकर मिलावट कर रहे हैं तो इस कलियुग में क्या उम्मीद करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं मंत्री जी थोड़ा मेहरबानी करें, शायद वर्तमान और पूर्व दोनों मंत्रियों का ध्यान कहीं और है, शायद कहीं मंथन चल रहा है राजस्थान के बारे में। इस मिलावट के ऊपर अभियान चलाएं। अपने को यह काम करना पड़ेगा तो आधी बीमारी अपने-आप खतम हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, करोड़ों रुपये देकर डाक्टर बनते हैं तो अपन क्या उम्मीद करते हैं और बाकी मैं इस बात का मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुतबड़ा आपने काम किया है, कल जो भाई खुशवीर सिंह जी कह रहे थे कि यह जो नौकरशाही हावी है, अपन सभी दिल से मेहनत करें तो यह बात जो आपने की है इस बात में वज़न कम होगा और कभी भी इस लोकतंत्र में नौकरशाही हावी नहीं हो सकती। आपने इतने बड़े भैंसे का इलाज कर दिया तो माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं 6 महीने से घूम रहा हूं कि बाड़मेर का पुराना सीएमएचओ है, अपने राज में लोगों में यह संदेश जा रहा है कि आप कह रहे हो कि अब राज चैंज हुआ है लेकिन दुकानें तो वो की वो शुरू हैं। किसका दबाव है कि उसको अपने को रखना जरूरी है? मेरे यहां यह कोई जरूरी नहीं है कि किसको लगाना है लेकिन मेहरबानी करके हफ्ते भर में ऐसे भ्रष्ट लोगों का इलाज नहीं किया तो आज लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी, एक ईमानदार मुख्य मंत्री जी और आज अपनी सरकार की जो छवि है वह जनता में गलत संदेश जाता है। अगर किसी का दबाव है तो वो चाहे लगा लो, लेकिन नहीं रहना है, नहीं रहना है। मेहरबानी करके मैं बार-बार कहूं अच्छा नहीं लगता और आपको धन्यवाद देता हूं मंत्री जी, जब जसोल की घटना घटी माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी आये, आप भी आये और माननीय कल्ला साहब भी थे और आपने राजकीय नाहटा अस्पताल जो जिले का सैकंड मुख्य जिला अस्पताल है, मैं निवेदन करता हूं कि इसको जिला अस्पताल का दर्जा देकर और धन्यवाद इस बात का देता हूं कि मंत्री जी ने

(श्री मदन प्रजापत)

दिल खोलकर ट्रोमा सेन्टर की जो बालोतरा में घोषणा की है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि बालोतरा में ट्रोमा सेन्टर होगा और एक बात का धन्यवाद देता हूं कि मैं आपके पास में आया कि ब्लड बैंक का लाइसेंस नहीं मिला है। सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री जी को पुन: बधाई देता हूं कि वह ब्लड बैंक का लाइसेंस भी मिल गया। ट्रोमा सेन्टर की घोषणा भी हो गई और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बालोतरा का कार्यक्रम बनायें और ब्लड बैंक का उद्घाटन आपके कर कमलों से हो और एक बात मैं छोटा-सा निवेदन करता हूं कि आईसीयू सघन चिकित्सा इकाई कक्ष की स्थापना पहले हो चुकी है उसमें थोड़े सुधार और बजट की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इनके अलावा कई बातें हैं। कोई कमी नहीं है और आपने पीएचसी, सीएचसी की जो नियमानुसार घोषणा काफी की है जो भी सबको मिले वो बराबर भाग हमारे को भी मिले। मैं ज्यादा लालची नहीं हूं और हमारे कोई कमी नहीं है, सब अच्छी व्यवस्था है और इनके अलावा शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, जो इनके प्रशासनिक अधिकारी हैं इनकी अलग विंग और इकाई हो। वो ही लोग आपस में मानिटरिंग करते हैं। मेरा मानना है, मेरा निजी सुझाव है कि डिपार्टमेंट के कंट्रोल के लिए इनकी अलग चाहे हैल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, इनके जो ऊपर प्रशासनिक व्यवस्था है, वो अलग से अधिकारी और अलग विंग और इकाई हो, ताकि वास्तव में डाक्टर इस फालतू के काम में नहीं लगे और एमबीए और दूसरे अधिकारी भी लग सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक सीएमएचओ के अलावा एक छोटा-सा कर्मचारी मैं यहां बात करूं तो शर्म आती है एनआरएचएम में लगा हुआ आता ही नहीं कभी और वह तनख्वाह लेकर घूम रहा है। उसकी जांच करवायी जाए। एक छगन नाम का जो पोस्टेड है एनआरएचएम में, उसने बिलकुल कभी जिन्दगी में नौकरी की नहीं। यह जनता की गाढ़ी कमाई है। पहले वालों ने तो न मालूम किसके दबाव में बर्दाश्त किया होगा। अपने को कौनसा लालच है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें जो मेहनत करता है उनको मजदूरी मिले और जो मेहनत नहीं करता उनके ऊपर सख्त कार्यवाही हो और मैंने लिखित में भी दिया है, और दे दूंगा जिसका नाम यहां इस बड़े सदन में बात करें तो अच्छा नहीं लगता और जनता क्लिनिक की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने की। सभापति जी, आज आसन पर विराजमान हैं, जो सुबह वक्तव्य दे रहे थे कि मैंने मां के बेटे को किन हालात में देखा, बहन के भाई को किन हालात में

(श्री मदन प्रजापत)

देखा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने दवाइयां फ्री कीं और मुझे उस बात का दु:ख होता है 2013 के चुनावों में पूर्व मुख्य मंत्री जी ने इस दवा योजना को जहर शब्द तक कहा था। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, आज वह वरदान साबित हुई है और जनता क्लिनिक, मैं यह कह सकता हूं कि 'इलाज आपके द्वार, इलाज जनता के द्वार' इनसे बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। दवाई फ्री कर दी माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने, डिलीवरी का खर्चा फ्री कर दिया और सबकी भावना है कि यह पीपीपी माडल वाला जो घोटाला है यह पीपीपी माडल वगैरह ये राज्य के खूब डाक्टर हैं और अपनी व्यवस्था अपन खुद जब दवाई फ्री कर सकते हैं तो ये पीपीपी वाले बीच के बिचौलिये और दलालों का सिस्टम बंद हो। हास्पिटल अपना, हास्पिटल किसी दानदाता और भामाशाह ने बनाया और एक दो टके की दुकान पीपीपी के नाम पर अगर वह करोड़ों की सम्पत्ति का मालिक बनकर बैठ जाता है तो मेहरबानी करके इसके ऊपर भी थोड़ा गहराई से मंथन करें और एक सभी सर्वसम्मति से राठौड़ साहब, मैं निवेदन करता हूं कि ब्लड बैंक की बोतल पर जीएसटी है। सबकी भावना है इसमें कोई किन्तु-परन्तु नहीं तो लोगों में लगता है कि मैं मेरे कलेजे से खून निकालकर दान कर सकता हूं, उनके पैसे नहीं लगते और उस थैली और बोतल के जीएसटी लगती है तो यह हिन्दुस्तान अंगदान, नेत्रदान, रक्तदान और क्या-क्या, हर मामले में समाज सेवा में है।

माननीय सभापति महोदय, बाल विवाह की जो बात आई, मैं खुद इसका शिकार हूं और लगभग यह जांच करें तो 60-65 लोग तो इस विधान सभा के माननीय सदस्य हैं। यह अपनी गलती तो है नहीं। शायद जागरूकता की कमी थी, पुराना जमाना था और वास्तव में आज कम से कम साठ एमएलए तो शायद हैं। गत बार 2008 में 85 थे, हमने काउंटिंग की थी। इनके अलावा माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पूरा दिल खोलकर समय दिया। आपको बहुतबहुत धन्यवाद और मंत्री जी का पुन: आभार कि आपने ट्रोमा सेन्टर की घोषणा की और ब्लड बैंक का लाइसेंस परसों आ गया है। आपसे पुन: आग्रह है कि आप पधारें और उद्घाटन आपके हाथों से हो। पुन: आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री सुरेश मोदी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, ऐसा तो मत करो। एक इधर से और एक उधर से होना चाहिए। आप संख्या देख लो। हम पूरे 99 हैं। ये बीच वाले भी बैठे हैं। ऐसा मत करो साहब। सभापति हो साहब।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, मैं पहले अपने क्षेत्र की बात करूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नीमकाथाना के नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में तीन अस्पताल चालू थे। एक छावनी में पीएचसी कार्यरत थी। मुझे खुशी है जिसमें अध्यक्ष महोदय के पिताजी सबसे पहले डाक्टर थे। दूसरा शाहपुरा रोड़ पर एमसीडब्ल्यू सेन्टर चालू था और एक तीसरा कपिल हास्पिटल कपिल मंडी में चालू था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन तीन अस्पतालों में से दो अस्पताल बंद हो गये। चिकित्सा सुविधा बढ़ने के बजाय कम हो गई। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोगों का रुझान अस्पतालों में इलाज कराने के लिये बढ़ा है लेकिन मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आई है। तीन में से दो अस्पताल बंद हुए हैं। इन सबका नतीजा यह हुआ कि जो तीसरा अस्पताल है उस पर भार ज्यादा पड़ा। मैं कुछ आंकड़ों की तरफ माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस अस्पताल में ओपीडी 4 लाख से ऊपर है। आईपीडी 21 हजार से ऊपर है। एक्सीडेंटल केस 3 हजार से ऊपर हैं और जो केस रैफर होते हैं, जिनका इलाज नीमकाथाना में नहीं हो पाता है, वह 1800 से ऊपर हैं। नीमकाथाना औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र है। सभी ओर से कई हाईवेज से जुड़ा हुआ है और इसी कारण एक्सीडेंटल केसेज बहुत आते हैं। 70 किलोमीटर की दूरी में कोई ट्रोमा सेंटर नहीं है। 5 लाख से ऊपर की आबादी है। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि नीमकाथाना में ट्रोमा सेंटर खोला जाना बहुत आवश्यक है। उपरोक्त बंद अस्पतालों को चालू किया जाना भी नीमकाथाना में बहुत आवश्यक है। कपिल अस्पताल में एक सोनोग्राफी मशीन है, जिस पर बहुत भार है। बहुत सारी सोनोग्राफी मरीजों को बाहर करानी पड़ती है और उसके लिये बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मेरा चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि नीमकाथाना में एक सोनोग्राफी मशीन और दी जाए और एक डिजिटल एक्स-रे मशीन और दी जाए। जो डिजिटल मशीन नीमकाथाना में चल रही है वह बाबा आदम के जमाने की है। वह एक कंडेंसर पर चल रही है जो कभी भी खराब हो जाती है और उसको दुरुस्त करने में काफी समय लगता है।

(श्री सुरेश मोदी)

मेरे क्षेत्र चला में पीएचसी का भवन बहुत जर्जर हालत में है। वह कभी भी गिर सकता है, वह इस तरह की स्थिति में है। मेरा चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि उसकी या तो मरम्मत कराई जाए या पीएचसी को नया भवन दिया जाए, यह मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करता हूं।

मेरे क्षेत्र में ग्राम बिहार में एक डिस्पेंसरी बहुत पहले से चालू थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। वहां पर भवन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरा निवेदन है कि उस डिस्पेंसरी को वापस चालू किया जाए।

डाबला पीएचसी में पिछले 6 माह से कोई डाक्टर नहीं है। आस पास बहुत बड़ी आबादी लगती है और वहां पर 6 माह से कोई डाक्टर नहीं है। मैंने कई बार चिकित्सा मंत्री जी को निवेदन किया लेकिन अभी तक वहां पर कोई डाक्टर नहीं लगा है। मेरा इस सदन के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन है कि वहां जल्द से जल्द डाक्टर की नियुक्ति की जाए।

मेरे यहां से चिकित्सा विभाग में डेपुटेशन पर कई जगह लोग गये हुए हैं। पिछले भाजपा के शासन में खैरात बंटी है। सीकर में किसी को जगह नहीं मिल रही तो नीमकाथाना में पोस्टिंग कराकर डेपुटेशन पर सीकर चले जाओ। कांग्रेस शासन आने के बाद मैंने काफी डेपुटेशन कैंसिल कराये हैं। मेरा चिकित्सा मंत्री जी से एक निवेदन है कि यह डेपुटेशन का सिस्टम ही खतम किया जाए। यह एक बैक डोर एंट्री है, गलत तरीका है। एक दूसरे अस्पताल में जाने से आप तनख्वाह किसी और अस्पताल से उठाते हो और काम किसी और अस्पताल में करते हो। यह एक बड़ी गलत परिपाटी है, इसे बंद किया जाए और जिस व्यक्ति की जहां पोस्टिंग है, वह वही काम करे। मेरे क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिये नई पीएचसी व सीएचसी खोले जाने का भी मैं निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टरों के और पैरामेडिकल स्टाफ के जितने रिक्त पद हैं, उन्हें शीघ्र भरा जाए। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि विशेष डाक्टरों को उनके स्वीकृत पदों पर जरूर लगाया जाए क्योंकि आज हर व्यक्ति विशेषज्ञ डाक्टर को ही दिखाना चाहता है और अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टर नहीं मिलने पर वह प्राइवेट डाक्टरों का रुख करता है। इसी प्रकार हर महिला डिलीवरी अस्पताल में कराना चाहती है इसलिए हर अस्पताल में गायनिक डाक्टर अवश्य लगाई जाए एवं इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वह गायनिक चिकित्सक हमेशा अस्पताल में अवेलेबल रहे। अक्सर गांवों के अस्पतालों के

(श्री सुरेश मोदी)

डाक्टर डिप्लोमा करने चले जाते हैं एवं सालों तक वहां की जनता चिकित्सा सुविधा से वंचित रहती है क्योंकि सरकार के रिकार्ड में वहां डाक्टर लगा हुआ है लेकिन प्रेक्टिकली वहां कोई डाक्टर नहीं है। यही स्थिति महिला चिकित्सक के सीसीएल (चाइल्ड केयर लीव) की लंबी छुट्टी जाने पर होती है। मेरा चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि किसी भी कारण से चिकित्सक के लंबी छुट्टी जाने पर उसकी पोस्टिंग डाइरेक्ट्रेट में करें एवं संबंधित अस्पताल में दूसरी पोस्टिंग करें। पीएमओ के भी अक्सर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने चिकित्सकीय काम पर ध्यान नहीं दे पाता है, इस ओर भी चिकित्सा मंत्री जी ध्यान दें। अक्सर देखने में आता है कि सरकारी सेवा में कार्यरत डाक्टरों के परिवारों के सदस्य के अस्पताल चलते हैं। उनका ध्यान अपने उन प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर रोक लगे, ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें।

ज्यादातर अस्पतालों में जांच की मशीनें बहुत पुरानी हैं एवं उनकी संख्या बहुत कम है जिससे मरीजों को बाहर पैसे देकर जांच करानी पड़ती है। जांच करने वाले टैक्निशियन के छुट्टी जाने पर भी यही हालात होते हैं। मेरी जानकारी में है राज्य के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में जांचें प्राइवेट पार्टी को ठेका देकर करवाई जाती हैं। जिस पार्टी को ठेका दिया गया था, उसके ठेके का समय मार्च में समाप्त हो गया है। नई उन्नत मशीनों से जांच का नया टेंडर भी विभाग ने किया, उसमें लोगों ने बिड भी दी परन्तु अकारण ही उन्हें काम नहीं दिया गया एवं पुराने ठेकेदार से ही, पुरानी मशीनों से ही जांच का काम करवाया जा रहा है। मुख्य मंत्री जी ने ...(व्यवधान) मैं तो एक मिनट और लूंगा, आप फिर आराम से बोलना। मुख्य मंत्री जी ने अब और जांचें और लोगों के लिये भी नि:शुल्क करने की घोषणा की है। और जांचों की संख्या बहुत बढ़ने की उम्मीद है। अत मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस ओर ध्यान देकर मामले की जांच कराएं कि यह क्या खेल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में चल रहा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप जिस आसन पर विराजे हैं, यह विक्रमादित्य का आसन है, यह निष्पक्ष आसन है। सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के लोगों को अधिकार है, हम संख्या में एक दो नहीं हैं, 73 हैं, +++ तो हम बाहर निकलते हैं। आप तीन-तीन लोगों को उधर से बुलाओगे, +++ आप कांग्रेस के सदस्य नहीं ....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) आप आसन की निष्पक्षता पर प्रश्न मत कीजिए माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपके तय समय से ज्यादा समय दिया गया और कल भी आपने 58 मिनट भाषण दिया है, 58 मिनट बोले हैं आप कल ...(व्यवधान) 58 मिनट समय था क्या आपका? (व्यवधान) आप इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। गलत है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) नहीं बुलाना हो तो बताओ आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान) मैं ध्यान रखूंगा माननीय ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, समय नियत है।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, पूरा समय देना आप इनको बोलने के लिये। तीन-तीन लोग वहां से बोल रहे हैं, यहां से एक, कैसे होगा?

श्री सभापति: पूरा समय देंगे।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं होगा। जितना समय आपको अलोटेड था, उससे ज्यादा आप लोग बोल चुके हो। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ये तो सत्ता पक्ष के लोग हैं। ये तो वैसे ही मांग कर रहे हैं। ये तो अपने आप ही बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जितना समय आपको अलोटेड है, उससे ज्यादा आप लोग बोल चुके हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको बोलने के लिए पूरा समय दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जितना समय आपका तय है, उससे ज्यादा समय आप बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान) कुछ लोग हैं, जिनकी बात मंत्री जी नहीं सुनते, इसलिए यहां बोलना पड़ रहा है। (व्यवधान) जो विपक्ष में हैं उनको बोलने दीजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप समय नहीं दे रहे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बहुत सीनियर हैं। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये बार-बार कागज लेकर डराइए मत। आपने कल 58 मिनट भाषण दिया है। बजट में आपके तय समय से ज्यादा समय आपको दिया है। सरकार आपको बोलने का पूरा मौका दे रही है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप कौन होते हो चैलेंज करने वाले? बोलने का समय चेयर देती है, आप नहीं देते हो। आप कोई नहीं हो जो इस तरीके से चैलेंज करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आसन की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप आसन नहीं हो। आप इसको शुद्धीकरण करो कि आप आसन नहीं हो। आसन समय दे रहा है, वे बोल रहे हैं। आप बीच में बोलने वाले कौन होते हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जैसे आप हैं, वैसे ही हम हैं। जिस हैसियत से आप खड़े हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। संयम जी, संयम रखें ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति जी, टोकते क्यों नहीं हो, ये सीधी बात क्यों करते हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को आप ही की कही गयी बात से शुरू करना चाहती हूं। आपने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा आउटडोर वर्तमान में हमारा एसएमएस हास्पिटल जयपुर है। निश्चित तौर में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किये। इस एसएमएस हास्पिटल में पूर्ववर्ती सरकार ने भी ऐसे-ऐसे काम करके दिखाए कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस जयपुर की धरती पर इम्प्लांट्स चेंज होंगे, ट्रांसप्लांट होंगे। कोटा की धरती पर ट्रांसप्लांट होंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करके दिखाया है।

मैं आपके माध्यम से सदन में विराजमान सम्माननीय मंत्री महोदय जी और सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी। करवर क्षेत्र का

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

एक गंभीरा गांव है। मस्तराम सैनी नाम का पेशेंट जिसका एक्सीडेंट 06.04.2019 को हुआ। नैनवां हास्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया। बेहोशी की हालत में था, कोमा में था। वहां से उसे जयपुर रैफर किया गया और उसको 10.04.2019 को यहां पर मृत घोषित कर दिया गया। उसके पिता अनपढ़ थे, उसके चाचा अनपढ़ थे। लगातार 16 घंटे तक डैड बाडी के लिए जूझते रहे। उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि हम लोगों को कैसे भी करके हमारे बालक की डैड बाडी दे दीजिए। हम गांव में जाएंगे उसका अंतिम संस्कार करेंगे। उनसे एक पेपर पर साइन भी करवाया गया कि हम आपके बालक का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मुझे इस सदन में बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज भी उसके माता-पिता जब अख़बार में उसका फोटो देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप देखिए, यहां से उसको लेकर गये और ले जाने के बाद जब उन्होंने उसको घर जाकर देखा, तो उसके हार्ट पर पट्टी, उसकी किडनी पर पट्टी, उसके लीवर पर पट्टी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। गांव के लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि पोस्टमार्टम इसी तरह से होता होगा। अंतिम संस्कार करने के बाद दूसरे दिन उसके पिता ने जब पेपर में देखा। जब गांव वाले पेपर लेकर आये उन्होंने पढ़ा। पेपर की कटिंग और फोटो मेरे पास है। उसमें लिखा हुआ था कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आईएलबी की टीम ने आने से मना किया, 25 वर्ष के युवक ने किडनी, लीवर, हार्ट को डोनेट किया और आज होंगे ट्रांसप्लाट।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बिना सहमति के पार्ट निकाल लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं किसी तरह का कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहती। पता नहीं, स्थिति और परिस्थिति क्या थी? किस तरह से डाक्टर्स ने इस तरह का डिसीजन लिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं, मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जिस पिता का 25 वर्षीय बालक मरा, वह मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिये दो महीने से चक्कर काट रहा है। वह जब भी मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने आता है, उसे धक्का मारकर भगा दिया जाता है। आप देखिए, सम्माननीय बिरला जी को पत्र लिखा। मेरे पास चार बार आये, और तो और उसके माता-पिता के पास वर्तमान में कोई सबूत नहीं है कि उसके बेटे को यहां पर एडमिट किया। पता नहीं, किस तरह से गलती से, कोई हास्पिटल में मिलने आया और उसने एंट्री पास की मोबाइल में फोटो खींची, वह भी हमें इतनी मुश्किल से मिली है, जिसकी कोई हद नहीं है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं। मैं फिर बोल रही हूं मेरा किसी तरह का आरोप नहीं है। इस बात का पता लगाया जाए कि इस तरह की हरकत जयपुर के एसएमएस हास्पिटल में हो जाए। वह कैसे हुई? एक टीम गठित की जाए और इस बात की जांच की जाए कि क्या उसके माता-पिता जो बोल रहे हैं, वह बात सच है या गलत है? पूरे क्षेत्र में इतना डर बैठा हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि जयपुर में कभी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात की जांच होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बात और भी हैं, जिनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कोटा में हमने कैथ लैब शुरू की है। बहुत खुशी की बात है। मेडिकल कालेज है होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि न्यूरोसर्जरी विभाग के सह आचार्य विभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं और सरकार की निगाह में उन्होंने डाला कि अगर न्यूरो सर्जरी विभाग में न्यूरो इंटरवेशन की सुविधाएं कार्डिक कैथ लैब में अपग्रेड की जाती हैं तो मात्र सवा करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। उसके बावजूद भी हम आठ करोड़ रुपये खर्च करके अलग से कैथ लैब बना रहे हैं, इसका क्या कारण था? क्या हम आठ करोड़ रुपये में कोटा की जनता को अलग से सुविधा नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में जब मंत्री जी जवाब दें तो मुझे बताएं तो निश्चित है कि बहुत अच्छा काम होगा।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी। वास्तव में, डाक्टर्स हमारे लिये और पूरी जनता के लिए दूसरे भगवान होते हैं। एक भगवान ने हमें जन्म दिया। यहां पर भेजा। आज की तारीख में भगवान का दूसरा रूप माना जाता है तो डाक्टर्स को माना जाता है। आज यह स्थिति है कि किसी भी प्राइवेट हास्पिटल में कोई चला जाए और कुछ बोल दे। चाहे नेता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो तो उसे भी हमेशा इस बात का डर होता है कि अगर मैंने इनके खिलाफ आवाज उठायी तो मेरे खिलाफ ये हड़ताल पर जाएंगे। ये धरने पर बैठ जाएंगे और यही हालात हुए। मेरी मात्र इतनी-सी गलती थी कि मेरी गनमैन की बेटी का रामपुरा सैटेलाइट हास्पिटल में जन्म हुआ। उसको चैकअप के लिए मैत्री चिकित्सालय में लाया गया। मैत्री चिकित्सालय में जब उसको लाया गया तो उसके परिवारजन से कहा गया कि इसके हार्ट में छेद है और आप इससे नहीं

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मिल सकते। हम लोग इसको आईसीयू में रख रहे हैं। कम-से-कम 20 से 25 दिन इसको यहां एडमिट रखना पड़ेगा। मैं इस बात को यहां इसलिए बताना चाह रही हूं कि क्या हालात हैं? मैंने हास्पिटल में जाने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि उस बालिका को मैं देखकर आऊं। आप देखिए, मैंने जैसे ही डाक्टर्स के खिलाफ आवाज उठायी कि मैं अंदर जाना चाहती हूं, स्पष्ट करना चाहती हूं कि आखिर बच्ची किस हालात में है। इतनी-सी आवाज में सारे के सारे डाक्टर्स कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मेरे खिलाफ स्ट्राइक, हास्पिटल बंद करने की धमकी, इस तरह के हालात। आपको बताना चाहती हूं कि आज दो-ढाई साल बाद भी वह बालिका इतनी अच्छी है कि आप हिन्दुस्तान के किसी भी हास्पिटल में दिखा लें, कोई डाक्टर यह नहीं बोल सकता कि उसके हार्ट में छेद है। तो क्या यह लूट-खसोट की जा रही है, 20 से 25 दिन आईसीयू में रखने की, वेंटीलेटर पर रखने की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कहूंगी कि यह जनता के साथ धोखा हो रहा है। यह गरीब जनता के साथ धोखाधड़ी है। इस ओर में आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूं।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहती हूं। सम्माननीय मंत्री चांदना जी को धन्यवाद दूंगी। मेरे ही गृह जिले से आते हैं, शिलान्यास करने का शायद उनको, होना भी चाहिए, अधिकार है, आपकी सरकार है। मैं इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती, लेकिन हमारा बलकासर पीएचसी है। मुझे लगता है इसकी जमीन का अभी तक टाइटल भी क्लियर नहीं होगा और टेंडर भी नहीं हुए, उसके बावजूद भी आनन-फानन में शिलान्यास कर देना, लेकिन मैं आपसे मांग करती हूं कि उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए।

आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि बूंदी जिले का हास्पिटल, आईसीयू में यह हालत है कि एयर कंडीशनर किसी दानदाता ने पुराने डोनेट किये थे, कम से कम 15-20 साल पहले। आज ऐसी स्थिति में है कि उसकी वजह से आग लगी और पूरा हास्पिटल खाली करवाना पड़ा, अभी कुछ दिन पहले। मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से आईसीयू में हमें एयर कंडीशनर की सुविधा की जाए। स्पेशल बजट हमें दिया जाए ताकि हमारे जिला हैडक्वार्टर का क्योंकि मजदूर इलाका है। आप देखिए पूरा माइनिंग एरिया है बूंदी के आस पास। पूरा मेरा विधान सभा क्षेत्र और तीनों विधान सभा क्षेत्रों में गरीब लोग रहते हैं कि उन्हें लाभ मिले जब वह आईसीयू में एडमिट हो।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि निशुल्क जांच योजना और नि:शुल्क दवा योजना आपकी चलती है। उसमें अगर बजट की आवश्यकता होती है तो लोकल स्तर पर हम लोग परचेज करते हैं। आप देखिए जिला हैडक्वार्टर के हर हास्पिटल में यह प्राब्लम हो सकती है। मैं मेरे जिले की आपको बता रही हूं। तीस से चालीस लाख रुपये नेगेटिव में चल रहा है वर्तमान में बूंदी का हास्पिटल। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हम जनता को अगर सस्ता इलाज और जांच देना चाहते हैं तो कम से कम इस बजट में जो आरएमआरएस के माध्यम से आपका आता है, उसमें व्यवस्था की जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगी कि एक्सरे मशीन लाखेरी हास्पिटल में लगी हुई है। लेकिन अगर उसमें फिल्म नहीं है, रील नहीं है तो किस काम का है? एक्स-रे उसमें नहीं हो पाए तो बेकार है। मेरा निवेदन है, या तो हम डाक्टर्स को पाबंद करें कि आपके पास जो बजट है उसमें लेकर आइए। लेकिन उनका कहना है कि हम कब तक इस पैसे को खर्च करें। हम लोग इधर-उधर से पैसा मांग-मांगकर खर्च कर रहे हैं। इसकी व्यवस्था की जाए।

मेरा निवेदन है कि आपने ट्रोमा हास्पिटल, पूरे 57 ट्रोमा हास्पिटल वर्तमान में राजस्थान में चल रहे हैं। हमने ट्रोमा हास्पिटल खोल दिए। सरकार ने, सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने फिर बजट में घोषणा की कि हम 5 ट्रोमा सेन्टर और खोलेंगे। हम ट्रोमा सेन्टर तो खोल रहे हैं लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि हमें उसमें आर्थोपेडिक डाक्टर की जरूरत है, हमें एनस्थीसिया की जरूरत है। अगर आप मात्र और मात्र पूरे राजस्थान के 57 हास्पिटल में ढांचा खड़ा कर दें तो इससे जनता का इलाज नहीं होने वाला, जनता को रिलीफ नहीं मिलने वाला क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन हास्पिटल में एक्सीडेंटल केस आते हैं। रैफर किये हुए आते हैं। लाखेरी हास्पिटल के नाम पर मात्र एक बिल्डिंग, एक आफिस पड़ा हुआ है और कुछ भी वर्तमान में नहीं चल रहा है। मेरा निवेदन है कि मजदूर एरिया है, इसकी व्यवस्था वहां पर की जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सोनोग्राफी मशीन हमें दी जाए। मैं तो आपसे मांग करना चाहूंगी कि अगर जिला हैडक्वार्टर जिला अस्पताल भी अगर इस लाखेरी की सीएचसी को बनाते हैं तो वहां की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है क्योंकि मजदूर इलाका है।

अभी सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हम शिशु मृत्यु दर और मात्र मृत्यु दर को कम करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हमें मात्र भाषण देने से या आंकड़े लेने से, क्योंकि आंकड़े कभी-कभार गलत भी मिल जाते हैं। इस सदन में यह भी हुआ है कि आंकड़े गलत मिल गये। मेरा एक 131 जो मैंने तीन साल पहले लगाया था। उसमें आप देखेंगे तो आप खुद भी ताज्जुब करेंगे कि किस तरह से यहां से हमें जवाब मिलते हैं, अधिकारियों से। उसमें दिया गया है कि प्रसवों की वर्षवार सूची तथा मातृ मृत्यु दर 2008 से 2012, जननी सुरक्षा के दावों की पोल खोलती दिखाई पड़ती है और उसमें आप देखिए जीता-जागता उदाहरण, 2008-09 में बारां, बीकानेर, जयपुर द्वितीय और पाली जिले की मातृ मृत्यु दर शून्य दर्शायी गयी है। जब हम इसी आंकड़े को देखेंगे तो आप देखिए 2008-09 में बारां में प्रसव दिखा रहे हैं 22091, बीकानेर में दिखा रहे हैं 34809, पाली जिले में 28381 और एक भी मृत्यु नहीं हुई। यही आंकड़ा आप आगे जाकर देखेंगे तो इस आंकड़े में आपको देखने को मिलेगा कि वर्ष 2008-09 में शून्य मृत्यु दर। इसके बाद अचानक स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी क्या गड़बड़ाई कि शून्य से बढ़कर 2009-10 में यही आंकड़ा बारां में 56, बीकानेर में 3, पाली में 33 मातृ मृत्यु दर और आप देखिए 2012-13 जनवरी तक बांसवाड़ा जिले में गत वर्ष की तुलना में प्रसवों की संख्या लगभग 5 हजार कम हुई और उसके बाद भी मातृ मृत्यु दर 68, मेरा निवेदन है कि हम आंकड़ों पर नहीं जाएं। आंकड़े कुछ भी उपलब्ध हो जाते हैं। यह रिकार्डेड आपके यहां का विधान सभा में लगा हुआ मुझे मेरे 131 में जवाब मिला है। उसको पढ़ रही हूं। इसकी जांच करवा लेना आप।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारा बूंदी का जिला हास्पिटल वर्तमान में एक ऐसा हास्पिटल, क्योंकि पूरी आबादी बढ़ती जा रही है और हमें अलग से सीएचसी की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वर्तमान में दो डिस्पेंसरी चल रही हैं। उसके लिए तो मैं कहूंगी कि ठीक है.....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): बूंदी में हमारे दो अरबन डिस्पेंसरी चल रही हैं। इसके बावजूद भी हास्पिटल पर लगातार भार बढ़ रहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं, दूरी भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हमें दो अरबन डिस्पेंसरी देवपुरा और उंडातियोक में देंगे तो निश्चित है कि वहां की जनता को लाभ होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप बहुत वरिष्ठ हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं बैठ रही हूं साहब। आपके आदेश की पालना की जाएगी।

हमारे जितने भी डाक्टर्स हैं, जो डेपुटेशन पर लगे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूं कि मैं तीसरी बार विधायक हूं और मैंने हमेशा प्रतिनियुक्ति पर उंगली उठाई है। मैं हमेशा यही कहती हूं कि गांव की जनता को भी डाक्टर्स की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है लेकिन गांव के नाम पर पोस्टिंग, आज भी आप देखिए कितने हमारे देहात के डाक्टर्स प्रतिनियुक्ति के नाम पर जिला हैडक्वार्टर पर लगे हुए हैं। ये सारे डेपुटेशन निरस्त कीजिए।

लास्ट में मेरा एक बिंदु है कि सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक बात कही और उन्होंने जो बात कही थी, हमारी सम्माननीय बहिन अनिता जी भी उस बात को बोली थीं कि बीकानेर में दर्द रहित प्रसव करवाने के लिए, मेरा निवेदन है कि इसमें आप देखिए, आप पूरे राजस्थान के आंकड़े निकलवाएं। आप दो साल के, तीन साल के, दस साल के निकलवाएं कि जितने भी हमारे प्राइवेट हास्पिटल और डिस्पेंसरियां हैं, उनमें देखिए कि कितने प्रसव, डिलीवरियां आपरेशन से हुई। यह महिलाओं के लिए घातक है। आप सरकारी हास्पिटल में जाएं आपको कम से कम सिजेरियन मिलेंगे। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि कम से कम महिलाओं के

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए और ब्लड बैंक लाखेरी में शुरू हो जाए इतना ही निवेदन है। आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गणेश घोघरा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति जी, बीच वालों के साथ भी न्याय कीजिए।

श्री सभापति: मुझे ध्यान है आपका।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हम एक-दो ही हैं। दो तो हम ही बच रहे हैं। ये बसपा वाले, बीटीपी वाले बचे हैं। आधी रात हो जाएगी।

श्री सभापति: मुझे सर, आपका ध्यान है। नैक्स्ट मैं आपको लूंगा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे वागड क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र में हमारे जन-जन के लाड़ले यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमको मेडिकल कालेज दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का। हमारा आदिवासी क्षेत्र बिखरा हुआ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, अनपढ़ लोग है, उन सब बातों को ध्यान रखकर हमको मेडिकल कालेज मुख्य मंत्री जी ने दिया। तहेदिल से उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं।

इसी के साथ पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार जैसे ही सत्ता में आई, उस मेडिकल कालेज को पीपीपी मोड पर लाकर खड़ा कर दिया। अब पीपीपी मोड पर लाकर खड़ा कर दिया। वहां आदिवासी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। पीपीपी मोड गरीबों के लिए ठीक नहीं है। गरीब कहां से इतना पैसा लाएगा? कहां से बच्चे पढ़ सकेंगे? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में पीएचसी और मेडिकल कालेज जो पीपीपी मोड पर लिए गए हैं, उनको सरकार स्वयं संचालित करे, यह मैं मांग रखता हूं।

(20.00 बजे)

सभापति महोदय, डूंगरपुर मुख्यालय पर एकमात्र हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय है। इसमें मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां बैड बढ़ाए जाएं जिससे वहां के गरीब लोगों को लाभ मिल सके।

(श्री गणेश घोघरा)

सभापति महोदय, ट्रोमा सेंटर खुला हुआ है लेकिन डाक्टर की कमी से चल नहीं रहा है। छोटे-मोटे एक्सीडेंट होते हैं तो उनको अहमदाबाद रैफर करना पड़ता है या उदयपुर रैफर करना पड़ता है। कई मरीजों की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है, उनको वापस लाना पड़ता है और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को इधर से उधर भटकना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि डाक्टर्स का पदस्थापन किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि हास्पिटल में साफ-सफाई ठीक नहीं है। गायनिक वार्ड हो, मेडिकल वार्ड हो, चद्दरें आठ-आठ दिन में भी नहीं बदली जाती हैं, इससे मां व बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। हास्पिटल में साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए। वहां के स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता। गांव से अनपढ़ लोग आते हैं उनको दुत्कारा जाता है। दूसरी बार वह उस हास्पिटल में आते ही नहीं हैं, प्राइवेट हास्पिटल में इलाज कराते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि डाक्टर को, स्टाफ को पाबंद किया जाए। जैसे गुजरात में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वह प्यार से बोलते हैं तो आधी बीमारी तो उनकी वैसे ही खतम हो जाती है लेकिन हमारे यहां ऐसा व्यवहार होता है चल बाहर निकल, ऐसा कर, वैसा कर। नर्स कम्पाउण्डर उनको डराते-धमकाते हैं तो बेचारे इलाज कराने आते ही नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि यह सब हास्पिटल में हो रहा है। डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स अनुशासन में रहें, उसके लिए उनको पाबंद किया जाए।

सभापति महोदय, डूंगरपुर में मात्र एक ही हास्पिटल है, यहां बहुत रिक्त पद पड़े हैं। डाक्टर्स की कमी है। मैं मंत्री जी से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे टीएसपी एरिया की जो भी नर्स, डाक्टर, बाहर ज़िलों में हैं उनको तुरन्त प्रभाव से हमारे डूंगरपुर ज़िले में, टीएसपी क्षेत्र में लगाया जाए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे सामने जो विपक्ष में बैठे हुए हैं मेरे साथी, उन्होंने कई आरोप-प्रत्यारोप किए, लेकिन मैं सी.एम. साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने निशुल्क दवाइयां, ऐसा जन नायक, गरीबों का मसीहा, ऐसी सोच रखी कि हर गरीब को दवा मिले, फ्री दवा मिले। मैं मुख्य मंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट

(श्री गणेश घोघरा)

करना चाहता हूं। फ्री जांचें भी कीं, तो यह तो हमारे लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए, टीएसपी क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हुआ। जनता क्लिनिक, गली-मौहल्लों में, पहाड़ों पर, आदिवासी बिखरी हुई बस्ती में रहते हैं उनके लिए तो यह संजीवनी बूटी के समान हुई है। जनता क्लिनिक के लिए मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, पूर्व कांग्रेस सरकार में, 2013 में सैकण्ड ग्रेड की 15773 नर्स के पदों पर विज्ञप्ति निकाली थी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने आते ही उसमें से 4514 पदों की कटौती कर दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने 15773 पदों की विज्ञप्ति निकाली थी, शेष बचे 4514 पदों की भर्ती की जाए। इसमें संविदा नर्सेज, जो 10-15 साल से काम कर रहे हैं उन सभी का भला हो जाएगा। 2013 नर्सिंग भर्ती पूर्ण कराई जाए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जो पद बचे हुए हैं उनको भरा जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि डूंगरपूर में मेडिकल कालेज खोला गया है, इस कालेज में भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला हो रहा है। इस मेडिकल कालेज में कितनी राशि खर्च हुई, कितना बजट स्वीकृत हुआ, क्या-क्या उपकरण खरीदे, कौन सी निविदा डाली, किसको लिया गया, कोई अता पता नहीं है।

टीएसपी एरिया में स्थानीय लोगों को भर्ती नहीं किया गया। राजस्थान के लोगों को भर्ती नहीं किया गया। उसमें वार्ड ब्वाय, हैल्पर, स्वीपर राजस्थान के बाहर से, दूसरे लोगों को लिया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह निविदा किसकी है, यह टेंडर किसका हुआ, यह बिल वाउचर कैसे लगे, इनकी जांच होनी चाहिए। टीएसपी क्षेत्र के लोगों को फायदा क्यों नहीं मिला यह जानकारी मैं चाहूंगा। मेडिकल कालेज में डाक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक, अन्य अस्थाई कर्मियों की सूची, नाम, पद, वेतन, प्रथम उपस्थिति, मोबाइल नम्बर के साथ उपलब्ध कराएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बीछीवाड़ा क्षेत्र, हाईवे नम्बर आठ, वहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं लेकिन वहां रात को न तो डाक्टर मिलता है, न ही नर्स मिलती है, न ही कम्पाउण्डर

(श्री गणेश घोघरा)

मिलता है, ऐसी स्थिति में कई मरीजों की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। जहां पीएचसी है, सीएचसी है वहां रात को या तो नर्स रुके या कम्पाउण्डर रुके, इमरजेंसी में एक डाक्टर भी रुके जिससे टीएसपी एरिया के आदिवासियों को लाभ मिल सके। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के ज़ीने का अधिकार यह अनुच्छेद देता है। ज़ीने के साथ-साथ उसी में शामिल है स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार भी उसे प्राप्त है। राज्य उसको अच्छा स्वास्थ्य देगा। केन्द्र ने स्वास्थ्य के लिए मात्र डेढ़ प्रतिशत जीडीपी खर्च करने का फैसला किया है। ब्रिक्स में हिन्दुस्तान के साथ रूस, साउथ अफ्रीका, भारत की तरह दूसरे ब्राजील यह सारे देश अपनी जीडीपी का 8 से 9 प्रतिशत चिकित्सा पर खर्च करते हैं।

मेरे तमाम साथी चर्चा करते हैं कि हमारे ट्रोमा सेंटर नहीं, हास्पिटल है तो डाक्टर नहीं, डाक्टर है तो उसके पास उपकरण नहीं, सोनोग्राफी की मशीन नहीं, हकीकत तो यह है कि हमारे पास बजट नहीं। मैं यह जिक्र करना चाहूंगा ...(व्यवधान) नहीं, नहीं खुश मत होओ, अपन सारे एक से हैं। खुश मत होइये, मैंने केन्द्र से ही शुरू किया है और डेढ़ ही परसेंट दे रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, बात सुनो गौर से, बड़ी तसल्ली से सुनो। (व्यवधान) केरला में यह बजट 5.1 प्रतिशत है जनाब, इसलिए आप और हम इस बात की चर्चा करे, अच्छा स्वास्थ्य अगर हम चाहते हैं तो हमें अच्छे बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। 13 हजार करोड़ रुपये राज्य की सरकार ने पिछले बजट से 863 रुपये बढ़ाए हैं, मैं तो कह रहा हूं डबल करते, तो फिर हम सब की मांग पूरी तो नहीं होती पर कुछ न कुछ शुरू हो जाती। इसलिए हम जिक्र करना चाहेंगे कि जिस तरह हिन्दुस्तान में एजुकेशन प्राप्त करने का बिल प्राप्त हो चुका, अधिकार प्राप्त हो चुका, हमें भी स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। फिर मेरी कोई बहन चन्द्रकांता यह नहीं कहे कि मेरे इलाके का आदमी, उसकी किडनी निकाल ली, उसकी आंखें निकाल लीं, हार्ट निकाल लिया, हकीकत तो यह है कि आदमी का दिमाग निकाल लिया।

प्राइवेट हास्पिटल में जितनी भी बच्चियां डिलीवरी के लिए जाती हैं, यह दर्द हम सबका है, 85 से 95 परसेंट तक सिजेरियन होता है। आप और

(श्री बलवान पूनियां)

हम, सब लोग गांव में पैदा हुए हैं, उस समय तक प्रसव के लिए मां को कोई हास्पिटल नहीं लेकर जाता था। सब नोर्मल डिलीवरी की संतान हैं हम, पर अब सब के सब हास्पिटल में सिजेरियन से पैदा होते हैं। यह सिर्फ पैसे का मसला नहीं है। जिस बच्ची का सिजेरियन से प्रसव हुआ, उसको आने वाले दिनों में कैंसर होने का खतरा होगा। उनकी दसवें और पन्द्रहवें साल बच्चादानी बाहर निकालनी पड़ती है। यह भविष्य है। जो हास्पिटल से अपने पोते और पोती को लाकर खुश होते हैं, वे दस-पन्द्रह साल के बाद अपने बेटे की बहू को, या अपनी बेटी को हास्पिटल फिर ले जाइये, इस बात के लिये कि थोड़े दिनों में उसकी बच्चादानी का भी आपरेशन होगा। यह हमारी व्यवस्थाएं हैं। इस बजट के कट-मोशन में हम इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात करना चाहते हैं।

जब हम आज चर्चा के लिये विधान सभा में घुस रहे थे तो हमारे चार-पांच संगठन ज्ञापन देने के लिये आ गये। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में आयुष नर्सेज को मेडिकल नर्सेज के समान वेतनमान व नर्सिंग भत्ता दिये जाने, कैडर रिव्यू और रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ करने की मांग संख्या 26 में आप रखें, ताकि सरकार हमारी सुने।

दूसरे संगठन ने कहा कि नि:शुल्क दवा योजना में कार्यरत फार्मासिस्ट्स को नियमित करने की मांग उठाई जाए। मैं सदन में मांग करता हूं कि उनको नियमित किया जाए और बहुस्तरीय प्रमोशन कैडर निर्माण, छठा वेतन आयोग और उनकी विसंगतियां, वेतन विसंगतियों को दूर करने की उनकी मांग पूरी की जाए।

सभापति महोदय, मैं सदन में मांग करता हूं कि निशुल्क जांच योजना के कार्मिकों को स्थाई करना, मानदेय बढ़ाना, उनको समय पर उपकरण, सामान की आपूर्ति करना और समय पर उनका भुगतान करना, यह राजस्थान की सरकार करे।

मैं आपके मार्फत मांग करता हूं कि नर्सिंग भर्ती में 2013 में ए.एन.एम. को पूरे पदों पर अभी भी 6700 बच्चियों को ए.एन.एम. के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई है। उनको न्याय दिया जाए। यह सदन बड़ी गम्भीरता के साथ, बात कर रहे हैं, हम रोजगार मांग रहे हैं। अभी 2013 की बात 2019 में हम करते हैं। आरोप और प्रत्यारोप से स्वाद नहीं आयेगा। काम करने से काम

(श्री बलवान पूनियां)

चलेगा। इसलिये मैं सभापतिजी के माध्यम से मांग करता हूं कि यहां हम काम की बात को आगे बढ़ायेंगे।

मैं कल शाम को सदन के पूरा होने के बाद जब घर जाने की तैयारी में था, साथी अमित और हम दोनों एस.एम.एस. हास्पिटल गये। साक्षी नाम की एक बच्ची यहां गाइनकोलोजिस्ट बनने के लिये आई थी। उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इसलिये, कि वह कह रही है कि मेरे पर दबाव था। सुसाइड में उसने कहा है कि मैं बहुत दबाव में काम कर रही थी। एसएम.एस. हास्पिटल में इतना दबाव, प्रेशर है। जब हम डाक्टरों से बात करने के लिये गये तो उन्होंने कहा कि आठ की जगह साठ पेशेंट हैं। हम सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अगर सारे के सारे लोग यूं दबाव में करते रहे तो कौन अपनी बेटी को गाइनोकोलोजिस्ट बनायेगा। फिर कौन हमारी बेटियों की नार्मल डिलीवरी सरकारी हास्पिटल में कराएंगा।

मैं भादरा के हास्पिटल में, जब से एम.एल.ए. बना हूं, एम.एल.ए. बनने से पहले भी गाइनोकोलोजिस्ट की सीट चाहता था। मैं खाली पदों को भरवाने की मांग चाहता था। मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके में मुंसरी गांव में डुंगराना गांव में, निनाण गांव में पी.एच.सी. बने। मैं चाहता हूं कि मेरे वहां ब्लड बैंक शुरू हो। उससे पहले मैं यह बात चाहता हूं कि हमारे यहां लोगों का स्वास्थ्य इतना ऊंचा हो कि वे सौ साल जियें, सवा सौ साल जियें। किसी को वैचारिक रूप से अगर बुरा लगे तो मुझे कोई गुरेज नहीं पर दुनिया के जिन समाजवादी मुल्कों में समाजवादी सरकारें रही हैं वहां बहुत लोगों की आयु सौ साल से ऊपर बढ़ी है क्योंकि उन्होंने, जब बच्चा मां के पेट में आया, उस दिन से ले करके और जब तक धरती से गया, तब तक की जिम्मेदारी सरकारों ने ली। आज तो निजी चिकित्सालयों की हालत यह है कि वह आदमी को आदमी नहीं, एक ऐसा बकरा समझते हैं, अगर यह शब्द असंसदीय नहीं है, क्योंकि वह बकरा है और उसको कैसे हलाल करें। मरने के बाद दो-दो, तीन-तीन, चार-चार घण्टे तक उसको धड़काते हैं।

हमारे पास में हास्पिटल हैं, हिसार के हास्पिटल, 72-72 घण्टे बाद वहां लोग झण्डा लेकर जाते हैं कि डेड बाडी दो। जीने के लिये आदमी की मांगें हजार रहती हैं, मरने के बाद झण्डा उठाकर लोग कहते हैं कि हमारा आदमी मर गया, आदमी दे दो क्योंकि हमारे पास तो व्यवस्था नहीं है।

(श्री बलवान पूनियां)

सुबह कोई कह रहा था कि गुजरात जाना पड़ता है। मैं कहता हूं मेरे नजदीक हरियाणा है, हरियाणा जाना पड़ता है। हम हमारे पेशेंट्स को राजस्थान में ही दिखा लें और जिन बीमारियों से हम घिरे पड़े हैं, कैंसर जैसी बीमारी, जुकाम की तरह फैल रही है उसके लिये हमें खोज करनी पड़ेगी। हमें स्वास्थ्य की जांचों को करना पड़ेगा। मैं एम.एल.ए. बनने के बाद कई हास्पिटल्स में निरीक्षण के लिये गया। सभापतिजी, निरीक्षण रजिस्टर धूल फांक रहे थे। हमारे यहां सी.एम.एच.ओ., ब्लाक सी.एम.एच.ओ. कभी निरीक्षण करने के लिये गये नहीं। गये, तो ए.एन.एम., जी.एन.एम. और स्टाफ पर झूठी डांट मार कर आये, और 6-6, 8-8 घण्टे मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे हैं। काहे की वीडियो कांफ्रेंसिंग? तुम्हारे पास इलाज है ही नहीं, वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे हो।

मैं कहना चाहता हूं, चिकित्सा मंत्री महोदय चले गये, उनको यह कहना चाहता हूं कि वे जो जंग लगे हुए ब्लाक सी.एम.एच.ओ. और सी.एम.एच.ओ. बैठे हुए हैं उनको हटाओ और पूरे राजस्थान से हटाओ। इन व्यवस्थाओं को बदलो। व्यवस्था नहीं बदलेगी तो कोई फील नहीं करेगा कि सरकार बदली है। इधर से जो बार-बार हमले आ रहे हैं, यह व्यवस्था पैदा करके गये हैं। आज इनका हक भी है That is democratic right of ours कि हम सरकार से कहें कि सरकार, यह व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। यह व्यवस्था तब दुरुस्त होगी जब हम चीजों को ठीक करना प्रारम्भ करेंगे।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो-जो निजी चिकित्सालय हैं, उनकी फीस का बाकायदा स्टैण्डर्ड, बाकायदा बोर्ड लगाना चाहिए कि इस हास्पिटल में जुकाम की फीस इतनी होगी, बुखार की इतनी होगी, पीलिया की इतनी होगी। इसको अगर मोतियाबिंद है तो इसके आपरेशन की इतनी होगी। निःशुल्क यह होगी और शुल्क वाली चीज यह होगी। लूट है, साहब। इतनी बड़ी लूट। एक सीधा सादा आदमी, गरीब आदमी चला जाए, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आजादी के 70 साल बाद अगर कोई किसी की सुने नहीं तो हम सब लोग, दो सौ के दो सौ लोग राजस्थान के सवा सात करोड़ लोगों को क्या संदेश दे पाएंगे। मैं गया हूं एस.एम.एस. हास्पिटल। मुझ से गार्ड ने कहा कि होंगे आप एम.एल.ए., मुझे चार महीने की तनख्वाह दिलवाइये। मेरी चार महीने की तनख्वाह बाकी है। एक बुजुर्ग, मेरे बाप की जितनी उम्र का गार्ड मुझे यह बात बोलता है। मैं उनसे माफी मांगकर आया

(श्री बलवान पूनियां)

और मैंने प्रिंसिपल से बात की कि इसकी तनख्वाह चार महीने से क्यों नहीं मिल रही है। ये व्यवस्था के प्रश्न हैं। ये कांग्रेस-बी.जे.पी. के प्रश्न नहीं हैं, ये सी.पी.एम., ब.स.पा. और बी.टी.पी. के प्रश्न नहीं हैं। यह इन्सान का प्रश्न है, आदमी का प्रश्न है। हम लम्बा जीना चाहते हैं। सवा सौ साल जीना चाहते हैं। हम बहुत जीना चाहते हैं। हंसी-खुशी से जीना चाहते हैं। इसलिये आज के इस कट-मोशन चर्चा में हम यह चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार गम्भीरता से, सारे के सारे लोग, वह डाक्टर साहब, जो राजस्थान के पूरे के पूरे अधिकारी हैं, ए.सी.एस. हैं, मैंने उनसे बार-बार निवेदन किया कि आप हमें लेडी डाक्टर उपलब्ध कराइये। उन्होंने लास्ट में हाथ खड़े कर दिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप ओजस्वी वक्ता हैं। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): थोड़ा-सा सफाई पर और बोलूंगा, साहब।

पिछली बार जब सफाई की बात आई, पूरे इलाके में डेंगू का प्रसार हो गया। अब डेंगू के लिये स्प्रे करते हैं गांव में, शहर में। स्प्रे की मशीन ले करके गांव-गांव में दौड़ रहे थे। उससे पहले एक आदमी ने मुझे रोककर यह कहा कि पहले यह कीचड़ वाला पानी निकालने का प्रबंध तो करो। शहरों की गलियों को साफ तो करो, नालियों को साफ तो करो। मेरे भादरा शहर में आज भी सीवरेज का काम चल रहा है। मंत्री महोदय, काम में थोड़ी तेजी आई है आपसे बात करने के बाद लेकिन वह तेजी नहीं आई। दो बार बरसात हुई है, पूरा शहर एकदम समुद्र की तरह भरा पड़ा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी 20 वक्ता दोनों तरफ के हैं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): इसलिये मैं चाहता हूं की सफाई की एकदम दुरुस्त व्यवस्था करवाने के लिये जल्दी से जल्दी शहर में सीवरेज का काम आप कमप्लीट कराएं और जो मेरे शहर में डूम सागर, पांच, छह, सात, आठ नम्बर वार्डों में पानी भरा हुआ है, उसको निकलवाने का काम करेंगे। इस मौसम के अन्दर जैसे बीमारी, मलेरिया, डेंगू और ये बीमारियां न फैलें, इसके लिये समय-समय पर दवाइयों का छिड़काव करवाने का काम करेंगे और स्प्रे करवाने का काम करेंगे ताकि लोगों के डेंगू नहीं हो, और डेंगू से कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग महिला इस दुनिया से रुखसत न हो जाए हमें उलाहना देते हुए, हमें ओलमा देते हुए।

श्री सभापति: मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एक सैकण्ड की बात और रही है।

एस.एम.एस. हास्पिटल और पी.बी.एम. हास्पिटल, दोनों हास्पिटल ऐसे हैं, पी.बी.एम. बीकानेर का, जहां पूरे राजस्थान के पेशेंट आते हैं। मेरा तो सदन से एक छोटा सा प्रस्ताव है। एस.एम.एस. के लिये सरकार बहुत गौर करती है, इसमें कोई दो-राय नहीं। पिछली सरकार ने भी की है, रघु शर्माजी भी कर रहे हैं। फिर भी एस.एम.एस. पूरे, सारे के सारे विधायकों के पेशेंट एस.एम.एस. में आते हैं। अगर हम, फिर भी बजट की अगर कमी रहती है, अगर राजस्थान की सरकार हर एम.एल.ए. का पांच करोड़ रुपये बजट बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर देती है तो मैं मेरे विधायक कोटे से एक करोड़ रुपये एस.एम.एस. में देने की घोषणा करता हूं।

श्री सभापति: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मौका दिया, मेरे विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन के अंदर चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, मांग पर चर्चा हो रही है और अगर अपन प्रदेश की बात करें तो चिकित्सा की व्यवस्था अत्यधिक चिंतनीय और विचारणीय है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका के अलवर एडिशन में छपे 26 जून के लेख के बारे में मैं यहां पर बता रहा हूं। उसकी हैडिंग थी कि 14 साल के अंदर 28 हजार करोड़ खर्च करने पर भी शिशु-मां को बचाने के इंतजाम नहीं और उसकी सब हैडिंग थी कि प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांक में 16वें नम्बर पर रहने का बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा ही नहीं सुधरा।

माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर जो मुख्य कारण बताये गये, वह थे डाक्टर्स की कमी। दूसरा बड़ा कारण था सरकारी भर्तियां समय पर नहीं होना जिसकी वजह से आज करीब 60 हजार पद रिक्त हैं। डाक्टर सरकारी सेवा में आने के लिए उपलब्ध है, लेकिन सरकार अपनी जेब देखकर पदों की स्वीकृति देती है। जैसा कि अभी अपन ने बजट के अंदर देखा कि सरकार ने 60 हजार पद रिक्त होने के बाद भी मात्र 15 हजार की ही भर्तियां निकाली है। चौथा कारण, इसमें बताया गया कि जिला लेवल के अस्पतालों में सभी

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

तरह की सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। जब जिला में ही नहीं है तो हम यह कैसे उम्मीद करें कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वह सुविधाएं हमें मिल सकें?

माननीय सभापति महोदय, लोक सभा चुनावों से पहले मुझे खुद को स्वाइन फ्लू हुआ था और मैं मेरी जांच के लिए एस.एम.एस. अस्पताल गया। जब मैं इमरजेंसी के अंदर घुसा तो आगे से स्वागत करता हुआ कुत्ता मेरे सामने आ रहा था। अगर एस.एम.एस. के ही यह हाल है, अपन सब एस.एम.एस. की बड़ाई करते नहीं थकते। जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि आज एशिया के अंदर सबसे बड़ा आउटडोर है तो अपने एस.एम.एस. का है। अपन उसकी बड़ाई करते नहीं थकते, अपन सब जानते हैं कि एस.एम.एस. के अंदर विश्व स्तर के डाक्टर अपने पास यहां पर हैं पर जब उसकी व्यवस्था ऐसी है कि उसके अंदर से एक गली का कुत्ता निकलता हुआ आ रहा है तो अपन यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आज जो व्यक्ति सक्षम है, जो अपना खर्चा प्राइवेट हास्पिटल में जाकर उठा सकता है वह वहां पर आएगा? तो मोटे तौर पर अपन यह मानें कि सरकार जो सुविधाएं उपलब्ध करवाती है वह गरीब के लिए उपलब्ध करवाती है, गांव के लोगों के लिए उपलब्ध करवाती है। अगर ऐसी उपलब्धता सरकार गरीब के लिए और उस किसान के लिए देती है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन संस्थाओं को बंद कर प्राइवेट अस्पतालों में तब्दील कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है और सब्सिडी के तौर पर उन ग्रामीणों को दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अब अपने क्षेत्र की मांग सरकार के सामने उठाना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में चार सी.एच.सी. सेंटर्स आते हैं। मुण्डावर जो मुख्यालय उप केन्द्र पर है, दूसरा नीमराना जो दूसरे एस.डी.एम. मुख्यालय केन्द्र पर है और तीसरा शाहजहांपुर और चौथा ततारपुर।

सबसे पहले मैं मुण्डावर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बात करना चाहूंगा। यहां पर तीन कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं पर आज की तारीख में वहां पर एक कनिष्ठ विशेषज्ञ सरकार ने नहीं लगाया है। यहां पर चार मेडिकल आफिसर्स हैं, जिनके अंदर से दो, सरकार के एक मंत्री के कहने पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पर सरकार के एक मंत्री के कहने पर सी.एम.एच.ओ.

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

साहब ने प्रतिनियुक्ति कर उनके क्षेत्र में भेजा हुआ है। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे यहां पर चिकित्सक की कमी पहले ही है तो आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि साहब, मेरी मजबूरी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा तबादला सी.एम.एच.ओ. से यहां के अलावा कहीं और कर दिया जाएगा तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यह निवेदन है कि आप मेरे पर प्रेशर न करें और उनको वहीं पर प्रतिनियुक्ति पर रहने दें।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सारी प्रतिनियुक्तियां कैंसिल कर रखी हैं फिर भी मेरे यहां से डाक्टर हटाकर आपने दूसरे क्षेत्र के अंदर प्रतिनियुक्ति पर लगा रखे हैं तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र की जनता के ऊपर भी आप ध्यान दें और उन डाक्टर्स की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर आप मेरे क्षेत्र में वापस लगाने का काम करें।

(20.24 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, कनिष्ठ विशेषज्ञ, बाल रोग कार्यरत है परन्तु पर्याप्त मात्रा के अंदर स्टाफ और उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां पर बच्चों की जांच नहीं हो पाती है। अगर मैं जनरल सर्जन की बात करूं तो पद तो स्वीकृत है पर वहां पर जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं है। इसके कारण से अगर क्षेत्र में कोई छोटी-सी भी घटना हो जाती है तो डाक्टर को उसको अलवर अस्पताल में रैफर करना पड़ता है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर से करीब 60 किलोमीटर दूर पड़ता है और आप सब जानते हैं कि आज अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इतना लंबा अंतराल है, 60 किलोमीटर है, एक घंटा पहुंचने में लगता है तो रास्ते में कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर सी.एच.सी. अस्पताल काफी समय से बना हुआ है। आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी बड़ा हास्पिटल नहीं होने की वजह से अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो या तो अलवर जाना पड़ता है या जयपुर आना पड़ता है या सटे हुए हरियाणा के क्षेत्र में जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा और मेरे क्षेत्र की जनता की पहले भी यह मांग रही है कि इसको 100 बैड के अस्पताल में क्रमोन्नत कर क्षेत्र की जनता को

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

लाभ पहुंचाने के लिए आप सरकार से कहें कि वह इसका काम करे। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अगर मैं बात करूं तो मेरे क्षेत्र से नेशनल हाईवे नम्बर-8 करीब 20 से 25 किलोमीटर लंबाई के अंदर गुजरता है जिसके अंदर कई बड़े-बड़े गांव लगते हैं और दो सी.एच.सी. भी इसके ऊपर लगती हैं, शाहजहांपुर और नीमराना, जिसके अंदर जैसा कि मैंने कल बोला था कि यहां पर बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। आप सब जानते हैं कि नीमराना औद्योगिक क्षेत्र है। आज विश्व पटल पर इसकी पहचान है पर वहां पर ट्रोमा सेंटर नहीं होने की वजह से छोटे-छोटे हादसों के लिए भी आगे रैफर करना पड़ता है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर, कहीं पर भी, जहां पर भी सरकार को सहूलियत लगे, नीमराना सी.एच.सी. में या शाहजहांपुर सी.एच.सी. में ट्रोमा सेंटर बनाकर वहां की जनता को सहूलियत पहुंचाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं पर ई.एस.आई. का एक छोटा सा अस्पताल है अगर सरकार इसको क्रमोन्नत कर बड़ा करने का काम कर दे तो वहां पर लाखों लोग जो फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, उनको सुविधाएं मिल सकेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब बात करूंगा ततारपुर सी.एच.सी. की। अलवर से लेकर अगर आप बहरोड़ जाएंगे तो करीब 65 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है जिसके अंदर से अधिकतर क्षेत्र मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र से होकर निकलता है और रास्ते पर ही हाईवे के ऊपर सी.एच.सी., ततारपुर पड़ती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लंबा क्षेत्र होने की वजह से अगर बीच में भी कहीं पर दुर्घटना होती है तो या तो उस व्यक्ति को बहरोड़ भागना पड़ता है या अलवर आगे भागना पड़ता है तो निवेदन है कि ततारपुर एक मिड पाइंट है, बहरोड़ और मुण्डावर दोनों क्षेत्रों का तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सी.एच.सी. ततारपुर पर भी एक ट्रोमा सेंटर खुलवाकर वहां की जनता को सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं मई के अंदर एस.एम.एस. हास्पिटल गया था और वहां पर मेरा स्वागत एक कुत्ते ने

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

किया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए आप विशेष व्यवस्थाएं सी.एच.सी., पी.एच.सी., सब-सेंटर्स की और बड़े-बड़े अस्पतालों की सफाई के लिए करें और विशेष तौर से स्ट्रीट डाग्स के लिए कि वह वहां पर नहीं मिले और जब मान लीजिए मेरे साथ तो एकाध व्यक्ति और भी होता है, पर गांव का कोई गरीब आदमी, कोई बच्चा वहां पर पहुंच जाए तो उसकी क्या हालत बने, यह आप सब जानते हैं। कुत्ते से मेरे जैसे बड़े आदमी को जब डर लगता है तो एक छोटे बालक को तो लगेगा ही लगेगा तो इस चीज का विशेष ध्यान रखकर सरकार इसके ऊपर विशेष काम करे।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक समस्या मोटे तौर पर आती रहती है। रात के समय में जब कोई व्यक्ति अपने मरीज को लेकर सी.एच.सी. या पी.एच.सी. पहुंचता है तो एक शिकायत जरूर करता है कि साहब, मैं रात को फलां समय पर पहुंचा था और मुझे यहां पर न कोई अटेंडेंट मिला और न कोई डाक्टर मिला तो आपके माध्यम से सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक सी.एच.सी. सेंटर पर, प्रत्येक पी.एच.सी. सेंटर पर, प्रत्येक सब सेंटर पर, सब जगह पर कम से कम इमरजेंसी हाल में तो कैमरे लगवाये जाएं जिससे कि यह असुविधा वहां की जनता को नहीं हो। कल को वह शिकायत करें तो अपने पास भी एक प्रमाण हो कि डाक्टर था या नहीं था तो अपने को जांच के अंदर सहूलियत मिलेगी क्योंकि आप जब डाक्टर का पक्ष सुनेंगे तो वह कहेगा कि साहब, मैं तो पूरी रात यहीं पर बैठा हुआ था, वह आया नहीं, बिना वजह कहीं और चला गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक और निवेदन करना चाहूंगा। मैंने जैसा कहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर नेशनल हाईवे नम्बर-8 लगता है और दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। जब दुर्घटना होती है तो 108 नम्बर की एम्बुलेंस उसको सी.एच.सी. पर तो लेकर आ जाती है पर अगर दुर्घटनावश कहीं उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको मोर्चरी में पहुंचाने का काम वह नहीं करती है। उसके लिए या तो व्यक्ति को खुद का साधन लाना पड़ता है या उसको पुलिस के पास जाना पड़ता है कि वह अपनी गाड़ी के अंदर डालकर उस व्यक्ति की लाश को वहां मोर्चरी के अंदर रखवाकर आए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि मेरा हाईवे का क्षेत्र लगता है और बहुत लंबा क्षेत्र लगता है तो वहां पर कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

करवाई जाए। कल को किसी के साथ अनहोनी हो जाती है या किसी के परिजन की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम उसकी डैड बॉडी को तो अपन स-सम्मान उस मोर्चरी के अंदर पहुंचा सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। विराजिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविंद राम।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी विशेषज्ञ रहना नहीं चाहता और यह बिलकुल सच्चाई है कि आज मेरे क्षेत्र में भी तीन सी.एच.सी. हैं-खाजूवाला, पूगल और छतरगढ़, लेकिन चाहे गायनोकोलोजिस्ट हो, चाहे सर्जन हो, चाहे आर्थोपेडिक्स हो, कोई डाक्टर नहीं रहना चाहता। दूसरा यह है कि पी.बी.एम. हास्पिटल में जो लोग वर्षों से जमे हुए हैं, हम सभी आफिसर्स का ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जिन डाक्टरों को हम भगवान के रूप में देखते हैं, उनके ट्रांसफर बहुत कम होते हैं। तीसरा पाइंट, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, एक जमाना था जब कान में दर्द होता तो मां तेल गर्म करके कान में डाल देती थी, वह भी एक समय था लेकिन, आज समय बदल चुका है। अगर हम विदेशों में देखें तो अगर बड़े से बड़ा एक्सीडेंट होगा तो 10 मिनट के बाद न तो वह व्यक्ति मिलेगा जो घायल हुआ है, न वह टूटी हुई गाड़ी मिलेगी। उनको यथास्थान पर अपनी-अपनी जगह भेजकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है।

आज मैं अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे प्रदेश में नि:शुल्क दवाई की शुरूआत की। मुझे इस बात का दुख है कि जब-जब भी देश के अंदर किसी ने भी अच्छा काम किया है, हम प्रथमदृष्टया उसका विरोध करते हैं। 1848 में ज्योतिबा फूले जी ने महिलाओं में और दलितों में शिक्षा देना शुरू किया तो जो कुछ धर्म के ठेकेदार थे, जब उनकी पत्नी सावित्री देवी पढ़ाने जाती थी तो उनकी साड़ी पर कीचड़ फेंका जाता था। उसी प्रकार मुझे दु:ख इस बात का है कि गहलोत साहब ने नि:शुल्क दवाई की

(श्री गोविंद राम)

शुरूआत की, फिर भी हमारे प्रतिपक्ष के साथी उनको वाहवाही देने के बजाय, उनको समर्थन देने के बजाय यह कहते थे कि फ्री की जो दवाइयां हैं, उससे सही ट्रीटमेंट नहीं होता। यह कहकर हमने इस योजना को कमजोर किया। लेकिन आज जब कालीचरण जी सराफ बोल रहे थे तो मैं देख रहा था, उन्होंने यह कहा कि हमने नि:शुल्क दवाइयों को कम नहीं किया, हमने दवाइयों को बढ़ाने का काम किया। हमने बजट को भी बढ़ाने का काम किया है। एक दिन मैं इनको देख रहा था कि रघु जी का यह बड़ा विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि आपके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार का। लेकिन आज मैं देख रहा हूं दोनों बैठकर बहुत हंसी-ठिठोली कर रहे थे तो मुझे लगा कि वह बात बनावटी थी। रियल में यह मन से असत्य बोल रहे थे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो हमारी नि:शुल्क दवाई की योजना है, आज मुझे खुशी इस बात की है कि मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क दवाई में और जांचों में और अधिक बढ़ोतरी की है। नि:शुल्क दवाई में 104 प्रकार की दवाइयां बढ़ायी हैं और जांच भी 70 की जगह 90 की है। मैं मेरे प्रतिपक्ष के जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं, सभी हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी केन्द्र सरकार पर दबाव डालकर विदेशों की तरह पूरे देश में नि:शुल्क दवाई की व्यवस्था करो ताकि यह मांग तो खतम हो कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अन्यथा हकीकत यह है, सभापति महोदय, जो लोग हास्पिटल में जा रहे हैं, बहुत अच्छे डाक्टर भी हैं, जो सेवा-भाव से काम करते हैं। लेकिन कुछ डाक्टर कसाई का काम भी करते हैं। मरीज को कई बार छोटे-से इलाज की जरूरत होती है, प्राइवेट में एक्स-रे वालों से मिले हुए हैं, एम आर आई वालों से मिले हुए हैं। कह देते हैं कि हास्पिटल में तो एम आर आई खराब है और प्राइवेट में भेजकर उसको कसाई की तरह चुपचाप काटते हैं। कसाई दिखता है और वह कलम से चुपचाप लिख देते हैं 10 जांच, तीन हजार का बिल। मेरा एक मित्र है जयपुर के अंदर। एक्स-रे की उन्होंने दुकान खोल रखी है। मैंने पूछा यहां आस-पास हास्पिटल नहीं, यहां आपने कैसे खोल रखी है? उन्होंने छोटा-सा जवाब दिया कि कहीं कहने की जरूरत नहीं है, डाक्टरों से हमारा तालमेल है, जो भी एक्स-रे कराने आएगा, वह अपने आप भेजेंगे और उसमें जो आय होगी, उसमें आधी इनकम उसके घर हमें देनी पड़ती है। यह सिस्टम है साहब, पूरे राजस्थान में।

(श्री गोविंद राम)

सभापति महोदय, इसलिए, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज जरूरत है इस बात की, कि हमें एक ऐसी टीम बनानी चाहिए कि कम से कम डाक्टरों में सेवाभाव पैदा करें और वह ऐसा सेवाभाव पैदा करें कि आप अनावश्यक जांच ना लिखें, गरीब के साथ में लूट नहीं करें। मैं हकीकत में कह रहा हूं मैं शुगर की टेबलेट लेता हूं लेकिन जब मैं पूर्व विधायक था तो मैं एक बार यहाँ आया और मैंने मेडिकल डायरी बनवायी और मैं यहां से दवाई लेकर गया और जब पी.बी.एम. में जाकर दिखाया, आज तक मैं वह टेबलेट ले रहा हूं। वह निशुल्क ले रहा हूं अन्यथा उसमें लाखों रुपये लगते हैं। जब मैं एक पूर्व विधायक के रूप में ले सकता हूं तो जो साधारण आदमी को दी जाती है, आज लाखों रुपये का बचाव हो गया है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो नि:शुल्क दवाई की शुरूआत की है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि केन्द्र में भी योजना लागू हो और आप लोगों को वहां दबाव डालना चाहिए और पूरे देश में नि:शुल्क दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

अब हम राजस्थान की बात करें। अभी चन्द्रकांता जी ने एक बहुत गम्भीर विषय रखा। यह हकीकत है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): कि आज डाक्टर किडनी निकाल ले, इससे बुरा काम नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मैं दो साल पहले हास्पिटल गयी, हास्पिटल बंद हो गया। मैं कहता हूं जब एक विधायक के बारे में, उस टाइम बीजेपी का राज था, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी आफिस में चले जाइए आपसे अफसर ढंग से बात करेगा, लेकिन अगर हास्पिटल में जाओगे तो वह गर्दन ऊंची करके नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके पास फीस की लाइन लगी हुई है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि डाक्टरों में आप सेवाभाव जागृत करें। विशेषकर मैं बीकानेर के बारे में कहना चाहता हूं कि पीबी.एम. हास्पिटल में आपने नि:शुल्क कैंसर के जांच की घोषणा की है, उसके अंदर आपका खर्च बढ़ेगा। इसलिए आपने वहां पी.जी. की सीटें बढ़ा दीं। आज हमें कम से कम छात्रावास

(श्री गोविंद राम)

के लिये 100 बैड की और व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज वहां वेंटीलेटर नहीं हैं, हमें 40 वेंटीलेटर वहां खरीदने की आवश्यकता है। उसकी मैंने अभी लिस्ट भी बनायी थी कि आई.सी.यू. शिशु रोग हेतु 15 नग चाहिए, आई.सी.यू. सर्जरी में 15 नग, कैंसर रोग के लिये 6 नग। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इसमें हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और यदि बिना दवाई के होता है और अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि योग से इलाज होता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी फिर इतनी दवाइयां निकालकर क्यों बेच रहे हैं, क्यों बड़े-बड़े विज्ञापन दे रहे हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। कन्क्लूड करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): इसलिए अब अंध-विश्वास का समय खतम हो गया। मैं पुन: धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि इन्होंने जो इतनी व्यवस्था दी है मेडिकल साइड में, इसको हमें पूरे देश में लागू करने की व्यवस्था हो। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा और सफाई पर बोलने के लिये मुझे अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान् मानव जीवन के लिये स्वास्थ्य ही सबसे अहम है, जिसके बिना जीवन ही नहीं, प्रदेश में चिकित्सा सुविधा बेहतर करना ही हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। डाक्टरों में भी वह भावना होनी चाहिए कि हम सेवा की भावना से काम करें। मरीजों के साथ व्यवहार ही इनका इलाज है। सरकार चिकित्सकों को समुचित सुविधा देना चाहिए ताकि हड़ताल, प्रदर्शन, धरना न हो। ऐसा होने से आम जन को परेशानी झेलनी पड़ती है। राज्य सरकार को भी इस हेतु स्थायी प्रबन्ध आवश्यक रूप से करने चाहिए। चिकित्सक जो भी जांच एवं दवाई लिखे, वह नि:शुल्क उपलब्ध हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राजकीय आवासों में निवास कर रहे चिकित्सक मरीजों से देखने का अपने आवास में शुल्क लेते हैं, वह आम जनता को लूटने का काम करते हैं। इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। चिकित्सा सुविधा के साथ ही सफाई में विशेष ध्यान देने की भी आवश्यकता है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत कई स्थानों पर अस्पतालों में अच्छा

(श्री हमीर सिंह भायल)

प्रबन्ध है, लेकिन इसमें और अधिक बल देने की आवश्यकता है। सफाई से ही स्वस्थ रहा जा सकता है। अस्पतालों में मरीजों को घटाकर सुविधा के साथ ही सफाई का प्रबन्ध आवश्यक है।

सरकार द्वारा जारी बजट 2019-20 में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिये नये क्लिनिक सब-सेंटर, पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. खोलने के प्रस्ताव रखे हैं। वह क्लिनिक किस प्रकार से कितने एवं किसके द्वारा संचालित होंगे, यह प्रावधान नहीं किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधित आंकड़ों से राजस्थान स्वच्छता सेवाओं में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़े आंकड़ों के कारण हमने भामाशाह...(व्यवधान)..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी जगह पर विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें। विराजिए आप।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): स्वच्छ अभियान योजना भी इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अस्पतालों में भी चिकित्सा सुविधा मिलती है, जिससे तीस हजार से तीन लाख तक का इलाज मुफ्त होता था। मेरे क्षेत्र के कई लोगों के आपरेशन एस एम एस में मैंने स्वयं करवाए और वह स्वस्थ होकर आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिये औषधीय वन विकसित जैसी योजनाएं बनायी गयी थीं, लेकिन इस बजट में आयुर्वेदिक विभाग ही गायब है। लेबर रूम को लेकर पिछले लंबे समय से अखबारों में आ रही है। वहां का स्टाफ मरीजों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता। सरकार को लेबर रूमों की भी स्थिति को सुधारने के प्रबंध करने चाहिए। प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है। सब जगह पूरे प्रदेश में और बाड़मेर जिले में भी और मेरी विधान सभा में भी कई रिक्त पद पड़े हैं, वो भी शीघ्र भरने के लिए मैं आंकड़ा बताऊंगा। माननीय सभापति महोदय, एक ही डाक्टर के भरोसे सी.एच.सी. चलाना आम जन के लिए असुविधा है। क्षेत्र में 7 लाख की आबादी पर भी 25 वर्षों से महिला चिकित्सक नहीं है। बड़ी विडम्बना है कि यह सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है लेकिन महिला चिकित्सक न होना एक समस्या है।

माननीय मंत्री महोदय, आपने अभी डाक्टर के पद-स्थापन आदेश खूब दिये लेकिन सिवाना विधान सभा क्षेत्र में एक भी डाक्टर लगाना, सिवाना भी राजस्थान का ही एक अंग है जबकि डाक्टर के 11 पद रिक्त पड़े हैं। मोकलसर और खंडप पी.एच.सी. बिना डाक्टर के पिछले चार माह से चल रही

(श्री हमीर सिंह भायल)

है। मेरे क्षेत्र में एक मात्र पी.एच.सी. पादरू जिसकी ओ.पी.डी. पूरे जिले में सबसे अधिक है एवं विभागीय नोर्म्स भी पूरा करती है तो इस पी.एच.सी. पादरू को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाना आमजन के हित में रहेगा। जनसंख्या एवं दूरी के आधार पर भी क्षेत्र में पांच सी.एच.सी. की कमी है। वर्तमान में दो नई पी.एच.सी. खोली जाएंगी तो इसमें पूरे क्षेत्र में नई पी.एच.सी. डन्डाली और सिणेर खोली जावे। पंचायत समिति समदड़ी मुख्यालय पर भी सभी विभागों के अलावा ब्लाक लेवल अधिकारी बैठते हैं अत: चिकित्सा विभाग ब्लाक समदड़ी अलग किया जाए।

सिणधरी उपखण्ड में दो हाईवे निकलते हैं। श्रीमान जी, कई बार हादसे हुए हैं जिसमें उपचार के अभाव में जन हानि होती है। सिणधरी में ट्रोमा सेन्टर खोला जाए तो राहत मिल सकती है।

सिवाना-पचपदरा क्षेत्र के लिए, अभी जो हमारे पचपदरा से आने वाले साथी भाई मदन जी बता रहे थे कि ब्लड बैंक की मंत्री जी ने मन्जूरी दे दी है, बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं कि वहां बड़ी आवश्यकता थी, सवा सौ किलोमीटर जोधपुर और बाड़मेर, तो अगर बालोतरा में ब्लड बैंक की स्थापना हुई है तो मैं इसका स्वागत करता हूं अभिनन्दन करता हूं।

सिवाना में सी.एच.सी. वर्षों पुरानी है। एक भामाशाह की अच्छी बनाई हुई बहुत बड़ी बिल्डिंग है वहां 30 बैड हैं वहां 50 बैड करने की आवश्यकता है। समदडी के अन्दर 2013 में 30 से 50 बैड करने की घोषणा की थी। और समदड़ी की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो इतनी पुरानी और जर्जर स्थिति में है, मेहरबानी करके उसके लिए भी अगर बजट दिया जाए तो उस बिल्डिंग की हालत सही हो जाए, उस भवन में आज की तारीख में बरसात होती है तो डाक्टर बाहर आकर देखते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन रहेगा। मेरे क्षेत्र में पिछली भा.ज.पा. सरकार में एक पी.एच.सी. और तीन भवन ...

श्री सभापति: कनक्लूड करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): आदरणीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 9 करोड़ 95 लाख के कार्य हुए थे, अभी भी मैं निवेदन करूंगा कि बाड़मेर जिले में कुल डाक्टर्स के 266 पद में

(श्री हमीर सिंह भायल)

से 112 पद रिक्त हैं, एएनएम में 1133 में से 440 और मेरे सिवाना में टोटल पैरामेडिकल स्टाफ सहित 114 रिक्त पद पड़े हैं, इनको भरने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, एक प्रार्थना है। पूरे बालोतरा ...

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा। विराजिए, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए, अंकित नहीं होगा। प्लीज, सहयोग करें, विराजिए। श्रीमती इन्द्रा।

माननीय सदस्या, आपको पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही आप बोलें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सभापति महोदय, मैं तो कम ही बोलती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

आपके माध्यम से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने 2019-20 के बजट में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की है जिससे ग्रामीण परिवेश के लोगों को बहुत ही सुविधा मिल पायेगी और अच्छे फायदे मिल पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी।

सभापति महोदय, हम बताना चाहेंगे कि पिछली भा.ज.पा. सरकार ने एक एम.एम.यू. (मेडिकल मोबाइल यूनिट) करके दो बसें संचालित की थीं। हमको ध्यान है कि हरी झण्डी दिखाने के टाइम वो हमको दिखी और जनता को भी उसी टाइम दिखी, उसके बाद में सब लोग उस एम.एम.यू. को भूल चुके थे। अभी चुनाव जीतने के बाद में जब मैंने पहली मीटिंग ली उसमें वह रिकार्ड में पायी गयी कि एम.एम.यू. गांवों के अन्दर जाती है और गांवों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, फ्री जांचें होती हैं, डाक्टर जाते हैं, सभी दवाइयां भी उसमें रहती हैं लेकिन जब धरातल पर उसकी जांच की गई, धन्यवाद यात्रा के दौरान जब मैं गांवों में पहुंची, मैंने लोगों से मालूम किया कि यहां तुमको कोई बस दवाई देने आती है, एक भी व्यक्ति ने उस बस को

(श्रीमती इन्द्रा)

देखा हुआ नहीं बताया। किसी ने भी यह नहीं कहा कि गांवों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है या हमको कहीं इस तरीके से इलाज मिल पाता है।

सभापति महोदय, जब हमने उसकी जांच करवायी और हमने कहा कि अगर आप गांवों में जाते हो और हकीकत में इलाज कर रहे हो तो आप हमारे वाट्सएप पर डिटेल भेजिये तो सभापति महोदय, जिस प्रकार पहले व्यवस्थाएं चल रही थीं उन्होंने उसी प्रकार व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हुए मेरे मोबाइल पर पूरी लिस्ट भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, एक व्यक्ति को फोटो भेजते हैं, दो का भेजते हैं, इससे ज्यादा फोटो किसी की भेजते नहीं हैं। कई बार बच्चों को खड़ा करके फोटो बनाकर और भेजते रहते हैं। जब हमने ब्लाक सी.एम.एच.ओ. को भेजकर उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी तो ब्लाक सी.एम.एच.ओ. की तरफ से उसमें स्पष्ट लिखा गया ...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, कृपया शांत रहें। शांत रहें, माननीय। प्लीज, डिस्टर्ब नहीं करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): उसमें बताया गया कि जिस डाक्टर की ड्यूटी एम.एम.यू. में लगा रखी है वो डाक्टर तो ट्रेनिंग करने यहां जयपुर में है। सभापति महोदय, ऐसी व्यवस्थाएं हमको देखने को मिल रही हैं, इन व्यवस्थाओं को ठीक करना अति आवश्यक है और सरकार का जो अनावश्यक खर्चा है वो काफी बढ़ रहा है, इनके माध्यम से लाखों रुपया महीने का खर्च हो रहा है और इनका पता नहीं, किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। 15 प्रकार की जांचें उसमें दे रखी हैं लेकिन जांच का एक भी सामान नहीं है। सारी बस आज की कंडीशन में खराब पड़ी हैं लेकिन फिर भी उसका रिकार्ड आ रहा है और उसका पैसा जा रहा है तो, सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी को अवगत कराना चाहेंगे कि इसकी जांच करवायी जाए और इनकी व्यवस्थाएं ठीक करवायी जाएं।

सभापति महोदय, 2019-20 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य के विभिन्न अस्पतालों में कुछ 500 बैड बढ़ाये जाने की घोषणा की है, हम माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें भी बौंली के अन्दर 30 बैड का हास्पिटल, 1955 में बौंली का हास्पिटल खुला और आज इतने लम्बे टाइम से, चार-पांच साल तो मुझे खुद को देखते हुए हो गये कि उसमें बराबर बैड बढ़ाने की मांग चलती आ रही है, तो हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि उसमें 20 बैड बढ़ाकर 50 बैड का किया जाए।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सर, अभी तो आधा ही नहीं बोला।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें आप।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जनरल सर्जन का पद लम्बे समय से रिक्त पड़ा है। साथ में बामनवास क्षेत्र में कई डाक्टर, नर्स, कम्पाउंडरों की जगह बिलकुल खाली पड़ी है जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। बौंली और बामनवास में दोनों ब्लाक में अभी लगभग 60 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि हम उम्मीद करते हैं ये पद जल्दी से भरे जाएंगे।

सभापति महोदय, हम एक और दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगी कि पिछली गवर्नमेंट में कई सारे जो पीएचसी, वे पीपीपी मोड पर दिये गये।

श्री सभापति: समाप्त करें। विराजिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सभापति महोदय, थोड़ा 2 मिनट और दे दें।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): धन्यवाद।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सर, एक मिनट।

श्री सभापति: विराजिए। आप एक मिनट विराजिए। महेन्द्र जी, आप विराजिए।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सर, समय बढ़ाना है।

श्री सभापति: बढ़ा देंगे। अभी टाइम है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

शासकीय वक्तव्य

'सुपर-30' फीचर फिल्म पर जीएसटी की छूट

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं एक सूचना आपके माध्यम से पूरे सदन को देना चाहता हूं कि 'सुपर 30' फिल्म इस सप्ताह रिलीज हुई है। यह फिल्म आनंद कुमार नामक भारतीय गणितज्ञ एवं शिक्षाविद् पर आधारित है। जो गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों को वर्ष 2002 से आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाकर, उन्हें चयनित करवाते हैं जिससे उनका देश के अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हो सके। यह फिल्म सामाजिक सरोकार से परिपूर्ण है तथा गरीब युवाओं व छात्रों को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है। जो समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस फिल्म को राजस्थान में प्रदर्शन पर राजस्थान जीएसटी की सम्पूर्ण छूट देने की घोषणा की है।

श्री सभापति: श्री रामलाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सेवाएं पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, 5 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करनी है। महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ही अपनी बात कहें। प्लीज, सहयोग करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं कल बोल लूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। शांत रहें। माननीय मंत्री महोदय, प्लीज शांत रहें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रहार करे, थप्पड़ मारने का काम करे तो उसके खिलाफ 323, 341 के अंदर मुकदमा दर्ज होता है। अगर

(श्री रामलाल शर्मा)

चोट उससे ज्यादा है तो उसके खिलाफ 324 के अंदर चालान पेश किया जाता है। अगर चोट उससे भी कहीं अधिक है तो उसके खिलाफ 325 की धाराओं में चालान पेश किया जाता है। अगर चोट उससे भी ज्यादा घातक है तो उसके ऊपर 307, प्राण घातक हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। अगर किसी को मृत्यु कारित करने का आरोपी माना जाता है तो उसके खिलाफ 302 के अंदर चालान पेश किया जाता है।

सभापति महोदय, यह सदन उन लोगों के खिलाफ कौनसी कार्यवाही कर रहा है जो इस राजस्थान के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से मौत के कगार पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सदन के सभी माननीय सदस्यों ने यह चिंता जाहिर की है कि मिलावट के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गम्भीर बीमारियों के अंदर लोगों को पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं इस सदन के माध्यम से चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ, जो मिलावट के माध्यम से लोगों को मौत के मुंह में भेजने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। उनको उम्र कैद की सज़ा हो। अगर वे दोषी पाए जाएं तो उनको मौत की सजा, फांसी के तख्ते पर भी लटकाया जाए तो मेरे खयाल से कम होगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज हम सबका सौभाग्य है कि इस सदन के सदस्य रहे, लोक सभा के भी सदस्य रहे और जिनकी सेवाओं की राजस्थान ही नहीं अन्य प्रदेश के लोग भी सराहना करते हैं, ऐसे डा. करण सिंह जी हमारे बीच में चिकित्सा की मांग को सुनने के लिए उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे चिकित्सक का, जिन्होंने एसएमएस की सेवाएं देते हुए इस एसएमएस हास्पिटल का मान बढ़ाने का काम किया।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सभी माननीय सदस्यों की चिंता थी कि एसएमएस के अंदर बहुत अधिक भार है। आप क्यों नहीं नीति बनाकर 30 किलोमीटर की परिधि में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल खोलने का काम करें। आप बगरू के अंदर खोलें। आप चाकसू के अंदर खोलें। आप बस्सी के अंदर खोलें। आप चौमूं के अंदर खोलें। आप अचरोल के अंदर खोलें। अगर 30 किलोमीटर की परिधि के अंदर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल रहेंगे तो अपने आप एसएमएस का दबाव कम होगा।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन है कि एक ऐसी बीमारी जो कि इतनी गम्भीर है कि जिससें राजस्थान में 20 से 25 हजार मरीज पीड़ित हैं। उस बीमारी का नाम मस्कुलर डिस्ट्राफी है। यह एक ऐसी गम्भीर बीमारी है जिसमें 7-8 साल की अवस्था में यह बीमारी शुरू होती है। उसकी मांसपेशियां जकड़ना शुरू होती हैं। उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं। 10 साल की उम्र में वह मरीज व्हील चेयर पर पहुंच जाता है। जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ वह 15 से 20 साल की जिंदगी जीता है। ज्यादा से ज्यादा 20 साल की उम्र में यह दुनिया छोड़कर के उसको जाना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि ऐसी गम्भीर बीमारी जिसके राजस्थान में 15 से 20 हजार मरीज हैं, उनके इलाज के प्रति चिकित्सा मंत्री किस तरह की पद्धति को अपनाते हैं, किस तरह से बाहर के डाक्टरों की सेवाएं लेकर, वह अपनी संवेदनशीलता दिखाने का काम करें।

सभापति महोदय, जितने भी माननीय सदस्य हैं, उन्होंने रिक्त पदों की चिंता जाहिर की है। अगर कहीं आर्थोपैडिक का डाक्टर है तो वहां एनेस्थिसिया का डाक्टर नहीं है। अगर एनेस्थिसिया का डाक्टर है तो वहां सर्जन नहीं है। सर्जन अगर कहीं है तो वहां स्वीपर नहीं है। स्वीपर है तो टेक्निशियन नहीं है। आप राजस्थान की जितनी भी सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं, उनको उठाकर के देख लें, आप उनके आपरेशन के आंकड़े तो मंगाकर देखें कि वे कर क्या रहे हैं? मेरा दावा है कि राजस्थान में सीएचसीज जहां आपने सर्जन लगा रखे हैं, उनमें बहुत कम सीएचसीज ऐसी हैं जहां सर्जरी का काम होता है। बाकी सब जगह नहीं। मुझे वह चीजें बयां करने की जरूरत नहीं है, जो अन्य माननीय सदस्यों ने की हैं।

सभापति महोदय, इस बजट में होम्योपैथिक चिकित्सा और आयुर्वेद के लिए बजट के अंदर भी प्रावधान नहीं किया। इनके लिए हम क्या करने वाले हैं। इसकी चिंता भी जाहिर नहीं की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगा कि होम्योपैथिक के कम से कम उपखण्ड स्तर पर चिकित्सालय खुलें। आयुर्वेद के जो औषधालय हैं, उनके अंदर कम से कम दवाइयां, जड़ी-बूटी तो पहुंचे, ताकि एक बेहतरीन सेवाएं वे दे सके।

सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा है लेकिन फिर भी मैं बयां कर रहा हूं। एसएमएस हास्पिटल के अंदर बीपीओ की डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों के साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ है, 4 साल का कोर्स करने के बाद उन

(श्री रामलाल शर्मा)

विद्यार्थियों को बताया गया कि हमने तो आरसीआई से रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। जब आपने आरसीआई से रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो यह बच्चे कहीं प्रेक्टिस नहीं कर सकते। बच्चे कहीं आवेदन नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि इन बच्चों का समय खराब नहीं हो। इसके लिए सरकार काम करे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, निजी चिकित्सालयों की स्थिति पर सभी माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। कोई स्थान ऐसा तो बने जहां लिखा होता है कि समस्याओं का आखिरी पड़ाव।

श्री सभापति: कनक्लूड करें माननीय सदस्य। कनक्लूड करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सिर्फ 2 मिनट लूंगा। 2 से 3 मिनट में बैठा देना।

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): समस्या का आखिरी पड़ाव जो लिखा हुआ होता है, वह आएगा कहां से? गांव का रहने वाला पीड़ित है, वह कहता है कि सुधार करो। जिले में आते हैं तो जिले के कलेक्टर से कहते हैं तो वह भी कहते हैं कि ऊपर देखो। अब यह सदन भी अगर चिंता जाहिर कर रहा है तो आखिरकार समस्याओं का आखिरी पड़ाव है कहां?

सभापति महोदय, निजी चिकित्सालयों में जिसकी लूट चल रही है, आप राजस्थान की एक कमेटी ऐसी बनाएं जो सभी हास्पिटलों की समीक्षा करें और जो आवश्यक हो वही इलाज करें। जिन बीमारियों का इलाज सिर्फ मेडिसिन से हो सकता है, सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के क्रिया कलाप करने वाले हास्पिटलों के ऊपर रोक लगाने का काम करें।

सभापति महोदय, जो निजी महाविद्यालय हैं और उनके अंदर जिस तरह से फीस ली जाती है, उनके ऊपर भी आप अंकुश लगाने का काम करें।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, एक अंतिम मेरे क्षेत्र की मांग है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, भूतेड़ा मेरे यहां ग्राम पंचायत है, वहां पर पीएचसी खोलने का काम करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। विराजें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अणतपुरा, आलीसर के अंदर भी पीएचसी खोलने का काम करें।

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन है। जिस तरीके से राजनीतिक द्वेषता के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हो।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप योग्यता के आधार पर करें तो उसका स्वागत है।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मेरे यहां चौमूं सीएचसी के अंदर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए। सहयोग करें माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: सब सहयोग कर रहे हैं। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: समाप्त करें। आप विराजें। माननीय सदस्य, आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। मैं 2 मिनट में ही खतम कर देता हूं। इतने सारे वक्ता हैं बोलने वाले। एक ही चीज को बार-बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं होता।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरा सिर्फ इतना-सा कहना है कि मंत्री

(श्री रोहित बौहरा)

जी को इस पर बहुत ध्यान देना है कि आज महाविद्यालयों की जो फीस है, 15 से 25 लाख रुपए can we produce doctors like this और फिर आप

(21.00 बजे)

एक्सपैक्ट करते हो कि जो डाक्टर सिर्फ एमबीबीएस पर खर्च करेगा सवा करोड़ रुपया और फिर आप उससे सोचते हो कि वह आपकी सेवा करेगा, जब तक हम इसको नहीं सुधारेंगे, जब तक हम इस सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा, यह आपको करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि इसमें दोनों पार्टीज, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमें एकमत बनाना पड़ेगा कि हमारा क्या फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे गरीब का बच्चा भी पढ़ सके और अमीर का बच्चा भी पढ़ सके, तब तो हम उनसे कह सकते हैं कि वह देश की सेवा करें और मरीजों की सेवा करें। एक करोड़ रुपया खर्च करके कोई आपकी सेवा करने के लिए नहीं बैठा है, फिर आप सोचते हो कि वह विलेज में जाकर, गांव में जाकर आपकी सेवा करेगा? हम क्या एक्सपैक्ट कर रहे हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा और हमें यह करना पडेगा। हमारे पूर्व मंत्रीजी आज हंस रहे हैं, आज से पांच साल पहले इनको कर देना चाहिए था। इन्हीं के टाइम पर यह फीस ...(व्यवधान) मैं मजाक नहीं कर रहा माननीय मंत्रीजी, यह आपको डिसीजन लेना चाहिए था, यह भलाई का डिसीजन था। इससे पूरे प्रदेश की हालत जो चिंताजनक बनी हुई सब कह रहे हैं कि हमारे यहां वैकेंसी है, वैकेंसी लेकर जो एक करोड़ रुपये खर्च करेगा, फिर एमडी पर एडमीशन के लिए एक करोड़ रुपए खर्च करेगा वह विदेश जाएगा, वह आपके पास क्यों टिकेगा? वह आपकी सेवा करने के लिए क्यों टिकेगा यदि वह दो करोड़ रुपए खर्च करेगा?

माननीय सभापति महोदय, आज जयपुर में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ रैफरल हास्पिटल्स बने हुए हैं, सब हास्पिटल्स जो जयपुर के पैरीफेरी में बने हुए हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स हैं, they all are referral hospitals, उनका वश चलता है तो इलाज ही नहीं करते हैं। उनका काम क्या है, सिर्फ रैफरेंस करना एसएमएस हास्पिटल के लिए। यह प्रथा, यहां मंत्रीजी बैठे हैं। सीएमएचओ को कहना चाहिए, हमको फोन करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में कि आपरेशन कर दो। वह कहते हैं कि हमारे से आपरेशन नहीं होगा। वहां आपरेशन थियेटर है, वहां एनेस्थेसिस्ट है, सब काम हो सकते हैं

(श्री रोहित बौहरा)

लेकिन फिर भी यह काम क्यों नहीं हो रहा है, इसका कोई सिस्टम होना चाहिए। यदि गवर्नमेंट में डाक्टर रैफर कर रहा है तो उससे पूछना चाहिए कि यह मरीज रैफर क्यों हो रहा है? यह स्पेशलिटी नहीं है तभी रैफर होना चाहिए। यदि स्पेशलिटी उस हास्पिटल में है तो वह रैफर क्यों हो रहा है?

माननीय सभापति महोदय, आप यह देखिए कि जयपुर में एक एनजीओ है, थैलेसीमिया इंस्टीट्यूट में बोनमेरो ट्रांसप्लांट हो रहा है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे यहां से जेके लोन हास्पिटल से वे लोग कैम्प लगाते हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, विदाउट एनी चार्ज और यह सब बीपीएल बच्चे हैं, यदि उनका बोनमेरो ट्रांसप्लांट नहीं होगा तो वह जिंदगी जी भी नहीं सकेंगे, इसमें भी कमीशनबाजी चल रही है, इसमें भी कमीशनबाजी चल रही है। किस चीज पर सब वक्ता बोल रहे हैं? हमारे यहां यह नहीं है, यह नहीं है, जब तक यह बेसिक चीजें हम नहीं सुधारेंगे माननीय सभापति महोदय, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज धौलपुर हमारी पूर्व मुख्य मंत्री का जिला है, 50 प्रतिशत डाक्टरों की वैकेंसी पड़ी हुई है पांच साल से। एक साल से नहीं साहब, पांच साल से। मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री के जिले का यह हाल था तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान का क्या हाल होगा?

माननीय सभापति महोदय, इश्यू यह है हम सब बात कर रहे हैं कि हमारे यहां सीएचसी कर दो, जितने सीएचसी और पीएचसी खुले हुए हैं उसी में आप डाक्टर लगा दो तो आधी तो प्रोब्लम वहीं की वहीं सोल्व हो जाएगी। आज ब्लड बैंक के लिए हम कह रहे हैं कि हमें नए ब्लड बैंक चाहिए, एक्जिस्टिंग ब्लड बैंक में ही ब्लड नहीं है, ब्लड ही नहीं है, एग्जिस्टिंग ब्लड बैंक में ही ब्लड नहीं है क्योंकि हम लोग आपस में इस प्रथा को, हमारे ईस्टर्न राजस्थान में तो प्रथा है कि यदि खून दे दिया तो भाया, कल मर जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सबको, जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको सिखाना पड़ेगा कि जैसे ही आप ब्लड देते हो विदिन 24 आवर्स उतना ब्लड आपका बन जाता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना सा कहना है कि जब तक बेसिक चीज पर हम प्रहार नहीं करेंगे तब तक हमारी व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी।

माननीय सभापति महोदय, एक सैकंड और ले रहा हूं। जो आप बोले उससे पहले एक सैकंड की बात कर रहा हूं।

(श्री रोहित बौहरा)

सबसे बडी चीज क्या है? मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं और इस पर across the party line, चाहे वह बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मिलावटखोरों के ऊपर कोई दण्ड की प्रक्रिया होनी चाहिए, इस पर बिल लाना पड़े तो हमको बिल लेकर आना चाहिए इस विधान सभा में। हम इतने बिल लेकर आ रहे हैं, मिलावटखोरी के ऊपर हम एक बिल लेकर नहीं आए, ऐसी क्या प्रोब्लम है कि हम यह नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, दूसरा बिल हमको लाना चाहिए कि जो झोला झाप डाक्टर्स हैं उनके लिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सबने झोला छाप डाक्टर्स की बात की है, why can't we bring a bill? यह हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसी हमारी क्या मजबूरी है कि हम यह नहीं कर सकते? मेरा इतना सा कहना है। मैंने आपका समय लिया उसके लिए, आपने मुझे समय दिया उसके लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। दो मिनट का समय लिया, ढाई मिनट लगाए। राम-राम सा।

श्री सभापति: श्री कान्ति प्रसाद। श्री कान्ति प्रसाद (अनुपस्थित)।

श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। सभी सदस्यों की तरफ से, ज्यादातर की तरफ से सुझाव आता रहा, यह बात आई कि डाक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आज हम विधान सभा आए तो गेट पर हमें ज्ञापन मिले। मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि एनएचएम में जो संविदा पर आयुष चिकित्सकों को आपने रख रखा है, वह वर्षो से काम कर रहे है, उनको अनुभव भी है, जन घोषणा पत्र में अपन ने उनसे कमिटमेंट भी किया कि हम आपको नियमित करेंगे तो क्यों नहीं उनको नियमित कर दिया जाए, उसमें आप एक कंडीशन रख सकते हैं कि आपको इतने साल गांव में सर्विस देनी पड़ेगी तो वह खुशी-खुशी गांव में सेवा भी देंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा और उनके बच्चों को खुशी भी मिलेगी।

(श्री बलजीत यादव)

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आयुष नर्सेज उनको 1998 से 2013 तक मेडिकल नर्सेज के समान वेतन मिलता रहा। अब उनके वेतन में विसंगति आ गई, उनको पे-ग्रेड 3600 दिया जाता है जबकि मेडिकल नर्सेज को 4200 दिया जाता है। मैं आपसे सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई का जमाना है। वर्षों से कोई संविदा पर सेवा दे रहा है, सरकार कोई भी रही हो, यह कमिटमेंट किया कि इनका वेतन है वही आपको दिया जाएगा। अब अगर वेतन आयोग सातवां लग गया और उनको पीछे छोड़ दिया तो उनको ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वह भी सब हमारे ही हैं इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उनको भी उनके समान जब तक उनको नियमित न करें वह वेतन दिया जाए और अगर इन नर्सेज को भी नियमित कर देंगे और कंडीशन रख देंगे कि आपको इतने साल गांव में सेवा देनी पड़ेगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जनता को भी बहुत राहत मिलेगी और इन लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, कोई भी व्यक्ति जब किसी जोब में जाता है तो उसके परिवार में बड़ी खुशी का माहौल होता है, जब कोई संविदा पर भी जोब किसी को मिलती है तो एक आस जाग्रत हो जाती है कि एक न एक दिन हमें नियमित कर दिया जाएगा। उनके बच्चों का स्कूल में एडमीशन करा दिया जाता है और उसको बीच रास्ते में अगर हम छोड़ दें तो उसके बच्चों पर क्या गुजरती होगी? वह कहीं का नहीं रहता है। वह दूसरी फिर जोब भी नहीं पा सकता इसलिए सरकार इनके प्रति सहानुभूति बरतते हुए मैं चाहूंगा जल्द से जल्द इनको नियमित करे। पिछली सरकार ने नहीं किया, दिन रात इन्होंने मेहनत करके, दिन रात प्रार्थना करके यह कोशिश की कि राजस्थान में आपकी सरकार बने और आपकी सरकार बनी, अब वह बड़ी उम्मीद के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब आपके उनके घर में भी खुशियां लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनको भी खुशियां मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ज्यद्दातर जो बीमारी होती है वह मिलावटी खानपान के कारण होती है। मैंने इस सदन में कई बार इस बात को रखा। मेरे अलवर जिले में चाहे सरस का दूध हो, चाहे अमूल का दूध हो, चाहे कोई दूसरे प्लांटों में, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और किसी में अगर पकड़ने की हिम्मत हो तो मैं मंत्री जी से कहता हूं कि मेरे साथ टीम भेज देना, रंगे हाथों मैं आपको पकड़ा दूंगा। जिस दिन जिस समय

(श्री बलजीत यादव)

भेजें, मैं पकड़ा दूंगा, लेकिन पता नहीं हो क्या रहा है कि उन्हें कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। साफ-साफ यूरिया से दूध बनाकर सप्लाई होती है, सबको पता है। आप दिल्ली जाते हैं, किसी भी रिक्शेवाले को रोककर पूछ लेना कि यूरिया का दूध कौन-से गांव में कौन आदमी बनाता है। मंत्री जी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चलता रिक्शेवाला आपको नाम नोट करा, देगा फलां गांव में फलां आदमी बनाता है। कौन नकली दे रहा है। वह पहले साइकल पर चलता था, अब फार्च्यूनर में चल रहा है या आडी लेकर आ गया है। अब उसने बंगला बना लिया है, अब उसने कोठी बना ली है। उन्हें पकड़ें, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, बस तीस सैकिण्ड में अपनी बात कह दूंगा। जयपुरिया अस्पताल जो है, इसे पीपीपी मोड पर दे रखा है। सीटी स्कैन और एमआरआई की जांच होती है, इन्हें कह रखा है सीनियर सिटीजन, इनके साथ बीपीएल को 10 परसेंट करेंगे, केवल। 10 परसेंट, एक-एक महीने तक उनका नम्बर नहीं आता है। मर जाएगा एक महीने में अगर जांच नहीं होगी तो। अगर फ्री कर दिया है तो आप उसे चैक करें। अगर 10 परसेंट से ज्यादा आ जाए तो उसका पैसा उसे सरकार दे।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। श्री गोविन्द प्रसाद। अंकित नहीं होगा। विराजिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। इसके लिये जरूरी है कि स्वास्थ्य संस्थाएं खोलने के लिये सरकार द्वारा जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं तो पीएचसी मोरोली की सीएचसी अकलेरा से महज चार किलोमीटर की दूरी है तथा मोरोली गांव की जनसंख्या एक हजार है और उक्त पीएचसी कभी भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं रहा, फिर भी पीएचसी खोल दी गयी जबकि विधान सभा क्षेत्र की कोलू खेड़ी कलां जो कि सीएचसी मनोहरथाना से लगभग 25 किलोमीटर है, वहां केवल उप-स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है तथा गांव की जनसंख्या भी लगभग चार हजार है और आसपास के गांवों की जनसंख्या मिलाकर पंद्रह से बीस हजार है। रास्ता भी जंगल में होकर जाता है तथा रात के समय कोई बीमार

(श्री गोविन्द प्रसाद)

भी हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाने में डर लगता है। अत: कोलू खेड़ी कलां के उप-स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए।

ठीक इसी प्रकार पीएचसी सरडा है, जो सीएचसी अकलेरा से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ क्षेत्र में भी है। उक्त पीएचसी में अभी 60-70 प्रसव हर माह होते हैं, वहां भी स्टाफ की हमेशा ही कमी बनी रहती है। चिकित्सक का पद भी अधिकांश समय रिक्त रहता है तथा एएनएम का पद हमेशा से ही रिक्त रहा है तथा अधिकांश क्षेत्र में कम्पाउन्डर के द्वारा प्रसव कराए जाते हैं जो कि खेद का विषय है। अत: पीएचसी सरडा को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी तथा आमजन को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य सेवाएं खोलने एवं क्रमोन्नत करने के साथ -साथ यह भी आवश्यक है कि वर्तमान की सभी संस्थाएं सीएचसी, पीएचसी एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ के स्वीकृत पदों के अनुसार कार्यरत हों तथा स्टाफ के रिक्त पद तुरन्त भरे जाएं।

सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र अकलेरा के सीएचसी में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों, महिला रोग, शिशु रोग, सर्जन आदि के पद रिक्त होने के कारण सिजेरियन प्रसव की सुविधा नहीं है। अत: रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाए। इससे प्रसूता महिलाओं को 60 किलोमीटर दूर मेडिकल कालेज, झालावाड़ रैफर नहीं करना पड़ेगा।

इसके साथ ही क्षेत्र की सीएचसी मनोहरथाना एवं पीएचसी जावर में एक भी स्थायी चिकित्सक कार्यरत नहीं है, जिससे क्षेत्र की लगभग एक से सवा लाख जनसंख्या को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है।

सीएचसी अचनावर में भी मात्र एक चिकित्सक ही कार्यरत है, जिससे क्षेत्र के रोगियों को असुविधाएं हो रही हैं। अत: सभापति महोदय, मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र में सभी सीएचसी एवं पीएचसी पर चिकित्सकों एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाए।

सभापति महोदय, मनोहरथाना सीएचसी पर 108 एंबुलेंस भी बहुत पुरानी हो चुकी है। एंबुलेंस का माडल लगभग 10-12 साल पुराना है तथा आये दिन खराबी होती रहती है तथा इस स्थान पर नयी एंबुलेंस भी उपलब्ध करायी जाए।

(श्री गोविन्द प्रसाद)

चिकित्सा संस्थानों की स्वच्छता एवं साफ-सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ आज भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि सरकार द्वारा साफ-सफाई हेतु पीएचसी एवं सीएचसी पर 50 हजार रुपये प्रतिमाह तक राशि देय होती है। इसके बावजूद आज सफाई के ऐसे बुरे हालात हैं जो कि आये दिन देखने तथा पढ़ने को मिलते हैं। महोदय, इसके पीछे सबसे मुख्य बात यह है कि अस्पताल में साफ-सफाई के ठेके अपने मिलने वाले लोगों, परिचितों अथवा राजनीतिक व्यक्तियों को देना, जो सीधे ही बिना निविदा आमंत्रित किये, दिये जाते हैं तथा ऐसी स्थिति में सफाई ठेकेदार पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है। अत: मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार राज्य सरकार साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है, ठीक उसी तरह अस्पताल स्तर पर ही इसे सुनिश्चित कर लें एवं विशेष ध्यान दें।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): सभापति महोदय, सुपरविजन हेतु राज्य स्तर से समितियां गठित की जाएं। महोदय, साफ-सफाई एवं स्वच्छता हेतु सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शायद दस लाख रुपये भी कायाकल्प हेतु दिये जाते हैं, उसकी भी कही मॉनीटरिंग नहीं की जाती है, न ही किसी को पता होता है। अत: इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र में पीएचसी जावर, सरडा, चूरेलिया और गेहूंखेड़ी को क्रमोन्नत किया जाए।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। श्री इंद्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग चिकित्सा विभाग, जिसके पीछे हमारा जीवन चलता है, उस पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, जैसा कि हमारे भादरा से आने वाले सदस्य बलवान पूनियां जी ने बात उठायी कि हमारे एसएमएस अस्पताल में बहुत ज्यादा मरीजों का भार है। राजस्थान ही नहीं, आसपास के प्रदेशों के लोग भी एसएमएस अस्पताल में मरीजों को दिखाने के लिये आते हैं। एक-एक वार्ड में, गैलेरी में और बाहर मरीजों की लाइन लगी रहती है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से,

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से देश में एम्स की शाखाएं खोली गयीं, उसी प्रकार राजस्थान में एसएमएस अस्पताल की शाखाएं खोलनी चाहिए।

सभापति महोदय, जो बड़े अस्पताल हैं, जिला लेवल के अस्पताल हैं, उन्हें अगर एसएमएस की शाखा के रूप में क्रमोन्नत किया जाए तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में चिकित्सा व्यवस्था राजस्थान में बहुत अच्छी हो सकती है।

हमारे कोटपूतली में 250 बैड का बीडीएम अस्पताल है। 50 बैड बढ़ाकर के अगर वहां मेडिकल कालेज खोला जाए तो मैं मानता हूं कि आसपास से आने वाले, सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, अलवर, हरियाणा से आने वाले मरीजों को एसएमएस अस्पताल में नहीं आना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने सदन के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का विराटनगर सीएचसी, जिसका आउटडोर लगभग 800 प्रतिदिन का है, वह 50 बैड का है। विराटनगर काफी पुराना ऐतिहासिक स्थल है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि उसमें 50 बैड बढ़ाकर उसे 100 बैड किया जाए।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 25-30 किलोमीटर नेशनल हाई-वे 8 निकलता है, जहां बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। जो पावटा सीएचसी है, वह 50 बैड का है, अगर उसे क्रमोन्नत करके 100 बैड का किया जाए तो हाई-वे पर होने वाली दुर्घटनाओं से मरीजों को बचाया जा सकता है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीएचसी मेड़, 2018 के बजट में माननीया मुख्य मंत्री जी के बजट रिप्लाई में उसे सीएचसी घोषित किया गया था, लेकिन तत्कालीन सरकार की उदासीनता के कारण उस सीएचसी के आदेश जारी नहीं हो पाये। दस ग्राम पंचायतों का एक ऐसा समूह है मेड़ कस्बा, जहां हजारों लोग निवास करते हैं उस पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

इसके अलावा आंतेला हमारा एक कस्बा है जहां काफी अच्छी संख्या में लोग रहते हैं, उसको भी सीएचसी में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीएचसी बहुत कम संख्या में हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करता

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

हूं कि मेरे यहां बड़े गांव हैं जैसे बाड़ीजोड़ी, छापड़ा, पालड़ी, भांकरी, मण्ढ़ा, इन सब गांवों में पीएचसी खोले जाएं ताकि आने वाले समय में मरीजों को सुविधा उपलब्ध हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, क्योंकि जयपुर जिले के नजदीक है, हमारे साथ सबसे बड़ी विडम्बना क्या होती है कि जयपुर के आस-पास के डाक्टरों की वहां पोस्टिंग कर दी जाती है और उसके बाद वे डाक्टर सैलेरी वहां से लेते हैं और अपना डेपुटेशन कराकर जयपुर में आकर बैठ जाते हैं तथा परेशानी हम लोगों को होती है। मेरे विराटनगर सीएचसी में 14 पोस्ट स्वीकृत हैं, 14 में से 3 खाली हैं, 3 डाक्टर डेपुटेशन पर बैठे हैं, 24 घंटे की सीएचसी है, एक-एक डाक्टर भी वहां हिस्से में नहीं आता है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि डेपुटेशन तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाएं तथा 3 पद जो खाली हैं उन पदों को भरने का काम किया जाए।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, नर्सिंग स्टाफ भी मेरे वहां बहुत ज्यादा खाली है, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तुरन्त प्रभाव से नर्सिंग स्टाफ भरा जाए।

सभापति महोदय, मेरे विराटनगर और पावटा सीएचसी, दोनों में सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है। एक नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर है जहां बहुत ज्यादा मरीजों का भार रहता है और एक विराटनगर पौराणिक स्थल है जिसमें कम से कम 800-1000 के बीच में आउटडोर रहता है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मांग करता हूं कि दोनों अस्पतालों में सोनोग्राफी की व्यवस्था की जाए ताकि क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, सत्ता जब बदलती है, एक सत्ता बदलती है दूसरी सत्ता बनती है। पूरे राजस्थान की जनता इस विधान सभा की ओर देखती है। कल मैंने राजस्व पर कटौती प्रस्ताव लगाया

(श्री गिरधारीलाल)

था उसमें समय नहीं मिला। सभापति महोदय, आज जब आपकी मेहरबानी से मिला तो मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बरजांगसर की महिला सरपंच उप स्वास्थ्य केन्द्र की मांग को लेकर छह दिन से भूख हड़ताल पर ग्रामीण चौपाल पर बैठी है। सभापति महोदय, मैं रविवार को वहां गया था और आज छठा दिन है पर आज तक उनको पूछने वाला वहां नहीं पहुंचा। उस महिला सरपंच की सिर्फ भवन निर्माण की मांग है और हम बड़े-बड़े अस्पताल बनाने की बात करते हैं। गांवों के अन्दर उप स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं सीएचसी बनी हुई है। ग्राम पंचायत बरजांगसर है।

(21.24 बजे)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

कहीं भी डाक्टर, नर्स, एएनएम, सब जगह खाली है और कहीं है तो वो उपस्थित नहीं है, उपस्थिति दर्ज नहीं कराती। यह हालत मेरे विधान सभा क्षेत्र में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए मेरे क्षेत्र की मांग ही रखूंगा। श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 2 सीएचसी हैं और मैं चाहूंगा कि गुलचासर ग्राम पंचायत सबसे बड़ा क्षेत्र है, आस-पास के गांव लगते हैं, वहां पीएचसी से सीएचसी क्रमोन्नत की जाए। मेरे क्षेत्र चीतासर ग्राम पड़ता है एनएच 11 पर, बड़ा कस्बा है, वहां भी पीएचसी खोली जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र जो नोखा क्षेत्र में पड़ता है, सादासर के आस-पास बड़े गांव हैं इसलिए वहां भी पीएचसी खोली जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, समाप्त करें। हो गया आपका नहीं तो फिर 12 बजेगी। प्लीज, समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): एक सैकण्ड सर। उदरासर ग्राम पंचायत में पीएचसी खुली हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, उनको शुरू करवायी जाए। सावंतसर के अन्दर, सावंतसर, बीघा, रीड़ी, ऊपणी, पून्दरासर, सेरूणा, लक्खासर, गुलचासर, तमाम जगह जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। पदमाराम। माननीय सदस्य, तीन-तीन मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे अब।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 26 के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री पदमाराम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन, जो पाण्डवों की तपोभूमि है वहां सीएचसी है। सीएचसी के अन्दर 50 बैड का हास्पिटल है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको 100 बैड का हास्पिटल बनायें और वहां जो खाली पद हैं उनको भरने की मेहरबानी करें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां 3 पीएचसी फागलिया, बाम्बड़ला और बामणोद 6 साल से चल रही है, वहां हास्पिटल चालू है परन्तु भवन की कमी है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जल्दी से जल्दी भवन बनायें जिससे आम आदमी को सुविधा मिल सके।

मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो नि:शुल्क दवा योजना चालू की है वह बहुत अच्छी योजना है गरीब आदमी के लिए। जो गरीब है उसके जेब में पैसे नहीं है वह हास्पिटल जाएगा, पीएचसी जाएगा, उप स्वास्थ्य केन्द्र जाएगा, अपने बेटे को या अपने परिवार के किसी सदस्य को नि:शुल्क दवा मिलेगी तो उनको बहुत बड़ी सुविधा होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो निशुल्क दवा योजना चलाने वाले कम्प्यूटर आपरेटर और फार्मासिस्ट हैं उनको अभी संविदा पर रखा हुआ है और उनका मामूली ही वेतन है तो उनको स्थायी किया जाए और उनका वेतन बढ़ाया जाए तो इस योजना को लाभकारी सिद्ध करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अन्दर आप सहयोग करें। जांच योजना और नि:शुल्क दवा योजना के अन्दर आप सहयोग करें और उन संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की मेहरबानी करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र के अन्दर जो झोलाछाप डाक्टर हैं जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री पुखराज। माननीय सदस्य जो बोल नहीं पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि राइटिंग में अपनी बात मंत्री जी के पास पहुंचा दें।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अपने-अपने क्षेत्र की जो बातें उठा रहे हैं उनके बारे में आप काग्नीजेंस लेकर उनको जवाब दें। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि रिप्लाई दें। रघु जी, एक मिनट। पुखराज जी, मात्र तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जोधपुर जिले में उम्मेद अस्पताल के बाद सर्वाधिक संस्थागत प्रसव भोपालगढ़ के सीएचसी में होते हैं। वर्ष भर में करीब 3 हजार के लगभग प्रसव इस संस्थान में होते हैं। भोपालगढ़ क्षेत्र के साथ में, नागौर जिले के मूंडवा, मेड़ता, खींवसर इलाके की भी गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए यहां आती हैं लेकिन भोपालगढ़ सीएचसी में सुविधाओं की बेहद कमी है, प्रसव के दौरान कभी रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड बैंक के अभाव में ऐसे मुश्किल हालात में मजबूरन गर्भवती महिला को तत्काल जोधपुर रैफर करना पड़ता है। भोपालगढ़ सीएचसी में ब्लड बैंक की स्थापना की जाए, यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा।

दूसरा, भोपालगढ़ सीएचसी में तीस बैड का हास्पिटल संचालित है। मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के जवाब में लिखा कि 30 नहीं 100 बैड का हास्पिटल भोपालगढ़ में चालू है लेकिन उसमें 100 बैड के हिसाब से किसी तरह की कोई व्यवस्था या संसाधन नहीं है, डाक्टरों के पद खाली पड़े हैं। जहां 24 डाक्टर होने चाहिए, 100 बैड के हिसाब से वहां 7 डाक्टर लगे हुए हैं। जहां नर्सिंग स्टाफ करीब 44 होना चाहिए, उसकी जगह 3 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें 100 बैड के हिसाब से जो भी संसाधन हैं उपलब्ध करवाएं और वित्तीय स्वीकृति कर सभी पद भरने की कोशिश करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर सीएचसी सेन्टर है बनाड़, उस बनाड़ सीएचसी सेन्टर से माननीय तीन हाईवे गुजर रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, बनाड़, भोपालगढ़, कुचेरा और नागौर, जोधपुर बाईपास के जरिए, वो भी बनाड़ से जुड़ गया है तो मैं अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज को-आपरेट करें, को-आपरेट करिए, समाप्त कीजिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एक ट्रोमा सेन्टर हो जाए, बनाड़ बिलकुल सेन्टर है और बनाड में ट्रोमा सेन्टर होने की वजह से एमडीएम के अंदर जो एक बहुत ज्यादा भार बढ़ा है, वह भी कम हो जाएगा और बिलकुल तीन-चार हाईवे को टच करता हुआ बिलकुल सेन्टर पाइंट है और पूर्व सरकार ने भी बनाड़ को ट्रोमा सेन्टर घोषित करने की, इसको चालू करने का निवेदन करना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी समय बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, 10 बजे तक का समय है न।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, इंटरवीन करता हूं। 10 बजे तक का समय है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा व आयुष जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने वाले सभी माननीय पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत ही सारगर्भित सुझाव पूरे राजस्थान के कोने-कोने से माननीय सदस्यों ने आज सदन के समक्ष रखे हैं। कुल मिलाकर 341 कटौती प्रस्ताव पेश किये गये हैं। मैं सदन को और आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र उन कटौती प्रस्तावों का जवाब माननीय सदस्यों को प्रेषित कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसके प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है। जिस तरह आज के हालात हैं, बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति, दूषित खान-पान है, खान-पान में मिलावट है, जल की अशुद्धता है, हमारी जो जीवनशैली है, वह परिवर्तित जीवनशैली है और ये सारे फैक्टर्स हैं, जो एक आम आदमी के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

मैं हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि राज्य के तीसरी बार वे मुख्य मंत्री बने, हर बार वे कोई न कोई ऐसी नई योजना, ऐसी स्कीम लेकर आए कि व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के हर फेज का

(श्री रघु शर्मा)

उन्होंने अपनी योजनाओं में ध्यान रखा है और वे योजनाएं आज राजस्थान में बहुत पापूलर रूप में हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पूरे हिन्दुस्तान का जो टोटल भू-भाग है, उसका 10 प्रतिशत हिस्सा हमारे राजस्थान का है। हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां, यहां वागड़ है, मेवाड़ है, आदिवासी अंचल है, एक तरफ मगरा क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र है, अलग-अलग भौगोलिक परिस्थिति में हमारे यहां के लोग रहते हैं, रेगिस्तान के इलाके में तो बहुत छितराई हुई पापूलेशन है और इन सबके लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना एक चुनौती भरा काम है।

मुझे खुशी है इस बात की चिकित्सा विभाग के हमारे चिकित्सकों ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ अनेक वर्षों से राजस्थान के आम और अवाम की सेहत की चिंता करने का काम किया है और आने वाले समय में भी जो चुनौती हम लोगों के सामने है, उस चुनौती का मेरा विभाग बहुत बेहतर तरीके से उसका मुकाबला भी करेगा और आम आदमी को राहत भी पहुंचाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग में एक लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और अगर आशा सहयोगिनियों को हम शामिल कर लेते हैं तो करीब डेढ़ लाख लोग इस विभाग के अंदर काम करते हैं। कुछ वर्षों पुरानी बात है, 1998 से पहले क्या हालात थे, राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में, हमारे यहां पर सरकारी मेडिकल कालेज मात्र 6 थे। हमने कांग्रेस की सरकार के रहते हुए प्राइवेट सैक्टर को अनुमति दी, प्राइवेट सैक्टर में मेडिकल कालेजेज खुले। अब यह बहस का विषय मैं नहीं रखना चाहता कि बाद में इन 6 मेडिकल कालेजेज को बढ़ाकर हम 14 की संख्या तक पहुंचे हैं। ये किसके काल में खुले हैं, किसके काल में नहीं खुले, मैं समझता हूं चिकित्सा एक ऐसा सब्जैक्ट है जो राजनीति से परे होना चाहिए।

आज कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण सुझाव दिये और मैं सदन में आपके माध्यम से तमाम सदस्यों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में हम किस तरह आगे बढ़ें, किस तरह हमारे गरीब आदमी को, जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, हम उसको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएं।

(श्री रघु शर्मा)

सरकार की जो नीतियां पापूलर बनी हैं, उन नीतियों का लाभ हम कैसे सुनिश्चित करें और यह काम माननीय अध्यक्ष महोदय, अकेला चिकित्सा मंत्री के रूप में मैं भी नहीं कर सकता, न मेरी सरकार कर सकती है, न विभाग कर सकता है। मैं अपील करना चाहता हूं तमाम माननीय सदस्यों से कि इसमें सबका सहयोग जरूरी है क्योंकि यह एक पुनीत काम है, एक आदमी को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 17 हजार से अधिक राजकीय चिकित्सा संस्थान अभी कार्यरत हैं। ये विगत वर्षों में राजस्थान की उपलब्धि है कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, कड़ी मेहनत के साथ हमारे नेताओं की सूझ-बूझ और उनकी कार्य क्षमता के आधार पर, आप यह देखिए जिला अस्पताल हो, उप जिला अस्पताल हो, सैटेलाइट हास्पिटल हो, ये तमाम की संख्या गिनें 103 है, इनकी संख्या पूरे राजस्थान के अंदर और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बात करें तो 606 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आज राजस्थान में कार्यरत हैं। पीएचसी की बात करें तो 2090 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में आज कार्यरत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14376 सब -सेन्टर्स उप स्वास्थ्य केन्द्र आज राजस्थान के अंदर कार्यरत हैं। गांव में, ढाणी में रहने वाले आम आदमी की चिकित्सा का खयाल रखते हुए ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया है। शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पांच शहरी सीएचसी, 139 शहरी पीएचसी भी अपनी सेवाएं वर्तमान में प्रदान कर रही हैं। राजस्थान में चिकित्सा महकमे के अंदर 51 हजार बैड की सुविधा राजस्थान सरकार के माध्यम से हम लोग अभी उपलब्ध करवा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा द्वारा राजकीय क्षेत्र में जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि अब 14 मेडिकल कालेजेज स्वीकृत हैं राजस्थान में। पन्द्रहवें मेडिकल कालेज की घोषणा की मुझे खुशी है कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इसी बजट में की है। ये जो हमारे मेडिकल शिक्षा से जुड़े हुए चिकित्सा संस्थान हैं इनमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय, बीस हजार बैड की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की हुई है वर्तमान में। आयुष के अन्तर्गत 471 यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सालय राजस्थान में संचालित हैं अभी। मैं राजकीय संस्थानों में 2008 की ओपीडी की बात करता हूं तो 12 करोड़ की ओपीडी एक साल के अन्दर पूरे राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों में हुई। अब कई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि आबादी राजस्थान की आज की अनुमानित 7 करोड़ 48 लाख है,

(श्री रघु शर्मा)

यह 12 करोड़ कैसे होगी संख्या? एक पेशेंट कई बार दिखाता है। एक पेशेंट कई बार ओपीडी में जाता है इसलिए 12 करोड़ का यह फीगर एक साल का आया है, जिसको मैं मानता हूं कि संतोषप्रद फीगर है। आम आदमी की चिकित्सा सेवा में हम लोग किस तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं यह उसका द्योतक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो ओपीडी की बात है। 71 लाख लोगों को आईपीडी की सुविधा भी इस वित्तीय वर्ष में 2018 तक हम उपलब्ध करा चुके हैं और राजस्थान का ...(व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2019 है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं-नहीं। जो मैं बोल रहा हूं मुझे बोलने दीजिये 2018 की ही बात कर रहा हूं। 1 जनवरी, 2019 से लेकर 31 मई, 2019 तक आपको खुशी होगी कि राजकीय संचालित चिकित्सालयों में 1 जनवरी से 4 करोड़ 44 लाख 50 हजार 297 रोगियों ने आउटडोर ओपीडी में सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया है और इसी अवधि में 20 लाख 31 हजार 894 रोगियों ने इनडोर आईपीडी में चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर के एसएमएस हास्पिटल की बात करूं मैं, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि ओपीडी के हिसाब से जयपुर का एसएमएस अस्पताल एशिया का नम्बर-1 अस्पताल बन चुका है जहां लगभग तीस लाख की ओपीडी है सालाना और हर रोज करीब साढ़े नौ हजार रोगी इस चिकित्सालय में आते हैं और आईपीडी की बात करें हम तो 2 लाख 15 हजार की आईपीडी इस अस्पताल की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अस्पताल में वृद्धजन भी आते हैं, दिव्यांग भी आते हैं। अभी दो दिन पहले हमने एक नयी शुरूआत की है और यह शुरूआत हमने एसएमएस अस्पताल के द्वारा की है। हमारे जितने वृद्धजन हैं, जितने दिव्यांग हैं उनके लिए ओपीडी में हमने कुर्सियां लगाई हैं ताकि लंबी कतारों के बीच में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं उनको परेशानी नहीं उठानी पड़े। उनके लिए हमने कुर्सियां लगाई हैं और यह व्यवस्था की है हमने कि जो वहां बैठे हुए हैं वहीं पर उनकी जांच हो जाए, वहीं पर उनको

(श्री रघु शर्मा)

दवा मिल जाए, वहीं पर उनके सैम्पल कलेक्शन का काम हो जाए और वहीं पर उनको रिपोर्ट मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि एक प्रयोग अभी एसएमएस अस्पताल में हमने किया है, हम राजस्थान के तमाम जो मेडिकल कालेजेज से जुड़े हुए बड़े अस्पताल हैं जहां ओपीडी ज्यादा हैं हम उन तमाम अस्पतालों में यह प्रयोग आने वाले समय में करने वाले हैं, ताकि राजस्थान में जहां पर ओपीडी ज्यादा है वहां पर आने वाले हमारे वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को हम सुविधाएं मुहैया करा सकें, उनका खयाल रख सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप हमने एक नयी पहल और की है अभी। कैंसर जो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आज की दुनिया में माना जा रहा है और कैंसर के इलाज की जो व्यवस्था एसएमएस अस्पताल में थी माननीय अध्यक्ष महोदय, ओपीडी अलग थी, ऑंकोलोजी की सर्जरी अलग थी, ऑंकोलोजी की रेडियेशन अलग थी। मुझे यह बात कहते हुए सदन में खुशी है कि अभी दो दिन पहले हम एक छत के नीचे इन तीनों सुविधाओं को लेकर आये हैं जिससे राजस्थान में एक नयी शुरूआत हुई है कैंसर रोगियों के इलाज के लिए। हमारा सेवा भाव माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि 'बीमार तुम पड़ो तो तड़फते हैं हम।'

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरी तरफ इशारा कैसे किया आपने?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सर, मैंने आपकी तरफ नहीं किया है। मैं यह गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं?

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भगवान अपको लंबी उम्र दे। कभी बीमार नहीं पटके और आपकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारी हो। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान नहीं करे कैंसर किसी को हो लेकिन कैंसर जिस परिवार में हो जाता है और जो आखिरी स्टेज पर कैंसर का मरीज गुजरता है वह बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान के आम अवाम को यह बताना चाहता हूं कि एसएमएस हास्पिटल में पैलिएटिव केयर यूनिट हमने शुरू की है और उसके माध्यम से जो असहनीय दर्द होता है कैंसर पेशेंट्स को, उसको हम कम कर पाएंगे, असहनीय दर्द की पीड़ा से मुक्त हो पायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय गहलोत साहब का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने बजट के आबंटन में आशातीत वृद्धि की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है। इस वर्ष चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में 13,018 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और यह समग्र बजट का 5.96 प्रतिशत है। मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि चिकित्सा सेवाओं में गत वर्ष जो आपका बजट पेश हुआ उससे यह बजट सात प्रतिशत अधिक है। यह अलग बात है आपने आंकड़ों की कारीगरी करके 1 पाइंट तो उठा लिया बजट से लेकिन यह बजट पूरा बजट है जिसमें सात प्रतिशत राशि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के आम और अवाम के लिए ज्यादा रखी है। लिख लीजिये इसको।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): महंगाई कितनी बढ़ी है? यह भी तो बताओ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको मैं बराबर सुनता रहता हूं। उलटेसीधे आरोप लगाते हैं, तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, मैं कभी नहीं बोलता हूं। क्या तकलीफ है मैं बोल रहा हूं तो? इसमें से चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 5,315 करोड़ का बजटीय प्रावधान हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए इस वर्ष 3,249 करोड़ से अधिक रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि आपका गत वर्ष का बजट कितना था, 2,692 करोड़। अभी का बजट कितना ज्यादा है 21 परसेंट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन- 2,101 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है और माननीय नेता प्रतिपक्ष, शायद सो रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इन्होंने बड़ी चिन्ता प्रकट की जब मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया। मुझे माफ करें सर, मैं आपका सम्मान करता हूं। बजट पेश किया तो इन्होंने कहा कि आयुर्वेद पर और आयुष पर इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि बजट का आबंटन हुआ है और बजट का आबंटन ही नहीं हुआ पिछले वर्ष से

(श्री रघु शर्मा)

दस प्रतिशत ज्यादा बजट आयुर्वेद के लिए भी हमारी सरकार ने किया है और यह राशि 989 करोड़ रुपये की है।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये हम जानते हैं कि एसएमएस के ऊपर कितना भार है। शहरी क्षेत्रों में सब जगह कमोबेश यही स्थिति है। उसका भार कम करने के लिये, लोगों की परेशानी को दूर करने के लिये एक शानदार योजना आदरणीय मुख्य मंत्री जी बजट के माध्यम से लेकर आये हैं, वह है 'जनता क्लिनिक'। अब यह सवाल उठा सकते हैं कि यह कैसे खुलेगा, बजट कैसे आयेगा, डाक्टर कैसे आयेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ कहां से आयेगा, कुछ जिम्मेदारी तो हमारे पर भी छोड़ दो। मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के लोगों को जो यह सौगात दी है इसको साकार रूप देंगे, यह मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 200 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की है। 5 नये ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा की है। 50 नये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की घोषणा की है। 10 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करके प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की घोषणा की है। 10 नये सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की घोषणा की है और 500 नये बैड बढ़ाने की भी घोषणा आदरणीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गई है।

मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को एक तुलनात्मक अध्ययन बताना चाहूंगा क्योंकि आज यहां पर बहुत बातें हुई हैं। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि चिकित्सा का सब्जैक्ट राजनीति करने का नहीं है लेकिन जो तथ्यात्मक आंकड़ें हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो मुझे सदन में रखने ही पड़ेंगे। मैं यहां विशेष रूप से इधर के लोगों का नहीं, उधर के लोगों का ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2008 से लेकर 2013 के मध्य में 200 से अधिक सीएचसी खोली गई थीं कांग्रेस की सरकार के द्वारा। 700 से अधिक नई पीएचसी खोली गई थीं कांग्रेस की सरकार के द्वारा और 3500 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये थे कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 3400 शय्याओं की वृद्धि की गई थी। इन्होंने क्या किया, यह बताना भी मेरा धर्म है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में मात्र 50 सीएचसी, 60 पीएचसी और लगभग 1000 शय्याओं की वृद्धि इन्होंने 5 साल में की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वर्तमान

(श्री रघु शर्मा)

बजट की घोषणाएं मुख्य मंत्री जी ने की हैं, इनके पांच साल के कार्यकाल के बराबर तो यह पहले बजट में ही मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर महीने में चुनाव हुए थे, हमने राजस्थान की जनता को जन घोषणा पत्र के माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय ...

श्री अध्यक्ष: सवा दस तक बढ़ाया जाए।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आज की मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सवा दस बजे तक। माननीय मंत्री जी, प्लीज वाइंडअप।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जवाब तो देने दो, साहब।

श्री अध्यक्ष: जवाब दें लेकिन टाइम फ्रेम का ध्यान रखें, प्लीज।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, थोड़ी मेहरबानी करो, सरकार का पक्ष जाने दीजिए। मुझे खुशी है इस बात की कि जो वादे करके हम दिसम्बर में सत्ता में आये थे, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनी, 1998 में भी सरकार बनी थी, 2008 में भी सरकार बनी थी और अभी भी सरकार बनी है। कांग्रेस पार्टी की फितरत में यह नहीं है कि हम चुनाव के पहले अलग चेहरा रखे और चुनाव के बाद हमारा चेहरा दूसरा हो जाए। याद कीजिए 1998 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): फिर लोक सभा के चुनाव की बात चलेगी, चेहरा दिखा दिया लोक सभा में आपका। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, पुरानी मित्रता निभा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, जल्दी खतम करो आप।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस जब जब सरकार में आती है, हम जनता से जो वादे करते हैं, सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में कांग्रेस के घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाने का फैसला राजस्थान में अगर किसी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किया है और न केवल एक बार 2008 में भी किया और इस बार भी जब हम सत्ता में आये हैं तो यही काम हमने अभी किया है। यह तो चुनावी घोषणा पत्र को डस्टबीन में डालते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा मत करो पहले 21 रह गये और अबकी बार आल आउट हो, यह भी ध्यान रखो।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसा है मैं आप ही का नारा बोल देता हूं, यह जो आपने 25 सीट जीती हैं, आपको कोई ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिये कि आपकी मेहनत से जीती हैं। यह जो भाषा आप लोग बोलते हो न...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी कृपा से जीती है, आपके कर्मों से जीती हैं हमने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। मंत्री जी ...(व्यवधान) आप सीनियर आदमी हैं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। मंत्री जी ने यील्ड नहीं किया है। आप गलत परम्परा नहीं सीखें, मंत्री जी ने जगह नहीं दी है, बोल रहे हैं, don't intervene.

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर में राजस्थान की जनता ने हमको जनादेश दिया था और अभी जो लोक सभा के चुनाव हुए उसमें जनादेश भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी को मिला है। उस जनादेश पर मुझे भी कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और न अधिकार आपको है। जो जनादेश राजस्थान की जनता ने दिया है वह भी जनादेश है और यह भी जनादेश है। लोकतंत्र में यकीन रखते हो तो जनादेश का सम्मान करना सीखो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी एक बहुत बड़ी जन घोषणा चिकित्सा के क्षेत्र के लिये थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम राजस्थान के 7 करोड़ 48 लाख लोगों के लिये जो इस जमीन पर, इस माटी में पैदा हुए हैं, उनको हम क़ानूनन चिकित्सा का

(श्री रघु शर्मा)

अधिकार देंगे और मैं आज खुशी के साथ यह कह सकता हूं कि हमारी तैयारी पूरी है। आने वाले सत्र में राजस्थान की जनता के लिये अधिकार के युग की शुरूआत हम करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, राइट टू हैल्थ के माध्यम से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, गलत परम्परा नहीं, प्लीज।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिशु मृत्यु दर में 3 अंकों की गिरावट आई और मुख्य मंत्री जी ने उसको बोला। प्रतिपक्ष के माननीय नेता जी को यह भी रास नहीं आया कि यह क्यों बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी भी मेहनत हो सकती है लेकिन उससे पहले माननीय गहलोत साहब ने जो स्कीमें चलाईं, जरा उन पर भी गौर कर लो आप। वह स्कीमें इतनी शानदार थीं, उन स्कीमों को चलाने के बाद उसके जो परिणाम सामने आये, वह हमको परिलक्षित हो रहे हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिये। एक बात बताइए मेरे को, नीति आयोग हमने तो नहीं बनाया, नीति आयोग तो प्रधान मंत्री जी ने बनाया। अब कोई वृद्धिशील श्रेणी में राजस्थान दूसरे पायदान पर आ जाए तो पीठ थपथपानी चाहिये या नहीं थपानी चाहिये। हैल्थ इंडेक्स के मामले में जो वृद्धिशील 21 राज्य हैं ...(व्यवधान) मैंने कहा ही नहीं, माननीय आप इतने वरिष्ठ हैं, आप जब बोलते हैं धारा प्रवाह बोलते हैं, सच बोलते हैं या असत्य बोलते हैं, मैंने आपको कभी नहीं टोका लेकिन जब मैं चिकित्सा मंत्री के नाते जवाब दे रहा हूं, आप जवाब को सुनिए, क्या दिक्कत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी के जन्म दिन पर 2 अक्टूबर, 2011 को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने एक नई योजना की शुरूआत की 'मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना', जो हिन्दुस्तान के लिये नजीर बनी और मुझे याद है क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, वर्तमान प्रधान मंत्री जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक टीम भेजी थी। इस योजना की स्टडी करने के लिये टीम भेजी थी और वह टीम स्टडी करके गई। उन्होंने इस योजना को सराहा कि यह कैसे सम्भव हो सकता है राजस्थान के इतने बड़े भू भाग में, इतनी बड़ी जनसंख्या में नि:शुल्क दवा योजना की कल्पना कैसे की जा सकती है और अगर की जा

(श्री रघु शर्मा)

(22.00 बजे)

सकती है तो उसको मूर्त रूप कैसे दिया जा सकता है, लेकिन मैं खुशी के साथ आज सदन को यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 606 दवाइयां आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पहले नि:शुल्क दवा योजना के दायरे में लाकर रखी थीं और सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम पूरे राजस्थान में लागू है। हमारे बड़े से बड़े अस्पताल से लेकर सबसे छोटी यूनिट उप स्वास्थ्य केन्द्र तक मुफ्त दवा योजना सफलतापूर्वक राजस्थान में चल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जन घोषणा-पत्र में राजस्थान की जनता को भरोसा दिलाया था कि कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है। जिस किसी के परिवार में ये बीमारी आ जाएंगी, तो वह परिवार तबाह होने के कगार पर पहुंच ही जाता है क्योंकि इनका इलाज महंगा है। हमने कहा था, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन महंगी दवाओं को भी मुफ्त दवा योजना के दायरे में लेकर आएंगे। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट घोषणा में इन तमाम बीमारियों को शामिल करते हुए 102 दवाओं को मुफ्त दवा योजना में शामिल करने की घोषणा की है। अब राजस्थान में 712 दवा नि:शुल्क दवा योजना के दायरे में आ चुकी हैं।

इसके अलावा एक बहुत अफसोस की बात है। राजनीति में हम कितना नीचे चले जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि चिकित्सा ऐसा क्षेत्र है, जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के बीच में वोट लेने गये और क्या प्रचार किया कि दवा के नाम पर जहर बेच रही है कांग्रेस की सरकार। मेहरबानी करके आपको इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। लोगों के मन में इस मुफ्त दवा योजना के बारे में जो विश्वास पैदा हुआ, उस विश्वास को तोड़ने का पाप कर रहे हो, आप अपराध कर रहे हो और आपने किया है। मैं विनम्र शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि इनकी योजना अच्छी होगी, हमको तारीफ करनी चाहिए। योजना हमारी अच्छी होगी, तारीफ इनको करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इनका राजनीतिक हित ज्यादा बड़ा है, राजस्थान की जनता का हित छोटा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुफ्त दवा योजना के अभी मेरे पास तो आंकड़े भी हैं। आप जो बात कर रहे थे न कि मुफ्त दवा योजना में हमने बजट बढ़ाया। मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य, यह जो छह महीने का बजट मुफ्त दवा योजना में

(श्री रघु शर्मा)

हमारी सरकार ने दिया है, वह छह सौ करोड़ रुपये से ऊपर का है। आपके पांच साल के आंकड़े उठाकर देख लें। कोई वित्तीय वर्ष में अगर छह महीने के कार्यकाल में, हमारी सरकार को बने हुए छह महीने ही हुए हैं। इतने बजट का अलोकेशन अगर किसी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आपको यह ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना दम तोड़ चुकी थी और जिस तरह से दवाइयों के कुछ पत्ते रखे और पांच साल तक ड्रामा किया गया। इन लोगों ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डालने के अलावा किया क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने दवा योजना का दायरा ही नहीं बढ़ाया है, मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान में 600 नये दवा वितरण खोलने की भी घोषणा की है। हम बात करते हैं तो आधार के साथ करते हैं। कैसे करेंगे, वह भी सामने है। 600 नए दवा वितरण केन्द्र और राज्य में अभी कुल 3502 दवा वितरण केन्द्र हो जाएंगे, यह मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में यह योजना शुरू हुई। अब तक इस योजना में राजस्थान के 66 करोड़ 74 लाख मरीजों ने लाभ उठाया है। पड़ौस के राज्यों के भी आते हैं, एसएमएस हास्पिटल में भी आते हैं। आज राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह की हमारी योजनाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग भी चिकित्सा के लिये आते हैं। मैं परसों एसएमएस अस्पताल में गया था। मुझे हरियाणा का आदमी मिला। मुझे कहा कि हम आपके बहुत आभारी हैं। आपकी वजह से हमारी जिंदगी बच रही है। मुझे मध्य प्रदेश का आदमी मिला। अनेक राज्यों के लोग हमारे राज्य में चिकित्सा योजनाओं के लाभ उठाने के लिये आते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना 7 अप्रैल, 2013 को हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना की शुरूआत की और पहले चरण में मेडिकल कालेज से संबंधित, जो हमारे बड़े अस्पताल हैं, उनको शामिल किया गया। उसके बाद दूसरे चरण में 1 जुलाई, 2013 को सीएचसी को शामिल किया गया और तीसरे चरण में 15

(श्री रघु शर्मा)

अगस्त, 2013 को सीएचसी और डिस्पेंसरीज को शामिल किया गया। यह भी राजस्थान की अनूठी पहल थी कि लोगों को, जिनकी पाकेट अलाउ नहीं करती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मुफ्त जांच योजना है, यह राजस्थान के गरीब के लिये संजीवनी बनकर आयी है और इसकी शुरूआत कांग्रेस की सरकार ने की है। इसकी शुरूआत हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने की है। मुझे खुशी है कि बजट घोषणा आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने की है। हमने जांच योजना का दायरा बढ़ाकर 70 से 90 करने की घोषणा की है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय सदस्य ये सोचते हैं कि अभी यहां ही क्यों की है? यह जनादेश पांच साल के लिये हमको मिला है। आगे देखते जाइये, क्या-क्या होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एसएमएस हास्पिटल में हमारी ही सरकार के द्वारा सीटी स्कैन और एमआरआई की वृद्धजनों को... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डिबेट को बंद करें। प्लीज। मंत्री जी बोल रहे हैं तो कमेंट कर रहे हैं। आपको इंटरेस्ट नहीं है बंद कर दें, वाइंड अप कर दें। माननीय मंत्री जी सदस्यों की भावना को समझकर... माननीय 37 मिनट से ऊपर हो चुके हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): घोषणा कर दूं क्या फिर? थोड़ा बहुत बोलने दो साहब।

श्री अध्यक्ष: बोलने में तकलीफ नहीं है। आपके मित्र आपकी तरफ देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एसएमएस हास्पिटल में वृद्धजनों के लिये, बीपीएल परिवारों के लिये हमने सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करायी। अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें एंजियोग्राफी को शामिल किया है और राज्य के मेडिकल कालेज से जुड़े हुए अन्य अस्पतालों में भी यह सुविधा हम शुरू करने वाले हैं। (व्यवधान) वे तो हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहते आप कमाल कर रहे हो। अध्यक्ष महोदय, हैडिंग ही बता दूं।

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, आप एमबीए के स्टूडेंट हैं, प्रिसाइज होकर आप वाइंड अप करें ताकि कल सुबह वापस आ सकें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एनिस्ट्रिल हाइजिन की

(श्री रघु शर्मा)

कमी की समस्या से निजात दिलाने के लिए राजस्थान में गुणवत्ता के सैनेट्री नेपकिन्स, पैड्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। ये लोग पहले भी कर रहे थे। अभी जैसे सैक्रेटेरिएट में वैंडिंग मशीन लगायी। हम राजस्थान के हर शिक्षण संस्थान में, जो पब्लिक प्लेसेज हैं, सरकारी कार्य करने के जो संस्थान हैं, जगह है, आफिस हैं, सब जगह पर हमारी बहनों के लिये इस सुविधा का दायरा बढ़ाने की हमारी सरकार की कार्य योजना है और बढ़ायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इनकी चालू की हुई है हम आपकी तारीफ करते हैं कि इसमें 96 लाख परिवारों को आपने कवरेज दिया और सामान्य बीमारियों में 30 हजार और गम्भीर बीमारियों में 3 लाख रुपये का कवरेज दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी समझ में नहीं आयी। मैं जहां तक समझ सकता हूं, मैं भी पढ़ा-लिखा आदमी हूं। आपने भामाशाह योजना को लागू किया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन इसके साथ आपने जो कार्ड पकड़ाया है, उस कार्ड की मेरी नजर में कोई जरूरत नहीं थी। यह तीन सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की आपने जो फिजूलखर्ची की, राजस्थान की गरीब टैक्सपेयर जनता की कोस्ट पर, उसका जवाब आप राजस्थान की जनता को कभी नहीं दे पाएंगे। यह खर्चा किया, मैं समझता हूं योजनाएं हम भी लाते हैं। अच्छी-अच्छी योजनाएं लाते हैं लेकिन उसमें फोटो छपाओ, पार्टी का झंडा लगाओ, कमल का फूल जो आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उसको लगाओ। क्या परोसना चाहते हो? अगर आप लोगों को राहत देना चाहते हैं तो राहत में भी राजनीति करेंगे आप?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत योजना प्रधान मंत्री जी लेकर आए। पांच लाख का कवरेज है और इसमें करीब 56 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा राजस्थान में। अब आप मुझको एक बात बताएं कि यहां भी इनकी सरकार, वहां भी इनकी सरकार। प्रधान मंत्री योजना कब लेकर आए थे? एमओयू भी हो गया। लागू क्यों नहीं किया? इनकी मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारी योजना बेहतर है। आयुष्मान भारत योजना बेहतर नहीं है इसलिए राजस्थान में लागू नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात सुनने का माद्दा रखो भाई। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर, वह भी योजना चले और यह भी योजना चले, कुछ ओवरलेपिंग है। अब यह आंकड़ा जाएगा 1 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि राजस्थान

(श्री रघु शर्मा)

में भामाशाह योजना के साथ-साथ हम आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करेंगे। हो सकता है कि इनकी मुख्य मंत्री की और प्रधान मंत्री की बनती नहीं हो या प्रधान मंत्री इनकी मुख्य मंत्री को पसंद नहीं करते हों। लेकिन राज्य को क्यों भेंट चढ़ाया? राज्य के हितों को क्यों भेंट चढ़ाया? यह योजना लागू क्यों नहीं हुई? सरकार राजस्थान में आपकी, दिल्ली में आपकी, नेता आपके प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री आपकी पार्टी की। योजना लागू क्यों नहीं हुई? राजस्थान की जनता पूछना चाहती है। हम तो आपकी पार्टी के नहीं हैं। हमने लागू करके दिखाया है। आपकी नीयत में खोट थी। पार्टी विथ डिफरेंस की बात करते हो, लेकिन पार्टी विथ कांफ्लिक्ट है। पार्टी में झगड़े हैं, बार-बार उठकर दो पावर सेंटर बने हुए हैं, आप ही तो बोलते हैं। यह क्या है? प्रधान मंत्री से टकराहट का नतीजा राजस्थान की जनता ने भुगता। यह सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। इस सच्चाई को इनको सुनना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को हैल्थ और वैलनेस सेन्टर में तब्दील करने की योजना भारत सरकार के सहयोग से हम लोग प्रारम्भ करने वाले हैं और वर्ष 2019-20 में कुल 3 हजार 971 स्वास्थ्य केन्द्रों को हैल्थ एंड वैलनेस सेन्टर में हम तब्दील करने जा रहे हैं। इनमें 1817 पीएचसी होंगी, 30 यूपीएचसी होगी, 2124 उप स्वास्थ्य केन्द्र होंगे। मैं माननीय, हमारे, चले गए क्या? मालवीय नगर से आने वाले सदस्य, एक तो मैं लाया हूं क्योंकि इन्होंने मुझ जैसे आदमी को जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है। मुझको कहा कि इसको बर्खास्त कर दो। अध्यक्ष महोदय, गुनाहगार ही नहीं हूं। मुझे 302 की सज़ा कैसे दे सकते हैं? इस सदन का दुरुपयोग किया है इन्होंने। एक अख़बार में तीन दिन खबर क्या छपी, एक दिन छपी कि एक प्राइवेट चैनल ने ट्वीट किया कि 250 पदों की भर्ती चिकित्सा विभाग में होगी। हमारी तरफ से रीट्वीट हुआ कि खुशी की बात है। इसका मतलब यह है कि मुझे जानकारी है। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी? भर्ती में क्या नार्म्स अपनाए जा रहे हैं? परीक्षा किसके माध्यम से कराई जाएगी? परीक्षा का पेपर कौन सैट करेगा? दूसरे दिन आया अजमेर जिले को शामिल नहीं किया इसलिए माननीय मंत्री नाराज है। तीसरे दिन आया कि मेरे पास कोई आयुष डिपार्टमेंट के लोग आए। उन्होंने कहा कि हमको भी, एनएचएम के नार्म्स है, अध्यक्ष महोदय, हमको भी इस भर्ती का लाभ मिलना चाहिए। एनएचएम की गाइड लाइन देखी मैंने। मैं इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ

(श्री रघु शर्मा)

कहना चाहता हूं कि न तो मेरे पास कोई फाइल आई और माननीय अध्यक्ष महोदय, 1999 में रेपसार एक्ट बन गया। एक नये पैसे का भी खर्चा, चाहे आप संविदा पर भर्ती कर रहे हो, चाहे आप स्थायी भर्ती कर रहे हो, बिना वित्त विभाग के तो कोई भर्ती हो ही नहीं सकती। बिना वित्त विभाग के, बिना एनएचएम नार्म्स को फोलो करते हुए जब हमारी बदनामी होने लगी, मैंने तो भ्रष्टाचार रोकने का काम किया। मैंने तो इस अनियमितता को रोकने का काम किया। मैंने क्या गुनाह किया? और माननीय मालवीय नगर से आने वाले सदस्य मेरी बर्खास्तगी की बात करते हैं। किनको ताकत देना चाहते हो आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नये पैसे का भ्रष्टाचार अगर हो जाता, कुर्सी का लालच नहीं है हम लोगों को। इस सदन को छोड़कर, सदस्यता छोड़कर चला जाता मैं। लेकिन गैर-जिम्मेदारी का बयान देना, वह भी एक अपराध है। यह कह दिया कि इससे 600 करोड़ के नुकसान में जाएगा राजस्थान। अख़बार में छपी-छपाई बातों को अगर इस सदन में आप मुद्दा बनाते हैं, एक नये पैसे का नुकसान राजस्थान की जनता को नहीं होगा और होने भी नहीं दिया जाएगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष, इनके खिलाफ भी, आप पर अभी आ रहा हूं मैं। चिंता मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष की तरफ देखकर बोलें। माननीय श्री संयम लोढ़ा जी, प्लीज डिबेट को सुनिये। मंत्री जी, अध्यक्ष की ओर देखकर बोलें आप।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन पर पांच-पांच एसीबी के केस महापौर रहते हुए लग जाएं, विचाराधीन हों, वह मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है तो मुझे भी जवाब देने दीजिए। इनकी एनआरएचएम पर आप एक घंटे की डिबेट दे दो। हम भी अपना पक्ष रख देंगे, ये भी अपना पक्ष रख दें। कौन दूध से धुला हुआ है सामने आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत परम्परा नहीं। आपका नाम नहीं लिया है। एक तरीका है, इसमें लिखा हुआ है। आप अपनी बात कह सकते हैं। अभी यील्ड नहीं किया, प्लीज। गलत परम्परा नहीं। मंत्री जी ने अभी यील्ड नहीं किया है। आपको भी मौका मिलेगा। अभी बीच में क्यों इंटरवीन कर रहे हैं। कोई तरीका है। आप पर यदि आरोप लगेगा, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यदि मुझे अनुमति मिले तो मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठिए आप। माननीय सदस्य, मैं खड़ा हूं, प्लीज आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये नोटिस दें। अगर....

श्री अध्यक्ष: माननीय आप बैठें प्लीज। मैं खड़ा हूं। आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। मंत्री यील्ड ही नहीं कर रहा है और आप कर रहे हैं। आप पर यदि आरोप लगाया है तो आपको पूरा मौका मिलेगा जवाब देने का, but don't intervene. अध्यक्ष खड़े हैं तो भी आप बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, प्लीज, वाइंड अप करें। आलरेडी 45 मिनट हो गए हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने 15 मिनट.....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज आप इसको वाइंड अप करें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में आरोप लगाए थे इन्होंने मेरे ऊपर। मैं जवाब भी नहीं दूं उन पर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज आप अपनी बात बोलें। आप मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आपको वाइंड अप करना है। मैंने यह थोड़े ही कहा कि क्या बोलें, मैंने कहा कि आप वाइंडअप करें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी मालवीय नगर से आने वाले सदस्य ने कहा कि 8 तारीख को, 8 फरवरी थी या मार्च थी। 8 फरवरी....

श्री अध्यक्ष: माननीय, आप उनको एड्रेस कर रहे हैं या मुझको कर रहे हैं?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह आरोप लगाया कि एलबेंडाजोल, जो दवाई है वह राजस्थान सरकार प्रोक्योर नहीं कर पाई इसलिए 8 फरवरी को यह डी-वार्मिंग का काम हम नहीं कर पाए। अब इसकी सच्चाई सदन के सामने रखनी पड़ेगी। आज ही बोलें हैं ये। बायोकैम्प कंपनी के पास आपके समय में, लिख लेना आपको याद नहीं रहे तो, बायोकैम्प कंपनी के पास आपके समय में रेट कान्ट्रेक्ट था। उसने 2018 में जुलाई से लेकर 20/11/18 तक दवाई सप्लाई नहीं की। जब दवाई सप्लाई नहीं की 20/11/18 को आप ही लोगों ने नोटिस दिया उसको और दिनांक 03/01/2019 को नया रेट कान्ट्रेक्ट हमारी सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नया रेट कांट्रेक्ट होता है तो दो महीने की अवधि दी जाती है सप्लाई के लिए। सप्लाई के साथ-साथ जो दवाई हम प्रिक्योर करते हैं उसको डीवार्मिंग के लिए राजस्थान के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए भी समय चाहिए। ऐसे अनर्गल आरोप लगाने से पहले आदमी को, सदस्य को जरा सोचना चाहिए। इनको मालूम ही नहीं या छिपा गए, भारत सरकार ने दो दिन तय कर रखे हैं डीवार्मिंग के लिए, उसमें से 8 फरवरी तो है ही लेकिन दूसरा दिन 9 अगस्त है। माननीय, बारिश का टाइम होता है ज्यादा परेशानी कब होती है, बारिश के मौसम में। मैं सदन को यह कहना चाहता हूं कि हमने यह दवाई प्रिक्योर कर ली है। पूरे राजस्थान में भेज दी है, आने वाला 9 अगस्त है, 9 तारीख का हम संपादित करेंगे। इसलिए अनर्गल आरोप लगाने से बचना चाहिए।

हमारी एक बहन अजमेर से आती है, मुख्य मंत्री की घोषणा पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। आप कोई डाक्टर तो हैं नहीं, आप इस सदन में बोल रही हैं तो यह तो पूछो कि यह घोषणा हुई, यह घोषणा क्या है, यह कोई कम्पेल करने के लिए है महिलाओं को, कि आप तो कम्पेल करोगे सिजेरियन डिलीवरी कराने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विकसित देशों में बहुत प्रचलित उपाय है। जिसको हम बीकानेर से शुरू करने वाले हैं इसलिए किसी तरह की भ्रांति न तो सदन के अंदर फैलनी चाहिए और न ही सदन के बाहर फैलनी चाहिए। जो काम सरकार कर रही है वह सोच समझकर कर रही है।

(श्री रघु शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मौसमी बीमारियों के बारे में बहुत सारे प्रश्न यहां उठते हैं। चिंता का विषय भी है कि मौसमी बीमारियों पर समय रहते काबू पाना चाहिए। हमने जब से सरकार संभाली है एडवांस मैनेजमेंट, एंटीसिपेशन के आधार पर कौन सी बीमारी कौनसे मौसम में मौसमी बीमारी हो सकती है, हमने जितनी ब्रीफ्रिग मीटिंग ली है, जितना हमारे विभाग को तैनात किया है, जितने स्टाफ को तैनात किया है, जितना अवेयरनैस का कार्यक्रम लिया है, जितना स्क्रीनिंग का कार्यक्रम किया है, यह तो पांच साल के आंकड़ा बोलते हैं। किस साल स्वाइन फ्लू से कितनी मौतें हुई हैं यह कोई छिपी बात नहीं है लेकिन हमारी मंशा यह नहीं है कि राजस्थान में किसी भी एक आदमी की जान स्वाइन फ्लू से या डेंगू से या अन्य मौसमी बीमारियों से एक भी आदमी की जान जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों के सामने अपनी एक चिंता प्रकट करना चाहता हूं, 1400 करोड़ के लगभग इन्होंने जयपुर शहर में खर्च किए। कहा कि द्रव्यवती प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री तो यही की यही है। अगर आप वहां एक घंटे खड़े रह जाओ तो पांच हजार का इनाम आपको मैं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, वहां पर मच्छर पनप रहे हैं। मौसमी बीमारियां फैलेंगी। आप योजना लाए, मैं नहीं कहता कि खराब योजना है, लाए तो सड़ने के लिए तो पानी नहीं छोड़ते। पूरा उपाय तो करते, ट्रीटमेंट के प्लांट तो लगाते। जो लोग द्रव्यवती नदी के किनारे-किनारे रह रहे हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनके मौसमी बीमारियां होगी तो हमको उनका इलाज करना पड़ेगा और यह सौगात में इनसे हमको मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी चिंता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे नेशनल वायरल हैपेटाइटिस कंट्रोल का प्रोग्राम हो, चाहे स्वाइन फ्लू की बात हो, अन्य मौसमी बीमारियों की बात हो, चाहे नोन कम्युनिकेबल डिजीज हो, अध्यक्ष महोदय, अब मैं कितनी बात करूं, आप मेरे को अलाउ ही नहीं कर रहे हो। चाहे कैंसर की बात हो, 200 प्रकार के कैंसर होते हैं, उसमें से 25 टाइप के कैंसर आम आदमी में होते हैं, जिनकी गिरफ्त में आम आदमी आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक कोई सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि राजस्थान में कैंसर के पीड़ित कुल कितने मरीज हैं। हमारी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं बड़े-बड़े अस्पतालों में हैं। ग्रामीण अंचल में आदमी रहता है वह कैंसर की गिरफ्त में आ जाए, अर्ली

(श्री रघु शर्मा)

स्टेज में पता ही नहीं चलता है, वह कैंसर अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस होती है तो उसका इलाज सम्भव है।

अध्यक्ष महोदय, हमने पहली बार एस. एम. एस. हास्पिटल से एक प्रयोग शुरू किया कैंसर की रजिस्ट्री करने का। जितने पेशेंट एस. एम. एस. में चिकित्सा के लिए आएंगे उनका डाटा संधारण किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान का, रजिस्ट्री का कार्यक्रम, हमारा विभाग करेगा ताकि जिन लोगों को कैंसर जैसी भयावह बीमारी है उनको समय पर चिकित्सा मिल सके, हम उसका समय पर ट्रीटमेंट करके, उसकी जिंदगी बचा सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे, केशवरायपाटन से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि जन्मजात दिल का छेद। यह वाकई चिंता की बात है। अनेकों बच्चे हृदय रोग, दिल में छेद, वाल्व में छेद, इस बीमारी को लेकर पैदा होते हैं। गरीब परिवार में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो उस परिवार पर क्या कहर बरपता होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं, न केवल बच्चों को, जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चे हों या बड़ी उम्र के लोग हों, हमने राजस्थान में एक अभिनव प्रयोग किया है, दिल विदाउट बिल। इसके लिए गुजरात की सत्यसांई फाउण्डेशन से राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने एक एमओयू किया है। उस एमओयू की यह शर्त है कि जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनका गांधी नगर में नि:शुल्क इलाज होगा। उनके साथ जो अटेंडेंट जाएंगे उनके खान पान की भी नि:शुल्क व्यवस्था होगी। अहमदाबाद तक जाने का किराया हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी की तरफ से राजस्थान सरकार देगी। जो 18 साल से बड़े लोग हैं, तंगी हालत है, इलाज नहीं करा पाते हैं उनके लिए राजकोट में इलाज की नि:शुल्क व्यवस्था होगी। खाने-पीने व इलाज के लिए एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, और पांच हजार उनको भी राजस्थान की सरकार देगी। मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ नेतृत्व ही इस तरह के फ़ैसले कर सकता है। मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री का व्यक्तित्व मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। वह जानते हैं कि तकलीफ क्या है।

(श्री रघु शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, तम्बाकू, नशा, यह बहुत बड़ी बीमारी पैदा करने वाली चीज़ें हैं। महात्मा गांधी जी का निर्वाण दिवस 30 जनवरी, 2019, हमारी सरकार बनने के बाद सर्वोदय दिवस, हमारी सरकार ने एक दिन में 01 करोड़ 14 लाख लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। मुझे सदन में यह कहते हुए खुशी है कि पूरे हिन्दुस्तान में एक मात्र राजस्थान सरकार है जिस को इस काम के लिए डब्ल्यू एच ओ ने पुरस्कृत किया। हमारी मंशा है कि राजस्थान में नशे की आदत हमारी नौजवान पीढ़ी को बर्बाद नहीं करे। हमारे मुख्य मंत्री ने सरकार बनने के बाद ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया। अब हमारी तैयारी है कि हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाए। बहुत लोग आलोचना करते हैं कि यह क्यों कर रहे हो। मां-बाप से पैसे लेकर यहां पर पढ़ने आते हैं। उनको पता नहीं है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, यह हुक्का बार है तो धुआं ही। ई सिगरेट जिसका पता ही नहीं कहां से आई, कैसे बिक रही है। डिपार्टमेंट के द्वारा छापे मारे गए, लाखों रुपये की ई-सिगरेट हमने बरामद की। मैं आज यह कह सकता हूं कि यह अभियान हमारी सरकार निरन्तर चलाती रहेगी ताकि राजस्थान को हम नशा मुक्त राजस्थान बनाएं। राजस्थान रोग मुक्त तभी बनेगा जब राजस्थान नशा मुक्त बनेगा।

इसके अलावा मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर माननीय सदस्यों ने बहुत चिंता व्यक्त की। हमने सरकार संभाली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी बात आंकड़ों के आधार पर, मेरे पास तैयारी है, लेकिन मैं आपको आज कहना चाहता हूं, सरकार की यह मंशा है कि आम आदमी की जिंदगी के साथ मिलावटखोर खिलवाड़ कर रहे हैं, एक भी मिलावटखोर को राजस्थान में आने वाले समय में बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी सरकार बख्शेगी भी नहीं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मिलावटखोरी के खिलाफ कानून लाने की बात हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में कही है और आने वाले समय में हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि राजस्थान में, क्योंकि हमारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है, अभी हमने 98 पदों की भर्ती के लिये आर.पी.एस.सी. को लिखा है, अध्यक्ष महोदय, और आने वाले समय में अगर इसको और बढ़ाना पड़े, वित्त विभाग से और हमें स्वीकृति लेनी पड़े, लेंगे लेकिन राजस्थान में हरगिज मिलावटखोरी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि, अब देखिये, मिलावट करने

(श्री रघु शर्मा)

वाला चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बी.जे.पी. का हो, मेहरबानी करके किसी की सिफारिश मत करना। यह सिफारिश अमान्य होगी। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी के पास हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्षजी के द्वारा एक चिट्ठी गई थी। वह चिट्ठी जरा गौर कर लो कि हमारे विभाग ने ईमानदारी से सच्चाई के साथ, जहां मिलावट है तेल में, जहां मिलावट है खाद्य पदार्थ में, क्या उसको छोड़ दें। हम ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से कार्यवाही करेंगे। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिशु मृत्यु दर में तीन अंकों की गिरावट आई है। मुझे खुशी है, अभी इस बजट में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन्दिरा प्रियदर्शनी बेबी किट उपलब्ध कराने की घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इम्यून सिस्टम शरीर का कमजोर हो, हमारी बहनें, बच्चियां, महिलाएं, अगर उनमें एनीमिया की कमी हो तो उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो दूसरी मौसमी बीमारियां, क्रोनिकल डिजीज उस कमजोर इम्यून पर अटैक करती हैं और वह गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने राजस्थान में एनीमिया मुक्त राजस्थान के संकल्प के साथ इसी साल 30 जनवरी को जोधपुर से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है एनीमिया मुक्त राजस्थान। मैं पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जो राजस्थान में सफल होना चाहिए। यह आम आदमी की जिंदगी, आम आदमी की सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर टीकाकरण की भी बात हुई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2018-19 में 90 प्रतिशत टीकाकरण का काम पूरा हुआ। 22 जुलाई, 2019 से खसरा और रुबेला, राजस्थान की सरकार टीकाकरण की दिशा में यह अभियान चला रही है। नौ माह से पन्द्रह माह के करीब 2 करोड़ 26 लाख बच्चों को ये टीके आने वाले समय में लगाए जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी एश्योरेंस, राजस्थान में हमारा यह कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक चला है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के छह अस्पतालों को नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट ...(व्यवधान) अब घोषणा कर रहा हूं। अनाउंसमेंट तो कर दूं सर।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, हां, बहुत अच्छा। जल्दी घोषणा करें आप।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ।

श्री अध्यक्ष: वह घोषणा क्या कर रहे हैं, आप बताएं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चलो, अनाउंसमेंट कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, घोषणाएं हो रही हैं। आप कम-से-कम यह तो सुनें। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने इस वर्ष प्रस्तावित बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 15 हजार नियुक्तियां देने की घोषणा की है। हालांकि मैं प्रश्नकाल में बता चुका हूं। माननीय कटारिया साहब ने कहा कि तीन हजार डाक्टर्स की वैकेंसी राजस्थान के अन्दर है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 737 डाक्टर्स के पद भरने की वित्तीय स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। हम अतिशीघ्र राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थसाइंसेज के माध्यम से परीक्षा आयोजित करवा इन डाक्टरों की भर्ती का काम भी पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चे पी.जी. करने जाते हैं। हर साल 1500 का बैक-लॉग, कोई सरकार हो, क्योंकि हम बच्चों को आगे पढ़ने से भी नहीं रोक सकते हैं। 1500 का बैक-लॉग यह है और 500 का बैक-लॉग दूसरे कारणों से होता है। मैंने कैलकुलेट किया है कि करीब 2000 का बैक-लॉग हर साल चिकित्सकों के पदों का रहता है। मैं इस सदन में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने 2000 डाक्टरों के नये पद सृजित करने के लिये अपनी तरफ से वित्त विभाग को अनुरोध पत्र भेज दिया है और आने वाले समय में इसकी स्वीकृति भी कराएंगे। तो ये 2000 और 737, इस प्रकार 2737 के करीब ये पद जब भर जाएंगे तो आने वाले समय में, अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां चिकित्सक नहीं हैं, पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं है, 15000 की भर्ती यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, 737 भर्ती अभी कर रहे हैं, 2000 की स्वीकृति मिलेगी, वह भर्ती करेंगे। राजस्थान में चाहे आदिवासी अंचल हो, चाहे दूरदराज का कोई इलाका हो, हमारी सरकार एक भी जगह चिकित्साकर्मियों की कमी नहीं रहने देगी। यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं।

(श्री रघु शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आम जन को दंत रोगों के उपचार हेतु उपलब्ध सुविधाओं में बढ़ोतरी किये जाने हेतु दंत चिकित्सा अधिकारियों के 480 नये पद सृजित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप तो डाइरेक्ट घोषणा करो, प्रयास क्या किये जा रहे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राज्य सरकार मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध अस्पतालों की प्रगति एवं सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। बाड़मेर जिले में सौ एम.बी.बी.एस. सीटों की प्रवेश क्षमता का नया मेडिकल कालेज प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पूर्व में संचालित मेडिकल कालेजों में, हमारी सरकार बनने के बाद की मैं यह बात कर रहा हूं, 550 एम.बी.बी.एस. सीटों की वृद्धि की गई है। अब प्रदेश में एम.बी.बी.एस. की कुल सीटें 1950 से बढ़कर 2600 हो गई हैं।

सीकर मेडिकल कालेज के बारे में वहां के माननीय विधायक राजेन्द्र पारीकजी, वे भी चिंतित थे। कई दिनों से यह मामला अटका हुआ था। मेडिकल कालेज की घोषणा हो गई लेकिन जमीन के मामले को लेकर यह मामला लम्बित चला आ रहा था। मैंने मंत्री बनने के बाद उनको भी बुलाया। वहां पर एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के लोगों को भी बुलाया। वित्त विभाग के ए.सी.एस. को भी हमने आमंत्रित किया। उस समस्या को हमने रिजोल्व किया। अब मैं यह कह सकता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से सीकर मेडिकल कालेज को भी प्रारम्भ करने की हम योजना रखते हैं।

धौलपुर मेडिकल कालेज को लेकर माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की। बिना राजनीतिक भेदभाव के जल्दी से जल्दी वहां भी बिल्डिंग बनाने के काम की शुरुआत, हम मुख्य मंत्रीजी को वहां लेकर जाएंगे और उनके कर-कमलों से धौलपुर के नये मेडिकल कालेज के भवन की आधारशिला रखेंगे और वह काम भी आगे बढ़ेगा, अध्यक्ष महोदय।

चिकित्सा महाविद्यालयों में 46 पी.जी. सीटों में से 11 सीटें सुपर स्पेशलिटी के सब्जैक्ट्स हैं, उनकी वृद्धि हुई है।

अभी, हमारे डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी एक सरपंच प्रधानसर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग को लेकर छह दिन से उपवास पर बैठी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं कि प्रधानसर में उप स्वास्थ्य केन्द्र हम खोल देंगे।

(श्री रघु शर्मा)

माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी सरपंच का अनशन तुड़वा दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.एम.एस. अस्पताल के रोगी-भार को कम करने के लिये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन 500 बैड के नये अस्पताल को प्रारम्भ कर दिया गया है। यह भी हमारी सरकार बनने के बाद हमने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने एस.एम.एस. अस्पताल के अत्यधिक दबाव को देखते हुए 10 करोड़ रुपये की लागत से 50 बैड के एडवांस्ड मेडिकल आई.सी.यू. के साथ ही यूरोलाजी विभाग में दो करोड़ रुपये की लागत से 10 बैड का स्ट्रोक आई.सी.यू. बनाने की घोषणा की है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है।

जयपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लाक के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, यह मैं माननीय सदस्यों को आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं। इसमें हमने जो जन घोषणा-पत्र में वादा किया था आर्गन ट्रांसप्लांट का, यह जो भवन बनेगा इसमें आर्गन ट्रांसप्लांट की स्थापना की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में दानदाता के सहयोग से कैंसर रोगियों के उपचार के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से ब्रैकीथेरेपी मशीन की स्थापना एवं 2 करोड़ 61 लाख की लागत से आपातकालीन इकाई का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त अजमेर में 4 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से 4 आपरेशन थियेटर का नवीनीकरण कर अत्याधुनिक माड्यूलर ओ.टी. की स्थापना की गयी है। राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, अजमेर में आक्सीजन गैस प्लांट की स्थापना कर रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, टेबल कर दूं? एक घोषणा तो अभी अजमेर की बाकी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, अब आप प्रस्ताव करें कि मांग स्वीकार की जाए?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कर रहा हूं। इसको टेबल करने के बाद?

श्री अध्यक्ष: हां, टेबल कीजिए।

(श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) द्वारा शेष उत्तर सदन पटल पर रखा गया।)

(मा. मंत्री महोदय के शेष उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जिम्मेदारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे सौंपी है, मैं उसके निर्वहन के लिए पूरे सदन का साथ चाहता हूं और सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि-

"हर दिन इम्तिहान चुनौतियों का सिलसिला है,
शिद्दत से करूंगा जो काम मुझको मिला है,
हो सके तो हाथ तुम भी बढ़ाना साथियों,
यहीं से यह हिम्मत और हौसला मिला है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी भावना के साथ सदन से यह आग्रह करता हूं कि मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई को पारित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। कम से कम सीनियर मैम्बर को याद तो है कि हमें आगे क्या करना है।

मांग संख्या 26 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,04,41,27,20,000/- (एक सौ चार अरब इकतालीस करोड़ सत्ताईस लाख बीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 22.43 बजे शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

उर्दू विषय के शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

204. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों से उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक उर्दू विषय ऐच्छिक कर दिया गया है? क्या वर्तमान में अधिकांशत: विद्यालयों में उर्दू शिक्षक नहीं है? क्या सरकार उर्दू विषय के शिक्षकों के रिक्त पदों पर उर्दू विषय के शिक्षक लगाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 में अनिवार्य विषय तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती) के रूप में स्वीकृत है तथा कक्षा 11 व 12 में वैकल्पिक विषय के रूप में स्वीकृत है। स्टाफिंग पैटर्न के तहत नामांकन के आधार पर उर्दू विषय के पद स्वीकृत किए गए हैं।

जी नहीं। अधिकांश विद्यालयों में स्वीकृत पदों पर उर्दू शिक्षक कार्यरत हैं। राउमावि में उर्दू व्याख्याताओं के 433 स्वीकृत पदों में से 341 पदों पर व्याख्याता कार्यरत हैं। वरिष्ठ अध्यापक उर्दू विषय के भर्ती परीक्षा 2016 के 56 विज्ञापित पदों में से 51 अभ्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है एवं भर्ती परीक्षा 2018 के 131 पद उर्दू विषय के विज्ञापित हैं। उक्त 131 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन करवाया जा चुका है। आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के उपरान्त अभिस्तावना प्राप्त होने एवं पदोन्नति से आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डानुसार छात्र संख्या उपलब्ध होने पर तृतीय भाषा के रूप में उर्दू तृतीय भाषा शिक्षण करवाये जाने की सुविधा छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाता है।

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
वरिष्ठ अध्यापक	77	16	61
तृतीय श्रेणी अध्यापक (ले-द्वितीय)	206	148	58

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

उक्त उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क-1 एवं क-2 पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती 2018 लेवल-द्वितीय अन्तर्गत उर्दू विषय के 150 पदों पर सीधी भर्ती की गयी है तथा वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-द्वितीय उर्दू विषय के पद सीधी भर्ती से भरने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ जिले में पेसा एक्ट के तहत आदिवासियों पर दर्ज मुकदमे

211. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़, सुहागपुरा, धोलापानी, सालमगढ़, घंटाली थाना क्षेत्रों में आदिवासियों पर देशी शराब के कितने-कितने मुकदमे किस-किस धारा में व किन-किन थानो में दर्ज किये गये? क्या उक्त मुकदमे पांचवीं अनुसूची व पेसा एक्ट के अन्तर्गत जायज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुसूचित क्षेत्र में क्या ग्राम सभाओं के द्वारा लिये गये निर्णय को थानाधिकारियों द्वारा माना जाता है? यदि हां, तो अब तक कितने केस आये जो मान्य किये गये? अनुसूचित क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ जिले के देवगढ, सुहागपुरा, धोलापानी, सालमगढ़, घंटाली थाना क्षेत्रों में आदिवासियों पर जनवरी, 2014 से 30 जून, 2019 तक देशी शराब के कुल 487 मुकदमे दर्ज हुए हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे पेसा एक्ट से विरोधाभासी नहीं हैं और दर्ज मुकदमे आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत विधिक प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं के द्वारा पेसा एक्ट के तहत लिये गये निर्णय को थाना अधिकारियों द्वारा माना जाता है। प्रतापगढ़ के उपरोक्त पांचों थानों में शराब के उपभोग व उत्पादन के बारे में ग्राम सभाओं के पारित निर्णय प्राप्त नहीं हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में पदोन्नति में लागू रोस्टर प्रणाली

217. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 (यथा संशोधित) के तहत नियुक्त कार्मिकों के पदोन्नति से संबंधित नियमों के नियम 7(4) के अनुसार कार्मिकों की पदोन्नति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों की पदोन्नति नियमानुसार रोस्टर प्रणाली से की जा रही है? यदि हां, तो जयपुर महानगर एवं श्रीगंगानगर न्याय क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में सभी संवर्गों में जारी पदोन्नति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार के नियमानुसार समय पर पदोन्नति समिति की बैठक कर कार्मिकों की पदोन्नति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो जयपुर महानगर एवं श्रीगंगानगर न्याय क्षेत्र की विगत पांच वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के पदोन्नति हेतु रोस्टर पंजिका संधारण किया जा रहा है? यदि हां, तो जयपुर महानगर एवं श्रीगंगानगर न्याय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के रोस्टर पंजिका का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राजस्थान के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में सभी संवर्गों में सेठी आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में दिनांक 01.04.2003 से जो पदोन्नतियां की गयी हैं, उनमें वर्षवार वरीयता सूची जारी करते हुए स्वीकृत पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को नियमानुसार रोस्टर प्रणाली से पदोन्नति दी गयी है? यदि हां, तो जयपुर महानगर एवं श्रीगंगानगर न्याय क्षेत्र में सभी संवर्गों में जारी आदेशों की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला एवं सेशन न्यायाधीशों द्वारा राजस्थान जिला

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 के नियम 7(4) के अनुसार कार्मिकों को नियमानुसार पदोन्नति दी जा रही है। नियम की प्रति प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

तथापि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वारा राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 के नियम 7(4) के अनुसार पदोन्नति नहीं दी जाकर तैयार की गयी अस्थाई वरीयता सूची जारी करने के पश्चात आपत्तियां प्राप्त कर स्थायी वरीयता सूची तैयार की जाकर स्थाई वरीयता सूचियों के आधार पर पदोन्नति दी जा रही है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा द्वारा मार्च 2018 में पदोन्नतियों दी गयी थीं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4562-4564/2017 The State of Tripura & Ors Vs. Jayanta Chakraborty & Ors. तथा SLP (Civil) No 28306/2017 में पारित निर्णय क्रमश: 14 व 15 नवम्बर, 2017 में अनुसूचित जाति/जनजाति के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16((4), 16 (4)(a), 16 (4)(b) में जो प्रावधान किये गये है उनके पुनरवलोकन के लिये संवैधानिक पीठ का गठन किया जाना प्रस्तावित किये जाने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक द्वारा अनु. जाति/जनजाति के कार्मिकों को नियमानुसार रोस्टर प्रणाली से पदोन्नति नहीं दी जाकर वरीयता के अनुसार दी गई है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों से प्राप्त समेकित सूचना प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। अधीनस्थ न्यायालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को जिला एवं सेशन न्यायाधीशों द्वारा रोस्टर प्रणाली से पदोन्नति दी जा रही है।

तथापि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर एवं टोंक द्वारा रोस्टर प्रणाली से पदोन्नति नहीं दी गई अपितु नियमानुसार तैयार की गयी स्थायी वरीयता सूचियों के आधार पर पदोन्नति की जा रही है।

इसी प्रकार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा द्वारा मार्च 2018 में

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

पदोन्नतियां दी गयी थीं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4562-4564/2017 The State of Tripura & Ors Vs. Jayanta Chakraborty & Ors. तथा SLP (Civil) No 28306/2017 में पारित निर्णय क्रमश: 14 व 15 नवम्बर, 2017 में अनुसूचित जाति/जनजाति के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16((4), 16 (4)(a), 16 (4)(b) में जो प्रावधान किये गये हैं उनके पुनरवलोकन के लिये संवैधानिक पीठ का गठन किया जाना प्रस्तावित किये जाने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका। इस वजह से रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की गई।

इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देश की प्रति प्रदर्श-8 पर संलग्न है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर एवं श्रीगंगानगर द्वारा जारी पदोन्नति आदेशों की प्रतियां प्रदर्श-3 एवं प्रदर्श-4 पर संलग्न है।

(3) जी हां। समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों द्वारा नियमानुसार समय पर पदोन्नति समिति की बैठक कर कार्मिकों को पदोन्नति दी जा रही है। विवरण की प्रति प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर एवं जयपुर महानगर से प्राप्त विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का विवरण प्रदर्श-5 एवं प्रदर्श-6 पर संलग्न है।

(4) जी हां। जिला एवं सेशन न्यायाधीशों द्वारा रोस्टर पंजिका का संधारण किया जा रहा है।

तथापि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर एवं कोटा द्वारा रोस्टर पंजिका का संधारण नहीं किये जाने पर इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीशों को रजिस्टर संधारण करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर से प्राप्त रोस्टर पंजिका की छायाप्रति प्रदर्श-7 पर संलग्न है।

(5) जी हां। जिला एवं सेशन न्यायालयों द्वारा वर्षवार वरीयता सूची जारी नहीं करते हुए पूर्व की वरीयता सूची के अनुसार नियमानुसार रोस्टर प्रणाली से पदोन्नतियां दी जा रही हैं जिनका विवरण प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

तथापि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वारा पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2001 द्वारा एवं इसके पश्चात् जारी स्थायी वरीयता सूचियों को समेकित कर शीघ्रलिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग की इकजाई पृथक-पृथक अस्थायी वरीयता सूचियां तैयार की गयीं किन्तु समयाभाव एवं शीघ्र पदोन्नति देने के निर्देशों के कारण अस्थाई वरीयता सूची जारी नहीं की जा सकी है। तत्समय गठित समिति द्वारा दिनांक 01.04.2003 से तैयार की गई वरीयता सूचियों में आरक्षित वर्ग के नाम के सम्मुख उनकी श्रेणी अंकित नहीं की गई है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में दिनांक 01.04.2003 से वरीयता सूचियां तैयार की जा रही हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा द्वारा मार्च 2018 में पदोन्नतियां दी गयी थीं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4562-4564/2017 The State of Tripura & Ors Vs. Jayanta Chakraborty & Ors. तथा SLP (Civil) No 28306/2017 में पारित निर्णय क्रमशः 14 व 15 नवम्बर 2017 में अनुसूचित जाति/जनजाति के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16((4), 16 (4)(a), 16 (4)(b) में जो प्रावधान किये गये हैं उनके पुनरवलोकन के लिये संवैधानिक पीठ का गठन किया जाना प्रस्तावित किये जाने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक द्वारा अनु. जाति/जनजाति के कार्मिकों को नियमानुसार रोस्टर प्रणाली से पदोन्नति नहीं दी जाकर वरीयता के अनुसार दी गई है।

इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां प्रदर्श-6 पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगनहर/इंदिरा गांधी परियोजना में केमिकलयुक्त पानी को रोकने की कार्ययोजना

220. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

(1) गंगनहर परियोजना व इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पंजाब क्षेत्र में लगातार कारखानों/फैक्ट्रियों का कैमिकलयुक्त पानी डाला जा रहा है जिसके कारण राजस्थान में फसलों के साथ-साथ मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बीकानेर संभाग में प्रतिदिन कैंसर रोग के मरीज बढ रहे हैं। क्या सरकार स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजनाओं में कैमिकलयुक्त पानी डालने से रोकने के लिए पंजाब सरकार के साथ क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंजाब क्षेत्र में लगातार कारखानों/फैक्ट्रियों का कैमिकल युक्त पानी/अपशिष्ट सतलुज नदी में प्रवाहित किया जाता है, जो दूषित पानी अन्ततः हरिके पर प्राप्त होता है। यहां से यह पानी बीकानेर कैनाल एवं इंदिरा गांधी नहर फीडर में प्रवाहित होता है। नहरों के माध्यम से प्राप्त होने वाले पानी का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ट्रीटमेंट उपरांत पेयजल हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाता है। पंजाब क्षेत्र में प्रवाहित कैमिकलयुक्त/अपशिष्ट पानी को प्रवाहित किये जाने को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पंजाब सरकार के मार्फत लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) पंजाब क्षेत्र में कैमिकलयुक्त पानी को प्रवाहित होने से रुकवाने के संबंध में लगातार प्रयास किये गये/किये जा रहे हैं। शासन सचिव, जल संसाधन ने पत्र दिनांक 08.02.19 व 12.04.19 को तथा मुख्य सचिव, राज. सरकार ने पत्र दिनांक 01.04.19 को पोल्यूटेड वाटर रुकवाने जाने के संबंध में पंजाब सरकार से आग्रह किया है। माननीय मुख्य मंत्री ने पत्र दिनांक 16.04.19 द्वारा माननीय मुख्य मंत्री पंजाब से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु एवं राजस्थान को स्वच्छ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

निजी विद्यालयों में फीस में विसंगतियां को दूर करने की कार्ययोजना

222. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में फीस निर्धारण हेतु कोई व्यवस्था है? फीस किस आधार पर एवं किनके द्वारा निर्धारित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में निजी विद्यालयों में फीस में असमानताएं एवं विसंगतियां हैं? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या-क्या प्रावधान किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निजी विद्यालयों की फीस को सम्पूर्ण प्रदेश में एक समान रूप में निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सरकार द्वारा निजी विद्यालयों की फीस निर्धारिण हेतु राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 एवं नियम, 2017 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम एवं नियम के आधार पर विद्यालय के मुखिया द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ के तीस दिवस के भीतर-भीतर माता-पिता अध्यापक संगम का गठन किया जाता है। अधिनियम की धारा 4(1)(ग) के अनुसार माता-पिता अध्यापक संगम का गठन हो जाने के पश्चात् विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किया जाता है।

(2) प्रदेश में निजी विद्यालयों में फीस में असमानताएं एवं विसंगतियों को रोकने के संबंध में प्रावधान राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम,2016 में किये गये हैं, जिसका विवरण परिशिरष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) प्रत्येक विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं भिन्न-भिन्न होने की वजह से व्यावहारिक रूप से एक समान फीस लागू किया जाना उचित नहीं होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में रिक्त पद

223. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में स्वीकृत-कार्यरत-रिक्त पदों की सूचना मय पद रिक्त होने की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक स्वीकृत पदों के वेतन का भुगतान हेतु सरकार से प्राप्त राशि की उपलब्धता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से रिक्त पदों के वेतन के लिए प्राप्त राशि व्यय नहीं होने पर अवशेष राशि का उपयोग किस-किस मद में किया जाता है? गत तीन वर्षों में ऐसे समस्त अवशेष राशि समायोजन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध कितने पदों पर पे-माइनस पेंशन/फिक्स मानदेय और कितने पदों पर संविदा पर कार्मिक/शिक्षक लगाये गये हैं और इन्हें वेतन/मानदेय किस मद से दिया जा रहा है? प्रत्येक, पदवार एवं पदस्थापन तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में कुल कितने शिक्षक/कार्मिक अस्थाई रूप से पदस्थापित हैं? उक्त किस-किस रिक्त पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं?

(6) उक्त में से किस-किस शाखा/विभाग में कितने अस्थाई कार्मिक कार्यरत हैं और प्रत्येक को क्या-क्या जाब चार्ट आबंटित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में स्वीकृत-कार्यरत-रिक्त पदों की सूचना मय पद रिक्त होने की दिनांक से अशैक्षणिक एवं शैक्षणिक की पदवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के स्वीकृत पदों के वेतन के भुगतान हेतु सरकार से प्राप्त राशि की उपलब्धता का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली ब्लाक

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

ग्रान्ट की गणना वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 21 मार्च, 2017 में दिये गये पैमानों के आधार पर की जाती है जो परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को पिछले 03 वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार द्वारा दी गई ब्लाक ग्रान्ट की उपलब्धता का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) पे-माइनस पेंशन पर कोई भी संविदा कार्मिक एवं शिक्षक नहीं लगाये गये हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा फिक्स मानदेय पर लगाये गये कार्मिकों की (अशैक्षणिक) की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में शिक्षक/कार्मिक अस्थाई रूप से पदस्थापित नहीं है।

(6) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में शिक्षक/कार्मिक अस्थाई रूप से पदस्थापित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा व बूंदी जिले की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

224. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में चरागाह, सिवाय चक, गोचर, राजकीय कार्य हेतु आरक्षित भूमियों पर अतिक्रमियों द्वारा हजारों बीघा राजस्व भूमियों पर कब्जे कर रखे हैं? यदि हां, तो कोटा व बून्दी जिले में किस-किस तहसील, कानूनगो सर्किल, पटवार मण्डल में किस-किस अतिक्रमी द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर कब-कब से अतिक्रमण कर रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब-कब, कितना-कितना किस-किसका अतिक्रमण हटाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध अनेक कानूनी कार्यवाही नोटिस, सजा आदि की कार्यवाहियां की गई हैं? यदि हां, तो कोटा व बून्दी जिले में किस-किस प्रकार की कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार आगे भी शेष अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले की तहसीलों, कानूनगो सर्किलों, पटवार मण्डलों में अतिक्रमीवार अतिक्रमित भूमियों की सूचना अतिक्रमण दिनांक सहित परिशिष्ट-अ पर एवं बून्दी जिले की तहसीलों, कानूनगो सर्किलों, पटवार मण्डलों में अतिक्रमीवार अतिक्रमित भूमियों की सूचना अतिक्रमण दिनांक सहित परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। कोटा जिले में हटाये गये अतिक्रमण की सूचना का विवरण परिशिष्ट-स एवं बून्दी जिले में हटाये गये अतिक्रमण की सूचना का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) जी हां। कोटा जिले में अतिक्रमियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-य पर एवं बून्दी जिले में अतिक्रमियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(4) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष निरन्तर कार्यवाही कर खरीफ एवं रबी फसल की गिरदावरी से प्राप्त अतिक्रमण रिपोर्ट पर न्यायालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा निर्णय कर अतिक्रमण हटाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की कार्ययोजना

225. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये बनायी गयी पर्यटन नीति, 2019 के अन्तर्गत कितने पर्यटन उद्योग लगाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल लाल मीना)

(2) क्या यह भी सही है कि पर्यटन उद्योग के लिए आबंटित की जाने वाली भूमि की दर अधिक होने से उद्योग नहीं लग पा रहे हैं?

(3) क्या सरकार D.L.C. रेट पर उद्योग लगाने के लिए नीति में संशोधन कर पर्यटन को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में पर्यटन नीति, 2019 विद्यमान नहीं है। पर्यटन नीति, 2001 वर्तमान में प्रभावशील है। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, 2015 के प्रावधानों के अनुसार पर्यटन उद्योग को रियायतें प्रदान की जा रही हैं। पर्यटन इकाई नीति, 2015 की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, 2015 में पर्यटन इकाइयों हेतु डी.एल.सी. दर पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भूमि आबंटन का प्रावधान है। वर्तमान में इसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर में मास्टर प्लान में निर्धारित सड़क पर अतिक्रमण

226. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम अजमेर क्षेत्र में आनासागर झील से पुष्कर झील को जाने वाले सड़क मार्ग की मास्टर प्लान में लम्बाई चौड़ाई निर्धारित की हुई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? मय मास्टर प्लान नक्शा व इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क की मास्टर प्लान में निर्धारित सड़क की चौड़ाई को दरकिनार करते हुए पूर्व निर्धारित सड़क मार्ग पर ही निर्माण की अनुमति देकर सड़क मार्ग की जगह-जगह से चौड़ाई घटा दी गई है? यदि हां, तो क्यों? व किन नियमों के तहत?

(3) अजमेर में होटल रिसोर्ट आदि समस्त निर्माणों की सूची मय स्वीकृत नक्शों की प्रति कम्पलीशन सर्टिफिकेट की प्रतियां, जिम्मेदार अधिकारियों, अतिक्रमणकारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

(4) क्या यह भी सही है कि मास्टर प्लान के विपरीत जाकर आनासागर झील के 250 मीटर के रेडियस में निगम अधिकारियों के संरक्षण में होटल, रिसोर्ट व्यवसायियों के अतिक्रमण व निर्माण हो गये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक निर्माण अतिक्रमण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम, अजमेर क्षेत्र में आनासागर झील से पुष्कर झील को जाने वाले सडक मार्ग की अजमेर मास्टर प्लान-2023 में चौड़ाई निर्धारित की हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. राम नगर जंक्शन से नौसर घाटी हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार की अन्तिम सीमा तक अजमेर मास्टर प्लान-2023 के अनुसार सडक का मार्गाधिकार 160-200 फीट निर्धारित है जिसे सड़क मार्गाधिकार समिति द्वारा 160 फीट निर्धारित किया गया है।
2. (1) एन.सी.सी. कार्यालय से चौपाटी तक अजमेर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार सडक का मार्गाधिकार 120-160 फीट है, जिसे सड़क मार्गाधिकार समिति द्वारा 100 फीट निर्धारित किया गया है।

   (2) चौपाटी से रीजनल कॉलेज तिराहे तक अजमेर मास्टर प्लान-2023 के अनुसार सड़क मार्गाधिकार 120-160 फीट है, जिसे सड़क मार्गाधिकार समिति द्वारा 120 फीट निर्धारित किया गया है।

   भू-उपयोग मानचित्र-2023 परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है एवं जारी नोटिफिकेशन की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त सड़क की चौड़ाई को अजमेर मास्टर प्लान-2023 में निर्धारित चौड़ाई से मास्टर प्लान में उल्लेखित प्रावधान बिन्दु संख्या 5.7 (1)ब (परिशिष्ट "स" पर संलग्न है) के अनुसार उपयुक्त मार्गाधिकार निर्धारित करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 17.06.2008 एवं 28.08.2008 में लिये गये निर्णयानुसार किया गया है। (परिशिष्ट "द") नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 14.11.2008 के द्वारा इसका अनुमोदन किया गया, (परिशिष्ट "य")

(3) नगर निगम, अजमेर क्षेत्र में गत दो वर्षों में होटल व रिसोर्ट व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति का विवरण एवं अदेय प्रमाण-पत्र की प्रति परिशिष्ट "र" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) नगर निगम, अजमेर क्षेत्र में आनासागर झील के केन्द्र से 250 मीटर के रेडियस से गत दो वर्षों में किसी भी प्रकार का कोई नवनिर्माण नहीं है। नगर निगम, अजमेर क्षेत्र में आनासागर झील की परिधि 250 मीटर से अधिक के रेडियस से गत दो वर्षों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये गये अवैध निर्माण पर धारा 194 के तहत सीज एवं ध्वस्त की कार्यवाही की गई। सीज किये गये व्यवसायिक अवैध निर्माणों का विवरण परिशिष्ट "ल" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झाड़ोल में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति

227. श्री बाबु लाल (झाडोल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल के कोटड़ा उप खण्ड मुख्यालय पर बिजली आपूर्ति की समस्या रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार कोटड़ा में 132 के.वी. का जी.एस.एस. स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाडोल के कोटड़ा क्षेत्र में 33 केवी विद्युत लाइनों की लम्बाई अधिक होने के कारण, 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव परीक्षण उपरान्त तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य पाया गया है। इसके क्रियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

डूंगरपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

228. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन क्षेत्रों/गांवों में अभी तक सड़क

(श्री गणेश घोघरा)

नहीं बनी हैं, उनमें नवीन सड़कें बनाने एवं इनका सौन्दर्यीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्तमान में कुल 22 सड़कें 61.74 किमी. लम्बाई में क्षतिग्रस्त हैं। इन सड़कों की मरम्मत की स्थिति निम्न प्रकार है:-

सड़कों की मरम्मत के लिए 25.20 लाख की राशि की स्वीकृति जारी कर दी गई है एवं राशि 96.00 लाख की स्वीकृति और जारी किया जाना प्रकियाधीन है।

शेष सड़कों का नवीनीकरण शीघ्र करने के लिए विचार किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में जनगणना 2001 के अनुसार 4 राजस्व गांव एवं 113 ढाणियां/बसावटें 250 की आबादी से कम होने के कारण डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं।

उक्त राजस्व गांव व ढाणियों को डामर सड़क से जोडने के लिए सरकार प्रयासरत है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बढ़ते साइबर क्राइम

229. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में साइबर क्राइम के प्रकरण प्रदेश में काफी बढ़ गये हैं? विगत एक वर्ष में श्रीगंगानगर जिले में ऐसे कितने प्रकरण दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) साइबर क्राइम की समस्या से निपटने के लिए क्या सरकार तकनीकी योग्यताधारी कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में साइबर क्राइम के प्रकरण वर्ष 2017 में कुल 1277 प्रकरण व वर्ष 2018 में कुल 1053 प्रकरण दर्ज हुए। इस प्रकार तुलनात्मक रूप में वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में कमी आई है।

(गृह मंत्री)

श्रीगंगानगर जिले में गत एक वर्ष (20.06.2018 से 20.06.2019) में साइबर क्राइम के कुल 43 प्रकरण दर्ज किये गये। विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) साइबर क्राइम की समस्या से निपटने के लिए एसओजी में एक विशेष साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन यूनिट स्थापित की जायेगी, यह बजट में घोषणा हो चुकी है अत: कर्मचारियों की भर्ती पर विचार किया जा रहा है जिसमें विशेषज्ञों की भी सेवायें ली जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कपासन के लुहारिया बांध की मरम्मत पर व्यय राशि

234. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन के लुहारियां गांव के पास बांध बना हुआ है? यदि हां, तो इसकी भराव क्षमता कितनी है? इस बांध के निर्माण व मरम्मत पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध की आवक व वितरिकाएं कच्ची हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें पक्की बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बांध की भराव क्षमता 103 मि. घन फीट है। बांध के निर्माण पर रुपये 54.61 लाख एवं मरम्मत पर महानरेगा अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान राशि रुपये 24.17 लाख का व्यय किया गया है।

(2) जी हां। बांध में पानी की आवक प्राकृतिक नाले एवं अकाल राहत में निर्मित फीडर चैनल के माध्यम से होती है। लुहारियां बांध की दोनों मुख्य नहरे पूर्व में पक्की निर्मित हैं तथा खालों को पक्का किए जाने के प्रस्ताव आवश्यकता एवं संसाधन उपलब्धता के मध्यनजर विचाराधीन नहीं है।

पाली जिले में राज्य मार्ग 61 पर घटित दुर्घटनाएं

235. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में परिवहन/पुलिस/सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितने स्थल/राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्ग सड़क दुर्घटना संभावित स्थलों के रूप में ब्लेक स्पाट के रूप में चिन्हित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मार्गों पर ब्लेक स्पॉट चयनित किये जाने के क्या-क्या कारण रहे?

(3) चयनित ब्लेक स्पॉट पर दुघर्टनाओं को रोकने हेतु अब तक राजकीय स्तर पर क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(4) पाली जिले में राज्य मार्ग 61 पर जोजावर से देवगढ़ के बीच काली घाटी क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में हुई दुघर्टनाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या पुलिस द्वारा परिवहन विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपरोक्त स्थल पर दुर्घटनाओं की रिपोर्ट ब्लेक स्पॉट हेतु प्रस्तुत की गई? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2018 में कुल 1038 स्थल/ राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्ग सड़क दुघर्टना संभावित स्थलों के ब्लेक स्पाट के रूप में चिन्हित किये गये हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित "राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य किस्म की सड़क (राज्य राजमार्ग/अन्तर जिला सड़क/अन्य सड़क) पर 500 मीटर तक की दूरी के क्षेत्र में पिछले तीन साल में मिलाकर या तो 5 सड़क दुर्घटनाएं (प्राणघातक/गम्भीर किस्म की चोट) या 10 मौते हुई हों", के आधार पर ब्लेक स्पाट चयनित किए गए हैं।

(3) राज्य में कार्यरत विभिन्न सड़क एजेंसियों के द्वारा विगत वर्षो में चिन्हित किये गये सहित कुल 1516 ब्लेक स्पाट दुरस्त कर दिये गये हैं। चयनित ब्लेक स्पाट पर दुघर्टनाएं कम करने एवं रोकने हेतु समय-समय पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) पाली जिले में राज्य मार्ग 61 पर जोजावर से देवगढ के बीच काली घाटी क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में हुई (वर्ष 2014 से मई 2019 तक) दुर्घटनाओं की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(5) जिला पुलिस अधीक्षक, पाली द्वारा परिवहन विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपरोक्त स्थल पर दुर्घटनाओं के ब्लेक स्पॉट हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ जिले के कर्मचारियों के मेडिक्लेम के आवेदन

236. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा योजना, प्रावधायी निधि योजना, साधारण बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मेडिक्लेम योजना व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आदि के द्वारा समय-समय पर लाभ दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में विगत 3 वर्षों में किन-किन राज्य कर्मचारियों द्वारा उक्त योजनाओं में मेडिक्लेम हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये तथा सरकार द्वारा किन-किन कर्मचारियों के आवेदनों को स्वीकार कर मेडिक्लेम दिया गया तथा किन कर्मचारियों के आवेदन किन कारणों से अस्वीकार किये गये? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) द्वारा चित्तौड़गढ़ के एक कर्मचारी जो पेन्क्रियाज नामक गम्भीर बीमारी से ग्रसित है के मेडिक्लेम दावा संख्या 029164 एवं 030369 की राशि को अस्वीकार कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे कर्मचारी जो पैन्क्रियाज जैसी गम्भीर बीमारियों से ग्रसित है, उनके मेडिक्लेम दावों में शिथिलता प्रदान कर दावा राशि स्वीकार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में विगत 3 वर्षों में जिन राज्य कर्मचारियों द्वारा मेडिक्लेम हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये तथा जिन कर्मचारियों के आवेदनों को स्वीकार कर मेडिक्लेम दिया गया तथा जिन कर्मचारियों के आवेदन किन्हीं कारणों से अस्वीकार किये गये, उनका कारण सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) की अनुशंसा पर मेडिक्लेम दावा संख्या 29164 एवं 30369 को अस्वीकृत किया गया है क्योंकि उक्त दावे पैन्क्रियाज से सम्बन्धित नहीं होकर पेट दर्द की बीमारी से सम्बन्धित थे। कारण सहित विवरण (प्रोसेस शीट्स) परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि मंत्री)

(4) ऐसे कर्मचारी जो पैन्क्रियाज जैसी गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके मेडिक्लेम दावों को स्वीकार करने का प्रावधान मेडिक्लेम पालिसी के बिन्दु संख्या 6.3 में पहले से ही विद्‌यमान है। मेडिक्लेम पालिसी की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में प्रस्तावित एनीकट, तालाब व बांध

237. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में कितने एनीकट, तालाब व बांध कहां-कहां पर स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान व आगामी वर्ष में कहां-कहां नये एनीकट, तालाब व बांध बनाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्षा जल संग्रहण के दृष्टिकोण से नये एनीकट व बांध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जल संसाधन विभाग के अधीन स्थित कुल 22 बांध/तालाब/एनीकटों का स्थानवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में नये एनीकट/तालाब/बांधों के कार्य कराये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये एनीकट व बांध बनाने की मांग/ प्रस्ताव प्राप्त होने पर जल की उपलब्धता का तकनीकी आंकलन कर उपादेय पाये जाने पर तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदन एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य कराये जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के पुलिस थानों में दर्ज एफ. आई. आर. पर कार्यवाही

238. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) जयपुर जिले के थाना झोटवाड़ा में एफ. आई. संख्या 16/13, 196/18, 306/17, 632/19, 640/19, 641/19 व थाना विश्वकर्मा में 55/13 व थाना चौमूं में 592/15 तथा थाना गलता गेट में 234/09 किस-किस अभियुक्त के विरुद्ध किस-किस प्रकरण में किस-किस धारा में दर्ज है? पीड़ित पक्षकारों के नाम व एफ.आई.आर. की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त थानों में दर्ज एफ.आई.आर. में संबंधित थानों के द्वारा 29 जून, 2019 तक किस-किस प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही कर पीड़ितों को राहत पहुंचाई गयी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मुल्जिमानों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आयुक्त जयपुर को पीड़ित पक्ष द्वारा कोई ज्ञापन भी दिया गया है? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गयी? ज्ञापन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त मुल्जिमानों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी व अपराधों को रोकने हेतु इनकी फोटो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने व टी.वी. चैनलों में दिखाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस थाना झोटवाड़ा, विश्वकर्मा, चौमूं तथा गलता गेट में अभियुक्तों के दर्ज प्रकरणों व परिवादियों के सम्बन्ध में परिशिष्ट-अ पर तथा एफ.आई.आर. की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) पुलिस थाना झोटवाडा,विश्वकर्मा, चौमूं तथा गलता गेट में दर्ज प्रकरणों में कार्यवाही कर पीड़ितों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट-अ कालम संख्या 8 पर संलग्न है।

(3) हां। यह सही है कि पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस थाना झोटवाडा के प्रकरण संख्या 306/17 के आरोपी श्री सुरेश तिवाड़ी पुत्र श्री धरमीधर तिवाड़ी (डी.डी. तिवाडी,) व श्री अंशुल तिवाड़ी पुत्र श्री सुरेश तिवाड़ी को गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही हेतु पुलिस आयुक्त जयपुर को दिनांक 9.5.2018 को ज्ञापन दिया था। आरोपी सुरेश तिवाड़ी को दिनांक 11.7.2019 को पुलिस थाना झोटवाड़ा के प्रकरण संख्या 640/19 धारा 420, 406 आईपीसी में जुर्म

(गृह मंत्री)

प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी है। ज्ञापन की छाया प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) उक्त अपराधियों में से सुरेश तिवाड़ी को पुलिस थाना झोटवाड़ा के प्रकरण संख्या 640/19 धारा 420, 406 आईपीसी में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी है। अन्य अपराधियों की संलिप्तता एवं वांछित होने पर विधि अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरी खुर्द तहसील किशनगढ़ रेनवाल में विकास कार्य

239. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द तहसील किशनगढ़ रेनवाल जयपुर के द्वारा वर्ष 2008 से मार्च 2019 तक किस-किस ग्राम में क्या-क्या कार्य किस-किस योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि के पूर्ण कराये गये एवं कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस ग्राम में कराये जाने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1998 में वर्ष 2013 तक कौन-कौनसे गांव से किस-किस व्यक्ति के द्वारा पट्टा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से किन-किन व्यक्तियों को पट्टा जारी किया गया? पट्टा जारी नहीं करने के क्या कारण हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधायक कोष की राशि में से कार्यकारी एजेंसी द्वारा उक्त ग्राम पंचायत के किस-किस ग्राम में क्या-क्या कार्य कराने हेतु कितनी-कितनी राशि की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई तथा उसमें से किस-किस ग्राम में क्या-क्या कार्य पूर्ण करा दिये गये तथा क्या-क्या कार्य कराये जाने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत में विधायक कोष की स्वीकृत राशि के कई कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं एवं कई कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं? क्या सरकार वर्तमान में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द में वर्ष 2008 से मार्च 2019 तक कुल 124 कार्य करवाये गये हैं जिसमें से 123 कार्य मार्च, 19 तक पूर्ण हो गये हैं। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। एक कार्य ग्राम रामपुरा ब्राह्मणों के मौहल्ले में ओमप्रकाश शर्मा के मकान नौहरा के पास स्थित खुर्रा निर्माण व बाउन्ड्रीवाल का कार्य विवादित होने के कारण अप्रारम्भ है।

(2) ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द में वर्ष 1998 से वर्ष 2013 तक पट्टा चाहने हेतु 70 व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया है जिसमें से 11 व्यक्तियों को पट्टा जारी किया गया तथा 59 व्यक्तियों को पट्टा जारी नहीं करने के कारण स्पष्ट नहीं है। 70 आवेदकों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) स्थानीय विधायक कोष से स्वीकृत 6 कार्यों में से 5 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। एक कार्य जनता के विरोध के कारण अप्रारम्भ है। विवरण परिशिष्ट -3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द के विधायक कोष में स्वीकृत 6 कार्यों में से मात्र एक कार्य जनता के विरोध के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रेवदर में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन के तहत व्यय राशि

240. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर की पंचायत समिति रेवदर तथा पंचायत समिति आबूरोड के किन-किन गांवों में विगत 2 वर्षों के दौरान मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कितनी–कितनी राशि के कार्य कहां–कहां कराये गये? वर्षवार पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन जल संरचनाओं के निकट पौधरोपण किये जाने का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो संरचनावार पौधों की संख्या, साइज, किस्म एवं उन पर की गई व्यय राशि, पौधों की वर्तमान भौतिक सत्यापन जांच रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगसी राम)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जल स्वावलम्बन के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, उपयोगिता का ध्यान नहीं रखा जाकर प्रावधानों के अनुरूप पौधरोपण कर उनका संरक्षण भी नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त में से प्रत्येक जल स्वावलम्बन कार्य की थर्ड पार्टी जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो, कब तक व यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत जिला सिरोही के विधान सभा क्षेत्र रेवदर की पंचायत समिति रेवदर तथा पंचायत समिति आबूरोड में विगत 2 वर्षों में कराये गये कार्यों का वर्षवार, पंचायतवार विवरण मय राशि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) हां जल संरचनाओं के निकट पौधरोपण का प्रावधान रखा गया था। जल संरचनाओं पर किये गये वृक्षारोपण की संरचनावार पौधों की संख्या, साइज, किस्म एवं उन पर की गई खर्च राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त दोनों पंचायत समितियों में कराये गये वृक्षारोपण की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) उक्त जल स्वावलम्बन अभियान के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं उपयोगिता का ध्यान रखा गया है एवं प्रावधानों के अनुरूप ही पौधरोपण व उनका संरक्षण किया गया है।

हाल ही में विकास अधिकारी एवं तहसीलदार, पंचायत समिति आबूरोड एवं रेवदर के द्वारा वन विभाग की पौधरोपण की रिपोर्ट के 10 प्रतिशत कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाया गया। गत वर्ष कम वर्षा होने पर भी लगभग 52 प्रतिशत पौधे जीवित पाये गये।

(4) मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत 10 प्रतिशत कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराने का प्रावधान है, जिसमें प्रथम चरण में 131, द्वितीय चरण में 306 तथा तृतीय चरण में 289 कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया गया है। अत: पुन: कार्यों की तृतीय पक्ष जांच की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर उपखण्ड में बाघेर से पनवाड सड़क का निर्माण

241. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खानपुर उपखण्ड में बाघेर से पनवाड वाया हरिगढ़ सड़क मार्ग लम्बे समय से अपूर्ण है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खानपुर उपखण्ड में बाघेर से पनवाड वाया हरिगढ़ सड़क मार्ग के कार्य की प्रगति पूर्व में धीमी थी, वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

(2) उक्त सड़क का निर्माण कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शीघ्र पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

बानसूर में बी.पी.एल. सूची से वंचित परिवार

242. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बी.पी.एल. सूची के लिये सर्वे कितनी अवधि के अन्तराल में किया जाता है तथा इस सर्वे के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर में अनेक परिवार बी.पी.एल. सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पुन: अभियान चलाकर वंचित रह गये व्यक्तियों को बी.पी.एल. सूची में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रत्येक पांच वर्ष में भारत सरकार द्वारा बीपीएल सर्वे करवाया जाता है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में वर्तमान में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 का सर्वे किया जाकर अन्तिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

बीपीएल सेन्सस 2002 के चयन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों

(ग्रामीण विकास मंत्री)

के अनुसार 13 आर्थिक एवं सामाजिक सूचकों के आधार पर सर्वे करवाकर 52 अंकों में से अंक प्रदान किये गये थे। सर्वे से प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में सूचियां तैयार कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक आने वाले परिवारों को एकल कट आफ स्कोर के आधार पर शून्य से 12 अंक तक प्राप्त करने वाले समस्त एवं 13 अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों को बीपीएल सूची 2002 (ग्रामीण) में चयन किया गया था।

(2) जी नहीं। बीपीएल सूची 2002 (ग्रामीण) में शामिल होने से वंचित रहे परिवारों के लिये भारत सरकार के निर्देशानुसार बीपीएल सेन्सस 2002 (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को शामिल करने हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है। इसके अनुसार प्रथम अपील संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को की जा सकती है। अपील प्रक्रिया द्वारा ही बीपीएल सूची 2002 में पात्र परिवारों को शामिल किया जा सकता है।

(3) बीपीएल सेन्सस 2002 के चयन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 13 आर्थिक एवं सामाजिक सूचकों के आधार पर सर्वे करवाकर 52 अंकों में से अंक प्रदान किये गये थे। सर्वे से प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में सूचियां तैयार कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक आने वाले परिवारों को एकल कट आफ स्कोर के आधार पर शून्य से 12 अंक तक प्राप्त करने वाले समस्त एवं 13 अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों को बीपीएल सूची 2002 (ग्रामीण) में चयन किया गया था।

बीपीएल सूची 2002 (ग्रामीण) में शामिल होने से वंचित रहे परिवारों के लिये भारत सरकार के निर्देशानुसार बीपीएल सेन्सस 2002 (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को शामिल करने हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है। इसके अनुसार प्रथम अपील संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को की जा सकती है। अपील प्रक्रिया द्वारा ही बीपीएल सूची 2002 में पात्र परिवारों को शामिल किया जा सकता है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार बीपीएल सर्वे करवाया जाता है। पूर्व में इसकी पंचवर्षीय योजना काल (2002-2007) के लिये वर्ष 2002 से बीपीएल सर्वे हुआ था फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सेक (Secc) सर्वे 2011 में किया गया है जिसकी अन्तिम सूची का प्रकाशन अप्रैल 2016 में किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामपुरा रोड, सांगानेर के सी.जी.एम. नगर में पेयजल आपूर्ति

243. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के अन्तर्गत रामपुरा रोड पर विगत दो वर्ष पूर्व सी.जी.एम. नगर व सचिवालय विहार विस्तार, कल्याणपुरा, सांगानेर जयपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु नवीन पाइप लाइन डालकर आपूर्ति की गई थी? यदि हां, तो 31 मई, 2019 तक कितने कनेक्शन आबंटित किये गये तथा वर्तमान में कितने कनेक्शनों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान पाइप लाइन में सीमा से अधिक कनेक्शन दिये गये हैं तथा लाइन के विस्तार के समय वाल्व आदि नहीं लगाये गये? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग ने पेयजल आपूर्ति का ठेका निजी संस्था को रखरखाव व मरम्मत हेतु अधिकृत कर रखा है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ठेका दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार का उक्त कालोनी में सुचारु पेयजल आपूर्ति हेतु नवीन ट्यूबवैल खोदकर या बीसलपुर से आपूर्ति को यथावत रखते हुए पेयजल उपलब्ध कराने का विचार है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के वार्ड संख्या 34 के अंतर्गत रामपुरा रोड, सांगानेर की पुनर्गठित जल योजना हेतु दिनांक 28.01.2013 को राशि रुपये 1216.69 लाख की स्वीकृत योजना के कार्य दिनांक 15.10.2016 को पूर्ण किये जाकर, इस योजना के प्रावधानों के अनुरूप बिछाई एवं जोड़ी गई पाइप लाइनों से वर्णित कालोनियों सहित अन्य कालोनियों में बीसलपुर बांध से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की गई।

उक्त पेयजल योजना अंतर्गत लाभान्वित सी.जी.एम. नगर, सचिवालय विहार विस्तार एवं कल्याणपुरा कालोनियों में विभाग द्वारा क्रमश: 20, 510 एवं 355, इस प्रकार कुल 885 जल संबंध उपभोक्ताओं को दिनांक 31.05.2019 तक जारी किये गये हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

बीसलपुर बांध में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के समय उक्त जल योजना हेतु 2.7 मिलियन लीटर पेयजल प्रतिदिन की उपलब्धता हो रही थी परन्तु वर्ष 2018 में अपर्याप्त वर्षा से बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता अत्यन्त कम रहने के फलस्वरूप, प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाकर जयपुर जिले सहित अन्य संबंधित जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 01.10.2018 से कटौती प्रारम्भ की गई।

उक्तानुसार बांध में जल उपलब्धता की कमी के फलस्वरूप उक्त योजना अंतर्गत 2.7 मिलियन लीटर प्रतिदिन के स्थान पर उक्त दिनांक से 2.0 मिलियन लीटर प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति किये जाने से इन कालोनियों के अंतिम छोर के कुछ जल संबंधों में पानी कम दबाव एवं मात्रा में उपलब्ध हो पा रहा है। इन स्थानों पर मांग एवं आवश्यकतानुसार प्रतिदिन 3 टैंकर ट्रिपों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी नहीं। उक्तानुसार पूर्ण की गई योजना के अभिकल्पन में सांगानेर क्षेत्र की सम्मिलित कालोनियों की कुल पेयजल मांग के अनुरूप अन्य कार्यों सहित पाइप लाइन बिछाने व जोड़ने का कार्य किया जाकर उपभोक्ताओं को जल संबंध जारी किये गये तथा योजना के स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप मुख्य एवं वितरण पाइप लाइनों में विभिन्न श्रेणी के वाल्व स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप उक्त योजना का कार्य निष्पादित कराये जाने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(3) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन विभिन्न पेयजल योजनाओं का सुचारु संचालन एवं संधारण का कार्य निजी ठेकेदारों के स्तर पर कराये जाने के संबंध में विभागीय वित्त समिति की 308वीं बैठक दिनांक 13-14.05.1998 के अंतर्गत नार्म्स निर्धारित किये गये हैं।

इन निर्धारित नार्म्स की अनुपालना में शहरी जल योजना, सांगानेर अंतर्गत निर्मित पम्प हाउस, राइजिंग एवं वितरण पाइप लाइनों एवं अन्य संबंधित कार्यों के रख-रखाव एवं योजना के संचालन/संधारण तथा इसके अतिरिक्त उक्त योजना अंतर्गत राजस्व संबंधी समस्त कार्यों के 5 वर्ष की अवधि तक निष्पादन हेतु मैसर्स डाइनमिक इलेक्पावर प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा को दिनांक 08.03.2019 को राशि रुपये 341.79 लाख का कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) भू-जल विभाग की दिनांक 31 मार्च, 2013 की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति क्षेत्र, सांगानेर अतिदोहित (ओवर-एक्सप्लोईटेड) श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण, क्षेत्र में भू-जल की सीमित उपलब्धता के फलस्वरूप उक्त वर्णित कालोनियों हेतु नवीन नलकूप निर्माण किया जाना तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं है।

बीसलपुर बांध में आगामी समय में पानी की आवक बढ़ने तथा उक्त योजना की पेयजल वितरण प्रणाली में आवश्यक न्यूनतम सुधार किया जाकर उक्त वर्णित कालोनियों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से सम्भव हो सकेगी।

बामनवास में विद्युत कनेक्शन के लम्बित आवेदन

244. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि विद्युत कनेक्शन व घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु नियम निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो निर्धारित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में दिसम्बर, 2018 तक कृषि एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं तथा इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के कनेक्शन जारी करने हेतु सरकार द्वारा समय सीमा तय कर रखी है? यदि हां, तो कितनी व क्या उसकी पालना हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में लम्बित पड़े कृषि विद्युत कनेक्शन व घरेलू विद्युत कनेक्शन के आवेदनों का कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में कृषि एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने के नियमों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माह दिसम्बर, 2018 तक विद्युत कनेक्शन हेतु 783 कृषि एवं 179 घरेलू आवेदन लम्बित हैं, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

उक्त विद्युत कनेक्शन लाइन के कुछ सामान की अनुपलब्धता के कारण लम्बित रहे थे एवं वर्तमान में इनमें से अधिकतर को विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

(3) जी हां। प्रदेश में कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने के नियमों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

घरेलू विद्युत कनेक्शन आवेदन होने के बाद, जहां स्थापित विद्युत तंत्र से ही विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है, वहां 30 दिवस में कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है एवं जहां विद्युत तंत्र में विस्तार प्रस्तावित है, उस मामले में कार्य के प्रकार एवं वोल्टेज स्तर के अनुसार 15 दिवस से 180 दिवस में जाब कार्य पूर्ण करने व जाब कार्य पूर्ण होने के बाद 15 दिवस में विद्युत कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है।

(4) प्रदेश में सामान्य वर्ग कृषि श्रेणी के दिनांक 31.01.2012 तक पंजीकृत आवेदकों के मांग पत्र जारी कर मांग पत्र जमा आवेदकों को वरीयतानुसार एवं सामान की उपलब्धतानुसार कृषि कनेक्शन दिये जा रहे हैं। लम्बित घरेलू विद्युत कनेक्शनों को दिनांक 30.09.2019 तक जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

245. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नगर खण्ड बाड़मेर में शहरी पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यादेश कब जारी हुए एवं कितनी राशि इसमें स्वीकृत हुई है? उक्त योजना में क्या-क्या कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं? अब तक कितना कार्य पूर्ण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जिला बाड़मेर में विभाग के नगर खण्ड बाड़मेर के अधीन बाड़मेर शहर की पुनर्गठित पेयजल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय वित्त समिति की 733वीं बैठक दिनांक 27.10.2017 द्वारा राशि रुपये 368.96 लाख एवं तकनीकी स्वीकृति दिनांक 02.01.2018 को राशि रुपये 312.81 लाख की जारी की गई।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त स्वीकृत योजना के कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु मैसर्स मंत्री बिल्डर्स, जोधपुर को राशि रुपये 252.79 लाख का कार्यादेश दिनांक 07.06.2018 को जारी किया गया। कार्यादेशित फर्म द्वारा विभाग से नियमानुसार अनुबंध निष्पादित नहीं करने एवं योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण, वित्तीय नियमों के अनुसार उक्त कार्यादेश को निरस्त करते हुए निविदा लागत की सम्पूर्ण 2 प्रतिशत धरोहर राशि रुपये 6,25,640/- जब्त करते हुए इस कार्य हेतु निविदा के पुनर्आमंत्रण में हिस्सा लेने से वंचित किया गया। इसके उपरान्त उक्त योजना के कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु मैसर्स अमरदीप बिल्डर्स, जोधपुर को राशि रुपये 337.62 लाख का कार्यादेश दिनांक 05.10.2018 को जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार योजना का कार्य दिनांक 04.10.2019 को पूर्ण करना निर्धारित है।

उक्त स्वीकृत योजना में प्रावधित कार्य एवं इनकी वर्तमान प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु योजनाएं

246. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2009 से 2013 तथा वर्ष 2014 से जून, 2019 तक बिजली का उत्पादन किन-किन माध्यमों से कितना-कितना हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश की वर्तमान में बिजली की कुल कितनी आवश्यकता है तथा इसकी पूर्ति हेतु बिजली का अतिरिक्त उत्पादन किये जाने की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में बिजली के उत्पादन व उपभोक्ताओं को दी जा रही प्रति यूनिट की दर क्या-क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती व नियमित बिजली आपूर्ति कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व इसके लिए सरकार की क्या कार्य-योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से वर्ष 2009 से 2013 तथा वर्ष 2014 से माह मई, 2019 तक बिजली उत्पादन का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में वर्तमान में कुल 2300 LU प्रतिदिन बिजली की मांग है। अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु 1320 मेगावाट उत्पादन क्षमता की सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना की इकाई संख्या 7 एवं 8 का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इस परियोजना से क्रमश: माह अक्टूबर, 2019 एवं माह फरवरी, 2020 से विद्युत उत्पादन संभावित है।

माह जुलाई के शेष दिनों के लिये लगभग 2203 लाख यूनिट बिजली की प्रतिदिन आवश्यकता है तथा इसकी पूर्ति की जा रही है।

(3) राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट विक्रय दर का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है एवं वर्तमान में बिजली के उपभोक्ताओं को दी जा रही प्रति यूनिट बिजली की दर का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर में बीसलपुर पेयजल योजना की स्वीकृति

247. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्ष 2014 से 2018 के मध्य कुल कितनी पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गईं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के लिए बीसलपुर से पेयजल सप्लाई की योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त योजना के अभी तक क्रियान्वित नहीं होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त योजना के तहत वहां के निवासियों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु एवं सामान्य बनाये रखने हेतु वर्ष 2014 से वर्ष 2018 की अवधि में 75 संवर्धन/पुनर्गठित/पुनरूद्धार पेयजल योजनाओं हेतु राशि रुपये 5326.48 लाख, 16 आर.ओ. संयंत्र के स्थापना कार्य हेतु राशि रुपये 315.89 लाख तथा सौर ऊर्जा आधारित 12 बोरवेल्स मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट के स्थापना कार्य हेतु राशि रुपये 150.18 लाख, इस प्रकार कुल 103 योजनाएं/ अन्य कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 5792.55 लाख की स्वीकृतियां जारी की गईं।

उक्त स्वीकृतियों के विरुद्ध 72 संवर्धन/पुनर्गठित/पुनरूद्धार पेयजल योजनाएं तथा समस्त 16 आर.ओ. संयंत्र एवं समस्त सौर ऊर्जा आधारित 12 बोरवेल्स मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा वर्ष 2018 की स्वीकृत एवं शेष रही 3 पेयजल योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आमेर के वार्ड संख्या 91 को बीसलपुर बांध के स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करने हेतु पुनर्गठित शहरी पेयजल योजना, आमेर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय वित्त समिति की 743वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 द्वारा राशि रुपये 3389.00 लाख की जारी की गई थी। इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु मैसर्स एस. बी. एन्टरप्राइजेज, जोधपुर को राशि रुपये 2472.00 लाख का कार्यादेश दिनांक 05.10.2018 को जारी किया गया।

उक्त स्वीकृत जल योजना का 15 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। अनुबंधक फर्म द्वारा योजना के कार्यों की गति धीमी रखने के कारण, अनुबंध की शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा फर्म की रुपये 7.72 लाख की क्षतिपूर्ति राशि रोक ली गई है। कार्यादेश अनुसार उक्त योजना का कार्य दिनांक 04.04.2020 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को आबंटित भूमि

248. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

(1) क्या यह सही है कि नीरजा मोदी स्कूल को स्कूल संचालन हेतु रियायती दर पर जमीन आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कब व किन नियमों एवं शर्तों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्कूल को कितनी जमीन आबंटित की गई थी व वर्तमान में स्कूल के कब्जे में कितनी जमीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त विद्यालय में नियमों के विपरीत अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नीरजा मोदी स्कूल के नाम से कोई भी भूमि आबंटित नहीं की गई है, अपितु मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में ट्रस्टी कृष्णा चेरिटेबल ट्रस्ट को 43728.49 व.मी. भूमि का आबंटन व आबंटन पत्रांक 601 दिनांक 24.09.1999 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है एवं 3636.70 व.मी. भूमि का आबंटन, आबंटन पत्रांक 5695 दिनांक 28.02.2001 तत्पश्चात् कृष्णा चेरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा मण्डल में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कृष्णा चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री मोदी शिक्षण संस्थान का गठन किया है जो शिक्षण संस्थान है। इसलिए कृष्णा चेरिटेबल ट्रस्ट को आबंटित भूमि को श्री मोदी शिक्षण संस्थान के नाम करने बाबत निवेदन करने पर मण्डल (मु.) स्तर पर परीक्षण कर सहमति उपरान्त कार्यालय आदेश क्रमांक 908 दिनांक 27.06.2006 के द्वारा कृष्णा चेरिटेबल ट्रस्ट को आबंटित भूमि श्री मोदी शिक्षण संस्थान के नाम की गई।

पुन: श्री मोदी शिक्षण संस्थान को खेल मैदान हेतु 5048 व.मी. भूमि का आबंटन पत्रांक 1090 दिनांक 19.09.2006 के द्वारा प्रचलित संस्थानिक दर व ऊपरी व्यय भार की लागत पर जारी किया गया था। संस्था को भूमि का आबंटन डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1970 की समस्त शर्तों के अनुसार किया गया है (आवंटित भूमि के आबंटन पत्रों की छाया प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है)। संस्था को आबंटित उक्त समस्त भूमि का आबंटन तत्समय प्रचलित संस्थानिक आरक्षित दर पर किया गया।

(2) श्री मोदी शिक्षण संस्थान को मानसरोवर योजना, जयपुर में 43728.49 व.मी. का आबंटन पत्रांक 601 दिनांक 24.09.1999 व 3636.70

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

व.मी. भूमि का आबंटन पत्रांक 5695 दिनांक 28.02.2001 जारी किया गया है। पुन: श्री मोदी शिक्षण संस्थान को खेल मैदान हेतु 5048.00 व.मी. भूमि का आबंटन पत्रांक 1090 दिनांक 19.09.2006 को प्रचलित संस्थानिक दर व ऊपरी व्यय भार की लागत पर जारी किया गया था। वर्तमान में संस्था के पास मण्डल द्वारा जो उपरोक्तानुसार भूमि आबंटित की गई है उतनी ही भूमि संस्था के कब्जे में है।

(3) वर्तमान में संस्था को जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन किया गया था, उसी के अनुरूप गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, अन्य कोई विपरीत गतिविधियां संचालित नहीं की जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली में प्रधानमंत्री जन आवास योजना (शहरी) के तहत आवेदन

249. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद्, पाली में प्रधानमंत्री जन आवास योजना (शहरी) में किन-किन व्यक्तियों ने आवास निर्माण हेतु राशि के लिए नगर परिषद् में कब-कब आवेदन किया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में किसी निजी कंपनी द्वारा भी सर्वे किया गया था? यदि हां, तो निजी कंपनी के सर्वे में किन-किन आवेदनों को पात्र माना गया था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में अब तक नगर परिषद् द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(4) उक्त आवेदनों की जांच कराकर इन्हें केन्द्र सरकार को कब तक भिजवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, पाली में प्रधानमंत्री जन आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिये दिनांक 14.04.2018 से 27.04.2018 तक शिविरों का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त योजना में सलाहकार फर्म मैसर्स यांशी कन्सल्टेंसी

(स्वायत्त शासन मंत्री)

प्रा. लि. द्वारा पाली शहर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (ई.डब्लू.एस.) एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी) के आवासहीन परिवारों के आंकलन हेतु डिमाण्ड सर्वे करवाया गया है। जो निम्नानुसार है-

1. सहभागिता में किफायती आवास (एएचपी) घटक-2403
2. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण नवीन/अभिवृद्धि (बीएलसी) घटक-4939
3. स्वस्थाने कच्ची बस्ती पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक-1170
4. ऋण पर आधार अनुदान (सीएलएसएस) घटक-84

कुल 8596 आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अनुदान हेतु पात्र पाये गये है। वार्डवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) नगर परिषद्, पाली द्वारा पात्र आवेदनों में से निम्नानुसार आवास निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को भिजवाये गये थे, जो किं दिनांक 30.10.2017 एवं 25.06.2018 के द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. सहभागिता में किफायती आवास (एएचपी) घटक-1056
2. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण नवीन/अभिवृद्धि (बीएलसी) घटक-4153

(4) जी हां। एएचपी घटक में 1056 तथा बीएलसी घटक 4153 आवासों के निर्माण के प्रस्ताव केन्द्र सरकार से स्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष आवेदनों का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं नगरपालिका में सीवर लाइन की योजना

250. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का कार्य अब तक प्रारम्भ हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ? इसके क्या कारण हैं और कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

(श्री रामलाल शर्मा)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सीवर लाइन योजना की क्रियान्विति जुलाई माह से शुरू कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका चौमूं क्षेत्र में आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण के अन्तर्गत सीवर/फिकल स्लज मैनेजमेन्ट की योजना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 221.17 करोड रुपये होगी, जो एशियन विकास बैंक से बाह्य वित पोषित है।

(2) चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का कार्य आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण में कराया जाना प्रस्तावित है। नगरपालिका चौमूं द्वारा सलाहकार फर्म के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किये जाने का कार्य किया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एशियन विकास बैंक द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त टेण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

(3) जी नहीं। चौमूं में जल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है तथा वर्तमान में कोई सतही जल स्त्रोत नहीं है। चौमूं के लिए फीकल स्लज मैनेजमेन्ट एक विकल्प है। नगरपालिका चौमूं द्वारा नियुक्त सलाहकार फर्म को निर्देश दिये गये हैं, कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त चौमूं शहरवासियों द्वारा अन्य जल स्रोतों से जल उपयोग जैसे निजी नलकूप, पानी के टैंकरों द्वारा आपूर्ति, वर्षा जल संरक्षण इत्यादि का सघन सर्वेक्षण कर वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करें जिससे प्रति व्यक्ति जल उपयोग स्तर की मात्रा को सुनिश्चित कर एशियन विकास बैंक को मय तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। जिसके अनुमोदन पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

नये नगर सुधार न्यासों का गठन

251. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने नगर सुधार न्यास कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर सुधार न्यास के गठन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले

(श्री सुरेश टाक)

निकायों में नगर सुधार न्यास का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कब तक व यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 14 शहरों में नगर विकास न्यास, कार्यरत है। न्यासों के नाम व कार्यरत की तिथि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 8, 9 व 13 के अनुसरण में राज्य सरकार के निर्णय उपरान्त नगर विकास न्यास का गठन किया जाता है, की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार की उच्च स्तर पर निर्णय उपरान्त नगर विकास न्यास का गठन किया जाता है। इस हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। वर्तमान में न्यास गठन के संबंध में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवली-उनियारा में महिला शौचालयों का निर्माण

252. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले के देवली-उनियारा में सार्वजनिक महिला शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है?

(2) क्या सरकार महिलाओं को हो रही असुविधा को देखते हुए उक्त कस्बों के मुख्य बाजारों, बस स्टैंडों पर महिला शौचालय की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। टोंक जिले की नगरपालिका देवली एवं उनियारा में सार्वजनिक महिला शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था है।

(2) नगरपालिका देवली द्वारा बस स्टैण्ड, पैट्रोल पम्प चौराहा, जहाजपुर चुंगी नाका, राजकीय चिकित्सालय, तहसील परिसर एवं दशहरा मैदान में शौचालय बनवाये हुए है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नगरपालिका उनियारा द्वारा बस स्टैण्ड, सरदार सर्किल, फुलबारी गेट, खातोली गेट, भूतेश्वर गेट, बैरवां मौहल्ला में शौचालय बनवाये हुए हैं।

डोली भूमियों पर पुजारियों की खातेदारी का अधिकार का निर्णय

253. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डोली भूमि को पुजारियों की खातेदारी भूमि मानकर उसके समस्त खातेदारी अधिकार पुजारियों को दिये जाने का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में समस्त डोली भूमियों पर पुजारियों की खातेदारी दर्ज कर दी गई है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। देवमूर्ति शाश्वत अवयस्क है तथा देवमूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर अलग से रखा जाता है जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जाता है। परिपत्र दिनांक 13.12.91, 24.05.2007, 25.11.2011 एवं 12.09.2018 की प्रति संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर के पर्यटक स्थलों की विकासोन्मुख योजना

254. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, अलवर जिले में कुल कितने पर्यटन स्थान हैं? उक्त पर्यटक स्थलों में विगत

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

पांच वर्षों में विकास से सम्बन्धी क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में अनेक ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनका विकास नहीं हुआ है? क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थलों का विकास करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले के सिटी पैलेस, राजकीय संग्रहालय, मूसीरानी की छतरी, सागर, किशन कुण्ड, बाला किला, फतेह जंग गुम्बद, कम्पनी बाग, जयसमंद, मोतीडूंगरी, सिलीसेढ, तालवृक्ष, भृर्तहरी, सरिस्का नेशनल पार्क, पाण्डुपोल, भानगढ किला, गरवाजी, नारायणी धाम, तिजारा का जैन मन्दिर, नीमराना की बावड़ी, होप सर्कस अलवर, नलदेश्वर, नटंनी का बांरा, तिजारा भृर्तहरि गुम्बद, तिजारा लाल मस्जिद आदि महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में राशि रु. 30.00 लाख व्यय कर सिलीसेढ तिराहे से सिलीसेढ तक सड़क की मरम्मत कार्य कराया गया।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक 30.03.2017 के द्वारा पाण्डुपोल के लिये राशि रु. 188.42 लाख तथा भृर्तहरि के लिये राशि रु. 129.14 लाख तथा स्वीकृति दिनांक 28.06.2017 के द्वारा बाला किला के लिये राशि रू 166.22 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

बसई नवाब उप तहसील का नवीन भवन

255. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला धौलपुर की तहसील सैपऊ के अधीन बसई नवाब में उप तहसील संचालित है? यदि हां, तो क्या सरकार बसई नवाब में उप तहसील के लिए नवीन भवन बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। उक्त तहसील संचालित है व राज्य सरकार भवन निर्माण पूर्ण करने का विचार रखती है।

उप तहसील बसई नवाब के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में आबंटित राशि रुपये 4.98 लाख से भूमि की बाउण्ड्री वाल (चारदीवारी) का निर्माण हो चुका है परन्तु आबंटित भूमि पर सिविल कोर्ट का स्थगन आने के कारण भवन निर्माण का कार्य नहीं हो सका। वर्तमान में कोर्ट का स्थगन आदेश हट गया है। वर्तमान में निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

मसूदा में नवीन पटवार घर

256. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में कितने पटवार घर सरकारी भवन में स्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने पटवार घर किराये पर ले रखे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने पटवार घर निर्माणाधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जहां पटवार घर नहीं है, वहां नये पटवार घर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में 61 पटवार घर सरकारी भवन में स्थापित हैं। सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) कुल 40 पटवार घर रुपये 1000/- मासिक किराये पर ले रखे हैं। सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में एक भी पटवार घर निर्माणाधीन नहीं है।

(4) जहां पटवार घर नहीं है वहां पर नये पटवार घर बजट की उपलब्धता के आधार पर बनाये जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पिण्डवाड़ा-आबू में पटवारियों के रिक्त पद

257. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू की पंचायतों में पटवारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू में पटवारियों के 28 पद रिक्त हैं। पटवारी के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

दूदू में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभ से वंचित परिवार

258. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू के 31 जनवरी, 2014 से पूर्व कितने परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जोड़कर उन्हें दो रुपये किलो गेहूं योजना से लाभांवित किया जा रहा था? ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सूची से दिनांक 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् कितने व्यक्तियों के नाम काटे गये? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेंज पर रखें।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2017 के पश्चात् खाद्य सुरक्षा योजना में कितने नाम जोड़े गये हैं? ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में 31 जनवरी, 2014 से पूर्व कुल 77283 परिवारों को 2 रुपये किलो गेहूं से लाभान्वित किया जा रहा था। ग्राम पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त सूची से 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् किसी व्यक्ति का नाम नहीं काटा गया है।

(3) 1 जनवरी, 2017 के पश्चात् खाद्य सुरक्षा योजना में कुल

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

22649 नाम जोड़े गये हैं। ग्राम पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना में कम गेहूं का आबंटन

259. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत माह-मई, 2019 में कम गेहूं आबंटित किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) निगम द्वारा कम गेहूं आबंटन से कितने उपभोक्ता गेहूं वितरण से वंचित रहे?

(3) क्या इस प्रकार कम गेहूं आबंटन से भविष्य में केन्द्र से मिलने वाले गेहूं के आबंटन पर भी असर पड़ने की संभावना है?

(4) गेहूं कम आबंटन के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वस्तुत: गेहूं का आबंटन राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नहीं किया जाकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की धारा 7 (3) के अनुसार आबंटन करते समय उचित मूल्य दुकानदारों के पास उपलब्ध गेहूं के स्टाक का समायोजन कर आबंटन जारी करने के प्रावधान के क्रम में मई, 2019 के लिए जारी होने वाले आबंटन में 1 मार्च, 2019 को उचित मूल्य दुकानदारों के पास उपलब्ध 33089 मै. टन गेहूं के स्टाक को समायोजन कर 196386 मै. टन गेहूं का आबंटन जारी किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) चालू माह के साथ पूर्व माह के अवितरित गेहूं को देने के प्रावधान के तहत वंचित उपभोक्ताओं को जून 2019 में वितरण कर दिया गया।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जी नहीं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3(1) की अनुसूची 4 के अनुक्रम में आबंटन किया जाता है। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) इस विषय में मूल्यांकन किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राशन सामग्री का आनलाइन वितरण

260. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राशन डीलरों के राशन सामग्री वितरण पर प्रभावी मानिटरिंग करने हेतु व्यवस्था की जा रही है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आनलाइन मशीनों द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में व नहीं, तो कब तक उन क्षेत्रों में आनलाइन मशीनों द्वारा वितरण करने की व्यवस्था कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राशन डीलरों के राशन सामग्री वितरण पर प्रभावी मानिटरिंग करने हेतु राज्य में राशन डीलरों द्वारा राशन सामग्री का वितरण दिनांक 01.08.2015 से पोस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर करवाया जा रहा है। संबंधित आदेश दिनांक 29.09.2016 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सरकार द्वारा राशन डीलरों के राशन सामग्री वितरण पर प्रभावी मानिटरिंग करने हेतु जिला स्तर, तहसील स्तर एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। साथ ही विभागीय पर्यवेक्षण अधिकारियों, जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी पर्यवेक्षण किया जाता है।

(2) जी नहीं। राज्य में 103 उचित मूल्य दुकानों को छोड़कर सभी उचित मूल्य दुकानों पर राशन वितरण पोस मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

इन 103 उचित मूल्य दुकानों पर नेटवर्क उपलब्धता नहीं/न्यून होने के कारण विभाग द्वारा आफलाइन राशन सामग्री वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त शेष 103 उचित मूल्य दुकानों पर नेटवर्क की समुचित उपलब्धता होने पर इन क्षेत्रों को भी पास मशीन द्वारा वितरण शुरू करवा दिया जाएगा। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 24.04.2018 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रविन्द्र इन्टरनेशनल स्कूल, सांगानेर के विरुद्ध शिकायतें

261. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रविन्द्र इन्टरनेशनल स्कूल डिग्गी मालपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर के विरुद्ध अधिक फीस वसूली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय की फीस का निर्धारण कब किया गया? क्या उक्त विद्यालय का निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में विगत तीन वर्ष में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया? विद्यार्थियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत तीन वर्ष में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उक्त विद्यालय में प्रवेश दिये गये विद्यार्थियों की कितनी राशि का भुगतान किया गया? विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन कब-कब किसके द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। रविन्द्र इन्टरनेशनल स्कूल डिग्गी मालपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर के विरुद्ध अधिक फीस वसूली की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) विद्यालय की फीस का निर्धारण अप्रैल, 2019 में विद्यालय की

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

मैनेजिंग कमेटी द्वारा किया गया है। सामान्यत: विद्यालयों की शिकायत होने पर निरीक्षण किया जाता है अथवा आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।

(3) उक्त विद्यालय में विगत तीन वर्ष में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या शून्य है।

(4) चूंकि उक्त विद्यालय में विगत तीन वर्ष में शिक्षा के अधिकार के तहत कोई भी विद्यार्थी प्रवेशित नहीं हुआ, अत: भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

लाडनूं के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अधीन उर्दू विषय के अध्यापक

262. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, लाडनूं (नागौर) के अधीन तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल-2) विषय उर्दू के कितने अध्यापक कार्यरत हैं? इन समस्त अध्यापकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से इनका पदस्थापन कहां-कहां व कितनी अवधि के लिए रहा है? उक्त समस्त अध्यापकों की नियुक्ति, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालय के अधीन कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल-2) विषय उर्दू के अध्यापकों की परिवीक्षा अवधि कब से कब तक रही एवं उनका नियमितीकरण किस-किस दिनांक को किया गया? उक्त समस्त अध्यापकों की परिवीक्षा अवधि, नियमितीकरण के आदेशों की प्रति एवं तत्समय कार्यस्थल पदस्थापन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन उर्दू के अध्यापकों के परिवीक्षा काल से नियमितीकरण से संबंधित समस्त पत्राचार/अभ्यावेदन/आदेश माननीय न्यायालय के आदेश (यदि कोई हो) का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग अन्तर्गत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लाडनूं (नागौर) के अधीन वर्तमान में एक तृतीय श्रेणी अध्यापक मोहम्मद असलम (लेवल-2) विषय उर्दू कार्यरत है।

श्री असलम की प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 12.09.2013 से

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

13.04.2015 तक राउप्रावि, कुन्दनपुरा, ग्रा.पं.- सेड़वा, चौहटन, बाडमेर तथा दिनांक 15.04.2015 से राउप्रावि, सं.-05, लाडनूं, नागौर में लगातार कार्यरत है। श्री असलम अध्यापक की प्रथम नियुक्ति, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट- "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लाडनूं (नागौर) के अधीन वर्तमान में मोहम्मद असलम (लेवल-2) विषय उर्दू शिक्षक कार्यरत है, जिनकी परिवीक्षा अवधि दिनांक 12.09.2013 से 12.09.2015 तक रही है तथा श्री असलम का वेतन नियमितीकरण मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, लाडनूं (नागौर) के आदेश क्रमांक 443 दिनांक 27.09.2016 के द्वारा एवं स्थाईकरण आदेश जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर के आदेश दिनांक 22.11.2017 एवं संशोधन आदेश दिनांक 04.12.2017 के द्वारा किया गया है, जिनकी छायाप्रतियां परिशिष्ट- "ग" एवं "घ" पर संलग्न है।

(3) मोहम्मद असलम (लेवल-2) विषय उर्दू शिक्षक के परिवीक्षाकाल से नियमितीकरण तक के समस्त पत्राचार/अभ्यावेदन/आदेश/माननीय न्यायालय के आदेश एवं कार्यालय टिप्पणी मय आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट- "ग" एवं "घ" तथा "ड़" पर सम्मिलित/संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति

263. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश के शिक्षकों के लिए कोई स्थानांतरण नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

शिक्षा विभाग अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निदेर्शो के तहत स्थानान्तरण किये जाते हैं।

फुलेरा में संचालित विद्यालयों के भवनों की मरम्मत

264. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में कौन-कौन से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवन कब से मरम्मत योग्य हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु कितनी राशि का आबंटन कब-कब किया गया? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत अथवा नवीन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के मरम्मत योग्य भवनों की विद्यालयवार व वर्षवार सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विगत 5 वर्षों में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवनों की मरम्मत एवं निर्माण की वर्षवार एवं विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-ख पर तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षों/अन्य गतिविधि निर्माण की वर्षवार एवं विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-ग पर संलग्न है। विगत 05 वर्षों में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य नहीं करवाये गये हैं।

(3) जी हां। समग्र शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अनुमत निर्माण कार्य/गतिविधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष स्वीकृत किये जाते हैं। इन आवश्यक कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु देय सुविधाएं

265. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री फूल सिंह मीणा)

(1) प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा विद्यालय व कालेज स्तर पर खिलाड़ियों के लिए क्या-क्या योजनाएं संचालित है व उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा खिलाड़ियों को जिला स्तर व राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर खेलने पर सरकारी नौकरी या अन्य सुविधाएं दी जाती हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी नौकरियां किस-किस विभाग में दी गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खेलों हेतु प्रदान किए जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर विशेष उपलब्धि हेतु विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रतिवर्ष आयु वर्ग 14 वर्ष-छात्र-छात्राओं की क्षेत्रीय/जिला/राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कुल 17 प्रतियोगिताओं से पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इसके लिए खिलाड़ी छात्र-छात्राओं को दिया जाने वाला भोजन भत्ता व पोशाक भत्ता निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**प्रतियोगिता स्तर पर व अन्य भत्ता**	**वर्तमान में देय भोजन भत्ता राशि (रुपयों में)**
1	जिला एवं राज्य	50
2	राष्ट्रीय प्रतियोगिता	150
3	स्थानीय खिलाड़ी अल्पाहार	10
4	निर्णायक अल्पाहार	10
5	पोशाक भत्ता	150

प्रदेश के महाविद्यालयों में खेलों का बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु आयुक्तालय, कालेज शिक्षा द्वारा नवाचार के रूप में प्रदेश के 14 राजकीय महाविद्यालयों में प्रारम्भिक चरण के लिए "अर्जुन दृष्टि योजना" शुरू की गई है। इसके तहत खेलकूद एवं स्पोर्टस हब विकसित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी राजकीय महाविद्यालयों में नियमित खेलकूद गतिविधियां संचालित की जाती हैं। विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

महाविद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों को खेल सामग्री व खेलने के लिए आवश्यक सुविधाओं युक्त खेल मैदान उपलब्ध करवाये जाते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बाहर जाने पर दैनिक व यात्रा भत्ता, ठहरने की उचित व्यवस्था तथा नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय प्राथमिकता तथा पुरस्कार का लाभ दिया जाता है।

(2) जी हां। राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों हेतु कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 के द्वारा अधीनस्थ/मंत्रालयिक सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर व अन्तरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप पुरस्कार राशि एवं विशेष सहायता प्रदान की जाती है। नियम की प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालय महुवा में रिक्त पद

266. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में स्थित राजकीय महाविद्यालय महुवा में किस-किस श्रेणी के पद वर्तमान में स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? श्रेणीवार पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त महाविद्यालय में वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा खेत्र महुवा में स्थित राजकीय महाविद्यालय महुवा में शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-01 एवं अशैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) राजकीय महाविद्यालय महुवा में रिक्त पदों को पदोन्नति/चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/अनुकम्पात्मक नियुक्ति/स्थानांतरण के समय भरा जा सकेगा।

(3) राजकीय महाविद्यालय महुवा में वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों की सूची मय नाम एवं मोबाइल नम्बर परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क

267. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों एवं छात्राओं से प्रतिवर्ष कुल कितना शुल्क लिया जाता है एवं उक्त शुल्क किस-किस शीर्ष में लिया जाता है?

(2) सरकार छात्राओं का किस-किस शीर्ष में कुल कितना शुल्क मुक्त कर रही है?

(3) प्रत्येक छात्रा पर प्रतिवर्ष कुल कितना सकल शुल्कभार है एवं कितना शुल्क मुक्त किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से तीन शीर्ष राजकीय मद में राज्य सरकार के अनुसार एवं छात्रनिधि मद तथा अन्य मदों में महाविद्यालय की स्थानीय आवश्यकतानुसार शुल्क का निर्धारण प्राचार्य स्तर पर ही किया जाकर लिया जाता है। राजकीय महाविद्यालयों में मदवार ली जाने वाली फीस का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के समय छात्राओं/महिलाओं से ली जाने वाली फीस का विवरण निम्न प्रकार है-

1. छात्रनिधि मद।
2. राजकीय मद (पंजीकरण शुल्क, ट्यूशन फीस, प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकालय शुल्क)
3. अन्य शुल्क (महाविद्यालय विकास समिति कोष)

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

उपरोक्त वर्णित शुल्कों में से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(3) शिक्षा/ग्रुप-3/2019 दिनांक 05.03.2019 के तहत शैक्षणिक सत्र 2019-20 से राजकीय महाविद्यालयों की सभी वर्ग की समस्त छात्राओं/महिलाओं के प्रवेश के समय ली जाने वाली राजकीय निधि कोष की राशि को माफ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को राजकीय मद में लिये जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त किया गया है व छात्रनिधि मद एवं अन्य मद में लिये जाने वाला शुल्क सभी राजकीय महाविद्यालयों में अलग-अलग है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत के राजकीय महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

268. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सोजत शहर में स्थित राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यो?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के रायपुर ग्राम में महाविद्यालय स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति कब जारी की गई? स्वीकृति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त महाविद्यालय का भवन निर्माण व अन्य सभी कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि व्यय कर पूर्ण किये गये एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं?

(4) उक्त महाविद्यालय में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, सोजत सिटी से लगभग 38 किमी की दूरी पर जिला मुख्यालय पर स्नातकोत्तर स्तर के राजकीय महाविद्यालय, पाली एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली संचालित हैं।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय महाविद्यालय, सोजत सिटी को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) सोजत विधान सभा क्षेत्र के रायपुर ग्राम में राजकीय महाविद्यालय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत किया गया। स्वीकृति आदेश परिशिष्ट-01 पर संलग्न है। राजकीय महाविद्यालय, रायपुर के नवीन भवन निर्माण हेतु जिला कलेक्टर, पाली द्वारा भूमि आबंटित की जा चुकी है। परिशिष्ट-02

महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। राशि स्वीकृत होने पर भवन निर्माण करवाया जायेगा।

(3) राजकीय महाविद्यालय, रायपुर के भवन निर्माण का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। राजकीय महाविद्यालय, रायपुर में शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-03 एवं अशैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-04 पर संलग्न है।

(4) राजकीय महाविद्यालय, रायपुर के रिक्त पदों को पदोन्नति/चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/अनुकम्पात्मक नियुक्ति/स्थानांतरण के समय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा

269. श्री संदीप शर्मा (कोटा उत्तर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया है? यदि हां, तो कौन-कौन से पाठ्यक्रमों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस योजना के तहत वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में भी बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा संचालित देवनारायण स्कूटी योजना के अन्तर्गत

(श्री संदीप शर्मा)

कॉलेजों में स्कूटी वितरण के क्या नियम व मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक प. 6(3)शिक्षा/ग्रुप-3/2019 दिनांक 05.03.2019 के अनुसरण में शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र क्रमांक प.22(2)शिक्षा-4/2019 दिनांक 04.06.2019 द्वारा विश्वविद्यालयों की सभी वर्गों की समस्त छात्राओं/महिलाओं से प्रवेश के समय ली जाने वाली विश्वविद्यालय निधि कोष/समकक्ष कोष की राशि को माफ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस विश्वविद्यालय की प्रकृति अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) होने के कारण राज्य सरकार की छात्राओं/महिलाओं के नि:शुल्क की योजना को इस विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय से प्राप्त विस्तृत औचित्य परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना के नियमों की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

हड्डा रोड़ी समस्या का निराकरण

महोदय,

मैं आपका ध्यान एक गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहूँगा कि हड्डा रोडी हर गांव शहर में है, परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि हड्डा रोड़ी समस्या आए दिन गम्भीर होती जा रही है। हड्डा रोडी आवश्यक सेवा के अंतर्गत आती है परन्तु आज जहां है वहां पर और जहां नहीं है वहां पर भी समस्या गम्भीर होती जा रही है। जहां है वहां पर नज़दीक आबादी है जिसके कारण से वहां के आसपास में रहने वाले नागरिकों की जिंदगी नर्क की बनी है, जीना बहुत ही दुर्लभ है। दूसरी बात जहां पर हड्डा रोडी नहीं है उन आबादी वाले गांवों की स्थिति दयनीय है। महोदय, काफी गांवों में पशुधन अधिक है परन्तु यहां पर हड्डा रोड़ी नहीं है उन गांवों में मृत पशुओं को डालने के लिए कोई स्थाई जगह नहीं है।

महोदय, जो पशुओं के ठेकेदार हैं उन्होंने पशुओं को उठाना बंद कर दिया है। अब पशु मालिक उक्त मार्ग से मृत पशुओं को अपने ट्रैक्टर या अन्य संसाधन के पीछे बांधकर निजी जमीन में चमड़ी सहित उस पशु को डाल देते हैं। चमड़ी सहित मृत पशु में बदबू अधिक आती है जिससे गंभीर बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मृत पशुओं के डालने के लिए हड्डा रोड़ी की गम्भीर समस्या की तरफ ध्यान दें। परन्तु आज जहां हड्डा रोडी गांव के नजदीक है वहां पर और जहां हड्डा रोड़ी नहीं है वहां पर भी समस्या बहुतगंभीर होती जा रही है। इन दोनों समस्या का समाधान सरकार करें ताकि हड्डा रोड़ी जगह पर यहां पर नई तकनीक से हड्डा रोड़ी बनाई जाए, उससे बदबू को राहत मिले, प्रत्येक आबादी क्षेत्र में समस्या का हल समाधान हो सके।

धर्मेन्द्र कुमार

(पीलीबंगा)

अजमेर के राजकीय विधि महाविद्यालय को स्थाई मान्यता

महोदय,

राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर को स्थाई मान्यता प्राप्त नहीं है। यहां प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए गत वर्षों में महाविद्यालय को अस्थाई मान्यता दी जाती रही है, परन्तु इस प्रक्रिया में लगभग नवम्बर माह तक विद्यार्थियों को प्रवेश मिल पाते हैं।

गत वर्ष महाविद्यालय में शिक्षकों के पदस्थापन किये गये थे तथा वर्तमान में 10 स्वीकृत पदों में से 2 ही पद रिक्त है, परन्तु छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों के अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है। यहां पर स्थाई प्राचार्य तथा लाइब्रेरियन व शारीरिक शिक्षक के पद रिक्त हैं। महाविद्यालय भवन की बाउण्ड्रीवाल, सेमिनार हाल आदि का निर्माण व खेल मैदान का विकास नहीं हो रखा है। इन कमियों के चलते बीसीआई के नोर्म्स पूरे नहीं होने के कारण महाविद्यालय को मान्यता नहीं मिल पा रही है। स्थाई मान्यता नहीं होने तथा अस्थाई मान्यता में लगने वाले समय के कारण विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ती है। सत्र विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण शिक्षण कार्य भी प्रभावित होता है जिससे विद्यार्थियों में भविष्य की अनिश्चितता का वातावरण बन रहा है। अजमेर ही नहीं प्रदेश में स्थित 15 राजकीय विधि महाविद्यालयों में से 11-12 की स्थिति लगभग ऐसी ही है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर सहित प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों को स्थाई मान्यता दिलाने के क्रम में बीसीआई के नोर्म्स के अनुसार स्टाफ की नियुक्ति व अन्य आवश्यक संसाधनों की पूर्ति कराने के साथ ही वर्तमान सत्र को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं जिससे विद्यार्थियों को परेशान न होना पड़े। धन्यवाद।

वासुदेव देवनानी

(अजमेर उत्तर)

अवैध बजरी खनन की रोकथाम

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी

नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं खनिज मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि पूरे प्रदेश में माननीय न्यायालय के निर्णय के चलते बजरी खनन पर रोक है। कोर्ट की रोक के बावजूद पूरे प्रदेश में बजरी का अवैध खनन हो रहा है। बजरी माफिया पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है एवं वे स्थानीय पुलिस एवं खनन अधिकारियों से मिलीभगत कर अपना व्यापार धड़ल्ले से चला रहे हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना में भी अवैध बजरी खनन हो रहा है जिसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को भी है परन्तु वे आंख मूंदे हुए हैं। हालात इतने विकट हैं कि आम आदमी अवैध खनन करने वालों की शिकायत करने से भी डरता है क्योंकि प्रदेश में ऐसे कई वाकये हो गये हैं जिनमें अवैध बजरी व्यापार करने वालों ने अधिकारियों एवं आम जनता को अपना शिकार बनाया है। स्थिति की भयावहता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि बजरी माफिया के लोग हत्या तक करने से गुरेज नहीं करते हैं।

ऐसी विकट परिस्थितियों में मेरा राज्य सरकार एवं खनिज मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रदेश के साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना में हो रही अवैध खनन गतिविधियों पर तुरन्त लगाम लगाई जाए एवं दोषी अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से बर्खास्त किया जाए। साथ ही बजरी माफिया से जुड़े लोगों को जेल के सींखचों में डाला जाए। धन्यवाद।

विजयपाल मिर्धा

(डेगाना)

जोबेनेर के श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विज्ञान संकाय में छात्रों के साथ धोखाधड़ी

महोदय,

मैं उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के द्वारा कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के मामले में छात्रों के साथ हुई धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान एवं अनियमितताओं से छात्रों के भविष्य पर रोजगार के संकट के बारे में विशेष उल्लेख प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं कि विश्वविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम स्वयं वित्त पोषित योजना में होने के कारण प्रति छात्र शुल्क 10 लाख रुपये लिये गये एवं लगभग एक करोड़ रूपये का फण्ड प्राप्त हुआ। वर्ष 2014-2016 सत्र में कुल 9 छात्रों ने कृषि विज्ञान में

स्नातकोत्तर उपाधि पूर्ण की। चूंकि यह पाठ्यक्रम न तो राज्य सरकार से और न ही ICAR New Delhi से मान्यता ली गई थी। विश्वविद्यालय के अपने दीक्षान्त समारोह में इन विद्यार्थियों को किसी प्रकार के आनर्स एवं मेडल से भी वंचित रखा गया।

चूंकि पाठ्यक्रम स्वयं वित्त पोषित योजना से एवं ICAR New Delhi से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य की अन्य भर्तियों में भी कई प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, जो कि उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए एक चिंतनीय विषय है।

उक्त प्रकरण में पाठ्यक्रम के शुल्क संबंधी मानदण्डों एवं नियमों की उचित पालना किये जाने पर संशय है, जिसकी जांच करवाया जाना औचित्य प्रतीत होता हैं। इसके साथ ही इस संबंध में प्राप्त लगभग एक करोड़ रुपये की राशि का क्या प्रबंधन किया गया, वो भी जांच करवाने का विषय है। कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम को शीघ्र मान्यता दिलाये जाने के सकारात्मक प्रयास किये जाने चाहिए। साथ ही पूर्व में इस पाठ्यक्रम को पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों के साथ भी सहानुभूति पूर्ण विचार कर न्याय दिलाया जाना चाहिए।

सतीश पूनियां

(आमेर)

रूपवास में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन कर आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास कस्बे की शिक्षा व्यवस्था की और करना चाहता हूं। रूपवास कस्बे के आसपास करीब-करीब दो सौ गांव हैं। रूपवास कस्बे में एक भी राजकीय महाविद्यालय न होने के कारण विद्यार्थियों को यहां से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर भरतपुर आना-जाना पड़ता है जिससे विद्यार्थियों को पर्याप्त अध्ययन का समय भी नहीं मिल पाता है। यहां पर तकरीबन हर साल एक हजार से अधिक ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो महाविद्यालय नहीं होने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यहां एक राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की बहुत आवश्यकता है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इसी सत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र के रूपवास में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा करने की कृपा करें।

सादर।

अमर सिंह

(बयाना)

जोधपुर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर में खेल विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। पूरे विश्व में खेल राष्ट्र की वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय हो गया है। खेलों में उच्च उपलब्धियां वाले देश की विश्व पर्यटन मानचित्र पर ऊंची रेटिंग होती है। भारत भी खेल उपलब्धियों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के खिलाड़ियों का खेलों में प्रदर्शन बहुत ही उच्च स्तरीय उपलब्धियों का रहा है। ऐसे में भारत के पश्चिमतम प्रान्त राजस्थान को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। खेलों में लगातार बढ़ रही तकनीक के प्रयोग ने इसे पूर्णतया वैज्ञानिक कौशल युक्त प्रशिक्षण-अभ्यास क्रम बना दिया है। अतः खेलों में आगे बढ़ने के लिए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना एक योजनाबद्ध कार्ययोजना की मजबूत कड़ी सिद्ध होगा। मेरी मांग है कि जोधपुर में राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर से संलग्न 35 बीघा भूमि का उपयोग करते हुए यहां राजस्थान खेल विश्वविद्यालय, जोधपुर खोला जाए। यहां पर खेल विज्ञान और खेल औषधि, खेल प्रबन्धन और तकनीकी खेल शिक्षा, खेल से जुड़े विभिन्न विषयों का आपसी जुड़ाव, खेल का समाज जीवन पर प्रभाव, खेल का आर्थिक प्रभाव, खेलवार प्रशिक्षण के अलग-अलग संकाय खोलकर उच्च स्तरीय शोधपरक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इससे हमारे राजस्थान में युवाओं के जीवन को सकारात्मक दिशा मिलेगी। खेल मानचित्र पर राजस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। युवाओं में खेल की प्रवृत्तियों का विकास होने से वे घातक मादक पदार्थों के सेवन की बढ़ रही प्रवृत्तियों एवं अन्य नकारात्मक गतिविधियों में संलग्न होने से बच सकेंगे। खेलों के बढ़ रहे चलन के लिए उच्च स्तरीय खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, खेल निर्णायकों की उत्पन्न होने वाली मांग की पूर्ति के लिए हम तैयार हो पाएंगे। यह नवीन

राजस्थान का एक महत्वपूर्ण आयाम सिद्ध होगा और शिक्षा को पूर्णता प्रदान करेगा।

सादर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

पाटन (नीमकाथाना) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पाटन एक महत्वपूर्ण एवं बड़ा कस्बा है जहां पंचायत समिति एवं उप तहसील है लेकिन कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है जबकि कई प्राइवेट महाविद्यालय चल रहे हैं।

महोदय, उपरोक्त कस्बा मेरे क्षेत्र से काफी बड़े क्षेत्र पाटनवाटी के मध्य में स्थित है एवं सीकर दिल्ली लिंक हाईवे पर स्थित है। इस कस्बे में एवं इसके आसपास किसान एवं मजदूर काफी संख्या में रहते हैं जिनके बच्चे निजी संस्था में अध्ययन करने हेतु आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं क्योंकि निजी संस्थाओं में मोटी फीस वसूल की जाती है, जो किसान एवं मजदूर वर्ग वहन नहीं कर सकता। इस वर्ग के लोग अपनी बेटियों को दूर पढ़ने के लिए भेजने में भी हिचकते हैं। यह क्षेत्र खनन क्षेत्र भी है, अतः काफी खनन श्रमिक भी यहां रहते हैं। उपरोक्त कारणों से उक्त क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग काफी समय से कई संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं जनता की ओर से उठाई जाती रही है। भामाशाह महाविद्यालय के लिए भवन बनाने को भी तैयार है एवं सरकारी भूमि भी कस्बे में काफी उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से इस विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करता हूं कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बाद क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने हेतु पाटन कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

सुरेश मोदी

(नीमकाथाना)

बौंली में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के निय 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बामनवास काफी बड़ा क्षेत्र है। इसमें दो पंचायत समिति बामनवास एवं बौंली हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में लगभग तीन लाख की जनसंख्या निवास करती है। मेरा विधान सभा क्षेत्र जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कोई भी राजकीय महाविद्यालय वर्तमान में संचालित नहीं है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कालेज में पढ़ाई करने से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर जनजाति बहुल होने के कारण छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने में असुविधा हो रही है। यहां से 12वीं पास करने के बाद बालक/बालिकाएं उच्च अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं तथा निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों की फीस बालक/बालिकाएं भरने में असमर्थ होते हैं।

अतः मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करती हूं कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बौंली में राजकीय महाविद्यालय खोलने के आदेश जारी कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्रीमती इन्द्रा

(बामनवास)

गैर मुमकिन भूमि पर बसी कालोनियों का आबादी भूमि में परिवर्तन

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान में स्थित अनेक गांव की जनसंख्या गैर मुमकिन भूमि पर बसी होने के कारण केशवरायपाटन (बून्दी), रामगंजमंडी (कोटा) विधान सभा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण प्रदेश के इन स्थानों पर केन्द्र व राज्य सरकार की अनेक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना, सड़क, चिकित्सा, विद्यालय व सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण व जनता की मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली को पहुंचाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में लगभग 7 करोड़ जनता निवास करती है जिसमें अनुसूचित जाति 19% अनुसूचित जनजाति 13%

जनसंख्या लगभग है जो अधिकतर गैर मुमकिन भूमि पर निवास करते हैं। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ भी लगभग इन्हीं वर्गों के व्यक्तियों को प्राप्त होना है। इन योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायतों व नगर निकायों द्वारा आवास बनाने हेतु पट्टे जारी नहीं करने के कारण आवास निर्माण नहीं हो पा रहे हैं। ग्राम पंचायतों व नगर निकायों द्वारा भी समय-समय पर उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को भेज रखे हैं।

इसीलिए मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि प्रदेश में स्थित सभी गैर मुमकिन भूमियों का सर्वे कराकर सूची बनाकर व भौतिक सत्यापन कर, कैम्प लगाकर आबादी भूमि में परिवर्तित किया जाने व इन भूमियों पर बसी हुई जनता की बस्तियों को ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर परिषद् व नगर निगमों को निःशुल्क आवासीय पट्टे जारी करने के आदेश राज्य सरकार से प्रदान कराने की कृपा करें।

इसी आशा एवं विश्वास के साथ विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सधन्यवाद,

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल

(केशवरायपाटन)

जयपुर के दरबार स्कूल की जमीन पर हाई स्कूल और बालिका महाविद्यालय की स्थापना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में राजकीय उच्च प्राथमिक बेसिक माडल दरबार स्कूल जो प्राचीन एवं ऐतिहासिक धरोहर है तथा यह स्कूल शहर के मध्य स्थित है। इस स्कूल का भवन आज जर्जर अवस्था में है और खंडहर हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस भवन का पुनर्निर्माण कराया जाए जिससे सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके। साथ ही यह भी अनुरोध है कि यदि इस प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाकर शेष बची हुई जमीन पर यदि कन्याओं के लिये कन्या महाविद्यालय भवन बनवा दिया जाए तो इससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित होगा तथा क्षेत्र की गरीब एवं मध्यमवर्गीय जनता को काफी राहत मिलेगी।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बजट में राजकीय उच्च प्राथमिक बेसिक माडल दरबार स्कूल को प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करें एवं बालिका महाविद्यालय शीघ्रातिशीघ्र खोले जाने के आदेश प्रदान करें।

अमीनुद्दीन कागजी

(किशनपोल)

भादरा व नोहर में सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भादरा नोहर का हिस्सा माह जुलाई में 850 क्यूसेक प्रतिदिन तय हैं लेकिन हरियाणा व पंजाब की तरफ से प्रतिदिन 300-400 क्यूसेक कम पानी दिया जा रहा है जिससे हमारी सिद्धमुख नहर, अमरसिंह ब्रांच, नोहर फीडर में पूरा पानी नहीं मिल रहा। जिससे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर हिस्से का पूरा पानी दिलवाकर किसानों के लिए पूरे पानी की व्यवस्था की जायेगी। खाला निर्माण में मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी पूरे खाले नहीं बने हैं जिससे किसानों को भारी परेशानी आ रही है। अत: सरकार तकरीबन 40 करोड़ रुपये का प्रबंध कर किसानों के खेतों में सिंचाई पानी के खाला निर्माण का प्रबंध करवाये।

बलवान पूनियां

(भादरा)

रूदड़ी (कपासन) के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान व श्मशान की भूमि पर अतिक्रमण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के खेल मैदान की व श्मसान की भूमि पर पड़ौसी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक व ग्रामवासियों ने अतिक्रमण हटाने की शिकायत उपखण्ड अधिकारी को दी गई। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की गई परन्तु अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण कर लेता है। मेरा निवेदन है कि अतिक्रमी के कब्जे से विद्यालय के खेल मैदान की व श्मशान की भूमि को मुक्त कराने की पुख्ता कार्यवाही कराएं।

इसी के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अर्जुन लाल जीनगर

(कपासन)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक **चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में चिकित्सकों, नर्स एवं कम्पाउण्डरों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवाई वितरण केन्द्रों में मरीजों को पूर्ण दवाइयां नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के चिकित्सालयों में उचित तरीके से साफ-सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

4. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के चिकित्सालयों में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर):

5. जिला नागौर के नागौर शहर में मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र नागौर के नागौर शहर में सैटेलाइट चिकित्सालय अथवा शहरी सीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

7. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बैड किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के प्रतापगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टहला में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के बस्सी जोगियान, नीमला व हमीरपुर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित चिकित्सकों के स्वास्थ्य केन्द्रों से नित्य नदारद रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

12. पंचायत समिति समदड़ी मुख्यालय पर नवीन ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. उपखण्ड मुख्यालय सिणधरी पर ट्रोमा सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी पर बिजली कट होने पर जनरेटर सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के विभिन्न पीएचसी एवं सीएचसी में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने एवं पूरे क्षेत्र में महिला चिकित्सक 20 वर्षों से पदस्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की मुख्य पीएचसी पादरू को सीएचसी में क्रमोन्नत एवं नई पीएचसी सिणेर एवं डन्डाली में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

17. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर में ट्रोमा सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. घासा (मावली) की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर में ANM प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

20. मालपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को ट्रोमा अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायत मोर, पारली व उणियारा

खुर्द को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. टोडारायसिंह में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये नवीन भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. मालपुरा अस्पताल में नवीन ब्लड बैंक की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की मरम्मत कराने एवं संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

25. ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में चिकित्सकों व कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर भेजने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में चिकित्सा सेवा के सभी रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. शहर व गांवों में एक समान चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. कुन्दनपुर पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

29. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के मरायता ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में नकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बैडों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनवाड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सभी सरकारी चिकित्सालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी रिक्त पदों को तुरन्त भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

32. विधान सभा क्षेत्र आहोर के शंखवाली में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र आहोर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सियाणा में चिकित्सको के रिक्त पद को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. ग्राम हरजी में स्थित पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

36. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के नगरपालिका क्षेत्र में फैल रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन व ट्रोमा सेन्टर हेतु भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. चौमूं में सड़क व नालियों की सफाई नहीं होने तथा गन्दगी के ढेर लगे होने से फैल रही बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम अणतपुरा-जैतपुरा, आलीसर व धोबलाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

41. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की सीएचसी को 100 बैड के चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बानसूर एवं नारायणपुर सीएचसी पर स्त्री रोग विशेषज्ञ का पदस्थापन करने व रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के नारायणपुर ब्लाक व गांवों में फैल रही बीमारियों की रोकथाम के लिये फोगिंग मशीन से कीटनाशक का छिड़काव करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. प्रदेश में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी (आयुष) चिकित्सक व

नर्सेज का एक समान वेतनमान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

45. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों व नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. श्री सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ में नवीन कैथ लैब की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

47. श्रीडूंगरगढ़ तहसील के गांव दुलचासर में स्थित पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. श्रीडूंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के चिकित्सालयों में ANM एवं GNM के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

52. बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के ग्राम पराड़ीया में पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के चिकित्सालयों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. बाड़मेर जिले के भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरडीया, बालेवा व रामदेव मन्दिर हेतु भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. बाड़मेर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धोनिया-खलीफे की बावड़ी में चिकित्सकों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. बाड़मेर जिले की तहसील रामेसर के कस्बा गागरिया की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

57. मेडिकल कालेज बाड़मेर के अधीन राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पीएचसी, सीएचसी में अधिशेष उप स्वास्थ्य केन्द्र साजटा को उप स्वास्थ्य केन्द्र सुजान नगर, उप स्वास्थ्य केन्द्र भादरेश को उप स्वास्थ्य केन्द्र गुडीसर, उप स्वास्थ्य केन्द्र नांद को उप स्वास्थ्य केन्द्र नारणोणियों की ढाणी, उप स्वास्थ्य केन्द्र मीण्डा को उप स्वास्थ्य केन्द्र कनोड़ा तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र बेरीवाल तला को उप स्वास्थ्य केन्द्र चवोणी मेघवालों की ढाणी में शिफ्ट करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

59. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में मेडिकल कालेज बनाने व उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमर सिंह (बयाना):

60. राजकीय चिकित्सालय बयाना में सोनोग्राफी मशीन के अभाव में मरीजों को हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र बयाना (भरतपुर) के रूदावल कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 108 एम्बूलेंस की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रूपवास में सोनोग्राफी मशीन के अभाव में मरीजों को हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र बयाना में स्थित सीएचसी, पीएचसी व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र बयाना (भरतपुर) के रूदावल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

65. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के आनन्दपुर कालू की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की सीएचसी हेतु 75 बैड की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

68. विधान सभा क्षेत्र दौसा के बनियाना, काली पहाड़ी एवं लाहड़ी का बास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र दौसा के उपखण्ड मुख्यालय नांगल-राजावतान पर संचालित पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

70. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र सिलदर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र जावारय को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. सिरोही जिले के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पराडा, आलपा, मनादर, बांट को पीपीपी मोड से हटाकर वापस सरकार के अधीन लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. सिरोही जिले के चिकित्सालय की क्षमता 200 बिस्तर से 300 बिस्तर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में मेडिकल कालेज के लिये 15 हैक्टेयर भूमि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

75. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के पुर (उपनगर) में 35 वर्ष पुरानी पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. भामाशाह स्वास्थ्य योजना में होने वाला 03 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के उपनगर पुर जो कि शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, की पीएचसी में 24 घण्टे चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. भीलवाड़ा शहर में जवाहर नगर लेबर कालोनी एवं गांधी नगर में एक नया पीएचसी शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

79. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव फेकारिया, पाती, बस्सी, मुरडिया, साजी में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव मांडावास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र पाली के बांगड़ अस्पताल के आपरेशन थियेटर में हड्डी रोग वाले थियेटर में टूटी हुई आपरेशन टेबल को नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र पाली के बांगड़ अस्पताल में नाक, कान एवं गला रोग विभाग में गूंगे-बहरे लोगों की जांच हेतु आडियो मीटर उपकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

83. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता में ब्लड बैंक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मोकलपुर, इन्दावड़ जैसे बड़े गांवों में चिकित्सा व्यवस्था की बिगड़ी हुई हालत पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता को 100 बैड का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. मेड़ता शहर में सिटी डिस्पेन्सरी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

87. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में पशु चिकित्सालय, जालूपुरा की भूमि को चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर कर सैटेलाइट अस्पताल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

88. बांगड़ चिकित्सालय पाली में निश्चेतना विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

89. सीएचसी जहाजपुर में ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत करने एवं चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के नाथुण, तलोदा व भवानीपुर में सब-सेन्टर स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के लुहारी कलां में पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम अमरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पन्डेर व खजूरी के पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

94. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के सभी चिकित्सालयों के रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

95. विधान सभा क्षेत्र कपासन के सभी चिकित्सालयों में विभिन्न रिक्त पदों पर पदस्थापन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

96. डीडवाना उप जिला अस्पताल में ट्रोमा सेन्टर की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की राजकीय चिकित्सा इकाइयों में चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृतशुदा पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के गांव चक खारडिया गिरधारीपुरा खुडी निम्बी, पाबूपुरा, पाटण, पावटा में चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावरा एवं

ठाकरियावास को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के चिकित्सा उपकेन्द्र सानिया एवं सिंघाना को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर):

101. विधान सभा क्षेत्र डग में अस्पताल को क्रमोन्नत करने, ट्रोमा सेन्टर खोलने व चिकित्सक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मंजु देवी (जायल):

102. विधान सभा क्षेत्र जायल के मुख्यालय पर स्थित सीएचसी में रिक्त पद को भरने एवं बैड संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

103. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सभी सीएचसी में सोनोग्राफी मशीनें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जमवारामगढ़ को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

105. सामान्य चिकित्सालय बाड़ी को 200 बैड, सैपऊ अस्पताल को 50 बैड एवं बसई नवाब अस्पताल को 50 बैड का किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

106. राज्य में औषधि नियन्त्रक विभाग द्वारा नकली वैक्सीन, नकली दवाइयां एवं मेडिकल दुकानों की नियमित जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. जयपुर मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा, माण्डल चौराहा तक स्टेट हाईवे पर ट्रोमा सेन्टर की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थापित अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप केन्द्रों में चिकित्सक, नर्स, कम्पाउण्डर, टैक्निशियन व अन्य सहायक कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में शाहपुरा नगर में स्थापित सैटेलाइट अस्पताल में 100 बैड के मापदण्ड के अनुरूप साधन-सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. राज्य में बिना बताये लम्बे समय से अनुपस्थित चिकित्सकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

111. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में सामुदायिक केन्द्रों व डिस्पेन्सरियों में चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कार्मिकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. ग्राम रोनीजायान (कठूमर) में चिकित्सक का पद स्वीकृति के बाद भी कई वर्षों से पदस्थापन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. सरकारी अस्पतालों (कठूमर, खेरली) में मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

114. विधान सभा क्षेत्र नोखा की नोखा तहसील मुख्यालय पर स्थित मांगीलाल बागड़ी राजकीय रैफरल चिकित्सालय में ट्रोमा-सेन्टर की स्थापना, रक्तकोष व सोनोग्राफी जांच की सुविधा उपलब्ध करवाने व उक्त चिकित्सालय में स्वीकृत सभी रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र नोखा में स्थित आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कक्कू व जांगलू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र नोखा में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत मुख्यालय जेगला, बंधाला व रोड़ा में स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र नोखा में भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण एवं रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

118. अलवर शहर में मेडिकल कालेज के लिये जेल परिसर में आबंटित

भूमि पर मेडिकल कालेज का निर्माण शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. अलवर शहर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय व सैटेलाइट अस्पताल काला कुआं में 100-100 बैड बढाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. अलवर शहर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों के पद सृजित कर नियुक्ति करने व सभी चिकित्सालयों में वरिष्ठ, कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. अलवर शहर में स्थित शहरी चिकित्सालय नम्बर 02, एन.ई.बी. को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने एवं वैशाली नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

122. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के राजकीय नाहटा चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

124. नाहटा चिकित्सालय में सघन चिकित्सा इकाई, डायलिसिस मशीन स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के विभिन्न ग्रामों में नये चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. राजकीय नाहटा चिकित्सालय में बरसाती पानी के भराव से निजात दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

127. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सामान्य चिकित्सालय में सोनोग्राफी, एन्जियोग्राफी, सी.टी. स्कैन, एमआरआई कार्डियोग्राफी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने तथा बैड संख्या 100 से 200 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजस्व गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा आयुर्वेदिक विभाग में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद भरने

तथा प्रथम श्रेणी चिकित्सालय केजड में आयुर्वेदिक चिकित्सक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के बडावली, बरोडा, सराडी व करावली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर्स एवं मेल नर्स क्वाटर्स का निर्माण नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडावली बरोडा, सराडी, करावली, जयसमन्द में चिकित्सकों, नर्स कम्पाउण्डर, सफाईकर्मी के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में इडाणा, खरखा, गुडेल, खैराड, डाल, टोडा, पीलादर केवड़ा, नठारा, बलुआ आदि में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा जावद, देवपुरा, उथरदा, बडगांव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

132. विधान सभा क्षेत्र चूरू में चिकित्सा केन्द्रों में आवश्यक संसाधनों के अभाव में चरमराई हुई स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र चूरू के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र चूरू में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित अन्य चिकित्सा केन्द्रों पर पैरामेडिकल के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर):

135. चिकित्सालय, सवाई माधोपुर में जांच सुविधा/सफाई पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

136. चिकित्सा विभाग में रिक्त डाक्टर्स के पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. जयपुर में निर्मित कैंसर हास्पिटल को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. जयपुर शहर के एस.एम.एस. हास्पिटल पर बढ़ रहे मरीजों के दबाव को कम करने के लिए शहर के कांवटिया, जयपुरिया एवं गणगौरी बाजार स्थित अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल के मुख्य भवन की नियमित रख-रखाव न होने के कारण लगातार भवन जर्जर होता जा रहा है, पर चर्चा के लिये।

140. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रदेश में अघोषित रूप से बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

141. विधान सभा क्षेत्र बाली के सादलवा, टीपरी, चिमनपुरा, रडावा, इन्द्रा कालोनी फालना, भागली, फतापुरा आदि में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र बाली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जर्जर अवस्था में पड़ी वाहन 108 व 104 को शीघ्र बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र बाली के भंदर ग्राम पंचायत में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की चर्चा के लिये।

144. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाली में ब्लड बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाली को रैफरल अस्पताल में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

146. सीटी स्कैन, सोनोग्राफी व MRI जैसी अधिक खर्च वाली जांचों को फ्री जांच की सूची में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में ब्लड बैंक की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. मुण्डावर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर 100 बैड का बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

149. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की राजकीय चिकित्सा इकाइयों में महिला चिकित्सक व महिला स्टाफ लगाते हुए लेबर रूम्स को स्वच्छ व सुविधा युक्त बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के रेवदर मुख्यालय एवं आबू रोड में ब्लड बैंक स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र रेवदर उपखण्ड क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की सभी एम्बुलेंस सुविधाएं बन्द पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरोही, मण्डार एवं चनार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गांव थल, वाडका, दादरला, रानाडी, आवाडा आदि गांव में चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

154. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में मेडिकल मोबाइल यूनिट सेवाओं का सही ढंग से संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सी.एच.सी. बौंली में शय्याओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पी.पी.पी. मोड पर संचालित पी.एच.सी. सुकार एवं गुर्जर बड़ौदा को पीपीपी मोड से हटाकर सरकार के अधीन लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में चिकित्सा केन्द्रों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करना एवं टेण्डरों में सीएमएचओ द्वारा भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

158. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में बाईपास सर्जरी (हृदय) प्रारम्भ करने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक का पदस्थापन शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. उप स्वास्थ्य केन्द्र हाथीखेड़ा, अजमेर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में सुपर स्पेशलिटी ब्लाक स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में नई सी.टी. स्कैन मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. राजकीय महिला चिकित्सालय, अजमेर में रक्त आदि की सम्पूर्ण जांच हेतु प्रयोगशाला खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

163. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी होने व बिल्डिंग का रिनोवेशन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

164. पीलीबंगा राजकीय चिकित्सालय में बैड बढ़ाने व नर्सिंग स्टाफ एवं डाक्टरों की स्थाई पोस्टिंग करने एवं जर्जर हालात में बिल्डिंग का पुनर्निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा):

165. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू के अन्तर्गत आने वाले पी.एच.सी., सी.एच.सी. में डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल):

166. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फलासिया का भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फलासिया में बैड बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन की व्यवस्था शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

170. कोटा व बून्दी जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक उप-केन्द्रों व मेडिकल कालेज कोटा में रिक्त पदों को भरने हेतु चर्चा के लिये।

171. कोटा व बून्दी जिले में स्थित सभी ग्राम पंचायतों पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. कोटा संभाग में स्थित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक की शीघ्र नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. लाखेरी नगर में स्थित राजकीय ट्रोमा चिकित्सालय में स्वीकृत

चिकित्सक, सर्जन व नर्सिंग स्टाफ की शीघ्र नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. बून्दी व बारां नगर में मेडिकल कालेज की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

175. विधान सभा क्षेत्र दूदू के कार्यक्षेत्र में रसीली से बगरू एम.डी.आर. रोड 81 पर चिकित्सा विभाग के एन.आर.एच.एम. विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क परिधि की सीमा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झाग का भवन बनाने से एक्सीडेंट होने की सम्भावना पर चर्चा के लिये।

176. नेशनल हाई-वे जयपुर अजमेर रोड़ पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फर्स्ट रैफरल यूनिट दूदू को क्रमोन्नत कर उप जिला अस्पताल के रूप में घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दूदू को 100 बैड का अस्पताल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. प्रदेश के निवासी की वर्ष में एक बार हार्ट, कैंसर व किडनी की निःशुल्क जांच करने की निःशुल्क जांच योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. जयपुर जिले के खण्ड दूदू और खण्ड फागी के कार्य क्षेत्र में स्वीकृत उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

180. विधान सभा क्षेत्र कामां के अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण व मशीनें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र कामां के सब-सेन्टरों को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

182. विधान सभा क्षेत्र आमेर के जालसू में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. आमेर शहर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

184. जयपुर जिले की सीकर एवं दिल्ली रोड पर ट्रोमा सेंटर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

185. चिकित्सकों की कमी को पूरा करने हेतु विशेषज्ञों की नई भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में PHC/CHC सब सेन्टर, चिकित्सालयों में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने व जांचों की व्यवस्था करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

187. किडनी, लीवर व हार्ट ट्रांसप्लांट-अंगदान के विषय में जन चेतना व अस्पतालों में व्यवस्था करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

188. सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के भवन की जर्जरता को देखते हुये नया भवन बनाने की आवश्यक्ता पर चर्चा के लिये।

189. नये मेडिकल कालेजो में चिकित्सा शिक्षकों व स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

190. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में PHC एवं CHC के सरकारी भवन निर्माण करने तथा चिकित्सक/स्टाफ क्वाटर्स बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में PHC एवं CHC चिकित्सालयों में विशेषज्ञ/चिकित्सक, जांच उपकरण एवं दवाइयों का अभाव रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में चिकित्सालयों में ही प्रतिमाह विशेषज्ञों द्वारा बीमारी की जांचों हेतु शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोजवाड़ी एवं बड़वा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा उप केन्द्र-खतेपुरा एवं लालगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के कानोता, बस्सी, तूंगा एवं बांसखोह में गंदगी के कारण उत्पन्न बीमारियों एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

195. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर में रैफरल हास्पिटल की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर में 108 एम्बुलेंस की उपलब्धता का केन्द्र स्वीकृत किये जाने के संबध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

197. रावतसर ट्रोमा सेन्टर में ब्लड बैंक शुरू करने, नर्सिंग स्टाफ व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

198. प्रदेश में चिकित्सकों के खाली पद भरने एवं चिकित्सालयों में अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना):

199. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जावर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

200. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में कोल्हु, खेड़ीकला, ल्हास एवं सोरती में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

201. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के बुहाना सामुदायिक केन्द्र में आपरेशन थियेटर तैयार होने के बावजूद भी आपरेशन की सुविधा से वंचितहोने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सूरजगढ़, बुहाना व सिंघाना चिकित्सालयों में मुर्दा घर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सामुदायिक केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत डाक्टर व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सूरजगढ़, बुहाना व सिंघाना में अस्पताल को 50-50 बैड के किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में BCMO आफिस खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी) **:**

206. रामगंजमण्डी तहसील के सभी चिकित्सालयों में पूरा स्टाफ व अन्य तय सुविधाएं नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

207. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में डाक्टर्स एवं नर्सिंग कर्मी के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के सभी PHC को CHC में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

209. एस.एम.एस. अस्पताल सहित सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई के उचित प्रबंधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. प्रदेश में आमजन का भामाशाह कार्ड एवं केन्द्र सरकार की आयुष्मान योजना की तरह 8 लाख तक का इलाज नि:शुल्क करवाने की योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. एस.एम.एस. हास्पिटल में अन्तरराष्ट्रीय सुविधा युक्त प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के सांगानेर कस्बे में सैटेलाइट अस्पताल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादडी):

213. सी.एच.सी. बड़ी सादड़ी को 100 बैड अस्पताल में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

214. सरकार की प्रदेश में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा अनुरूप चिकित्सा विभाग में डाक्टरों व पैरा मेडिकल के हजारों पद रिक्त होने के कारण चिकित्सा व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

215. राजकीय मेडिकल कालेजों में डाक्टर एवं पैरा मेडिकल के विभिन्न स्टाफ की अत्यधिक कमी होने के कारण कालेजों की मान्यता पर संकट उत्पन्न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

216. राज्य में विभाग द्वारा विभिन्न खाद्य सामग्रियों के हजारों की संख्या में सैम्पल वर्षों तक उचित निर्णय के अभाव में लंबित पड़े रहने के कारण विभाग की उपयोगिता समाप्त हो जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

217. बाजारों में बिकने वाली अमानक दवाइयों की रोकथाम पर विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की विफलता पर चर्चा के लिये।

218. सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में आयुर्वेद पद्धति पर ध्यान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

219. जिला जयपुर के जामडोली में स्थित कुष्ठ रोगियों के अस्पताल/आश्रम में उपलब्ध करीब बारह बीघा भूमि पर जिला अस्पताल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

220. सेठी कालोनी आदर्श नगर जयपुर में स्थित हास्पिटल को 125 शय्या की सुविधा में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

221. जयपुर शहर के मोती डूंगरी रोड पर स्थित मोबाइल सर्जिकल यूनिट को सैटेलाइट में परिवर्तित करने के संबंध में।

222. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में ग्राम पंचायत विजयपुरा, सुमैल एवं बगराना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

223. प्रतापगढ़ जिले में ग्राम पंचायत देवपुरा मुख्यालय पर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

224. प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में 120 बैड की अतिरिक्त बढ़ोतरी करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ में सुहागपुरा एवं दलोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में रायपुर जंगल, मोटा धामनिया, बोरी- A, हिगंलाट, चकुण्डा, उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत के संबंध में चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरिया, अचनेरा, आम्बीरामा को पी.पी.पी. मोड से हटाकर पुन: सरकार द्वारा संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

228. संगरिया व टीबी में राजकीय चिकित्सालय में बैड बढ़ाने व नर्सिंग स्टाफ व डाक्टरों की स्थाई नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

229. एम्बुलेंस सेवा 104 व 108 के सुसंचालन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

230. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम बूज, नेवर, इन्द्रगढ़, सामरेड, फूटाला, नीमला एवं महंगी के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नायला के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की पी.एच.सी. ताला को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

234. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को नये भवन में शिफ्ट करने के संबंध में चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के समस्त चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में स्थित फुलेरा, सांभर, किशनगढ़, रेनवाल तथा नरैना में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

237. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा, किशनगढ़-रेनवाल एवं सांभर तथा नरैना के चिकित्सालयों में स्टाफ के आवास की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

239. विधान सभा क्षेत्र नोहर के चिकित्सालय को 100 बैड के चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुंदा):

240. विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा के चोरबावड़ी, माजावाड़ा, मोरवी, तुला, रावलिया कलां में ANM सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्राम-मजावद, तहसील-गोगुंदा (उदयपुर) में नई पी.एच.सी. खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. सी.एच.सी. गोगुन्दा को 30 बैड से 50 बैड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. सी.एच.सी. गोगुंदा में सोनोग्राफी मशीन लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

244. ब्लाक गोगुंदा (उदयपुर्) के BCMO कार्यालय हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

245. विधान सभा क्षेत्र लोहावट के स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

246. जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पोस्टीकीयो विट्रक्टोमोइ मशीन खराब होने से नेत्र रोग मरीजों को हो रही परेशानी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

247. अजमेर शहर के सैटेलाइट अस्पताल आदर्श नगर में आने वाले मरीजों को 24 घण्टे चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सालय के समीप स्थित रिक्त भूखण्डों पर चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों के आवास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदेश के मरीजों को दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. NURHM के तहत स्वीकृत एवं निर्मित स्वास्थ्य केन्द्र चन्दबरदाई एवं नाका मदार में स्थाई चिकित्सकों के पद सृजित कर नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना):

251. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

253. प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टर्स के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने हेतु आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

254. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सामान्य चिकित्सालयों में मरीजों के अनुपात में बैड बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में ट्रोमा सेन्टर में संबंधित डाक्टरों के पदस्थापन के संबंध में चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में डाक्टरों व नर्स के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

258. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र मझोला में पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

259. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करड़ा में भवन निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

260. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त चल रहे चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों आदि के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र कुडा (पांचला) हेतु नये भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम वाडा भोजा, सेवाडिया, रूपावटी कलां में स्वीकृतशुदा उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम जीतपुरा, बिकनवास, धनपुरा, कोटड़ा, जैतपुरा, चारा व चेकला, नेलीया में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

264. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़ में स्वीकृत चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

265. गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर State Highway No. 03 पर अनूपगढ़ शहर में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

266. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़ में परीक्षण जांच हेतु सोनोग्राफी और एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

267. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़ के जर्जर स्टाफ क्वार्टर्स का पुनर्निर्माण किये जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रावला मण्डी के 20 बैडेड अस्पताल को 30 बैडेड अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

269. विधान सभा क्षेत्र डग में उमरिया उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

270. प्रदेश में सभी स्वास्थ्य केन्दों पर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

271. आवर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिये जाने एवं चौमहला सीएचसी को 50 बैड में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

272. विधान सभा क्षेत्र डग के डग कस्बे में स्थित सीएचसी को ट्रोमा सेन्टर बनाये जाने तथा स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

273. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

274. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के सुरसुरा तथा कुचील प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करना तथा भायोलाव, देवपुरी, खण्डाच, खातोली, नलू, मुण्डोलाव तथा बरना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

275. किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय के रेडियोलोजी विभाग को जिला स्तरीय विभाग में क्रमोन्नत कर उसी अनुरूप संसाधन उपलब्ध करने पर चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के मनोहरपुरा, ढसूक, बांदरसिंदरी ग्राम के उप स्वास्थ्य केन्दों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

277. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ में स्थित ट्रोमा सेन्टर में वांछित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

278. जैतारण सीएचसी में 75 बैड की स्वीकृति के साथ-साथ ट्रोमा सेन्टर भी खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

279. जैतारण क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केन्दों पर महिला चिकित्सकों (स्त्री रोग विशेषज्ञ) की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

280. मकराना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

281. बोरावड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

282. विधान सभा क्षेत्र करौली में पुराने हास्पिटल को सेटेलाइट हास्पिटल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
283. विधान सभा क्षेत्र करौली में सामान्य चिकित्सालय, पीएचसी एवं सीएचसी में चिकित्सकों, नर्सिंग चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
284. विधान सभा क्षेत्र करौली में सामान्य चिकित्सालयों को एक स्थान पर शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
285. विधान सभा क्षेत्र करौली में ग्राम कटकड एवं कोटरी में पीएचसी स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

286. ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
287. पूगल, छतरगढ़ एवं खाजूवाला सीएचसी में भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
288. कैंसर, पीलिया सहित सभी बीमारियों पर नियंत्रण हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
289. केला, नाल, कालासर, आनन्दगढ़, 2KWM सहित कई जगह पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
290. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के पीएचसी एवं सीएचसी में चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

291. धौलपुर में मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

292. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
293. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के दौलपुरा, रोजडा, नवागुडा, पोईना तथा भाचुन्दा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
294. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिन्दरू व चांचोड़ी के उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की पंचायत समिति सविनी, चाणोद व रूपावास के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

296. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में मेल नर्स प्रथम के 03, मेल नर्स द्वितीय के 30 एवं ANM के 43 रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

297. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के धनारी पीएचसी में 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

298. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में तिवासी पीएचसी को सीएचसी में, उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने, नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा मथानिया में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

299. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में चिकित्सकों, कम्पाउण्डर एवं नर्स के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

300. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद होने के कारण मरीजों को हो रही समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

301. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में गलियाकोट और सागवाड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी):

302. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित चिकित्सालयों में एम्बुलेंस ड्राइवर सहित, सोनोग्राफी व अन्य जांच मशीनें मय टैक्निशियन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

303. सोजत चिकित्सालय में सी.आर. मशीन उपलब्ध करवायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

304. विधान सभा क्षेत्र सोजत के बगड़ी नगर सीएचसी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

305. विधान सभा क्षेत्र सोजत के बगड़ी नगर के सीएचसी में डिजीटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

306. राजकीय चिकित्सालय सोजत में ट्रोमा सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

307. विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुरा चिकित्सालय को शहरी से ग्रामीण में सम्मिलित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

308. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में चिकित्सकों के खाली पद भरने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीविजयनगर एवं रायसिंहनगर में अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

309. रायसिंहनगर उपखण्ड पर ट्रोमा सेन्टर स्थापित करने तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

310. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की नीमराणा व मुण्डावर सीएचसी में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना कर सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

311. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के सभी राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

312. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

313. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की ग्राम पंचायत मायापुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

314. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रूपनगर उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय में पर्याप्त स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

315. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की ग्राम पंचायत तबीजी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

316. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम लाडपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

317. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल, जयपुर में राजकीय चिकित्सालय मोतीकटला को क्रमोन्नत करने तथा जालूपुरा, जौहरी बाजार, नाहरी का नाका में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

318. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बर्डोद (बहरोड़) में सीबीसी मशीन और फुल आटोमेटेड एनेलाइजर बायोकेमेस्ट्री उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

319. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांडण में बार-बार बिजली आपूर्ति ठप होने के बावजूद भी जनरेटर की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

320. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरोड़ में मरीजों के लिए 220 CFT सिलेण्डर एवं बैठने के लिए बैंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

321. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वेन्टीलेटर मशीन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

322. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरोड़ में नेबुलाइजर मशीन और पल्स आक्सीमीटर 05 पैरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

323. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

324. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

325. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों में निर्धारित मानदण्डानुसार जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

326. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नये चिकित्सा केन्द्र खोलने तथा क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

327. प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

328. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवलगढ़ के निर्माण कार्यों को पूरा कराने तथा विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

329. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर):

330. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के मंगलाना, पीलवा, जोखर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

331. परबतसर सीएचसी को क्रमोन्नत करने तथा ट्रोमा सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

332. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के बड़ू एवं बिदियाद पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

333. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूणकरणसर में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने एवं महिला चिकित्सक का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

334. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के मूंडसर, रामसर, कृजटी, राजासर उर्फ करणीसर एवं घीरेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

335. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के उप स्वास्थ्य केन्द्र राणीसर (रामबाग ग्राम पंचायत), रावांसर, खारी, खोडाला एवं डांडूसर के भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

336. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेन्टर में 24 घण्टे सोनोग्राफी तथा एमआरआई/सी.टी. स्कैन मशीन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

337. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के गांवों के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ANM के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

338. विधान सभा क्षेत्र जालौर में आयुर्वेद चिकित्सकों, आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

339. विधान सभा क्षेत्र जालौर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों, नर्सो एवं लैब टैक्नीशियनों के रिक्त पद शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

340. विधान सभा क्षेत्र जालौर में होम्योपैथिक चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं परिचारकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

341. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सायला में ब्लड बैंक स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

लिखित वक्तव्य

मांग संख्या 26 पर श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) का शेष वक्तव्य जिसे पढ़ा हुआ माना गया

अध्यक्ष महोदय,

मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा व आयुष जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार व्यक्त करने वाले पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को मैं अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपने बहुमूल्य सुझाव देकर मेरा मार्गदर्शन किया है। माननीय सदस्यों ने सदन में 341 कटौती प्रस्ताव के माध्यम से अपनी मांग प्रस्तुत की है।

इन प्रस्तावों में मुख्य रूप से चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों को भरने, नवीन चिकित्सा संस्थान स्वीकृत अथवा चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत करने, चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि करने आदि की माग माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

अध्यक्ष महोदय,

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि समस्त कटौती प्रस्तावों के जवाब माननीय सदस्यों को अतिशीघ्र प्रेषित कर दिये जायेंगे। माननीय सदस्यों द्वारा वर्णित गये क्रियान्वित करने योग्य सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल आरोग्य "स्वास्थ्य" है इसलिए आरोग्य दान से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आरोग्य दान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी दान हो जाता है।

प्राणीमात्र की अभिलाषा नीरोग रहने की रहती हैं। जनश्रुति भी है

"पहला सुख नीरोगी काया"

हमारा तो जीवन दर्शन भी रहा है-

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया'

अर्थात् सर्वत्र लोग सुखी रहें, सभी लोग नीरोग और स्वस्थ रहें।

लेकिन आज के भागदौड़ के समय में आम आदमी की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम होती जा रही है। इसी के साथ मिलावटी खाद्य पदार्थ, नशे की प्रवृति, दूषित पानी, पर्यावरण प्रदूषण एवं बदलती हुई जीवनशैली

(Sedentary Life style) के कारण लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। हमारा जोर बीमारियों से बचाव का होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाए।

महोदय,

मैं आभारी हूं मुख्य मंत्री गहलोत साहब का आप राज्य के तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं और तीनों बार ही जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक अभिनव योजनाएं बनाकर उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करवाया है।

राजस्थान भू-भाग की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का 10 प्रतिशत भूभाग राजस्थान में है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। इस समय राजस्थान की जनसंख्या अनुमानित 7 करोड़ 48 लाख से अधिक हो चुकी हैं।

विशाल भू-भाग के साथ ही प्रदेश में अनेक भौगोलिक पारिस्थितिक विषमताएं मौजूद है। मारवाड़ के रेगिस्तानी इलाके में आबादी छितरी हुई है। वागड़ और मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र ढूंढाड़, मगरा, शेखावटी, हाड़ौती, डांग क्षेत्र, मेवात और ब्रज सभी क्षेत्रों में पहुंच, आवागमन की अपनी अलग समस्याएं हैं।

प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र तथा इन दूर-दराज के क्षेत्रों की छोटी-छोटी ढाणियों और मगरों में रहने वाली आबादी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी सरकार स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत बनाने के साथ ही चिकित्सा विज्ञान की नवीनतम तकनीकें आमजन को उपलब्ध करवाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। हमारे डाक्टर्स पैरामेडिकल एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की अथक मेहनत से ही यह सम्भव हो पा रहा है। विभाग में विभिन्न वर्गों के लगभग एक लाख कर्मी कार्यरत हैं। यदि आशा को भी सम्मिलित कर लें तो यह संख्या 1.5 लाख है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में 17 हजार से अधिक राजकीय चिकित्सा संस्थान संचालित हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 103 चिकित्सालय जिनमें जिला, उप जिला व सैटेलाइट चिकित्सालय सम्मिलित हैं, 606 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2090 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 190 डिस्पेंसरीज, 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, 51 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 14 हजार

378 उपस्वास्थ्य केन्द्र, जो गांव एवं ढ़ाणी की मजबूत स्वास्थ्य इकाई है, स्थापित हैं।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत 5 शहरी सीएचसी व 139 शहरी पीएचसी भी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करा रही हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित चिकित्सालयों में कुल लगभग 51 हजार बैड्स की व्यवस्था है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय क्षेत्र में 14 मेडिकल कालेज से सम्बद्ध 52 चिकित्सालय संचालित किये जा रहे हैं तथा इनमें लगभग 20 हजार बैड्स की व्यवस्था है।

आयुष के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं योग के 4071 चिकित्सालय एवं औषधालयों का संचालन संबंधित निदेशालयों द्वारा किया जा रहा है।

राजकीय चिकित्सा संस्थानों में वर्ष 2018 में 12 करोड़ से अधिक रोगियों ने ओपीडी में एवं 71 लाख से अधिक रोगियों ने आईपीडी में सेवाएं प्राप्त की हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित चिकित्सालयों में 1 जनवरी, 2019 से 31 मई, 2019 तक 4 करोड़ 44 लाख 50 हजार 297 रोगियों ने आउटडोर (ओपीडी) एवं 20 लाख 31 हजार 894 रोगियों ने इन्डोर (आईपीडी) में चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त किया। उक्त गणनाएं एक मरीज के एक से अधिक बार लाभान्वित होने को सम्मिलित करते हुए की गयी हैं।

मुझे माननीय सदन को यह बताते हुए खुशी है कि जयपुर के एस.एम.एस. हास्पिटल दैनिक ओ.पी.डी. संख्या की दृष्टि से एशिया का अव्वल नम्बर का अस्पताल बन चुका है। इस अस्पताल में मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, पंजाब आदि राज्यों से भी बड़ी संख्या में रोगी उपचार के लिए आते हैं।

एसएमएस चिकित्सालय की सालाना ओपीडी लगभग 30 लाख है और IPD 2.15 लाख है। चिकित्सालय में प्रतिदिन 9.5 हजार से अधिक रोगी उपचार करवाने आते हैं। इनमें से लगभग 1 हजार से 1500 तक वृद्धजन एवं दिव्यांग रोगी होते हैं। हमारी सरकार द्वारा इन कैटेगरी के रोगियों के लिए ओपीडी में पृथक् से बैठने, वहीं पर जांच के लिए सैम्पल लेने, वहीं पर दवा

उपलब्ध कराने का कार्य राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गललोत जी के मंशा के अनुरूप शुरू किया गया है।

इसी प्रकार एसएमएस अस्पताल में कैंसर रोगियों को एक छत के नीचे सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है।

हमारा सेवा का भाव यह है कि-

"बीमार तुम पड़ो तो तड़पते हैं हम

सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है"

क्रोनिक एवं लाइलाज बीमारियों के अंतिम चरण में मरीजों को दर्द एवं अन्य तकलीफों के कारण अत्यधिक असहनीय एवं कष्टदायी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसे रोगियों की पीड़ा कम करने एवं शेष रहे जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एसएमएस चिकित्सालय में मानवीय संवेदनाओं को केन्द्र में रखकर पेलेटिव केयर की सुविधा प्रारम्भ की गई है जिसे सुचारु रूप से प्रदान करवायी जाकर (1) अंतिम चरण के कैंसरग्रस्त रोगियों को तकलीफदेह लक्षण जैसे असहनीय दर्द, भूख नहीं लगना, उल्टियां आदि (2) मरीजों के घावों का उपचार (3) घावों में कीड़े व पस पड़ने, बदबू आना आदि का उपचार किया जाना है।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस वर्ष के बजट आबंटन में आशातीत वृद्धि कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है।

इस वर्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु 13 हजार 18 करोड़ 27 लाख रुपये किया गया है, जो कि समग्र राज्य बजट का 5.96 प्रतिशत एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु गत वर्ष आबंटित बजट से लगभग 7 प्रतिशत अधिक है।

मुख्य रूप से-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 5 हजार 315 करोड़ रुपये से अधिक राशि का बजटीय प्रावधान किया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए इस वर्ष कुल 3 हजार 249 करोड़ रुपये अधिक राशि का बजट प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष के व्यय 2 हजार 692 करोड़ से लगभग 21 प्रतिशत अधिक है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2 हजार 101 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

आयुर्वेद विभाग पर इस वर्ष के बजट में करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि कर 989 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया।

मुख्य मंत्री महोदय ने इस वर्ष के बजट में प्रदेश में मोहल्लों में "जनता क्लिनिक" शुरू कर, इनमें नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

प्रदेश में पहली बार प्रारम्भ होने वाला यह कार्य स्वास्थ्य की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कार्य होगा। इससे आमजन को स्थानीय स्तर पर बीमारियों की जल्दी पहचान करने एवं उनका शीघ्र उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही आम-अवाम में स्वास्थ्य के प्रति चेतना भी बढ़ायी जा सकेगी।

मुख्य मंत्री महोदय ने इस वर्ष के बजट में प्रदेश में 200 नए स्वास्थ्य उप केन्द्र, 5 नए ट्रोमा सेंटर तथा 50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, 10 स्वास्थ्य उप केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने तथा अस्पतालों में 500 बैड्स बढ़ाये जाने की घोषणा की गयी है। इससे प्रदेश के स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।

महोदय, मैं, यहां पर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर माननीय सदस्यों का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी गत सरकार द्वारा वर्ष 2008 से 2013 के मध्य 200 से अधिक सीएचसी, 700 से अधिक पीएचसी, लगभग 3500 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये एवं विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 3400 शय्याओं की वृद्धि की। इसके मुकाबले गत सरकार द्वारा 5 वर्ष में मात्र 50 सीएचसी 60 पीएचसी एवं लगभग 1000 शय्याओं में वृद्धि की जबकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा हमारी वर्तमान सरकार के प्रथम वर्ष में ही गत सरकार के 5 वर्ष जितनी उपलब्धि की घोषणा की गयी है, जो कि हमारी सरकार का जन घोषणा पत्र के अनुरूप किये जाने वाले कार्यों का प्रथम सोपान है।

हमने जन-घोषणा पत्र में सबके लिये स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के साथ ही रोगमुक्त राजस्थान के निर्माण का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव मील का पत्थर साबित होगा।

हमारे जन-घोषणा पत्र में हमने प्रदेशवासियों को राइट-टू-हैल्थ देने का वादा किया था और अब हम इसे अंतिम स्वरूप प्रदान कर विधान सभा में लायेंगे तथा शीघ्र ही कानून का स्वरूप प्रदान करेंगे। इससे प्रदेश की करीब साढ़े सात करोड़ जनता को विधिक रूप से स्वास्थ्य का अधिकार मिल सकेगा। साथ ही राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकार युग की शुरूआत कर राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बनेगा।

हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नही है। वर्ष 1998 और 2008 में सरकार में आते ही हमने घोषणा पत्र को ही यथा नीतिगत दस्तावेज बनाकर लागू किया। इसी प्रकार अबकी बार भी हम जन-घोषणा पत्र को अक्षरशः लागू करेंगे। हमारी सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है।

स्वास्थ्य सूचकांक

अध्यक्ष महोदय,

प्रतिपक्ष के नेता ने शिशु मृत्यु दर में 3 अंकों की गिरावट के बारे में पिछले दिनों यह प्रश्न उठाया था कि क्या 6 माह के कार्यकाल में यह उपलब्धि हुई है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह उपलब्धि आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल के कारण नहीं, बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना रैफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आदि अभिनव योजनाओं के कारण अर्जित हुई है।

महोदय, इसीलिए केवल 6 माह की अल्पावधि में स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

नेता प्रतिपक्ष, नीति आयोग का गठन तो आपकी केन्द्र सरकार ने किया है। इसके आंकड़ों को तो आप मानोगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यों के मध्य प्रतियोगी वातावरण तैयार करने के लिए नीति आयोग ने 23 प्रकार के स्वास्थ्य सूचक निर्धारित किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार राजस्थान वृद्धिशील श्रेणी में 21 बड़े राज्यों में दूसरे पायदान (2nd Most Improving

State) पर है। मैं आश्वस्त हूं कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य एक माडल स्टेट बनने की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने बीमारियों का उपचार आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के रूप में एक ऐतिहासिक पहल की। महात्मा गांधी जन्म दिवस के दिन 2 अक्टूबर, 2011 से राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारम्भ हुआ।

आज यह योजना देशभर में एक अनुकरणीय मिसाल बन चुकी है। अनेक राज्यों ने इस योजना का अध्ययन कर इसे लागू किया है। अनेक अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस योजना को सराहा गया है।

प्रधान मंत्री महोदय जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधिमण्डल यहां भेजा था, इस योजना को समझा और इसकी तारीफ की। आप लोग गुजरात माडल की बहुत चर्चा करते हो। मेरा आग्रह है कि राजस्थान के इस माडल की भी तो तारीफ करो।

आपकी मुख्य मंत्री ने तो इस योजना की तारीफ करना तो दूर, बल्कि चुनाव जीतने के लिए ओछी राजनीति की। मुफ्त दवाओं को जहर बताकर आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया और जनता के विश्वास पर चोट पहुंचाने का कार्य किया। यह सब किया केवल अपने सियासी फायदे के लिए। माननीय, मेरा मानना है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको राजनीति से परे रखा जाना चाहिये।

आपके समय में आम आदमी की जरूरत की दवाएं गायब हो गईं एवं सिर्फ महंगी दवाइयां ही खरीदी गईं।

गत पांच वर्षों में दुर्भाग्य से आपकी इसी सोच के कारण हम योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ गये। अब दिसम्बर 2018 से हमारी सरकार बनने के पश्चात् इस योजना पर फोकस केन्द्रित करने के फलस्वरूप हम पुनः पूरे देश में योजना के क्रियान्वयन में एक नम्बर पायदान पर आ गये हैं। हमारी सरकार सियासी फायदे नहीं आम आदमी के फायदे के लिए काम कर रही है।

हमारे जनघोषणा पत्र की अनुपालना में निःशुल्क दवा योजना को और मजबूत किया जा रहा है।

जनघोषणा की अनुपालना में मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना के

तहत 608 निःशुल्क दवाइयों की संख्या में 104 तरह की नई दवाइयां शामिल करने से कैंसर, हार्ट एवं किडनी सहित अन्य गम्भीर बीमारियों के उपचार में लाभ मिलेगा। यह संख्या बढ़ाने से निःशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाली निःशुल्क दवाइयों की संख्या बढ़कर कुल 712 हो जायेगी।

प्रदेश में मरीजों को सुगमता से निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के लिये राजकीय चिकित्सा संस्थानों 600 नये दवा वितरण केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। अब प्रदेश में कुल 3 हजार 502 दवा वितरण केन्द्र संचालित हो जायेंगे।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत वर्ष 2011 से लेकर अब तक 66 करोड़ 74 लाख मरीजों को निःशुल्क दवा दी जा चुकी है। प्रतिदिन लगभग 2 से 2.5 लाख मरीजों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

अशोक गहलोत साहब ने अपने गत कार्यकाल में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को लागू किया। प्रथम चरण में 7 अप्रैल, 2013 से मेडिकल कालेज अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों में, द्वितीय चरण में 1 जुलाई, 2013 से सीएचसी व तृतीय चरण में 15 अगस्त 2013 से पीएचसी व डिस्पेंसरीज में इसे लागू किया गया।

योजना अन्तर्गत 271 एक्स-रे मशीनें, 378 ईसीजी मशीनें, 374 सेमी ओटोमेटेड बायोकेमेस्ट्री एनेलाइजर, 460 ब्लड सेल काउन्टर तथा 32 फुली ओटोमेटेड बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर उपलब्ध करवाये गये हैं।

बजट घोषणा में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत मेडिकल कालेज स्तर पर निःशुल्क जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है।

एसएमएस की तर्ज पर वरिष्ठ नागरिकों एवं बीपीएल परिवारों को प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों में भी सीटी स्कैन एवं एमआरआई की तथा एंजियोग्राफी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत 30 जून, 2019 तक लगभग 24 करोड़ 75 लाख निःशुल्क जांचें कर लगभग 12 करोड़ 4 लाख मरीजों को लाभान्वित किया गया। इस योजना के तहत प्रतिदिन लगभग एक लाख निःशुल्क जांचें की जा रही हैं।

हाईजीन हेतु निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन

अध्यक्ष महोदय,

मैनस्टुअल हाईजीन की कमी के कारण बालिकाएं एवं महिलाएं अनेक गंभीर रोगों से ग्रस्त हो सकती हैं। मैनस्ट्रूअल हाईजीन के संबंध में जागृति लाने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले सेनेटरी पैड्स उपलब्ध करवाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र बालिकाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना में प्रत्येक बालिका को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित करने का प्रावधान है। इस योजना का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है।

सेनेटरी नैपकिन के प्रयोग को बढ़ावा देने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से शासन सचिवालय जयपुर में सेनेटरी नैपकिन, वेन्डिंग मशीन लगाई है।

योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि बालिकाओं को इसका वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

अध्यक्ष महोदय,

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवारों को सामान्य बीमारियों हेतु 30 हजार तथा गम्भीर बीमारियों हेतु 3 लाख रुपये का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है।

योजना में उपचार हेतु 1401 पैकेज सम्मिलित किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए मर्यादाओं और सीमाओं को भी ताक में रख दिया गया तथा इस योजना को लागू करते समय मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश की जनता पर लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक का अनावश्यक वित्तीय भार डालकर भामाशाह कार्ड पर मुख्य मंत्री का फोटो, भाजपा का रंग और चुनाव चिन्ह छापा गया। जब आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजना में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इस प्रकार की फिजूलखर्ची नहीं की गई तो फिर राज्य में पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा इस प्रकार की फिजूलखर्ची किये जाने के कारण क्या रहे,

इसकी जानकारी तो स्वयं ही बता सकती हैं। आपके लिए यह आत्म चिंतन का विषय है। क्या इसके बिना इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता था? मेरा मानना है कि इस कार्ड के बिना भी उक्त योजना का लाभ दिया जा सकता है।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आयुष्मान भारत योजना को राज्य में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ एकीकरण करते हुए लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है।

इस योजना को राजस्थान ने लागू करने के लिए गत सरकार द्वारा अगस्त 2018 में ही केन्द्र से एमओयू कर लिया गया था। मूलतः राज्य की पिछली सरकार की इस योजना को लागू करने की मंशा ही नहीं थी। इसके चलते पिछली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण ही नहीं कराया क्योंकि राज्य एवं केन्द्र में एक ही पार्टी की सरकार होते हुए भी मतभेदों के चलते इस केन्द्रीय योजना को जान बूझकर उपेक्षित रखा गया। मुख्य मंत्री द्वारा अपने प्रचार-प्रसार की भामाशाह योजना को चलाने में रूचि अधिक थी और इसका परिणाम प्रदेश के लाखों मरीजों ने भुगता।

तत्कालीन मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के मध्य चली टकराहट, जो आज तक नजर आ रही है, के कारण गत सरकार द्वारा इस योजना को लागू नहीं किया गया। हमारी सरकार ने वैकल्पिक तरीका तलाश किया है और हम इसे पूर्ण मनोयोग से लागू करेंगे।

मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत लगभग 96 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़कर लागू किये जाने पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवार योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।

आयुष्मान भारत के अंतर्गत हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टर

आगामी वर्षो में सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 3 हजार 971 स्वास्थ्य केन्द्रों को हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें 1817 पीएचसी, 30 यूपीएचसी एवं 2124 उप स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं।

हमारी सरकार ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां आयुर्वेद विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दोनों के चिकित्सा संस्थान संचालित हैं वहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवाएं आयुर्वेद औषधालयों में एक छत के नीचे उपलब्ध कराये जाने का प्रयास करेगी।

मौसमी बीमारियों की रोकथाम

मौसमी बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूकता लाने के लिये स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिये निदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र लिखा जा चुका है।

मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूं कि इस सरकार की छह माह की अवधि में जो भी मौसमी बीमारियों के दौर आये, उसके चिकित्सा एवं बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेद विभाग ने सजग रहकर टीम भावना से मुस्तैदी से कार्य किया।

प्रदेश में 15 मई से 31 जुलाई तक डीडीटी स्प्रे कार्यक्रम का प्रथम चरण चलाया जा रहा है एवं द्वितीय चरण में 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक डीडीटी स्प्रे कार्यक्रम चलाया जायेगा।

यह भी एक विडम्बना है कि गत सरकार द्वारा 1400 करोड़ रुपयों की बर्बादी कर अत्यन्त अविवेकपूर्ण तरीके से अमानीशाह नाले को द्रव्यवती नदी के रूप में बदला गया है। इस तथाकथित नदी के अनेक हिस्सों में जमा पानी के कारण मच्छर पनप रहे हैं जिनसे मौसमी बीमारियां होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जयपुर के लोगों को भाजपा सरकार ने ये सौगात दी है या सजा दी है ये मेरी समझ से परे है।

हमारी सरकार ने मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक पर्याप्त मात्रा में दवाइयां पहुंचाना सुनिश्चित किया है।

नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम

राजस्थान पंजाब के बाद नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाला दूसरा प्रदेश बना है। यह कार्यक्रम इसी वर्ष 7 जून, 2019 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत वायरल हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग तथा समय पर उपचार की सुविधा सुलभ करायी जायेगी।

एसएमएस जयपुर, जे.एल.एन. अजमेर तथा जोधपुर के मेडिकल कालेज को आदर्श उपचार केन्द्र चुना गया है। इनके साथ ही जिला स्तर पर भी हेपेटाइटिस उपचार सुविधाएं सुलभ करायी जायेंगी।

स्वाइन फ्लू एवं अन्य मौसमी बीमारियां

बढ़ते प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, असुरक्षित खान-पान आदि कारणों से अनेक नयी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इनमें स्वाइन फ्लू, जीका, स्क्रब टाइफस व चिकनगुनिया जैसी बीमारियां शामिल हैं।

स्वाइन फ्लू रोग की रोकथाम, जांच, उपचार बचाव एवं नियंत्रण के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में स्क्रीनिंग कर उपचार के लिए रेपिड रेस्पोंस टीमों का गठन किया गया है। स्वाइन फ्लू पोजिटिव के सम्पर्क में आये व्यक्तियों की स्क्रीनिंग एवं नजदीकी क्षेत्र के 50 घरों का सर्वे कर लक्षण पाये जाने पर तुरन्त दवा दी जाती है।

स्वाइन फ्लू के लिए पर्याप्त मात्रा में दवा व आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। हमारी सरकार द्वारा टेमीफ्लू की 10 लाख गोलियों की आपूर्ति की गयी एवं इसकी उपलब्धता उप स्वास्थ्य केन्द्रों तक सुनिश्चित की गयी। यह हमारी चिकित्सा सेवा की कसौटी रही।

स्वाइन फ्लू के उपचार के लिये जिला अस्पतालों, सीएचसी व पीएचसी स्तर तक 3 हजार 33 अस्पतालों में स्क्रीनिंग सेंटर कार्यरत है। विभाग द्वारा स्वाइन फ्लू के रोगी की शुरूआती दौर में पहचान एवं उपचार करने एवं रोग की प्रभावी रोकथाम के लिए डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग अभियान लाया गया। प्रदेश में 12 प्रयोगशालाओं में स्वाइन फ्लू जांच की सुविधा उपलब्ध है।

मैं, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सर्दी के महीनों में स्वाइन फ्लू रोग ज्यादा फैलता है। साथ ही ऐसे रोगी, जिनके पहले से ही गम्भीर एवं Chronic बीमारियों से ग्रसित होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) कम हो गयी है, के लिए अधिक घातक सिद्ध होता है। हम इसके प्रभावी रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में इससे होने वाली विपरीत परिणामों से बचा जा सकेगा।

असंक्रामक रोग

विश्वभर में असंक्रामक रोगों का प्रकोप निरन्तर बढ़ रहा है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि मिलावट और नशा अनेक बीमारियों की जड़ है। इनको रोकने के लिए हमारी सरकार कानून सख्ती से लागू करेगी। जरूरत के अनुसार कानून में कड़े से कड़े प्रावधान किये जायेंगे ताकि दोषियों के हौसलें पस्त हों। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आमजन का स्वास्थ्य महफूज रहे, ये हमारा ध्येय रहेगा।

बदलती जीवनशैली, व्यायाम की कमी, तनाव, असुरक्षित खानपान, आदि कारणों ने असंक्रामक रोगों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप की संभावनाओं को बढ़ा दिया है।

प्रदेश में वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह एवं स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है।

कैंसर

प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को अर्ली कैंसर डिटेक्शन कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।

यूनिवर्सल स्क्रीनिंग आफ कामन एनसीडीज प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार का फैमिली सर्वे कर 30 से 65 आयु वर्ग के व्यक्तियों की असंक्रामक बीमारियों की स्क्रीनिंग का प्रावधान किया गया है।

जिला कैंसर केयर कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला चिकित्सालयों पर प्रशिक्षित चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मियों द्वारा कैंसर रोगियों को फोलोअप कीमोथैरेपी सहित अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

वर्तमान समय में दुनिया में सर्वाधिक मौतें कैंसर रोग के कारण होती हैं। मेरी सूचना के अनुसार लगभग 200 प्रकार के कैंसर होते हैं, जिनमें लगभग 25 कैंसर कॉमन प्रकार के हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, हमने एसएमएस चिकित्सालय में कैंसर की सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की है। इसके अन्तर्गत मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एवं रेडियेशन ऑन्कोलॉजी की सुविधाएं कैंसर रोगियों को एक स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं।

कैंसर के रोगियों की रजिस्ट्री संधारित नहीं होने के कारण इसकी वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसके लिए हमने एसएमएस अस्पताल में पहली बार कैंसर की रजिस्ट्री संधारित करने का कार्य प्रारम्भ किया है। इससे कैंसर के प्रकार तथा रोगियों की वास्तविक संख्या का आंकलन कर इसके रोकथाम, उपचार हेतु कार्ययोजना बनायी जा सकेगी। इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। हमने हाल ही में कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज भी घोषित किया है।

हृदय रोग

बच्चों में जन्मजात दिल में छेद के साथ ही अन्य विकृतियों तथा

जरूरतमंद हृदय रोगियों का उपचार करने के लिए 28 मई, 2019 को चिकित्सा विभाग ने सत्यसांई फाउण्डेशन राजकोट के साथ एमओयू किया है। इस एमओयू के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अहमदाबाद में तथा अन्य हृदय रोगियों को राजकोट ले जाकर फाउन्डेशन द्वारा "दिल विदआउट बिल" की तर्ज पर पूर्णतः निःशुल्क उपचार किया जायेगा।

प्रतिवर्ष एक हजार हृदय रोगियों का निःशुल्क उपचार कराया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रति मरीज और उनके एक परिजन को अहमदाबाद अथवा राजकोट आने-जाने के व्यय के लिए 5 हजार रुपये की राशि दी जायेगी।

इससे हृदय रोगियों के उपचार हेतु वर्तमान में होने वाले वेटिंग पीरियड में कमी आने के साथ-साथ निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी, 2019 को सर्वोदय दिवस पर 'नशा मुक्ति अभियान' आयोजित किया गया। इस दिवस पर 1 लाख 56 हजार 376 संस्थानों में 1 करोड़ 13 लाख 98 हजार 285 व्यक्तियों ने नशा न करने की शपथ ली।

राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विक्रय, वितरण भण्डारण एवं विज्ञापन को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा सर्च व सीजर की कार्यवाही की जा रही है।

जयपुर में लगभग 15 लाख रुपये के इलेक्ट्रोनिक सिगरेट निकोटिन, कार्टरेज, वैप आदि जब्त किये गये हैं। साथ ही हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित करने के लिय एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जा रहा है।

सभी जिला चिकित्सालयों में तम्बाकू मुक्ति परामर्श एवं उपचार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। तम्बाकू छोड़ने के लिये टोल फ्री नं. 104 व नेशनल क्विटलाइन 1800112356 पर तम्बाकू परामर्श की सेवाएं प्रदान की जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस-2019 के अवसर पर प्रदेश में तंबाकू निषेध के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए दक्षिण एशिया में सरकारी क्षेत्र में एकमात्र राजस्थान राज्य को अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

सुरक्षित मातृत्व

जननी सुरक्षा योजना

संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित कर सुरक्षित प्रसव कराने के साथ ही मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी जननी सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2011 से राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क प्रसव सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

योजना से सम्बद्ध चिकित्सालयों में प्रसवोपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

राज्य सरकार ने मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर कम करने के उद्देश्य से 12 सितम्बर, 2011 से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया। कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं बीमार एक वर्ष तक की आयु के शिशुओं को राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रसूताओं व शिशुओं को निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, निःशुल्क परिवहन व निःशुल्क भोजन सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

शिशु स्वास्थ्य

अध्यक्ष महोदय,

एक स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ प्रदेश और स्वस्थ समाज के लिए शिशु स्वास्थ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिशु अवस्था में रही शारीरिक व्याधियां जीवनपर्यन्त स्वस्थ जीवन के समक्ष गम्भीर चुनौतियां बनकर सामने आती हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस वर्ष एसआरएस के जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की एक वर्ष तक की आयु की शिशु मृत्युदर में 3 अंकों की गिरावट आयी है और यह 41 से घटकर 38 रह गयी है।

मुख्य मंत्री महोदय ने इस वर्ष के बजट प्रावधानों में नवजात बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबीकिट उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इससे शिशु मृत्युदर में और कमी लाई जा सकेगी।

शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से नवजात शिशुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में कुल 53 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट एवं मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों में कुल 7 न्यूबोर्न इन्टेंसिव केयर यूनिट संचालित की जा रही है।

एनीमिया

एनीमिया की कमी के कारण महिलाओं एवं बच्चों में अनेक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आयरनयुक्त भोजन करने से बच्चों में 20 से 30 प्रतिशत के बीच में अनिमिया को कम किया जा सकता हैं।

एनीमियामुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक बच्चों, किशोर-किशोरियों एवं महिलाओं में एनीमिया में कमी लाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। प्रदेश में 30 जनवरी, 2019 को जोधपुर से एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारम्भ किया गया।

रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने का प्रमुख कारण आयरन की कमी होती है।

एनीमियामुक्त राजस्थान अभियान के तहत महिलाओं, किशोर-किशोरियों एवं बच्चों को आयरन की पूर्ति के लिये आयरन फोलिक एसिड की गोलियां व सीरप स्कूलों व आंगनबाड़ी तथा चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से दिये जा रहे हैं। उद्घाटन के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी को प्रदेशभर में 74 लाख 47 हजार से अधिक बच्चों को आईएफए की खुराक दी गयी।

टीकाकरण

शिशु मृत्यु को कम करने के लिए प्रदेश में पेंटावैलेन्ट वैक्सीन टीकाकरण, आईपीवी, रोटा वायरस वैक्सीन, मिशन इन्द्रधनुष, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2018-19 के मूल्यांकन के अनुसार राज्य में 90 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण हुआ है।

खसरा रोग के उन्मूलन एवं रूबेला रोग के नियंत्रण के लिये प्रदेश में 22 जुलाई, 2019 से खसरा रूबेला अभियान का शुभारम्भ किया जा रहा है।

इस अभियान के अंतर्गत 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के लगभग 2 करोड़ 26 लाख बच्चो को खसरा रूबेला का टीका निःशुल्क लगाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि वे टीकाकरण अभियान में सक्रिय सहभागिता कर अभिभावकों को

प्रेरित करें। इस टीकाकरण कार्यक्रम से प्रदेश में बच्चों की मृत्यु दर में कमी आयेगी।

इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में रूबेला के संक्रमण से होने वाले गर्भपात तथा नवजात शिशु में अंधेपन, बहरेपन जैसी विकलांगता और हृदय रोग के मामलो में कमी आयेगी।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। प्रशिक्षित 502 मोबाइल हैल्थ टीम द्वारा सरकारी विद्यालयों, मदरसों व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चिन्हित 38 बीमारियों से ग्रस्त बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाता है।

राज्य के सरकारी अस्पतालों के साथ ही यह उपचार 18 निजी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम

राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों के संतुष्टि स्तर बढ़ाने के लिए गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम संचालित है।

गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में अब तक 10 राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों को नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन करवाया गया है एवं 12 राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों को राज्य स्तरीय सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है।

जनवरी 2019 से 5 माह में 6 अस्पतालों का नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन कराया गया।

जिला अस्पताल हनुमानगढ़ ने 81 प्रतिशत अंक, जिला अस्पताल चित्तौड़गढ़ ने 91 प्रतिशत, पीएचसी इस्लामपुर (झुन्झुनू) ने 86.7 प्रतिशत अंक, पीएचसी सल्लोपात (बांसवाड़ा) ने 87.7 प्रतिशत अंक, पीएचसी सिंगोली ने 92.6 प्रतिशत अंक एवं शहरी पीएचसी देवीनगर (जयपुर प्रथम) ने 93.8 प्रतिशत अंक अर्जित करते हुए नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि जिला अस्पताल सीकर, धौलपुर, झुंझुनूं एवं डूंगरपुर लेबर रूम एवं मेटरनल ऑपरेशन थियेटर को भारत सरकार द्वारा लक्ष्य प्रमाणन (Certification) किया गया है।

बेटी-बचाओ : पीसीपीएनडीटी

घटता लिंगानुपात हम सब के लिए चिंता का विषय रहा है। प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात मात्र 888 था। शिशु लिंगानुपात में सुधार करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की सख्ती से पालना करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 में लागू होने के बाद भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त लोगों को पकड़ने की योजना के तहत अब तक 45 इन्टर स्टेट सहित कुल 152 डिकॉय आपरेशन किये जा चुके हैं।

वर्ष 2019 में अब तक 11 डिकाय कार्यवाही की जा चुकी है। शीघ्र ही पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक कर नयी रणनीति तय की जायेगी।

पीसीटीएस के तहत दर्ज आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 में जन्म के समय शिशु लिंगानुपात मात्र 929 था। वर्ष 2016-17 में 938, वर्ष 2017-18 में 944 एवं वर्ष 2018-19 में 948 दर्ज हुआ है।

राजस्थान मेडिकल काउन्सिल, जयपुर द्वारा 22 चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन निलम्बित किये गये हैं। लिंग जांच में लिप्त चिकित्सकों की सूचना देने वाले व्यक्तियों के लिये प्रारम्भ "मुखबिर योजना" में मुखबिर को 2.50 लाख रुपये की इनामी राशि प्रदान की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा

मिलावटखोरी पर कड़ा नियंत्रण हमारी विशेष प्राथमिकता है। इसके लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट की तर्ज पर सख्त कार्यवाही की जायेगी तथा इसके लिए विशेष दल गठित किये जायेंगे।

मिलावटियों को दण्डित करने के लिए नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही हैं। वर्ष 2019 में समय-समय पर विशेष अभियान चलाये गये हैं।

फरवरी माह में संचालित विशेष अभियान में कुल 865 संस्थानों का निरीक्षण कर 642 नमूने लिये गये। होली पर विशेष अभियान में कुल 587 संस्थानों का निरीक्षण किया जाकर 403 नमूने लिये गये।

वर्तमान में राज्य में 6 खाद्य प्रयोगशालाओं में खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। 5 नई खाद्य प्रयोगशालाएं भरतपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, चूरू व जालौर को शीघ्र ही क्रियाशील की जायेंगी।

उदयपुर व जोधपुर में पेस्टीसाइड एवं हेवी मेटल्स की जांच के लिए आवश्यक उपकरण व मानव संसाधन उपलब्ध करवाकर कार्य प्रारम्भ करवाया जायेगा।

माह जनवरी 2019 से जून 2019 तक राज्य में जांच हेतु 2 हजार 986 खाद्य नमूने लेकर जांच करवायी गयी। इनमें 380 सबस्टैण्डर्ड, 211 मिसब्रांड एवं 156 अनसेफ पाये गये हैं।

इसमें न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर के यहां सबस्टैण्डर्ड वाले मामलों में 5 लाख तक व मिसब्रांड वाले मामलों में 3 लाख तक की पेनल्टी लगाने के प्रावधान हैं। जन स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ ना हो इसके लिए हम जीरो टोलरेंस की नीति लेकर चल रहे हैं।

वर्तमान कानून सख्ती से लागू करने, लम्बित प्रकरणों में त्वरित सुनवाई व दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जरूरत पड़ी तो कानून में सुधार कर कड़े प्रावधान लाये जायेंगे।

अभी लैब टेक्निशियन, नर्सिंग के स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग देकर फूड इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी दी गयी है और 98 में से 60 पदों पर इनको लगाया गया । इसमें समस्त 98 पदों पर प्रावधित योग्यतानुसार खाद्य निरीक्षक भर्ती की अभ्यर्थना प्रेषित की जा चुकी है, जिन पर शीघ्र ही भर्ती से समस्त पद भर दिए जायेंगे। इसमें सैम्पल लेने की तकनीकी योग्यता वाले अधिकारी की कानून अपेक्षा की कमी भी दूर हो जायेगी।

भविष्य में कार्य योजना बनाकर पीसीपीएनडीटी एक्ट के दस्ते की तर्ज पर ही खाद्य सुरक्षा एक्ट के क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा।

इन्टीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा

सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतें हम सब के लिए चिंता का कारण है। सामान्यतः युवा इन दुर्घटनाओं का अधिक शिकार होते हैं। दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में चिकित्सा सुविधा प्रदान कर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचायी जा सकती है।

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों, प्रसूताओं, नवजात शिशुओं एवं गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को भी आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा के तहत कुल 1 हजार 508 एम्बुलेंस संचालित की जा रही हैं।

इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा के तहत तय समय सीमा शहरी क्षेत्र में 20 मिनट, ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट एवं रेगिस्तानी व पर्वतीय क्षेत्र में 40 मिनट है। हमारा प्रयास इस तय सीमा को और कम करने का है।

इसमें पुलिस, यातायात, नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग व चिकित्सा विभाग के समन्वय को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, जो हमारी अगली कार्य योजना रहेगी।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम

विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी मार्ग दर्शन तथा भारत सरकार के सहयोग से संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत डायरेक्टली आब्जर्वेशन ट्रीटमेन्ट शार्ट कोर्स (डॉट्स) प्रणाली वर्ष 1995 से प्रारम्भ की गई। राज्य सरकार टी.बी. के उन्मूलन के लिए कृतसंकल्प है।

टीबी रोगियों द्वारा कई बार उपचार को बीच में ही छोड़ देने के कारण, इस रोग का ड्रग रेजीस्टेंस बढ़ रहा है। इस प्रकार के रोगी पारम्परिक उपचार से ठीक नहीं हो पाते हैं। इन रोगियों को मल्टी ड्रग रेजीस्टेंस उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

निक्षय पोषण योजना के तहत क्षय रोगियों को इलाज की अवधि के दौरान पोषण हेतु रुपये 500 प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में सहायता के रूप में दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

गांधीजी के निर्वाण दिवस पर 30 जनवरी से 13 फरवरी, 2019 तक स्पर्श कुष्ठरोग जागरूकता अभियान संचालित किया गया। प्रदेश के 7 जिलों अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली एवं उदयपुर में कुष्ठ रोगी खोज अभियान के तहत डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है।

सार्वजनिक निजी सहभागिता

प्रदेश के 34 जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड पर हीमोडायलिसिस, 8 जिला चिकित्सालयों में आईवीएफ सेन्टर, एमआरआई की सुविधा 4 स्थानों पर, 30 चिकित्सा संस्थानों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

वर्तमान में 84 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड पर सचालित किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आमजन को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इनमें विशेष क्षेत्रों अथवा सेवाओं के उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निजी जनसहभागिता शुरुआत की गयी। मुझे यह बताते हुए दुख एवं रोष होता है कि गत सरकार द्वारा अपने दायित्वों से मुंह मोड़ते हुए अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे कई राजकीय चिकित्सा संस्थानों को पीपीपी मोड पर दे दिया गया। इससे जीवन रक्षा की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इसमें पूर्व सरकार ने अपने चहेतों को काम देकर उपकृत किया है।

इस संबंध में सम्माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारी सरकार पीपीपी मोड पर संचालित संस्थानों/योजनाओं पर गुणावगुण के आधार पर पुनर्विचार कर इन पर उचित निर्णय लेगी और इनकी आड़ में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कार्यवाही करेगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

अध्यक्ष महोदय,

तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह तथा यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की पहल पर वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस की सोच थोथी वाह-वाही लूटने की नहीं बल्कि धरातल पर ठोस काम करने की रही है।

वर्ष 2012 में एनआरएचएम का प्रथम चरण पूर्ण होने पर अवधि को लगातार जारी रखते हुए 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को जोड़कर अब यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में कार्यरत है।

एनयूएचएम के अन्तर्गत प्रदेश के 61 शहरों की कच्ची बस्तियों की आबादी सहित कुल सवा करोड़ से अधिक आबादी को लाभान्वित किया जा रहा है।

आयुष चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण कार्य

इस वित्तीय वर्ष में कुल 43 करोड़ रुपये की राशि के संस्थानों के भवन निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

वर्तमान में 50 शय्याओं वाले 3 आयुष चिकित्सालय बीकानेर,

भीलवाड़ा व अजमेर के भवन निर्माण कार्य तथा 124 आयुष चिकित्सा संस्थानों के भवनों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

विगत 6 माह में एक 50 शय्याओं वाले चूरू आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य तथा 43 अन्य आयुष चिकित्सा संस्थानों के भवनों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग-उपलब्धियां एवं घोषणाएं

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 15 हजार नियुक्तियां प्रदान करने की घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उल्लेख किया था कि चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों के लगभग 3 हजार पद रिक्त हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये पद पिछले 6 माह में रिक्त नहीं हुए हैं। ये रिक्तियां पिछली सरकार से हमें विरासत में मिली हैं। ये अपने कार्यकाल में क्या करते रहे, इसका जवाब तो ये ही देंगे। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

चिकित्सकों के 737 पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इन पदों को शीघ्र भरा जायेगा।

आमजन को दंत रोगों के उपचार हेतु उपलब्ध सुविधाओं में बढ़ोतरी किये जाने हेतु दंत चिकित्सा अधिकारियों के 480 नये पद सृजित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवारत चिकित्सक प्रतिवर्ष पीजी हेतु चयनित होते हैं। 3 वर्ष की पीजी के दौरान लगभग 1500 चिकित्सक पीजी करने के लिए विभाग से अवकाश पर होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ चिकित्सक सीनियर रेजीडेन्सी अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर अथवा सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के पदों पर चयनित हो जाते हैं। अतः विभाग में स्वीकृत पदों में से लगभग 2 हजार पद रिक्त रह जाते हैं।

चिकित्सकों की इस कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा विभाग में पीजी लीव रिजर्व के रूप में चिकित्सा अधिकारियों के 2 हजार पद स्वीकृत करवाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष महोदय,

यह कार्य पिछली सरकार भी कर सकती थी, लेकिन पिछली सरकार ने तो इस समस्या पर चिंतन मात्र भी नहीं किया। उनकी चितांयें तो दूसरी ही थीं।

पिछली सरकार के दौरान पीजी करके आने वाले सेवारत चिकित्सकों को पदस्थापन के लिए महीनों इंतजार करवाया जाता था और वे अपने मनवांछित स्थान पर पदस्थापन के लिए जुगाड़ करते रहते थे। हमने मात्र 10 दिन की अवधि में ही पीजी पूर्ण करके आये 306 सेवारत विशेषज्ञ चिकित्सकों का विशिष्टता की आवश्यकतानुसार पदस्थापन कर दिया।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी को तत्काल पूरा करने के लिए अर्जेन्ट टेम्परेरी बेसिस पर चिकित्सकों को लिये जाने की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जायेगी।

इन सभी तथ्यों को हम अपनी अगली कार्य योजना का हिस्सा बनाकर चल रहे हैं ताकि एच.आर. व फैकल्टी मैनेजमेंट में बेहतर समन्वय हो सके और पदों की रिक्तियों, पदस्थापन में अनावश्यक इंतजार से चिकित्सा सेवाओं पर विपरीत प्रभाव ना पड़े।

हमारी सरकार भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित करेगी।

जनघोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुसार राज्य की एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4 नये व्यापक स्तनपान प्रबंधन केन्द्र अजमेर, कोटा, बीकानेर तथा जोधपुर में खोलने की घोषणा करता हूं। इस संबंध में उत्तर भारत का क्षेत्रीय संदर्भ केन्द्र जे. के. लोन अस्पताल जयपुर में स्थापित किया जायेगा।

राज्य के थैलेसीमिया के मरीजों को 2 करोड़ 88 लाख रुपये लागत के फिल्टर बैग उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं।

चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 732 करोड़ रुपये की राशि से 59 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 74 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 170 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नवीन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जायेगा।

विगत 6 माह में 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 32 उप स्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर उपयोग हेतु सौंप दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है, हमारी

सरकार मिलावटी खाद्य पदार्थों एवं नकली दवाइयों पर प्रभावी रोकथाम हेतु दृढ़ संकल्प है।

मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने एवं बेचने के दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को वर्तमान में प्रचलित धाराओं में 6 माह तक की सजा दिये जाने के प्रावधान को गैर जमानती करने एवं सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाये जाने हेतु संशोधन प्रस्तावित किया जायेगा।

इसी प्रकार नकली दवाइयों के निर्माण एवं बेचान में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को वर्तमान में प्रचलित धाराओं में 6 माह तक की सजा दिये जाने के प्रावधान को गैर जमानती करने एवं सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाये जाने हेतु संशोधन प्रस्तावित किया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा-उपलब्धि एवं घोषणा

अध्यक्ष महोदय,

राज्य सरकार मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध अस्पतालों की प्रगति एवं सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु सतत प्रयत्नशील है।

इसी वर्ष राज्य के बाड़मेर जिले में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता का नया मेडिकल कालेज प्रारम्भ भी कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में पूर्व से संचालित मेडिकल कालेजों में 550 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि की गई है। अब प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटें 1950 से बढ़कर 2600 हो गयी हैं।

सीकर मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य व जिला अस्पताल का उन्नयन एवं विस्तार कार्य प्रगति पर है। इसको अगले शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

धौलपुर मेडिकल कालेज के निर्माण का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा।

चिकित्सा महाविद्यालयों में 46 पी.जी. सीटों में तथा 11 सीटें सुपरस्पेशलिटी विषयों में वृद्धि की गई है।

जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया एसएमएस अस्पताल देश ही नहीं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। इस अस्पताल में प्रदेश ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ चिकित्सक, निःशुल्क दवा व जांच के चलते अनेक पड़ौसी राज्यों के मरीज उपचार के लिए आते हैं।

एसएमएस अस्पताल के रोगी भार को कम करने के लिए राजस्थान

स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन 500 बैड के नये अस्पताल को प्रारम्भ कर दिया गया है।

अत्यधिक रोगी भार के कारण मरीजों की लम्बी कतारें लगती हैं। इन कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए एसएमएस में क्यूलेस पंजीकरण व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है।

इस अस्पताल में बेहतर अस्पताल प्रबंधन के लिए इन्टीग्रेटेड हैल्थ मैनेजमेंट सिस्टम प्रभावी तरीके से लागू किया जायेगा।

मरीजों की सुविधा के लिए एसएमएस अस्पताल में अपाइन्टमेन्ट के लिए एक मोबाइल एप भी प्रारम्भ किया गया है।

एसएमएस हॉस्पिटल में 16 जुलाई, 2019 से वरिष्ठजनों व दिव्यांग मरीजों की सुविधा के लिए हैल्प डेस्क चालू किये गये हैं, जिन्हें अन्य अस्पतालों में भी लागू करने के प्रयास किये जायेंगे तथा आन्कोलोजी के नये ओपीडी ब्लाक का शुभारम्भ भी किया गया है।

मुख्य मंत्री महोदय ने एस.एम.एस. अस्पताल के अत्यधिक दबाव को देखते हुए 10 करोड़ रुपये की लागत से 50 बैड के एडवांस मेडिकल आईसीयू के साथ ही न्यूरोलोजी विभाग में 2 करोड़ रुपये की लागत से 10 बैड का स्ट्रोक आईसीयू बनाने की घोषणा की है।

जयपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से सुपरस्पेशलिटी ब्लाक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसमें आर्गन ट्रान्सप्लान्ट संस्थान की स्थापना की जायेगी।

एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर में अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए स्टेट आर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांट संगठन की स्थापना की गई है।

जयपुर व जोधपुर मेडिकल कालेज में अंग प्रत्यारोपण किया जा रहा है। शेष राजकीय मेडिकल कालेजों में नान ट्रांसप्लांट आर्गन रिट्रीवल सेन्टर की स्थापना की जा रही है। भविष्य में शेष राजकीय मेडिकल कालेजों को आर्गन ट्रांसप्लांट सेन्टर के रूप में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 305 किडनी, 13 हार्ट एवं 42 लीवर का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया जा चुका है जिसे कि इस दिशा में बढ़ते कदम के रूप में देखा जा सकता है।

मेडिकल कालेज अजमेर में 71 लाख रु. की लागत से सेमीनार हाल का निर्माण पूर्ण कर 8 मार्च, 2019 को इसका लोकार्पण किया गया।

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में दानदाता के सहयोग से कैंसर रोगियों के उपचार हेतु 2 करोड़ 40 लाख रु. की लागत से ब्रैंकीथैरेपी मशीन की स्थापना एवं 2 करोड़ 61 लाख की लागत से आपातकालीन इकाई का निर्माण किया गया है।

इसके अतिरिक्त अजमेर में 4 करोड़ 42 लाख रु. की लागत से 4 आपरेशन थियेटर का नवीनीकरण कर अत्याधुनिक माड्यूलर ओ.टी. की स्थापना की गयी है। राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, अजमेर में आक्सीजन गैस प्लान्ट की स्थापना कर रोगियों को बेहतर सुविधा देना प्रारम्भ कर दिया गया है।

कोटा, बीकानेर व उदयपुर में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हेतु नवीन ब्लाक्स की स्थापना के बाद अजमेर हेतु भी सुपरस्पेशलिटी ब्लाक की स्थापना हेतु प्रस्ताव केन्द्र को प्रेषित किए जा रहे हैं।

राज्य में संक्रामक रोगों एवं महामारी की अन्वेषण एवं अनुसंधान को गति देने के लिये जोधपुर में स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस बजट में जो घोषणा की है उससे जोधपुर में 31 करोड़ रु. की लागत से कैंसर रोगियों के उपचार हेतु राजकीय क्षेत्र में लिनियर एक्सीलरेटर मशीन की स्थापना की जा रही है।

जोधपुर मेडिकल कालेज में न्यू ओ.पी.डी. में एक्स-रे हेतु 1.5 करोड़ की डी.आर. मशीन 25 मार्च, 2019 को स्थापित की गयी है।

मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में अत्याधुनिक एडवांस्ड लाइफ सेविंग एम्बुलेंस उपलब्ध करायी गई है एवं ब्लड बैंक हेतु एक सामान्य एम्बुलेंस भी उपलब्ध करायी गयी है।

राजमेस-राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी

इस सरकार के 6 माह के कार्यकाल में-

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के अन्तर्गत संचालित 5 नवीन मेडिकल कालेजों (भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, चूरू एवं डूंगरपुर) को भारत सरकार से फर्स्ट रिनुवल प्राप्त हो गया है एवं एक मेडिकल कालेज (बाड़मेर) को शिक्षण सत्र शुरू करने हेतु Letter of Permission (LO.P.) जारी हो चुका

है। साथ ही इन 5 मेडिकल कालेजों में 250 सीटों की वृद्धि की जा चुकी है। जहां पिछले वर्ष राजमेस कालेजेज में कुल 500 छात्र-छात्राओं का चयन हो रहा था, वह अब बढ़कर 6 मेडिकल कालेजों में 850 हो गया है।

सभी नवीन मेडिकल कालेजों में अनुसंधान कार्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु मल्टीडिसीप्लीनरी रिसर्च यूनिट स्थापना किये जाने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जा रहे हैं।

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी द्वारा 139 चिकित्सक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में 113 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गयी, जिसमें से राज्य के नवीन मेडिकल कालेजों में 34 व पिछली भर्तियों के 9 चिकित्सक शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया है। रिक्त भर्तियों के लिए अभियान चलाकर भर्तियां शीघ्र की जायेंगी।

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की उपलब्धियां एवं घोषणाएं

अध्यक्ष महोदय,

आयुर्वेद भारतीय जन-जीवन में रची-बसी हमारी जीवन पद्धति है। आयुर्वेद को विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति माना जाता है। आयुर्वेद की तरह ही योग विश्व समुदाय को भारत की सबसे बड़ी देन माना जाता है।

हमारी सरकार आयुष चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा सिद्धा के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

आयुष चिकित्सा पद्धतियों की दृष्टि से हमारे प्रदेश में देश का सबसे बड़ा ढांचा उपलब्ध है। हमारे यहां आयुर्वेद चिकित्सा विभाग के 3711 औषधालय, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के 190 औषधालय, यूनानी चिकित्सा विभाग के 131 औषधालय तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के 39 औषधालय संचालित हैं।

राज्य में आयुष शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा राजकीय क्षेत्र में डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, मदनमोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर तथा केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में उपलब्ध है।

शुद्ध एवं प्रामाणिक औषधि के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर आयुर्वेद औषधि गुणवत्ता की जांच हेतु समस्त सहायक निदेशकों को अधिसूचित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आयुर्वेद पर आपने चिंता व्यक्त की, हकीकत ये है-

मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के नेता, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का मुद्दा उठाया है, मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के कार्यकाल (2009-2013) में 42 आयुर्वेद, 31 यूनानी एवं 14 होम्योपैथी, कुल 87 चिकित्सालय/औषधालय कमोन्नत/नवीन खोले गये।

आपकी सरकार (2014-2019), जो कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित पोषक बताती है, के कार्यकाल में मात्र तीन आयुर्वेद चिकित्सालय/ औषधालय खोले गये और होम्योपैथी एवं यूनानी का एक भी चिकित्सालय/ औषधालय नहीं खोला गया।

हमारी सरकार ने आयुर्वेद नर्सिंग के लिए राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद्, 2012 इसी सदन में पारित करवाया, परन्तु गत पांच वर्षों में इस पर कोई कार्यवाही नहीं की परन्तु हमारी सरकार ने मात्र 6 माह में इसके नियम बनाये हैं एवं आगामी तीन माह में हम आयुर्वेद नर्सिंग का पंजीयन प्रारम्भ कर देंगे, जो एक ऐतिहासिक कदम होगा।

ड्रग्स एवं मेजिक रेमीडिज एक्ट, 1954 के तहत भ्रामक एवं जादुई उपचार के विज्ञापनों को रोकने के दृष्टिकोण से पहली बार जिला स्तर पर अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है।

अजमेर मुख्यालय पर 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन कर लगभग 56 हजार व्यक्तियों को तथा 6 संभागों में 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेलों का आयोजन कर लगभग 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को आयुष चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित किया गया।

आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा क्षारसूत्र के लिए 29 शिविरों का आयोजन कर कुल 2 हजार इन्डोर एवं 36 हजार आउटडोर रोगियों को उपचारित किया गया।

मौसमी बीमारियों से बचाव एवं चिकित्सा हेतु आयुर्वेद विभाग द्वारा लगभग 66 लाख व्यक्तियों को औषधीय काढ़ा निःशुल्क वितरित किया गया।

विभागीय चिकित्सा केन्द्रों की भूमि, भवन, आधारभूत संरचना, फर्नीचर, उपकरण तथा विभागीय सेवाओं से सम्बन्धित आयुष विभाग का आयुरस साफ्टवेयर को विभाग में पहली बार तैयार किया गया।

अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से चयनित जिला औषधालयों में 28 जनवरी से 25 फरवरी, 2019 तक 25 निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।

महाविद्यालय में दो नवीन विषयों में सत्र 2019-20 से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जून 2019 में एलओपी प्रदान कर दी गई है। इनमें इसी सत्र 2019-20 से प्रवेश प्रारम्भ होंगे।

राज्य में पहली बार इस वर्ष से प्रत्यक्षतः समस्त आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों के परामर्श पर मुख्य मंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत जांच का लाभ आमजन को प्राप्त हो रहा है।

आयुष चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण कार्य

इस वित्तीय वर्ष में कुल 43 करोड़ रुपये की राशि के आयुष चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

वर्तमान में 50 शय्याओं वाले 3 आयुष चिकित्सालय बीकानेर, भीलवाड़ा व अजमेर के भवन निर्माण कार्य तथा 124 आयुष चिकित्सा संस्थानों के भवनों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

विगत 6 माह में एक 50 शय्याओं वाले चूरू आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य तथा 43 अन्य आयुष चिकित्सा संस्थानों के भवनों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की घोषणाएं

पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान लम्बे समय से रूके हुए श्रीगंगानगर में मेडिकल कालेज का कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है।

सीकर मेडिकल कालेज में चल रहे निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कर इसे अगले शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के धौलपुर मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में मल्टी स्टोरी आईसीयू वार्ड का चरणबद्ध रूप से निर्माण किया जायेगा।

मेडिकल कालेज अजमेर जो कि वर्तमान में शहर के बीचों-बीच स्थित

है एवं अस्पताल के अत्यन्त निकट है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए रोगी भार को दृष्टिगत रखते हुए अस्पताल के विकास एवं मेडिकल कालेज को भी 250 एमबीबीएस सीटों की प्रवेश क्षमता हेतु आवश्यक स्थानाभाव जो अजमेर के कारण बाधक सिद्ध हो रहा है। अतः मेडिकल कालेज अजमेर को कायड ग्राम में नवीन भवन के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ताकि कालेज और अस्पताल दोनो का समुचित विकास हो कालेज के सके इससे भविष्य में कालेज के वर्तमान भवन की जगह सुपरस्पेशलिटी ब्लाक की स्थापना भी सुगमता से की जा सकेगी।

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग की घोषणाएं

जन घोषणा पत्र की अनुपालना में सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। वर्तमान में 62 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन स्थानों पर आयुर्वेद चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभागीय औषधालय प्रारम्भ किये जायेंगे।

राज्य में आयुर्वेद औषधालयों को चरणबद्ध रूप से "हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स के रूप में प्रोन्नत किया जायेगा जिसके अन्तर्गत योगाभ्यास, निःशुल्क आयुर्वेद उपचार एवं परामर्श तथा जड़ी-बूटियों की जानकारी दी जायेगी।

मगरा, डांग, मेवात क्षेत्र के निवासियों को यूनानी चिकित्सा का लाभ देने हेतु यूनानी चिकित्सा मोबाइल यूनिट प्रारम्भ की जायेगी।

मेडिट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में संचालित पंचकर्म केन्द्र को आधुनिक एवं सुसज्जित किया जायेगा।

आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं योग चिकित्सा सेवाएं एक छत के नीचे प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सीकर जिला मुख्यालय पर 50 बैड का नया एकीकृत आयुष चिकित्सालय का निर्माण किया जायेगा।

बीकानेर, चूरू एवं भीलवाड़ा जिला मुख्यालयों पर 50 बैड के नये एकीकृत आयुष चिकित्सालय प्रारम्भ किये जायेंगे।

आयुर्वेद विज्ञान के स्वास्थ्यपरक उपादेयता, शुद्ध पेयजल, जड़ी बूटियों

के ज्ञान आदि के लिए राज्य के 5 गांवों को आयुष ग्राम के रूप में विकसित किया जायेगा।

85 आयुर्वेद औषधालयों के नवीन भवन निर्माण व मरम्मत कार्य किया जायेगा।

राजस्थान आयुर्वेद सेवाओं में एकरूपता लाए जाने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 2008 तथा अधीनस्थ ग्रामीण सेवा नियम, 2008 को रिपील किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष से जुड़े सभी विभाग पूर्ण तत्परता के साथ प्रदेश के रेगिस्तानी, डांग, आदिवासी इलाकों सहित दूर-दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। विभाग द्वारा इन चुनौतियों का सामना कर प्रदेशवासियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा।

"हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है

हम उम्मीद पर नहीं जिद में जीया करते हैं।"

माननीय सदस्यों ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव देने के साथ ही अपने-अपने क्षेत्रों की स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मांगें प्रस्तुत की हैं। इन सभी का व्यापक रूप से अध्ययन करवाकर होने योग्य सभी कार्य यथाशीघ्र करवाये जायेंगे।

अन्त में मैं सदन के समस्त माननीय सदस्यों से स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय योगदान करने की अपील करता हूं।

मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर सेवा के इस पवित्र कार्य में सकारात्मक एवं सक्रिय रहकर प्रदेशवासियों को स्वस्थ और नीरोग बनाने में सफल सिद्ध होंगे।

हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय के दिल में जो करुणा का भाव हमेशा रहता है उसे मैं व्यक्त करना चाहता हूं-

''मैं अल्फाज हूं तेरी हर बात समझता हूं
के अहसास हूं तेरे जज्बात समझता हूं
सिर्फ हालात नहीं पूछूंगा सेवा का जज्बा है
मैं दिल रखता हूं तेरे हालात समझता हूं''